

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दुस्थानका कानून दिवालिया

अर्थात्
प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०
प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०६ ई०
Provincial Insolvency Act 5 of 1920.

AND
Presidency Towns Insolvency Act 3 of 1909.

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और सन १९३० ई० तकके समग्र
संशोधनों व नज़ीरों आदि सहित

लेखक. —
बाबू रूपकिशोर टण्डन

एम० ए०, एलएल० बी०, एम० आर० ए० एल० एडवोकेट

प्रकाशक : —
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल
सन १९३० ई०

मुद्रित
कानून प्रेस, कानपुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य
२५ रुपया प्रति

भारत

कानून दिवालीया

प्रान्तिक कानून दिवालीया (एक्ट ५ सन १९५० ई०)

प्रेसीडेन्सी गवर्नर्स कानून दिवालीया (एक्ट ३ सन १९५६ ई०)

इस समय भारतवर्षमें प्रत्येक प्रचलित कानूनका हिन्दी भाषामें होना आवश्यक है क्योंकि इस भाषाको जानने व समझने वालोंकी संख्या बहुत है तथा वह दिन बदिन बढ़तीही जाती है। प्रचलित कानूनोंका ज्ञान भी जनसाधारणके लिये किसी हद तक परमावश्यक है क्योंकि उनकी पाश्चीसे वह लोग बच नहीं सकते हैं। समझदार व्यक्तियोंका यह कर्तव्य है कि यह ऐसी बातोंको अवश्य जानते रहें जिससे किसी समय भी अनायास हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो अथवा जिनके आधार पर वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सकते हों। मनुष्यकी अवस्था सदैव एकसी नहीं रहती है कभी उसे लाभ होता है तथा कभी हानि, परन्तु वही मनुष्य अपनी स्थिति को समयानुकूल सँभाल सकता है जिसे प्रचलित नियमोंका यथा सम्भव ज्ञान होवे। ऐसे नियमों का जानने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं कर सकता है किन्तु वह अपनी सलाहसे दूसरोंको भी लाभ पहुँचा सकता है।

देशमें व्यापार फैलाने तथा लेनदेनका काम विस्तृत रूपसे हो जानेके कारण इन कामोंसे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियोंका अनायास ही हानि पहुँचनेके अवसर आजाते हैं। चालाक व्यक्ति प्रचलित कानूनोंका अनुचित लाभ उठा कर दूसरे लोगोंको जो उन कानूनोंसे अनभिज्ञ होते हैं तब तरहकी हानियाँ पहुँचा दिया करते हैं। कानून दिवालीयाका प्रयोग अब बहुतायतसे किया जाने लगा है इस कारण उक्त कानूनका ज्ञान लेना हर व्यक्तिके लिये आवश्यक माना जाता है जिससे कि वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सके तथा जहाँ तक होसके हानियोंसे भी बच सके। इसी प्रकारकी आवश्यकताको प्रतीत कर कानून दिवालीया हिन्दीमें प्रकाशित किया गया है।

यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें लिखी गई है। प्रत्येक दफाका अनुवाद समझने योग्य भाषामें दिया जानेके अतिरिक्त उसकी व्याख्या भी पूर्ण रूपसे की गई है। व्याख्यामें दफाओंका अर्थ भली भाँति समझानेका प्रयत्न किया गया है तथा उन सब उल्लेखनीय मुकद्दमोंका भी

हवाला दिया गया है जो भिन्न भिन्न हार्दिकोंतों तथा चीफकोर्ट द्वारा अवतक तय किये गये हैं। यह पुस्तक दो भागोंमें विभक्त है एकमें प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १६२० ई०) का पूरा वर्णन है तथा दूसरेमें प्रेसीडेन्सी टाउनस कानून दिवालिया (एक्ट ३ सन १६०६ ई०) का उसी प्रकार विवरण दिया हुआ है।

ब्रिटिश भारतमें कानून दिवालियाका चलन इङ्ग्लैण्डके चैम्बर्ली एक्टको देख कर हुआ है तथा उसी एक्टके नियमोंका अधिकतर प्रयोग पहिले होता रहा है अब भी कानून दिवालियाके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका अर्थ लगाते समय चैम्बर्ली एक्टका सहारा लिया जाता है तथा अङ्गरेजी अदालतों द्वारा तय किये हुए फैसलोंका उल्लेख हार्दिकोंके जज अपनी सजवीजोंमें किया करते हैं। प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२० ई०) के लागू होनेसे पहिले प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९०७ ई० (एक्ट ३ सन १८०७ ई०) प्रचलित था। इससे पेशतर इस एक्टके स्थानमें जो नियम लागू थे उनका उल्लेख संग्रह जायता दीवानी (Code of Civil Procedure) में मिलता है अर्थात् संग्रह जायता दीवानीमें दिवालेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम मुकदिसलमें लागू थे। इस प्रकारके नियमोंका हवाला सबसे पहिले सन १८५६ ई० के संग्रह जायता दीवानीमें मिलता है इसके पश्चात् सन १८७३ ई० व १८७६ ई० के संग्रह जायता दीवानीमें भी ऐसे नियमोंका उल्लेख है। संग्रह जायता दीवानीमें जिन नियमोंका हवाला मिलता है उनका सम्बन्ध केवल उन कर्तव्यवाहोंसे है जो स्वयंकी वसुलीके सम्बन्धमें डिक्री हासिल कर चुके हैं तथा उन मजिस्ट्रेटोंका है जो गिरफ्तार हुए हों या जिनकी जायदाद कुर्क की गई हो। इस प्रकार उन नियमोंसे सब प्रकारके कर्तव्यवाहों के फर्जोंकी रक्षा नहीं हो सकती थी और न उनसे कर्तव्यवाहोंका ही पूर्ण बचाव था। उन नियमों को अपर्याप्त समझ कर तथा उनको संग्रहीत करनेके लिये एक्ट ३ सन १८०७ ई० (प्रान्तिक कानून दिवालिया १८०७ ई०) बनाया गया था जो पहिली जनवरी सन १८०८ ई० से लागू हुआ था। यह एक्ट सन १९१४ ई० में कुछ संशोधित किया गया था और लगभग १० साल तक इसका प्रयोग जारी रहा। इस दर्मियानमें बहुतसी न्यूनताएँ इस एक्टमें दिखलाई दीं जिनके दूर करनेके लिये भिन्न भिन्न अवसरों पर जजों वकीलों व व्यापारियों आदिने अपनी रायें प्रकट कीं। उन्होंने न्यूनताओंको दूर करनेके लिये प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १८२० ई० (एक्ट ५ सन १६२० ई०) बनाया गया इसके अनुसार धोड़ा देन वाले कर्तव्यवाहोंको उचित दण्ड दिया जासकता है। अदालत दिवालिया धोखा देने वाले दिवालियाके बहाल होनेमें रुकावट डाल सकती है तथा उससे रोक भी सकती है। इस कानूनमें अज्ञात दिवालियाके अधिकार जो उसे वाक्याती या कानूनी मसलोंको तय करनेके सम्बन्धमें हैं भली प्रकार दिखला दिये गये हैं। सरसरीमें सुने जाने वाले मामलोंको नियमबद्ध कर दिया गया है इसी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें बड़ा दीगई हैं तथा संशोधित कर दीगई हैं जो एक्ट ३ सन १८०७ ई० में नहीं थीं। इस एक्टमें भी सन १८२० ई० के बाद कुछ संशोधन हुए हैं जिनका हवाला संलेपमें दे दिया गया है। सन १८२६ ई० के संशोधनके अनुसार अर्थात् एक्ट ६ सन १८२६ के अनुसार प्रान्तिक कानून दिवालियाका प्रयोग कराची टाउन पर नहीं रहा है इससे पहिले यहीं एक्ट उस टाउनके लिये प्रयोग किया जाता था। अब प्रेसीडेन्सी टाउनस इन्सलवेन्सी एक्ट उस टाउन (Town) के लिये लागू है। इसी प्रकार संशोधनके अनुसार अदालत दिवालिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटके पास इस एक्टके अनुसार किये हुए जुर्माना इस्त-

भासा भेज सकती है पहिले वह स्वयं उन जुर्मोंकी सुनती थी और इधर भी बहुतसे संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दिया गया है ।

प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्ट (एक्ट ३ सन १६०६ ई०) केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई व मदरास), रंगून व कराचीके लिये लागू है इस एक्टसे पहिले इसके स्थान पर दि इण्डियन इन्साल्वेन्ट एक्ट सन १८४८ [Indian Insolvent Act 1848, (11 & 12 Vic. C. 21)] लागू था परन्तु वह एक्ट केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स व रंगूनके लिये लागू था । यह एक्ट अर्थात् एक्ट ३ सन १६०६ ई० भी केवल इन्हीं शहरोंके लिये लागू था । परन्तु सन १६२६ ई० के संशोधनके अनुसार इस एक्टका प्रयोग कराची शहरके लिये भी किया जाने लगा है । प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालियामें भी संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दे दिया गया है ।

जहां तक हो सका है इस पुस्तकमें कानून दिवालिया सम्बन्धी सभी बातों पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है । प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ४ सन १६२० ई०) अर्थात् पहिले भागके अन्तमें कुछ नमूने भी दे दिये हैं जिनके अनुसार दिवालियेकी कार्यवाईके सम्बन्धमें दूरवार्ते दी जा सकती हैं । नमूनोंके अतिरिक्त कानून दिवालियाके सम्बन्धमें बनाये हुए भिन्न भिन्न हाईकोर्टोंके नियम भी लिख दिये गये हैं । इस पुस्तकको पढ़ कर कर्जदार अधिक कर्ज हो जाने पर अपनी रक्षाका विधान कर सकता है तथा इसी प्रकार कर्जप्राप्त भी दिवालिया कर्जदार से अपना कर्ज वसूल करनेके तरीकोंका प्रयोग कर सकता है, धोखादेहीसे किये हुए सौदोंको रद्द करा सकता है, किसी कर्जदारको दिवालिया प्रारंभ दिला सकता है तथा भोखेबाज़ दिवालियों को अदालत द्वारा सज़ा दिया सकता है और उनको हमेशाके लिये दिवालियेके गहमें डकेल सकता है ।

आशा है कि पाठकगण इस पुस्तकको अपश्य अपनायेंगे जिससे लेखक व प्रकाशक अन्य कानूनी अर्थोंको भी इसी प्रकार उनके सम्मुख रखनेका प्रयत्न कर सकें । जो त्रुटियां पुस्तकमें रह गई हों पाठकगण उन्हें भी बतलाने की कृपा करें जिससे वह आनन्द सुधारी जा सकें ।

निवेदक:—

रूपकिशोर टण्डन

वृत्त	विषय	पेज
—	गोनमे दाम दिवाल्याके नाम नहीं है—१ ...	१३
—	कौतुबाने जब अपने महाजन या उसके पूजेन्तों यह सूचना दी हो कि मैं दिवाल्या हू	१३
—	जब मालधर्मो माल खरीद जाने और उसे बेच कर दूसरा बर्तन चुगाया गया हो	१३
—	जब कौतुबाने मञ्जर किया हो कि मुझे इतना कर्म देना है मगर इन वक्त सुगतान नहीं दे सकता है ...	१३
—	गोनमे काम दिवाल्याके काम हैं—१ ...	१४
—	जब कौतुबाने सब जायदाद दूसरे किसी को दे दी हो कि वह उसका सब कर्ज चुका देगा	१४
—	जब कौतुबाने दिवाल्या बननेकी अर्जी दी हो और चाहे वह अर्जी स्वीकृत भी हो गई हो	१४
—	जब कौतुबाने दरबान्ते देनेके तीन महीनेके अन्दर बर्जदारने यह प्रकट किया हो कि वह कर्ज नहीं चुका सकेगा	१४
—	दुखियोंके सुपुर्द जायदादना किया जाना ...	१४
—	जब कौतुबाने अपनी जायदाद इस इशारेमें हटा दे कि उसमें बर्जदारको लाभ न उठा सके	१४
—	एक बर्जदारको दूसरे बर्जदारके मुगलियों फायदा पहुँचाया हो	१५
—	दिवाल्या पर उस अदालतमें दरखास्त दिवाल्या-बनने में नहीं जायगी बल्कि वह इतना हो या धन्दा करता हो	१४
—	जब कौतुबाने अपनी जायदाद चला आवे, छिटा जावे, भग जावे या गिरफ्तार जाते चला जावे	१५
—	हस्ता, भागना, छिटना आदि इस मशरूफे हैं कि कौतुबाने कदा कदा मारपाके या देश बसूरतों में हैं ...	१५
—	कौतुबाने बर्जदारी, दिवाल्याके इन्कार किया हो और कोई बड़ा काम हटा दी हो	१५
—	जब बर्जदार नाम लाने और एक बर्जदार दूसरे को जाना कि वह इतना उस इशारेमें कर्ज ले	१५
—	पादरी अर्जी दिवाल्या बननेकी अगर रखिन हो जय तो दूसरी जर्जी दूसरी कोई हर्जी नहीं पड़ेगा	१५
—	किसी कायदा दिकरीमें कौतुबाने जायदाद बिनाजय तो माना जायगा कि वह दिवाल्याका काम है ..	१५
—	जब कौतुबाने तारबार हो और एक आदमीकी जायदाद दिकराने बिना तो दूसरे दिवाल्या दिवाल्या न माने जायगे	१५
—	जब कौतुबाने दिवाल्या बननेका अर्जी दी और वह नामञ्जर हो गया वही उरुन फिर दी तो यह काम दिवाल्या का काम समझा जासकता है	१५
—	कौतुबाने अपने किसी बर्जदारको जब नोटिससे उसने कर्जी देना बन्द कर दिया है	१५
—	एक शरीफदारके पैसा नोटिस देने पर कि वह कर्जा नहीं चुका सकता तो दूसरे शरीफदारों पर असर नहीं पड़ेगा	१५
—	बर्जदारके मुनाम या एजेन्ट का किया हुआ काम बर्जदारका किया हुआ काम समझा जायगा	१५
—	मुनीम या एजेन्ट का काम उभी वक्त मालिक को फायदा होगा जब उसने अपने अधिकारके अन्त काम किया हो	१५
७	दरखास्त और दिवाल्या करार दिया जाना ...	१५
—	कौतुबाने और बर्जदार दोनों को अवधार है कि दिवाल्या करार दिये जाने की अर्जी दे सके	१५
—	दिवाल्याके अर्जी देनेमें पहिले कोई न बाँटे काम दिवाल्याका जरूर होना चाहिये	१५
—	जब कौतुबाने दफ्तर १ और १० में उन जत्तों तक निकट कि उनका ध्यान अर्जी के समय रखना चाहिये	१५
—	जब कौतुबाने सिर्फ अर्ज बर्जदार पर अर्जी दे सकता है बर्जदारके वाजिब पर नहीं दे सकता	१५
—	जब बर्जदार की दिवाल्या बननेकी अर्जी दी गई हो और वह मर गया हो तो अर्जी स्वीकृत न जायगी	१५
८	समा आदिक दिवाल्या की कार्यवाहीसे बरी होना	१५
—	यजमान या समा या कम्पनीके सिर्फ दिवाल्या बनने की अर्जी नहीं दी जासकती	१५
—	एगोप्रेशन, कार्पोरेशन और कम्पनी का फायदा	१५

क्षम	विषय	पृष्ठ
—	—बिबी फर्मके खिलाफ दिवालिया अर्जी श्री जासखा इ १९	१९
—	—नावालिग, निवालिग करार भरी दिशा जासखा १९	१९
—	—शामिल शासक हिंदू कुटुम्बक जेब वालिग इहरमदार निवालिग बनाने गये हैं तो नावालिगकी जायदाद रिहीवर अपन कजम नहीं गेया १९	१९
६	कर्जद्वाराके दरखास्त देने की शर्तें १९	१९
—	—ऊपर दस्ता ६ में बताप हुए कामाम स कर्जदारने कोई एक काम छ कामक अदर किया हा ... २०	२०
—	—कर्जदारने याना अजा देने वात का कर्जी ५००) रुपयम कम न हो ... २०	२०
—	—कर्जदारने १० कर्जद्वाराक कजत २ कार १००० हा तो अदागत स दामदका तय कर द ॥ ... २०	२०
—	—पाइल जगलन गढ़ जाव करी कि कर्जदारने कज ५००) ६० या १००० है या नहीं ... २०	२०
—	—इज अमला हाना चाहिये और उसरी जिम्मेदार कर्जदार पर हाना चाहिये ... २०	२०
—	—नव कज किता सामिल कामक हिंदू गावरा पर ने ता अदरकालय कोई व्यापक इवाक्या बनाना जासकताह ... २०	२०
—	—कर्जद्वाराक लिय जन्मी नहा इ कि नह इवाक्याया हुकम हान तर कजगव न बना रहे ... २०, २१	२०, २१
—	—अगर कर्ज वसूल बनन लिय दावा किया जातुग हो तो भी उस कजक आधार पर दिवालियेका अजा दा जासखा २०	२०
—	—एक या बहु एक मिलकर कर्जद्वारा, कजदारकी दिवालिया बनानकी दरखास्त द सनते हैं .. २०	२०
—	—नव कजक पानके कई एक इकदार हैं ता उभेस एव दिवालिया बनाने की अर्जी नहीं द सनता .. २०	२०
—	—नवीनी तादाद खास आर नय का हुई तादाद हाना चाहिये २१	२१
—	—इजेका रजमका कर्जी १०० मानकर दिवालियेका अर्जी नहीं दा जासकता .. २१	२१
—	—कर्जद्वारा, दिवालियेक जस कामके आधार पर अर्जी दे वह काम अर्जी देनेकी तागिलस ३ मासके अदर हाना चाहिये २१	२१
—	—अगर अर्जी गजत अदालतमें दा गई हा तो सही अदालतमें अजा दनक लिय वह मियार नहीं मिलेगा ... २१	२१
—	—शर्तें खान या कजनी कर्जदारका दिवालिया बनानक लिय अर्जी द सकता इ ... २१	२१
—	—अर्जी दिवालियेके काम या कामा का पूरा निक होना चाहिये चलताऊ न हाना चाहिये ... २२	२२
—	—चाह दूसरे बहुतस काम दिवालियेक इवाक्य गय हैं अगर इस कजुनके एक भा न हो ता अर्जी नहीं चलगा ... २२	२२
—	—मइकून कर्जद्वारा भा दिवालिया बनानकी अजा द सकता है अगर च द शर्तोंक साथ ... २२	२२
१०	वद शर्तें जय कि कर्जदार दिवालिय की दरखास्त दे सकता है २२	२२
—	—प्रमाण सा खजने चाह वह इवाक्या कया इदा गय हा तो भायद १०० उगम लागू हाया ... २३	२३
—	—कर्जदार इवाक्या बननका अजा उस दशम दे सकता है जब वह कज अदा न कर सकता हा .. २३	२३
—	—१०० कजदारके कज ५००) स कम न हा और उकी वद अजा न कर सक्ता हा .. २३	२३
—	—नव कजदार किता डिफामें गिणवार हो गया हो आर इकरा का कजया अजा न कर सकता हो .. २३, २४	२३, २४
—	—नव डिफामें कजदारका जयदाद चुक हा गई हा आर वह अजा न कर सकता हा .. २३	२३
—	—कजदारकी एहा अजा नेक गायताम और मचा हना चाहिये नामापन फायदा उठानक ठिय न हा .. २३	२३
—	—कर्जदारका पावना, कर्जेस बादा हा ता अदालत दिवालिया नहा बनानकी २३	२३

दफा	विषय	पन्ना
—	जजदार जब गिफतार किया गया हा और छेड़ दिया गया हा ता वह दिवाणिया बननी अता नहीं दे सकता	२३
—	शाहिलदारीक पावनाम भाप आर दा लडकोंके हान पर दिवाणिया बननका प्रश्न	२४
११	वह अदालत अहा दिवाणिया की दरखास्तें दी जावें	२५
—	अनी दिवाणिया की वहा दी जायगी अहा पर जजदार उपादा तर रहता हो उस जगहका अदालतमें	२५
—	दिवाणिलयनी अजा वहा भी दा जायगा जहा कजदार व्यापार करता हो	२५
—	जहा पर कजदार गारफ्तार हुआ हो वहा का अदालत भा दिवाणियाका अनी दा जायगी	२५
—	नन कि गलत अदालतमें आग पेश की गई हा ता उअ बहुत अरद करना जरूर है	२५
१२	दरखास्तकी तस्दीक	२७
—	ज वहा दाव नीकी ताह दिवाणियाका अनी का भा तरदाक का जायगा	२७
१३	दरखास्तमें दिखताई आने वाली बातें	२७
—	उन कर्जदार कजारा जुगता न दे सकता हा तब वह दिवाणियाका अजा दे सकता है	२८
—	सय कजदक रखना बुराया जो कजदारक निम्न न का हा वह कजा समझा जायगा	२९
—	अनीम कजरावाहा ने नाम व उनका पना व कर्जा आद साफ साफ बताना चाहिये	२९
—	कर्जदारो अपनी सब जायदाद व लइना व प्रावाड ड फण आदि बताना चाहिये	२९
—	अनी देनक बाद दिवाणियाकी सब जायदाद रसमवरक सिधुर हा ताब ता	२९
—	मुदलखड लख एलमशा एकर व प्राविड ड फड एक्की जायदाद कूक व नालम न हो ही	२९
—	दिवाणिलयका दरखास्तके अने तान बात निहायन जरूरी है, स्थान, नाम, आर कर्ज	३०
१४	दरखास्तका वापिस लिया जाना	३०
—	अनी देनक बाद, फिर वाई बिना अदालतका आह्राके अनी वापिस नहीं ल सकता	३०
—	जब सब मामल तर हा गये हो तो भा अदालतकी अधिकार है कि अनी वापिस न देके	३०
१५	कई दरखास्तों देने में अदालतका अधिकार	३०
—	वह कर्जदारान दिवाणिया करार दनगी दरखास्तें दा हो तो वे सब साथही सुनी जावगी	३१
—	शामिल स। क। इ. दू आनदानके खिलफ उरी समय दिवाणिलयकी दरखानत दा जायगा जब शामिल श। क। उस प्रकारके काम हो	३१
१६	कार्रवाईका तर्न बदलनका अधिकार	३१
—	अदालतका अधिकार दूसरका बदलाह मान लेनका जब बसका तर्न का ५८०) २० स कम न हो	३१
—	कजरावाह दरखानत देने क बाद अगर इवा लिखे मिल जाव तो अदालतके अधिकार	३१
—	जब कर्जदारान अता देने के बाद परकी करना छड दिया हा	३१
१७	कर्जदारके मर जाने पर कार्रवाईका खाल रहना	३२
—	दिवाणिलयकी कार्रवाई खतम हुनस पहिल अगर कर्जदार मर जाव तो उसके लम्हे अपना हक नहीं प्राप्त करे	३२
—	कजदारक मर जान पर भा उस अदालत दिवाणिया करार द सुनता ह	३२

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१८१	१८१	१८१
१८२	१८२	१८२
१८३	१८३	१८३
१८४	१८४	१८४
१८५	१८५	१८५
१८६	१८६	१८६
१८७	१८७	१८७
१८८	१८८	१८८
१८९	१८९	१८९
१९०	१९०	१९०
१९१	१९१	१९१
१९२	१९२	१९२
१९३	१९३	१९३
१९४	१९४	१९४
१९५	१९५	१९५
१९६	१९६	१९६
१९७	१९७	१९७
१९८	१९८	१९८
१९९	१९९	१९९
२००	२००	२००
२०१	२०१	२०१
२०२	२०२	२०२
२०३	२०३	२०३
२०४	२०४	२०४
२०५	२०५	२०५
२०६	२०६	२०६
२०७	२०७	२०७
२०८	२०८	२०८
२०९	२०९	२०९
२१०	२१०	२१०
२११	२११	२११
२१२	२१२	२१२
२१३	२१३	२१३
२१४	२१४	२१४
२१५	२१५	२१५
२१६	२१६	२१६
२१७	२१७	२१७
२१८	२१८	२१८
२१९	२१९	२१९
२२०	२२०	२२०
२२१	२२१	२२१
२२२	२२२	२२२
२२३	२२३	२२३
२२४	२२४	२२४
२२५	२२५	२२५
२२६	२२६	२२६
२२७	२२७	२२७
२२८	२२८	२२८
२२९	२२९	२२९
२३०	२३०	२३०
२३१	२३१	२३१
२३२	२३२	२३२
२३३	२३३	२३३
२३४	२३४	२३४
२३५	२३५	२३५
२३६	२३६	२३६
२३७	२३७	२३७
२३८	२३८	२३८
२३९	२३९	२३९
२४०	२४०	२४०
२४१	२४१	२४१
२४२	२४२	२४२
२४३	२४३	२४३
२४४	२४४	२४४
२४५	२४५	२४५
२४६	२४६	२४६
२४७	२४७	२४७
२४८	२४८	२४८
२४९	२४९	२४९
२५०	२५०	२५०

दफा	विषय	पेज
—	अगर कर्मदारका लहना कर्जे ज्यादा हो तो भी कर्जा चुकानेकी अवसर्यता कही जासकेगी ...	४०
—	अदालत सरसरी जाय करेगी, पूरी तोरसे नामक जाय करने की जरूरत नहीं है ...	४०
—	अदालत, दिवालिया हो जायतुर्की कीमत कायदा पर ध्यान रखेगी और देनेकी कि उससे कर्जे चुकाये जायकेमे? ...	४०
—	कर्जे सही माने जायगे जब तक वे कर्जों न साबित हो जावें ...	४१
२५	दरखास्तका होना ...	४१
—	नायत दिवालियेकी उस समय देखी जायगी जब उसके पहाल होनेका हुक्म होने वाला हो ...	४१
—	दिवालिया अगर दते समय, दिवालियेकी नीयत क्या थी यह देखना जरूरी नहीं है ...	४१
—	जब अर्जों खारिज की जाय तो अदालत सब कारण हुक्ममें लिख देगी ...	४२
—	दिवालियाकी अर्जों सिन सिन कारणोंमे खारिज हो जायगी ई उनका खोरा ...	४२
—	दिवालियेकी अर्जों देनेके बाद जब कर्तदारने किसीको मर्यादा चुकाया हो तो हर्जा नहीं पड़ सकता ...	४३
२६	हज्जेका मिलना ...	४३
—	कर्जदारका दावा ही हुई अर्जों खारिज हो जाने पर (१०००) रु० तक हरना कर्जदारको मिल सकता है ...	४४
—	हार्ड रोड में इस दफ्तारी अंगीकृत करेगी ...	४४
२७	दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म ...	४४
—	अगर दरखास्त दिवालिया खारिज न हो तो अदालत जरूर दिवालिया करार देगी ...	४४
—	मोहूरतर्फी अर्जों दो जासगी है कि तारीख आगे बढ़ा दी जाय ...	४५
—	अदालतका कर्तव्य है कि दिवालिया करार देने पर पहाल होनेकी तारीख जरूर बना देने ...	४५
२८	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका अखर ...	४५
—	दिवालिया करार दिये जाने पर उज्जदार सब बजोसे मुक्त हो जाता है अगर जेलमे नहीं होता ...	४५
—	सब जायदाद कर्जदारकी रिसीवरके जिम्मे पूरी तोरसे हो जायगी और उसमें कर्जा भरा जायगा ...	४६
—	कोई छद्मदार कुछ भी कार्रवाई न कर सकेगा ...	४६
—	हिस्ती कर्मके दिवालिया करार देने पर उस कर्मके सब साक्षीदार दिवालिया माने जायगे ...	४६
—	दिवालियाका हुक्म होने पर टिकीदार कर्जदारको अदालतकी इनायतसे भिरकना व वेद रंग सकता है ...	४७
—	सामिलदगी कि दु कुटुम्बके बालिय मॅम्बरोंके दिवालिया होने पर उनके हक रिसीवरको प्राप्त हो जाने हैं ...	४७
—	दिवालिया बन जाने पर कर्जदार किसी महानको कपया नहीं दे सकता रिसीवर दे सकता है ...	४७
—	जन किसी कर्मके कुछ हिस्सेदार दिवालिया हों तो रिसीवरको यह हक नहीं है कि उस कर्म का जायदाद पर अनेके सबकी तरफसे कब्जा करे ...	४७
—	मिताधारार्थ के दि० पूरिवारके पिताके दिवालिया होने पर उसके लडकों की जायदाद भी बाबन्द होती है और रिसीवरके कब्जेमे दी जा सकती है ...	४८
—	शामिलदगी कुटुम्बके मेनेजरके दिवालिया होनेकी सूखनेमें रिसीवरके हक व अधिकार ...	४८
—	मालखानाके दिवालिया होने पर उसकी सारी जमीन रिसीवरके कब्जेमे जावेगी अगर मौसली कायद नहीं जावेगी ...	४८
—	हरामी या रेलवे प्रावोडेड कब्जकी रकम पर दिवालिया ना कोई अखर नहीं पड़ता ...	४८/४९

दण	विषय	पंज
—	आपस देनेकी एवढे अवकाश दयावता दावा हो सका है	१८
—	चर दिवा लेने आने कहींको बिभी दूधको दे दिया हो तो हम पर सिरेवरता हक नहीं रहा	४१
—	द्वार अगर दिवाले घने किमी दूर दे दिये हो और दफ्ताराना न किया हा तो दे दिवालेके नमस्त जदिये	४१
—	दिवाले का देनेके बाद वज्रदारकी अमदनी या नमस्तारके सिवा दिग्गको सिरेवर ने सवना है	४२
—	जा जादर कानूनमे कुर्क नहीं हो सवनी वद दिवालेके भी न होगी	४२
—	मुद्राखण्डमे जगजग देका हानो की अमदनी कुर्क नहीं हो सवनी तो हम कानूनमे भी न होगी	४२
—	मृज वज्रदार पर हम दफतार अदर नहीं पटना वद अपना रररा दफ्तार वर सवना है	४२
—	अन्ता दिवा जग की हानिमे दिवालेका माना जाइगा	४३

२६	बाद कारवाइयो का मेका जाना	४२
—	जिनकी अदायेमे कोई मामला दिवालेका पर या दिवालेकी तरफमे दफ्तार होगा सब वद हो जदिये	४०
—	वज्रदार अगर दाह तो अपना माना दाह आ रहा सवना है	४०
—	वद वरदाममे लक्ष्मीर या अदिकत सिरेवर फाँक मुकदमा बनाया जाना देवे	४०
—	दफ्तारकी आपदारके खीरको सब हक सगे दी हुई वामदामे न पेश होना	४०
—	दफ्तार दिवालेका कर्तार है उमकन न वद होनी उवादकारमान अर्वा दी होमगर कतर न दिया गया हो	४१

२७	दिवालिया करार देने वालें हुक्मकी मुदतदारी	४१
—	दिवालेका करार दिये जाने पर तरफकी चमकेमे वाम, वना, देहा, मवाशि जिया जाइगा	४१

दिवालिया करार दिये जानेके बादको कारवाइ

२८	दिवालेकी दाका हुक्म	४१
—	पाइके कानूनमे दिवालेका कग देने हो वज्रदार जेलखानेमे बने हो जग वा पर अब नहीं होना	४२
—	वज्रदारको जेलमे बचनेके लिये दुपग अर्वा विपारके अदर देना सवनी है	४२
—	जब तक वज्रदार दिवालेका कग न दिया जाय तब तक जेलमे हुक्मकी अर्वा नहीं दे सवना	४२
—	अदालत मजदूर को है कि वज्रदारको जेलखानेमे बचनेका हुक्म जलर दी दे दे	४२
—	वेदभरती को पूरा हक है कि वज्रदारको जेलमे हुक्मकी अर्वा देने की अर्वा पर उम करे, सुदूर है	४२
—	मरकासी वज्रको लिये जेलमे सुकना वज्रदपका हानि नहीं होगी	४३

२९	दिवालिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार	४२
—	दिवालेका करार देनेके बाद अदर जेलमे रशक हुक्म देनेमे चलेने अदालत वज्रदरकी गिरफ्तार कर सवनी है	४३
—	अदालतको अधिकार है कि वज्रदारको ३ मग जेलमे रसे	४३

३०	कर्तारजाहकी सूची	४३
—	जेलखानेका अन्ता वज्र को सवनी वर सवनी जब दिवालेका हुक्म हो जाय	४४
—	वज्रदारकी सूची तय्य करेना अदालतका कर्तार है	४४
—	सूची वज्रदारको को कग पेश होगी जदिये कग सिखा जायगा, वद वज्रकी, वाम वज्रदेशा है	४४

दफा	विषय	पृष्ठ
—	अगर किसी का कोई कर्ज साबित करनेसे छूट गया हो तो वह भी सचिवन किया जा सकता है ...	५४
—	सब कर्ज कर्जदारके बहाल (जल्दसे छूटने) होने तक सूचीमें दर्ज हो जाना चाहिये ...	५४
—	अगर कोई जमानदार दूसरे लहेनदारका कर्ज भन्त भगाय तो अज्ञात इस मामलेको तय कर देगी ...	५४
—	अगर कोई कर्जम्बाह मर जाये तो उसके वारिसों को नोटिस दिया जाना चाहिये ...	५५
३४	यह कर्ज जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जा सकते हैं ...	५५
—	वे कर्ज नहीं दिलाये जायग जिनकी कीमत वा अमाना अदाकत नहीं लगा सकती ...	५६
—	लहेनदारोंके कर्जें नहीं माने जायगे जो जलसे छुटता पानेसे पहिले साबित कर दिये गये हों ...	५६

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

३५	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अधिकृतपाद ...	५६
—	जब अदालतकी सभमें दिवालिया करार न दिया जाना चाहिये ...	५७
—	जब सब कर्जें पूरे पूरे बहालन लेहनदारों को चुका दिये जायें ...	५७
—	दिवालिया करार देनेके हुक्मकी ममूखी की दस्तावेज कर्जदार खुद भी दे सकता है ...	५७
—	अगर कर्जदारने लेहनदारोंको बांधाई अदि कर्जों चुकाना मजूर किया हो तो हुक्म मसूब न होगा ...	५७
—	कर्जदारके कर्जें दूसरा आदर्श भी अदा कर सकता है, यह जरूरी नहीं है कि कर्जदार ही अदा करे ...	५८
३६	एक साथ दिये हुए दो दिवालियोंके हुक्मकी मंजूरी करनेका अधिकार ...	५८
—	जब दूसरी अदालतमें दिवालियोंकी कार्रवाई चलती हो तो एक अदालत बन्द कर देगी ...	५८
—	कर्जदारके कर्जोंके बटनमें जहासे सद्बिचय हो वहा पर कार्रवाई होना चाहिये ...	५८
३७	मंजूरीके याचकी कार्रवाई ...	५९
—	कर्जदारको समझी जायदाद का वापिस मिल जायेगी ...	५९
—	बहालकी दस्तावेज न देने पर दिवालियोंके हुक्मकी ममूखी होना ...	५९
—	ममूखीके हुक्म कार्रवाई गमरेमें प्रकाशित किया जायगा ...	६०

तस्फीया तथा तय करनेका तरीका

३८	तस्फीया तथा तय करनेका तरीका ...	६०
—	कर्जदार अपने लेहनदारोंसे तस्फीया कर सकता है कि वे कम कमाय लेकर पूरे कर्जोंकी भुगतान कर दें ...	६१
—	कर्जदारों की माहितीकी जायगी और जो तीन चौथाईतय कम न हों या उनके प्रतिनिधि हों ...	६१
—	जिस कर्जदारकी सूचना न मिली हो वह माहितीकी कार्रवाईका पाबन्द न होगा ...	६१
—	कर्जदारोंकी माहितीमें वही शरीफ होंगे कि जिनक कर्जें सूचीमें दर्ज हो चुके हैं ...	६१
—	कर्जदारने जब रिहाइते जियाकर किसी लेहनदारको रुपया दिया हो तो क्या फल होगा ...	६२
३९	मंजूर करने पर हुक्म ...	६२
—	तमकालमें कार्रवाई कर्जें कर्जदारों पर जाएंगे होगी जिनका कर्ज सूचीमें दर्ज हो चुका है ...	६२

वक्र	विषय	पेज
४०	कर्जदारको फिर दिवालिया करार देनेका अधिकार	६२
	—समझौतेके सुताविक विस्तरी अदायगी ठीक तौर पर न हो या घोस दिया गया हो	६३
बहाल होना (जेलखानेसे छुटकारा पाना)		
४१	बहाल होना	६३
	—किसी मियाद तक अदालत बहाल होनेका हुक्म मुलमली कर सकती है	६४
	—जेलखानेसे रखाका हुक्म अदालत बहुत सोच समझ कर देगी	६४
	—अदालत बहाल होनेमें शर्तें लगा सकती है जिससे कर्जदारका आमदनी, आगे भी लड़नेदारोंका दावा जाय	६४
४२	पूर्ण रूपसे बहाल होनेका हुक्म अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण	६४
	—जब लड़नेमें आधा बर्ज भी न सुनाया जासकता हो	६५
	—हिस्सा इतना कर्जदार ने न रखा हो या ठीक न रखा हो	६५
	—रिहीनमें कर्जदारके व्यवहार, खाल चलन आदिक बारेमें खराब रिपोर्ट दी हो	६५
४३	बहालकी दरखास्त दिये जाने पर दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी संसूची	६६
	—कर्जद्वारा इजाजत लेकर इस हुक्मकी अपील कर सकता है	६७
४४	बहाल होनेके हुक्मका असर	६७
	—बहाल होनेसे कर्जदार उन सब बजोसे छूट जावेगा जो सूचीमें दर्ज हो चुके होंगे	६८

तीसरा प्रकरण

कर्जोंके साधित करनेका तरीका (जायदादका प्रबन्ध)

४५	आइन्दा अदा होने वाले कर्ज	६९
	—जब कोई बर्ज आयन्दा वाग्विजल अदा हो तो वह पहिले ही हाविन हो जायगा	६९
४६	आपसका ब्योहार से मुजरार	६९
	—अगर दिवालिया और महाजन दोनोंम एकदूमेसे लेना देना हो तो मुजरार होकर रकम निश्चित न होगी	७०
	—हिस्सा होनेके बाद रकमकी मुजरार होगी, पहिले नहीं	७०
	—दोनोंके हिस्सा प्रस्ता देने पर जिसके किये बाकी निचले वह उस रकमका देनदार होगा	७०
४७	महफूज कर्जद्वारा	७०
	—जब किसी चीज की जमानत पर बंधा दिया गया हो तो वह बंधा पूरा मिलेगा	७१
	—जब कि कुछ बंधा जमानत पर हो कुछ न हो तो बंधा हालत होगी	७१
	—जमानतमें ज्यादा बंधा जब लड़ना निश्चय हो तो साधित करना होगा	७१
	—महफूज कर्जदार जमानत ठीक तौर पर दे, उसकी हानि पर निर्भर है	७१

क्रमा	विषय	पेज
४८ सूद (ब्याज)	...	७१
—जब सूद की दर ठहरी न हो तो	६) रुपया सेवक सालाना की दरसे सूद लगाया जायगा	७२
—सूद, दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मना तारीख तक दिलाया जायगा	...	७२
—पहिले सूद तय न हुआ हो पीछे नोटिस दी गई हो तो नोटिस लिखी हुई होना चाहिये	...	७२
—परफूट करीबना सूद, कर्जा वसूल होनेकी तारीख तक मिल सकेगा	...	७२
४९ साबित करनेका तरीका	...	७२
—कर्जा किस प्रकार साबित करना चाहिये उसका तरीका	...	७३
—जैसे दूसरे कहे साबित किये जाते हैं वैसे यह भी होंगे	...	७३
—इच्छानामोंके द्वारा कर्जोंका तफ्तील आदि दाखिल करके कर्जा साबित हो सकता है	...	७३
—वह कागजात या बहोखाता पेश होंगे जिनसे कर्जा साबित होता हो	...	७३
५० सूचीके इन्तख़ाबको नामंजूर करना या घटाना	...	७३
—अदालतका अधिवार है कि सूचीके कर्जों को हटा सके, बदल सके आदि	...	७३

पहिले किये हुए सौदों या कार्रवाईयों पर दिवालिया असर

५१ इजरायमें कर्तव्याधानके हकमें रुकाव	...	७४
—दिवालियेकी अर्जों देनेके बाद उसकी जायदाद एक आदमी दीनार न करा सकेगा	...	७४
—दीनार चाहे हो गया हो मगर रुपया चाहेमें वसूल होगा तो वह रसीदकरना होगा	...	७५
—जसदातल ३ रुपया दे दिया पीछे दिवालियाकी अर्ज दी गई तो सब रुपया रसीदके बख्तेमें गया	...	७५
—रुपया कर्तव्याहकी मिलनेसे पहिले यदि दिवालियेकी अर्ज दी गई हो तो वह रुपया रसीदकरना है	...	७५
—जब खसदार्को यह न मालूम हो कि वह दिवालियाकी जायदाद है और बेकसीयतीसे ले ली हो	...	७५
५२ जायदादके खिलाफ डिक्री इजराय करमें अदालतके कर्तव्य	...	७५
—दिवालियाकी जायदादसे सब कर्तव्याहोंको लाभ पहुंचानेका बख्ते	...	७७
—अदालतको नोटिस मिलना तब तक जायदादको, जब दीनार किया जाना	...	७७
५३ अपने आप किये हुए सौदोंकी मंजूरी	...	७८
—दिवालियेके पहिलेके इन्तकायात्र कब किस दशामें मसूम हो सकेंगे	...	७८
—अदालतके अधिकारसे बाहरनी जायदादका इन्तकाल भी मसूम हो सकता है	...	७९
—गैर, जैसे, किस तरहके व रिम इन्तकाल मसूम होंगे	...	७९
—दो सालके अंदर किये हुए इन्तकाठ ही रहें हो सकेंगे	...	८०
—दो सालके भिदाद अर्जों देनेकी तारीखसे न ली जायगी बल्कि हुक्ममें ली जायगी	...	८०
—कोई भी इन्तकाल उसी समय मसूम होगा जब दिवालियाकी कार्रवाई चलती हो	...	८१
—रसीदोंर किसी इन्तकालके प्रत्येक तय नहीं कर सकता	...	८१
—इन्तकाल मसूम की कार्रवाई उससे तोरसे नहीं की जायगी	...	८१

पृष्ठ	विषय	पेज
५४	कुछ मामलों की की हुई तरजीह की मंजूरी	८२
	—दिवालिया करार दिये जान बाल हुसमना असर पिछर सौदों पर क्या पड़ता है	८२
	—तीन महानेके सौदों पर असर पड़ता है इससे पहिलेके सौदों पर नहीं पड़ता	८२
	—वह कौनसे सौदे हैं जिन पर दिवालियाका असर पड़ता है	८२
	—कौन सातोंके पदा हानि पर छोड़े रह दा जावेग	८२
	—सौदोंके सम्बन्धमें दिवालिये की इजाजी जान करना जरूरी है	८३
	—सौदोंका मसूदा की अर्जी दिवालियाकी कार्रवाई खतम होनेसे पाहल दा जायगी	८३
	—कौन सौदे फव नहीं मसूदा समझ जावेग	८४
	—जब दबाव या धारी या आगते कोई सौदा किया गया हो उसका असर	८४
	—जब कोई वाम पदा दिया गया है जिसमें एक ज़ादमीने लाभ होना हो दूसरको नहीं	८५
	—कर्मदारने जब न लिखत बचने और दशा फिर नेके छिये जायदाद देहन कर दी हो	८५
	—गिठल कर्जें और कुछ रुपये दूसर दानाके बदल जब जायदाद देहन कराई गई है	८६
	—नालपस जायदाद बचानका मतलब जब जायदाद देहन कर दी गई हो	८६
	—कर्मदारने मित्री कथा याद बिना सारमें दिया है तो वह उसे बचपस वासवेगा	८६
	—कलेक्टरके कपरा खर्चके लिये जिस इजाजत पहिल जमा कर लिया जायगी	८६
	—सातोंके बारेमें सत्यता परावर्त नहीं होगी बका जलब की जायगी	८७
५४ (५)	मंजूरीकी दरखास्त कौन लोग दे सकते हैं	८७
	—सौदों की मसूदा कार्रवाई अर्जी कौन ९ लोग दिये तथा परिणाम	८७
५४	नकलीपतीले किये हुए सौदों की रक्षा	८८
	—कौन सौदे इस कानूनके अनुसार रह नहीं गिय जायगे	८९
	—कैसे जोर कर वे सौदे रह न होंगे	८९

जायदादका बसूल करना

५६	रिसीदकी नियुक्ति	८९
	—दिवालिया की कार्रवाईके तैयारीमें अदालत रिसीदके नियम उसकी सब जायदाद दे दर्ती है	९०
	—रसायनक बचमें जायदादका हाना, अदालतक बचमें होना माना जायगा	९१
	—अदालतको अधिकार है कि किसी आदमी की भी रिसीद नियुक्त कर दे	९१
	—किसी कर्मध्याइका, दिवालियाकी जायदाद पर रिसीद नियुक्त न करना चाहिये	९१
	—जहा तक हो सम्मता बातोंके जानन बाला ही आदमी रिसीद नियुक्त किया जाय	९१
	—रसायनको अदालत न मानना चाहिये, वह अदालतका अधिकार मान है	९१
	—दुबानीके मामलेमें नियुक्त किये हुए रिसीद और दिवालियाक रिसीदका अधिकारमें फरक है	९१
	—रिसादर द्वारा बची हुई जायदादके परीक्षणको, कब हानि होगी और कब नहीं	९२
	—रिसादरमें अदालत जमानन से सखी है जिसमें दाखिल क्या सखी है	९२

दफा	विषय	पेज
—रिसेवरकी फीस, कमीशन, तनखाह अदालत तय कर सकनी है	...	१२
—दिवालियारा अर्जी खातिज ओ हो जावे तो भी रिसेवरकी वह फीस मिलेगी जो अदालतने तय की हो	...	१२
—बन्धनमें ५) सैकड़ासे ज्यादा रिसेवरकी नहीं मिलता	...	१३
—रिसेवरके अधिकार, वर्तव्य, जायदाद पर कब्जा आदिमा होना	...	१३
—खराद काम करने पर रिसेवरको अदालत सजा दे सकती है	...	१३
५७ सरकारी रिसेवरको नियुक्त करनेके अधिकार	...	१४
—आफिशियल रिसेवर बन, कैसे किस दशामें नियत किया जावेगा	...	१५
—अधिकार, वर्तव्य, जायदाद पर कब्जा लेना, उसकी फीस आदि	...	१५
५८ अदालतके अधिकार जय कि रिसेवर नियुक्त न किया गया हो	...	१५
५९ रिसेवरके कर्तव्य व अधिकार	...	१६
—रिसेवर मुकदम करेगा सबन, अधिकार, वर्तव्य, ओहदेस वर्धन	...	१७
—जायदाद बेचना, समझौता करना, इन्तजाम करना, कर्जो वसूल करना, और नाकियों करना	...	१८
—रिसेवर मुकदमामें, रिसे कर्जदार पर दावा कर सकता है	...	१९
६१ (ए) दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्यास्त करनेके अधिकार	...	१००
—गैर आदिमियोंके बन्धे की जायदाद, दस्तावेजात, बागजान आदिमा तलब करना	...	१०१
—जब कोई शरय, तलब किया गया हो, न आवे या वह चीज शामिल न कर तो वाण्ट जारी होगा	...	१०१
—जिस इस मतलबके लिये तलब दिया जायगा उर्जो दिया जायगा	...	१०१
६० गैर मनकूला जायदादके लिये खास नियम	...	१०१
—मरकारि टैक्स देने वाली जायदाद या जमीन वास्तवी रिसेवर नहीं बेंच सकता है	...	१०२
—अदालत तीन महीनेका पहिले निर्णय करेगी	...	१०२
—कलक्टरके द्वारा चीज जायदाद किस कयदसे बेची जायगी	...	१०३
—जब कि डिकरी किसी मुआहिदेके अनुसार नहीं दी गई है	...	१०३
—डिकरीदारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादमा दावा करते हैं	...	१०३
—डिकरीका पना खाना निश्चित करना और जायदाद गैरमनकूला मुहैया करना	...	१०३
—जब जिले की अदालतने नोटिस जारी कर दिया हो	...	१०४
—अदालतमा फैसला करकेनके बीच एक प्रकयकी डिकरी समझा जायगा	...	१०४
—कयया वसूलका तरीका और बिचार जायदादको सुरक्षित रखत हुए	...	१०४
—कलक्टरकी हिसाब देनेकी जिम्मेदारी अदालतकी	...	१०५
—जायदाद बेचनेका तरीका और सहायक तथा लाभ का ख्याल	...	१०६

तकसीम जायदाद

६१	कर्जोंका पेयतर चुकाया जाना	१०७
----	----------------------------	-----	-----	-----	-----

धारा	विषय	पेज
—	—दिवालयिके रीतों व जै पहिले चुकाने जायगे उसका वर्णन ...	१०७
—	—समाप्त न जाँ और उसके बाद २०) से कम कर्मचारियोंका व तें वास्ते चुकाना जायगा ...	१०७
—	—कौन कर्ज पूरे चुकाने जायगे और कौन कर्जोंमें हिस्सा रखना दिया जायगा . .	१०८
—	—यहाँ जा वसूल्दारोंमें पड़े हों कष्ट जिये जायगे तथा सूद या बुझाया जायगा ...	१०८
६२	डिवीडेण्ड, हिस्सा रखदीका लगाया जाना ...	१०८
—	—कौन कर्जोंमें हिस्सा रखदी कय्या बाण जायगा, तर्फीका, कर्तव्य और अधिकार ...	१०९
६३	डिवीडेण्ड आहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्जख्याहने कर्ज साधित नहीं किया है उसके हक ...	१०९
—	—जब लहनदारने, कय्या तबसीय करनेके बाद अपना कर्ज साधित किया हो तो उसे कुछ न मिलेगा ...	१०९
—	—जब लहनदारने, पहिले कय्या तबसीय होनेके बाद कर्ज साधित किया हो तो दूसरे बार उसे कय्या मिलेगा ...	१०९
—	—अगर लहनदारने देखे अपना कर्ज साधित किया तो उसका हक पाया नहीं जायगा ...	११०
६४	आखिरी डिवीडेण्ड ...	११०
—	—रिसीवरका कर्ज नोटिस देनेका उन लोगोंके विनय कर्ज साधित नहीं हुआ ...	१११
—	—आखिरी कय्या उन सबोंमें बाँटा जायगा जो पहलेके समय कर्जखानोंकी सूचीमें दर्ज हो चुके हैं ...	१११
६५	डिवीडेण्डके लिये कोई शर्त नहीं हो सकती ...	१११
—	—अगर रिसीवर कय्या न दे और उसका नाम सूचीमें हो तो उसे अर्ज देने पर शर्त मिल जायगा ...	१११
६६	दिवालयिके द्वारा इन्तज़ाम और उसका मत्ता ...	१११
—	—कलेक्टर दिवालयिके भा उसकी जायदादका शब्द सुपुर्दे किया जायकना है ...	११२
—	—जो काम बार चलता हो उसे इदालिया कायम रख सकता है और प्रबंध कर सकता है ...	११२
—	—दिवालयिके प्रबंधते जो कय्या जमा होया या लाभ होया सब कलेक्टरोंके बाँटा जायगा ...	११२
—	—दिवालयिके तनखा, या कमीशन अगलत दिशा नहीं है ...	११२
६७	यचे हुए दिवालयिके अधिकार ...	११२
—	—पूरा कर्ज, सूद, सबे सुधारे जायके बाद जो कुछ बचे वह दिवालयिके भिन्न जायगा ...	११२
६७ (घ)	जांचकी कमेटी ...	११३
—	—रिसीवरके कामों को जांचके लिये अगलत एक कमेटी नियत कर सकता है, व अधिकार ...	११३

रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

६८	रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील ...	११४
—	—रिसीवरके बिना नाम या हुक्मसे किसीको हाजि पढ़ावो हो वह उसकी अगलत अदालतमें कर सकता है ...	११४
—	—अपील नोटिस दिन सूचीमें अपील का सकता है ...	११४

दफा	विषय	पेज
—	अपीलकी मियाद २१ दिनों की है इसके बाद रिस्तिनरके किसी काम या हुक्मकी अपील न होगी	११४
—	अदालतके हुक्मकी भी अपील दूसरी अदालतमें की जासकती है	११५
—	अगर किसीने २१ दिनोंके अन्दर अपील न की हो तो वह दीवानोंमें दावा दापर कर सकता है	११५
—	रिस्तिनर यदि किसीका बर्जो मजबू न करे तो वह अदालतमें अपील कर सकता है	११५
—	रिस्तिनर अगर दूसरे आदमी को जायदाद, दिवालिखारी जायदाद समझ कर ले लेवे	११६
—	दूसरे आदमी की जायदाद पर अगर रिस्तिनर क़आ कर लेवे	११६
—	इस दफाके अनुसार अपील करने पर उसे अलग दावा, दीवानोंमें दापर करनेका हक़ नहीं रहेगा	११६

चौथा प्रकरण

दण्ड (सज़ा)

६९	दिवालियेके जुर्म	११८
—	क्रायदेके अनुसार काम न करने पर जो बर्जो है वे इस दफामें बताने में है	११९
—	दिवालिखाने जान बूझ पर जायदाद पर क़आ रिस्तिनरको न दिया हो या काम न किया हो	११९
—	जब कि बर्जोद्वारे धोखाधेने की नियतसे काम किया हो	११९
७०	दफा ६९ का जुर्म लगाने पर कार्रवाई	१२०
—	जब दफा ६९ के जुर्म दिवालिखाने किये हों तो मजिस्ट्रेटके पास मुकदमा भेजा जायगा	१२१
७१	बहाल होने या तस्फीया हो जानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी	१२२
—	दिवालिखेकी अर्जी मजबू होने पर और बहाल होने पर भी वह सज़ा पायेगा अगर जुर्म दफा ६९ के हों	१२२
७२	बिलाय बहाल किया हुआ दिवालिखा अगर कर्ज लेवे	१२३
—	दिवालिखे ५० के बग़ावत बर्जो किया हो याद कि वह बहाल नहीं हुआ तो जुर्म है	१२३
—	ऐसा दशमें दिवालिखा कौनदारी सिपुर्द निया जायगा और सज़ा होगी	१२४
७३	दिवालिखेकी असुविधायें (रुकावटें)	१२४
—	कौन्सिलका मेम्बर नहीं हो सकता जब तक कि बहाल न हो गया हो-	१२५
—	नावालिखकी जायदादका बर्जो नहीं हो सकता, हो तो हथिया जायगा	१२५

पाँचवां प्रकरण

सरसरी कार्रवाई

७४	सरसरी कार्रवाई	१२६
—	छोटे २ मामले जल्द फैसल कर दिने जायेंगे ताकि दिवत न बढने पावे	१२६
—	५०० से कम कीमतमें जायदादके सम्बन्धमें ही सरसरी कार्रवाई की जासकेगी	१२७

दफा

विषय

पेज

छठवां प्रकरण

अपील

७५ अपीलें	१२८
—दिवाणिया अदालतके हुक्मकी अपीलें जिनकी अदालतमें सब हो सकती है	१२८
—जलदकी अदालतकी नियमनी हार्डकोर्टमें होगी जो शिड्यूल १ में बताई गई है	१२८
—जायदादीदानी की दफा १०० के अनुसार हार्डकोर्टमें अपीलें, व मापलोंकी निर्णयें	१९९, १३०, १३१

सातवां प्रकरण

विविध सुतफारिक

७६ खर्चा	१३४
—दिवाणियेकी जेज्जानिमें रखनका खर्चा दिहना अदालत पर निर्भर है	१३४
—दीवानी अदालतमें जिकीरकी खर्चा देना पड़ता है मगर दिवाणियामें नहीं देना पड़ेगा	१३४
७७ अदालतमें एक दूसरेको मदद देवैगी	१३४
—एक अदालत, दूसरी अदालतकी दिवाणियेके काम करनेका लिख सकती है	१३५
७८ मियाद	१३५
—अपील करनेकी मियादमें कानून मियादकी दफा ५११२ लागू होगी	१३५
७९ नियम बनानेके अधिकार	१३७
—भारत सरकारकी आज्ञासे कलकत्ता हार्डकोर्ट और स्वामी सरकारकी आज्ञासे अन्य हार्डकोर्ट नियम बना सकते हैं	१३७
८० सरकारी रिखीवरको अधिकारोंका दिया जाना	१३९
८१ प्रान्तिक सरकार द्वारा कुछ नियमोंका प्रयोग कुछ अदालतके लिये रोका जाना	१४०
८२ बचत (Savings)	१४०
८३ मंजूरी	१४१

सूची (शिड्यूल) और हार्डकोर्टोंके बनाये रूल्स

सूची नं० १ वह फैसले व हुक्म जिनकी अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हार्डकोर्ट में हो सकती है	१४२
सूची नं० २ ऐक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोका जासकता है	१४३
सूची नं० ३ यह सूची रिपीलिंग ऐक्ट सन् १६२७ ई के द्वारा हटा दी गई है	१४३

दफा

विषय

पेज

कलकत्ता हाईकोर्ट रुल्स

कलकत्ता हाईकोर्टके बनाये हुए नियम कानून दिवालियाके सम्बन्धमें	१४४
—बायदे दिवालियाकी अर्जीस लेकर अन्त तककी कार्यवाईके सम्बन्ध तक	१४४
—रिहीवरकी नियुक्ति, अधिवार, कर्तव्य और अन्य सब बातोंका वर्णन	१४५
—कजोके साबित किये जानेके सम्बन्धमें पूरी कार्यवाईका किया जाना	१४६
—दिवालियेकी योग्यताकूला जायदादका बेचा जाना	१४७
—हिस्सा रसदोश दिया जाना और अन्य बातें	१४७
—सरसरी कार्यवाई किन किन मामलोंमें कैसी की जावेगी	१४८
—नमूना, कर्जदार दिवालियाकी दारखास्त का (अर्जी)	१४८
—दिवालियाकी दारखास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जत्वाहोंको दिया जायगा	१४९
—दिवालिया कुरार दिये जानेका हुक्म	१५०
—नमूना उस कर्जदारकी दारखास्तका, नोटिस जिसका नाम सूचीमें दर्ज नहीं है	१५०
—दिवालिया कुरार दिये जाने वाले हुक्ममें मसूखोंका हुक्म	१५१
—तस्दीया या हुप करनेकी रसीम पर चौर करनेके लिये जो तारीख हो उसकी सूचना देना	१५१
—उन कर्जत्वाहों की फहरिस्त जो तरकीया या तय करते समय रसीममें शामिल हों	१५२
—रसदवाहोंकी बहाल होनेकी दारखास्तकी सुचना	१५२
—आददा होने वाली आमदनी या मिशने वाली जायदादमें चौर पर बहाल होनेका हुक्म	१५३
—कजो साबित किये जानेका आम तरीका	१५३
—रिहीवरकी नियुक्ति का हुक्म	१५४
—अन्तिम हिस्सा रसदी बाटनेका नोटिस जो कर्जत्वाहोंको दिया जायगा	१५४
—कर्जत्वाहोंकी सरसरी कार्यवाईका नोटिस	१५५

इलाहाबाद हाईकोर्ट रुल्स

इलाहाबाद हाईकोर्टके बनाये हुए नियम कानून दिवालियाके सम्बन्धमें	१५६
—बायदे दिवालियाकी अर्जीस लेकर अन्तिम कार्यवाईके सम्बन्ध तक	१५६
—रिहीवरकी नियुक्ति, अधिवार, कर्तव्य, और अन्य सब बातोंका वर्णन	१५७
—कजोके साबित किये जानेके सम्बन्धमें पूरी कार्यवाईका किया जाना	१५८
—दारखास्त व नोटिस	१५७
—दिवालियेकी योग्यताकूला जायदादका बेचा जाना	१५७
—सरसरी कार्यवाई किन किन मामलोंमें कैसी की जायगी	१५८
—नमूना—नतरल टाइटल का लिखा जाना	१५८
—कर्जदारकी दारखास्तका जिसका	१५८
—कर्जत्वाहोंकी दिवालियेकी दारखास्त सुने जानेका नोटिस	१५९

दस्ता	विषय	पेज
—दिवाणिया करार दिये जानेका हुक्म	...	१६३
—रिमांवरकी नियुक्तिका हुक्म	...	१६३
—कर्मका मानिन किया जाना तारीफा	...	१६४
—मजदूरोंका कर्म साधित किया जाना	...	१६४
—तस्वीया या तय होनेकी रसीम पर कर्मकाहोंके नाम नोटिस जारी किया जाना	...	१६५
—उन कर्मकाहोंकी फहरिस्त जो तस्वीया या तय होने वाली रसीमके समय बचाई जावे	...	१६५
—दफा ६४ के अनुसार दिया जाने वाला नोटिस	...	१६६
—दिवाणिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदा या हुक्म	...	१६६
—कर्मकाहोंकी बहालकी दरखास्तका नोटिस	...	१६६
—आमदनी व चार्जमें आने वाली जायदादके सम्बन्धमें लगाई हुई फाँकों साथ बहालकी हुक्म	...	१६७
—कर्मकाहोंके नाम नोटिस सरकारी कारिवाइमें	...	१६७
—वेहे कर्मकाहकी दरखास्तका नोटिस जिसका नाम सुर्खमें दैन नहीं है	...	१६८

घम्वई हाईकोर्ट रूलस

घम्वई हाईकोर्टके धनाये हुए नियम कानून दिवाणियाके सम्बन्धमें	...	१६८
—बाबई दिवाणियाकी अर्जमें लकर आतम कारिवाई तक	...	१६८
—कसौम साधित किया जाना पूरी कारिवाई	...	१६९
—रिमांवरकी नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और अन्य बातोंका वर्णन	...	१७०
—दिस्मा रसदी और बहाल होना	...	१७१
—हर एक दफाके अनुसार किस तरह नोटिस जारी किया जायगा	...	१७२
—मरसला कारिवाई दिन दिन मामलोंमें कैसे की जायगी	...	१७४
—मुआदना और बरीअर्थी कीम आदिका वर्णन	...	१७६
—नमूना आम उनबला	...	१७६
—कर्मकाह द्वारा दी जाने वाली दिवाणियाकी दरखास्त	...	१७७
—कर्मकाह द्वारा दी जाने वाली दिवाणियाकी दरखास्त	...	१७८
—कर्मकाहानो दिवाणियाकी दरखास्त सुने जानेकी तारीफका नोटिस	...	१७९
—दिवाणिया करार दिये जानेका हुक्म	...	१७९
—रिमांवरकी नियुक्तिका हुक्म	...	१८०
—छाँवा सुबूत (आम तारीफा दफा ४९) के अनुसार	...	१८०
—मजदूरोंके कर्मका सुबूत	...	१८१
—तस्वीया या तय होनेकी रसीमका नोटिस जो कर्मकाहोंके दिया जाना चाहिये	...	१८१
—कर्मकाहोंकी फहरिस्त जो तस्वीया या रसीम पर विचार करते समय बचाई जाय	...	१८२
—अन्तिम दिस्मा रसदी बोधनेसे पहिले कर्मकाहोंको दिहा जाने वाला नोटिस	...	१८२
—दिवाणिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदाका हुक्म	...	१८३

दफा	विषय	पेज
—बहाल होनेकी दरखास्त नोटिस जी कर्जदारोंको दिया जाना चाहिये	...	१८३
—सरसरी धारबादगी नोटिस दफा ७४ के अनुसार	...	१८३

मान्ति कानून दिवालियाके अनुसार नमूने

नमूने का फार्म नं० १	कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त	...	१८४
११ ॥ नं० २	कर्जस्वाह द्वारा दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त	...	१८५
११ ११ नं० ३	दरखास्त वाले नापेस छाने मुकदमा	...	१८६
११ ११ नं० ४	कर्जस्वाहन द्वारा दरखाल दमियाना रितावरके मुकदमे करनेके लिये	...	१८७
११ ११ नं० ५	नोटिस वाले दरखास्त दिवालियाके छाने जानेकी	...	१८८
११ ११ नं० ६	कर्जदारके मुक्त रिये जानेके लिये दरखास्त दफा २३ के अनुसार	...	१८८
११ ११ नं० ७	प्रोटेक्शन ऑर्डर मिन्चकी दरखास्त	...	१८९
११ ११ नं० ८	क्षमानतनामा	...	१९०
११ ११ नं० ९	अर्जी मिन्जानिब कर्जदार बाबत दिमाये जाने हनी दफा २६ के अनुसार	...	१९१
११ ११ नं० १०	दरखास्त वाले शिफारस किये जाने दिवालियाके दफा ३२ के अनुसार	...	१९१
११ ११ नं० ११	कर्जा साबित करनेकी दरखास्त	...	१९२
११ ११ नं० १२	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूचीके लिये कर्जदारकी दरखास्त	...	१९३
११ ११ नं० १३	दरखास्त कर्जबाह वाले मसूची हुक्म दिवालिया	...	१९३
११ ११ नं० १४	तरफीया या रजामे पेस करनेका दरखास्त	...	१९४
११ ११ नं० १५	दरखास्त वाले बहाल रिय जानेके	...	१९५
११ ११ नं० १६	दूसरा नमूना दरखास्त बाबत बहाल रिय जानेके	...	१९६
११ ११ नं० १७	बहालका दरखास्तके विषयके दी जाने वाली दरखास्त	...	१९६
११ ११ नं० १८	दरखास्त बाबत मसूचा इन्काल जामदाद	...	१९८
११ ११ नं० १९	धोखादेहीसे तरफीह देने बाबत इन्काल मसूचीकी दरखास्त	...	१९८
११ ११ नं० २०	दरखास्त कर्जस्वाह बाबत मसूची इन्काल जामदाद	...	१९९
११ ११ नं० २१	दरखास्त बाबत तरफीकात रुधे दिवालिया	...	२००

शब्दार्थ सूची

अ

अदालत-कचेहरी, न्यायालय
अभिप्राय-मतलब, आशय
अहाता-प्रदेश, सूबा
अनुसार-मुताबिक
अलहदा-भिन्न, अलग
अर्थ-मतलब, मानी
अधिकतर-बहुतायतसे, अक्सर
अधिकार-अक़्वाय
अदालत एकीकृत-रमात काजकोर्ट
अवध-जकर
अतिरिक्त-अलावा
अर्जों-दरखवास्त
अन्न-घात
अन्नतजवीजमुदा-जिन यातका फैसला हो
गया हो
अदमपैरवी-पैरहाजिरीमें
अपील-हुक्मके विरुद्ध अर्जों
अद्वयगी-देना
असर-प्रभाव
अद्वयार-अधिकार
अनुविधा-अद्वन
आकिशल पसायनी-सरकारी रिखीवर
आवश्यकता-जकरत
आगरा टेनेन्सी पक्ट-कानून लगान आगरा
अ अवध
आधिपत्य-प्रधानता

इ

इन्तकाल-हस्तान्तरित
इस्तकारिया-किसी वक्के मान लिये जाने
के लिये

इनकारी-न मानना
इन्सालघेन्सी-विवालिया
इजराय-डिकरी-डिकरीका जारी करना
इजराय-जारी करना
इतलाय-संदिस
इस्तनार् हुन्म-हमेशाके लिये हुक्म जारी होना
इतजाम-प्रबन्ध

उ

अदाहरण-मिसाल
उल्लेख-जिकर
उपस्था-इफाके अन्दरका अंक
उचित रूपसे-जायज़ तरीक़े
उपस्थित-मौजूद

ए

एडीशनल-संस्करण, जुड़ा हुआ
एकतर्फा-एकहीपक्ष
एतराज-आपत्ति
एक्ट-कानून

क

कमिश्नरी-सूबेकी बड़ी अदालत
कर्जतवाह-लेहनदार जिन लोगोंका रुपया
कर्जदार पर बाकी हो
कर्जदार-रु० जिस पर बाकी है, (दिवालिया)
कर्ज-करजा, अश्न
क़रार देना-मान लेना, तप कर देना
कम्पनी-जमात
कर्तव्य-कर्ज
कमटी-समाज, सम
काज-अन्दर या ऊपरकी दफा या अंके
कानून इन्काल जायदाद-ट्रान्सफर आफ़
प्रापटी

कारवाई-काम करना, कारगुजारी

कारण-सबब

कास अपील-अपील करने पर दूसरा पक्ष भी जो अपील कर दे

ख

ख्याल करना-मान लेना

खफीफा की अदालत-स्माल क्लाज कोर्ट

खबर-सूचना

खास-विशेष

खानदान मुश्तका-शामिल शरीक परिचार

खारिज-रद्द कर देना

खुलासा-सारांश

ग

गिरफ्तारी-कैदके लिये पकड़ना

गिरफ्तार-कैदके लिये पकड़ लेना

गैरहाजिर-न उपस्थित होना

गैरमनकूला-अच्छल जायदाद, स्थावर

घ

घटना-वाकिया

घोषणा-सूचना, खबर

घोषित-प्रकाशित

ज

जमानतदार-जिसने जमानत की हो

जमाअमानत-मांगतेही मिलने वाली वस्तुका रखना

जराअत काइतकारी

जागीरें-सरकारसे इनाममें पाई हुई जायदाद

जागीरदार-इनामदार, मालगुजार

जायदाद-सम्पत्ति

जायदादीवानी-सिविल प्रोसीजर कोड

जायदाद फौजदारी-क्रिमिनल प्रोसीजर कोड

जाती-निजी

जिक-उल्लेख, बयान

जुर्म-अपराध

ट

टापू-जिस ज़मीनके चारो तरफ जल हो

टाउम्स-कलकत्ता, यम्बई, मद्रास, कापंची

ड

डिक्रीदार-जिसके हकमें फैसला हुआ हो

डिक्री-अदालतका फैसला मुद्देके पक्षमें

डिवीडेण्ड-निश्चित समयमें बांटने वाली रकम

त

तय-फैसला, ठीक

तस्दीक-ज्ञानूनके अनुसार मंजूरी

तजवीजगुदा-जिसका फैसला हो गया

तहरीर-लिखित

तहरीरी-लिखी हुई

तस्फीया-आमलका मय हो जाना

तस्फीयानामा-फैसलानामा

तर्ज-प्रकार, क्रिस्म

तर्जुआमता-बर्नाथ की क्रिस्म

तरीफा-तरह, रीति

तरजीब-भेद्यता

तकलीम-बंद जाना

तजवीजगुदानी-हुक्मके विचारके लिये अर्जों

तात्पर्य-मतलब

द

दरमियान-अध्यम, बीचमें

दरअसल-वास्तवमें

दस्तूर-कायदा

दस्तन्दाजी-आपत्ति करना

दफा-धारा

दरखवास्त-अर्जों, प्रार्थना पत्र

दरमियाबी-बीचमें

दस्तावेज-लिखतें जो स्टाम्प पर हों

दण्ड-सजा

दाखिल होना-पेश होना

दाया-नालिश

दिवालिया-कर्जदार
दिवालियेके काम-जिन कामोंसे दिवालिया
बनाया जा सके
दीवानी अदालत-दीवानीकी फोर्ट
दफ्तर-सम्हाल, निगरानी

ध

धन-रुपया
धनराशि-रुपयोंकी शकलमें
ध्यान रखना-ब्याल रखना

न

नगरस्थानी-कैवलके लिये दुवारा विचार
कराने की अर्जी
नाबालिग-अज्ञान
नावाक़िफ-न जानने वाला, अज्ञान
निम्न-जैस, नीच
निर्धारित-मुक़रर
निश्चित-कसई तय कर देना
नियम-क़ायदे
नियत-मुक़रर
निजीतौर पर-घरेलू
नियुक्ति-मुक़ररी
नियुक्त-मुक़रर
नीयत-ईमान
नैकनीयती-शुदावरण ईमानदारीसे
नोद्विष-सूचना

प

परिमाणा-खास अर्थ का मान लेना
परिशिष्ट-तितम्भा
प्र-न्तु-लेकिन
परवाह-मानना, ऊक़रत
प्रधान-मुख्य
प्रसङ्ग-सम्बन्ध
प्रयोग-इस्तेमाल
प्रकरण-बेप्तर

प्रकाशित-ज़ाहिर
प्रश्न-सवाल
प्रचलित-रायज है
प्रतिनिधि-एवजमें, स्थानापन्न
प्राप्त-ज़िला
प्राप्तिक-सुवेका
प्राप्त-मिल गया
प्राचिडेन्ड फंड-काट काट कर जो रुपया जमा
किया जाता है
पूर्णतया- पूरी तरहसे
पंशा-धंधा
पेश्वर-पहले
प्रेसीडेन्सी-सुबा
प्रेसीडेन्सी टाउन्स-कलकत्ता, बम्बई, मद्रास,
करांची रंगून
पेंशन-नौकरी के बाद की तनखाह
पोलिटिकल पेंशन-राजनैतिक पेंशन

फ

फर्म-दुकान, कोठी
फार्म-तरीका, छपा हुआ काग़ज़
फीसदी-सैकड़े पर
फैसला-तय हो जाना, निश्चित हो जाना
फैसल- तय होना
फैलाय-विस्तार

ब

बयान लहरीरी-जवायदावा
बहुमत-कसरतराय
बहाल होना-ज़िलसे रखा पाजाना
बरी करना-छोड़ देना
बहेंसियत-इज्जतके मुताबिक
बयनामा-बैचा नामा
बयबात-बेहनमें यह शर्त होती है
बख़त-बकाया
बार सुबूत-सुबूतकी ज़िम्मेदारी
बिडिश-अङ्गरेज़ी

ब्रिटिश भारत-अङ्गरेजीराज वाला भारत
बुन्देलखण्ड लैन्ड एलीमेशन ऐक्ट-बुंदेलखंड

का ज़मीन लेने सम्बन्धी कानून
घेनामीदार-फर्जी नाम वाला व्यक्ति
वेजा लाभ-अनुचित लाभ
वेजा-नाजायज़

भ

भसा-खर्चा

भोंति-तरह, प्रकार

म

मध्यमदेश-सो० पी० प्रंत

मदियून-जिस पर डिकरी हो

महफूज-रेहन रखने वाला

महफूज कर्जब्याह-ज़मानत पर जिसने रुपया
बिधा हैमनकूला जायदाद-जंगम जायदाद, जो
जायदाद खल सकती है

मतालिवा-कीमत

मामला-मुकद्दमा

मातहत-वशीभूत

मातबल-पहल

मालकियत-हकीयत

भिताकरा-धर्म शास्त्रका मान है

मुतकरिफ़-फुटकल

मुनाफा-लाभ

मुन्तकिज़-इस्तान्तरित करना

मुन्तकिलअलेह-जिसके पास हत्यादी जाय

मुआहिदा-इकरार

मुश्तहरी-घोषित की हुई

मुकरर-नियत

मुहय्या-होसिल की गई

मुर्तदन-जिसने रेहन रखा हो

मौदसी-पैतृक

मंसूखी-रद

र

रक्षा-महफूज

रह-मंसूख

रसदी-हिस्सेके मुताबिक

राय-मत

रिखीवर-अदालतका एक अफसर

रिहई-छुटकारा पाना

रिपीजिंग ऐक्ट-जिसके द्वारा अन्य कानून
रद हो

रुकावट-अड्डम

रुस-कायदे

रस्पान्डेन्ट-जिसके खिलाफ अपील हो

ल

लागू-सम्बन्ध

लाभ-फायदा

व

व्यवस्थापक-कायम करने वाला

व्यवस्थापिका सभा-जहां पर कानून बना
जाते हैं

व्यक्ति-शख्स

व्यवहार-तर्ज़अमल

वाक्य-अल्फाज़

वाकियाती-जो कानून सम्बन्धी न हो

वारिस-उत्तराधिकारी

वांट-गिरफ्तारीका हुक्म

व्याख्या-तशरीह

बिस्तार-तशरीह

बिपरीत-खिलाफ़

विविध-मुस्तलिफ

व्यौरा-तफसील

श

शब्द-लेफ़्ज़

शर्त-पाबंदी

शुद्ध-व्यक्ति
शरीकदार-हिस्सेदार
शामिल शरीक खानदान-मुश्तरका परिवार

स

सरसरी-साधारण
सीमा-द्द
साधारण-सरसरी
सूची-फेहरिस्त
सूचना-इस्लाह
सूद-न्याज

संशोधित-तरीम किया हुआ
संदिग्ध-मुश्तर
संगीन-मुश्किल, कठिन

ह

हकीकतमें-दरअसलमें
हक-स्वत्व
हस्तक्षेप-मुश्किल होना
हक-शिका-दक दूसरेसे पहले अपना
हस्य-अनुसार
हिस्सा रसदी-हिस्सेके अनुसार

अङ्ग्रेजी नज़ारोंकी सङ्केताक्षर सूची

A या All.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स इलाहाबाद सीरीज
A. I. R. (All.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (इलाहाबाद सीरीज)
A. I. R. (Cal.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (कलकत्ता सीरीज)
A I R (Mad)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (मद्रास सीरीज)
A. I. R. (Bom)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (बम्बई सीरीज)
A. I. R. (Pat)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (पटना सीरीज)
A. I. R. (Rung.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (रंगून सीरीज)
A I. R. (Pn.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (प्रिंसी काउन्सिल सीरीज)
A I. R. (Nag)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (नागपुर सीरीज)
A. I. R. (Sindh)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (सिंध सीरीज)
A I R. (Lah.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (लाहौर सीरीज)
A. L. J.	इलाहाबाद लॉ जर्नल
A W. N.	इन्डियन वीकली नोट्स
B. या Bom.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स बम्बई सीरीज
B H. C.	बंगाल हाईकोर्ट रिपोर्ट्स
B. L R	बम्बई लॉ रिपोर्ट्स
Bur L. R.	बरमा लॉ रिपोर्ट्स
C. या Cal.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स कलकत्ता सीरीज
C. L J.	कलकत्ता लॉ जर्नल
C. W. N.	कलकत्ता वीकली नोट्स
F. B.	फुलबैच
I. C.	इन्डियन केसेज लाहौर
L. B. R.	लोअर बरमा रिपोर्ट्स
M. या Mad.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स मद्रास सीरीज
P. L. J.	पटना लॉ जर्नल

प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन् १९०६ ई०

[कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची शहरोंके लिये]

सर्वाङ्ग पूर्ण व्याख्या और हाल तककी नज़ीरों सहित दफावार सविवरण सूची

पृष्ठा	विषय	पृष्ठा
१	नाम व प्रारम्भ	१
—	ता० १ जनवरी सन् १९१० ई० से यह कानून लागू होगा	१
—	प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास) के अलावा भी यह कानून ऐक्ट नं० ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार रंगून और कराचीमें भी लागू किया गया है	१
—	प्राथमिक कानून दिवालिया और इस कानूनका भेद	२
—	इस ऐक्टका पहलेके कानूनों पर प्रभाव क्या पड़ता है	२
२	परिभाषाये	२
(ए)	'कर्जस्त्राह' (Creditor) शब्दके अन्तर कौन लोग शामिल किये जायेंगे	३
(बी)	'कर्ता' (Debt) और कर्जदार (Debtor) शब्दोंका अर्थ	३
(सी)	'आफिशियल एससिने' (Official Assignee) शब्दका मतलब	३
(डी)	'निर्धारित किये हुए' (Prescribed) शब्दका अभिप्राय	३
(ई)	'जायदार्' (Property) का अभिप्राय और मतलब	३
(एफ)	'नियमों' (Ruls) का अर्थ और अभिप्राय	३
(जी)	'सहस्रज कर्जस्त्राह' (Secured Creditor) का मतलब व अर्थ	३
(एच)	'अदालत' (The Court) शब्दका मतलब	३
(आई)	'इन्गकाल जायदार्' (Transfer of Property) शब्दका अर्थ व अभिप्राय	३
—	किसी बेनामीदारको कर्जस्त्राह नहीं समझना चाहिये	३
—	अगर कोई साया दस्तावेज व हर हालतमें अदा करनेका है तो वह कर्ज है	३
—	उधार देने वाले और उधार लेने वालोंपर परस्पर सम्बन्ध क्या है	३
—	जब किसीने अपना दूसरेको दिया कि वह तीसरे आदमीको देदे तो सम्बन्ध क्या होगा	३
—	इस कानूनके पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या वहीं होगी जो अन्य कानूनोंमें दी गई है	४
—	इस कानूनके सम्बन्धमें इंगलिश फ्रैन्चमें सब तात्विक हो सकते हैं	४

वक्र

विषय

पृष्ठ

पहिला प्रकरण

अदालतों की व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

३ यह अदालतें जिनको दिवालियेके अधिकार प्राप्त हैं	४
—बलवत्ता, प्रदत्त, जर्ज और नवो हार्डिंग तथा सिन्धके हार्डिंग ट्रिब्यूनल	४
४ अकेला एकही जज इस पदके अधिकारोंको चरित सकता है	५
—हार्डिंग या चीफ कोर्टके चीफ जस्टिसको अधिकार है कि किसी एक जनको दिवालियेके कामके लिये नियत करे	५
५ कमरेमें जजोंका काम करना	५
—जनको अधिकार है कि वह चाहे खुली अदालतमें मामला सुने या कक्षमें	५
६ अदालतके अफसरोंको अधिकार प्रदान करना	५
—चीफ जनको अधिकार है कि वह दिवालियेके मामलोंके सुननेका अधिकार किसी अफसरको देवे	६
—जिस अफसरको दिवालियेके मामला सुननेके अधिकार मिले हों वह ही होगा	६
—अधिकार प्राप्त अफसरको तारीफ अदालतके मामलोंसे सम्बन्ध न होना	६
७ दिवालियेके सम्बन्धमें पैदा हुए सब प्रश्नोंको तय करनेके अधिकार	६
—आदिशत प्रमाणों आदिके बीचके सम्पर्कोंके तय करनेका अधिकार	७
—दिवालिया अदालतके हुक्मको रद्द करनेके लिये कोई मुकदमा दोबानोंमें दाखल किया जाएगा	७
—अधिकार सीमाके बाहर किसी जायदादके बारेमें अदालत हुक्म दे सकती है	७
—कानूनकी पाबंदी करनेके लिये अदालत भी दिवालियेके मामलोंमें बाध्य है	७
—क्योंकि पैसा अदायगीके बारेमें जो प्रश्न होंगे तब दिवालिया अदालत तय करेगी	७
—२०० मीलस ज्यादा दूरीके आदमीको भी सब अदायत तलब करेगी	७
—नव दूर, गवाह पछ हो तो उसे सब सुविधायें मिलेंगी जो दूसरोंको मिलती है	७
—बाई शक्स गवाही देनेसे इन्कार नहीं कर सकता	८

अपील

८ दिवालियेके मामलों की अपील	८
—अदालत दोबारा अपने हुक्मों पर दुबारा विचार कर सकता है	८
—नवास्तानी (Keyrow) उसी इतिहासके सामने होगी जिसने हुक्म दिया हो	८
—अगर बदल गया हो या दृष्टा हासिल आगया हो तो तबका सामने भी नज़रआती होगी	८
—जिस हुक्मकी अपील जिस तरह कहा पर की जाएगी और कहा पर नहीं	९
—दोबानोंकी अपीलका तबका बान सामनेमें अपील का आगयेगा	९

दूसरा प्रकरण

दिवालियेके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्यवाही

दिवालियेके काम

१ दिवालियेके काम	५
— दिवालियेके काम कौन कौनसे होते हैं और कौन नहीं	५
— जिस पर डिफ्टी होगई हो दिवालियाका काम है	५
— “ कर्जदार ” शब्दके अन्तर कौन लोग होते हैं, साधारण अर्थ माना जाता है	५
— किसीके देनेको जो कपया लिया जाय तो लेने वाला कर्जदार नहीं माना जायगा	५
— परमपूज्य रहने वाला आदमी भी दिवालिया करार दिया जासकता है	५
— जो व्यक्ति सही मुआहिदा कर सकते हैं वह दिवालिया करार दिये जासकते हैं	१०
— दिवालियेको अपनी सब जायदाद दे देना चाहिये चाहे जहा पर वह हो	११
— अगर कर्जदारमें कपया मगानेके लिये सब या कुछ जायदाद दया दी हो	११
— जब कर्जदारने किसी खास लड़नदारको कपया चुकया हो दूसरोंका नहीं तो ऐसे मामलोंका विचार	११
— जब कर्जदार अङ्गरेजों मारते बाहर चला जावे या मृत हो जावे, भाग जाय	१२
— किसी फर्मका एक डायरेक्टर जब बाहर चला जाय तो फर्म दिवालिया न होगी	१२
— कर्जदारके अधिकतर रहनेवाली जगह कौन समझी जायगी	१२
— कैसला आरसी और अदालतकी डिक्लीरेशन फार्म	१३
— जब कर्जदारने लड़नदारको यह नोटिस दिया हो कि कपया नहीं चुकाया जावेगा	१३
— किसी डिक्लीरमें कर्जदार जब कैद कर लिया गया हो तो वह काम दिवालिया है	१३

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

१० दिवालिया करार देनेके अधिकार	१३
— जहाँ देने पर भी दिवालिया करार देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है	१३
— इक्वैटिमें दिवालिया बन जाने पर भी हिदुस्थानमें दिवालिया बनना आवश्यकता है	१४
११ अधिकारोंमें रुकावट	१४
— फ्रिज एन्ड दशाग्रमें अदालतकी दिवालिया करार देना अधिकार नहीं है	१५
— कर्जदारका दीनानी की जेलमें होना और एक साल तक अदालतकी माँगमें रहना	१५
— जब किसी फर्मके दिवालिया बननेकी अर्थात् दी जाय तो उस फर्मको एक साल बढ़ा होना चाहिये	१५
— दिवालिया बननेके लिये किसी एकही शर्तका पूरा करना काफी होता है सबका नहीं	१५
— कमीशन लेकर काम करने वाला, एजेंट नहीं कहा जाता है	१५
— जैसे मुनीम, गुप्तार, मुख्तार आदि जो उसी मालिकता ही बड़ा काम करते हैं एजेंट हैं	१५

वर्ग	विषय	पृष्ठ
—	निवास स्थान कर्जदारका एक साल तक जिस अदालतकी सीमामें हो—मतवेद ...	१५
—	होटलमें रहना भा अदालतके अधिकार सीमाके अन्दर माना जायगा ...	१५
—	पुनर्हित ४ मास तक बन्दहमें शिष्टोंके पास रहा तो उसका बन्दहमें रहना नहीं माना जावेगा ...	१६
—	धूमने जाना, सैरके जाना, निवास स्थान नहीं माना जावेगा ...	१६
—	दिन्दू परिवारका कर्ता जहा काम करता हो तो वह न माना जायगा कि दूसरे लोग भी वहां रहते हैं ..	१६
३२	यह शर्तें जिनके अनुसार कर्जद्वारा दिवालिया क्रमर दिलायेकी दुरवस्थास्त दे सकता है	१९
—	कर्जद्वारा कम, जिस दशामें, कर्जदारके निरुद्ध दिवालिया की अर्जी दे सकता है ...	१९
—	(५००) २० वा कर्जा होना एक सहनदारका या कई सहनदारोंका होना जरूरी है ...	२०
—	तीन महीनेके अन्दरके वे फाय होना चाहिये जिन काममें दिवालिया बनाया जाता हो ...	२०
—	सुराहिन (जिसके पास जायदाद रहन हो) रहनका एक छेद कर अर्जी दे सकता है ...	२०
—	सुराहिन जब अपनी रहनकी जायदादका अर्धांश खगा दे तो दूसरा पौर्ष उसे खतना दे सकता है ...	२०
३३	कर्जद्वाराकी दुरवस्थास्त पर कार्यवाई तथा उस पर हुकम ...	२०
—	कर्जद्वारा द्वारा अर्जी देने का कौन कर्जवाई आवश्यक होगी ...	२०
—	कर्जद्वारा जब दिवालिया बननेकी अर्जी दे तो उसे हलफनामा दाखिल करना होगा ...	२०
—	वे बातें सब साबित करना पड़ेगी जो अर्जमें लिखी गई हैं ...	२१
—	अदालतकी अधिकार है कि कार्यवाई करनेके लिये वारीज बदा दे ...	२१
—	सुराहिन सुननेके बाद अदालत यदि समझे तो अर्जा खारिज कर सकती है ...	२१
—	कर्जदार, पंजरी अदा कर सकता है, या उसने वे बाने न कां हो तो अर्जा खारिज होगी ...	२१
—	समन मिलने पर अगर कर्जदार न आवे तो अदालत उसे दिवालिया बना सकती है ...	२१
—	कर्जद्वारा तादातमें समझा हो तो अदालतकी जमानत मागनेका अधिकार ...	२०
—	कर्जद्वारा अपनी अर्जी बिना अदालतकी मजूरीके वापिस नहीं ले सकता ...	२०
३४	यह शर्तें जिनके अनुसार कर्जदार दुरवस्थास्त दे सकता है ...	२०
—	(५००) २० कर्जा हो या गिरफ्तार किया गया हो या जायदाद कुके की गई हो ..	२०
—	बिक्रीके द्वारा धुनी रुपयेकी अदवसीके लिये होना चाहिये ...	२०
३५	कर्जदारकी दुरवस्थास्त पर कार्यवाई च उस पर हुकम ...	२१
—	अदालत पहले यह देखेगी कि उसके समातके योग्य वह अर्जी है या नहीं ..	२१
—	अर्जी उभी समय तक वापिस हो सकती है जब तक दिवालियाका हुकम न हो गया हो ...	२१
३६	दरमियांनी रिसीवरकी नियुक्तिके लिये अदालतकी स्थतन्त्र अधिकार ...	२१
—	अदालत बीचमें जायदाद पर रिसीवर नियत कर सकती है यह बात उसकी शर्त पर है ...	२२
—	अर्जी देनेके बाद और दिवालियाका हुकम होनेसे पहले रिसीवर नियत किया जासकता है ...	२२
—	रिसीवर आगिशल एसायरी नियत किया जायगा ...	२२
—	दरमियांनी अफिशल एसायरीकी जयता दीनार्नाके गारंटी ४० के हक होगे ...	२२

दफा	विषय	पेज
—	जायता दावाना ऐक्ट न० ५ सन १९८ ई० वा आर्दर ४० ...	२२
—	अदालत आ फ़ैसल एसायना वा फ़ैसल निदान कर सकता है ..	२२
—	रिडीवरसे जमानत ली जासकता है, और हुक्मोंका मानना उकवा बतलाना होगा ..	२३
—	अगर रिडीवर हिंसा न दारिज कर या रुपया अदा न करे या चलती करे .	२३
—	अदालत कम्पट साइवका या रसदर निवृत्त कर सकता है जब मादगुजारी की आपदा हो ...	२३
१७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी प्रभाव .	२३
—	दिवालियाकी अर्ज देने पर कोई कर्जनाह अर्हदा वालिया नहीं कर सकता ..	२४
—	जब जाना क्षाजन दाखिल किये गये हों तो अदालतसे आका लकर दावा हा सकता है ...	२४
—	रेहन रखने वालका सामान्य मद नहीं करवा जासकता बस स्वतंत्रता रहेगी ..	२४
—	शामिल शराफ परिवारके बापका आयदादमें लड़कों, पतोंका हक शामिल रहेगा ...	२४
—	जब कोई मुकदमा दायर हो पांच फ़ासक दिवालिया हा जाय ता जब तक उसका फ़ैसला न हो मुकदमा न चलेगा . . .	२४
१८	कारवाईका रोक जाना , ...	२४
—	दिवालिया अदालत दूसरा अदालतका अर्जवायना राक सकता है .	२५
—	गहनका हुक्म लकड़ जिरिस्त भगा जासकता है या नक़ल भगी जासकती है ...	२५
—	कोई मामला चाह दिवालिया करार दनक बाद भी चलता हा ता या राका जासकता है ...	२५
—	कलकता हाईकोर्टका राय है कि जल्ल भगकी कारवाई दिवालिया, टाउसु कार्यसे राकी नहीं जासकती ..	२५
—	टाउसु हा सल्ल स अदालत, निजामी दिवालिया अदालतकी कारवाई नहीं राक सरती ..	२५
१९	विशेष मेनेजरकी नियुक्तिके अधिकार ..	२५
—	विशेष मेनेजर तब नियुक्त किया जावे जब कर्जदारका आयदाद विशेष प्रकाशकी हो ..	२५
—	आकिदात एसायना आर विशेष मेनेजरका कर्क ..	२५
—	विशेष मेनेजरसे जमानत ली जापगी उसे सब हुक्मोंकी तामाक करना होगी .	२५
२०	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा ..	२६
—	दिवालिया करार दिये जानकी घोषणा सरकारी गजटमें की जापगी ..	२६
दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी		
२१	कुल मामलोंमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अधिकार ...	२७
—	या ता उसे दिवालिया करार दिया हा न जाना चाहिये या या कर्जाना चुकाया जाना ..	२७
—	नहनदातक कुल कर्जे चुका दिये गये हों तथा दिवालियाका व्यवहार आद ..	२७
—	दिन सूतोंमें कर्जोंकी अदापगी मान ला जावगी—अदालतका रयाक ..	२८
२२	अगरकी अदालतमें साथ साथ कारवाईका होना ...	२८
—	जब १६ अदालतमें कारवाई चालू हो ता उस अदालतमें होगी जिसमें सहूलियत हो ...	२८

धारा	विवरण	पन्ना
२३	मंजूरी पर होने वाली कार्यवाई	२८
	—मंजूरी के दृष्टिकोण परलेके वाम सब सहा मान जावेंगे जो अदालतने किये लें	२९
	—मंजूरी के बाद कर्जदार जेम्स भजा जासकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है	२९
	—मंजूरी के दृष्टिकोण कायमा सराफा गजटमें अवश्य की जायगा	२९

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होने पर कार्यवाई

२४	दिवालिये द्वारा दी जाने वाली सूची	३१
	—जर्जदार को सूची अपने इसकामके साथ दाखिल करना जरूरी होगा	३०
	—सूची कैसे बनाई जायगी, कब दाखिल होगी और उसका असर क्या होगा	३०
	—किसी भी दस्तावेज पर अदालत कर्जदारके कसूर पर सजा दे सकती है	३१
	—कर्जदारने अगर सूची न बनाई व न दाखिल की तो आर्थिक एसायनी बनवेगा	३१

२५	रक्षा का हुक्म	३१
	—जर्जदार अपनी गिरफ्तारी और जेल जानेसे बच सकता है	३१
	—रक्षा जेल जानेसे कहीं कहीं दीर्घ हो सकती जो सूचामें बताया गये हैं	३१
	—कर्जदार अदालतमें दिवालियेकी रक्षा करनेके हुक्ममें उद्युक्त कर सकता है	३१
	—कर्जदारके लिये जलसे रक्षा का हुक्म देनेमें अदालत धूस विचार करेगी	३१

२६	कर्जद्वाराओंकी मीटिंग	३२
	—अर्ज देने पर अदालत सब लहनगोंकी मीटिंग करने व मामलात दृष्ट करनेका हुक्म देगी	३२

२७	दिवालियाका खुली अदालतमें बयान	३२
	—जर्जदारका बयान उसके बर्तान, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें अदालतमें होगा	३२
	—सूची कर्जदारी दाखिल करनेके बाद जेम्स वगैरह दिवालियेका हाना चाहिये	३२
	—आर्थिक एसायनी बयानके समय भाग लेगा तथा बोर्ड प्रश्न पूछ सकती है	३२
	—जर्जदारका बयान, लिखा जायगा, हर कैडनदार उसे देख सकेगा, बयान हल्काम होगा	३३
	—जब जर्जदार पागल हो या बेगुनाह हो या नाबालिग हो या अशक्त हो	३३
	—किन हालातमें व किनसे अदालत बयान लेनेसे नकार सकती है	३४

तस्फीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

२८	प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका कर्जद्वाराओं द्वारा स्वीकार किया जाना	३४
	—कर्जदारका आधार, स्वीकार पेश करनेका, व दाय करनेका, प्रस्ताव पेश करनेका	३४
	—एमे प्रस्तावकी दरुआवा कर्जदारका पास भजा जाना और वसूली करना	३४
	—प्रस्तावका मंजूरान, और कर्जद्वाराओंका अधिकार मंजूर करनेका	३४
	—कर्जदारका द्वारा प्रस्तावकी मंजूर कब मानी जायगी	३५

दफा	विषय	पंज
६४	—कस्तूरवाह अपनी राय लिखे ३१ दिन पहले आधिकारिक एसायनीके पास भेज सकते हैं ...	३५
६६	अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति ...	३६
	—कस्तूरवाहोंके मजूर करने पर अदालतमें दगवास्त दी जायगी ...	३५
	—होन बर्जवाह विरोध कर सकता है, ३५ ३२ सनता है और कैसे रहेगा ...	३५
	—प्रस्तावकी मजूरीके पहले आधिकारिक एसायनीकी रिपोर्टका अदालतमें प्रमाण जाना ...	३६
	—किन बानोंके होने पर अदालत प्रस्तावकी मजूरीको रद्द कर देगी और फोन उग्र करेगी ...	३५
	—मरसौरी की कार्यवाहीमें अदालतकी आज्ञा के ३१ मामला तय किया जा सकता है ...	३५
	—अदालत प्रस्तावका मामला तब तक मजूर न करेगी जब तक कम्पे कम्पेमें थार आका अक्ष न हो ...	३६
७०	प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुक्म ...	३७
	—आपसी समझौता कर्जदार और कर्जदारके बीच तस्वीर नहीं समझा जायगा ...	३६
७१	दिवालियेका दुबारा दिवालिया करार देनेका अधिकार ...	३८
	—अगर कर्जदार तस्वीरमें किन्तु ठीक वक्त पर अदा न करे तो दुबारा दिवालिया बनाया जासकेगा ...	३८
	—अदालतके अधिकार जब कर्जदार अपने पूरी न करे ...	३८
	—दुबारा दिवालिया करार देनेकी अर्जी देने पर सब कर्जें सानित किये जायेंगे ...	३८
७२	तस्वीर या स्वीकृतिका प्रभाव ...	३८
	—फोन कर्जें तस्वीर हो जाने पर भी जैसेके तैसे बने रहेंगे उन पर दस्तक अक्ष न पड़ेगा ...	३८

दिवालियेकी ज्ञात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

७३	जायदादके चतकाने या उसको बसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालियेके कर्तव्य ...	३९
	—कर्जदारको, कर्जदारकी मॉर्गमें शामिल होना जरूरी होगा ...	३९
	—कर्जदार अपनी जायदादकी कर्जदार देवे बयान देवे, शक्ति हो, दस्तावेज मिलें आदि ...	३९
	—कर्जदार, कर्जदार वसूलीमें मदददे, या हुक्मकी तात्काल न करेगा तो सजा दी जायगी ...	३९
७४	दिवालियेकी गिरफ्तारी ...	४१
	—३५, किन्तु दशम, कैसे, दिवालिया गिरफ्तार किया जायगा और जेल भेजा जायगा ...	४१
	—नद दिवालिया भ्रम जाय, या भागने काय हो, या भागनेमें उत्पन्न टाकता चाहे ...	४१
	—यदि यह मादूम हा कि कर्जदार अपनी जायदाद हटाने काग है या हटा दी है ...	४१
	—यदि विना आज्ञा आधिकारिक एसायनीके ५०) से ज्यादा कर्जें जायदाद हटा दी हो ...	४१
	—यदि कर्जदारने अपनी दस्तावेजों, नहीं खाता अदिनो छिपा लिया हा ...	४२
७५	खुर्साका दूसरी जगहोंके लिये भेजा जाना ...	४२
	—कर्जदारके नामके भनीआउर, जारसल, खद, बंया आदि ७७ आधिकारिक एसायनीकी दिवे जायेंगे ...	४२
७६	दिवालियेकी जायदादका पता लगाना ...	४२

दफा	विषय	पेज
—अदालत ऐसे व्यक्तियोंको तब तक कर सकती है जिनके कन्जेम दिवालयिकी जायदाद हो	...	४३
—नई श्रमस वाण्टसे गिरफ्तार होगा या अदालतने हुकम पर न आवे या दस्तावेज न दे-	...	४३
—दिवालयिकी कब्जा किसी पर साबित होने पर उचित दण्डसे वसूल किया जावेगा	...	४३
—दिवालयिकी अदालतके हुकमोंकी तासील जानना दोनानीकी डिफेंसी तरफ तासील होगी	..	४४
—जायदाद दोनानी ऐक्ट न० ५ सन १९०८ का आर्डर २१ कूल ३०३३१३५३६	...	४४
४७ कमीशन जारी करनेके अधिकार	...	४६
—गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन भी जारी किया जायकता है	...	४६
—गवाहोंका कमीशन जायदाद दोनानीके बायदोंके मुताबिक जारी होगा	...	४६
—जायदाद दोनानी ऐक्ट न० ५ सन १९०८ का आर्डर २६ कूल १ से ८ और १५ से १८	...	४६
दिवालयिकी बहाल किया जाना		
४८ दिवालयिकी बहाल किया जाना	...	४८
—दिवालयिकी बयान देनेके बाद जेल्से छुटकारा पानेकी दरखास्त दे सकना है	...	४८
—जेल्से रक्षक हुकम देनेसे पहले अदालत जाकिराल एसापनेसे रिपोर्ट मांगगी	...	४८
—अदालतके अधिकार दिवालयिकी जेलम रखा करनेके सम्बन्धमें	...	४८
४९ यह मामले जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुकम देनेसे इनकार कर देना चाहिये	...	४९
—जिन दस्तावेजोंमें दिवालयिकी जेल मानसे रखा अदालत नहीं देगी	...	४९
—जब दिवालयिकी तासीलतहिमी दण्ड ४२१ से ४२४ के ऊर्ध्व गिये हों	...	४९
—दिवालयिकी अपराधोंका बर्णन जिनके सबबसे जेल जानेमें रखा नहीं मिल सकता	...	४९
—अदालत तीन तीन बातें पहले दैगी जब जेलसे कर्जदारकी रक्षा हुकम देगी	...	४९
५० बहालकी दरखास्तका मुला जाना	...	५१
—बहाल होने अर्थात् जेल जानगी श्राफा हुकम होनेकी घोषणा ठीक रीतिसे की जावेगी	...	५१
५१ बहाल होनेकी दरखास्त न देने पर दिवालयिकी क्रार देने वाले हुकमकी मंजूरी	...	५३
—यदि दिवालयिकी बहालकी अर्जी न दी, या शक्ति न हुआ तो पहले अर्जी खारिज हो जायगी	...	५४
—यहकी अर्जी खारिज होने पर कर्जदार जेल मेंना जायकता है	...	५४
५२ बहाल होनेकी दरखास्तका हुबारा दिया जाना	...	५४
—दुशरा दरखास्त बहाल होनेकी मियादके बाद नहीं दी जायगी तथा न सुनी जायगी	...	५४
५३ बहाल किये हुए दिवालयिकी जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य	...	५५
—जब दिवालयिकी जेलसे रखा पानेके बाद भी कर्जा वसूलमें बदल न दे तो सबा दी जायगी	...	५५
५४ धोखेदेहीसे किये हुए सौदे	...	५५
—दिवालयिकी जायदाद जब अपनी ओर या लड़कों के नाम लिख कर हटा दी हो	...	५५
—तो ऐसा पुआहिदा जिसमें जायदाद दिवालयिकी कानूनोंमें आने वाला होवे	...	५५

दफा	विषय	पेज
४५	वहातके हुक्मका प्रभाव ...	५६
	—नेमये रवा पातनेका हुक्म किन बातों पर जहर नहीं करता उनका वर्णन ...	५६
	—हरकत बर्बा, धोखेके मामले, जाना चौकदारोंको दफा ४८८ के मामलों पर प्रभाव न पड़ेगा ...	५६

तीसरा प्रकरण

कज़ोंका साबित किया जाना

४६	दिवालयिके सम्बन्धमें साबित किये जाने योग्य कज़ें ...	५७
	—दिवालयिके बर्जानोंमें कौन कौन साबित होंगे कौन नहीं उनका वर्णन ...	५८
	—मुआदिदे, दस्तावेज, भागे, कमानों, जिनकी कीमत निश्चित न हो, जिम्मेदारियों आदि का वर्णन ...	५९
४७	अपस्तमें व्यवहार व उसकी सुजरारहें ...	५९
	—जब एक दूतरेका पावना एक दूसरे पर हो तो दोनोंमें मुजरार हो जायगी ...	६०
	—केवलद्वाराके पावनाको वज्रदार मजूर न बतला हो तो आक्राइल पतायनी उसका कर्ता न मानेगा ...	६०
४८	कज़ों साबित करनेके नियम ...	६०
	—ऐसे कज़े साबित गिये जावें जेव्हा दूतरी सूची १० ३ से ६ ...	६०
४९	कज़ोंका एक दूसरेमें पहिले अदा किया जाना ...	६१
	—दिवालयिके बर्जानोंमें कौन कौन पहले बुकाये जावेंगे और कौन उसके बाद ...	६१
	—हरकती कज़ें मोक़रों की तनख़ाह, मसूफ़ा दाम, मरानका बिराया आदि पहले बुकाये जायेंगे ...	६१
	—साबित करनेके बुकाये जायेंगे तरीक़ा, व बचतके रूपसे देवता तरीक़ा ...	६१
	—जितने कज़े साबित हो चुके हैं उन पर हिस्सा रसदी मिलनेका तरीक़ा ...	६२
५०	दिवालयिका क्रमसे दिये जानेसे पहिलेका किराया ...	६२
	—पहिलेका किराया कौन मानकर हिस्सा रसदी बुकाया जायगा ...	६३

वह आयदाद जिससे कि कज़ें चुकाये जासकते हैं

५१	दिवालयिकी कारयारिका सम्बन्ध ...	६३
	—दिवालयिके समयका प्रारम्भ दिवालयिके काम होनेमें अदालतमें आना जायगा ...	६३
	—तीन सालके अन्दर जो काम सबसे पहले हुआ हो उसके दिवालयिके समय माना जाना ...	६३
५२	जो आयदाद कज़ेवाहोंमें बाँटी जासकती है उसका विवरण ...	६४
	—अमानतरी चायदाद, निजारी अमानत, पहलनेके वपड़े भरतन नहीं दाते जावेंगे ...	६४
	—जिस सब कोड़े जाले दाते सामानकी कीमत २०० रु० से ज्यादा न हो तो वह बाय जायगा ...	६४
	—कौन आयदाद कज़ेवाहोंकी बाँटी जायगी उसका वर्णन ...	६५
	—प्रामेसरी नोट जो उस दिवालयिकाके पास अमानतमें हों ...	६५

दण	विषय	पेज
—	नो सोना जेवर बनानेको दिया गया हो और इसके पहले वह दिवालिवा हो गया हो	६५
—	दिवालिवाके पास जो जायदाद बतौर अमानतके हो या ट्रेडिङ वद उसकी न होगी	६५
—	गवर्नेमेण्ट श्रमिकों को अमानत पाने पर मरदास बस	६५
—	इसमें से पाठिस दिवालिवाके कारिगों को दियाई गई	६५
—	डिप्टीके कानून के पत्र पर लेइनदार डिप्टीसरग पूरा इक माना जावेगा ?	६५
—	तनखाह भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है	६६
—	जबकि गादामें गाल भरा हो और चार्ज कर्जदारके पास कुछ समय रहती हो	६६
—	जो माल दिवालिवाके नौकर या सिपुर्दारके कब्जे हो तो वह उसीका समझा जायगा	६६

पिछले सौदों पर दिवालिवा होनेका प्रभाव

५३ इजराके सम्बन्धमें बिक्रीदारोंके अधिकारोंमें रुकावट

- जब लेइनदारों दिवालिवा बात न मालूम हो और डिप्टीका रूपया नमूल करले
- रेगनी जायदाद पर जब रुकावट प्रभाव कुछ भा नहीं पड़ सकता है
- नीलाममें पहले दिवालिवा बन गया हो तो खरीदार जायदादका उसमें रुक नहीं होगी
- यदि मोदियून हाजिर न हो और रूपया जमा किया गया हो डिप्टीदारको मिलेगा
- अगर किसी ने नैनीयतीये यह बात बिना जाने कि वह दिया लिया हो है खरीदी हो

५४ इजराय करने वाली अदालतोंके दिवालिवाकी जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य

- अगर अदालतको दिवालिवाकी खबर मिल जाय तो इजरायी करिवार रोक देवेगी

५५ स्वयं किये हुए इन्तकाल जायदादकी भेखड़ी

- कहाँ नैतकाल जायदादके दो वर्षों के अन्दरके मसूल हो जासकते हैं

५६ कुछ मामलोंमें तरजीहका रद्द किया जाना

- बरोक्षाने जब किसी एक लेइनदारको सब रूपया चुकाया हो दूसरोंको न दिया हो
- नैनीयतीये जब कोई कर्ज चुकाया गया हो, बेईमानीका इरादा न हो
- बरोक्षाने सोचे विचे हुए उस समय रद्द होगे जब वह अपने रूपयासे अन्य कर्जों न चुका सके
- वेसे सोचे और मामले बरोक्षाने विचे हुए रद्द होगे और काम कम न होंगे

५७ नैकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी वचत

- जैसा दशम वक्तदारके किये हुए सोचे सही माने जावेंगे और रद्द न होंगे

जायदादका वसूल किया जाना

५८ आफिशल एनायनी द्वारा जायदाद पर कब्जा लिया जाना

- नियती ४ की दोसरे आफिशल एनायनी दिवालिवाकी जायदाद पर कब्जा करेगा
- आफिशल एनायनीके अधिकार और हक तथा कर्तव्योंका वर्णन

दफा	विषय	पृष्ठ
५९	दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेना	७१
	—दिवालियेके वमेर, मजानम छुप कर तलाशी लेने आदिका हुक व अधिकार	७२
	—दिवालियेके लगे कौन कान सामान छाड़ दिया जासक्ता है	७२
	—दिवालियेकी जायदाद जब किन्ना दूसरक धम हो या कस्तेमें हो तो बारण्ट जारी होगा	७२
६०	दिवालियेकी तनख्वाहका कर्जखर्चाहोके लिये लिया जाना	७३
	—सरकारी नाहरीरी तनख्वाह दिवालियेकी लेहनासामें भायी जचिगा	७३
	—दिवालियेकी आयदना आद बेस, बानमी, कब लइनासामें बापा जायगा	७३
६१	जायदादका एकके पासले दूसरेके पास जाना या एकच दूसरेको मिलना	७३
	—एक अफिशल एसायनीके हाथत दूसरे अफिशल एसायनीके हाथमें जायदाद जासक्ता	७३
६२	बिला लाभको व भारी बार वाली जायदादका छोड़ दिया जाना	७४
	—जिस जायदाद पर ज्यादा कला लदा है या बहुत झगडा है वह छाड़ा जासक्ती है	७४
	—'१' मामक अन्दर भायी बार वाली या उल्लानकी जायदाद छाड़ा जासक्ती है	७४
	—अफिशल एसायनीके छाड़ देने पर उस जायदादमें दिवालियाका हुक न होगा	७४
६३	ठेकाका छोड़ा जाना	७५
	—दिवालियेके ठेका अदालतवा मज्गसे अफिशल एसायनी छाड़ सकता है	७५
	—छानामें नद ई हुई चानों आदक लगे छाड़ जानामें प्रावब	७५
६४	अफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छुड़ाया जाना	७५
	—भगर २० दिनक अन्दर जायदाद छाड़नकी बाबत तय न हो ता फिर नहीं छाड़ा जासक्ती	७५
	—अदालत २० दिनका मियादमा अपने हुकमत नदा सकती है	७६
६५	अदालत द्वारा मुआहिदोंके छोड़े जानेका अधिकार	७६
	—मुआहिदा पूरा न करनेक कारण अदालत हरना लल्ला सकता है	७६
	—जिस मुआहिदेमें लाभ हाता हो उसका अर्धों पर अदालत उस मुआहिदे पर बिषार करती	७६
६६	छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सिपुर्देगीका हुकम दना	७६
	—छाड़ा हुई जायदादके मिलनके लिय जब किसान चर्को अदालतमें दा हो	७७
	—एसा अजामें अपना आवका, हुक आद जाहिर करना जरुर है	७७
	—अदालतका अधिकार शो लगानेका, सिपुर्दे करत तथा दनका	७७
६७	छोड़ी हुई जायदादसे जिस हानि पहुचती हो वह साबित कर सकता है	७८
	—छोड़ा हुई जायदादसे जो हानि हो वह बतौर बर्जेके दिवालियामें बसूल का जचिगी	७८
६८	जायदादकी वसूलीमें अफिशल एसायनीके कर्तव्य व अधिकार	७८
	—गितनी मज्ग हो सके दिवालियेका कया वसूल करत वर्तव्य होगा	७८

दण्ड	विषय	पेस
—	जायदाद या हिस्सा बेचना, कपया वसूल करना, व्यापार चलाना, धुकहमा लड़ना, रेंटन करना आदि ...	७९
—	चूँच फ़ैमला करना, वसूली रुपयेको रसीद देना, अदालती कामोंका करना आदि ...	७९
—	अभिप्राय प्राप्तियोंके अधिन, हक और कर्तव्योंका वर्णन ...	७९

जायदादका घांटा जाना

६१	हिस्सा रसदीका पलान व उसका घांटा जाना ...	८०
—	परिष्ठा हिस्सा रसदी एक सालके अन्दर पलान करके बाय जाना चाहिये ...	८०
—	दुबारा हिस्सा रसदी जहा तक हो ६ मासके अन्दर बाय जाना चाहिये ...	८०
—	हिस्सा रसदी बाटे जानेके पहिले सूचना सब लेहनादारोंको भेजी जावेगी जिनके नाम दर्ज हैं ...	८०
७०	संयुक्त तथा अलगकी जायदाद ...	८१
—	बुदागाना कर्से बुदागाना जायदादसे पहिले बुकावे जावेगे पोंडे अन्य कर्से ...	८१
७१	हिस्सा रसदीका अन्दाजा लगाया जाना ...	८१
—	बुद्ध कपया रोके कर बाकी कपया हिस्सा रसदीमें आकिशक प्राप्तियों काट देया ...	८१
—	जायदादका इन्तजाम करनेके लिये जो खर्च पड़े बसके लिये कपया रोका जासकता है ...	८१
७२	उस कर्ज-प्याहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके पलानसे पहले, अपना कर्ज साबित न किया हो ...	८१
—	उन कर्ज-प्याहोंको हिस्सा मिल सकेगा जो रसदीके बाद अपना कर्ज साबित करे ...	८१
—	साबित होनेके बाद जो कपया दुबारा बटेगा उसमें उनकी हिस्सा रसदी मिलेगा ...	८१
७३	अन्तिम हिस्सा रसदी ...	८२
—	आखिरी कपया बांटेने पहिले उन लेहनादारोंको सूचना देना जिन्होंने कर्ज साबित नहीं किया ...	८२
—	नोटिसकी प्रत्येकके अलावा लेहनादारोंको मोहकत भी मिल सकेगी ...	८२
७४	हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता ...	८३
—	जिसे हिस्सा रसदी न मिले वह अदालतमें अर्जी दे सकता है अगर दावा नहीं कर सकता ...	८३
—	अदालत, रोके हुए समयका खान और अर्जाका खर्चा भी देना सकता है ...	८३
७५	दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तजाम कराया जाना तथा उसे उसके पयज़में श्रम-फल मिलना ...	८४
—	दिवालियेसे जायदादका प्रबन्ध, व्यापारिक इन्तजाम आदि करना जासकता है ...	८४
—	अदालत दिवालियेसे काम लेनेके बदलेमें उसे उतगत दे सकती है खर्चके लिये ...	८४
७६	वचने हुए हिस्सेको पानेका हकदार दिवालिया है ...	८४
—	उन सब लेहनादारोंका कपया अदा हो जाय तो नार्क सब जायदाद दिवालियेको मिलेगा ...	८४

दफा	विषय	पृष्ठ
	चौथा प्रकरण	
	आदिफल एसायनी	
७७	दिवालियोंकी जायदादके लिये आफिशल एसायनीकी नियुक्ति तथा हटाया जाना ...	८५
	—बलकता, बर्ग, मकान, बरामें आफिशल एसायनीकी नियुक्ति कैसे होगी ...	८५
	—आफिशल एसायनीके कर्तव्य, अधिकार और हक्कोंका वर्णन ...	८६
७८	हस्तक देनेके अधिकार ...	८६
७९	दिवालियोंके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्तव्य ...	८६
	—दिवालियोंके कामों व व्यवहार पर भी पूरा विचार दिया जायगा ...	८६
	—जेलसे छुटकारा पानेके समय दिवालियोंके व्यवहारोंकी रिपोर्ट मांगी जायगी ...	८७
	—जब कर्जदारने धोखेके काम जालसाजी, बेईमानी आदि की हो तो अदालत विचार करेगी ...	८७
८०	कर्जप्राप्तियोंकी फेहरिस्त दाखिल करनेका कर्तव्य ...	८७
	—लेहनदारोंकी अधिशर दिवालियोंके लेहनदारोंकी फेहरिस्त देनेका ...	८७
८१	धमकल-मेहनतकी फीस ...	८७
	—आफिशल एसायनीकी फीस अदालत निर्दिष्ट करेगी देहो नियम ११२ (५) ...	८७
८२	आफिशल एसायनीकी बैठनवानी ...	८७
	—अदालत, आफिशल एसायनीकी बरनी आदेशे पैदा हुई इमिती की पूर्ति करा सकती है ...	८८
	—अदालतका कर्तव्य है कि वह आफिशल एसायनीमें घल्लाके बोमें जवाब तलब करे ...	८८
८३	किस नामसे दावा दायर किया जाना चाहिये या दावा उस पर होना चाहिये ...	८८
	—सब बार्बार् ^१ दिवालियोंकी जायदादका आफिशल एसायनी ^२ इस नामसे की जायगी ...	८८
८४	दिवालिया होने पर आफिशल एसायनी अपनी जगहसे हट जायेगा ...	८८
	—अगर छुट आफिशल एसायनी दिवालिया हो जाय तो वह अपने पदसे कौत हटा दिया जायगा ...	८८
८५	मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी ...	८९
	—लेहनदारोंका मशआरानेके लिये मीटिंग करना उचित माना गया है ...	८९
	—मीटिंगमें पास हुए प्रस्ताव पर अमल करना जरूरी होगा ...	८९
	—आफिशल एसायनीको जायदादके प्रबन्धमें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी ...	८९
८६	अदालतमें अपील ...	८९
	—आफिशल एसायनीके प्रत्येक काम और हुक्मकी अपील अदालतमें हो सकेगी ...	९०
	—इस कानूनकी दफा १०१ के अनुसार २० दिनोंके अन्दर अपील करना चाहिये ...	९०
८७	अदालतका दवाव ...	९०

वर्ग	विषय	पंज
—आरिश्तल एसायनों के खिलाफ़ कार्रवाई की जायगी तथा उसने कोई सिविल काम किया हो	...	९०
—एसायनों के हिसाबका जाल या जासकती है, जवान पूरा आसकता है	...	९०

पाँचवां प्रकरण

जांच कमेटी

८८ जांच कमेटी	९१
—छेदनदारोंकी एक जांच कमेटी, एसायनोंके कामोंकी जांचके लिये बनाई जासकती है	९१
—चीन लोग मेमबर होंगे, कमेटी क्या करेगी, कैसे बनाई तथा इक क्या होंगे	९१
८९ जांच कमेटीके, अधिकार, आरिश्तल एसायनोंकी जांचके सम्बन्धमें	९१
—कमेटीको जो अधिकार दिये गये हों उनमें ब्यादा प्रयोगमें नहीं लाये जासकते	९१

छठवां प्रकरण

कार्यक्रम

९० अदालतके अधिकार	९२
—दिवालयके मुकदमोंमें सब कार्रवाई, जमाना बीमानीरी तरह की जावेगी	९२
—अदालतके अभियोगका वर्णन, महाद्वान आदिके सम्बन्धमें कार्रवाई	९२
९१ पिटीशनोंका एक साथ शामिल किया जाना	९२
—एकही कर्जदारके अनेक छेदनदारोंकी अनेक अभिया एकात्मि शामिल होगी	९२
९२ एकक स्थानमें दूसरे कर्जस्वाह द्वारा कार्रवाईका किया जाना	९४
—जिसन दिवाल्या बनानेकी अर्जा दी हो और ठीक पक्की न करेता बदल दिया जायगा	९४
९३ कर्जदारके मर जाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना	९४
९४ कार्रवाईको रोकनेके अधिकार	९४
९५ किसी शरीकदारके विरुद्ध दिवालयको दुरस्वाम्तका दिया जाना	९४
—नाराजियोंमें कर्ज लिया हुआ व्यक्ति नाश्रि होने पर दिवाल्या नहीं बनाया जासकता	९५
९६ कुछ टेम्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दुरस्वाम्तका सारिज किया जाना	९५
—अनेक दिवालयामें जब कुछको अदालत परी करदे ता नारीक बग न मान जायेंगे	९५
९७ शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटीशनोंका दिया जाना	९५
—एक मापलसे सम्बन्ध रखने वाले जब अनेक मामलों हों तो एकही अदालत सुनेगा	९५

क्रमांक	विवरण	पेज
१६	ऑफिशियल एसायनी तथा दिवालियेके अधिकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमे ...	१६
	—एक सार्जीदारक दिवालिया बननेमें दूसरे सार्जीदार उन्नत कर सक्ते हैं ...	१६
१६	सामके नामसे मामलेका चलाया जाना ...	१६
	—जिस नामसे दूकान चलायी हो उस नामसे दिवालियेकी कोर्वाई चल सकती है ...	१७
	—किसी फर्मका नाराजिब सार्जदार दिवालिया करार नहीं दिया जासकता ...	१७
१७०	अदालत दिवालियाके धारण ...	१७
	—कायदा कौनसीके बाण्डोंके नियम इस दिवालियेकी कोर्वाईमें लागू होंगे ...	१७
	—कायदा फोर्जदारी दंड ७७ (२), ७९, ८२, ८३, ८४, तथा १०२ का वर्णन ...	१८

सातवां प्रकरण

मिथाद

१०१	अदालतके लिये मिथाद ...	१९
	—एसायनीक काम या हुक्मारी अग्रील २० दिनेके अन्दर हो सकती है ...	१९
	—जबके लिये जमानत हा मागवती है अगर अदालत मुतासिब समझ ...	१९

आठवां प्रकरण

दण्ड

१०२	गिला बहाल किया हुआ दिवालिया यदि कर्तुं लेवे ...	१९
	—बहाल होनेमें पहिल ५०) ६० से ज्यादा वर्ष जिया हो तो १ मासकी जेलकी सजा जरूर होगी ...	१००
	—वैसी दशमें सजा न होगी और वैसा हान्तमें अपराध न माना जाएगा ...	१००
१०३	कुछ जुर्मानेके लिये दिवालियेका सजा दिया जाना ...	१००
	—जब दिवालियेने बड़ी घाता न पैदा किया हो, धोखा दिया हो या छिपाया हो या जाल बनाया हो ...	१००
	—पूछा जाना खर्च किया हो, खिस्टाही न हो, या बदल दिया हो या ऐसेही अन्य काम किये हों ...	१००
	—अपना लहना छिपाया हो, जायदाद बचाई हो, या फोन किया हो, धोखा दिया हो ...	१००
	—किसी एक लेहनदारको सजा दे दिया हो दूसरोंको कम या कुछ न दिया हो ...	१०१
	—ऊपरके जुर्मानेके साबित होने पर २ साल जेलखानकी सजा दिवालियेको दी जावगी ...	१०१
	—प्राविन्सल फुडरस कपया उठा लेना जर्म नहीं माना गया बरु सजा दिवालियाका ही है ...	१०१
	—सजा देनेके लिये मुद्देबंदी, दिवालियेकी जयत साबित करना चाहिये ...	१०१
	—दिवालियेकी कोर्वाई जारी रहते समय फोर्जदारी मामला चलाया जासकता है ...	१०१
	—इस दफ्तरेके अनुसार दिवालिये पर जुरमाना नहीं लगा बरु जेलकी सजा होगी ...	१०१

दफा	विषय	पेज
१०४ दफा १०३ के जुमॉर्के लिये कार्यक्रम	...	१०१
—अफिशल एसायनीमे रिपोर्ट काना चाहिये कि दिवालियेने अप्रुअर अपगन किया है	...	१०२
१०५ यहाल होनेके बाद या नस्कीया होनेक बाद भी जिम्मेदारी	..	१०३

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाईयां

१०६ छोटे मामलोंमें सरसरीकी कार्रवाईयां	...	१०३
—जब दिवालियेकी जायदाद (१०००) ५० से ज्यादा न हो तो सरसरी कार्रवाई की जावेगी	...	१०४
—मामूकी कार्रवाईमें असील तब होनी जब फाईने अर्पाक करनेका हुक्म मिल जाय	...	१०४
—सरसरी कार्रवाईमें १३६३ काना बॉग दिया जावेगा, प्रिंसा रसदारी जरूरत नहीं है	...	१०४

दसवां प्रकरण

विशेष नियम

१०७ कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना	...	१०५
—रिजिस्ट्रेशन फॉर्म या कम्पना दिवालिया नहीं बनाये जासकेंगे	...	१०५
—एग्जिक्यूशन, कारपोरेशन, रीजिस्टर्ड कंपनी लिक्विडेशनमें जाती है	...	१०५
१०८ दिवालियेकी हालतमें मरने वाले कर्जदारकी जायदादका दिवालियेकी कार्रवाईके स्वत्वधर्ममें प्रबन्ध	...	१०५
—कर्जदारके या जाने पर भी वसूली जायदाद दिवालिया अदालतके अधिकारमें जासकती है	...	१०५
—किन शर्तों पर हुए कर्जदारके खिलाफ दिवालियेकी अर्जा दी जासकती है	...	१०६
१०९ जायदादका मिलना तथा उसके प्रबन्धका तरीका	...	१०६
—जब हो हुए कर्जदारके दिवालिया बनानेकी अर्जा हो तो वसूली कार्रवाईका तरीका	...	१०६
११० कानूनी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना	...	१०७
१११ एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा	...	१०८

ग्यारहवां प्रकरण

नियम (रूलस)

११२ रूलस (कायदे बनानेके अधिकार अदालतोंको)	...	१०९
—इस कानूनके कानूनी कामोंके लिये समस्त समय पर अदालतें नियम बना सकती हैं	...	११०
—किन किन कामोंके सम्बन्धन रूलस बनाना चाहिये उनका वर्णन	...	११०

दफा	विषय	पेज
११३	हलसके लिये स्वीकृति मिलना ...	११०
	विवाय कलकत्ता हार्नेमेर्टके अन्य अदानमें रुस्तकी मज्गी प्रान्तिक सरकारसे लेगी ...	१११
११४	हलसका प्रकाशित किया जाना ...	११०
	—जो रुस्त बनाये जावेगे वे सब सरकारी गजटमें छापे जावेगे ...	१११

चारहवां प्रकरण

११५	हल एस्टके अनुसार किये हुए इन्तकाल आदिका स्टाम्प या करसे बरी होना ...	१११
	—दिवानिया अरालतके बैदाया, देननाया, मोबसी, आदिके काप-जोंमें स्टाम्प बरौदा नहीं छगेगा ...	१११
	—आफिजल एसायनीकां अनी आदिमें भी कोई स्टाम्प नहीं छगेगा ...	१११
	—एसायनीकां तरफसे काप करने नाखोंकी भी कोई स्टाम्प आदि नहीं छगेगा ...	१११
११६	गजट शहादत होना ...	११२
	—सरकारी गजटमें जो प्रकाशित होगा वह शहादतमें काप जा सकता है ...	११२
११७	हलफनामोंकी तस्दीक ...	११२
	—हलफनामों, वहां पर किस अफसर द्वारा कैसे तस्दीक किये जायें उसका वर्णन ...	११२
११८	व्यवहारिक पलतीके कारण कार्रवाइयां रद्द नहीं होनी चाहिये ...	११३
	—छिन्ने आदिनी पलती होने पर वह कार्रवाई रद्द नहीं हो जावेगी ...	११३
	—व्यवहारिक पलती, नेतरतीनीके सबबसे वह काम रद्द नहीं हो जावेगा ...	११३
११९	ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे ऐक्टका लागू होना ...	११३
	—अगर दूरी सुद दिवालिया हो जाय तो बरद दिया जावेगा ...	११४
१२०	सरकारको पाबंद करने वाले कुछ नियम ...	११४
	—गजोंका एक हुमेसे पढ़के अदा किया जाना, तरकीया, आदिनी पाबंदी सरकार पर भी है ...	११४
१२१	मुलाकात के अधिकारों की वधत ...	११४
१२२	उन हिस्सा रसदीका सरकारको मिलना जिनका कोई दावेदार न हो ...	११४
१२३	दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दावे ...	११५
	—लेनदारके रुपया न देने पर अब सरकारमें जमा हो जाने तो कैसे वापिस मिलेगा ...	११५
१२४	दिवालियेकी किताबोंका मुयाजना व कब्ज़ा ...	११५
	—दिवालियेके नदी खानों पर समते पढ़के क्रमता एसायनीका होगा ...	११५
१२५	फीस ध.....की सैकड़ा ...	११५
१२६	अदालतें एक दूसरेकी सहायक होगी ...	११६
१२७	कानूनोंकी मसूखी ...	११६
	—तीसरी सूचीमें जो कानून बनाये गये हैं वे सब मसूख कर दिये गये हैं ...	११६

पहिली सूची (First Schedule)

क्रजकुवाहों (लेहनदारों) की भीटिंग

१ कजकुवाहों की भीटिंग ...	११७	१३ कजकुवाहों का मानन जोड़ देने के लिये कहने का अधिकार ...	१२०
२ भीटिंगका युगाया जाना ...	११७	१४ शरीरकदरता सुवृत्त ...	१२०
३ भीटिंगके नोटिस ...	११७	१५ एसायनोंके अधिकार कर्ता साबिन माननके कारण ...	१२०
४ दिनालिकिका इनदार ...	११८	१६ मौकसी ...	१२१
५ नोटिस न पहुँचने पर भीटिंगकी कार्यवाहीका रद्द होना ...	११८	१७ प्रार्थनाकी दस्तावेज ...	१२१
६ नोटिसके जारी होनेका सुवृत्त ...	११८	१८ प्रार्थनाका आम अधिकार ...	१२१
७ भीटिंगका कर्ष ...	१२८	१९ भीटिंगकी तारीखसे १ दिन पहले प्रार्थनाका दाखिल किया जाना ...	१२१
८ बेयरमिन ...	१२९	२० आफिसल एसायनोंका स्वयं प्रोवता होना ...	१२१
९ बोट देनेके अधिकार... ..	१२९	२१ भीटिंगका बन्दा दिया जाना ...	१२१
१० कुछ कर्जोंके हस्त-पक्ष बोट नहीं दिये जायेंगे ...	१२९	२२ कार्यवाही विवरण ...	१२१
११ महसूला बसौलवाह ...	१२९		
१२ उन दस्तावेजोंका सुवृत्त जो काबिल तला- मिलेके हैं ...	१२९		

दूसरी सूची (Second Schedule).

कर्जोंके सुवृत्त

१ सुवृत्त दाखिल करनेका समय ...	१२२	१५ जबकि कामानत बादमें बपुल हो तब सशोधन ...	१२५
२ सुवृत्त दाखिल करनेका तरीका ...	१२२	१६ हिस्सा रसरीके बचि रहना ...	१२५
३ हलफनामा दाखिल करनेका अधिकार ...	१२२	१७ पानेकी हद ...	१२५
४ हलफनामोंमें कपल मान दिखलाई जाना चाहिये ...	१२२	(रेहनकी जायदादका हिसाब व घेचना)	
५ हलफनामोंमें कामानतका जिक्र होना ...	१२२	१८ रेहननाम आदि की तहकाशत ...	१२५
६ कर्ज साबित करनेका कर्ष ...	१२३	१९ दस्तावेज इन्तबाल ...	१२७
७ सुवृत्त देनेके व जसका मुआयना करनेका हक ...	१२३	२० निकाका कपया ...	१२७
८ सुवृत्तों कटेका घयाया जाना ...	१२३	२१ तहकाशत पर कर्तवारी ...	१२८
(महफूज कर्जकुवाहोंका सुवृत्त)		२२ समय समय पर कपयेकी आमदनी ...	१२८
९ जबकि कामानत बसुवरी या उखी हा ...	१२३	२३ सुद ...	१२८
१० जबकि कामानत जोड़ दी गई हो ...	१२४	(चह कर्जों जो भविष्यमें अदा होना चाहिये)	
११ दूसरे मामलोंमें सुवृत्त ...	१२४	२४ भविष्यमें उग्रये जाने वाले कर्ज ...	१२९
१२ कामानतकी कीमतका लगाया जाना ...	१२४	२५ सुवृत्तका मान लिया जाना व सारिन होना... ..	१२९
१३ कीमतमें सशोधन ...	१२५	२६ बेकायदा सुवृत्तका सारिन होना ...	१३०
१४ ज्यादा बसुवृत्त हो जाने पर लौटा दिया जाना ...	१२६	२७ सुवृत्तके बारेमें अदा-तके अधिकार ...	१३०

तीसरी सूची (Third Schedule).

प्रान्तिक कानून दिवालिया एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०

**Provincial Insolvency Act,
No. 5 of 1920.**

भारतके समस्त प्रांतोंमें प्रचलित
सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र
नज़रों एवं उदाहरणों तथा अन्य
कानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :-

वाचू रूपकिशोर टाण्डन

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एत० एडवोकेट

प्रकाशक :-

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :-

कानून प्रेस, कानपुर

The Provincial Insolvency Act.

Act No. 5 of 1920.

प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन् १९२० ई०

भारत व्यवस्थापिका सभा (The Indian Legislative Council) द्वारा

पास किया हुआ और

ता० २५ फरवरी सन १९२० ई० को गवर्नर जनरल महोदय

द्वारा स्वीकृत किया हुआ

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउनस (Presidency Towns) तथा रगूत को छोड़कर शेष ब्रिटिश भारत (British India) की भदालतों में प्रयोग किये जानेवाले कानून दिवाला को सम्प्रदात तथा संशोधित करने के लिये बनाया गया है।

सूची यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दिवालिया सम्बन्धी कानून जिनका प्रयोग प्रेसीडेंसी टाउनस तथा रगूत को छोड़कर ब्रिटिश भारत की शेष सब भदालतों में होता है सम्प्रदात तथा संशोधित किया जावे अतः नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है।

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) यह एक्ट सन् १९२० ई० का प्रान्तिक कानून दिवालिया (The Provincial Insolvency Act 1920) कहलायेगा।

(२) सूची में दिये हुए जिलों (The Scheduled Districts) को छोड़कर यह एक्ट समस्त ब्रिटिश भारत में लागू होगा।

व्याख्या—

यह कानून कहां पर लागू नही होगा और विस्तार—यह प्दान रहे कि यह कानून प्रेसीडेंसी टाउनस (बलुक्ता, बम्बई, मद्रास के शहरों) और त्रिचची, रगूत तथा नीचे सूची में दिये हुए स्थानों में लागू नहीं होगा बल्कि अंग्रेजी भारत के सब हिस्सों में लागू होगा।

सूची में दिये हुए जिले जिनमें यह कानून लागू न होगा—सूची में दिये हुए जिलों का अभिप्राय उन जगहों से है जो सन् १८७४ ई० के शिन्धून डिस्ट्रिक्ट एक्ट न० १४ (The Schedule District Act XIV of 1874) की पहली सूची (The First Schedule) में दी हुई हैं वर मगर यह है उन जगहों में यह कानून लागू न होगा—

करते हैं परन्तु इस ऐक्टमें इस सम्बन्ध अर्थात् केवल कर्जों (Debts) से सम्बन्धित बाध्यता जो इस ऐक्ट की दफा ३८ के अनुसार स्थापित किये जा सकतों हैं।

महकाज़ा (बी) इस कलाकमें अदालत जिला (District Court) की परिभाषा दी गई है। पुराने ऐक्टमें कोई शब्दसी परिभाषा दी गई थी परन्तु इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार अदालत जिला (District court) को प्राप्त है और इसी शब्द (District court) का प्रयोगभी ऐक्टमें किया गया है इस कारण इसी परिभाषा दे दी गई है।

महकाज़ा (सी) इस कलाकमें प्रयोग किये हुये बियॉक्का टब्लेस दफा ७९ व ८० तथा एपेंडिक्स (Appendix) में दिये जा।

महकाज़ा (डी) (Property) 'जायदाद' शब्द की पूरी परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है। इस शब्द का प्रयोग जायदाद मनकूला, (Moveable), और मनकूला (Immoveable) तथा उन दावों के लिये (Actionable claims) किया गया है जो क़रिज नाशिम है।

मेसेस कापी मर्से इसकाजल जो छोटेया 11 Ind Case 14 में यह निश्चित हुआ था कि अगर कोई माल किसी अदालतके सुप्रीममें बेचनेके लिये दिया गया हो और अदालतके उस मालके अन्वयदा करनेका अधिकार हो तो कानून दिवाला (Insolvency Act) के अनुसार वह माल अदालतके जायदाद (Property) समझा जावेगी और वसूली भी अपने अन्वयदा करने में छे सकता है।

ऐसा ही बात रिमथ बनाम हलाहाद बैंक 23 All. 131 में निश्चित की गई है।

अमनादास बनाम बिनायक 10 Ind. Cas 698 में यह निश्चित हुआ था कि लाठी कर्माई भी जायदाद समझना चाहिये। रामचन्द्र बनाम झापाबास 19 C L J. 83 में यह तय हुआ था कि समझनाइसी जायदाद है। अधिकारानन्दन विस्वास 3 Cal 434 के मामलेमें यह तय हुआ था कि कानून दिवालाके अन्वयदा जायदाद समझना चाहिये। अनन्तमिह बनाम बालबासिह 48 Ind Cas. 526 में यह तय हुआ था कि अविनक्त मिताश्रम हिन्दू धरानमें दिवालाके का जिला मया हुआ हिस्सा जायदाद न समझी जावा चाहिये।

हमसुलतय सुन्माल बनाम राधागोहन 54 Ind. Cas. 93 में यही निश्चित हुआ था कि यदि किसी मिताश्रम हिन्दू धरानमें वित्त दिवालाके कारर दिया जावे और जिन कर्जोंके लिये वह दिवालाके कारर दिया गया हो नर्जित कायोंके लिये न लिए गए हों तो उस दिवालाके जायदाद तथा उसके अन्वयदा कर्जांग हिस्सा सब रितावर (Receiver) की सुप्रीममें आ जावेगा। वरदलाकाबा 2 M.L. 15 के मामले में यह तय हुआ था कि टूटकी जायदाद दिवालाके जायदाद नहीं मानी जावेगी क्योंकि उस जायदादकी अपने क यदेके लिए अलहदा कामका अधिकार टूटकी दिवालाके नहीं है।

महकाज़ा (ई) इस कलाकमें महकाज़ा व जिला महकाज़ा कर्ज स्वाहानका शिक है। महकाज़ा (Secured) कर्जान्वाइसे तात्पर्य इस अर्थसेवाइका है जिसने अपने कर्जोंके लिए कोई जमानत ले ली हो अर्थात् वह अपने कर्जोंको कर्जदारकी जायदादके वसूल कर सकता हो चाहे जायदाद कर्जदारके हावमें हो या उसने किसी दूसरेको दे दी हो और ऐसे कर्जसेवाइका इतक और जिला महकाज़ा (Unsecured) कर्जसेवाइके इकते पड़ले होगा अर्थात् जिला महकाज़ा कर्जसेवाइका या तो कर्जदारकी जायते जगहा कर्जों वसूल कर सकते हैं या उस जायदाद से वसूलकर सकते हैं जो महकाज़ा कर्जसेवाइके बर्ग उक्त जगह पर नये।

कर्जसेवाइका कर्ज जिस जायदादके लिए सुस्थित किया जाता है उसे जमानत (Security) कहते हैं।

महकाज़ा (एफ) इतकाल जायदाद (Transfer of property) का अर्थ केवल जायदादकी इतकाल कर देने, लिख देने या दे देनेसे नहीं है बल्कि जायदादके हक व उधने धनकोने इतकाल कर देने, लिख देने व दे देने से है।

उपदफा (२) बहुतेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग शा एक्टमें दिया गया है परन्तु उनकी कोई परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है। गो उनकी परिभाषा जानता दीवानोंमें दी गई है उन शब्दोंका अर्थ वही समझना चाहिए जो जानता दानाओंमें दिया हुआ है उदाहरणस्वरूप हुक्म (Order), गनकूला जायदाद (Moveable property) दिक्री (Decree) आदि शब्दोंकी परिभाषा जानता दीवानोंमें दी हुई है परन्तु इनकी परिभाषा शा एक्टमें नहीं है इत्यादि।

पहला प्रकरण

अदालतका सङ्गठन तथा उनके अधिकार

(Constitution & Powers of Court)

दफा ३ दिवालेकी कार्रवाईके लिये अधिकार की सीमा

(१) अदालत ज़िला (District Court) को इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार प्राप्त होगा:—

परन्तु प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सरकारी गज़ट द्वारा घोषणा प्रकाशित करके अदालत जिलाकी मातहत किसी दूसरी अदालतको, किसी खास किस्मके मामलात करनेका अधिकार दे सके और इस प्रकार जिस मातहत अदालतको अधिकार दिया जावेगा उसको अपने अधिकारकी सीमामें वही अधिकार प्राप्त होंगे जोकि अदालत जिलाके इस ऐक्टके अनुसार प्राप्त है।

(२) इस ऐक्टके लिये अदालत खकीफाभी अदालत जिलाकी मातहत समझी जावेगी।

व्याख्या—

क्लाज़ (१) अधिकारकी सीमा (Jurisdiction)—अदालत जिला प्रधान दीवानी अदालत है जिनको मूल अधिकार प्रेसीडेंसी डाउन्स व ग्यूनकी ओड़कर अन्य जगहोंमें प्राप्त है और अदालत जिलाके हाकिम को जिला जज (District Judge) कहते हैं। इसलिए जिला जजनी अदालतकी दिवालेकी दायरेमें सुनने का अधिकार है।

अदालत जिला उसी समय दूसरी अदालतोंकी करीवाई इन्साल्ट डिस्ट्रिमें इस्तखेफ कर सकती है जबकि वह इस ऐक्टके अनुसार काम करती हो आर दूसरी सूतमें उसे ऐसे इस्तखेफ करनेका अधिकार नहीं है अर्थात् जब मद्रून दिक्री दिवालिया करा दे दिया गया है या उसकी जायदादके लिए रिसीवर चुर्खेर कर दिया गया है उस समय सैरियत अदालत दिवालियाके अदालत जिलाको दूसरी अदालतोंकी इन्साल्ट डिस्ट्रिगे कार्रवाईमें इस्तखेफ करनेका अधिकार प्राप्त है देखो—अबूकूमर बनाम केशोदात 39 All. 547.

सहकारी जिला जज (Additional District Judge)—सहकारी जिला जजके उन कामोंको करेंगे जिन्हें जिला जज उनके सिपुर्दे करे और उन कामोंके करनेमें उनको वही आदेश प्राप्त होंगे जो जिला जजको प्राप्त है।

सहकारी जिला जज—जिला जजका मातहत नहीं है, देखो—मास्टरनल बनाम भीताल 34 All. 382; 9 A. L. J. 371. ऊपर दिए हुए मामलेमें अपीले समय यह भी प्रश्न उठा था कि जूनि (एवैक्लनल)

[illegible]

नोट (PROviso)—प्रारंभिक सरकारों यह आदेश प्राप्त हुआ कि वह अपना किन्ना मातृत्व अश्वत्थी जो कि अश्वत्थी इन गरीब मातृत्व द्वा दिवसलियास काय कनेस आधारा द सुनने परतु दस प्रकाश अधिकर देने की अर्वा प्रारंभिक सरकारों गजमें प्रकाशितना आना चाहिए और गजमें प्रकाशित कीदेई इन प्रारंभिक व प्रथम यह नी प्रकट किया गयात चाहिए कि किस प्रकारके मामले सुननेका आदेश उन मसलत अश्वत्थी दिया गया है ।

बूकि (Proviso 4) Class of cases (जिस किस्मके मुकदमे) का उद्देश है इसमें यह प्रश्न सीधा है कि प्रार्थक सरास मातृत् अश्वत्थों। इवमिति का मसके सुनकर अभिप्राय देते समय यह बात सती है कि अश्वत्थ मातृत् किस्म के मुकदमे सुनेगी परन्तु वह उसकी अभिप्राय मातृत् परिलक्षित नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका भी उद्देश Proviso (4) में अवश्य दिया जाता—तात्पर्य यह है कि आठव मातृत् इस ऐक्यके लिए प्रार्थक सरास दादा प्राप्त अभिप्रायों केवल अपा अभिप्राय सीमा में ही प्रयोग कर सकता है उसके बाहर नहीं।

किसी मान्य अदालत (Any Subordinate Court) से अभिप्राय यह है कि इसको भी विचारपूर्वक समीक्षा करने का दिया जा सकता है।

यदि, किसी अद्वैतवादी विद्वान् दाखिल करते समय उनसे छानने का अधिकार प्राप्त न हो, परन्तु उसे विधिमान् के सम्मुख पक्षों पर अधिकार प्राप्त हो जाय तो ऐसा अद्वैतवादी कदाचित् उचित फैसला, मन्त्रा-मन्त्राणां, वैदिक दृष्ट्यादयः पत्राणां सम्मुख 6 A L J 483, 2 L C 223

दफा ४ दिवाल्लेके सब प्रदनोंफो तय करनेके लिये अदालतके अधिकार

(१) यदि अदालत के सामने कोई दिवालिया सामग्री हो तो वसम जो प्रथम अदालत के सामने आवे या जिन प्रश्नों को निश्चित करना अदालत पूर्ण न्याय के लिये अथवा जायदाद को पूर्ण रूप से बाँटने के लिये उचित या आवश्यक समझे तो उन सब प्रश्नों जो तब कानून के पूर्ण अविचार अदालतको होना यदि वह अतः कानून हो या चाकियाती या साहेबद हकिफत क हां या हऊ माकूद (Priority) के हां या और किसी किस्मके हां परन्तु साथ साथ इस प्रोटोक नियमका पालन रखना आवश्यक है ।

(२) इस एकद के नियमों का पालन करते हुए तथा किसी दूसरे प्रचलित कानून की परवाह न करते हुए जो निर्णय अदालत करेगा वह अंतिम निर्णय होगा तथा यह निर्णय उन सब बातों के लिये माननीय होगा जो कर्तव्यवाद या उच्चरी जायदाद और इनक या टक्के हकदारों या हकदारों के हकदारों के लिये माननीय है।

(३) जब कि अदालत किसी ऐसे प्रश्नका भित्तका इच्छेय पहिची उपपत्ता में है तब कानून स्थित है। बा इच्छेय न खड़े पान्नु उसे विस्वास हो कि कर्मजवाहका देखनेका हक किसी जागदासमें पहुँचता है तो ऐसी धारतमें अदालतनहीं अधिकार है कि वह बिना अधिक जाँच परतान किये हुए जिस प्रकार वे जिन धर्मों के साथ सहे कर्मचार के ऐसे हक का देख सकता है।

उद्यारूपः—

इस दस्तावे के अनुसार आगस्त दिनांक १५ को वही दिवस अधिकार प्राप्त है । अतः १५ दिनांक, एक या दो प्रश्नों के जामना हक परिलक्षित है तथा कर सन्धी है । इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह जिन भी विषयक मामलों को वह चाहती है या चाहे वह वाक्यांशों को तथा वह सन्धी है जो कि किमी दिवाके मामले उसके सामने आये या जिने वह अब मामल के ठीक तो से फैसला करने में तय करना उचित समझ ।

यह प्रश्न नीचे दिये हुए मामलों में तय किये जा चुके हैं:—

हमिचन्द्र बनाम मीनता 48 All. 411, 24 A. L. J. 4951; मरुतना कुत्रा बनाम डेविड 46 All. 16, 21 A. L. J. 737, आफिश्च रिनीवर बनाम सीत्यशम 97 I. C. 321; राम स्वामी केठियार बनाम राम स्वामी अयगर 43 M. L. J. 165

यदि अज्ञात दिशक्तियामें उचित रूपमें हम दक्षिण अनुगत दृष्टिवात् दी गई हो, तो उमें अधिकार है कि वह हमें सतर्कता को कि असा जायदाद प्रदानिगी सी है या नहीं है तब कर सखती है, देखो—चित्तमल बनाम पोन्नू स्वामी ७० M. L. J 180, 92 (C 573).

इसी प्रकार अदालत दिवंगिता को अधिवार प्राप्त है कि वह इन दोनों प्रश्नों को एक साथ ही तय कर सकती है यह कि दिवंगिता वाणिज्य नियमों के तहत व्यापारों को देना है तथा उसकी मालिकाना वहा तक है, देखो—पन्ना १६७९।
पन्ना १६७९। A. J. R. 1926, Lab. 679.

२. जब कि अधूनतम दिनाङ्किके समाप्ते दृष्टा ५३. हातून हात्तास व्यवसायदे अत्रेभार यह प्रथम उपरिषद हेजे कि दोहे अन्यास आधुनिक कालिग गस्तुस, दे तो उमे चाडिगे नि वह ऐसे प्रयत्न किताब करते समय रिखीवर ही की रायरी पूर्ण रूपे मही न पाव से बरिह प्रेगे प्रशास, र्यां कानूनक अत्रेभार सुनकर तय करे, दखो—सिद्दिपत्तद बनाम अमीन अली 44 All. 71; 19 A. L. J. 86.

६।५३ जानून इतका जायतो अनुसार पेना हू प्रथमो सरासिमे तय नही करना चाहिये किन्तु उसे गन
६।५४में बचाना हू नियमों अंगार दख काना चाये. देखो—सरना मनाप मेरोर ३ I. R 1923 Oudh. 109.

इस दस्तावे अनुसार अत्राउक्त तीसरे दोषजनक हकका अवलियन तथा करने में पूर्ण अभिमत प्राप्त है, देखो—गज़ट
अवगत पृष्ठ 61 I. C. 589

इस। अभिप्राय यह है कि जब निम्नलिखित निम्नी जायदादको दिवसिर्वाही जायदाद द्वारा देकर वैयक्त चान्नी हो तो हीमिरे सुपक्षको जिराया दे। कि वह इस दफ्ति अनुसार अज्ञात तिलामे अपना हक उस जायदादके सिधे पेग पर मयदा है। देखा—बेन्पा चन्डिया वनाय समनाशन केन्डिया 17 Madras 446, A I K 1924 Mad 529, रादप्या वनाय मायम 2 Loh 147; 61 I C 332-

पाहुन ता गे रा मी यह भी उचित है कि वह जयंती एक उस जागरण के लिए मनाई जाए जिसके
अन्तर्गत दूसरी दैवीय अज्ञानता भी दूर हो जाए और सत्य है, देवी देवता बनाम बिहू A. I. R. (1925) 3
N 369, हरनाथ समाज बनाम A. I. R. 1923 Loh 224

जबकि किसी हिंदू मीतके दिवाणिया करार दिए जाने पर सिविलर उसकी कुछ खानदानी जायदाद पर कब्जा कर लेवे और उसके पक्षके इस बिना पर मि पिताने कर्जें गर बावनी थे, व बंदकबन्दीके लिए, लिए गए थे पुराज करें तो अदालत दिवाणियाको अधिकार है कि वह ऐसे प्रश्नको तय कर सकती है, देखो सन्तप्रसाद बनाम शिवदत्तसिंह 2 Pat. 724.

हकके प्रदन किस समय तक नहीं लिये जाना चाहिये—जो कि इस दफाके अनुसार। अदालत दिवाणिया को हर प्रकारके हक आदिके मामले तय करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु जहां हम प्रकारके महान प्रश्न या अस्वाभाविक उत्पन्न आ जावे वहां अदालतको चाहिए कि वह फर्जनेसे ऐसे मामलेकी जायदाद दावा दायर करे तय कर लेकी वह देखे, देखो—राधाविहारी बनाम आशिशाल एमथनी 25 O. W. N. 852, फूलडुमारी बनाम खिरोड 31 C. W. N. 502, 44 Mad. 524, 66 I. C. 863 (All).

अदालत दिवाणियाको चाहिए कि वह उस समय हकके प्रश्नोंसे तय करनेकी कोशिश न करे जबकि उसके माहूम हो जावे कि ऐसे प्रश्नको तय कर देने पर भी वह जायदाद पर कब्जा रखने वाले सम्बन्ध कब्जा न दिया संजोगी क्योंकि दिवाणियाको खुद भी उस जायदादमें मोखदा हक ऐसा नहीं है कि जिसमें वह कब्जा रखने वाला व्यक्ति इयाया आ सके, देखो—आशिशाल सिविलर बनाम परबल सिंह A. I. R. 1924 Mad. 87.

मामलोंको तय करनेका तरीका—हक आदिके प्रश्न तय करनेमें अदालत दिवाणियाको चाहिये कि वह मामूली अज्ञात दीवानोंके नियमोंका प्रयोग करे। अर्थात् अदालतके सामने दफ्तरातमें वह सब बातें दिवाणिया जाना चाहिये जोकि अजीदावामें दिखलाई जानी हैं और तब दूसरे फर्जको उसकी जवाबदेही करना चाहिये। इसके बाद तनहीं कीमाया चाहिये और तब जायदादीवानों व कानून सारादाके अनुसार उन प्रश्नोंका फैसला होना चाहिये देखो—विहामल बनाम चोन्न्नामी 49 Mad. 762, शिर्षप्रसाद बनाम अजीजखली 44 All. 71-19 A. L. J. 862.

अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata)

खपदका (२) का अतिप्रथम है कि अदालत दिवाणियाके फैसले अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) समझना चाहिए देखिये मिथीलाल बनाम रमैयालाल A. I. R. 1922 All. 128. दफा ११ जायदादीवानोंमें अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) का उल्लेख है। यह कहा जासकता है कि उस दफाके अनुसार नहीं अप्र तजवीज हुदा समझ जावेंगे जिनके हुन जानेका अधिकार पहिली अदालतकी रहा हो और पक्षी बाव अदालत दिवाणियाके लिए भा कहा जासकती है कि उसे अदालत दीवानोंके मामलेको सुननका अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए उसका फैसला अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) नहीं समझना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। इस दफाके अनुसार किया हुआ अदालत दिवाणियाका फैसला आखिरी फैसला है और हर एक फर्जनेके लिए माननीय है और वह फैसला द्वारा किसी अदालत दीवानोंमें नहीं उठाया जासकता है देखो—बहा बेराम बनाम देवनाथल A. I. R. 1923 All. 293

परन्तु वह बात, जिसका फैसला नहीं किया गया अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा देखिए नीरा बनाम नवाब सुल्तान 64 I. C. 523 (All) अगर किसी कर्जलेखने यह प्रश्न अदालत दिवाणियाके सामने उठाया हो कि दिवाणियाके कोई इतकाज जायदाद, पोखानेदीनी था और वह प्रश्न उसके विरुद्ध तय किया हो तो उसको अधिकार नहीं है कि वह दूसरा इस प्रश्नको उठा सके कि वह इतकाल जायदाद, फर्ज व पोखानेदीनी था पहिला फमला अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) ऐसे मामलेके लिए समझा जावेगा देखो—मथल बनाम हादतल 16 N. L. R. 201.

इस दफाके आधार पर अदालत दिवाणियाका एतर्फी फैसलाभी उस सूत्रमें अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) समझा जावेगा जबकि किसीबरेन दफा ५३ के अनुसार दिवाणियाके किसी इतकाज जायदादको फर्जों के तय देनेकी दखलातदी हो और उसकी इतरा पुतकितअवेह (Transfere) को हो जावे ऐसी सूत्रमें वह सुतकितअवेह

(Transferee) द्वारा इस्तक़ागिया मुवदमा इस अन्तर् लिखे दायर नया कर सकता है कि वह इतकाल मायदाद सही या और उस न्यायदाता वह माफिक ह दफा—कनीज़्का विमा बनाम गायनसिंह 24 A. L. J 897.

अदालत दिवालियाके हुजूमोंकी इजराय—अदालत दिवालियाके हुजूमोंकी इजराय दफा ५ में लिखे हुए नियमोंके अनुसार होनी अर्थात् अदालत दिवालयाने इजरायके सम्बन्धमें नई अधिकार प्राप्त होने जो उसे मूल दीवानोंके अधिसूचियों वगैरे में प्राप्त हैं, एको—गयसखानी चेष्टियर बनाम अफिसर रिनीजर मद्रास 4231 L J 185, 651 C 334.

अपील—इस दफाके अनुसार लिखे हुए कैमरेकी पहिली अतीत हार्डिमेंटें दफा ७५ (२) तथा सूची न० १ (Schedule 1) के आशय पर हो सकती हैं। यदि इस दफाके अनुसार किसी माददा अदालतने फैसला किया हो तो उसकी दूसरी अतीत (कानूनी मसल पर) हार्डिमेंटें दफा ७५ (१) के आधार पर भी जा सकती हैं। दूसरी अतीत आता दीवानोंकी दफा १०० में लिखे हुए नियमोंके अनुसार ही जानकीगी अर्थात् (१) उस समय जब कि कोई कानूनी मसला तय होनेमें होवे (२) उस समय जब कि कोई नक़्क़ी तय होवे तब तय होवे (३) जब कि कोई विशेष पत्रती या बरक़दारी मामलके सुननेमें बोलाई हो। मियाद अपील दफा ७५ (४) में दी हुई है, दफा—सेठ रिज्वाज़ बनाम गिरधारीदास A. I. R. 1924 Nag. 361, 19 A. L. J 862.

जब कि अदालत दिवालियाने उपदफा (३) के अनुसार बर्तक़ाईकी हो तो अदालतकी आज्ञा देने पर अपीलकी जा सकती है देखो—दफा ७५ (३)

चुकि अदालत दिवालियाके फैसलें अपीलकी जा सकती हैं, इस कारण यदि अदालत किसी मामलेसे इनकार करे तो उस इनकारकी भी अपील जा सकती है, जैसा कि नयनगर बनाम शम्सुद्दाय 52 Cal. 662. में तय हुआ है। यह सब फरज़ना हार्डिमेंटें ही दूसरे किसी हार्डिमेंटें राय इस नियममें खगोलक कुछनी नहीं है और न दूसरी पड़नेहीसे यह तय पाया जाता है।

जब कि बेसा मुद्देयाके देवरक सिलाफ किसी मुक़द्दमें कोई नयदाद कर्त की गई हो और मुद्देयाका आँक २१ रु० ५८ जाबता दीवानोंके अनुसार एतगज़री दरग़ाना देने और उमक़ वाददा उसका बंड देना दिवालिया कर दिया जावे तथा रिहोव उम देवरकी जगह करीक़ मुद्रमा बन जावे और मुद्देयाके दुबारा एतगज़री दरग़ाना दो पर वह दरख़ास्त नामज़र हो गई हो और इसके बाद मुद्देयाने वालिख, अपना हक़ साबित करनेके लिये दायरकी हो या यह तब पाया कि ज़दा त दिवालियाने फैसला जितम कि उनने मुद्देयाके एतराजको तय किया हो दफा ४ के अनुसार नई कमज़ सग़लना चाहिये और दुबारा उसके लिय कोई नया मुक़द्दमा नहीं दायर किया जानक़ता है। यह भी तब हुआ कि आँक २१ रु० ५८ के अनुसार दिया हुआ हुक़म कबई हुक़म नहीं है और उसके लिय नया मुक़द्दमा दायर जात जानक़ता है देखो—तमरानी बनाम मिह्मल बनाम जवाहिरलाक़ मदनलाक़ A. I. R. 1228 All 158

कानून दिवालियाकी दफा ४ (१) का प्रथम नियमित मुक़द्दमेंके अनुसार तय किया जाना चाहिये अर्थात् सब फरज़ोंकी सूचना दी जाना चाहिये तथा उनके बयान तदरीफ़ आदि ख़िखल होना चाहिये उनके काग़ज़ात ख़िखल कराना चाहिये तथा उनकी शहदत सुनी जाना चाहिये देखो—गनीमुद्दना बनाम दीनानाथ पुरी 108 I. C. 602, A. I. R. 1928 Lah. 556

इलावाइत हार्डिमेंटें सामने दो प्रश्न हज़ करनेके लिये रखे गये थे उनमेंसे पहिले प्रश्नको उत्तर दिया गया था पन्नु दूसरे उत्तरकी आवश्यकता नहीं मग़ज़ी गई थी पहिले यह कि यदि कोई इतराज नयदाद दिवालिया केग़र दिए जानने दो सात पड़िये हुआ हो और उस इतराजके लिये इक़फ़ा प्रश्न उपस्थित हो तो क्या अदालत दिवालिया को कानून दिवालिया की दफा ५३ के तालाफ़ोस ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नको तय करके तय बर्तक़ाई प्राप्त है। हार्डिमेंटें, ज़ जमाने इदुनने यह तय किया था कि अदालत दिवालियाका एमे प्रश्न तय नग़ोस बर्तक़ाई प्राप्त है।

इस प्रश्नको तय करते हुए नटुपन वाले नवोंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि यदि कोई मामला किसी अमनवीके खिलाफ भी अदालत दिवालिया से तय कर दिया जावे तो अदालत दीवानी उस फैसलेके विरुद्ध नहीं आसनेगी अर्थात् दफा ११ कायदा दीवानों लागू समझी जावेगी जैसा कि A. I. R. 1926 All. 470; A. I. R. 1927 All. 66 आदि में तय किया जाएगा है।

दफा ४ में अधिकारका वर्णन है और उसके बाद दूसरी दफाओंमें जो अधिकारोंका उल्लेख है उनका ध्यान रखते हुए ही दफा ४ में वक्त किये हुए अधिकारको समझना चाहिये। दफा ५३ व ५४ में अदालत दिवालियाके अधिकार सीमाका वर्णन नहीं है उनमें केवल वही रतलाया गया है कि अदालतमें उपस्थित होने वाले सात २ प्रत्येकी तय करते समय किम निर्णयोंका ध्यान रखना उचित है इस प्रकार उन दफाओंका कोई प्रभाव दफा ४ पर नहीं पड़ता है जो दफा ५६ का प्रभाव अवश्य पड़ता है अदालत दिवालियाको अधिभार है कि वह ऐसे प्रश्नों तय कर सके कि दिवालियाका हक किसी जायदाद पर पहुँचना है या नहीं परन्तु ऐसे प्रश्नों तय करते समय दूसरा फीकटो भी यथोचित अवसर उस दफा बालके सम्बन्धमें जाया दे दी करनेके लिये देना चाहिये। देखो—A. I. R. 1929 All 105.

दफा ५ अदालतके साधारण अधिकार

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको इस एक्टकी कार्रवाई वसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार वह दीवानोंके मूल अधिकारों को करने में करती है।

(२) ऊपर लिखे अनुसार हाईकोर्ट व मद्रास जिलाको अपनी मातहत अदालतके फायों के लिये वही अधिकार होंगे और वसी प्रकार बने जावेंगे जो अधिकार उनकी दीवानी मामलोंमें प्राप्त है व जिस प्रकार उनमें यह बतें जाते हैं।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको उन नियमोंके अनुसार भी कार्य करनेका अधिकार प्राप्त है जिन नियमोंका प्रयोग अदालत दीवानी किया बम्की है अर्थात् जायदाद दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अदालत दिवालिया भी काम कर सकती है केवल विरोधता यह है कि अदालत दिवालियाको चाहिये कि इस एक्टमें दिये हुए नियमोंका उद्भव न करे अर्थात् यदि इस एक्टमें बताया हुआ कोई नियम जायदाद दीवानोंमें नतलपड़े हुए किसी नियमके विरुद्ध पड़ता हो तो अदालत दिवालिया ऐसी सूत्रमें इस एक्टमें बताया हुए नियमोंके अनुसार कार्यवाही करेगी। जायदाद दीवानोंके नियमों उक्त समय कोई पर्वी न करेगी परन्तु जहाँ वा इस एक्टमें किसी कार्यके करनेके लिये कोई विशेष नियम न दिया हुआ हो वहाँ पर जायदाद दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार ही कार्य किया जावेगा इस प्रकार अदालत दिवालियाको इस एक्टमें दिये हुए नियमोंके अनिवारिक उन सब अधिकारोंके बर्तनेका अधिकार प्राप्त है जो अदालत दीवानी अपने मूल अधिकारोंके बर्तनेमें प्रयोग कर सकती है।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए अधिभार केवल उनही कार्रवारोंके लिये प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार की जानेनी है अर्थात् इस एक्टमें जिन कार्रवारोंको करनेका अधिकार अदालत दिवालियाको दिया गया है उन्हीं कार्रवारोंको करनेमें वह उक्त नियमोंका प्रयोग कर सकती है। देखो—चालीन बनाम अब्दुल 15. C. W. N. 253, नीलमनी बनाम दुर्गाचरण 22. C. W. N. 704, 46. L. C. 377.

इस दफाके इस एक्टके अनुसार कार्यवाहीसे अनिवार्य उस कार्यवाही है जो किसी अदालतमें कीजाने अर्थात् यदि इस एक्टके अनुसार कोई कार्यवाही स्थानीयके सामने हो रही हो तो उसमें जायदाद दीवानोंके नियमोंके प्रयोग लिये जानिका अधिकार नहीं दिया गया है। देखो—अदालत बनाम लक्ष्मणप्रसाद 39 All 267, 37 I. C. 830, मिट्ठलीपट्टी बनाम मट्ठलीपट्टी 47 I. C. 33, 24 M. L. T. 106

इसी प्रकार यह भी तथ्य हुआ है कि रिजीवर द्वारा दिवालियाई जायदाद बेच जान पर जायदादीदारों के नियम लागू नहीं हैं। देखो—हमने न्याय प्रहमद का. २६ O C 319=74 I. C 802, रिजीवर द्वारा रिहा जायदाद का बेचा जाना दफा ५ (१) के अनुसार की कार्यवाही नहीं है और इसी कारण ऐसे बेच जाने जायदादीदारों के आर्डर २१ रु. ८२ के नियम लागू नहीं हैं। देखो—A. I. R. 1928 Ran 60, 5 Rang 768.

इस दफा के अनुसार अ. १२८ दिवालिया तथा उत्तरी अर्ध सुनवाग अदालत उस अधिकार प्रयोग कर सकती है जो जायदादीदारों की दफा १५१ में दिया हुआ है। इस प्रकार वह अपने का निजी संपत्ति को सुधार करने में देता—रामचन्द्र बनाम मजहर हुसैन ७१ I C 55 (All) का याचने लिये रिहा आवश्यक आज्ञा दी सकती है देखो—अनुष्ठ न्याय मशीन १४ C. W. N. 586.

इसी प्रकार जब मित्र कार्यवाही का गई हो या नरनीयता दिवालिया बनने के लिये दाय्यार नहीं दी गई हो तो अदालत ऐसी दरखास्त को इसी बात पर खारिज कर सकती है। देखो—गिरनारी बनाम गजलाल 32 All 645

प्राप्त उपर से हुई बातों से यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत इच्छानुसार जब चाहे जिस हक की मूल्य कर सकती है अर्थात् किसी हक को उसी समय वह खारिज करगी जबकि कानूनन उसको उक्त खारिज करने का अधिकार प्राप्त होगा। देखो—हमने आर मिथ 82 I C 575.

दफा ५ के अनुसार अदालत दिवालियाई नहीं अधिकार प्राप्त है जो जायदादीदारों के अनुसार गाम्भीरी दीवानी अदालतों को प्राप्त है और इसी कारण यदि दो कर्जदारों में किना जायदाद के लिये संपत्ति बच रहा हो तो जबतक वह संपत्ति तब न हो जाये तब तक के लिये अदालत दिवालिया एक कर्जदार को उस जायदाद के नीलाम करने में रोक सकती है। देखो—A I R 1928 Rang 241

इस दफा के अनुसार जायदादीदारों के आर्डर ९ में दिये हुए नियमों का प्रयोग भी दिवालिया की कार्यवाही में किया जा सकता है इस लिये अगर कर्जदार दिवालिया की दरखास्त सुने जाने के समय खारिज न होवे तो वह दरखास्त खारिज कर दी जायेगी। दिवालिया की अधिकार दे कि वह या तो कि उसी दरखास्त के सुने जाने के लिये दरखास्त दे या वह नहीं दरखास्त दिवालिया बनने के लिये दे सकता है। लेकिन जब वह दरखास्त दिवालिया बनने के लिये दी जाये तो उसमें यह दिखलाना चाहिये कि दरखास्त किस कारण खारिज हुई थी और अनुसार दफा १० (२) के अनुसार द्वारा दरखास्त देने की आज्ञा प्राप्त करना चाहिये। अगर अदालतों में खारिज की हुई दरखास्त के बत व न्याय कायम होने की दरखास्त मजबूत न की जाये तो इससे यह न समझना चाहिये कि नहीं दरखास्त भी नहीं दी जा सकती है अर्थात् यदि कानूनन नहीं दरखास्त देने का हक प्राप्त है तो ऐसी दरखास्त नाममात्र होने पर भी द्वारा नहीं दरखास्त दिवालिया बनने के लिये दी जा सकती है। देखो—अनुष्ठ अजीन बनाम हबीद मिर्जा 49 I. C 228.

इस दफा के अनुसार कृषी कार्यवाही करने में अदालत दिवालिया को नहीं नियम करने चाहिये जो जायदादीदारों के अनुसार दीवानी के मूल अधिकारों का बनने लिये जाते हैं। देखो—इसमत नीला बनाम भगवानदास 36 All 65

अगर कानून लेने का वाद रिजीवर या उसके किसी खरीदार के हक में प्राप्त हो तो उसके प्रयोग करने में नहीं तरीका इस्तेमाल किया जायेगा जो दीवानी के मूल अधिकारों की बनने में दिया जाता है। देखो—समस्या के डेविड बनाम आकिश रिजीवर मद्रा 45 Mad 434

इस दफा के अनुसार अदालत दिवालिया (Insolvency Court) अपने हक की नरनीयता (Reveu) भी कर सकती है जैसा कि आर्डर ५७ जायदादीदारों में दिया हुआ है। देखो—51 M L J 60, 46 Mad 405, 44 All 605

उपबन्ध (१)—इस उपबन्धमें यह प्रकट है कि जबवा दावानाके अनुसार हाईकोर्ट व जराय्व निका मानवत सदाउन या अपऑको ठीक उसी प्रकार सुन करनी ह जमाने दावानी की अपछे मुने जनेस नियम ह अर्थात् आर्टर ४१ जावन दावानामे दिने दुए नियमके अनुसार अर्थात् वा जातनी ह व मुनी जातनी ह ।

इस उपबन्धके आसार पर जबवा दावानाके आर्टर ४१ क्ल ५ के अनुसार हाईकोर्टको अधिकार है कि वह किसी मामले की सुनवाई का बंद करके टुकम दे । देखो—नगिनक्षम बनाम वेगमार्ड 56 I C 449

दियागियाके मामले की अपछे मुने समय जिन जगहो वहा खीकर प्राप्त है जो उसे मामली दावानीके मुमर्गेन अर्थात् सुननेमें प्राप्त है । देखा मन्मथल बनाम कुनविहारी 44 All 605=A I. R 1922 All 206

इन्सोल्वेंसी (Insolvency) की अपछे होने वा गियाण्ट की नाम अपछे (Cross objection) आर्टर ४१ क्ल २२ जावना दावानाके अनुसार कमेंके अधिकार प्राप्त है । देखो—41 Mad 904.

प्रिवी काउन्सिल (Privy Council) में भी की जासकती है क्योंकि एकटो बोर्ड ऐसा बात नहीं है । देखा—छपाव बनाम लक्ष्मि 40 Cal. 680 14 Cal 535

दूसरा प्रकरण

दिवालेके कामोंसे लेकर बहाल (Discharge) होने तककी कार्यवाहियाँ

धका ६ दिवालेके काम

(१) नीचे लिखे हुए कामोंके करनेसे यह मानलिया जावेगा कि बर्जदारने दिवाले का काम किया है—

(ए) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह बर्जदारने अपनी जायदाद या करीब २ सज्जायशद किसी तीसरे शख्सके सुपुर्दे करदी हों जिससे कि उसके सब बर्जदारोंको लाभ न होसके ।

(बी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह बर्जदारने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस इरादेसे अलहदा कर दिया हो कि जिससे उसके बर्जदारोंका कर्जा बसल न होसके या उसके बसल होनेमें देर हो ।

(सी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या किसी दूसरी जगह बर्जदारने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस प्रकार अलहदा कर दिया हो जो इस एकट या किसी अन्य प्रचलित एकटके अनुसार उसके दिवालिया होने पर धांसका सौदा (Fraudulent preference) मान कर नाजायज़ (Void) क़ारर दिया जावे ।

(डी) यदि बर्जदार अपने बर्जदारोंका रुपया मारने या उनका कर्जा बसल होनेमें देर कामकी बजहसे —

(१) वह ब्रिटिश भारतसे चला जावे या बाहर रहे

(११) वह अपने सन्तूनती मकान या रोजगारकी जगहमें चला जावे या और किसी प्रकार घरहाजिर हो जाव, अथवा

(१११) वह छिप जाव जिसमें कर्जदारोंको उसकी खबर न मिल सके ।

(ई) जबकि कर्जदार की कोई जायदाद उनके कर्जमें इजराय डिक्री द्वारा अधिक गद्द हो

(यफ) जबकि वह इस एक्टके अनुसार दिवालिया बनाय जानिकी दरखास्त देव ।

(जी) जबकि कर्जदार अपने किसी कर्जदारवाहका यह नाटिस द्य कि वह अपना कर्ज अदा नहीं करेगा या उसकी अदायगी न करने पर इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुआ हो ।

(घच) जबकि कर्जदार किसी अदालत द्वारा रुपयेकी अदायगी न करने पर इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुआ हो ।

मुसाला (Explanation)—इस एक्टके अनुसार कार्याई करनेके लिये कारपरदाज (Agent) का काम मालिकका काम माना जासकता है ।

व्याख्या—

दिवालेके क़ाग (Acts of Insolvency)—इस दफ़ाम दिवालेके काम की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी हुई है कि तु इसमें ऐसे ग़ागना उल्लेख है जिनक वन वा हानेसे यह माना गया कि कर्जदारने दिवालेका काम किया है । अगर इन धर्माँ बतलये हुए दिवालेके कार्योंमें से कोई भी शय दिया जाव ता कर्जदारको खप या उसके किसी भी कर्जदारका दफा १ व २० क नियमागानान रखते हुए दिवालेकी दरख्तान देवका इक हो आवेगा जैसा कि दफा ७ म बतलाया गया है अ तथा कोई न दिया क़ार दिये जानते लिय दरखास्त नहा दा नामकता है ।

जिन कर्जदारका प्रयोग २३ दफ़ाम दिन छठ काम बतल नमें किया गया है उनका प्राधिक अर्थ जसेमा तैताहा टीक तारमे समझना चाहिये क्योंकि एसा काम करावत अत्यन्त लिय बहुतसी अशुविधाएँ उपस्थित हा जाती हैं । देखा—४९ Mad 250 परातु जब दिवालेका रयका दरख्तान देवे आरवतमें यह प्रकृ कर कि वह अपने कज़ारा अदा नहीं कर सक्ता है या वाकिएतत यह प्रकृ हा कि कतदार रयकी दिवालेका बनना चाहता है तो एसा दशाम यह आवश्यक नहीं है कि दिवाली क काम की बडा अनवान की जावे देखो—A. L. R 1925 Mad 483

फ़ौनसे काम दिवालेकाके काम नहीं है—कर्जदार काग किसी कर्जदार हा या उनके एजेंटों केवल यह सूचना देवता कि वह दिवालेका है दिवालेके शय नहा समझना चाहिये । देखो—मरकायल बैक बनाम आदितियन एसोस ३० Mad 230.

आर किसी एक कर्जदारको सोग खरीदा जाव व वह मीदा फ़ुक्तरमे दूसरोंसे बेचा जाव और बिकने दामसे दूसरे कर्जदारका कर्ज चुकाया जावे ता ऐसे कामको दिवालेका शय नहा समझना चाहिये देखा—दुर्गाराय बनाम हरकिशन 23 A. L. J 536=A. I. R 1925 All 564

बिभी आदमाको दिवालिया क़ार देवता काम एक बना समान काम है इस कारण अदालतका चाहिय कि दिवालेका क़ार दमेने पहिल मला भाते अनवीन सर लेव और यह देख लेवे कि कानून पूरतया लागू है " याद कोई कर्जदार म मानता न म काम कर लेवे कि उसे बिना कर्ज वा हा क़ारा देता है और वह उस कर्जको अदा नहीं कर सक्ता है तथा इसक पशान् उस कर्ज की शृण देता वा केवल इतनाही शायन यह है मान लिया जावेगा कि उस कर्जदारन दिवालका नाम

मिया है और न एसा काम दफा ६ के गिल २ वजोंमें बताये हुए कामोंमें आता है। देखो—A. I R 1928 Mad 393 यदि कोई कर्जदार अपने कर्जखानोंकी पाग होने पर यह प्रश्न करे कि वहने अपनी सब दस्तावेजों किसी तीसरे शायिके कन्समें देदा है जिसमें कि वह शक्य उसकी सब जायदाद सब तक और उसके वजोंका निपटा सक ता उसका यह काम दिखानेका काम समझा जावेगा। देखो—A. I R 1928 Mad. 903.

यदि कोई कर्जदार दिवालिया बननेके लिये दरखास्त देने तो चाहे उसका पेटीशन खारिज भी हो जावे तब भी यह समझना चाहिये कि उसने इस दफा ६ क्लॉज (ए) के अनुसार दिवालिया काम किया है। देखो—A. I R. 1929 Lah. 72 (1)

जबकि कर्जखाना देनेके दरखास्त देनेके तीन माहके अन्दर कर्जदारने यह प्रकट किया हो कि वह अपने कर्जोंका नहीं चुका सकता है तथा साथ २ यह भी अपने कर्जखाना देने कह दिया हो कि वह सबका रज एक साथही चुकावेगा अलहदा २ नहीं चुकावेगा तो हम प्रमाण कहना इत दफाके क्लॉज (जी) के अनुसार साफ तारीख नोटिस देनेके बराबर है। देखो—A. I. R. 1929 Lah 136

क्लॉज (ए) कर्जदारोंके कामके लिये दस्तियोंके सुपुर् आयदादका किया जाना इस क्लॉजके अनुसार दिवालिया काम है। देखो—इराफल बनाम गोटाम 19 I C 443

ब्रिटिश भारत (British India) का परिभाषा बमाल क्लॉज एक्ट (General Clauses Act X. 1897) की दफा ३ (७) में दी हुई है अर्थात् इसका अभिप्राय सब सब देशोंके है जो गवर्नर जनरल हिन्द या उसके मातहतों द्वारा शासित किया जाता है।

दिवालिया काम चाहे ब्रिटिश भारतमें किया जावे चाहे उसके बाहर किया जावे दिवालिया दरखास्त कर्जदारके विरुद्ध दी जा सकती है परन्तु दिवालियाकी दरखास्त उसी अदालतमें दी जाना चाहिये जिसमें अधिकतर सीमामें कर्जदार अधिकतर रहता हो या अपना धंधा करना हो, यदि कोई कर्जदार सबरा तासका करनेके लिये दस्तावेज (Composition deed) मिले तो यह दिवालिया काम समझना चाहिये। देखो—लालचंद खुशालदास बनाम हुसेनिया A. I. R. 1927 Sindh 78.

क्लॉज (बी) इस उपदशके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुल जायदाद या लगभग सब जायदाद हटा देवे इसके लिये यदि वह अपनी जायदादका मोटासा भी हिसा हटा देवे तो यह उद्देश्य लागू हो सकेगी परन्तु यह बात अवश्य साधित होना चाहिये कि कर्जदारने अपनी जायदाद इस कारण हटाई है कि जिसमें उसके कर्जखाने उस जायदादमें न पावें या बनका कर्ज नसूल होनेमें रुकावट पड़े न दे सके। क्लॉज (ए) के अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्ति का नाम की जाना चाहिये परन्तु इस क्लॉजके अनुसार जायदाद किसी कर्जखानेके नामकी न हो सकती है इसलिये यदि कोई कर्जदार अपने किसी एक कर्जखानेके हकमें अपना जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस मशरते लिख देवे कि उसके दूमे कर्जखानेका वह जायदाद न मिल सके या उनका कर्ज नसूल करने में देर हो जाय या यह काम दिवालिया काम समझा जावेगा।

क्लॉज (सी) इस क्लॉजके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपना कुल जायदाद को अलहदा करे जैसा कि क्लॉज (ए) के लिये आवश्यक है और न यह आवश्यक है कि इतकाल जायदाद कर्जखानेके कर्जों हस्त करने या उनके वसूल होने में देर लाजनेकी वजहसे किया गया हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि इतकाल किया जायदाद तीसरे क्लॉजके हकमें किया जावे अर्थात् इस क्लॉजके लिये चाहे कुल जायदाद या उसका कोई भी भाग दिया गया हो या किसी भी शायिके हकमें दिया गया हो और किसी भी मशरते दिया गया हो तो उप

यदि वह इतकाल जायदाद कानूनन दिवालििया होने पर इमतिना पर नाजायज कार दिया जासके कि वह धोरेसे कारदा देनेके लिये (*Fraudulent preference*) किया गया हो तो ऐसे इतकाल जायदाद के होने पर दिवालििया काम मासलिया जावेगा । ' *Fraudulent preference* ' धोरेसे कारदा पहुँचानेका अर्थ यह निकरता है कि " निम्नी एक कर्जवाहको दूसर कर्जवाहको मुकाबिलेमें कारदा पहुँचाना " इस प्रकार इतरान जायदाद उसी कर्जवाहको इकमे हाना चाहिये परन्तु वह इतकाल उस कर्जवाहको कारदा पहुँचानेके लिये स्वयं उसके हकमें किया जासकता है तथा और भी तीसरे शक्तक हकमें किया जासकता है निम्ने उस कर्जवाहको कारदा पहुँच सरे निम्ने वह फलदा पहुँचाना चाहता है ।

ऐसे इतकाल जायदाद होनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्नी द्रव्यसे बरपाया गया हो क्योंकि तर्जिह (*Pierference*) शब्दही इस बातका सातक है कि इतकाल जायदाद करने वालेने अपनी इच्छा माननूस कर एक कर्जवाहको दूसर कर्जवाहको मुकाबिलेमें कारदा पहुँचानेका इच्छा उस कामको किया है । देखो—देवी ब्रथाप बनाम आष्टोरे 21 C. L. J. 167; मोलावरदा बनाम तेजमल 11 A. L. J 545

परन्तु यदि ऐसा इतकाल जायदाद दबावही बजहसे किया गया हो तो उसमें यह शक होगा कि कर्जदार को मुश्ता हर्गिज यह नहीं थी कि वह एक कर्जवाहको दूसरके मुकाबिले जफिक लाभ पहुँचानेको इच्छा रखता हो और फिर यह बात साफ नहीं रह जावेगा अब दबावका अम ब होनाही इस बातकी मशारे लिये माना गया है ।

कलाञ्ज (डी) हम कर्जगो कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये यह बात साबित होना आवश्यक है कि कर्जदारने इस मशारे कि उसके कर्जवाहानका कर्जो वस्तु न किया जासके या उसके वस्तु होनेमें दर लग इस बातकी तीनों उपश्रुतोंमें इनकारें हुई कारवाही हो अर्थात् यदि ऊपर बर्नाई हुई मशारे मिश्रित मशारे बाहर रहता हो या खरा जावे अथवा अपने रहने या व्यापार का जगहसे हट जावे अथवा अपन कर्जवाहानमे छिप जावे तो यह मान लिया जावेगा कि उसने दिवालििया काम किया है ।

इस बातके आधार पर निम्नी कर्जदारगो दिवालििया कार देनेमें पहिले यह निश्चित करलेना चाहिये कि आया कर्जदार दरअसल हम नीयनसे कि उसके कर्जवाहानका मशरा मारा जावे या उसके वस्तु होनेमें देर हो, हट गया है । देखो—अबूहाजी बनाम हाजीमान ■ Bom L R 684.

चूँकि हटना, कर्जवाहानका रुपया मानने या उसके वस्तु होनेमें देर करनेकी मशारे होना चाहिये इस कारण यदि कोई व्यापक व्यापारके सम्बन्धमें खला जावे तो उसका जाना दिवालििया काम इस बातके अनुसार नहीं समझा जावेगा । देखो 1816 Holt (N P) 175

जबकि किसी कर्जदारने अपना हिसाब किताब कर्जवाहानको दिवालिनेमें इनकार कर दिया हो और एक लम्बी रकम इस मशारे लेन भपने व्यापारकी जगहसे हट गया हो कि जिसमें वह कर्ज न मरई जासके तो अतन्तका यह मामलेना कि वह कर्जदार अपने कर्जवाहानका रुपया हक करन या उसके वस्तु होनेमें देर डालनेकी मशारेसे हट गया है उचित होगा । देखा 21 Bom. 297.

यदि कोई मशारे अपने व्यापार की जगहको बंद जावे व नहा एक योगित दस्तखत अपने वकीलका लगा जावे कि कर्जवाहान उस मशारेसे अपने कर्जके निवत लितापटी करें तो यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे कर्जदारने दिवालििया काम किया है । देखो—ईलाखल डिकनराधन 97 I C. 446

जायसे केवल कुछ समयके लिये गेम्हाजिर होना इस बातके अनुसार गैरहाजिर होना नहीं समझना चाहिये । देखो — 23 A. L. J. 586—A I R 1925 All 564

जबकि वर्ज्यदर्शी दस्तावेज दिवाल्या बानके छिे स्मारित हो गई हो और एउ वर्ज्यताहरी दस्तावेज भा इन्ही तौर पर स्मारित हो गई हो और इसके बाद कोई दूसरा बजाएगा दिवाल्या बरार देनेके लिये दस्तावेज दब तो यह तथ हुआ है कि पहिली दस्तावेज स्मारित होना अत्र तमबीज मुदा दफा ११ जाबना बीदाबीके अनुसार नहीं समझा जावेगा यदि वह दूसरा वर्ज्यताहरी भा पहिली दस्तावेजमें फरीक रहा हो अर्थात् दूसरे वर्ज्यताहरी की दस्तावेज वाले फगर देने दिवालयिक सुनी न ना चाहिये । देखो—चौथमल बगम लेपमनदात A I R 1228 Pat 116

बलाज (ई) यदि वर्ज्यदर्शी जायदादवा कोई हिस्सा इन्गयडिमें नो म्प्रीके छिये हो बिनाजवे तो इस दफाके अनुसार यह मानलिया जावेगा कि उसने दिवाल्या बाम लिया है । जायदाद दस्तावेज बिक जाना चाहिये देखब उसका नोमान पर चढना फाफी नहीं है । देखो—दोन्मनदाम का मामला 56 I C 158

अगर कई दिस्तोयोंके उपर राजगार शतकनामे शम्भ धमें कोई डिस्टो छोड़े और किसी एक हिस्सेदारा अन्हद हिस्सा नीथम होनावे तो यह नहीं म ना जाबना कि अगर हिस्सेदारीने भी दिवाल्या बाम लिया है । देखो—A I R. 1926 Mnd 976

फलाज (एफ) जबकि वर्ज्यदार स्वय दिवाल्या बरार दिये जागे लिये दस्तावेज देने तो उसका यह काम दिवाल्या बाम समझा जावेगा और जबकि कि कोई बजह उसके स्मारित किये जावेगा न दिस्तोई जमि ना अमरी वह दस्तावेज मजूर होकर वह दिवाल्या बरार दिया जाना चाहिये । देखो—A. I. R. 1926 Mnd 494

जबकि किया गया फगर दूसरी हुम म्पूज ११ दिया गया हो और दिवाल्या कि दस्तावेज दिवाल्या निशानेनी देवे ता उसको इस दस्तावेज की मजुरीक लिय एक नया दिवाल्या बाम इस क्रमके अनुसार दिखाना चाहिये । देखो—फमा बीत बाम बिलम्बरदयाल 109 I C 578 (2)

फलाज (जी) यदि वर्ज्यदार अपने किसी वर्ज्यव इसो यह नोटिस देवे कि उसने अपना वर्ज्य देना बद कर दिया है या वह अपना कामगार बद करेगा है तो यह समझना चाहिये कि उसने अपना काम दिवाल्या बाम लिया है । देखो—बनारसीदास बनाम न दवदास A I R. 1926 Oudh 222

यदि नोटिस किसी बचीके माफन भी दिया गया हो तो वह ग्रांत है । देखो—A I R. 1926 Sind 18 पर नु मरि साफ श देखें ब ठीक होना चाहिये और उससे यह बात साफ स्पष्ट होना चाहिये कि वह वर्ज्य बद करना चाहता है या उसने अदायगी बद करदी है । उस नोटिससे उसकी यह बात मझा दानना चाहिय कि वह वर्ज्य देना बद करने वाला है या वर्ज्य देना बद कर दिया है नोटिस केवल इस बातसा कि वर्ज्यदार दिवालयानी हाजिर हो सफी नहीं होकर एते नोटिसके देखने यह नहीं जाना जावेगा कि वर्ज्यदारने दिवाल्या बाम लिया है । देखो—39 Mnd 250, नगमनदात बनाम बिम्पनलाल 25 A. L. J. 219

इस दफाके अनुसार जो नोटिस देना बालाया गया है उगमे मझ उस नोटिससा है जो वर्ज्यदार अपनी इ हुसरा देवे और वर्ज्यदारका यह इच्छा मामलके वाक्यान्ते समझी जासकता है । यह बात कि आप कोई नोटिस हम दफाके अनुसार फाफी है या नहीं हर मामलके आर सब बातोंको भी देखकर समझा जासकता है अगर हिस्सा कर्ज्यवादेने यह प्रगता की जाय कि जबकि आजारकी दशा सुधार न जावे वह अपना वर्ज्य बसूक करनेके लिय बरि दवाज न डाल ना समझे ता प्रसार का प्रस्ताव किया जावे कि वह अपने वर्ज्यका कुछ हिस्सा घुरे वर्ज्यी अदायगीमें लेब ता इस प्रकारवा नोटिस इस दफाके लिय वाफी नोटिस समझा जावेगा । देखो—A I R. 1926 Sind 246,

अगर कोई एक शर्तदार (Partners) इस प्रकारवा नोटिस देवे कि वह वर्ज्यी अदायगी नहीं करेगा तो

ऐसा नोटिस दूसरे शरीकदारों (Partners) के लिये दिवाने का काम नहीं समझा जावेगा । देखो—देवेन्द्र बनन पत्रोत्तर 55 I C. 186

इस कानून के लिये फ्रेन्च कम्पेनी अदायगी की बंद कर देनेसे विनाय मुखामत पैदा नहीं होती है किन्तु इस बंद कानून का नोटिस देनेसे विनाय मुखामत पैदा होती है और उम्मी समये मिथाद खजाना चादिष्ट । देखो—मोरामल बनन पत्र उपाध्याय A I R 1928 Sind 177.

बुलावना (Explanation)—एजेन्ट का दिया हुआ काम मालिक का काम समझा जावेगा । इस प्रकार यदि कोई व्यापारी बलवन्ता हार्डवेयरों अधिकार होमासे बाहर रहना हो परन्तु उसका एजेन्ट (मुमालता) उसकोमें नाम बगना हो और वह बुलावना कर्मोंसे अदायगी बंद कर दक्षे तथा अपनी दुकान छोड़ देने या कोई ऐसा काम करे जिसे यदि व्यापारी स्वयं करता तो वह दिवालिया करार दिया दिया जासकता तो एजेन्टके ऐसे काम करने पर उसका मालिक दिवालिया करार दिया जासकता । देखो—हर्षचन्द्र 5 Cal 805. लेकिन यह साथ इसके बाद वाले छुट्टियोंमें इस प्रकार नहीं चलती गईगी यानी यह तय पाया था कि यदि मालिककी रायसे कोई काम किया जावे तो उसकोही पावनी उस पर हो सकेगी । देखो—धूपतसिंह 20 Cal 771.

एजेन्ट का काम उनी वक्त मालिकको बंध सकेगा जबकि वह अपने अधिकारके अन्तर (नतीर एजेन्टके) काम करेगा । देखो—20 Cal. 771, 23 Cal 26 (I C)

दफा ७ दरखास्त और दिवालिया करार दिया जाना

जगर कोई कर्जदार दिवालियेका कोई काम करे तो उसका कोई कर्जदार या कर्जदार स्वयंही दिवालियेकी दरखास्त इस एकटमें दिये हुए शायतने साथ दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्त पर कर्जदारका दिवालिया करार देनेका हुक्म देसकती है इसी आर्डरका दिवालिया करार देनेका आर्डर (Adjudication order) कहते हैं उदाहरण (Explanation)—कर्जदार का स्वयं दरखास्त देना इस दफाके अनुसार एक दिवालियेका काम है और अदालत ऐसी दरखास्त पर दिवालिया करार देनेका हुक्म दे सकती है ।

व्याख्या—

दफा ७ में कर्जदारके उन कामोंका उल्लेख है जिनके करने या होनेसे यह मानलिया जावेगा कि उस कर्जदारने दिवालियेका काम किया है इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियेका नाम होने पर उसका धारणन क्या है तबता है अर्थात् इस दफामें यह बतलाया गया है कि जब कोई दिवालिया काम किया गया हो तो कर्जदार तथा कर्जदार के लोको अधिपति है कि वह अदालत दिवालियामें उम कर्जदारको दिवालिया करार दिये जानेका दरखास्त पेश कर सके और एसी दरखास्तने आकार पर वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जायके ।

इस दफाके साथ जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसको अन्तर इस बातमें पड़ो कि जिनमें कामदे का मम दूर हो सके क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त दी जानेसे पहिले कोई न कोई दिवालियेका काम अवश्य होना चादिगे । दफा ७ क्लोज (एक) के अनुसार यदि कोई दिवालिया कर्मकी दरखास्त दी जावे ता यह मानलिया जायगा कि दिवालियेका काम हुआ है इस कारण कर्जदार द्वारा कोई दरखास्त दिने जानसे पहिले एक बेवगी दरखास्त दी जा चुकना चादिगे इस मयवी दूर करनेके लिये तथा किशुनकी पावनीसे बचनेके लिये यह व्याख्या माफदा गी है जिनके अनुसार कर्जदारका स्वयं दरखास्त देना दिवालिया काम मान्य गया है तथा अदालतको ऐसी दरखास्त पर दिवालिया करार देनेका अधिकार प्राप्त है ।

■ इसके अनुसार अदालत दिवालिया करार देनेके लिय तय्य नहीं है किन्तु उसने इसका या दिवालिया करार देना निर्धार है यन्तु इस दफ्तरा अर्थ यह नहीं है कि अदालत मनमाने जैसा चाहे वना करे उस अर्थ है कि हाजिरी मनमोहे पानमें रखते हुए अपनी इन इच्छाओं प्रयोग करे और उसे नियमोंके अनुसार कार्य करना चाहिए । दफ्तरा—हरसहृदय बनाम कैरोप्रसाद 5 Cal. 259

दफ्तरा १ व १० में उन सब बातोंमें उल्लेख है जिनका ध्यान दफ्तराल में तय्य रखना आवश्यक है यन्तु उन दफ्तराओं में नहीं है जिनमें पूरा होना भी आवश्यक नहीं है । अतः यह अर्थ है कि अदालतके इसका भी विवेक रखने ध्यान रखना उचित है ।

कर्मचारि इस दफ्तराके अनुसार केवल अपने कर्मचारिोंके खिलाफ दफ्तराल दे सकता है । कर्मचारि जातिके खिलाफ दिवालियाके दफ्तराल किसी कर्मचाराद्वारा ठीक उक्त उक्त नहीं हो सकता है । यद्यपि इस कर्मचाराद्वारा व वास्तविक वाच्ये कर्मचाराद्वारा व कर्मचाराद्वारा सम्बन्ध स्थापित न हो गया हो । दफ्तरा—दिवालियाकरण 85. L R 93=25 I. C. 930

जबकि किसी कर्मचाराके खिलाफ दिवालियाके दफ्तराल देना नहीं है । अतः जबकि उस कर्मचाराकी सुकारिने दफ्तराल में जाते तो वह दफ्तराल प्राप्त करता जायगा जिसमें कि कर्मचारा जायदाद वसूल की जायके तथा बाकी जमाने के दफ्तरा १० में बताया गया है ।

अदालतने यह उचित नहीं है कि वह दिवालिया करार देने वाला इसमें देनेके लिय १ दिवालिया दफ्तरा फिले हुए दफ्तराओंकी भी समुचित धनदा इसमें दे देने । दफ्तरा—जर्जीडन बनाम जिन्ना 45 Mad 189=A 1 R. 1922 Mad. 246

दफ्तरा ८ तथा आदिका दिवालियाके कार्रवाईमें धरी होना

किसी जमाअन (Corporation) या किसी प्रचलित एस्टेट द्वारा गजिस्ट्रीकी हुई कमा या कम्पनीके खिलाफ कोई दिवालियाकी दफ्तराल नहीं दी जायेगी ।

व्याख्या—

इस दफ्तराके अनुसार गजिस्ट्री गुप्त समा (Association) व कम्पनीके खिलाफ दिवालिया दफ्तराल नहीं दी जायगी । यद्यपि किना कम्पनी (Corporation) व कम्पनीकी समा दफ्तराल दे लकिन (Corporation) के लिये गजिस्ट्री द्वारा होता आवश्यक नहीं माना होता है । अतः कम्पनीके लिये 'Association' इच्छा प्रयोग हो सकता है । और फिर 'Against' व 'Association' व कम्पनी इच्छा प्रयोग है किन्तु लकिन 'Incorporated' (गजिस्ट्री द्वारा) इच्छा प्रयोग है ऐसा । अतः यह माना जाता है कि केवल समा (Association) व कम्पनी (Company) या गजिस्ट्री द्वारा होता आवश्यक है ।

यदि हम दफ्तराके अनुसार दफ्तरा दफ्तरा प्रयोग इच्छा जमाअन (Corporation) समा (Association) व कम्पनी (Company) तथा यह प्रयोग होता है । अतः जमाने अतिथि अन्य दूसरे जमानेके खिलाफ दिवालिया दफ्तराल दा जायगी है । अतः यह भी माना जायगी है कि जब वे दा दफ्तरा करार मातायत चाहे जमाने किसी दफ्तराके लिये करार होता है तब खिलाफ दिवालियाके दफ्तराल दा जायगी है जो यदि अन्य इस दफ्तराके चाहे जमाने माना जाता नहीं है । अतः यह इच्छा नहीं है कि समा (Firm) व कम्पनी दिवालियाकी दफ्तराल दा जायगी है और साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि समा (Firm) दा दफ्तराल दिवालियाके

दरखास्त नहीं दी जा सकती है। ऐसी दशाप इस दफा का ध्यान रखन हुए तथा दफा ७९ (२) की पर दृष्टि डालने हुए यदि यह मान लिया जावे कि फर्म (Firm) के विरुद्ध दिवाल्याकी दरखास्त दी जा सकती है तो अनुचित न होगा। बर्तमान दिवाल्या फर्म (Firm) के नाम से ही जामज्नी हे गो अदान्तका दिवालिखा करार देनेवा हुक्म उस फर्मके सब शराकदारों (Partners) के लिये सम्प्रधान चाहिये।

नावालिग—इस एक्टमें कही पर यह नहीं नतलाया गया है कि नावालिग दिवालिखा करार दिया जा सकता है या नहीं परन्तु अधिस्तर वह व्यक्ति जो कानून प्रवर्द्धित कर सक्ता है दिवालिखा करार दिया जा सकता है बूकि नावालिग (Minor) मुआहिदा नहीं कर सक्ता है। इस कारण वह दिवाल्या भी नहीं करार दिया जा सकता है। पर प्रकार यह तय हुआ है कि किसी फर्म (Firm) का नावालिग (Minor) शरीकदार (Partner) निजीतौर पर (Individually) दिवाल्या नहीं कर दिया जा सकता है। देखो—सम्पादीकरण बनाम असम्पत्ति पौष 42 Cnl. 225, जानकीप्रसाद बनाम गिरधारीलाल 16 O O. 68.

कानून प्रवर्द्धित (Contract Act) की दफा २४७ का ध्यान रखने हुए किसी नावालिग शरीकदार (Partner) का दिवालिखा घोषित करना अनुचित है। देखो—जगमोहन बनाम गिरीश बानू 42 All 515

अनकि किसी स्युक्त हिंदू परिवारके बालिक (Adult) केममें दिवालिखा करार दिये गए हों तो उस परिवारके नावालिग (Minor) केव्वरवा हिस्सा रक्षितरती सूरक्षीमें नहीं जावेगा और रक्षितरती उस पर हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है। देखो—A I R 1924 Mad. 791

दफा ९ कर्जखाहके दरखास्त देनेकी शर्तें

(१) कोई कर्जखाह किसी कर्जदारके खिलाफ दरखास्त उस वक्त तक न देसकेगा जब तक कि:—

(ए) कर्जदारका कर्जा जो उसे दरखास्त देने वाले कर्जखाहको देना है या उन सब कर्जोंका जांच जो उमे उन सब कर्जखाहोंको देना है भिन्होंने एक साथ दरखास्त दी हो पांच सौ रुपये न हो। और

(बी) वह कर्ज निश्चित धन राशिमें रुपमें या तो फौरन अदा होना चाहिये या भविष्य में किसी समय अदा किया जाना चाहिये। और

(सी) दरखास्त में दिवालिखा करार दिये जानेके लिये जो दिवालिखेका काम दिखलाया गया हो वह दरखास्त दिये जानेके तीन महीनेके अन्दर हुआ हो।

(२) अगर दरखास्त देने वाला कर्जखाह एक महफूज कर्जखाह है तो उसे अपनी दरखास्तमें दिखलाना पड़ेगा कि अगर कर्जदार दिवालिखा करार दिया जावेगा तो वह अपनी जमानत दूसरे कर्जखाहोंके फायदेके लिये छोड़ देगा या वह अपनी दरखास्तमें जमानतकी क्रीमतका अन्दाजा देगा। जबकि वह दरखास्तमें अपनी जमानतकी क्रीमतका अन्दाजा देगा तो वह उतने रुपयेके लिये दरखास्त देने वाला कर्जखाह समझा जावेगा जितने रुपये उसके कर्जेमेंसे जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई क्रीमत घटा देनेसे बचेगे और उस बचाया रुपयेके लिये वह बिला महफूज कर्जखाह समझा जावेगा।

ज्याहना—

हा अपराध नर-पुत्र दण्डार्ह नहीं है जितने दोषित कर्म-साधक। अपने व्यवहारिक प्रित्याप्त दिवांगतों की सम्मानना के लिये प्रित्याप्त प्रसन्न है। उपद्रव (१) के हात (ए, पी) व (डी) में गिन बानोंका उल्लेख है वह नव बाने उपागित दोषा-
नित्ये तर्मा व्यवस्थाहीन दण्डास्त मन्त्रोपाय कर्मो हे अंग साध व कर्मो द्वा। किया हुआ दिवांगत धर्म
(Act of Inoffensiveness) की साधित होना चाहिये अर्थात् कर्म-साधक दण्डास्त पा कर्म कर्मो उनी अपराध
दिवांगत कर्मा दिया फलमेवा जबकि यह सिद्ध होना कि जितने दण्डा हे मे बताने हुए किनी दिवांगतोंके कर्मो
संस्कारास्त नित्ये अपने ही साधक अंदर किया हो तथा एम पर दण्डास्त देने वालोंका वर्त ५००) इत्यादि
उल्लेख नित्ये ही अंत वृत्तों एही समय या आगुदा किनी समय लामित्त धनवशिके कर्मो अंग नित्ये अति बाला हो ।

परन्तु इस प्रकार दिवालीया करार दिये जानेसे दायित्व दिये जाने पर अदायगी करने के बिना इस दायी जाव करे कि आपा दायित्व देने वाले परचबन्दा (Creditor) का पर ५००) ३० या इससे ज्यादा है या नहीं और उसे अधिकतर दाय ५० में घटायो हुए नियमाका पालन करना चाहिये। देख्यो—बायू नवाम गुजान दातगार A. I R. 1926 Lah 638 (2).

जगति धर्मोऽत्र दृग्भावात् तेन बाधे कर्मस्वात्मे अर्थमे हन्ता कं तो अदात्त दिवाहिय इत कादेशं लिख्य
सर्वतो हे । देतो - दुष्मोऽत्र वनाम आनन्द 7. Lah. L. J. 201.

जयति । इति । अथ दिवाग्न्या भागः सौ । अद्वान्त्ये चार्हते किं पठिते । बह्वं इति नाम्ना यजमानः काले किं
अथ द्वापराय देने यावा बर्जस्वाद् दग्धमथ दत्तये दग्धे च बर्जस्वाद् है या नह्यं नैमाति उत्तये दग्धमथ देन्याया ह
जितये किं उत्तये दग्धमथ दत्तये । एकं येन ह भू हो व्योहो जगत् बर्जस्वाद् दग्धमथ देनेन इदं दत्तं है या नह्यं है । देखो—
तापश्च इत्यम उल्लङ्घितो ७७ A. 1. 713

कर्ज (Debt) - कर्ज उसमें होता बाह्य तया उसकी अदायगी के लिये कर्जदार को स्वयं ज़िम्मेदार होना चाहिये जैसे दाई, पुराना कर्ज या बर्ताना आने पर अधिक दायित्व के लक्षणों के कारण कर्ज ठीके दिवसों पर अदा नहीं होये नामसे है ।

आदि निम्न वर्गकाहवा फलें मिथी हयुक्त हिन्दू पवित्रा प्र हविता पुने वर्गेन भि उम पवित्रका वारं भी
 व्यक्ति जो दिवाभिया कर दिना जामना है दिवाभिया करार दिना आचरेगा तेनेकि वरु धर्म सन्निहा होवे । देखो—
 इयुक्ता वना सिन्धुना 49 Mad. 217-A. I. R. 1926 Mad 183

[illegible]

११. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति या संस्था को उक्त कानून के अन्तर्गत कोई भी अधिकार प्राप्त हो, तो उसे उक्त कानून के अन्तर्गत ही कार्य करना होगा।
देखें *State of California v. Superior Court*, 1926 Cal. 234.

चूँकि एक मद्रास का नाम जोरि के आवाजाजितक है उसने यह प्रश्न दोगा है कि एक या दोभत जोरि वज्रवह
 दि०का दि०दि० काग० देनी दारकास द सतेते है शी प्रसाजकिक संयुक्त दि०दि० पीरारस वज्र हो तो उत पतिवारे
 मय मभन म गिनर वज्रवारे विरुद दि०दि० काग० देनी दारकास देसते है ।

अप्रतिनिधी वतीने पालके लिखे पुरस्कार खर्चक न्यायि. इच्छा हो पालु वनवेने एकही मान उर मंदुन वनेने.
अप्रतिनिधित्व दिना अन्तर वेनेने दारुणास्त वे तो एते दारुणे उर अंतरे न्यायिने दारुणास्त देना नोर् इत नदी ही ।
देना-A. I. R. 1926 Cal. 234.

निश्चिन धन राशि (Liquidated Sum)—जैसे ही तादाद एक खास व ठपकी हुई तादाद होना चाहिये जिसे कि अन्ततः उसी तादाद न निश्चिन करना पड़े। टॉर्ट (Tort) या मुआझदा शिर्कीके आधार पर होने आदि। दोषा एक अनिश्चिन (Unliquidated) वज्रो है इसलिये ऐसे दावोंके आधार पर दिवालियाकी दाखलात नहीं दी जासकती है जो यह वज्रो दूसरे वज्रोकी भाँति दफा ३४ (१) के अनुसार साबित किया जासकता है।

तीन महीनेके अन्दर—कर्मखवाह जिस दिवानेके मामलेके आधार पर अपनी दाखलात देने वह दिवालीया काग हावके बाद ठीक ता। माहके अन्दर दिवालीया कागर दिये जानेकी दाखलात देना चाहिये वरना इसके बाद देनेमें वह दाखलात बाद मियाद समझी जावेगी और उस दिवालीयेके मामलेके आधार पर वह दाखलात कबिल चलनके नहीं समझी जावेगी। देखो—A. I. R. 1925 Oudh 222.

यह तीन महीनेका समय अग्रेजी महीनोंके हिसाबमें गिनना चाहिये जैसाकि जनरल क्लॉजेस एक्ट (General Clauses Act) की दफा ३ में बखलाया गया है यदि आखिरी दिन छुट्टियोंमें पड़ जाय तो छुट्टियोंके समाप्त होने ही जिस दिन कचहरी खुले उस दिन दखलात दाखिल की जासकती है जैसाकि जनरल क्लॉजेस एक्टकी दफा १० में बखल था गया है क्योंकि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ ब २२ की ओवरर आ किमीके लागू होनेका निक दफा ७८ (१) में या कानून दिवालीया (Insolvency Act) का किसी अन्य दफा में नहीं है देखो—42 Mad 18.

यदि दाखलात निर्मा गणत अदालतमें देदी गई हो तो वह समय जेके गणत अदालतमें लग गया हो दुबारा दाखलात देने समय घुंजे नहीं मिलना देखो—39 Mad 74. यदि दाखलात ठीक समयके अन्दर दी गई हो परन्तु उसमें कोई गल्ती रह गई हो तो वह गल्ती आयन्दा ठीकरी जासकती है और उस गल्तीकी वजहसे वह दाखलात मियाद बाहर नहीं समझी जावेगी किन्तु वह दाखलात ठीक समयमें दी हुई ही मानी जावेगी।

कर्जखवाह (Creditor)—इसकी परिभाषा दफा २ (१) (९) में दी हुई है अर्थात्त कर्जखवाहसे अभिप्राय उस व्यक्ति है जो कि फौरम अपने कर्जके वसूल करनेका हकदार हो और जो उस कर्जके चुकतेकी शर्त देखसकता हो परन्तु इस एकके अनुसार केमाभी कर्जखवाह दाखलात देसकता है जो अपने कर्जके उसी समय वसूल कर लेनेका हकदार न हो किन्तु मविषयमें उसके पानेका हकदार हो।

यह आवश्यक नहीं है कि दाखलात देने वाला कर्जखवाह उस समयभी कर्जखवाह बना रहे जबकि दिवालीया कागर दिये जानेका हुक्म दिया जावे इसगरी पर्याप्त होगा कि वह कर्जखवाह दाखलात देने समय कर्जखवाह था। देखो—51 M. L. J 680=A. I. R. 1927 Mad 153

जबकि किसी वज्रो वहन अपने कर्जदाताके दिवालीया कागर दिये जानेके छिये दाखलात दी हो तो वह कर्जखवाह अपना कर्ज दावाके माँगी साबित कर सका है उसी साबित करनेके लिये अन्तःदा सामान्य दायर करनेकी जरूरत नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Rang. 21. यदि कर्जकी तादादके लिय कोई शकका हो तो अदालत दिव लिया की अधिकार है कि वह ऐम सुनके तोय कर सकती है देखो—A. I. R. 1925 Lah. 430, A. I. R. 1926 Lah. 638.

जमाखत (Corporation) न कम्पनीकी बहमियत कर्जखवाहके दिवालीया कागर दिये जानेके लिये अपने कर्जदारके खिलाफ दाखलात दसकती है जबकि किसी कर्जखवाह अपने मज कर्जोंकी निपटनेके लिय तफथियानामा (Deed of arrangement) लिखा हो और कोई कर्जखवाह उस तरफियामे शामिल हो वा वह कर्जखवाह उस त कथियानामाके दिवालत कागर काग देकर उस कर्जदारके खिलाफ दिवालीया कागर दिये जानेकी दाखलात नही दसकता है देखो—45 Mad 294=A. I. R. 1924 Mad 839.

कि उसको विश्वास न हो जाये कि कर्जदार किसी विशेष कारण वश बहाल होनेकी दृष्टिवात्त नहीं दे सकता था या उसकी पैरवी नहीं कर सका था या इस दूसरी दृष्टिवात्तमें कोई भिस कारण दिखलाया गया हो जो पहिले दिवालिया करार दीजानवाली दृष्टिवात्तमें नहीं दिखलाया गया था ।

व्याख्या—

१ सालवेसी एक्ट ११ सन् १९२० ई० [Insolvency (Amendment act) XI of 1927] के अनुसार क्लान (२) में (Made under this act) व स्थान पर 'Who there made under the Presidency Towns Insolvency Act 1909 or under this act' कर दिया गया है इस संशोधन का असर यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसावेता यज्जत व साधवर्ग एव के अनुसार भा दिवालिया करार दिया गया हो तो भी उस पर इस दफामें बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

कर्जदार दिवालिया करार देने जानिकी दस्तखत उम शय में देसकना है जबकि वह अपने कर्जोंका अदा न कर सकता हो तथा उसके साथ २ बन्धन (१) क (ए) (बी) व (सी) में बतलाई हुई बातोंमें कोई बात उपस्थित हो । यह आवश्यक नहीं है कि वह सन् बोले सा । २ उपस्थित होने अर्थात् (i) कर्जदार यदि अपने कर्जोंको अदा न कर सकता है व उसक कर्ज ५००) २० स कम न हाव ता वह दिवालिया बन सकता है, (ii) इसा प्रमाण जबकि वह अपने कर्जोंका अदा न कर सकता हो और भिसा इतराय बिक्रम विपणन होता भी वह दिवालिया बननेका इच्छा है, (iii) उस सूरतमेंभा जबकि वह कर्ज अदा न कर सकता है और उसकी वायदा इतराय बिक्रम पुक हो गई हो वह दिवालिया करार देने जानिकी दृष्टिवात्त दे सकता है ।

यदि ऊपर बतलाई हुई शर्तोंमें कोई भा शर्त उपस्थित न हवे ता अदालत एसा दस्तखतना स्वीकृत कर सकती है देखो—69 I C 622, 40 Bom 707 दिवालियाकी दस्तखत गजनीयतासे व सहायाग चाहिये वह कबल अदालतमें बेना कायदा उद्घोषी मशाये ही न होना चाहिये । दख—34 All 80, 44 Cal 899

यदि दिवालिया इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंका पूरा कर दव तो अगलकी कानूनन दिवालिया करार देनेका हुक्म देना पड़या अदालत उस दशम गजनी इच्छातुमार एसा हुक्म दतेसे इनकार नहीं कर सकता है । दख—44 Cal 505; 15 A. L. J 87; 96 All 250; 41 All 486, A. I R 1926 Cal 905

जबकि कोई कर्जदार अपनी दस्तखतमें वह बात दिखलावे जिसक आधार पर वह दिवालियाकी दस्तखत दे सकता है तो अदालतकी चाहिये कि वह दफा २५ में बतलाये हुए विपणन कानूनन या करे आ तब या ता जतकी दस्तखत स्वीकृत कर दव या उसे गज्ज कद । दख—स्थानागपन नमान वृ गज्ज 40 All 663

अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है—इसमें अभिप्राय यह है कि अदालत दस्तखत पर हुक्म देनेमें पहिले यह समझ लव कि आया दस्तखत दन बोले कर्जोंका इच्छा जा नसूत्र किया जासकता है उमक कर्जोंमें बादा तो नहीं है यदि उसका इच्छा (Assets) उमक कर्जोंसे ज्यादा समझ पड़े ना एभी दशम कर्जदार दिवालिया करार देने जानका इच्छा नहा है । पिछले एक्टके अनुसार इस प्रसारका बाधन नहीं था, हा दस्तखतमें यह कह दना आवश्यक था कि वह कर्ज अदा नहीं कर सकता है पर ३ एक्टके अनुसार अगलकी इस बातक विश्वास दिखाना आवश्यक है कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है । इस बाधनो साविन वगज्ज जिये कि वह कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है कोई बहुत सघुतकी आवश्यकता नहीं है केवल वतनाहा सघुत कदा हागा जिनसे अगलकी विश्वास हा जाव कि दस्तखत वह अपने कर्जोंको अदायगीका प्रव व नहीं कर सकता है । दख—A I R 1923 Mad 680

यः वाद कि कर्जदार अपने कर्जों को क्या करने के लिये नही है अदायग कानून तब करे और इस मामले पर अदायग अन विचार प्रथम करे। देखो—A. I. R. 1924 All 800.

उपपन्ना (१)

फलाज (ए) इस कलाजमें वद कर्जों तादाद बढाई गई जिसका कसमें कम होना आवश्यक है उन कि उसकी दरखास्त मजिस्ट्रेट जातेगी जबकि कोई कर्जदार अथ कर्जदारों के सम्पत्ति किसी कर्जों अदायगी का विरोध हो और वह कर्ज सवस या उनमेंसे किसीसे वसुक्त किया जा सकेगा हो तो ऐसी दशामें वह कर्जदार उस कर्जों के आधार पर दिवालिवा करार दिये जानेकी दरखास्त देसता है। देखो—मदराम बनारस रामचन्द्र 20 I. C 259, गुडामंदर बनारस मगलमेन देसतन A. I. R. 1926 Lah. 235

जबकि दिवालिवा करार दिये जानेकी दरखास्त दी गई हो और उसमें तादाद कर्ज ५००) करनेसे कम हो समके बाद दूसरा कर्जदार उस कमीमें पुन करनेके लिये सम्मेलन किया गया हो तो जित तागलने यह दूसरा कर्जदार का मिल किया गया हो उस तागलने दिवालिवा करार दिया जानेवाला हुक्म काममें लाया जा सकेगा। देखा—26 A. L. J. 941.

फलाज (बी) इस कलाजके अनुसार दिवालिवा दरखस्त देने समय कर्जदार का वह या दियामहमें होना आवश्यक है यह पर्यंत नहीं है कि वह गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार जबकि कोई कर्जदार किसी इलाय किमीस गिरफ्तार किया गया हो पस्तु उसके कुछही घटों बाद बाँक दिया गया हो तो ऐसी दशामें इस गिरफ्तारी के आधार पर वह कर्जदार दिवालिवा करनेकी दरखास्त नहीं देसता है। देखो—25 All. 209.

इसी प्रकार दरखस्त देनेसे पहिले ही उसकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिये यह पर्यंत नहीं होगा कि वह दरखास्त दिये जानेके बाद गिरफ्तार किया गया हो और तब वह इस गिरफ्तारी के आधार पर दिवालिवा बनवा चाहे। देखो—दिलमल बनारस सहाय लाल A I R 1927 Lah 88 इस कलाजमें देखो बाद आता रहने कोर है कि इसमें 'Arrest' म 'Imprisonment' दोनों शब्दों का प्रयोग किया है कि य कि गिरफ्तारी की शक्तों तथा जेलमें बंद होने पर दोनों दशाओंमें कर्जदार को दरवाद देनेका इर हुने।

फलाज (सी) इस कलाजके अनुसार जायदादनी कुर्मी किसी दानेकी डिक्तीमें (For payment of money decree) म होना चाहिये। दिवालिवा दरखस्त देने समय जायदाद कुर्मी की हुई होना चाहिये यह नहीं कि वह कुर्मी हो गई हो या वह फिर कुर्मी हो ऐसी दोनों शक्तोंमें जायदाद कुर्मी समझी जानेगी और यह कुर्मी कर्जदारकी जायदादनी होना चाहिये। देखो—मदराम बनारस सुहमद अजीमचरी 25 All 204

जबकि किसी हकूक दिवालिवामें एक विता तथा दो पुन होवें और यह दिखलाया गया हो कि कर्ज उन पुनोंमेंने एक्के लिया था तो उस वक्त तक पिछा तथा दूसरा पुन एके कर्जों अन्तर्ग म दिखलाया करार नहीं दिया जायगा जब तक कि यह साबित न हो जाय कि कर्ज पुरिदाया आवश्यकताके लिय दिया गया था। देखो—मदराम बनारस अजीमचर A. I R 1926 Lah 354

यदि दिवालिवा करार दिये जानेकी पहिली दरखस्त अदायग प्रेषन करनेकी कसमें खानि हो गई हो तो दूसरी दरखास्त दी जानेकी कर्जों पहिली दरखस्त पर कोई विचार उनको समझा आनेके बाने नहीं किया गया था कि काय वह अत्र तर्जुमा पुन (Re-judicata) दफ १) आस्ता दीवालिवाके अनुसार नहीं माना जावेगा। देखो—इसनदीन बनारस नृप राम A I R 1928 Lah 374

उपदफा (२)—इस उपदफाको बनाकर यह कोशिशकी गई है कि जिसमें कोई कर्जदार अदालतको बेना दमते परेशान न करे अर्थात् यह कि आज किसी कर्जाल्वाहसे परेशान होकर वह दरखास्त देने व इसके बाद उस कर्जाल्वाहसे समझाता हो जाने पर बहाल होनेसे लिये कोई पैवली न करे या नवाजकी दरखास्त योंही लागू होनासे देवे उसके बाद दुबारा फिर जब कोई दूसरा कर्जाल्वाह अपने कर्जोंके लिये उसे परेशान करे तब फिर दरखास्त अदालतमें देदेवे या इसी प्रकारके और किसी तर्गकेसे अपना बेना फायदा न अदालतको बेना परेशान करनेकी कोशिश करे। कर्जदारको मनमानी कार्रवाईसे रोकनेके लियेही यह उपदफा बनाई गई है कि जिसमें मेकनीपतीसे काम करने वालेही कर्जदारको इस एक्टके अनुसार काम उठानेका अवसर प्राप्त हो सके।

इसालेखे ही एमेन्डमेन्ट एक्ट ११मर्च १९२७ई० (Insolvency Amendment Act XI of 1927) के अनुसार इस उपदफामें यह भी बदा दिया गया है कि यदि प्रेसीडेन्सी टाउनस् इन्साल्वेन्सी एक्टके अनुसार भी कोई शफ्स दिवालिया करार दिया गया हो तो उसके लिये भी यह उपदफा लागू होगी।

जबकि कोई व्यक्ति दिवालिया करार दिया गया हो तब उसको यह हुक्म दिया गया हो कि वह छ. माहके अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त देवे और उसकी जायदाद व लहना आकिशियल रितीवर वी सुपुर्गामें के लिये गये हो तथा उस जायदाद आदिके दाम भी रितीवरके हाथ आगये हो परन्तु किसी कर्जाल्वाहने अपना हिस्सा रसदी न लिया हो और न दिवालिये ने बहाल होने की दरख्ताम्न द्य हो तथा ऐसी दशाम दिवालिया करार देनेका हुक्म मसूख कर दिश गया हो तो दरखास्त देने वालकी हक होगा कि वह दुबारा नई दरखास्त दिवालिया करार देनेके लिये दे सकता है। यह तय हुआ था कि घूके जायदाद आकिशल रितीवरकी ही सुपुर्गामें है और इसी कारण दिवालियाको सुमकिन है यह स्थान रहा हो कि जब तरु रितीवरके दशाम कर्जाल्वाहानकी रुपया न बट जाने तब तक उसे बहाल होनेकी दरखास्त देनेकी आवश्यकता नहीं है अतः इस दशामें अदालतको चाहिये कि उसे दुबारा दरखास्त देनेकी आज्ञा प्रदान करदे। देखो—A. L. R. 1928 Lah 452.

दफा ११ वह अदालत जहां दिवालेकी दरखास्तें दीजावेंगी

हर एक दिवालेकी दरखास्त उस अदालतमें दी जावेगी जिसके अधिकार सीमामें कर्जदार अधिकतर भिवास करता हो या व्यवहार करता हो या लाभके लिये कोई कार्य करता हो और अगर वह गिरफ्तार किया गया हो या कैदमें हो तो उस अदालतमें जिसके अधिकार सीमामें वह हिगसतमें (घन्दी) होवे। परन्तु अगर उस अदालतमें जिसमें कि दरखास्तकी सुनवाई हुई है जल्दीसे जल्दी कोई एतराज इस बातके लिये न किया जावे कि दरखास्त किस जगह देना चाहिये और और जगह दरखास्त देनेके कारण कोई अन्याय न हो गया हो तो अपील या निगमनीमें कोई इस प्रकारका एतराज न माना जावेगा।

ब्याख्या—

हर एक दिवालेकी दरखास्त चाहे उसे कर्जाल्वाह देवे या वह कर्जदार द्वारा दी गई हो उस अदालत दिवालियामें दी जाना चाहिये जिसके अधिकार सीमामें दिवालिया करार दिया जाने वाला व्यक्ति अधिकतर निवास करता हो या व्यापार करता हो या फायदेका और कोई काम करता हो। परन्तु जबकि दरखास्त देने वाला कर्जदार गिरफ्तार हुआ हो तो वह उस अदालतमें दरखास्त देसकता है जिसके अधिकार सीमामें वह बन्दी होवे।

अधिकार सीमाके लिये एतराज जिनकी जल्दी होसके किया जाना चाहिये अर्थात् जिस अदालतमें दरख्ताम्नकी सुनवाई हो रही हो, वही अदालतमें अल्दीसे अल्दी एतराज करना चाहिये वरना बाद फैसला दरखास्तके इस प्रकारका एतराज अदालत आगील या निगमनीमें उस बात तक न सुना जावेगा जबतक कि यद्यत् जगह सप्रत्य होवेकी वजहसे कोई विशेष हानि न पहुँची हो तथा अधिकतर सीमाका एतराज अदालत मानद्वेषमें जल्दीसे जल्दी न उठाया गया हो।

अधिकतर रहता हो या व्यापार करता हो—यदि छतर रहनेसे पत्रियाय-यह समझना चाहिये कि जहा पर यह व्यक्ति खाता हो पीता हो या सोता हो या जहा उसका परिवार या नौकर खाता पीता या सोता हो । किसी आदमीके रहनेकी जगह वह मानना चाहिये जहा खसबतसे उसका मजान रहने व सोनेका होवे देखो—38 Cal. 394. यह आवश्यक नहीं है कि बहुत दिनोंमें वहा रहता हो यदि थोड़ा समयसे भी व स्थित खास कामकी वसूहतभी वह वहा रहता हो तो यह मान लिया जावे कि वह उसके रहनेकी जगह है और जगहछतकी सुननेका अधिकार हो जावेगा । देखो—17 C. W. N. 405, A. I. R. Mad. 585

यदि बहुतसे लोग फायदा उठावेंगीं । पारससे अपने उसको रहनेकी जगहको छिया कर दूसरी दूरकी जगह दिवालिया बनने की घोषणा करते हैं जिसमें असली मुखालिफांम (विरोधक) सामने न आतेकें या उन्हें सामन आनेमें पेशानी छडाना पके इसलिये एकदम यह रक दिया गया है कि जहां अधिकतर कर्त्तदार निवात करता हो वही दरखास्त दाखाना चाहिये । जगहछतको दरखास्त सुनने समय यह निश्चात कर लेना चाहिये कि दरखास्त दते समय दिवालियाने उनके अधिसर सीमाके अन्दर अपनी सजुनत कायम काड़ी या । इसी प्रकार जबकि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारोंके साथ थोड़े समयमें रहने लगता हो तो ऐसे रहनेमें जगहछत दिवालियाको उसकी दरखास्त सुननेका हक है देखो—39 I. C. 463.

जगर कमी न वह जगह रहनेकी जगह छोड़कर चला जाता हो तो यह नहीं समझा जावेगा कि वह लगातार उस जगह पर नहीं रहता है । परन्तु इसके यह न मान लेना चाहिये कि यदि कोई जल्लत पलायातरी अपने किसी रिश्तेदारके सहा ठहर जावे तो उसका इस प्रकाश उठना बहाते रहनेके बराबर मान लिया जावेगा देखो—18 C. W. N. 1050

यदि कोई व्यापारी जिन जगहोंमें रहकर व्यापार करता हो तो वह उस जगह द्वारा दिवालिया करार दिया जासकता है जिसकी अधिकार सीमामें उसका पुनेना मजान व जमीन होवेगी देखो—(1925) M. W. N. 797. रहनेकी जगहका सर्वांग एक वाक्याती सर्वांग है और अधिकतर वह जगह जहां वह सारा भर नगर मिल सके उसके रहनेकी जगह मानना चाहिये उस व्यापारियोंके लिये जो जगह वसतग व्यापार करत है रहनेकी जगह वही समझना चाहिये जहा वह अपना रोमानाका काम करते हो व जीविका उपार्जन करत हो । देखो—22 A. L. J. 457.

जबकि कोई व्यक्ति निमी व्यापारमें सम्मेल रहता हो और उसके कार्यों भाग लेता हो और उसकी चीज नक में शामिल हो तो यह मान लिया जावेगा कि वह उस व्यापारको करता है और ऐसे व्यापारकी जगहमें वह दिवालेकी दरखास्त देसकता देखो—19 A. L. J. 626. किसी व्यापारका चाह रहना उस वक्त तब समझा जावेगा जबतक कि उसके वमें नक रहे और उसका लहना बसूल करनेको बना रहे (यदि देखो—48 Mad 798

व्यापारके लिये यह आवश्यक नहीं कि कर्त्तदार स्वयंही उस व्यापारकी करता हो किन्तु यदि व्यापार उसका, ऐजेंट याता या नौकर करता हो तो वह मानलिया जावेगा कि वही उस व्यापारकी करता है (देखो—A. I. R. 1922 All. 337. इस प्रकार यदि किसीके खास व्यापारकी जगह दूसरी हो परन्तु जहां परभी वह व्यापार करता होग वहाकी जगहछत उसे दिवालिया करार देसकनी है । देखो—A. I. R. 1926 Sind 18=97 I. C. 446.

• यह शब्द कि 'स्वयं या किसी ऐजेंटके ज़रिये' (Either personally or through an agent) इस कारण रखते गये हैं कि जिससे अदालत दिवालियाने अधिकार सीमाके अन्दर काम करने वाले बाहरी व्यापारियोंके साथ भी प्रम जाता रहे यदि वह एजे टोंके ज़रिये या मनजोंके ज़रिये जो खासकर काम करनेके लिये नियुक्त किये गये हैं काम करते हो परन्तु इसमें उस कर्म विक्रयकी गणना नहीं होगी जो किसी कमीशन ऐजेंट (अर्थात्) के ज़रिये किया जावे देता—A. I. R. 1929 Sindb. 24.

दफा १२ दरखास्तकी तस्दीक

हर एक दिवालियाकी दरखास्त निम्नकर दीजावेगी और उस पर हस्ताक्षर व तस्दीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार जाबता दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अर्ली दावा पर हस्ताक्षर व तस्दीक होती है।

व्याख्या—

जैसा कि आगता दीवानोंके आर्डर ६ रूल १४ में दिया हुआ है दिवालिया करार दिये जाने वाली दायताएँ पर दस्तखत दायताएँ देने बाछके तथा उसके बचीबचे होना चाहिये यदि दरखास्त देने वाला अपनी पैगुहासिगी या किसी खास कारणवश उपरिपत्र न हो तो उक्त नियमपूर्वक निम्न किन्ना हुआ एग्जेंट उसकी तफसे दस्तखत कर सकता है इसी प्रकार आर्डर ६ रूल १५ के अनुसार दायताएँके नीचे दायताएँ कुनिन्दा की तस्दीक इबागत द्वारा होना चाहिये या किसी ऐसे ब्यक्तिके द्वारा होना चाहिये जो उन सब बातोंको जानता हो। यदि कोई दायताएँ बाकबश तरदीककी हुई नहीं होवेगी तो उस पर दिवालिया करार दिया जाने बाठा हुकम नहीं दिया जावेगा। यदि दरखास्तमें ३३ तस्दीक इबागतमें कोई गळती हो जावे तो उसका सखोपन बादमें किया जानकटा देवे—22 All 55.

दफा १३ दरखास्तमें दिखलाई जानेवाली बातें

- (१) कर्जदारकी दी हुई दरखास्तमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये :—
- (ए) यह बयान कि कर्जदार अपने कर्ज अदा करनेके योग्य नहीं है।
- (बी) यह कि वह अधिकतर कहाँ रहता है या कहाँ रोजगार करता है या कामके लिये काम करता है और अगर गिरफ्तार हुआ हो या कैद हो तो वह किस जगह हिरासतमें है।
- (सी) किस अदालतके हुकम द्वारा वह गिरफ्तार या कैद हुआ है या किसके हुकम द्वारा उसकी जायदाद कुर्ककी गई है इसके साथ २ उस डिफ्रीका हालती देना चाहिये जिसके तिलसिलामें ऊपरका आर्डर दिया गया हो।
- (डी) अपने कर्जोंकी तादाद व उनकी तफसील व उनके साथ २ कर्जस्थाओंके नाम व पते जहाँ तक उसको मातुस हों या जहाँ तक वह अवित परवाह न प्रयत्न द्वारा जान सके।
- (ई) अपनी कुल जायदादकी तादाद और उसका हवाला और उसके साथ साथ
 - (i) रुपयेके अतिरिक्त जो जायदाद हो उसका मूल्य
 - (ii) वह जगह व जगहें जहाँ वह जायदाद हो
 - (iii) इस इच्छाकी घोषणा कि वह अपनी कुल जायदाद अदालतके सुपुर्दे करने को प्रस्तुत है केवल उन वस्तुओंकी छोड़कर जो जाबता दीवानों या अन्य किसी प्रचलित कानून द्वारा कुर्क या नीलाम नहीं होसकती हैं परन्तु इन वस्तुओंमें दिसाबकी किताबें नहीं हूट सकती हैं।

(एक) इस बातका ध्यान कि आया उसने दिवालिया बननेकी कोई दरखास्त पहिले कभी दी है या नहीं और अगर दी है तो

(i) अगर यह दरखास्त खारिज हुई है तो उसके खारिज होनेका काय क्या था, या

(ii) अगर कर्जदार दिवालिया करार दिया जा चुका है तो उस दिवालिका संक्षिप्त विवरण देना चाहिये जिसमें यह भी दिखलाया जावे कि आया पहिले दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर हुआ है या नहीं और अगर मंजूर हुआ है तो किन कारणोंसे

(२) जबकि दिवालिकी दरखास्त कर्जस्वाह या कर्जस्वाहों द्वारा दी जावे तो उसमें कर्जदारके बारेमें यह सब बातें दिखलाई जावेंगी जिनका उल्लेख (१) (घी) में है और यह भी दिखलाया जावेगा कि—

(ए) कौनसा दिवालिका काम हुआ है और कर्जदारने उसे किस तारीखमें किया है।

(घी) कर्जस्वाहोंके खिलाफ दरखास्त देने वाले कर्जस्वाह या कर्जस्वाहोंके कर्जोंकी क्या तादाद है।

ध्यास्या—

यह दफा दो उपदफाओंमें विभक्त है उपदफा (१) में उन बातोंका उल्लेख है जिनका दिखलाया जाना कर्जदार द्वारा दो हुई दरखास्तमें चाहिये है तथा उपदफा (२) में वह बातें बतलाई गई हैं जो कर्जस्वाहों द्वारा दी हुई दरखास्तमें दिखलाई जाना चाहिये है। पहिली उपदफाओं में श्रावण है और उन कर्जोंके बारेमें जो ठीक ठीक बात हो दरखास्तमें दिखलाई जाना चाहिये दूसरी उपदफाओं में यह बतलाया गया है कि पहिली उपदफाके प्राव (बी) की बातें होना चाहिये तथा उनके अतिरिक्त दोबारा और होना चाहिये जो उपदफा (२) के प्राव (ए) व (घी) में बतलाई गई हैं।

जुके अंतर्गत एवमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है इससे यह स्पष्टता चाहिये कि जिन बातोंका ज़रूर इस दफामें दिया गया है वह अवश्य दिखलाई जाना चाहिये परन्तु यदि कोई कर्जदार अपनी दरखास्तमें कर्जोंकी तालीकाल पालतू दिखलाई अर्थात् कर्जोंके तादाद का कम दिखला देवे या अपनी आवश्यकताओंका विचार न करे तो इस बिना पर तलबी दरखास्त नामका नही भी जावेगी अर्थात् यह पालतू होवे हुए भी यदि खानापूर्वी दुस्त हो तो यह दिवालिया करार दे दिया जावेगा परन्तु यदि वह पालतू भूलते हो गई हो तो हुक्म कराई जासकती है या अगर वह दरखास्त जानबूझकर दी गई है तो उस कर्जदार पर कानून दिवालियामें बतलाया हुआ जुर्माना लगाया और उसकी वस्तु जूरीके सामने होने पर उसके अनुसार दंड दिया जासकता यदि सब तथ्या दरखास्तमें न दिखलाया गयी हो तो इस बिना पर दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म नहीं दिया जावेगा—A. I. R. 1922 Bom. 80.

उपदफा (१)

खोज (घ) जबकि कर्जदार अपना कर्ज नहीं कर सकता हो तभी वह दिवालिया बननेकी दरखास्त देसकता है।

दफा १० में इसके बारेमें काफी चिन्ता जा चुका है इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जों न अन्तः कर सन्देश प्रभु रूपसे साबित किया जाये केवल इतनाही साबित कर दिया जाना कि सादिग वह कर्जदार अन्तः कर दे नहीं सका सन्देश है इस शब्दकी आवश्यकतासे पूर्ण करनेके बिना परीत होना।

फलाज (बी) अधिकांश खेतों की जगह आदिका उच्छेद इस कानून में किया गया है दफा ११ में इसके बारे में काफी कहा जाया है उसमें देखनेसे इस कानून का अभिप्राय सफ हो जावेगा ।

फलाज (सी) इसमें भिन्नकारी व कैद आदिका उच्छेद है इसके बारे में भी दफा ११ में काफी लिखा जा चुका है उसमें देखनेसे इस कानून का अभिप्राय भला भ्रम से प्रकट हो जावेगा । दरखास्त देने समय भिन्नकारी या कैद की दशा कायम होना चाहिये ।

फलाज (डी) इस कानून में बतलाये हुए सब दायों में अभिप्राय उन सब दायों व कर्जों का है जो इस एक्ट के दफा ३४ (१) के अनुसार साधित किये जा सकने हैं । यदि दरखास्तमें किसी कर्जदारका कर्ज दिखला दिया जावे तो वह रिक्छाया जाना उस कर्ज का इकबाल दफा १९ कानून मियाद के अनुसार सप्तमा जावेगा देखो— 16 C. W. N. 346. रोदी कपड़े के खर्च का बकाया जो कर्जदार के सिधे बाकी हो उसका कर्ज सप्तमा जावेगा और वह कर्ज भी कर्ज की सूची में दिखलाया जाना चाहिये, देखो—5 Cal. 536. कर्जों के साथ सब कर्जदारों के नाम महा दफा मालूम होमके उनका पूरा पता भी दरखास्तमें बतलाना चाहिये जिसमें उनकी सुविधा पूर्वक सूचना दी जा सके तथा वह दरखास्तमें बतलाये हुए कर्जों की सच्चाई व सुझाई का समझ कर अपना एतदाज पेश कर सकें व अपना ठीक कर्ज साधित कर सकें ।

फलाज (डी) इस कानून के अनुसार कर्जदार को अपनी सब जायदाद व छहना बतलाना चाहिये यदि कर्जदार को प्राविडेंट फंड (Provident Fund) से कपया मिलने वाला हो तो उस कपये की भी छहनामें दिखलाना चाहिये । देखो—10 Bom. 913.

उपफलाज (१) में कपये के आदितिक जो जायदाद होने उसकी कीमत का अन्धाजा भी दिया जाना चाहिये ।

(11) के अनुसार उन जगहों का बतलाना चाहिये जहां पर कि यह सब जायदाद होने, तथा

(111) के अनुसार एक जाबना ऐलान कर देना आवश्यक है कि वह अपनी सब जायदाद को अदालत की सुपुर्दगी में देने की प्रस्तुत है, जो ऐसा ऐलान चाहे किया जावे या न किया जावे दिखलिया करार दिये जाने का हुकम होने पर सब जायदाद अदालत या रिीवर की सुपुर्दगी में आ जाना है अर्थात् उनकी उस पर कब्जा कर लेने का अधिकार हो जाता है इस कलाजमें यह भी बतलाया गया है कि वह यीने जो जाबना दीवानी या अन्य किसी प्रचलित कानून के आधार पर हुई या भीष्म नहीं हो सकती है उनके सुपुर्दगी का सवाल पैदा नहीं होता है परन्तु हिनामकी कानून जो जाबना दीवानी के अनुसार हुई नहीं की जा सकती है इस एक्ट के अनुसार कर्ज की जाते केगी और कर्जदार को वह विताये अदालत या रिीवर की सुपुर्दगी में देने को तैयार रहना चाहिये ।

अन्य किसी प्रचलित एक्ट से अभिप्राय इन एक्टों से है जो प्रचलित हैं तथा जिनके नियमों के अनुसार कोई जात जायदाद कर्ज या गीला मामूली कानून तर्जसे नहीं की जा सकती है जैसे कि बुंदेलखंड लैंड एलियेशन एक्ट (Bundel Khand Land Alination Act) तथा प्राविडेंट फंड एक्ट (Provident Fund Act) आदि ।

नज़ (एफ) यदि दफा १० के कलाज (१) के अनुसार उन दिखलिया के लिये बकायद रखती गई है जिन्होंने विच्छेद दिवाल्ये की तरफाई या उनकी पैसी नेमनीयतीने नहीं की है इस कारण दरखास्त पेश करते समय ही यह बात प्रकट कर देना उन लोगों के लिये आवश्यक समझा गया है जिसमें जायदाद की उत्पत्ति जानी रहे व कोई शक्य जसली मामलों के विचार होना न देखे । इस कलाजमें दोनों बातों की तफरीह

कर्जदार द्वारा दी गई हैं। इस प्रकार जब एकही कर्जदारके विरुद्ध कई कर्जस्वाहोंने दिवालिया करार देनेकी दरखास्तें दी हैं तो वह सब दरखास्तें एकही साथ सुनी जा सकती हैं या जबकि संयुक्त कर्जदारोंने खिलाफ भिन्न २ दरखास्तें दी गई हैं तो ऐसी दरखास्तोंकी सुनवाई भी एग्री साथ होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर बतवाई हुई सभी दरखास्तें एक साथ अवश्य सुनी जाना चाहिये अदालतको अधिकार है कि भिन्न शर्तोंके साथ व जिन २ दरखास्ताका वह साथ सुना चाहे सुन सकती है अर्थात् जिन दरखास्तोंको सुविधापूर्वक एक साथ सुना जा सकता है उनमेंसे भी साथ सुना चाहिये। एग्न हाईकोर्टने A. I. R. 1925 Rang. 36 में यह तय किया था कि एक वर्गानिवासी व उसकी स्त्री दोनोंके खिलाफ दिवालिया करार दिये जानकी संयुक्त दरखास्त दी जा सकती है जबकि वह दोनों कर्जस्वाहोंके कृपा शर्तें तथा उन दोनोंने दिवालिया काय किया है।

इसी प्रकार मद्रास हाईकोर्टने 44 Mad 810 में यह तय किया था कि संयुक्त हिंदू परिवारके श्रेष्ठोंके खिलाफ संयुक्त दरखास्त दिवालिया करार दिये जाने पर उस समय दी जा सकती है जबकि उन्होंने संयुक्त दिवालिया काय किया है। परन्तु आगरा हाईकोर्टने A. I. R. 1926 Lab. 235 में यह तय किया था कि कई एक मद्रास मिशनर एक साथ दिवालिया करार देनेकी दरखास्त नहीं दे सकते हैं।

दफा १६ कार्रवाईका तर्ज बदलनेका अधिकार

जबकि दरखास्त देने वाला कर्जस्वाह अपनी दरखास्तकी पैरवी उचित प्रयत्नके साथ न करता हो तो अदालतका अधिकार है कि वह उसका स्थानपर किसी ऐसे दूसरे कर्जस्वाहको दरखास्त देने वाला माने जिसका कर्जा कर्जदार पर उस तादादके अनुसार हो जो एकदम दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके लिये बतलाई गयी है।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालतको अधिकार दिया गया है कि वह एक कर्जस्वाहकी जगह किसी दूसरे कर्जस्वाहकी दरखास्त देने वाला मानले बशर्ते कि उस कर्जस्वाहका कर्जा वह कर्जदार होने तथा उसके भी कृपा शर्तें तादाद ५०० से कम न हों। यह अधिकार इस कारण दिया गया है जिसमें दिवालियों दरखास्तकी पैरवी भली भाँति हो सके तथा दूसरे कर्जस्वाहोंको किसी प्रकारकी हानि न होवे क्योंकि एक कर्जस्वाह द्वारा दरखास्त दिये जानका अधिग्रहण यह होता है कि वह केवल अपनी सामर्थ्य दरखास्त नहीं देता है किन्तु उसकी दरखास्तमें सब कर्जस्वाहानका लाभ उठावेका अवसर प्राप्त होता है। इसीसे यदि बाद दरखास्त दिये जानेके दरखास्त देने वाला कर्जस्वाह अदालतमें मिल जावे और पैरवी दरखास्त न करे अर्थात् मोटिस आदिवाला सर्व न दाखिल करे तो दूसरे कर्जस्वाहोंको मोक्ष दिया जा सके जिसमें यदि वह चाहें तो कर्जदारके दिवाले के फायदे लाभ उठा सकें तथा उस दिवालिया करार दिलाकर अपना व दूसरे कर्जस्वाहोंका मुक्तान न हान दें।

दूसरे कर्जस्वाहोंका दरखास्त देने वाला मान लेनेसे वह दरखास्त उसी कर्जस्वाहकी दरखास्त समझा चाहिये तथा उसी तारीखसे समझना चाहिये जिस तारीखने पहिली दरखास्त दी गई हो और इसीलिये यह पर्याप्त है कि इस दूसरे कर्जस्वाहका कर्ज उस पहिली तारीख पर साबित किया जा सकता था। जबकि किसी कर्जस्वाहने दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त दी हो तथा मोटिस दूसरे कर्जस्वाहानक नाम जारी किया गये हो परन्तु इसका बाद अपनी दरखास्त देने वाला पैरवी छोड़ दे तथा अदालतने दूसरे कर्जस्वाहने पैरवीकी आज्ञा दे दी हो और यह साबित हो कि इस दूसरे कर्जस्वाह का कर्ज इस शामिल होने का गैर तालख पर प्रमाणिक अन्तर न आता हो तो यह तय किया गया कि उस कर्जस्वाहका शामिल किये जानेका हुक्म ठीक है और उस कर्जस्वाहका श्राव ऐसी दशम साबित किया जा सकता है, देखो—A. I. R. 1928 Mad 608

दफा १७ कर्जदारके मर जानेपर कार्रवाईका चालू रहना

अगर कोई कर्जदार जिसने दिवालिकी दरखास्त दी है या जिसके खिलाफ दिवालिकी दरखास्त दी गई है मर जाये तो उस सूरतमें जबकि अदालत कोई खिलाफ हुक्म न दये कार्रवाई उस हद तक चालू रखली जायेगी जिस हद तक कि उसकी जायदादको घसूल करने प धाँटनेके लिये आवश्यक हो।

व्याख्या—

यह दफा उन दोनों प्रकारकी दरखास्तोंके लिये लागू है जो चाहे कर्जदार द्वारा या चाहे कर्जदार द्वारा दी गई हों। इस दफाके अनुसार कर्जदार (दिवालिया) के मर जानेपर भी दिवालिकी कार्रवाई चालू बनी रहेगी अर्थात् रिसीवर या अदालतकी अधिकार होगा कि वह दिवालिकी मृत्युके पश्चात् भी उसकी जायदाद या उसके अर्धनेकी घसूल कर सके तथा उसके कर्जदारोंमें उस सम्पत्ति को बँट कर विभाजित कर सके।

दिवालिकी कार्रवाई समाप्त होनेसे पहले यदि कर्जदार मर जाये तो उसके लड़के रिसीवरसे अपना हक वापिस नहीं माँग सकते हैं यदि रिसीवर उनके हककी माँगके जीवनभरमें ले सकता हो। देखो—A. I. R. 1926 Mad 994.

अभिप्राय यह है कि दिवालिकीके मरनेपर रिसीवरके हाथमें सुदृढ़ी हुई जायदाद नहीं बिक्री सरती है। देखो—गोकुलसिंह बनाम किरण A. I. R. 1925 Lah 306.

अदालतकी अधिकार है कि कर्जदारके मर जानेके बादभी उसे दिवालिया करार देदे। देखो—A. I. R. 1928 Mad 476 (2); A. I. R. 1928 Mad. 480.

यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके खिलाफ अपील की गई हो और अपील सुने जानेसे पहले दिवालिया मर जाये तो वह अपील उसके मरनेसे समाप्त हो जायेगी। देखो—नरायणसिंह बनाम गुणकृष्णसिंह A. I. R. 1928 Lah 119 (1).

दफा १८ दरखास्तोंके लेनेका तरीका

जिस प्रकार सन् १९०८ ई० के क़ायदा दीवानोंके अनुसार अर्ज़ें दावे लिये जाते हैं उसी प्रकार दिवालिकी दरखास्तें जहां तक उनका सम्बन्ध होगा ली जायेंगी।

व्याख्या—

इस दफाके जावना दीवानीकी किसी खास दफाका खंड नहीं है केवल यह बतलाया गया है कि जिन नियमोंका प्रयोग अर्थात् अर्जके लिये जानेमें किया जाता है वही नियमोंका प्रयोग दिवालिकी दरखास्तोंके लिये जानेमें भी किया जावेगा अर्थात् नियम प्रसार दीवानीकी नालिशोंके दाखिले आदिम रजिस्टर रक्ता जाता है उसी प्रकार दिवालिकी दरखास्तोंके दाखिले होनेका भी रजिस्टर रक्ता जावेगा तथा उनमें तारीख दाखिले नाम्बर मुकदमा आदि का इन्तजाम भी उसी प्रकार होगा इस प्रकार दीवानीकी नालिशोंका होता है दरखास्त दिवालिया चाहे कर्जदार द्वारा दीजावे चाहे कर्जदार द्वारा दोनोंमें ऊपर बतलाया हुआ नियम बर्तना चाहिये।

दफा १९ दरखास्तें लीजानेके बादकी कार्रवाई

(१) जबकि अदालतने कोई दिवालिकी दरखास्तको लेलिया हो तो यह उसके सुननेके लिये कोई तारीख नियत करनेका हुक्म देगी।

(२) दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मका नोटिस कर्जस्वाहानको नियत किये हुए ढंग पर दिया जावेगा ।

(३) जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालीकी दरखास्त नहीं दी हो तो दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मकी सूचना कर्जदारको उस ढंग पर दी जावेगी जिस प्रकार सम्मन दिये जाते हैं ।

व्याख्या—

क्लॉज (१)—यह क्लॉज अनुसार उस समय जबकि दरखास्त जैली गई हो अदालतका कर्जस्वाहानका काम अपनी आत्मा द्वारा उस दरखास्तके सुननेके विषय कोई तारीख नियत करे । दरखास्तका लिया जाना उस समय समझना चाहिये जबकि इस दृष्टिमें बनलाये हुए नियमोंके अनुसार दरखास्त लिखी गई हो तथा उसी टीक दमते अदालतमें दाखिल की गई हो ।

क्लॉज (२)—यह क्लॉज कर्जदार व कर्जस्वाह दोनों द्वारा दी हुई दरखास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Lah. 360.

नियतरी हुई तारीखकी सूचना कर्जस्वाहानको दी जाना चाहिये उस समय जबकि किसी कर्जस्वाहानने दरखास्त दी हो तो शर्त कर्जस्वाहानके सूचनादी जानी चाहिये । नियत किये हुए दमते अधिनाय यह है कि इस दृष्टिमें बनलाये हुए नियमोंके अनुसार इस प्रकारकी सूचना दी जाना चाहिये यह नहा कि कोई निर्जीती पर कर्जस्वाहको सूचना देवे । सूचना कर्जस्वाहके ऐसे एजटको भी दी जा सकती है जिसके हुक्म गुस्तारनामा आम हो, देखो—कल्याणना बनाम बैंक आफ मद्रास 39 Mad. 693

इस उपदस्ताके अनुसार दिये हुए नोटिसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जाती तामील होवे । यह सूचना रजिस्ट्री द्वारा जतके आये भी दी जा सकती है यदि दाखलानके लिये या खास कर रजिस्ट्रीमें टीक पने पर सूचना भेजी जावे तो यह मान लिया जावे कि सूचना टीक प्रसारित हो गई है । जबकि रजिस्ट्री द्वारा पत्र और आने और उस पर लिखा हो कि लेनेमें इन्कार है तो यह मान लिया जावेगा कि उसके नाम वह रजिस्ट्री गईभी उसके सूचना निष्ठ गई है, देखो—गिरीशचंद बनाम मिस्त्रीमोहन 23 C. W. N. 319.

इस उपदस्ताके अनुसार दिये हुए नोटिस दरखास्तके सुने जानेसे पहिलेही कर्जस्वाहानके पास पहुँचना चाहिये जिसमें यदि वह चाहे तो अपन एतरात आदि पेश कर सके ।

क्लॉज (३) यह क्लॉज केवल उसी दरखास्तोंके सम्बन्धमें है जो कर्जस्वाहान द्वारा दी जावे इस क्लॉजके अनुसार नोटिस उस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिये जिस प्रकार क्लॉज (२) में कर्जस्वाहोंके लिये दिया जाना बनलाया गया है किन्तु इस नोटिसकी तामील कर्जदार पर टीक उसी प्रकार होनी चाहिये जलत प्रकार सम्मनकी तामील होती है अर्थात् जावता दवालीके आर्डर ५ में बनलाये हुए नियमोंके अनुसार ऐसे नोटिस की तामीलकी जाना चाहिये ।

दफा २५ (१) के अनुसार अदालतको अधिनाय दिया गया है कि यदि उसकी रायमें कर्जदार पर नोटिसकी जाकी तामील नहीं हुई हो तो यह ऐसी दरखास्तको खारिज कर देवेगा इस प्रकारकी बात कर्जस्वाहोंके नोटिसके सम्बन्धमें नहीं कही गई है कारण इसका यह प्रतीत होता है कि कर्जदारका नोटिसका पहुँचना बहुत आवश्यक है तथा उसके प्राप्त बिना नोटिस पहुँचे हुए जो कार्यवाई की जावेगी वह सब नकारात्मक समझा जावेगी व कर्जदारको एकतरफा की गई कार्यवाई को मसूदा कराना भी हक होगा इत्यादि ।

दफा २० दरमियानी रिसीवरकी नियुक्ति

अदालतको अधिकार है कि वह दिवालकी दरखास्त लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद उस समय जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालकी दरखास्त दी है जरूर कर्जदारकी कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्सेके लिये दरमियानी रिसीवर (Interim Receiver) नियुक्त करे जो कि उस जायदाद या उसके किन्हीं खास हिस्सेका कब्जा फौरन लेले और ऐसी सूत्रसे उसे दरमियानी रिसीवरको अदालत द्वारा दिये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १६०० ई० के आधुना द्वाभाके अनुसार रिसीवरको प्राप्त होसकते हैं। अगर इस प्रकार कोई दरमियानी रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है तो भी अदालतको अधिकार है कि दिवालिया करार देनेसे पहिले किसी दूसरे समयमें दरमियानी रिसीवर नियुक्त कर देवे और उसकी नियुक्तिमें इस दफाके नियमोंका उपयोग किया जायेगा।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा दिवालियेकी जायदाद पर कौन कम्पा कर लेनेका अधिकार अदालतको प्राप्त है अर्थात् जिन समय दरखास्तका किया जाना मजूर किया जाव उसी समय रिसीवर जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये नियुक्त किया जासकता है इससे दो बातोंकी सुविधा होगी। है एकतो यह कि जायदाद बरबाद होनेसे बच जाय है दूसरे वह कर्जदार जायदादकी दरखास्त देनेके बाद अलहदा नहीं कर सकेगा और सब उच्छेदादोंमें जायदादसे पूरा फायदा उठानेका साधन मिल सकेगा।

यदि कर्जदार द्वारा दरखास्त दी गई हो तो दरमियानी रिसीवर अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिये अर्थात् इस दशामें अदालतका कर्तव्य होगा कि वह रिसीवर नियुक्त करे परन्तु जब कर्जदार द्वारा दरखास्त दी गई हो तो अदालतकी अधिशार है कि वह चाहे रिसीवर, दरखास्त लिये जाने समय नियुक्त करे या उस समय न करे जहा आवश्यकता अदालतकी उस समय सम्पन्न पड़े—इसका कारण यह भी हो सकता है कि कर्जदारका दरखास्त देनाही दिवालिया काय बनाना या यथा है इस कारण उनके दरखास्त देतेही अदालत यदि रिसीवर नियुक्त करे तो कोई अशुक्ति न होगी परन्तु कर्जदारकी दरखास्त कभी न नेना दनाक कारणसे व फोसान करनेकी गरजतर्था ही जायसकती है इसलिये उस पर दरखास्त लिये जाने समझी रिसीवर नियुक्त कर देना एक प्रकारसे कर्जदारके ऊपर अशुद्धी होगी और इसीलिये बाद समाप्त होने व आवश्यकता समझने ही पर रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिये।

दरमियानी रिसीवर (Interim receiver) के अधिकार—दरमियानी रिसीवरको बड़ी अधिकार दिये जा सके हैं जो आधुना कानूनीके अनुसार नियुक्त लिये जानेवाले रिसीवरको प्राप्त हो सके हैं।

अदालत दिवालियाकी अधिशार है कि वह दरमियानी रिसीवरको उस समय दिवालियाकी जायदाद पर कब्जा के लेनेका हुक्म दे देव या किसी शर्तों के साथ न जा लेनेका हुक्म देवे अदालत दरमियानी रिसीवर चुनकर कम्पेका हुक्म देते समय उस हुक्ममें न अधिशारोंको उल्लेख कर सक्त है जो वह उस समय उस रिसीवरको दिया चाहती हो, देखो—42 Cal 289 दरमियानी रिसीवर तथा रिसीवरकी अदालत के कम्पेकि दरमियानी रिसीवरको जायदाद पर कब्जा ले लेनेकी अधिकार होता है तथा वह अधिशार उसे प्राप्त नहीं होने हैं जो अदालत उसके लिये अपन हुक्म द्वारा अदा न को परन्तु रिसीवर (Regular) रिसीवर दिवालिया कम्पे दिये जानेके बाद होता है और दिवालियाकी सब जायदाद उसकी संपूर्णतामें आसकती है तथा वह सब जायदाद उसकी समझी जाना चाहिये। इस एकके अनुसार जो रिसीवर नियुक्त किया जावे उसे (Public Officer) जानना रिसीवरकी दफा २ के अनुसार समझना चाहिये तथा उसके विरुद्ध कोई दावा करनेसे पहिले दफा ८० अनुसार रिसीवरको नोडित दिया जाना आवश्यक है, देखो—50 I. C. 411.

दफा २१ कर्जदारके खिलाफ दरमियानी कार्रवाई

दिवालेकी दरखास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद दिवालिघा करार देनेका हुक्म देनेसे पहिले अदालतको अधिकार है कि वह स्वयंही या किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर नीचे दिये हुए हुक्मोंमेंसे एक या एकसे अधिक हुक्म देसकती है:—

(१) कर्जदारको उसकी उस घकरी हाजिरके लिये उचित जमानत देनेका हुक्म देसकती है जबतक कि दिवालेकी दरखास्त पर आखिरी हुक्म न हो जावे ।

(२) कर्जदारके कर्जे या उसकी हुक्मतमें जो जायदाद हो उस सबको या उसके किसी हिस्सेको बजरिये हुक्म कुर्कीके कब्जा लेंनका हुक्म देसकती है लेकिन इससे वह सब चीजें अलावा हिसाब किताबकी किताबोंके बरी हैं जो सन् १९०८ ई० के ज़ावता दीवानी या किसी अन्य प्रचलित एक्ट द्वारा कुर्की व नीलामसे बरी हैं ।

(३) कर्जदारकी गिरफ्तारीके लिये जमानती या विला जमानती धारण निकास सकती है और यह हुक्म देसकती है कि वह दीवानी जेलमें उस तक तक कैद रखा जाये जबतक कि दिवालेकी दरखास्तको समाप्त (सुनवाई) न हो संघ या वह जमानत आदि उन मुनासिब शर्तों पर छोड़ दिया जावे जो उचित व आवश्यक प्रतीत हों ।

परन्तु बलाज (२) व (३) के अनुसार अदालत उस समय तक हुक्म न देगी जब तक कि उसको यकीन न होजावे कि कर्जदार अपने कर्जस्वाहोंकी वस्तुओंमें देर करने या उनके कर्जोंको मानेकी इच्छासे या अदालतके सम्मन न तामील होने देनेकी इच्छासे:—

(i) अदालतकी अधिकार सीमामें छिप गया है या भाग गया है या छिपने या भागने वाला है या बाहर बना हुआ है, या

(ii) उसने ऐसे कार्रगर्जोंको जो समाप्त मुकदमोंमें कर्जस्वाहोंके लिये फायदेमंद साबित होंगे छिपा दिया है, या बरबाद कर दिया है या दूसरेको दे दिया है या अधिकार सीमासे हटा दिया है या छिपाने वाला है, या बरबाद करने वाला है या दूसरेको देने वाला है या सीमासे हटाने वाला है, या ऊपर बताई हुई चीजोंको छेड़ कर अपनी कोई जायदाद इस प्रकार हटायी हो ।

ब्याख्या—

इस दफ्तेमें अदालतकी वह अधिकार दिये गये हैं जिनका प्रयोग वह दिवालिघा करार दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिले कर सकती है इन अधिकारोंका प्रयोग चाहे दारखास्त कर्जदार द्वारा दीगई हो चाहे कर्जस्वाह द्वारा दोनों दशाओंमें किया जासकता है । अदालत स्वयंही या किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर इस दफ्तेमें बतलये हुए अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है । इस दफ्तेमें बतलये हुए अधिकारोंका प्रयोग करनेमें दरखास्तके सुन जानमें सुविधा रहेगी तथा कर्जदार कार्रवाईमें लगबग या बाधा नहीं डाल सकगा और कर्जदारका हाजिराया इत्यादि कर्मबद होसकेगा । क्योंकि या तो उसे हाजिरके लिये जमानत देनी पड़ेगी या फिर वह दावाभी जेलमें बंद रहसुा जानकेगा जैसी आवश्यकता समकानूनान समझी जावेगी ।

इस दफ्तेमें बतलये हुए अधिकारोंका प्रयोग या तो न्यायालय सिद्ध जाने समय या फिर जमानत या फिर प्रमाण लिये जायगा ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देदिये जानेके बाद इस दफ्तेमें बतलये हुए नियमोंका प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बाद यदि आवश्यकता सम्पन्ना जावे तो दफा ३२ के नियमोंका प्रयोग किया जासकता है ।

क्लाज (१) चर्चिण सामानतः निर्णय अदालतकी इच्छा चाहिये अर्थात् अदालत वाकिफातकी समझकर तथा विचार कर जो जमावत देना निश्चित करे वही उचित जमावत समझना चाहिये परन्तु जमावत बहुत अधिक भी न होना चाहिये कि जिसका प्रमथ दिवालिया करही न सके व उसे जेलहीमें रहनेके लिये बाध्य होना पड़े । जमानत लेनेका अभिप्राय यह है कि उसे शक्ति होनेके लिये बाध्य होना पड़े यह अभिप्राय इतना नहीं है कि उस जमानतके हुक्मसे दिवालियेको परेशान किया जावे ।

क्लाज (२) इस कालमें दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवालियेकी जायदाद कुर्क किये जानेका उद्देश है । इस दफ्तेके अनुसार कुर्कका जो हुक्म दिया जावे वह खासतः दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार दिया जाना चाहिये देखो—इरमनकीनी नयाम भगवानदास 36 All 65

जिस जायदादकी कुर्कका हुक्म दिया जावे वह जायदाद बर्जदारके कब्जे या उसकी हुक्मनमें होना चाहिये ।

जिन चीजोंकी कुर्क जावता दीवानों या अन्य किसी प्रचलित एक्टके अनुसार नहीं की जासकती है उन चीजोंकी कुर्क इस एक्टके अनुसार भी नहीं कीजानेका केवल हिसाब किताबकी रीतिसे इस एक्टके अनुसार कुर्कका जासकता है गो यह कितने ताबता दीवानोंके अनुसार कुर्क नहीं हो जाना चाहिये जैसा कि जानता दीवानोंकी दफा ६० में दिया हुआ है ।

प्राबालेण्ट फाउ बर्जेलवाइके मामले पर कुर्क नहीं किया जासकता है इसी प्रकार न तो रिसीवर न कोर्ट बर्जेलवाइकी दिवालियाके रेलवे प्राक्टीशंट फाउकी कुर्क करा सकता है देखो—56 Ind Cas 450, 24 C W N. 288.

क्लाज (३) इस कालके अनुसार अदालतकी अधिरार प्राप्त है कि वह स्वयंही या किसी कमलावाइके दरवास्त होने पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिलेही बर्जदारकी गिरफ्तार कराने व उसकी कैद करके साथही साथ अदालतकी यहभी अधिकार प्राप्त है कि वह बाद गिरफ्तारी जमानत लेकर बर्जदारकी छोड़नी देवे अर्थात् जमानतका अभिप्राय यह है कि यदि बर्जदारकी उपरिपनि इच्छाश्रितकी दरवास्त सुनी जाते समय आवश्यक समझ पड़े या यदि उसकी जायदाद पर अधिकार करने आदिके लिये उसकी मददकी आवश्यकता प्रतीत हो और साथही साथ यह भी जान पड़े कि वह बर्जदार इस प्रकार उपरिगत न होगा या वह इस प्रकारकी सहायता प्रदान करनेसे हटगा तो अदालत अपने इस ज्ञानमें दिये हुए अधिकारका प्रयोग कर सकती है तथा वह निश्चित है। जाने पर कि वह उचित समय या खरमर पर हजरि होनेसे नहीं हटगा उसे छोड़नी सक्ती है हाजिरकी किये कचिन जमानत लेने का अदालतकी ऐसा विश्वास हो सकता है । परन्तु अदालतकी ऐसी गिरफ्तारीका हुक्म बहुत सोच समझ कर देना चाहिये जैसा कि एक्टके नियमोंसे प्रकट होता है क्योंकि बर्जदार को ऐसे हुक्मसे बड़ा गड़ पहुँचनेकी आशंका है ।

दफा २२ कर्जदारके कर्तव्य

जब कि दिवालेकी दरवास्त लिये जानेका हुक्म हो जाये तब कर्जदारको हिसाबकी सब किताबें पेश करना पड़ेगी और उसके बाद कितीभी समय अपनी जायदादकी फेहरिस्त देना पड़ेगी व अपने कर्जदारोंको व उनके कर्जोंकी तादाद तथा अपने कर्जदारों व उनसे लिये जाने वाले कर्जोंकी तफसील भी देना पड़ेगी और अपनी जायदाद या कर्जदारोंके धारमें जांच करना पड़ेगी और अदालत या रिसीवरके सामने हाजिर होना पड़ेगा वस्तावेज लिखना पड़ेगी और अधिकतर वह सब काम व याते अपनी जायदादके सम्बन्धमें करना पड़ेगी जो अदालत या रिसीवर नियमके अनुसार उससे कराना चाहेंगा ।

व्याख्या—

इस दफा में कर्जदारके कुछ कर्न योंका नश्वन है और इन कर्न-योंका अधिकतर सम्बन्ध अदालतके साथ है अर्थात् यदि इस दफा में बतलाये हुए नियमोंका अनुसार दिवालिया क्रम न करे ता उमरा यह क्रम अदालतके विरुद्ध समझना चाहिये न कि किसी कर्जालाहके देखो—54 I C 740.

इस दफा में बतलाये हुए कर्तव्योंका न करना एक प्रमाणसे अदालतके निर्धारित नियमोंके विरुद्ध काम करना समझना चाहिये किन्तु उसे कोई कौनदायीमा जुर्म न मानना चाहिये, देखो—39 All 171

हिसाबकी किताबें दरखास्त दिवालियाके लिये जते समय दाखिल करदी जाना चाहिये तथा उसके पश्चात् कर्ज-हवाहोंकी केहरिल कर्जोंकी तादाद व उनका व्योरा आदि भी दाखिल करना आवश्यक है परन्तु यह बात दरखास्त लिये जानेके बाद भा किसी समय दाखिल की जासकती है चूँकि बिना हिसाब किताबके देख कर्जों आदिके बारेमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है इस कारण उनका दाखिल होना प्राग्भवीमे अनिवार्य समझा गया है परन्तु हिम बकी-किताबें दाखिल हो जानेदीसे काम नहीं चलेगा कर्जदारको उसका पश्चात् अपनी जायदादकी तफ्तील कर्जोंकी केहरिल तथा उनका व्योरा आदि भी दाखिल करना पड़ेगा अर्थात् अपने कर्तव्योंकी तथा कर्जदारोंके नाम व उनसे सम्बन्ध किया जाने वाला या उनको दिया जाने वाला कर्ज तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली जानने योग्य सब बातोंका व्योरा दाखिल करना आवश्यक है ।

किताबों व कर्जों आदिका व्यास दाखिल होजानके बाद भी अदालत या रिसीवर जब चाहे कर्जदारको हिसाब समझनेके लिये तथा कर्जों आदि की असली हालत जाननेके लिये बुला सकता है और उस समय कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह अदालतकी व रिसीवरकी उन सब बातोंके समझनेमें सहायता प्रदान करे तथा उन सब बातोंका उत्तर दे जो उससे पूछा जावे या उन सब बातोंको कर जो अदालत या रिसीवर उस सम्बन्धमें उससे कराया चाहे ।

अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह किसी व्यक्तिकी २०० गीन्स अधिक फायनेसे भी उसकी जायदाद आदिके सम्बन्धमें जाच करनेके लिये बुला सकती है देखो—13 Bom 114, 33 Bom 462

इस दफाके अनुसार कर्तव्य करानेके लिये अदालत दिवालिया या रिसीवर कर्जदारको बाध्य कर सकता है । यदि रिसीवरकी नियुक्ति दरखास्त लिये जाते समय होजावे तो कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह रिसीवरने मिले व रिसीवरकी तब चाहिये कि उससे जानने योग्य सब बातोंकी केहरिल दाखिल करले तथा कर्जदारने अपनीभी वह सब बातें समझते जिनका समझना आवश्यक प्रतीत हो । अदालत या रिसीवर जब चाहे हम दरामें बतलाये हुए कर्तव्योंके पालनके लिये कर्जदारको बुला सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार डिलित आता दाराही बुलाया जावेया । देखो—बुगमल वनाम आदिकाल एसादनी 47 Cal. 56

इस दफा में बतलाये हुए नियमोंका पालन न करने पर कर्जदार दण्डका भागी होगा यदि जानबूझ कर कर्जदार नियमोंका पालन न करेगा तो उसे दफा ६९ के अनुसार दण्ड दिया जासकता गिम्के अनुसार एक वर्ष कागवास तकका दण्ड दिया जासकता है ।

दफा २३ कर्जदारकी रिहाई (छुटकारा)

(१) जबकि कर्जदार किसी इजराय डिक्लीमें रपयेंकी घमूलोंके लिये जेल या हिरासतमें होवे तो अदालतको अधिकार है कि दिवालीकी दरखास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद दिवालिया क्रम देनसे पहिले कर्जदारको जमानत आदिकी शर्तों पर जो उसे उचित व आवश्यक प्रतीतहो छोड़ देवे ।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्तिको जिसे उसने इस दफाके अनुसार छोड़नेकी आज्ञा दी है उसे फिर गिरफ्तार करवा लेवे या फिर उसे हिरासतमें भेजदे जहाँसे वह मुक्त किया गया था ।

(३) इस दफाके अनुसार हुक्म देते समय अदालत अपने हुक्म देनेका कारण लिख कर बतलावेगी ।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है कि वह दिवालिया कथार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिलेही कर्जदारको जेल या हिरासतसे मुक्त कर सके यदि वह कर्जदार किसी रुपयेके बसूलीकी डिक्तीके आधार पर गिरफ्तार किया गया हो । इस अधिकारका प्रयोग करना न करना अदालतके हाथमें है परन्तु जिस समय अदालत कर्जदारको जेल या हिरासतसे जमानत लेवामी छोड़नेसे इनकार करे तो उसे वह कारण लिखकर देखलाना पड़ेगे कि मिनरी बजहसे वह कर्जदार वा छोड़ा जाना उचित नहीं समझी है । देखो—A. I. R. 1924 Pat. 559.

कर्जदारको छुटकारा केवल रुपये बसूलीकी डिक्तीसेही मिल सकता है वह डिक्ती चाहे जिस अदालत द्वारा दी गई हो परन्तु छोड़े जानेका हुक्म देनेसे पहिले अदालत उचित जमानत कर्जदारसे लेवारी है । अदालत दिवालियाका इस दफाके अनुसार हुक्म बतौ दशमें होवेगा जब कि कर्जदार गिरफ्तारीकी हालतमें होवे अर्थात् या तो वह दीवानीकी जेलमें होवे या हिरासतमें लिया जा चुका हो । इस दफाके अनुसार हुक्म जहाँ कर्जोंके सम्बन्धमें दिया जावेगा ओ इस एक्टके अनुसार साबित स्थिति जानावते है । देखो—होराणाज बनाम तुलसीधाम 80 L. C. 946

इस दफाके बलाज (१) में अदालतको यहमी अधिकार दिया गया है कि वह कर्जदारको जेल या हिरासतसे मुक्त करनेका हुक्म देनेके पश्चात् उसे जब चाहे फिरसे गिरफ्तार करवावे परन्तु अदालत ऐसा हुक्म किसी विशेष कारणके उपस्थित होनेवाले पर देवेगी इस बलाजकी भाषासे यहमी प्रकट है कि अदालत दिवालिया कथार देनेके पश्चात् भी कर्जदारको गिरफ्तारका हुक्म दे सकती है परन्तु वह दिवालियाके बलाज ही जानेके बाद इस प्रकारकी गिरफ्तारीका हुक्म नहीं देवेगी क्योंकि यह बात न तो इस दफाकी भाषात प्रकट होती है न एक्टमें और किसी जगहही इस प्रकारका उल्लेख मिलता है, बलाज होनानके बाद यदि दिवालियेकी कोई अनुचित कार्रवाई साबित होती है तो दफा २६ के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाईकी जासकती है ।

बलाज (२) के अनुसार अदालत बाध्य है कि वह बलाज (१) या (२) के अनुसार हुक्म देते समय उन कारणोंके सहित वह अपने हुक्मको लिखे ।

दफा २४ दरख्वास्तके सुनेजानेका तरीका

(१) दरख्वास्तको सुननेके लिये नियतकी हुई तारीख पर या उसके बाद यद्वारहूई तारीख पर अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुवृत्त लेवेगी :—

(ए) यह कि कर्जद्वारा या कर्जदारको जिसने दरख्वास्त दी हो दरख्वास्त देनेका हक है या नहीं परन्तु जबकि कर्जदार दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति है तो वह इस बातको साबित करनेके लिये कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेके योग्य नहीं है केवल उतनीही शहादत देगा कि जिसमें अदालतको यकीन होजावे जाहिरा तौर पर कर्जदारका कहना ठीक है और अदालतको जब यह यकीन हो जावे तो वह इस बातके लिये और शहादत लेनेके लिये बाध्य नहीं है ।

(बी) जबकि कर्जद्वारा दस्तखस्त देने पर कर्जदार हाजिर नहीं हो, तो यह साबित होना चाहिये कि उसके पास दस्तखस्तके लेलिये आनेके हुक्मका नोटिस पहुँच चुका है।

(सी) यह कि कर्जदारने दिवालिया काम किया है जिसका करना उसके लिये बताया जाता है।

(२) अगर कर्जदार हाजिर होवे तो अदालत उसका भी बयान उसके धर्तावे, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें उन कर्जद्वाराओंके सामने लगी जो उस पेशी पर मौजूद हों और कर्जद्वाराओंकी भी अधिकार होगा कि वह कर्जदारसे उन बातोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर सकें।

(३) अगर पर्याप्त कारण दिखलाया जावे तो अदालतको अधिकार होगा कि वह कर्जदारया किसी कर्जद्वाराको उस शहादतको देनेके लिये अपसर देवे जो उसकी रायमें दस्तखस्तका ठीक २ फौसला निर्णय करनेके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(४) कर्जदारके बयानों तथा दूसरी जयानी शहादतके सारका लेखा अदालत रक्खेगी और वह लेखा मुकद्दमेकी कार्रवाईका भाग समझा जायगा।

व्याख्या—

इस दफा में उन नियमोंका वर्णन है जिनका प्रयोग दिवालियारी दस्तखस्त देने जाने समय किया जाना चाहिये चाहे वह दस्तखस्त कर्जदारने दी हो या वह दस्तखस्त उसने किसी कर्जद्वाराह दिला दी गई हो इस दफ्तार यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकारका सुवृत्त दस्तखस्तकी गामिन करनेके लिये आवश्यक है। सबसे पहिले अदालत यह देखेगी कि आया दस्तखस्त देने वाले कर्जदार या कर्जद्वाराको दस्तखस्त दिवालिया पेश करना इक है या नहीं यदि दस्तखस्त देने वाला कर्जदार है तो उसका इक दस्तखस्त दिवालिया देनेवाला वह समय जल्दा जावेगा जबकि वह अपने कर्जोंकी अदा न कर सकता हो तथा उसके साथ साथ या तो उसने कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिक हो या वह किसी रूपके बस्तुकी विक्रीके सम्बन्धमें गिरफ्तार किया गया हो या उसकी जायदाद कुँची गई हो। कर्जदारको यह बात साबित करके लिये कि वह अपने कर्जोंकी अदा नहीं कर सकता है केवल इतनाही सुवृत्त देना पड़ेगा जिससे अदालतको यह विश्वास हो जावे कि वह प्रकट रूपमें कर्जें अदा नहीं कर सकता है अदालत इससे अधिक सुवृत्त इस बातके साबित करनेके लिये सुननेको बाध्य नहीं है।

फगनु यदि दस्तखस्त देने वाला कोई कर्जद्वाराह है तो उसका इक दस्तखस्त दिवालिया पेश करनेका वह समय समझा जावेगा जबकि वह साबित करे कि कर्जदारने वह दिवालियाका काम किया है जिसका उल्लेख दस्तखस्तमें किया गया हो तथा कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिक हो और जिन कर्जोंका उल्लेख दस्तखस्तमें है वह बस्तु लिये जासकते हैं साथही साथ वही दस्तखस्तका नोटिसकी कर्जदार पर नियम पूर्वक तामील हो जाना चाहिये। ऊपर बताई हुई बातोंका वर्णन उपदफा (१) में किया गया है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि दस्तखस्त दिवालिया सुने जावे समय कर्जदार मौजूद हो तो अदालतका तर्क्य है कि वह कर्जदारका बयान अवश्य लेवे और कर्जदारका इस प्रकार बयान होने समय उसके कर्जद्वाराओंको इक है कि वह उससे निगद कर सकें अर्थात् दस्तखस्त चाहे कर्जदार द्वारा दी गई हो या उसके किसी कर्जद्वाराह द्वारा दी हो अदालत दोनों दशाओंमें कर्जदारके मौजूद होने पर उसके बयान अवश्य लेवेगी तथा कर्जद्वाराओंकी कर्जदारमें प्रश्न करनेका अधिकार इसी प्रकार प्राप्त है कर्जदारका बयान अवश्य होना चाहिये चाहे उस समय और किसी गवाहोंके बयान लिये जावे या न लिये जावे देतो—बनारसी बनाप बनारसी 9. A. L. J. 239; A. I. R. 1926 Lah. 508.

इस दफा में बतलाये हुए नियम ऐसे नहीं हैं कि जितनी अवहेलना की जास्के अर्थात् उनके अनुसार अदालत कार्य करनेकी बाध है इसलिये कर्जदारकी उपस्थितिमें उसका बयान लिये बिना यदि कोई हुक्म दे दिया जावे तो वह हुक्म ठीक नहीं समझा जावेगा देखो—39 I C 745, A I R. 1927 Cal 32.

कर्जदारका इस प्रकार जो आग्र बयान लिया जावेगा वह केवल उसकीके खिलाफ प्रयोग किया जास्केगा किसी दूसरेके खिलाफ नहीं प्रयोग किया जावेगा। इस प्रकारका बयान लिये जानेका तात्पर्य यह है कि जितनी जल्दी होस्के कर्जदारकी सब जायदाद ग्राह्य होस्के तथा वहभी ग्राह्य होस्के कि कर्जदारने अपनी जायदादके सम्बन्धमें क्या क्या किये हैं जिससे कि कर्जदारका या रिक्तीवर दिवालियाकी सब जायदादका ठीक पता पार्कर उसे समेट सके तथा बहाल होनेकी दरखास्त पेश होवे समयभी कर्जदारका इस प्रकारकी बातोंकी जानकारी उसकी बहालकी दरखास्तका विरोध कर सक्ते हैं। देखो—गिरधारी बनाम जयनारायन 32 All. 645.

उपदफा (३) में पर्याप्त कारणसे तात्पर्य उन कारणोंसे समझना चाहिये जो जायदाद कीबानीके आर्डर (XVII) १० क्ल १ के अनुसार पर्याप्त कारण माने जासक्ते हैं। शहादत खवानी या लिखित दोनोंहीसे तात्पर्य है तथा दोनोंहीके देनेके लिये मौका लिया जासक्ता है। गवाहान व सुदूतके कायनात उसी प्रकार तलब किये जासक्ते हैं जिस प्रकार जायदाद कीबानीके अनुसार तलब किये जासक्ते हैं।

[- उपदफा (४) में शहादत लिये जानेका उद्देश्य है शहादत उस प्रकार खीजनेकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि कीबानीकी अदालतोंमें खीजाती है इसमें उस प्रकार खीजासक्ती है जैसा कि सरसी यादवाई करनेमें खीजाना चाहिये परन्तु जो शहादत खीजावेगी उसको लिखा जाना चाहिये तथा उसकी असली सब बतों अदालतकी नोट कर लेना चाहिये वह अदालतकी मिसिलमें शामिल रहेंगी।

यदि कर्जदारके लहनेका मूल्य कर्जोंसे अधिक होतो कर्जदारका इस बिना पर यह नहीं कह सकता है कि कर्जदार अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ नहीं था देखो—हरनाम सिंह बनाम गोपालदास देसराज 109 I C 370, यदि अदालत किसी कर्जदारकी दरखास्त इस बिना पर खारिज कर देवे कि उसे दरखास्त देनेका कोई हक नहीं था तो अदालत का यह हुक्म और कर्जदारकोके खिलाफ अग्र तन्वीज शुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा। केवल इनके पास कोटिस पहुँच जानेहीसे यह नहीं मानलिया जावेगा कि वह हर मानके लिये कर्जोंक मुकदमा बना लिये गये हैं। देखो—110 I. C 730 (2)=A I R 1928 Sindh. 121.

यदि दिवालियेका दरखास्त किसी कर्जदारने दी हो तो दिवालिया करार देनेका हुक्म देने समय अदालतके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णरूपसे दरखास्तमें दिसलाये हुए कर्जोंकी जानकारी करे या उन बातोंकी खोज कर जिससे कर्जदारका जायदाद खीजाना या धीरेधीरे जायदादका हथका जाना साबित हो। ऐसी बातोंकी जानकारी दिवालिया करार दिये जानेके बाद तथा उस समयकी जाना चाहिये जबकि दिवालियेकी जायदाद रिक्तीवर या अदालतमें सुप्रीममें आजावे। देखो—109 I. C. 552.

दिवालिये करार देनेकी दरखास्त पर विचार करते समय अदालतकी चाहिये कि वह जायदादकी मौजूदा कीमतका जिससे कि उसके कर्जें चुकानेमें जायदादका यह देवे कि आधा दफा २४ (९) का ध्यान रखते हुए कर्जदारने अपने कर्जोंको न अदा कर सकनेकी बात साबित करदी है या नहीं देखो—A. I. R 1928 Nag. 226.

कर्ज न अदा कर सकनेकी बात साबित करनेके लिये यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कर्जदारका लहना उसके कर्जोंके कम है क्योंकि यदि कर्जदार अदालतको निश्चास दिल दे कि गो उसका लहना उसके कर्जोंके कम नहीं है किन्तु वह अपने कर्जोंको चुकानेके लिये अपनी सब जायदाद प्रयत्न कर देने परभी असमर्थ है तो अदालतकी यह मानना

चाहिये कि वह कर्जदार अपने कर्जों में चुसमोंमें असमर्थ है। देखो—109 I C 552=A I R 1929 Lah. 87. इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दिवालयियों द्वारा दख्खान देने वाले कर्जदारों का कर्तव्य है कि वह अदालतों के सामने पेश हो तथा उपरिष्ठ कर्जदारों से उनके प्रभु करने पर अपनी जायदाद तथा बर्जों आदिसे वारोंमें पूरा हाल बतलाव। यदि कोई कर्जदार यह बयान करे कि वह कर्जों अदा नही कर सकता है तथा यदि उसका जायदादमें तत्काल रुपया बमूज नहीं होना मना है तो कर्जदारका यह कदम कि वह अपने कर्जों को अदा नहीं कर सकता है अवश्य ठीक मान लेना चाहिये जबतक कि यह सचिज न हो जाये कि उसके सब बर्जों कर्जों हैं या उसने कित्ता दूमरा उद्धारमें दिवालेहों द्वारा दख्खान दी है तब तक इस बातसे कि कर्जदारके पास बहुतसी जायदाद है यह न समझ लेना चाहिये कि वह अपने कर्जों को अदा कर सकता है। A I R. 1928 Mad 1193.

दफा २५ दरखास्तका खारिज होना

(१) जबकि दिवालेही दरखास्त कर्जतबाह द्वारा की गई हो और अदालतका यह यकीन न हो कि उसे दरखास्त देनेका हक है या इस बातका यकीन न हो कि दरखास्तके लिये जानके हुक्मका नोटिस कर्जदारको पहुँच गया है या बलाये हुए दिवाले के कामका यकीन न हो या कर्जदार इस बातका यकीन दिला देय कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है या किसी दूसरे मुनामिय कारणसे यह स्वयंमें आवे कि कोई हुक्म न दिया जाना चाहिये तो अदालत दरखास्तको खारिज कर देगी।

(२) जबकि दरखास्त दिवाला कर्जदारने दी हो और अदालतको यह यकीन न होय कि कर्जदारको दरखास्त देनेका हक है तो वह उस दरखास्तको खारिज कर देगी।

व्याख्या—

इस दफामें उन मामलोंका उल्लेख है जिनसे कारण दरखास्त दिवाला खारिजका शक्तता है यह दफा, समझना बनाई गई है निम्न कि कर्जदार अपने कर्जोंमें बचने या गिरफ्तारसे बचनेका चाहते दरखास्त दिवाला देकर बना क्रायदा न उठा सके देखो—A I R. 1924 All 800

इस दफाके आधार पर दरखास्त खारिज की जाने पर बारी अर्जी हाईकोर्टमें की जा सकती है देखिये दफा ७५ (१) गेकि दफा २४ के अनुसार कर्जदारका जाना होते समय उसमें उसकी जायदाद आदिसे सम्बन्धित तय जायदाद है परन्तु फिर भी दफा २५ में यह नहीं बतलाया गया है कि यदि कर्जदारकी बदनामी साबित होय तो वह दिवालयी कारण नहीं दिया जाना चाहिये जहाँसे बदनामी अधिक कारण कर्जदार दिवालयी बनना नही रोका जायता है किन्तु बहाल होनेकी दरखास्त देने समय उसकी बदनामी आदि प्रभु सचिज न हो जायता है तो भी उनमें लाभ उठना जासम्बदा है। दला—गिरवार गरी बनाम जनगणन 32 All 40, 60 I C 848

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि इन दफा के अनुसार तदर्थकित करने समय इस प्रसंग तय करनेकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जदारने अपनी राय जायदाद ठीक ठीक दित्याह है या न। समझना यस्त कि क्या कर दिने जानका हुक्म दिये जाने पर बाद तय किया जायता है देखो—46 Bom 107. दिवालयी जानका प्रभु उम बच उठना होता है जब कि नही होनेकी दरखास्त देने उसमें पहिले नहीं दाखे—A I R. 1926 Mad 494.

इन बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि गुप्तमें रजिस्ट्रारने उसकी नकल चलि सधायमें कोई प्रसंगी नहीं पूछे जायते हैं गो इन प्रसंगों में निगणन शुल्क नही दिया जाना चाहिये किन्तु कि भी ऐसे प्रसंग बतला जाय हो सके

पूछना चाहिये किममें जल्दीमें जल्दी कर्जदारके सम्बन्धी ठीक बातों का पता लग सके तथा अधिकतर उनमें उचित लाभ उठाया जा सके । देखो—36 Mad 402.

हमारा यह सम्बन्धित दिवालयके खासिये करनेसे यहिसे अत्यन्तकर कर्जदार है कि वह नामके पूर्ण रूपसे सम्बन्धित हो जायित वरे तथा दम्बालन खासिये करनेके कारणसे अपने हुक्ममें दिव्यवाक इलाहाबाद हाईकोर्टने पुनर्दिष्ट चाफ जस्टिस (Acting Chief Justice) वाश (J Walsh) गह्वरा कल्ला था कि यह दफा उन जजाक लिप जो गामलकी मयहनका प्रथम नहीं करते हैं एक प्रचारका नाल है देखो—तापत्रन्द बनाम शुगुलकिशोर 46 All 71= 22 A L J 684.

दरदुवास्त दिवाला खासिये किये जानेके कारण यह हो सकते हैं:—

(१) उस समय जबकि किसी कर्जदाराने दरदुवास्त दी हो—

(॥) यदि कर्जदारको दिवालयके दरदुवास्त देनेका हक दफा २ के अनुसार प्राप्त न हो

(॥) यदि कर्जदार या दिवालयकी दरदुवास्त शुनरतक नाटिमकी मामला न हुई हो

(॥) यदि दरदुवास्तमें दिव्यवाक हुआ कर्जदारके दिवालयका नाम साबित न होवे

(॥) यदि कर्जदार यह साबित करे कि वह अपने कर्जोंसे ज्यादा कर सकता है

(॥) यदि दरदुवास्त नामकर करनेके लिये पर्याप्त कारण होवे ।

(२) उस समय जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालयके दरदुवास्त दी हो—

(॥) यदि कर्जदारका दफा २० के अनुसार दरदुवास्त देनेका हक प्राप्त न हो केवल कर्जदारही इस बिना पर एक सक्ता है कि वह अपने कर्जोंका चुकानेमें असमर्थ नहीं है दूसरे कोई व्यक्ति इस बिना पर नहीं लक सकता है जसे कि यदि कर्जदारने जिसके हकमें जगहाद कर या हा हा विसक हकमें जगहाद करे गहरे वेद इस बात पर महा लक सत है कि कर्जदार दिवालयका दरदुवास्त दिये जाने समय अपने कर्जोंका चुका करता था । तथा—A. I. R 1929 Lah. 79

यदि दरदुवास्त कर्जदार उतार या गई हो तो भी वह इस बिना पर खरिदनी जासकती है कि कर्जदार अपने कर्जोंको अदा कर सकता है अथवा नहीं । अर्थात् कर्जदार द्वारा दी हुई दरदुवास्त पर यह मानिये हाने पर कि वह अपने कर्जोंका अदा कर सकता है यह आवश्यक नहीं है कि दरदुवास्त दाता बिना पर खासिये करता जावे देखो—मिथपा बनाम कयनायन 32 All 647, 41 I C. 850, 73 I C 74

जिसपर ऊपर कहा जाचुका है कि कर्जदारका दरदुवास्त कबल हमारा बिना पर खरिदनी जासकती है कि हमको दरदुवास्त दिवालयका पेश करना हक प्राप्त नहीं है कर्जदारके दरदुवास्त दिवालयका पेश करनेका उच्च दफा १० में है और यदि दफा २० में बतलाये हुए निमाका पात्रन पूर्ण रूपसे महा होता है तो कर्जदारकी दरदुवास्त दिवाला खासिये जासकती है । परन्तु यदि दफा २० में बतलाये हुए निमाका पात्रन पूर्ण रूपसे हुआ है तो दरदुवास्त दिवाला अवश्य मजूर की जाना चाहिये । अतः करने के निमाके नेम कायदा खासिये बिना पर दरदुवास्त दिवालयके खासिये जानेका उच्च दफा दफा नहीं है ।

इस दफाके हाईकोर्टने बहुत महा निमित्तन किया था कि यदि दरदुवास्त अदा करने के निमाका बिना पात्रदा उतावेरी मगान दी गई हो तो पूर्ण दरदुवास्त अदागत इस बिना पर खासिये कर सकता है पन् 44 Cal. 535 में थिरी काजगल 1922 नमोन यह दफा का दिये है कि दरदुवास्त कबल हमारा बिना पर खासिये महा कर देना चाहिये कि नस

अदालत नियमों में वेना कायदा जमाने की सरतसे दायर है यदि इस एक में बतलाये हुए सब नियमों का पालन किया गया हो। कर्जदार की दरखास्त दिखला इस बात पर खारिज नहीं कानूनी कि उसने अपनी दरखास्त में कुछ गणनादकी जियाया है या अपना जामदारू वसमें चालत धार दिया है या अपने कर्जों का ठरक २ व्याय नष्ट दिया है दूनों—आपन बनाम साइनल 8 I C 1115; 38 I C, 822.

इसी प्रकार यदि कर्जदार बाकायद दिमाक किया नहीं रखा हो तो इसका बिना पर उसकी दरखास्त दिखाना नाममात्र नहीं की जा सकती है देखो—A I R. 1927 Lah 27 दरखास्त इस बिना या भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदार व कर्जदार का गाई मुअररा है और वह भारी शामक दरखास्त नहीं किया गया है दूनों—40 All 75 दिवालिया दरखास्त इस बात पर खारिज नहीं कानून धारिय कि कर्जदारने बददीयता का पालन लिया है तथा वसते पोषादहीत जामदारूकी अन्ध कर दिया है दूनों—12 C L J 400, 40 All 665

दरखास्त दिखाना इस बात पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदारने दरखास्त दूने के बाद तथा उसके सुने जाने से पहिल किमी कर्जदारको रुपय की अग्रगणी की है देखो—तागाचद बनाम उगुलकिओर 46 All. 713 दरखास्त इस बिना पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदारने उमम कुछ कल्प कर्म दिये हैं दूनों—मुसालास बनाम भागवानदास 26 I C 24, 37 All 252

केवल इस बिना पर कि नजर एक नईमान आदमी है उसकी दरखास्त दिखाना खारिज नहीं की जा सकती है गो उसके बहाल होने समय तक बात पर पूर्ण रूपसे तबतार किया जाना चाहिये देखो—निर्मलील बनाम अयोध्याप्रसाद 37 I. C 391.

अदालत इस दफा में बतलाये हुए किमी दूनों पर्याप्त कारणों के आधार पर केवल उन्हीं दरखास्तों को खारिज कर सकती है जो कर्जदार द्वारा दी गई हैं अर्थात् कर्जदार द्वारा दायरे दरखास्तों को रोकित दूनों पर्याप्त कारणों के आधार पर खारिज नहीं करेगा दूनों पर्याप्त कारण वह प्रकार के हो सकते हैं जिनका निगम करना अत्यन्त क्लेशमय है बहाल रूप में यदि कर्जदार यह दिखलावे कि उसके कुछ निगम उसके तब कर्जदार पूर्ण रूपसे अग्रगणी प्रकट कर देंगे तो यह पर्याप्त कारण समझा जा सकता है इस प्रकार कर्जदारका यह सविद करना कि उसके कुछ मापों चल रहे हैं तथा उनके तब जाने में वह अपने सब कर्जों को पूरा करेगा पर्याप्त कारण समझा जा सकता है देखो—तागाचद बनाम उगुलकिओर 46 All 713

दफा २६ हर्जेका मिलना

(१) जबकि कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्त दफा २५ (१) के अनुसार खारिज हो जाये व अदालतको यह यकीन होजाये कि दरखास्त फिजूल है या पेशान करनेकी गरजसे दी गई थी तो कर्जदारके दरखास्त देनेपर अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियों दरखास्त देने वाल कर्जदारको (१०००) एक हजार रुपये तक जैसाकि वह मुनासिब समझे बतौर हर्जेका कर्जदारको उन्के खर्च मुकदमा व नुकसानके बावत जो उस उस दरखास्त दिवालियों के सम्बन्धमें उठाना पड़ा है दिलावे और यह हर्जा बतौर मुनासिक वसूल किया जासकता है।

(२) इस दफाके अनुसार यदि कोई हर्जा दिला दिया जावेगा तो उस दरखास्त दिवाला या उसकी कार्यवाहियों के सम्बन्धमें कोई हर्जेका नालिश नहीं चलेंगी।

व्याख्या—

(१) दफाके अनुसार अदालत दिवालियों अधिकार प्राप्त है कि वह (१०००) एक हजार रुपये तक बतौर हर्जेका

उसके दायवास्त देने पर उसका कार्यागार भली प्रकार जांच देनेने पश्चात् इस एकमे बन्द्याप- हुए विमोके अनपार कजग-
दण्डा भागी दहाया आसक यदि उसन कोई ऐसा कार्य किया हा । 1- न्यिके लर भी एउ प्रकाशक सुवधा हा गई है
क्योंकि वह भागित समयके अंदर बहान्नी दख्खान देकर अपने विगड हुए पिछल कामने छुटगा पामकता यदि
उसने बंदीपनामे दख्खान नहीं दी है या उसने कोई अनियमित कार्य नहीं किया है ता अदालत उसे अवश्य बहा-
न देगा उपदफा (२) के अनुसार बहाल होनेका दायवास्त देनेका समय, अवसर तथा आवश्यकताके अनुसार बहाल भी
पामकता है इस प्रकार समय हुक्ममें वनमूल्य हुए समयके समाप्त हो जानेके पश्चात् भी बहाल जासकता है दली- A I
R 1924 Cal 777, A I R 1926 Sind 94, A I R 1929 Nag 11 (१).

समय बहानेकी दख्खान फर्जदार व फर्जदार दोनों हा दे सकत है क्याकि इस दफाके जामनामे यह नहीं बतयाया
गया है कि दख्खान किस दना चहिये । दली- A I R 1928 Lah 82, A I R 1927 Lah.
763 (1); गोपालाम बराम मगनीयम (A. I. R 1928 Pat 318) में यह तय हुआ था कि जदामतकर
कर्मचारी न कि बड अपने हुक्ममें बहाल होनेका समय अवश्य दिखता उके । बाद हुक्ममें बतयाय हुए समयके अंदर बहाल
हानेकी दख्खान न दी गई हो तो भी अदालतने उस समय तक आर समय बहा देनका अपिनार है अन तक कि दिवा-
लिया दिये जानेका हुक्म ममूल न किया गया हो । हुक्ममें दिये हुए समयक समाप्त हा जानेक पश्चात् दिवा-
लिया हुक्म अपन आप ममूल नहीं हो जाता है ।

दिवा-लिया करार दिये जानेके हुक्मकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है फन्नु यदि उपदफा (२) के अनुसार
समय न बहाया गया हा ता एह हुक्मकी अपील नहीं हा लेनेका देखा- A I R 1926 Oudh 186 तथा 105
M L J 837

दफा २८ दिवा-लिया करार दिये जाने वाले हुक्मका असर

(१) दिवा-लिया करार दिये जाने वाले हुक्मक होजाने पर दिवा-लिया अपपी शक्ति भर
अपनी जायदादके बसूल होने तथा उसकी कीमत कर्जदारोंमें ठेक सौर पर घटनेमें मदद देगा ।

(२) दिवा-लिया करार दिये जाने बल हुक्मके होने पर दिवा-लियेकी सय जायदाद
अशालत या किसी रिलीवरकी जैसा कि आगे दिया हुआ है समझी जावगी और उसके बाद
इस एन्टमें दिये हुए ब्रह्मचरोंका छुंडकर दिवा-लियेके किसी कर्जदारको किसी ऐसे कर्जेक
सम्बन्धमें जो इस एन्टक अनुसार साबित किया जासकता है दिवा-लियेकी कार्यवाईके दौरानमें
दिवा-लियेकी जायदादक खिलाफ किसी कार्यवाईके करनेका हक न होगा और बिला अशालत
की आशाके या उसकी शर्तके खिलाफ कोई मुकदमा या दूसरी अशालती कार्यवाई करमेका
हक भी न होगा ।

(३) दफा २८ (२) के लिये घट सय माल दिवा-लियेका समझा जायेगा तारीखके
दिन जिस पर कि हुक्म दिया गया हो दिवा-लियेके कज्जे, हुक्मत या निगरानीमें उसने व्यापार
या कारोबारके सिलसिलेमें असली मालिककी रजामन्दी व इजाजतके साथ ऐसी शकलमें हागा
कि लोग उसको उस मालका मालिक समझत हों ।

(४) दिवा-लिया करार दिय जाने वाले हुक्मके बाद बहाल होनेसे पहिले जो जायदाद

दिवालिया पैदा करेगा या पावेगा वह अदालत या रिसीवरको समझी आवेगी और उस जाय-जादक सम्बन्धमें दफा २८ (१) के नियम लागू होंगे ।

(५) इस दफाके अनुसार वह सब चीजें 'हिंसाबकी किताबोंको छोड़कर' जो जायता दीवानी या किसी दूसरे प्रचलित कानूनके ज़रिये कुर्बी व नीलामसे बरी है दिवालियेकी जायदाद नहीं समझी जावेगी ।

(६) यह दफा महफूज़ कर्ज़ेवाहके उन अधिकारोंमें कोई बाधा नहीं डालेगी जो उसे अपनी ज़मानत घसूल करने या जमानतके लिये और कोई कार्रवाई करनेके लिये प्राप्त हैं और यह उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा जिस प्रकार वह इस दफाके न होते हुए कर सकता था ।

(७) जिस तारीखको दिवालेकी दरख्वास्त दी गई हो उसी तारीखसे दिवालिया करार देने वाला हुकमका सम्बन्ध समझा जावेगा और उसी तारीखसे वह कार्यरूपमें परिणित होवेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) यह उपदफा बिल्कुल नई है इसमें दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेका जो कर्तव्य है वह बतलाया गया है जसा कि दफा २२ में दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवालियारा कर्तव्य बतलाया गया है ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म (Adjudication)—ये परिभाषा उन हुक्ममें है जिनके द्वारा कोई कर्जदार जिसने या तो स्वयं दिवालिखाना दम्बलत दी है या जिनके विरुद्ध दिवालिखाने दाम्बलत दी गई हो अदालत द्वारा दिवालिखा घोषित किया जावे अर्थात् अदालत यह स्वीकार करले कि दरअसल वह कर्जदार कानून अपने कर्जोंको अदा करनेमें असमर्थ है और ऐसे हुक्मका प्रभाव यह होता है कि वह कर्जदार अपने कर्जोंकी शिमेदारीसे मुक्त हो जाता है तथा उस हुक्मके बाद उसकी सब जायदाद व एहवा अस्त-वस्त या अदास्त द्वारा निपुण किये हुए रिसीवरके अधिकारोंमें आनाती है जिसमें कि उसके लहनेकी वसूल करके उसके कर्जोत्पादोंमें हिस्सा रसरीके हिसाबसे बांटा जायने । साथही साथ इस उपदफाके अनुसार दिवालियेका भी यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ऐसे हुक्म होनेके बाद अपनी शक्ति भर अपनी जायदादकी बसूनी तथा उसके उचित रूपमें विभाजित होनेमें सहायता प्रदान करे ।

उपदफा (२) इस उपदफामें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका जो कानूनी अन्तर पैदा होता है उसका उल्लेख है पहिले सामने यह दिखलाया गया है कि इस हुक्मके बाद क्या २ होवेगा तथा दूसरे सामने यह बतलाया गया है कि क्या २ काम न हो सकेगा । दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होते ही दिवालिखाने सब जायदाद अदास्त या अदास्त द्वारा निपुण किये हुए रिसीवरकी सुपुर्दगीमें सपूरी जावेगी और वह जायदाद दिवालिखानेके कर्जोत्पादोंमें बांटी जावेगी ।
देखो— A I R. 1922 All 448.

तथा कोई कर्जोत्पाद जिसका कर्जो दस एवम्के अनुसार साबित किया जायकता है अपने कर्जोंके लिये दिवालिखानेकी जायदादके विरुद्ध कोई दूसरी कार्रवाई उस समय तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह दिवालिखाने गायला समाप्त न हो जावे और न अदालत दिवालिखानेकी आज्ञा बिना लिये हुए कोई मुकद्दामों चला सकेगा ।

जबकि कोई फर्म (Firm) दिवालिखा करार दी गई हो तो वह फर्मका हर एक साझीदार दिवालिखा समझना चाहिये और इसी कारण उस फर्मके किसी भी साझीदारके विरुद्ध बिना अदालत दिवालिखानेकी आज्ञाके कोई दावा नहीं किया जासकता है । देखो—100 I C. 112

- चूँकि दिवालियेकी जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुबनके अनुसार रिसीवरके आधिकारमें उस समयसे सम्पत्ती जाती है जबसे कि दिवालिया करार दिये जानेकी दस्तखस्त दी गई हो इसलिये उस जायदादकी अन्तर्गत हानन भी उसी तारीखहोसे सम्पत्ती चाहिये और यदि उस जायदाद पर उस तारीखके बाद कोई बर हो जावे चाहे वह किसी अदालतकी डिक्क अन्तुमार पैदा हुआ हो या और किसी प्रकार पैदा हुआ हो तो उसमें पाव नहीं रिसीवर पर नहीं सम्पत्ती जानेकी देवो—A I. R 1928 Loh 738. (A I R 1928 Lah. 258) में यह तय हुआ था कि डिक्कार दिवालिया मद्दतकी गोस्तराके अन्तर्गत हुबन द्वारा कर्वावारे उस बत तक नडा कर सकता है जब तक कि वह अन्तर्गत दिवालिया रवीकृत न होवे । बिना अदालतकी आज्ञाके दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेके हुबन मुकदमा नहीं चल सकता है देवो—A I. R 1928 Lah. 28

यदि कोई सयुक्त हिन्दू परिवार गारप करता हो तथा उस परिवारमें एक या इमेने अधिक नाबालिग होवें आर उस नाबालिगोंका बिना मनजर (कर्ता) न हाव तथा उस परिवारक सब बालिग बन्धन मय मेनेजर (कर्ता) के इत्ताफिया करार दे दिये गये हों तो सयुक्त परिवारकी जायदादको व्यापार सम्पत्ती कर्ताके अदा करनेके लिये अग्रहदा करनेके या अधिकार मेनेजरका प्राप्त है वहा अधिकार रिसीवरको प्राप्त हा जावगे आर रिसीवर नाबालिगके हिस्सेकी पाबन्द कर सकता है देवो—55 M. L. J. 721—A. I. R 1929 Mad. 166

यदि अदालत दिवालियाके अनिश्चित किसीदूर्ग अदालतमें दिवालियेके विरुद्ध किसी समयके करनेके लिये (Specific performance) बिसक करनडा नादा उसन दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किया हो नावा दायर किया गया हो तो उस अदालतको यह तय करनेका अधिकार नहीं है कि दिवालियेने किसी एक कर्तव्यवाहसे दूसरेके मुकामल भाषा दक्ष लग पहुँचानेका प्रयत्न किया है देवो—A I R 1928 Mad 860.

यदि अदालत दफा ४२ के अनुसार दिवालियाको बहाल होनेका हुबन न देवे ता उससे यह नहीं सम्पत्ती जावेगा कि दिवालियाकी कर्वावारे समाप्त होगई है और बिना अदालतकी आज्ञाके जैमाकि दफा २८ (२) में बतलाया गया है कोई मुकदमा दिवालियेके विरुद्ध दायर न किया जासकेगा देवो—A I R 1928 Rang 109 यदि अदालतकी आज्ञा लिय बिना कोई मुकदमा चलाया गया हो तो वह चल नहीं सकता है देवो—110 I. C 386 (1)

दिवालियेकी दस्तखस्त दिये जानेके पश्चात् दिवालिया अपने किसी कर्तव्यवाहका उचित रूपमें बर्त कर नहीं कर सकता है आर यदि इस प्रकार कोई कर्तव्य दिया गया हो ता उसका कोई प्रयत्न रिसीवर पर नहीं होया देवो—78 I. C 16.

दिवालियेकी जायदाद रिसीवरके अधिकारमें आजावने पश्चात् रिसीवरकी दिवालियेके कर्तव्यों चुका सकता है । यदि दिवालियेने या उसकी तरफसे किसी दूसरे व्यक्तिने कोई कर्तव्य रिसीवरक छिपकर कर्तव्यवाहोंकी दिया हो तो यह कर्वावारे निष्कुल बेकामया है और इस प्रकार जो कर्तव्य दिया गया हो वह रिसीवरकी वापिस दिया जाना चाहिये पश्चात् इसके कि अदालत आपसमें तसकिया (Composition) करनेके इत्ताफन देवे देवो—A I. R. 1926 Mad 1166

यदि दिवालिया बिना कर्तव्यवार समकतीमें साक्षात्कार होवे तो उसके उस कर्तव्यवार शरकताके हिस्सेपा रिमादका अधिकार सम्पत्ती चाहिये देवो—A. I. R. 1924 Mad. 223.

जबकि किसी कर्मके शरीकदारोंमेंसे कुछ दिवालिया करार दे दिये जावें तथा कुछ दिवालिया करार न दिये गये हों तो रिसीवरका यह अधिकार नहीं है कि वह उस कर्म समकतीके कुछ भाग पर अकेले ही कब्जा कर लेवे किन्तु वह दिवालिया न करार दिये हुए शरीकदारोंके साथ भाग शरकतीका भागिक होगा और यदि रिसीवर चाहे तो दिवालिया करार दियो हुए शरीकदारके हिस्सेकी उस कर्मसे लेसकता है देवो—42 Cal 225 तन्मन्वाह भी इस दफाके अनुसार जायदाद सम्पत्ती चाहिये देवो—21 I. C 950

अदि किंवा मित्र द्वारा भिन्नाना पिता दिवालिया करार दिया गया हा तो रिमीवर उस परिवारके समुक्त वावायिप लडतीरी जायदाद पर भा अधिार कर सकता है बतने कि पिताका कण व्यापकार आदरे लिय न भिया गया हो देखा—
44 All 319, 47 All 263, A. I. R. 1926 Mad 52.

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि किसी समुक्त हिंदू परिवारका कोई मन्वर दिवालिया करार दे दिया जावे और उसमें मम १ आयदाद हा उ में उससे लडने व पातोहा भा हक पत्रवता से तो रिमावर उस जायदादसे उमा प्रसार आहूदा कर सकता हैम प्रसार वह मन्वर स्वय अपने लाभकेलिय अहदा कर सकता था देखो—A. I. R. 1925 Pat. 117, A. I. R. 1924 Mad 350 (A. I. R. 1925 Pat. P. 89) में यह तय हुआ था कि गौ लडकेकी जायदाद बरने दिवालिया कण लिये जाने पर रिमीवरकी नहीं समझता चादिहे किंतु किंभी रिमीवरको अधिार है कि वह या ब्राम्भ जायदादसे लडने व शिसे पर भी सकता यह समझने दृष्ट करले कि वापरा कर्त चुकाना लडकेका भी कर्त है हराव निय और भा देना—48 All 400, A. I. R. 1926 All 262

ममान हाईकोर्टी पुनर्वचने यह तय किया है कि दिवालियेक लडफत आविभक्त हिस्सा रिमीवरकी सुपुर्देगीमें नहीं जाता है किंतु उसकी सुपुर्देगीमें वापरा वह अधिकार आजाता है जो उसे अपन लडकीरी जायदादका अहदा करनेके लिये प्राप्त है और इसी कारण रिमावर समुक्त हिंदू परिवारकी कुल जायदाद बच सकता है देखा—A. I. R. 1926 Mad 994, A. I. R. 1927 Mad 1

सीर व मौलसी काइत—किसी मालगुजतके दिवालिया करार दिए जाने पर उसकी सीरकी समीन रिमीवरके तहतम आजाता है किंतु उसका मौलसी काइत नहीं आवेगी देखो—A. I. R. 1924 Nag. 15b इस दाके अनुसार दिवालियारी मालकी (Occupancy holding) सन रिमीवरकी सुपुर्देगीमें नहीं जाती है और अजावत दिवालियागो उमके अहदा जाने आदिवा अधिार प्राप्त नहीं है देखो—43 All 510.

सरकारी या रेलवेके प्राविडेन्ट फण्ड—मे जा रकम मनजान दाखिल कराई जाती है वह जायदादीनीके अनुसार काइल दुर्ग नहीं है और इलायि को मिसार भी जो इस एकके अनुसार नियत किया गया हा ऐसी रकम पर अधिार कानेका हकदार नहीं है देखो—सेकेरी आफ स्पेड बनाम राजकुमार 50 Cal. 347.

इसी प्रकार पोलिटिकल पण्डन (Political Pension) भी अजावत या रिमीवरके अधिारमें नहीं जाससती यदि ऐसी पण्डनता कुछ हिस्सा अदा कानेका हुकम दिवालियागो दिया जावे तो यह कानून अजा नहीं है देखो—4 I. C. 145, 20 A. L. J. 172

यदि कोई कर्त ऐसा हो जो हम एकके अनुसार माविन नहीं भिया जासकता है या कोई जायदाद ऐसी है जो दिवालियारी नहीं है वा एमे रकम या जायदादके लिये यह दफा लागू नहीं होना देखो—39 All 204, 1925 A. I. R. Nag 77

उपदफा (२) अगम टेनेस एक्ट (Agra Tenancy Act) के अगि लागू नहीं है इसलिये लगान का दावा किया जाससता है और उसकी डिमी वजयका कराई जाससती है किंवा इस बात पर ध्यान दिय कि कोई मारिदाई अजावत दिवालियामें है या नहीं देखो—L. R. 3 A. 339 (Rev) 44 All. 296.

उपदफा (२) में यह नहीं मतगया गया है कि कदावद कबल उर्दू कर्जवाहोके अगि होगी मिनतो बादिम पहुँच चुका है या मय कर्जवाहोके अगि पगु अवधमें एक मामलेम यह तय हुआ है कि कदावद उर्दू कर्जवाहोके अगि सपक्षना चादिहे नि ह नोमिम हा चुका है उन लोयोरे अगि नहीं जिहें बादिम नहा मिसा है देखो—25 I. C. 708.

उपदफा (३) कुर्कनी जल वाले जगहों पर जमीन देवोस व जमिनियत हानि काटने व नष्ट दिवाणिया की जायदाद नहीं सनती जायगी जहाँ कि यदि दिवाणिया अपना कोई कर्जा दिया दूसरे के हकमें कर देवे और वह दूसरा व्यक्ति दिवाणियों के कर्जदारों की सूची अपने हकमें होयगी सूचना देवे तो ऐसा सूचना दे दिवाणियों का अधिकार उस कर्जदार को जायगा देखो—पुनः १ बच्चा व नम भाषण 25 Mad 406 इसी प्रकार यदि दिवाणिया कोई भाला किसी शस्त्र के पास भेजे तथा देखे रहता उसे ददेने तो वह माठ दिवाणियों के कर्जदार व जमिनियत में न समझा जायगा देखी—परमिता व नाम धन 38 Mad. 664.

यदि दिवाणियों अपने शेयर (Shares) किसी दूसरे के नाम कर दिवे हा परन्तु कोई बदनाम न मिल गया हो या कम्पनका नाम न दिया गया हो तो वह शेयर (Shares) दिवाणियों के अधिकार में समझे जायेंगे और उनके दिवाणिया कर्ज दिवे जाने पर अधिकार एसायना (Official assignee) की सुर्दाम में जायेंगे देखो—2 Bom 542.

उपदफा (४) इस उपदफा में अनुसार वह सब जायदाद भी जो दिवाणियों द्वारा किया करार देने के हकमें बादा तथा बहाल हानि पक्षित भात होगी अर्थात् या रिवाजों सुर्दाम में आजायगी और वह उपदफा २ के अनुसार भी जायकेगी देखो—दुर्गमद कागिना व नाम सुर्दाम माळ 44 All. 617. और भी देखो—फलाचन्द व नाम व नाम जगनाथ 101 I C. 442

इस उपदफा के आधार पर अर्थात् या रिवाजों के अधिकार हैं कि वह दिवाणिया करार दिवे जानके बाद दिवाणियों की आमदनी या तनखाइका कट हिस्सा राज्यशासन के लिये लम्ब करे देखो—देवायदा व नाम 40 All 218

उपदफा (५) इस उपदफा में यह बताया गया है कि वह सब चाने आ कानून के नही आ जायकेगी, इस दफा अनुसार जायदाद न समझा जायगी यदि वह अर्थात् या रिवाजों सुर्दाम में न आजायके परन्तु दिवाणियों के दिवाणियों इस प्रकार नचिन नहीं हैं ।

यदि बुन्देलखण्ड लैंड एलियन एक्ट (Bundelkhand Land Alienation Act) की दफा १६ के अनुसार जगह पेशाक आदमी जायदाद कुर्क नहीं आ जायकेगी इसलिये वह रिवाजों में होगी देखो—दुर्गमद व नाम इयनरायन 42 All 142, नेत्रि व नाम गनराय 4 I R 1920 All 467 मूले आरम्भ में दिवाणियों का रिवाजों में होगी और अर्थात् दिवाणियों के उक्त का हक में दिवाणियों के अधिकार में होगा देखो—मल्लिकार्जुन व नाम गच्छि 43 All 510.

सत्तासि या प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) रिवाजों की सुर्दाम में जायगी ।

उपदफा (६) मरहूम कर्जदार पर इस दफा में कोई प्रभाव नहीं पडता जहाँ अधिकार हैं कि कोई विन प्रकार कोई अपना कर्जदार व मरहूम के देखो—आनन्द व नाम व नाम 43 All 553

उपदफा (७) इस उपदफा में बताया गया है कि दिवाणियों द्वारा दिवे जाने वाले हक में प्रभाव उन तरीकाने समझा जायेंगे जिन तरीकानों दिवाणियों द्वारा जगह बांटे हो या दिवाणियों द्वारा जगह बांटे हो जाने के बाद दिवाणियों की कोई अधिकार अपना जायदाद अर्थात् दिवाणियों नहीं रह जाय देखो—गिननाय व नाम मुन्ना 42 All 483.

दफा २९ चालू कारवाइयोंका सेका जाना

अगर किसी अदालत में दिवाणियों के खिलाफ कोई मुन्हा या कोई दूसरी का कोई चल रही हो और यह ज्ञात हो जाय कि इन एक्ट के अनुसार दिवाणिया करार देने वाला हक

हो चुका है तो वह या तो उस कार्टवार्डको बंद कर देगी या उन शर्तों पर चालू रखलेगी जो उसे मुनासिब मालूम होंगे ।

व्याख्या—

यह दया नहीं है हमसे पहिले यह बनलाया जा चुका है कि दिवालियेके विरुद्ध कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जायेगा इस दफ्तेमें यह बनलाया गया है कि यदि कोई मामला या मुकदमा पहिलेसे चल रहा हो न उसके पश्चात् दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो तो ऐसे हुक्मकी सूचना मिलने पर उस मामलेकी सुनने वाली अदालत या तो उसका सुनना बंद कर देगी या उचित शर्तोंके ऊपर उसकी समाप्त करता रहेगी । अदालत उसी मामले या शर्तोंकी शर्त सहा है या उस पर शर्त लगा सकती है जो उसके मामले पर हों तथा उसी समय ऐसा करेगी जब यह भावित कर दिया जावे कि दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म दिया जा चुका है देखो—A. I. R. 1925 Mad 1051-48 Mad. 750.

यदि किसी कर्जकी वसूलाया मामला चल रहा हो और सुप्रीम दिवालिया क़ारार दे दिया जावे तो यह उचित होगा कि वह मामला रोक दिया जावे तथा कर्जकारको अपना कर्ज अदालत दिवालियामें साबित करनेके लिये छोड़ दिया जावे देखो—34 All 106.

इस दफ्तेके अनुसार मामलेकी रोक देनेसे यह अभिप्राय है कि जिसमें कर्जकारका अदालत दिवालियामें अपना कर्ज साबित करनेका अवसर मिल सके परंतु कर्जकार अगल ऐसा चाहे तो कर सकता है वरना यदि न चाहे तो उसी मामलेकी जाहू रखनेके लिये अदालतसे यह सज्जा है देखो—उपर शरीफ नवाम अलाउद्दौल्लाह A. I. R. 1924 Nag. 300

जबकि कोई शरीफ दिवालिया क़ारार दे दिया जावे तो अदालतकी चाहिये कि दूसरे क़रीनको हुक्म देवे कि अतिशय रितीवारी वह 'करीफ मुकदमा' बना लेवे और यदि आक्रियल रितीवार करीफ मुकदमा न बनना चाहे तो अदालत निज शर्तों पर चाहे मुकदमोंकी सुन सकता है देखो—A. I. R. 1926 1146.

दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म इनके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदार दीवानीकी किमी इमरान किमी हाथ बंधी गई हो और उसकी सूचना रितीवारी न दी गई हो तो ऐसी इमराने नीजाममें खर्चद्वारे वालका कोई एक रकम न होगा और रितीवारीकी जाहू है कि वह अदालत दिवालियामें दफ्तरात देकर ऐसे बंधे जानेका मसूदा बना देवे । देखो—44 Mad. 524.

इस दफ्तेके अनुसार पश्चात् केवल उन्हीं मामलोंकी लिये नहीं की जायेगी जो दिवालिया क़ारार दिए जाते पहिले दायर किये गये हों किन्तु उन मामलोंके लिये भी की जा सकती है जो उसके पश्चात् दायर किये गये हों परन्तु इमरान दायरसल के हैं इन दायर किये समय न रहा हो । देखो—A. I. R. 1924 Nag. 300.

इस दफ्तेमें यह साफ़ तौर पर प्रकट है कि मामलेकी सुनने आदिना कोई प्रश्न उस समय तक टारिफ़ न होयेगा जब तक कि दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म न दे दिया जावे देखा—A. I. R. 1926 Mad. 432. इस तौर पर यदि कोई दिवालियेकी दायरवात देदी गई हो परन्तु उस पर दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म न दिया गया हो तो केवल इसी बातसे इनपय डिक्रीकी कारवाही बंद नहीं की जासकेगी देखो—A. I. R. 1924 All. 707.

इस दफ्तेमें यह साफ़ नहीं किया गया है कि अदालत किस प्रकारके मामलोंकी दफ्तरात रोक देगी तथा किस प्रकारके मामलोंको जाहू रखेगी यह जाहू अदालतकी इच्छा पर ही छोड़ दी गई है तथा जिस प्रकारका मामला हो या जितनी सूचना अवसर पर सज्ज हो सके करीब आधिकार अदालतकी पास है इस प्रकार क़रारकी मसूदों या हुक्म इत्यादी अर्थात्

मामलेमें चाद रखनेका हुक्म देनाही उचित प्रतीत होता है जब्ज खानगी (Maintenance) का दावा उत वक्त मुद्दाकेद्वारे विरुद्ध चाद रखा जासकता है जबकि रिपीवर गी मुद्दाकेद्वारे बना लिया जाये देखो—A. I. R. 1927 Mad 403. इस दफामें जो दूसरी कार्रवाईका चिक है उससे तत्पर उस कार्रवाई समझना चाहिये जो मुकद्दमेंके तौर पर होने या या किसी मुकद्दमेंके दौरानमें करी हो देखो—A. I. R. 1928 Cal. 782 (F. B).

दफा ३० दिवालिया करार देने वाले हुक्मकी सुस्तरी

१) दिवालिया करार देने वाले हुक्मका नोटिस सरकारी प्राप्तिक गजटमें या अन्य किसी नियत किये हुए रूपमें प्रकाशित किया जावेगा और उस नोटिसमें दिवालियेका नाम, पता व पेशा रहेगा तथा उस मियादका भी उल्लेख रहेगा जिसके भीतर दिवालियेको अपने बहालकी वरखास्त दे देना चाहिये और उसमें उस अवसलतका भी नाम होगा जिसने उसे दिवालिया करार दिया हो ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके पश्चात् इस हुक्मका सरकारी गजट या अन्य किसी निर्धारित रूपमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक बनलाया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि इसमें निम्न लिखित बातें प्रकाशित की जानी चाहिये ।

- (१) दिवालियेका नाम पता व पेशा
- (२) दिवालिया करार दिये जानेकी तारीख
- (३) वह मियाद जिसके आदर दिवालियेकी बहाल होनेकी वरखास्त देना चाहिये, और
- (४) उस अवसलतका नाम जिसने कि दिवालिया करार दिया हो ।

नोट —यदि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म गजटमें प्रकाशित होनेसे रद्द जावे तो यह कैदक देनारीकी समझना चाहिये तथा इसकी वजहसे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म रद्द नहीं समझा जावेगा या उसका अमर नहीं जाता रहेगा देखो—10 P R. 1900.

दिवालिया करार दिये जानेके बादकी कार्रवाई

दफा ३१ दिवालियेकी रक्षाका हुक्म

(१) दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अवसलतमें रद्द वरखास्त देसकता है और अवसलत उस वरखास्त पर दिवालियेको कैद व हिरासतसे बचानेका हुक्म दे सकती है ।

(२) रक्षाका हुक्म कर्जदारके सब कर्जोंके लिये या उसके किसी एक कर्जोंके लिये दिया जासकता है जैसा कि अवसलत उचित समझे और वह हुक्म उस वक्त व उतने समयके लिये लागू होगा जिसके लिये अवसलत हुक्म देवे और अवसलत उस हुक्मको रद्द कर सकती है या और बढ़ा सकती है ।

(३) जिस कर्जके सम्बन्धमें रक्षा हुन दिया गया हो उसके लिये दिवालिया जेल या हिरासतमें नहीं रहेगा और अगर कोई दिवालिया ऐसे हुक्मके विरुद्ध कैद किया गया या रोका गया हो तो वह छोड़ दिये जानेका इकद्वार होगा ।

परन्तु शर्त यह भी है कि इस किरमका कोई हुक्म जबकि वह मंजूर कर दिया गया हो या जबकि दिवालिया करार देने वाला हुक्म रद्द कर दिया गया हो कर्जएवाहके अधिकारोंके प्रयोगमें रुकावट नहीं डाल सकेगा ।

(४) हर कर्जएवाहको अधिकार है कि वह हाजिर होकर उसके हुक्मकी मंजूरीकी मुखातिफ करे ।

व्याख्या—

पिछले एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेकी दिवालिया बिना किसी दरवास्त आदिसे दिये हुए ही हिरासत आदिसे बचनस हकदार से जाना था परन्तु इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियाके दरवास्त देने पर यदि अगल चारे ती उत्तरी रक्षा हुक्म दे सकता है । इस दफ्तरा प्रयोग दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म है । जानेक पश्चात् ही लिया जावेगा देखो—A. I. R. 1924 Mad 893

इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अदालतमें दरवास्त दे सकता है ।

ऐसा स्पष्ट होता है कि इस एक्टके अनुसार रक्षा इतनाई हुक्म नहीं दिया जासकता है जो दफा २३ के अनुसार बन्दर दिवालिया करार दिये जानेमें पहिले ही कैद या हिरासतसे मुक्त किये जानना अधिकारी है । देखो—A. I. R. 1926 Cal 1011 में यह तथ हुआ था कि जब तब दिवालिया प्रत्येक दिये जानेका हुक्म होनासे तब तक रक्षाके लिये हुक्म देनेकाई नहीं जारी लिया जासकता है ।

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि अदालत दिवालिया करार दिये जानेके बाद रक्षा हुक्म देनेके लिये माग नहीं है अपितु वह अपनी इच्छानुसार हुक्म दे भी सकती है तथा उसके देनेसे इनकार भी कर सकती है । रक्षा हुक्म देने समय अदालतको चाहिये कि उपस्थित अवस्था तथा दिवालिया द्वारा दिये हुए कार्योंका ध्यान रहे और यदि दिवालियेने बर्तमान व बन्नीयतीसे किञ्चल खर्च आदि करके अपनी यह दशा बरती हो तो अदालत ऐसी दशामें रक्षा हुक्म नहीं देवेगा देखो—40 Bom 461.

उपदफा (२) अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षा हुक्म सिरी एही बजेंके सम्बन्धमें देवे या दिवालियाके सब बजेंके सम्बन्धमें दे देवे अदालतको जाने हुक्ममें यह दिवना देना चाहिये कि रक्षार्थ हुक्म सब बजेंके लिये दिया गया है या किसी काम केके लिये दिया गया है यदि हुक्ममें कोई ऐसा बजेंक न हो तो यह समझना चाहिये कि रक्षा हुक्म सब बजेंके लिये है ।

अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुक्म किसी खास मियादके लिये देवे तथा यह भी निश्चित कर देवे कि कबसे वह रक्षाके हुक्मका प्रयोग समझना चाहिये अदालत जाने रक्षाके हुक्मको रद्द भी कर सकती है व साथही बढ़ा भी सकती है । रक्षार्थ हुक्म जो दस दफाके अनुसार दिया जावेगा वह केवल उन्हीं बजेंके सम्बन्धमें हो सकता है जो इस एक्टके अनुसार स्थापित किये जासकते हैं देखो—हायल नगम तुम्सीराम A. I. R. 1925 Nag 77.)

उपदफा (३) कर्जएवाहको अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुक्म देते समय उपस्थित होकर उस हुक्मके देनेमें विरोध करे । इस उपदफामें यह बात स्पष्ट है कि रक्षार्थ दरवास्त पर निवार करनेसे पहिले उसकी सूचना उग कर्जएवाहको

भी हो जाना चाहिये जिनका उग दायित्वमे सम्बन्ध है देखो—25 C L J 456, 25 C. L J. 149. कन्यादान रक्षा दायित्वमा विषय उस पर हुनम हमिसे पाइयेही कर सक्ते हैं हुनम होनानक परान्त् बह हाजि होर उदरा विगेष नही कर सक्ते ।

अदालत दिवालियाको तरफसे कर्जे (Crown debts) के सम्बन्धमें एगान हुनम देनेका कोई अधिकार नहीं है देखो—A. I. R. 1928 Rang 81=109 I C 145

दफा ३२ दिवालिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार

अगर दिवालिया करार दियेके बाद कोई कर्जदारगह या रिसीवर इन बातकी दरखास्त देवे कि दिवालिया छिप रहा है या अदालती अधिकार सीमासे बाहर इस इनादेसे बला गया है कि जिसमे वह अपने कर्तव्यकी पूर्तिके लिये बाधित न किया जासक या इस एक्टके अनुसार कोई कार्यवाई उसके बिच्छ न की जासके और अदालतको एसी दरखास्त पर यकीन हो जावे तो उसे अधिकार है कि यह दिवालियाकी गिरफ्तारीके लिये बाराहट जारी कर सकती है इसके पश्चात् दिवालियाके हाजिर होने पर या उसके गिरफ्तार होने पर अगर यकीन हो जावे कि वह छिपा हुआ था या ऐसी इच्छासे भागा हुआ था तो उसे जमानत आदि की उन शर्तों पर छोड़ सकती है जो उचित व आवश्यक मतीन हों और अगर जमानत न दी जावे तो यह हुक्म दे सकती है कि वह दीवानीकी जेलमें रखा जाव लेकिन यह हुक्म तीन महीने तकके लिय दिया जा सकता है ।

धाराया—

दिवालिया करार देनेके बाद अदालत आवश्यकता मतीन होने पर दिवालियाको गिरफ्तार कर सकता है तथा उसे जेल दीवानीमें भी तीन माह तक रख सकती है परन्तु यह कार्यवाई अदालत उन्ही समय कभी जबकि गिरफ्तार या कोई कर्जदारगह उसके अगले या भागनके सम्बन्धम दरखास्त देवे तथा अदालतको भी विग्यास हो जावे कि दरअसल दिवालिया उसके अधिकार सीमासे बाहर जाना चाहता था जिसमें वह अपने कर्तव्योंकी पूर्तिके लिय बाध 7 किया जानके तो अदालत उसके गिरफ्तार होनेका हुक्म देसगी परन्तु गिरफ्तार हानके बाद भी अदालत जमानत लेस या किसी दूसरे इगसे यह विदवात होनाने पर कि दिवालिया भागेगा नहीं किन्तु अपने कर्तव्योंका पूर्णक लिय प्रस्तुत इगना उसे सुन कर सकती है ।

अदालत इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये राय नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयावकूष हुक्म दे सकता है जिसमे कि दिवालेस कार्यवाहिमें भी कवायद न पड़े तथा दिवालियाको भी किसी गहार बना तरफको पोराना 7 हाना 7

दफा ३३ कर्जखानाहानकी सूची

(१) जबकि इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दिया जाचुका है तब यह सय कर्जखाना जो इस एक्टके अनुसार अपने कर्ज साबित कर सकते हैं अपने अगन कर्जोंके लिये सुवृत्त पेश करंगे कि उनका कितना कर्जा है व बित्त किम्बका कर्जा है और अदालत अपने हुक्म द्वारा यह निश्चित करेगी कि कौन २ लॉगोंने अपनाको कर्जदारगह साबित किया है और उनका कितना कितना कर्ज है इन लोगोंकी व उनके कर्जकी प्रक सूची तैयार करेगी । परन्तु अगर अदालतकी रायमें किसी कर्जकी तादाद ठीक तौरपर निश्चित नहीं की जासकती है तो अदालत इसी क्रिमका हुक्म लिख देगी और इस पर वह कर्ज सूचीम सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

उपद्रफा (१) इस एक्ट के अनुसार दो प्रकारके वर्जें हैं जो शक्ति नहीं मिले जायेंगे अर्थात् एक वे कहे और शिमेदारिया जिनकी कौमरता अदाया अदालत द्वारा नहीं लगया जायकता और जो इसी कारण सुचाते निराल दिये गये हैं दूसरे वे मांगें जिनका दर्जा निश्चित नहीं किया गया है या धुआहिदा शिकमी व अपानर्ममें लयानन सम्बन्धी इन्हीं साबित मिले जासकते हैं उदाहरण स्वरूप हमारे आदि सम्बन्धी दर्जोंसे ऐसा माग समझना चाहिये जिनका कि हमें निश्चित नहीं किया गया है तथा महर सुवचन (Deferred dower) में साबित करने योग्य वर्जों नहीं हैं क्योंकि यह भविष्य होने वाला कर्म है और यह नष्ट कहा जायकता कि वह कर्म होवेगा या होवेगा ही नहीं देखो—50 I C 774.

उपद्रफा (२) उन दो प्रकारके वर्जोंको छोड़ कर जिनका उद्धृत उपद्रफा (१) में किया जाचुका है नाकी सब कहे व शिमेदारिया (चाहे वह मौज्जा हों या भविष्यमें होने वाली हों चाहे वह निश्चित हों या अनिश्चित) साबितका ज्ञान योग्य है क्योंकि कि कर्जदार दिवालिया करार दिये जाने समय उनका पाबन्द हो या बहाल होनेमें पहिले उनका पाबन्द हो जावे और यह पाबन्दी दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मसे पहिले मिले हुए कामके कारण हुई हो यदि कोई शिमेदारी दिवालिया करार दिये जानेके बाद हुई हो तो वह इस एक्ट के अनुसार साबित नहीं की जायकती है देखो—48 I C 913.

यदि भाँवर २४ सल ६ के अनुसार किसी न बनजाई गई हो अर्थात् यदि रदननामके वर्जोंका मतान्दके मिले किसी न बनजाई गई हो कि तु वह मतान्दिका निरालता हो तो कर्जदार ई ऐसे वर्जोंके साबित करनेमें बाधित नहीं रहा जासकता । कर्जदार दिवालियाके लिये यह साबित होना आवश्यक है कि वर्ज दरअसल निरालता है देखो—A. I. R 1925 Pat. 438 यदि दिवालियामें कोई बड़ा दिवालिया करार दिये जानेके बहुत देर बाद लिया हो तो ऐसे प्रकारके वर्जों साबित नहीं किया जासकता पालु इस सलके सम्बन्धमें आहदा कर्जदारोंकी जासकती देखो—A I R 1925 Oudh 668.

दिवालिया करार दिये जानेके बाद यदि दिवालीमें कोई जियादा निरालता हो तो इस शिमेदारिके लिये यह नहीं माना जावेगा कि वह दिवालिया करार दिये जाने समय निरालता था और इस कारण इस दशके अनुसार साबित नहीं किया जासकता है देखो—A I R 1922 Oudh 73.

जबकि किसी सलु हिंदू परिवारका एक मेमबर दिवालिया करार दिया गया हो तो वर्जखाहको चाहिये कि अपना पूरा कर्ज (Joint debt) अदालत दिवालियामें साबित करे और वह उस सलुन कर्जका दिवालिया व इला दिवालिया मन्त्रोंमें बाँट कर अलहदा नष्ट दिखलावे देखो—A. I. R 1923 Nag 257.

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी

दफा २५ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके अख्तियार

जबकि अदालतकी रायमें किसी कर्जदारको दिवालिया करार नहीं देना चाहिये था या जबकि अदालतको यकीन हो जावे कि कर्जदारके सब कर्ज पूर्ण रूपसे चुकता हो गये हैं तो कर्जदार या किसी दूसरे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिने दरखास्त देने पर अदालत लिखकर दिवालिया करार देने वाले हुक्मको रद्द कर देगा और अदालत स्वयं ही या रिसीवर अथवा किसी कर्जखाहके दरखास्त देने पर भी दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको उस समय रद्द कर सकती है जबकि कर्जदार अपनी ही दरखास्तके कारण दिवालिया करार दिया गया हो परन्तु यह दफा १० (२) के अनुसार ऐसी दरखास्त देनेका अधिकारी न होवे ।

व्याख्या—

इस दफा में नीचेका हिस्सा इस एकटके बन जानेके पश्चात् जोड़ा गया है अर्थात् दिवालिज ससोधक एन० १ सन् १९२७ ई० के अनुसार यह भाग सम्मिलित किया गया है । दिवालिजा कगार दिखे जान बाल हुक्मकी मसूखीके लिखे दो बातें बतलाई गई हैं एक (१) तो यह कि जब अदालतकी रायमें दिवालिजा कगारही नहीं दिया जाना चाहिये था (२) यह कि जब दिवालिजेके सब कर्जे पूरे रूपमें चुका दिये जावें । परन्तु अब ससोधित एकटके अनुसार उस समयभी इस हुक्मकी रद्द किया जासकेगा जबकि अदालतकी रायमें कर्जदारको दफा १० (२) के अनुसार दरखास्त देनेका हकही न रहा हो । किन्तु ऊपर कही हुई दोनों बातों या दो म से एक भी बावक साबित होने पर अदालत दिवालिजा कगार दिखे जाने वाले हुक्मकी रद्द कानेके लिख बाध्य है परन्तु इस ससोधित भागके अनुसार हुक्मका रद्द करना तथा न करना अदालतके अधिकासे है ।

दिवालिजा यह नहीं रद्द सकता है कि कर्जदारको सूचना नहीं दी गई है इस कारण मसूजीका हुक्म उचित नहीं है दफा—A. I. R. 1926 Mad 123.

इस दफाके अनुसार हुक्म रद्द किये जानेका दरखास्त दिवालिजा रजय भी दे सकता है तथा दूसरे लोग भी दे सकते हैं अर्थात् गिमीबर कर्जदारों तथा अन्य कोई व्यक्ति जिसका मसूखीके हुक्ममें लाभ पहुँचना हो ऐसी दरखास्त दे सकता है । अदालत रजय भी बिना किसी दरखास्तके और हुक्म रद्द कर सकता है । दिवालिजा कगार दिखे जानेका हुक्म थोड़ाहीकी बिना पर अथवा इस बिना कि अदालतकी रायमें ऐसा करना फायदा उठाया गया है मसूख किया जासकता है देखो—44 Cal. 899. इस बिना पर भी मसूख किया जासकता है कि अदालत दिवालिजाने उसकी अधिकार सीमा न होते हुए वह हुक्म दे दिया था देखो—रामकमल बनाम बैंक आफ बंगाल 5 O IV N 91

इस बिना पर भी मसूख किया जासकता है कि वह हुक्म दिया ही नहीं जाना चाहिये था क्योंकि जिस दिवालिजेके कामके आधार पर वह हुक्म दिया गया था वह दरअसल मौजूदी नहीं था देखो—A. I. R. 1926 Mad. 1159.

यदि कोई बच्चा (Infant) दिवालिजा कगार दे दिया गया हो तो अदालत ऐसे हुक्मको रद्द कर देगी देखो—18 A. L. J. 611.

इस दफा में अदालतसे बेजा लाभ उठानेका कोई उल्लेख नहीं है और इसीलिए यदि दिवालिजा इस एकटकी सब बातों की पूरा करदे जिससे कि वह दरखास्त देनेका अधिकारी समझा जासक तो यह नहीं कहा जावेगा कि उसने अदालत की कार्यवाही से बेजा फायदा उठाया है इसी कारण यह दफा ३५ के अनुसार दिवालिजा कगार ही नहीं दिया जाना चाहिये था । जब कि दिवालिजाने अदालत द्वारा नियत की हुई मियादके अंदर बहाल होने की दरखास्त दा हा और सब जग ऐसी दरखास्तों मसूख न करे तथा अपील किये जाने पर जजने भी बहालकी दरखास्त मसूर न की हो तथा वह दिवालिजा कगार दिखे जान बाले हुक्मकी भी रद्द कर देवे तो यह तब हुआ कि जज हा ऐसा हुक्म उभक अधिकारसे बाहर था देखो—A. I. R. 1928 Mad 609

कर्जे अदा हो जाने पर हुक्मकी मसूखी उसी समय हो सकेगी जब कि जब जज पूर्ण रूपसे चुका दिये गये हों 38 Bom 200 बादेके सूदका भी कर्ज ही समझना चाहिये और यदि यह बादका सूद अदा न हुआ हो तो कर्जका पूर्ण अदागमी न समझा जावेगी देखो—48 All 272

यदि दिवालिजाने अपने कर्जदारोंका बाहरा तौर पर यह तय कर लिया हो कि वह सब लोगोंको उनके कर्जोंका चौथाई अदा कर दगा तथा वह लोग उसी चौथाईसे अपना पूर्ण कर्ज चुकाया समझवेगे ता ऐसे समझीके कारण दिवालिजा कगार दिखे जाना हुक्म रद्द दफाके अनुसार रद्द नहीं किया जासकता देखो—43 Mad 71

इस दफ्तरों यह नहीं नज़र आया गया है कि कब जोर से पूरी अदायगी किम प्रमाण द्वारा चाहिये अर्थात् दिवायिया स्वयं भी उन नशों की अदा कर सकना है अथवा कोई दूसरा स्थान भी जगही ज़ोरों से अदायगी कर सकता है। इस दुफ्तार अतिरिक्त अदवतिया ज़रार दिख जायेगा हुकूम और दफ्तरों के आचार पर या समुदाय किया जासकता है दली - दफा ४३, ४९ व २६ दिवायिया कयम। इसे आलक हुकूम की भस्म की जित्त कर की जाना चाहिये।

॥ हुक्मना मसूदाभिा अमर बह नदी होता है जो बहानके हुक्मना हुक्म हुआ जाता है देखो—A I R 1926
Lah 489 इस दफ्तेके अनुसार दिखे हुए हुक्मना अपाक दफा ७५ (२) तथा सिद्धूल १ ४ अनुसार परिणाम
का जामना है ।

दफा २६ एक साथ दिये हुए दो दिवालेके हुक्मको मंसूख करनेका अधिकार

अगर किसी मुकदमे में दिवालिया करार देने का हुक्म दिया जा चुका हो और हुक्म देने वाली प्रगत को यह साबित हो जाए कि उसी कर्जदार के खिलाफ दिवालिया करार देने की वृत्ति से चलते चल रही है और उस दूसरी अदालत द्वारा कर्जदार की जायदाद सुविधा के साथ तकसीम की जा सकती है तो उस अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिया करार देने वाले हुक्म को मंजूर कर दे या दिवालिया करार देने को रोक दे।

व्याख्या—

इस दफ्तरे यह बतलाया गया है कि यदि दिवाण्या करार देवेग हुकम देने बाग अदागतमे यह मानिन हो जाव
(१) कि हिम दूसरा अगलमे भी उमो दिवाणियेके खिलाफ लिवायेसी करिवाई चल रहा है तथा (२) यह कि उस
दुसरा अगलमे सुविधा पूर्वक दिवाणियी जायदाद बागेश अवसर ह ए एम दफ्तरे पा तां यह अगलमे अपने हुकममे
हद कर पा जाव अतः यह उम दिवाणे समझ रहा सेन करिवाईयोरा बदल देवेगी । इस दफ्तरे यह नहीं बतलाया
गया कि इस दफ्तरे अगलमे हुकम यह उमेस दखलावे मान दब पा तु दफ्तरे यह बाग प्रकट है कि दिवाल्याय
दस्तावेज दाता ए इम दफ्तरे अनुसार करिवाई करेन । अन्य अदागतमे कह सकन है तथा अदागत मय भा उपर बतला
हुई दोों बागोंके मानिन हाल पा करिवाई कर सकता ह ।

अद्वैत ही शांति के अनुसार हृदय देने के। तब ही य तदा हे इमं अनुसार हृदय मना अद्वैतता। इमं पर निर्भर है।

जब कि वरि पाया था अदायतों द्वारा अलग अलग दिवायिग। अगर द दिवा रगा हो ना पहिले निवालय करार
दी बाजा अदायत द्वारा नियुक्त किया हु। रिसावर दिवायिगस जायदादस अगिसी समझा जायेगा तथा दुहाग दिन।
तथा कसरा 120 पायस हुन हो जानर कागण उमरा अधिहार हुन नहा जायेगा। परतु अब कि यह मालूम पड कि वादस
दिवायिग करार देने वाली अदायत सुविधा पूर्वक दिवायिगस जायदाद वास सहती है। त दिवालय करार दिये जाने वास
पहिल हुनको द दिवा जासरा द देखा--42 Mad. 121.

[illegible]

अपन १५वां सम्बन्धी लिख दिया था । यह भा पता लगा कि रावलपिण्डा के कर्षकवाहनों के लिये दाना के कुछ समझौता कर लिया है और वह लोग रावलपिण्डा जायदादों से अपने कर्षकों को दाना हिस्साई चुकाने के लिये वापस आ गये हैं — इन कारिगारों पर हाईकोर्ट ने दाना यह सब किया कि दिवालियाई कर्षकों को दाना जमाने में उन्हें यह तथा यह सब करने की आज्ञा दी गयी कि उनमें से किस अपना दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म मसूदा करवा लाये देता — A I R 1928 Lah 848-109 I C 648

दफा ३७ मंसूखीके बादका कार्रवाई

(१) जबकि कोई दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मंसूख कर दिया जाये तो वह सब धनधन व जायदादके तकसीमनामेषबद्ध सब रूपोंकी अश्वयगो तथा मृत मय कामजो इस मंसूखीके हुक्मसे पहिले किये जाचुके हैं ठीक समझे जावेंगे । परन्तु ऊपर दी हुई बातको ध्यानते हुए दिवालिया करार दिये जाने वाले कर्जदारकी जायदाद उस शर्तकी मिलगी जिस अश्वयग नियोक्त करे या अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त न किया जाये तो वह जायदाद कर्जदारकी को उस हद तक उन शर्तोंके साथ जो अदालत अपने लिखित हुक्म द्वारा घोषित करे व पिसि खली जावेगी जिस हद तक कर्जदारका हक व हिस्सा उस जायदादमें पहुँचता हो ।

(२) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजटमें तथा अन्य किसी नियत किये हुए स्थानसे प्रकाशित किया जावेगा ।

व्याख्या—

यस दफा में यह बताया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका मसूजा में पाहल अदालत या निम्नलिखित कामकी कर चुकाना व सब काम बन्द हो जाय जात्रग तथा मसूजा में हुक्म हात में रख जायदाद दिवालियाई वापिस नहीं मिल सकेगा किन्तु अदालतको चाहिये कि कर्षकवाहानक हकोंका रक्षा करे मसूजा में हुक्म देत समय किता एम व्यावसाय नियुक्त कर देव जो जायदाद पर कर्षक व सके दता—A I R 1926 Lah 370, A I R. 1925 Sindh 159

यस में जब कि अदालत द्वारा जायदाद पर कर्षक लनेके लिये कोई एम व्यक्ति नियुक्त न किया गया हो वह वह जायदाद दिवालियाई की वापिस मिल जात्रग । यदि कामवरक पास मा उस समय कोई जायदाद बची हो तो वह भी दिवालियाई का वापिस मिल जात्रग । जब कि दिवालियाई कोई जायदाद या लक्ष्य मसूजा में पहिले ही बरबाद हो चुका हो तो उसका किय कोई सहायता नहीं है कि तु सिवावरक खर्च आदि मिहालनेके पश्चात् तो बचेगा दिवालियाई के पानेका अधिकारी है दली—मुन्चद बनाम खजूर A I R 1925 All 735, अरुविरी बनाम आकिशाल सिवावर 98 I C 1000

यदि दिवालियाई कर्षकोंके दौलतम सिवावर दिवालियाई का सारा दमके विरुद्ध दिवालियाईके भागने लिये दावा करे और इसका बाद दिवालियाई कर्षकोंके मसूजा बरबाद जाव ता इससे वह दावा समाप्त नहीं हो जावेगा कि तु दिवालियाईके अधिकारी है कि वह उस दावेकी उस समय अपने नामस चालू रख सक देवो—11 All 200

जिसी कर्षकवाहकी दस्तखस्त पर दो माई दिवालियाई करार दिये गये व होन नियत किये हुए समयके अंदर दंडाल होनेकी दस्तखस्त नही हो इस कारण अदालत दफा ३३ के अनुसार दिवालिया करार दिये गये वाले हुक्मकी मसूजा कर दिया जाय इससे पश्चात् अपने दफा ३७ के अनुसार उनमें से एकस जायदादकी मा सिवावरके अधिकारी आगे की

उसको वापिस कर दिये जानेवा हुकम दे दिया। परन्तु अर्थात्में यह हुकम हुआ कि आपदाद पुनर्निर्माणके अधिकारमें रखा जासकता था। पहिले इसके कि कर्जवाह कोई कर्जवाह करे उस पुनर्निर्माणके आपदादको बँच डाला तथा उसे सूचीके कर्जवाहानमें दिखाने साक्ष्य तकभोग्य^१ दिया—आदर हाईकोर्टने यह तय किया कि आपदादका बँच जाना तथा उसका रहस्यी नौरसे बचा जाना कानूनन उचित है देखो—A. I. R. 1928 Lah 453

उपद्रवा (२) में बतलाया गया है कि मसूखीका हुकम प्रार्थिक मर्यादा गच्छतम अवस्था प्रशासित किया जाना चाहिये तथा निर्धारित नियम हुए बिना दूसरे रूपमें भी उसे प्रवृत्ति कर देना चाहिये। मसूखीका हुकम होते समय दिवालिये की आपदादका कि ॥ शर्तोंके साथ दिवालियेको विरुद्धके लिये जो हुकम किया जान उसकी अर्थात् हाईकोर्टमें दफा ७५ (२) व शिष्टपुत्र १ के अनुसार हो सकती है देखो—100 I. C 137.

तसफिया तथा तय करनेका तरीका

दफा ३८ तसफिया तथा तय करनेका तरीका

(१) अगर कोई कर्जदार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम हो जानेके पश्चात् अपने कर्जोंके तसफियाके लिये रहे या अपने मामलोंको तय करनेके लिये कोई तरीका बतलावे तो अदालत उसे प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये कोई तरीका नियत करेगी और सब कर्जवाहों को नियत ढंग पर मोडिस दिया जावेगा।

(२) अगर प्रस्ताव पर विचार करनेके पश्चात् कर्जवाह कसूरत रायसे और जिनका संयुक्त कर्ज कुल कर्जके १/३ कीमतसे कम न हो तथा उनके कर्ज साबित किये जाचुके हों और वह तोय स्वयं हाजिर हों या उनके वकील मौजूद हों इसप्रस्तावको मंजूर करलें तो यह मान लिया जावेगा कि कर्जवाहोंने उस प्रस्तावको भली भाँति स्वीकार कर लिया है।

(३) कर्जदारको अधिकार है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत होते समय उसे संशोधित कर सकता है अगर अदालतकी रायमें वह संशोधन अधिकतर कर्जवाहानकी भलाईके लिये है।

(४) अगर अदालत निश्चय किये हुए रिसीवरकी रिपोर्ट सुनकर तथा कर्जवाहों द्वारा या उनकी तरफसे किये हुए पत्राचारोंको समझकर यह राय कायम करे कि कर्जदारका प्रस्ताव उचित नहीं है या अधिकतर कर्जवाहोंके लाभके लिये नहीं है तो वह उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी।

(५) अगर कोई ऐसी बातें साबित हो जावे जिनके साबित होने पर अदालत यहाल करनेका हुकम न देसके या रोक दे या उसके साथ शर्तें लगा दे तो अदालत उस तक तक उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी जब तक कि बिला महफूज कर्जोंके लिये जो कर्जदार की आपदादके खिलाफ साबित किये जासकते हैं कमसे कम ६ आना की रुपयकी अदायगीका इन्तजाम न हो जावे।

(६) कोई तसफिया या स्कीम उस तक तक मंजूर नहीं की जावेगी जब तक कि उसके द्वारा उन कर्जोंकी अदायगीका इन्तजाम पहिले न हो जावे जिनकी अदायगी दिवालियेकी आपदादसे पहिले होना चाहिये।

(७) और किसी दूसरी सूत्रमें अदालतको अधिकार है कि वह चाहे प्रस्तावको मंजूर करे या नामंजूर करदे ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जानका हुकम से जानेके पश्चात् दिवालिया अपने कर्त्तव्यों निपटानेके लिये जो बर्गवाई कर सकता है उसका उद्भव इस दफामें दिया हुआ है ।

समस्या (Composition) से तात्पर्य उस समयवाले समझना चाहिये जो कर्जदार व कर्जखवाहोंके दामियान उनके कर्जों तथा किये जानेके लिये किया जावे तथा जिसके अनुसार कर्जखवाहान अपने कर्जसे कम लक्ष्य पूरा कर्जाई अदायगी मान लेंगे । जब कोई ऐसा प्रस्ताव अदालतके सामने उपस्थित हो ता अदालतका कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना कर्जखवाहान को दवे तथा इस दफाके अनुमतिका हुई सभा (Meeting) में उस प्रस्ताव पर विचार करे और यदि कर्जदारान जिनके कर्जों साबित हो चुके हैं बहुमतसे तथा इनके कर्जोंका योग कुल साबित किये हुए कर्जोंके तीन चत्वारहसे न्यून न होवे तथा जो स्वयं या जिनके बर्गीक उपस्थित हों उस प्रस्तावको स्वीकार करलें ता अदालतका चाहिये कि वह इस बातको नोट करले कि वह प्रस्ताव कर्जखवाहानसे मंजूर कर लिया है । परन्तु यदि स्वयं या बर्गीकों द्वारा उपस्थित कर्जखवाहान जिनके कर्जों साबित किये जाचुके हैं बहुमतसे या जिनके कर्जों तीन चत्वारह साबित किये हुए बताते कम न हों उस प्रस्तावको मंजूर न करें तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जावगा अदालतकी उस प्रस्तावको अस्वीकारके लिये चाहे जो कुछ राय रही हो । यदि प्रस्ताव कर्जखवाहान द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो तो अदालतका कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि आया वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं । अदालतको ठिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जखवाहान द्वारा स्वीकृत किया हुआ प्रस्ताव अवश्यही स्वीकार करल दलो—30 I C 694

इस दफामें बताये हुए नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे किया जाना चाहिये अथवा कोई समझौता माननके लिये बर्ज खवाहान बाधन नहीं होंगे और न ऐसा समझौता कानूनी समझौताही समझा जावेगा दलो—A I R 1926 Lah 87 समझौता कर्जखवाहानकी स्वीकृतहाने माननीय नहीं समझा जावगा कि तु उसका माननीय बनानेके लिये अदालतकी स्वीकृति आवश्यक है दलो—A. I R 1926 Lah 489

यदि किसी कर्जखवाहकी सूचना न पहुँचनेका कारण समझौता ठाक न रहे तो कर्जखवाहका अधिकार है कि वह अपने कर्जदारकी जापदादको कुर्क कर लेवे दलो—A I R. 1926 Lah 87

उपदफा (२) तथा अगरी उपदफाअसे यह प्रतीत होता है कि समझौतेके प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये एक सभा (Meeting) की जा जावेगा यदि कर्जखवाहान समझौतेको मंजूर कर लव तो यह मान लिया जावेगा कि वह प्रस्ताव पास हो गया है ऐसे प्रस्ताव पर वोट देनेका अधिकार उस कर्जखवाहको नहीं दया जाता कि कर्जों साबित नहीं किया गया है तथा जिसका नाम जब द्वारा सूत्रामें सम्मिलित नहीं किया गया है दलो—15 A. L. J. 166=40 I C 156

उपदफा (३) के अनुसार कर्जदार अपने प्रस्तावमें समझौत कर सकता है यदि अदालतकी रायमें उस समझौतसे कर्जखवाहानका लाभ पहुँचना हो ।

उपदफा (४), (५) व (६) में यह बतलाया गया है कि अदालत जिन २ दफाओंमें कर्जदारके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा ।

उपदफा (७) में उन मामलोंका सम्बन्ध कहा गया है जिनका उल्लेख इससे पादिने नहीं किया गया है अदालत

का एमे माफके रीतिर कामे व न खांसार कमेमें पूर्ण स्वतन्त्रता है उदाहरण स्वरूप यदि दिवालियाके सिंलीबरसे डिपारर बिना कतरवाइमें रुपया दिया जा ता अदाकर ऐसी दणमें समझौता नामचर कर सती है देखो—A. I. R. 1926 Mad 1166 अतिरार एमे प्रस्तावकी स्वाहृत लिखित हुक्मक अडुगारी की जाना चाहिये किन्तु एमे अवसर भी आजाते है जिनमे यह समझा जातके कि स्वाहृत प्रदान कर दी गई है यद्यपि उसके सम्बन्धमें कोई निश्चित हुक्म न दिया गया हो देखो—A. I. R. 1926 All 361.

दफा ३९ मंजूर करने पर हुक्म

अगर अदालत प्रस्तावको मंजूर करले तो सब शयें अदालतके हुक्ममें लिख दी जायेंगी और अदालत दफा ३३ के अनुसार एक सूची तैयार करेगी व दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर कर दिया जावेगा और दफा ३७ में दिये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा और तसकिया या स्कीम उन सब कर्जदारोंके लिये माननीय होगी जिनका उल्लेख सूचीमें है और जहां तक उनका तारलुक सूचीमें दिये हुए अपन कर्जोंसे है।

ब्याख्या—

जब कि अदालत प्रस्तावकी रीतिरार कर लेवे तो अदालतके चाहिये कि वह अपने हुक्ममें प्रस्तावकी सब बातोंको लिखा देने तथा दफा ३३ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जदारोंको व कर्जोंकी सूची तैयार करे और साथही साथ तसकिया करार दिये जाने वाले हुक्मको रद कर देने इसके परवात् दफा ३७ में बतलाई हुई कर्जदारों काय होगी देखो—24 A. L. J. 441 यदि प्रस्तावकी रीतिरारके साथ कोई शयें न लगाई जायें तो दिवालिया अपनी स्वाभाविक दशा को पात हो जावेगा और सिंलीबर अपनी कर्जदारोंका बरग बंद कर दगा देवी—A. I. R. 1926 Mad 1187.

समझतेकी रीतिरार केवल अर्धों कर्जदारों पर लागू होगी जिनके कर्जों माहित किये जाउरे है तथा जिनका नाम सूचावे जिला न्याया है। वह रजस्वाइन समझतेकी अवलम्ब नहीं कर सकने देखो—A. I. R. 1925 Lath. 316 वह कर्जदार जिनका नाम सूचावे नहीं आया है अपनी डिका इनका क्या सहा है देखो—A. I. R. 1926 Cal 489

दफा ४० कर्जदारको फिर दिवालिया करार देनेका अधिकार

अगर तसकिया या स्कीममें तय की हुई किनी कितकी अदायगी न हो सके या अदालत को यह मालूम हो कि जिला न्यायाकी या देर किये हुए उस पर अमल नहीं किया जातकता है या अदालतको यह यकीन हो जावे कि उसे धोखा देकर मंजुरी ली गई है तो वह अगर मुनासिब समझे कर्जदारको दुबारा दिवालिया करार दे सकता है और तसकिया या स्कीमको रद कर सकती है लेकिन वह सब इत्तमाल जायदाद अदायगी तथा दूसरे काम जो तसकिया या स्कीमके अनुसार दिये जाचुक है ठीक समझे जावेंगे।

जब कि कर्जदार इस दफाके अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो वह सब कर्जों भी जो दुबारा दिवालिया करार देनेसे पहिले लिये हैं और जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जातकते हैं साबित किये जासकेंगे।

दरबार की जाने पर अदायत मोई तारीख उनके समनेके लिये नियत करीगें तथा इस नियतकी हुई तारीखकी सूचना कर्तव्यार्थको निर्धारित दण पर दी जानेकी तब कर्तव्यवादाया विवेक उस दरबारस्तके लिये सुचारु तथा नियुक्त किये हुए रितीनका विवेक देकर अदायत अपना हुक्म देवेगी। अदालत अपने हुक्म तीन प्रकारका इस सम्बन्धमें दे सकती है जिनका उल्लेख उपद्रवा (२) के क्राउ (ए), (बी) व (सी) में किया गया है अर्थात् (१) या तो दिवालिगो बिल्कुल बहाल कर देगी या बहाल करनेसे इनकार कर देगी, (२) बहाल नो कर देगी परन्तु साथ साथ यह पक्क लया देगी कि बहालका हुक्म एक निषा किये हुए समयके पश्चात् प्रयोगमें आयेगा, तथा (३) किमी ऐसी शर्तके साथ उसे बहाल करेगी कि उसे अपनी आपदन्तीका कोई निर्विवाद भाग या बाइस प्राप्त होने का भी आवश्यक बहाल हो जानेके बाद भी देना पड़े। यदि कर्तव्यवादा व कर्तव्यवादे दायित्वान इस प्रकारका समझाना हो जावे कि वह कर्तव्यवादा बहाल होनेकी दरबारास्तफा जमान नहीं करेगा तो ऐसा समझौता केअग्र समझना चाहिये अर्थात् ऐसी समझौतेके हो जाने पर भी वह कर्तव्यवादा बहालकी दरबारास्तका विरोध कर सकता है देखो—20 Bom 616

उपद्रवा (२) बहालका हुक्म देना अदालतका इच्छा पर निर्भर है उसके देनेके लिये वह बाध्य नहीं है। दफा ४२ में इन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत बिल्कुल बहाल देनेका हुक्म नहीं देवेगी यदि बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर दिया जाये तो यह नहीं समझना चाहिये कि दिवालिगो अगर देनेका हुक्म मसूख कर दिया गया है। दिवालिगोवत उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि दिवालिगोकी मसूखीका हुक्म गफा कोर पर न दे दिया जावे देखो—55 M. L. J. 54

बहाल होनेके हुक्मको रणगित किये जानेसे अभिप्राय यह है कि किसी नियत समय तकके लिये दिवालिगो बहाल न समझा जायेगा किन्तु उस समयके यहीन होनेके पश्चात् दिवालिगो बहाल समझा जायेगा। जितने समयके लिये अदालत बहाल होनेके हुक्मको रणगित करना चाहे उतना उड़व अपने हुक्ममें कर देना चाहिये अर्थात् अनिश्चित समयके लिये उस रणगित न करना चाहिये जैसा कि क्राउ (बी) से प्रकट होता है। यदि बहाल होनेकी दरबारास्त नाममात्र किये जायेके बाद रक्षा (Protection) की दरबारास्त दी जावे तो अदालत उस पर बहुत मोच समझ कर हुक्म देगा। यदि दिवालिगोने बेसमय ब्रूँ तथा नईमानीसे तमाम कर्जें लाने लीं तो ऐसी दशामें अदालतको चाहिये कि वह कर्तव्यवादाको ऐसा मौका मिलने दे जिसमें वह बहैमान दिवालिगोको उसके कर्जोंका कूल देसके अर्थात् ब्रूँ कैद कर सके। रक्षाके हुक्मको देना न देना बिल्कुल अदालतके हाथ है जब कि अदालतको यह मालूम हो कि बिजुल खर्चा आदि करके दिवालिगो दमनेका मौका कबदरती दुलाया गया है तथा कर्तव्यवादाके कर्जोंका बिल्कुल ध्यान न देने हुए रुपया बरबाद किया गया है तो अदालतको चाहिये कि वह रक्षाका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे देखो—40 Bom 461.

दिवालिगोने बहाल होनेमें बाधकी कर्तव्य तथा नादमें प्राप्त होने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्तें लगा देनेसे अभिप्राय यह है कि जिसमें कर्तव्यवादाका यदि मौका हो तो कुछ अधिक प्राप्त हो सके। शर्तके साथ बहाल होनेका अभिप्राय यह नहीं है कि दिवालिगोकी तब कर्तव्यवादा समाप्त हो गई दम्भी कारण बाधमान जाने वाला कर्तव्यवादा भी अपने कर्जोंसे लाजित कर सकता है देखो—A. I. R. 1925 Pat 438

दफा ४२ पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण

(१) अदालत नीचे दी हुई बातोंमें से किसी एकको भी सार्वित होने पर दफा ४१ के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म नहीं देवेगी:—

(२) यह कि दिवालिगोकी जायदादकी क्रीमस उसके बिना महफूज कर्जोंके लिये रुपयों आठ आना या अरा कानके लायक नहीं हैं, जयतक कि दिवालिगो अदालतको

यह यकीन न दिला देवे कि उसकी जायदादसे बिला महफूज कर्जोंकी आधी अदा-यगीका इन्तजामका न हो सकता ऐसे कारणोंसे होगया है जिनके लिये वह उचित रीतिसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।

(धी) यह कि दिवालियेके पास यह हिसाबकी किताबें नहीं हैं जो अमूमन उसके ऐसे रोजगार करने वालोंके पास रहना उचित है और जिनसे उसके रोजगारका तथा माली हालतका हाल काफ़ी तौरसे दिवालिये कमनेसे तीन साल पहिले तकका मालूम होसकता है।

(सी) यह कि दिवालिया अपनेको दिवालिया जानते हुए भी रोजगार करता रहा हो।

(डी) यह कि इस एन्टक अनुसार साबित होने वाला कोई कर्ज दिवालिपने यह न जानते हुए लिया हो कि उसे उस कर्जेके अदा करनेका उचित अवसर न मिलेगा इसके साबित करनेका बार सुधूत दिवालिया पर होगा।

(ई) यह कि दिवालिया भले प्रकार यह नहीं साबित कर सका है कि उसके लहनेमें कमी क्यों हुई या उसके लहनेसे उसके कर्जोंकी अदायगी क्यों नहीं हो पाई।

(एफ) यह कि उसका दिवाला उसके जल्द ब ख़तरनाक सौदाँके करनेके कारण हुआ है या उससे दिवाला निकलनेमें मदद मिली है या उसके अनुचित रूपसे बहुत अधिक खर्च करनेके कारण हुआ है या जुधा ख़ेलनेके कारण या अपने व्यापारके अनुचित रूपसे अदबालना करनेके कारण हुआ है।

(जी) यह कि दिवालको दरखास्त दिये जानेके पहिले तीन माहके अन्दर जबकि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता था उसने किसी ख़ास कर्जद्वाराको देजा तौर पर तर्जिह दी हो।

(एच) यह कि दिवालिया इनसे पहिले भी दिवालिया करार दिया जाचुका है या वह कोई समझौता या तसफिया अपने कर्जद्वाराहोंके साथ कर चुका है।

(आई) यह कि दिवालिपने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा छिपाया है या हटा दिया है या और किसी प्रकारकी धोखादेही या अमानतमें सयानतका धोख़ाका काम किया है।

(२) इस दफाके लिये रिखीवरकी रिपोर्ट शहादत मानी जावेगी और अदालतको अधिकार है कि उसमें दी हुई किसी बातकी सच्चाईको मानले।

(३) अदालतको अधिकार है कि बहाल करनेके हुदमको स्थगित करने या उसके साथ शर्तें लगाने, दोनों बातोंको एक साथ भी कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालिपके व्यापार प्राग किये हुए वह सब साम दिलसवेगये हैं जिनके सन्नि होनेसे अदायत दिवालिपके पूर्ण रूपसे बहाल करनेमें तैयार नहीं होवेगी।

कात (५) से लया कर कात (जारी) तक जो बने दिखलाई गई है वह सब एक प्रकरण दिवालयीकी बदौलती भेजदोती तथा बुनपयोग के काम हैं यदि दिवालयी इन कामोंमें किया कामका बोरी समझा जावे तो वह कानून दिवालयी से इन बाने प्रायदोती कावेन खसता जावेगा । इस दफाका सम्बन्ध केवल दफा ४१ (२) के प्राज (५) के साथ समझना चाहिये अर्थात् इस दफामें बतलाई हुई बातोंमें होने पर कात (५) के अनुसार पूर्ण बहालका हुक्म नहीं दिया जावेगा । इस दफाका प्रभाव दफा ४१ (२) के प्राज (नी) न (सी) पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् इस दफामें बतलाई हुई बातोंके साहित होनेके कारण बहाल हुनमें जहाँ या कोई अवधि न बहा देना चाहिये देखो—39 I. C. 916.

जब कि दिवालयीके एहमसे उसका छापा बर्जों में न चकाया जायजना हो और दिवालयीके कमीकी वसूलीमें गिनीरके छिये बराबरे बाकी हो तो ऐसे दिवालयीके बहाल करनेमें इनकार कर देनेका हुक्म उचित हुक्म है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 112.

दिवान किताब न रखने पर ही पूर्ण बहाल किया जाना ठीका जायजता है देखो—A. I. R. 1927 All. 352 जब कि किसी अगलत दिवालयीमें किसी दिवालयीकी बहालका हुक्म देनेमें इनकार कर दिया हो तो वह अगलत करने इनकारके हुक्मकी बहाल नहीं करता है देखो—32 I. C. 575 परतु इससे यह न समझना चाहिये कि यदि बहाने होनेमें इनकार करनेका हुक्म तबैव आगम्य बना रहेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad. 915.

सीसीरकी रिपोर्ट एक प्रकरणकी साक्षरत समझी जावेगी और जब तक कि कोई बात उसके विरुद्ध न दिखलाई जावे वह रिपोर्ट ठीक समझी जावेगी देखो—36 I. C. 906, 37 All 429 यदि किसी दिवालयीके मामलेमें कौनसे आठ बने हुआ दिने गये हों और कर्त बहाल होनेका हुक्म एक अर्थ तक विरुद्ध रहे दे तो जमकर देता हुक्म विरुद्ध कानूनक विरुद्ध है देखो—A. I. R. 1928 Oudh 263.

बहालका हुक्म देने समय केवल यह मिल देना नहीं है कि सीसीरकी रिपोर्टमें कोई बात दिवालयीके बहालमें बराबर चलन बाधा नहीं है जहाँ इस बातका निश्चात कर लेना चाहिये कि दाखल दिवालयीकी कोई बहानेकी वनने अथवा रजम वसूल होनेमें बाधा न हो पड़ा है अर्थात् दिवालयीकी वेबनीसे ऐसा हुआ है । बिना इस किस्मकी समबोध बिने हुए अगलतका फैसला कानूनक उचित नहीं है । देखा—A. I. R. 1928 Cal 843.

उपदफा (३) एक प्रकरणसे दफा ४१ में सम्प्रतिती जानने योग्य है क्योंकि उसमें यह बतलया गया है कि जहाँ कानून न अवधिकी बहानेमें हुक्म साथ न गी दिने जायजने है अर्थात् दफा ४१ (२) के प्राज (नी) न (सी) की फर्वादाया एक साथी की गाराती है ।

दफा ४३ बहालकी दाखलास्त न दिये जानेपर दिवालयीकरार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

(१) अगर दिवालयी बहालकी दाखलास्त सुने जाने वाले दिनेया अदालतसे मुकरर किये हुए थानके किसी दिन पर हाजिर न हो या दिवालयी अदालतसे ही हुई मिश्रादकी अन्दर बहाल होनेकी दाखलास्त न देवे तो दिवालयी करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर कर दिया जावेगा और उसके बाद दफा ३७ की कार्याईका प्रयोग होगा ।

(२) जबकि कर्जदार इस हुक्मके अनुसार हिसाबतसे छोड़ा गया हो और दफा ४३ (१) के अनुसार उसके दिवालयी करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर कर दिया जावे तो अदालतकी अधिकार है कि अगर वह मुनासिब समझें तो कर्जदारको फिर उसी हिसाबतमें बंदे और जलका खपकर जिसकी सुपुर्गीकी कर्जदार इस प्रकार हुयाग दिया जावेगा उसको अपनी सुपुर्गीमें

सुपुर्दगीके हुक्मके अनुसार से लेवेगा और उस तक यह सब कार्यवाहियां जो कर्जदारकी ज्ञातके खिलाफ उसके छोड़े जानेके समय लागू थीं इस प्रकार चालू समझी जावेंगी मानो कोई दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म दिया ही नहीं गया था ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बात प्रकट है कि दिवालियेके लिये बहस होनेकी दरखास्त देना अति आवश्यक है वरना वह इस एक्टके नियमोंका लाभ उठावेसे बाधित रहता आसरेगा । बहस होनेकी दरखास्त अदाकृत होना नियत लिये हुए समयके अन्दरही देना जाना चाहिये अदालत हाथी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालिया अपने आपही बहाल नहीं हो जावेगा किन्तु उसके बहाल होनेके लिये अदालतका हुक्म देना आवश्यक है देखो—49 All. 201. दिवालियेके हुक्मके मसूखी तथा नशान होनेका हुक्म दोनों (1) एक्टके अनुसार एवही चीज नहीं है देखो—A. I. R. 1925 Lah. 376. यदि दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म देने समय बहाल होनेके लिये कोई मियाद नहीं दी गई हो तो यह दफा लागू नहीं होगी और बहालकी दरखास्त न देनेके कारण दिवालियेका हुक्म मसूख नहीं किया जावेगा देखो—A. I. R. 1926 Lah. 24.

उपदफा (१) इस दफाके अनुसार दिवालियेका हुक्म नीचे दी हुई किसी बातके होनेपर मसूख किया जासकेगा

(१) यह कि जब दिवालिया बहाल होने की दरखास्त देने जानेकी तारीख पर हाजिर न होवे

(२) यह कि जब वह तारीखके बाद जाने पर उस बड़ी हुई तारीखके दिन हाजिर न होवे

(३) यह कि जब दिवालिया दफा २७ के अनुसार नियतकी हुई म्यादके अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त न देवे ।

इस दफामें वक्तव्ये हुए नियमकी पाठ्य करनेके लिये अदालत कायदे A. I. R. 1926 Sind. 94.

इसलिये यदि दिवालिया क़रार वक्तव्ये हुई कोईभी गलती करे तो मसूखीका हुक्म होनाका चाहिये और दिवालिया उस समय जायना दिवालिके आदेश के अनुसार भी सहायता नहीं पायकता है अर्थात् मान वनकर सादिककी बर्बादी भी नहीं कर सकता है यदि दिवालिये से गलती किसी अनिवार्य कारणकी हो तो ऐसी ऐसी वह दफा १० (२) से काम बड़ा सकता है अर्थात् इसके अनुसार फिर दरखास्त दिवालिया देसकता है देखिये 49 Mad. 935; A. I. R. 1924 Mad. 635.

अदालत इस दफा के अनुसार स्वयं करवाई करसकती है तथा ऐसा कर्तव्यार्थी जिसको दिवालियेके हुक्ममें हाजिर पड़नी हो मसूखी के लिये दरखास्त देसकता है देखो—A. I. R. 1924 Mad. 635.

इस एक्टकी दफा ४३ आज्ञा कायिक है और अदालत को नियतकी हुई मियादके समाप्त होनेके पश्चात् समय बढ़ानेका अधिकार नहीं है म्याद सुर्जम के अन्दर दिवालिया या कर्तव्यार्थी दरखास्त देसकते हैं परन्तु नहीं ऐसा नहीं किया गया हो वहां दफा ४३ के अनुसार वार्डार्थी जानी चाहिये A. I. R. 1928 Mad. 265.

परन्तु अग्रा साहके मामलेमें यह तय हुआ था कि दिवालिये के हुक्ममें ही हुई मियादके बाद भी समय बढ़ाया जा सकता है ।

दफा ४३ (१) दफा २७ के साथ पढ़ी जाना चाहिये और अदालत को अधिकार है, जित अधिकार को उसे कानूनी दम से वहीना चाहिये कि यदि मातृक अदाकृतने समय बढ़ा दिया होतो वहभी समय बढ़ा रहने दे सिवा तबमें हाईकोर्ट एहि हुक्मका हटा नहीं सकता है देखो—1928 M. W. N. 441.

कर्जस्वाद इजानन लेकर इस दफा के अनुसार दिये हुए हुक्मकी अपील करसकता है 100 I. C. 137.

आज यदि अपील मन्त्र कटली जात तो यह मान लिया जावेगा कि इजानन छानाबुकी है A. I. R. 1928

दफा ४४ बहाल होनेके हुक्मका असर

(१) बहाल होनेका हुक्म दिवालियेको नीचे दी हुई बातोंसे बरी नहीं होने देगा.—

(ए) किसी सरकारी कर्जसे

(बी) धोखेबाजीसे या धोखा देकर अमानतमें खयालत करके अगर कोई कर्ज या जिम्मेदारी पैदा हुई है और जिसमें दिवालियेका भी हाथ रहा हो

(सी) अगर धोखेबाजीमें शरीक रह कर किसी कर्ज या जिम्मेदारीसे बरी होगया हो तो ऐसे कर्ज व जिम्मेदारीसे, या

(डी) अगर सन् १८६८ ई० के ज्ञायता कौजदारीकी दफा ४८८ के अनुसार कोई हुक्म परपरिशुका उसके खिलाफ दिया जावे तो ऐसे हुक्मकी जिम्मेदारीसे ।

(२) पहिली उपदफा अर्थात् ४४ (१) में दी हुई बातोंको छोड़ कर दिवालिया बहाल होनेके हुक्म हो जाने पर और सब कर्जोंसे मुक्त हो जायगा जो इस एक्टके अनुसार साबित लिये जासकते हैं ।

(३) बहाल होने वाले हुक्मसे ऐसा व्यक्ति बरी जिम्मा नहीं होगा जो दिवालिकी दर-फ्यास्त बिये जाते समय दिवालियेका साक्षी या संयुक्त ट्रस्टी रहा हो या जिसकी दिवालियाके साथ संयुक्त जिम्मेदारी या संयुक्त मुआहिदा रहा हो या जो दिवालियेके लिये जामिनदार रहा हो ।

व्याख्या—

बहाल होनेके हुक्म दिये जानेपर दिवालिया उन सब कर्जोंसे मुक्त होगाता है जो कानून दिवालियेके अनुसार साबित किये जासकते हैं परन्तु वह ऐसे कर्जोंसे मुक्त उस समयभी नहीं मगता जबकि भिनका वल्लेख इस दफाकी उपदफा (१) के खान (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है मुक्त होजाने से अभिप्राय यह है कि वह कर्ज समाप्त समझे जावेंगे । इस एक्टके अनुसार साबित किये जाने योग्य कर्जोंका वल्लेख दफा ३६ में किया गया है ।

यदि किसीने किसी कर्जको रद्दी न वसूल न किये जाने योग्य समझकर जोड़ दिया होतो दिवालिया बहाल होने पर ऐसे कर्जको वसूल कर सकता है व उसको मुनकिल कर सकता है, ३१ All. 223. यदि बहाल होनेकी दरखास्त एक बार नामखार करदी गई हो तोभी दिवालिया फिर दूसरी दरखास्त दूसरी बातों पर इसके लिये दे सकता है एक्टमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह मान लिया जावे कि बादकी बहाल होने की दरखास्त नामखार किये जानेका प्रमाण आलम्न तक कायम रहेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad 915.

दफा ४४ (१) के अनुसार दिवालियेका बहाल होनेका हुक्म होजाने के पश्चात् उन सब कर्जोंसे मुक्त समझना चाहिये जो इस एक्टके अन्तर्गत साबित किये जासकते हैं । यदि किसी कर्जस्वाहने जान बूझ कर साबित करने योग्य अपने कर्जको साबित न किया हो तभी इससे मुक्त नहीं हो सकता है, देखो—A. I. R. 1928 Nag 336

जामिनदार अपने अमानतकी जिम्मेदारी साबित कर सकता है । यदि मुद्दै किसी कर्जदारका जामिनदार होने और वह कर्जदार दिवालिया प्रचार दिये जानेके पश्चात् दफा ४१ के अनुसार बहाल कर दिया गया हो तथा इसके बाद कर्जस्वाह उस जामिनदारसे अपना कर्जा वसूल करले तो वह जामिनदार बहाल हुए कर्जदारके विरुद्ध अपना अपना वापिस पानेके लिये दावा करे तो यह तय किया गया कि कुछे वह कर्ज दफा ३६ (२) के अन्तर्गत नहीं आता है अतः कर्जदार (बहाल किया हुआ दिवालिया) उस कर्जकी जिम्मेदारीसे दफा ४४ के अनुसार मुक्त हायुक्त है, देखो—A. I. R. 1928 All. 306.

तीसरा प्रकरण

कजोंके साधित करनेका तरीका (जायदादका प्रबन्ध)

धृषा ४५ आइन्दा अदा होने वाले कजों

अगर किसी कर्जखाहका रुपया कर्जदारसे लेना हो लेकिन वह दिवालिया करार दिये जाते समय बाजिबुख अदा न हो बल्कि आयन्दा चल कर उसकी अदायगी होना चाहिये तो भी उस कर्जखाहको अधिकार है कि वह अपना कर्ज इस प्रकार साधित करे जैसे कि उसका कर्ज उम्मीद कर मिलना चाहिये और उसको दिवालियाकी जायदादसे हिस्सा रसदी दूसरे कर्जखाहों की तरह विलबाया जासकता है लेकिन उसके कर्जकी तादादसे उतना रुपया कम कर दिया जावेगा जो ६) रुपया सैकड़ा माहपारी सुइके हिसाबसे रसदी बैंक तक बकसे उसके कर्जकी असली अदायगीके बक तक निकलेगा ।

व्याख्या—

इस धृषाके अनुसार भविष्यके कजों पर भी हिस्सा रसदा प्राप्त हो सकता है अर्थात् यदि किसी कर्जखाहका कोई कर्ज दिवालियासे लेना हो परन्तु वह कर्ज दिवालिया करार दिये जाते समय बसूल न किया जासकता हो परन्तु उसके बाद भविष्यमें वह कर्ज बसूल किये जाने योग्य होवे तो भी कर्जखाह अपने उस कर्जसे मौजूदा कर्जोंभा भानि इस एकके अनुसार साधित कर सकता है परन्तु उसकी तादाद इस प्रकार निमित्तकी जावेगी कि पहिले यह देखना चाहिये, कर्जकी तादाद उस तारीख पर जबकि वह बाजिबुखअदा है क्या होगी अर्थात् मय ब्याजके उस तारीख पर कर्जखाहका कितना रुपया दिवालियासे मिलना चाहिये उसके पश्चात् यह देखना चाहिये कि क. रुपया सैकड़ा साठानाको दसरे रसदी बाटे गनिब; तारीख से असली अदायगाई; तारीख तक कितना ब्याज होगा तब पाइलकी रकमसे वह ब्याजकी रकम निम्नल देना चाहिये और बाकी बचा हुई रकमके हिसाबन हिस्सा रसदा मिलना चाहिये ।

धृषा ४६ आपसका व्यवहार व मुजरई

जब कि दिवालिया व किसी कर्जखाहके दरमियान आपसका व्यवहार रहा हो व दोनों का लेना देना होवे और इस एकटके अनुसार वह कर्ज साधित किया जा रहा हो तो इस बातका हिसाब किताब किया जावेगा कि एक फरीकको दूसरे फरीकसे इस व्यवहारके सम्बन्धमें क्या लेना देना है और एकका लेना उसके दोनमेंसे घटा दिया जावेगा और उसके बाद जो रुपया देना लेना चलगा बचल वही एक दूसरेसे पानेका मुस्तहक होगा ।

व्याख्या—

यदि किसी कर्जखाह व दिवालिया दोनोंके एक दूसरेसे लेना देना होवे या ऐसी दशामें दोनोंके लामार्थे इस दशामें यह चलनाया गया है कि लदनमस दोनो रकम घटा कर या रकम बच उसीको हिस्सा रसदी या बसूलके लिये असली कर्ज समझना चाहिये । कपाक याद दिवालिया कर्ज उमल पूरा बसूल कर लिया जावे परन्तु उस उमल बक पर और कर्ज-

बैंकोंकी भांति केवल हिस्सा रसदी ही दिया जावे तो उसका नुकसान रहेगा । इसी प्रकार यदि कर्जस्वाह अपने कर्जों पर हिस्सा रसदी छे लेवे परन्तु उसे दिवालियेका कर्ज अदा न करना पड़े तो दिवालियेका लहना कम वसूल हो सकेगा । इस तार पर यदि किसी कर्जस्वाहका कर्ज उसके देनेसे अधिक होवे तो वह अपने इस अधिक कर्जोंके लिये हिस्सा रसदी दिवालियेकी जायदादसे और कर्जस्वाहोंकी भांति भागिगा परन्तु यदि उसका देना उसके कर्जोंसे अधिक हो तो उसको वह अधिक निकलती हुई रकम रिसीवर या अदालतमें देना पड़ेगी । समुक्त कर्जोंकी छुट्टाई जेठे कर्जके सम्बन्धमें नहीं की जासकती है जैसे कि यदि किसी बैंकके डिपॉजिटर्सने छुट्टा लेह पर समुक्त बन्नेरी बिना पर नमिश्नकी हो और उनमेंसे किसी एक छुट्टाअछेदका कुछ बचवा बैंकमें समा हो तथा वह चाहे कि उस बचयेकी छुट्टाई दावेमें कर दी जावे तो यह छुट्टाई इस बिना पर नहीं की जायेगी कि हिस्सा रसदी, दो प्रकार है एक दूसरेसे छेन देनेके तौर पर नहीं है, देना—45 Bom. 1219.

यह दफा उसी समय लागू होगी जबकि फॉर्बैनके दायियाए एक दूसरेसे छेने देनेका व्यवहार रहा हो देखो—A. I. R. 1925 Sindh 158.

हिस्सा रसदीके बाद छुट्टाई होना चाहिये । इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि किंतु तारीख तकका हिस्सा रसदी होना चाहिये परन्तु यह प्रकट होता है कि हिस्सा रसदी तारीख तकका होना चाहिये जबकि रसदी बादी जाने वाली होवे या उस समय तक होना चाहिये जबकि कर्जों साबित किया जाने वाला हो ।

दफा ४७ महफूज कर्जस्वाह

(१) जबकि महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानत वसूल करले तो वह बाह छुट्टाई उस कुल रुपयोंके जो उसे जमानतसे वसूल होचुका है अपने बचे हुए कर्जोंको साबित कर सकता है ।

(२) जबकि महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानतको और सब कर्जस्वाहोंके साथ फायदा छटानेके लिये छोड़ देवे तो वह अपने कुल कर्जोंके साबित करनेका मुस्तहक है ।

(३) जबकि महफूज कर्जस्वाहने न तो अपनी जमानत वसूलकी और न उसको छोड़ताही है तो वह सूचीमें अपना कर्ज लिखवानेसे पहिले अपने कर्जोंका ब्योरा साबित करेगा और वह कीमत भी देगा जिसका उस अन्दाजा है और उस वक्त उसी रुपये पर रसदी पानेका मुस्तहक होगा जो उसके असली कर्जोंमेंसे अन्दाजा लगाई हुई कीमत छटानेके बाद बचे ।

(४) जबकि जमानतकी कीमतका अन्दाजा इस प्रकार लगाया जावे तो अदालतकी अधिकार होगा कि वह वसूलीसे पहिले किसी समय उस कर्जस्वाहकी अन्दाजा लगाई हुई कीमतको देकर उस जमानतको छुट्टा लेवे ।

(५) जबकि कर्जस्वाह अपने जमानतकी कीमतका अन्दाजा लगानेके बाद उस जमानतमें रुपया वसूल करले तो इस प्रकार जो रुपया वसूल किया जायेगा वही जायदादकी कीमत समझी जायेगी वजाय उस कीमतके जो कर्जस्वाहने उसकी पहिले लगाई हो और वह संशोधित कीमत सब मामलोंके लिये मानी जायेगी ।

(६) जबकि महफूज कर्जस्वाह इस दफाके अनुसार कार्रवाई अमलमें न लाये तो उसको वसूलीमेंसे कोई हिस्सा रसदी नहीं मिलेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें महफूज कर्जस्वाहके उन हकोंका वर्णन है जो वह अपनी जमानतके सम्बन्धमें कर सकता है तथा उसके

उन इकाईका भी वर्णन है जिसके अनुसार वह दिवालियेकी जायदादसे हिरा राखी प्राप्त कर सकता है। इस बातका रहना चाहिये कि यह दफा केवल उहीं कर्जाल्वाहोंके लिये है जो दासतब महजून कर्जाल्वाह है लेकिन जबकि महजून होनेका प्रश्न अभिविचन देने तो पहिले यह प्रश्न तय कर दिया जाना चाहिये तब यह दफा लागू हो सकेगी देखो
A. I. R. 1923 All. 159

महजून कर्जाल्वाहके यह हक समझना चाहिये कि, — या

- (१) वह अपने जमानतदारी पर भरोसा कर सकता है व अपना कर्ज न साबित करे, या
- (२) वह अपनी जमानत बसूल कर लेवे उसके पश्चात् बचे हुए रुपयोंको साबित करे यदि कुछ निकलते हों,
- (३) वह अपनी जमानत छोड़ देवे व अपना पूरा कर्ज साबित करे, या
- (४) वह अपनी जमानतकी कीमतका अन्दाजा लगा देवे तथा उससे अधिक जो रकम उसकी निकलनी हो साबित करे पशु ऐसी दशमें उनकी जदासा लयाई हुई कीमत उसे दी जाएर उगकी जमानत जून नामकेगी। दिवालियेकी वरिवाईका कोई प्रभाव महजून कर्जाल्वाहके कर्ज पर नहीं पड़ता है देखो—
A. I. R. 1923 All. 159. महजून कर्जाल्वाह (Secured creditor) की परिभाषा दफा २ (१) कानून (ई) में दी गई है। जमानतकी वसूलीसे यह तात्पर्य है कि वह जापदाद में बच जावे व उसकी बिक्रीकी कीमत के ली जावे देखो— 41 All. 481.

उपदफा (२) जमानतका छोड़ना या न छोड़ना महजून कर्जाल्वाहकी इच्छा पर निर्भर है वह अपनी जमानत छोड़नेके बिना बाध्य नहीं है यदि लिखनेके किसी महजून कर्जाल्वाह (मुनैडिन) की यह नोटिस दिया हो कि वह जापदादकी बिक्री करके बचनका जाहदा है व मुनैडिन इस पर जामोश रहा हो तो उसकी इस जामोशीसे यह नहीं मान लिया जावे कि उसने अपनी जमानत छोड़ी है देखो—47 Mad. 603 इस प्रकार जमानतका छोड़ा जाना दूसरे बावों या भावों नहीं माना जातकेगा निम्न महजून कर्जाल्वाहको चाहिये कि वह अपने आप जमानतको छोड़नेकी इजाजत देवे। इस दफा महजून कर्जाल्वाहके कर्जसे तात्पर्य उसके उम कर्जका समझना चाहिये निम्नकी जमानत है, यदि उसका कोई बिक्री महजून कर्जों में होवे तो वह बिक्री लिहाज इस दफाके ओर कर्जाल्वाहोंके कर्जोंकी तरह साबित किया जानकेगा केवल महजून कर्जों केलिये वह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंका प्रयोग कर सकता है यदि वह उसे जमानतकी कीमतसे अधिक समझता हो।

दफा ४८ सूद

(१) अगर कोई कर्ज या रुपया जो कर्जदारके ज़िम्मे उस धन निकलता हो जबकि यह दिवालिया क़ारार दिया गया हो और जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है तबकि उसके लिये कोई सूद मुकर्रर नहीं किया गया है और न तयशी हुआ है तो कर्जाल्वाह (२) रुपय सैकड़ा सालानासे अधिक सूद साबित नहीं कर सकता है।

- (ए) जबकि कर्ज या रुपया किसी दस्तवेजके आधार पर किसी खास समय अदा होना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया क़ारार दिये जानेके समय तक (अगर कहे हुए छः रुपय सैकड़ा सालानाके या हिसाबसे मिलेगा)
- (बी) जबकि कर्ज या रुपया किसी दूसरी सूतमें अदा होना चाहिये या और नोटिसके ज़रिये उसकी अदायगीके लिये कर्जदारसे कहा गया हो कि तुमको सूद अदा

करना पड़ेगा तो नोटिसकी तारीखसे सूद उस वक्त तक मिलेगा जबकि कर्जदार दिवालिया करार दिया जाय ।

(२) जबकि कोई कर्ज इस पक्षके अनुसार साबित किया जा चुका हो और उसमें सूद मिलित हो या सूदकी अगह कोई और मुनाफा लगाया गया हो तो हिस्सा रसदी देते समय वह सूद मुनाफा ६) रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे लगाया जावेगा परन्तु उस सूदमें जबकि और व कर्ज बूट तौर पर दिवालियेकी जायदादकी कीमतसे अदा किये जा चुके हो वचे हुए रुपयोंसे कर्जदारके असली सूदकी अदायगी होगी चाहे वह इससे अधिक दरका होवे ।

व्याख्या—

इस १४वें यह बतलाया गया है कि सूद किम दरसे लगाया जाना चाहिये ।

उपदफा (१) यदि कोई सूद न ठाढ़ हो तो ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे अधिक सूद नहीं लगाया जाना चाहिये । जबकि कोई कर्ज किसी खास समय पर किसी दस्तावेजके अनुसार अदा किया जाना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ७) रुपया सैकड़ाकी दरसे लगाया जावेगा इसी प्रकार जबकि जो और किसी प्रकारसे अदा किया जाने वाला होवे तथा कर्जदारको सूद अदा करनेके वास्तव नोटिस दिया गया हो तो उस नोटिसकी तारीखसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ७ रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे सूद मिलेगा ।

इस उपदफाके ब्राज (५) व (६) दोनोंहीके अनुसार सूद दिवालिया करार दिये जानेके हुक्म तक दिया जा सकेगा ।

ब्राज (६) में जो नोटिसका जिक्र है वह लिखित नोटिस होना चाहिये जबानी नोटिससे काम नहीं चलेगा ।

उपदफा (२) के अनुसार हिस्सा रसदी असल रकम व उस मूद या मुनाफाईके अनुसार मिल सकेगी जो रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे निकले अर्थात् यदि किसी कर्जद्वारा अर्पण साबित करते समय कुछ असल रकम मिलेलायें हो तथा कुछ सूद दिखलाया गया हो और वह सूद ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे अधिक हो तो हिस्सा रसदी देते समय उसकी असल रकम व उस पर ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे जो सूद होता हो उसीके अनुसार उससे हिस्सा रसदी मिल सकेगी परन्तु इस उपदफामें यह भी सक्रम कर दिया गया है कि अगर दिवालियेकी जायदादमें उसके सब में पूर्ण रूपसे अदा किये जा चुके व उसके बाद कुछ कालिख रकम बचे तो उस कालिख रकमसे कर्जद्वाराके असली सूदकी अदायगीकी जायेगी जो कि हिस्सा रसदीके समय उसके कर्जसे कम कर दी गई हो इस प्रकार कर्जद्वारा कालिख रकम निकलने पर घटेमें नहीं लगे जावेगा । इस दफामें उर्ही कर्जोंके सूदका जिक्र है जो दिवालिये पर होवे वन कर्जोंका जिक्र नहीं है जो दिवालियेको अपने कर्जदारोंसे बसूल करता हो इस कारण दिवालियेके कर्जदारों यह बतये समयमाना चाहिये कि यह निमित्तकी हुई दरके अनुसारही सूद अदा करे देखो—18 I. C. 205

मदकूम कर्जद्वारा (Secured creditor) को अधिकार है कि वह निमित्तकी हुई दरके अनुसार अपना सूद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् कर्ज बसूल होनेकी तारीख तक ले सके देखो—A. I. R. 1924 Rang 352. दिवालिया करार दिये जानेकी तारीखके बाद अदायग ६) रुपया सैकड़ाकी दरसे अधिकका सूद नहीं दिया जा सकेगा—A. I. R. 1926 All 361.

दफा ४९ साबित करनेका तरीका

(१) इस पक्षके अनुसार कर्ज साबित करनेके लिये कर्जकी तारीखमें हलफनामा अदा-
लतमें दाखिल किया जासकता है या वस्तुस्थिति रजिस्ट्रीके मेजा जासकता है ।

ह्राप मामला रख हुआ हो तो कर्जदारके दख्खाम्त देने पर अदालत ऊपरकी तरह सहकीकात फरक सूचीके इस्तख्वाफकी खारिज कर सकती है या कर्जको घटा सकती है ।

व्याख्या—

इस दफ्ते अदालत उस अधिकारका वर्णन है जिसके अनुसार वह सूचाने दिसागये हुए कर्जों। सूचाने दया सकती है या उसे कम कर सकती है । अदालतको चाहिये कि उस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें कगते समय स्वयं हो जाच कर आर उसके चाचका मार रिहारे पर न छाड देवें देखा—61 I. C 767, A. I. R 1926 Mad 1019 अर्थात् इस दफ्तेके अनुसार रितावरको अधिकार नहीं दिया गया है कि वह स्वयंहीं रिता वर्जित रह वगद अमरा सूचाने हगदे ।

अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह कर्जदैनकी उपस्थितिमें या उनका अधिन सूचाने दिये जानने परचात् कानूनन इस प्रश्नकी तय करे कि सूचीमें रिता नामको बढाना या घटाना चाहिये अथवा नहीं । अदालत बिना एसा रख हुए नाम बढा या घटा नहीं सकती है देखो—अमीरखन्दा बन्नाम अनुवृत्तचद A. I. R 1926 Cal 160

जब कि सब कर्जवाहें समाप्तकी आचुके और वह फर्गन जिसको हानि पहुँच रही हो सब कारवाहें कर चुका हो तो कर्जवाहें समाप्त हो जानेके बाद सूचा नहीं सुगगी जामकती है देखो—51 I. C. 55 इस दफ्तेमें यह प्रकट है कि अदालतको अपने आपकी इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें न करना चाहिये किन्तु रिता न रिनाफ दख्खालतून पर इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें करना चाहिये ऐसी दख्खाम्त ऊपरका (१) के अनुसार रितावरके ह्राप तथा ऊपरका (२) में रिती वर्जकराह या कर्जदार ह्राशरी जाना चाहिये । इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कर्जमें सम्मन्ध रखन वाले कर्जदारकी सूचना देवे जिसमें कि उसके निम्नक्त बाई हुकम बिना उसको सूचना मिल हुए न रिता जासके । यदि कोई तमाशे वर्जों बिना जाने हुए सूचीमें दर्ज हो गया हो तो उसका दर्ज हो जाना इस दफ्तेके अनुसार अनुचित है और इसी कारण उनको सूचीसे निपान दिया जाना चाहिये । एर कर्जकराह दूसरे कर्जकराहके रजेश बिशय कर सकता है देखो—37 All 252.

आकिशक रितावरका कर्जकराहानकी सूची तैयार करना कोई कानूनी या आनिग निर्णय नहीं है बिशय कर उन मामलोंके लिये जिनमें छगङ्गा हो और इसीलिये उसके सूचा तैयार कर देनेमें अदालतमें अधिकार सूचाने कर्जों निराल देनेके सम्मन्धमें जाता नहीं हैग दखो—45 I. C 67. बाद इस दफ्तेके अनुसार सूचाने बाई कर्ज निराल दिया जावे या कम कर दिया जाव तो उसकी अपील दफा ७५ (२) व सूचा न० १ के अनुसारही जासकेगा देखो—A I R 1926 All. 361

पहिले किये हुए सौदों (Transactions) या कारवाहियों पर दिवालेका असर

दफा ५१ इजरायमें कर्जकराहानके हक्कोमें रुकावट

(१) जबकि कर्जदारकी जायदादके खिलाफ डिफ्टी जरीकी आचुकी है तो रितावरके मुकाबिले किसी शख्सको उस इजराय में लाभ उठानेका हक्क न होगी परन्तु दिवालीमें दख्खाम्तके लिय जनेसे पहिले इजरायके खिलसिलेमें नीलाम या और किसी तरीक़ेस जो अस्सारा कर्जदार का हथ्य अ.रा हो उसमें यह बात ल.गू न होगी ।

(२) अगर कोई महफूज कर्जहवाह अपनी डिक्ली ज.यदादके खिलाफ जारी कराये तो उसके अधिकारोंमें कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(३) जो खरीदार नेकनीयतीसे हजरत द्वारा नीलाममें जायदाद खरीदे उसको रिसीवर के मुकाबले हर मामलेमें अच्छा हक पहुँचगा ।

व्याख्या—

इस दफा का अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जजोंदारी जायदाद दिवालियों की कार्रवाई की जानेसे पश्चात् सभ कर्जदारानके लाभार्थ बचाई जासके अर्थात् कोई कर्जहवाह दिवालियों द्वारा सभ अलिये जतने पश्चात् की हुई (अपनी कार्रवाईमें अनेके काम नहीं उठा सकेगा ।

इस दफासे कर्जहवाहोंके इन्तजाम बचाव पटनी है किन्तु इनकाय कर्जहवाहों अदालतके अधिकारोंमें कोई कमी नहीं पड़ती है क्योंकि वह अपने अधिकारके अनुसार इनकायकी कार्रवाई कर सकती है । इस कारण यदि अदालत किसी इमरायमें कोई जायदाद नीलाम करे तो दिवालियोंकी कार्रवाई काजाने पर वह नीलाम बन्द नहीं ठहराया जायगा देखो—A. I. R. 1925 Lah. 158. पालू ऐसी दशामें आगे नतलाई हुई दफा ५२ की परिवाहिका जयोंग किया जासकेगा ।

पुनर्ने अर्थात् सन १९०७ ई० के एक्टके अनुसार रिसीवरको कोई अधिकार नहीं था कि वह डिक्लीदारसे वह बयदा लेसके जो उसने दिवालिया करार दिये जाने वाले हुबसे पहिले वसूल कर लिया हो देखो—41 All 274. पालू इस एक्टके अनुसार ऐसा नहीं है दिवालियोंके द्वारा सभ ले लिये जाने (Admission) के बाद रिसीवरको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है उसमें पहिले जो वसूल हो चुके वह डिक्लीदारकी समझना चाहिये । इस बातको भली भाँति समझ लेना चाहिये कि दारम्वारके लिये आन (Admission) से पहिले इनकाय नीलाममें जा सभ वसूल हो चुकेगा बड़ी बच सकेगा और इस दफाका यही तात्पर्य समझना चाहिये देना—A. I. R. 1925 Mad. 224; A. I. R. 1926 Sind 199.

इस प्रकार यदि दारम्वार लिये जानेसे पहिले (Before Admission) नीलाममें हो चुके पालू बयदा बादमें वसूल हो तो यह रकम रिसीवरकी समझना चाहिये इनकाय कराने बाधा डिक्लीदार उसके पानेका हकदार न होकर देखी—A. I. R. 1925 Mad 248 में खनेदार नालामने कामत खरीदना खीपाई बयदा दे दिया था और बाकी बयदा जमा किये जानसे पहिले पदचूनन दिवालियों दारम्वार २५ था तब इस मासमें यह तब हुआ था कि डिक्लीदारको नीलामका बयदा नहीं मिलना चाहिये इस दफाके अनुसार नेवल कुर्के खने वाले डिक्लीदारकी बयदा नहीं बच सकता है किन्तु वह बयदा भी बच सकता है जा दूसर डिक्लीदारोंका जानना दावानीकी दफा ७३ के अनुसार खीर हिस्सा रखीके मिलना चाहिये क्योंकि हिस्सा समी हा जानेपर सभ उन डिक्लीदारोंका हो जाता है और पदचूनन उसमें कोई हक नहीं रह जाता है और इस कारण वह दिवालियोंकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं लिया जासकता है अर्थात् यदि दारम्वार दिवालियोंके लिये जानेसे पहिले (Before Admission) किसी इनकाय डिक्लीदार द्वारा सभ हिस्सा रखी लगाने वाले डिक्लीदारोंमें बट गया हो तो वह बयदा भी रिसीवर पानका अधिकार नहीं होगा देखो—A. I. R. 1922 Mad 31—381 C. 512.

यदि कोई बयदा कुछ होकर अदालतके हाथ आर्डर २१ रूल ५२ जानना दावानीके अनुसार आया हो पालू इस बयदेको दिये जानेसे पहिले पदचूनन दिवालिया करार दिय जानेकी दारम्वार देदी गई हो और आकिशर रिसीवर हुब समझना (Interim) रिसीवर नियुक्त कर दिया गया हो तो एमी हालतमें यह तब किया गया कि रिसीवरको उस बयदेके लिये हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है जिसमें वह एक्ट दिवालियोंके दफा ५२ (१) के अनुसार सभ कर्जहवाहोंके लाभार्थ दिया जानके देखो—A. I. R. 1928 Sind 165. दिवालियोंके दारम्वार ले लिये जान (Admission)

क पक्ष न कुं वगने नाठि डिक्लीटका इक कुंईरी हुई जायदाद पर नहीं पहुँचता है और वह जायदाद दिवालियाहोना नहीं रहती है तथा दिवालिया अंगर दिये जानके बाद वह रिमायन्स हो जाती है । अमेजी कानूनके अनुसार कुंई वगने वाल डिक्लीटका इक जायदाद पर हो जाता है आर एमो मागन वह कुंईरी हुई जायदादमें बच पर अपना वकै वगुन कर सक्ता है परन्तु भागवतमें ऐसा नहीं है बदाक कानूनके अनुसार कुंई कराने वाला डिक्लीटार यदि दरख्तास्त दिवालियाके श्रिये जानमे पहिले नीलाम कराके अपना रुपया न ले चुका हो ता उसका कोई इक कुंईरी हुई जायदाद पर नहीं पहुँचता और उसकी वकै स्थिति समझना चाहिये जो दिवालियाके दूसरे वर्जकाहोती है आर वह नीलामकी कमिडमे केवल हिस्सा रसदाही और वकैल्वाहोके साथ पासकेगा देला —44 Cal 1016

यदि दिवालियाका कोई वर्जकाह उसका रिस्त डिक्लीटो जो उसने किसी तीसरे शक्त्तके खिलाफ दावाया हो चुक कराले तो वह वर्जकाह इस कुंईमे लाभ नहीं उठा सकगा क्योंकि दिवालिया अंगर दिये जाने पर इमाग कानेका इक रिमीवरना हो जायेगा देलो—18 All 86

अस्सात्ता (Assets) से तात्पर्य उस चीजमे है जो इनसगमे कुंईरी हुई जायदादके मोताब होते पर वसूल होने ।

अस्सात्ता का वसूल होना (Realization of assets) उस वक्त मसझा जावेगा जबकि वह अस्सात्तके हारमो भाजक देलो—18 Cal 242, 28 Cal 264, 19 Mnd. 72, 9 A L J 707

यही बात नीचे दिये हुए मामलोंमें भी तयकी जाचुगी है देखी—44 Mad 100, A I R. 1923 Mad 505, 34 All 628, 101 I C 848 (Sindh.) इस 101 I. C 848 के मामलमें यह भी तय किया गया था कि यदि कुंई करनेवाली अदालत न वह अदालत जसमे रुपया कुंई किया जाने वाला होवे एकही होवे ता वह रुपया दफा ५१ (१) के अनुसार वसूल किया हुवा अमाग समझा जावेगा जो अदालत मद्रूनकी डिक्लीटके वकै फगत वाले डिक्लीटारके हकमें आने हुवा दावा मुन्तजिल पर दिया होवे ।

यह दफा उक्त वक्त क्यू होगी जब कि रुपया किसी डिक्लीटो इंगायमें वसूल किया गया हो हमलिये यदि अदालतमें कोई रुपया फगततका अमा हा तो उसके श्रिय यह नहीं रहा जावेगा कि वह रुपया इनसगमें वसूल किया गया है देला—31 I C 573, 19 A L J 898

उपदफा (२) यहकूज वर्जकाह इस दफाते वगी है यहकूज वर्जकाहोके दफा वर्णत दफा ५ (२), १८ (६) आर दफा २८ में है ।

उपदफा (३) यदि किसी म्पानिने नेवनीयनीसे नीलाममें जायदाद ठेकी हो तो उसकी शक्त्त वर्णत इस उपदफाम दिया गया है । नक्नीयनीसे नीलाममें जायदाद खगंनने अभिप्राय यह है कि खरादार नीलामको नालामफ मय यह न मोहद हो कि मद्रून नीलामने मय दिवालिया था आर न मद्रून तोसे पोशिश करने पर वह यह माझाही पर सक्ता था कि दिवालिया हुवा मद्रूनके खिलाफ दिवा जाचुगा है दफा—34 I C 829

दफा ५२ जायदादके खिलाफ डिक्लीट इजराय करनेमें अदालतके कर्तव्य

अगर कोई डिक्लीट कर्जदारकी उस जायदादके खिलाफ जारीकी जाने जो इजरायमें वकै आपकरी है और नीलामसे पहिले इजराय करने वाली अदालतको नोटिस मिल जावे कि कर्जदार द्वारा याउनके खिलाफ दीहुई दिवालिकी दरख्तास्त लेती गई है तो अदालत दरख्तास्त आन पर जायदादको अगर वह अदालतके वकैमें होगी रिमीवरके सुपुर्दे करनेका हुक्म देगी परन्तु उस सुफदमेका सुर्चे जिमे डिक्लीट हुई है तथा इजरायका खच उस जायदादसे सबसे

पहिले वसूल किये जायें और रितीवरको अधिकार है कि वह कुल जायदाद या उसके किसी हिस्सेको इन छूटोंकी अद्वयगीक लिये क्रयोक्त कर देवे ।

व्याख्या—

इस दफाका वही अभिप्राय है जैसा कि पिछली दफाका था कि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्जस्वाहोंकी लाभ पहुँचना चाहिये कोई एक कर्जस्वाह उस जायदादसे अग्रद्वारा जायदाद न उठा सके । यदि दिवालियेकी जायदाद लिये जाने (Admission) के पत्तापर दिवालियेकी कोई जायदाद नीलाम होने बाणी होने तथा नाश्या करने वाली अदालतको उस दिवालियेके दाख्वास्तकी सूचना मिल जावे तो वह रितीवरको उस जायदाद पर कब्जा देनेका हुक्म दे देवगा अगर जायदाद अग्राजतके कर्जमें होवेगो । पिछले एक्टके अनुसार दिवालिया क़ार दिए जानेके बाद इस प्रकारका हुक्म दिया जातकता था परन्तु इस एक्टके अनुसार दख्वास्त दिवालियाके लिये जाने (Admission) परही ऐसा हुक्म दिया जावेगा अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य है जैसा कि 'Shall' शब्दसे जो अपेक्षाके एक्टमें प्रयोग किया गया है प्रकट होता है ।

इस दफाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि दाख्वास्त दिवालिया कर्तदार द्वारा दा गई हो या किसी कर्जस्वाह द्वाराही दी गई हो । दाख्वास्त दिवालिया चाहे जिसके द्वारा दा गई हो इस दफाके अनुसार कर्जवाही बीनामनेगी केवल इतना आवश्यक है कि वह दाख्वास्त लेखी गई होवे ।

यह बात भी ध्यानमें रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार कर्जवाही बरानेक क्रिये दाख्वास्त दिये जानेकी आवश्यकता है अर्थात् इस मामले लिये अदालत इसमामे दाख्वास्त दी जाना चाहिये कि वह जायदाद रितीवरके सुपुर्दगी जावे यदि इस प्रकारका दाख्वास्त न दी गई हो औऱ अदालत नोटिस मिल जानेके बाद भी जायदादकी नीलाम कर देवे तो ऐसे बीनामका विरोध रितीवर या कर्ज कर्जस्वाह नहीं कर सक्ता है देखें—A. I. R. 1925 Lah 158

इस दफाके अनुसार कर्जवाहीकी जानेके लिये इनाय कर्जदारकी जायदादके खिलाफ होना चाहिये अर्थात् यदि इनाय कर्जदारके अन्तर्गत किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादके खिलाफ होगी या ऐसी जायदादके खिलाफ होगी जिसमें कर्तदार व अन्य लोगोंका भी हिस्सा होवे तो इस दफाके अनुसार कर्जवाही नहीं कीजाना चाहिये । इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि इनाय किसी ऐसी जायदादके खिलाफ होने गो जगहमें भेची जातकती हो । इस एक्टके दफा ४ व २८ में बचे जाने योग्य जायदादका विवरण दिया हुआ है तथा जीवना दाबालीकी दफा ६० में भी इसका विवरण मिलता ।

इस दफामें जो अभिप्राय उल्लेख है उसमे उस इच्छाका तात्पर्य नहीं है जो रहनवासकी बिक्री हो या किसी महकूज कर्जस्वाहका अमानतके सम्बन्ध हासिलकी गई हो देखें—A. I. R. 1926 Mad 194

इस दफाका यह अभिप्राय नहीं है कि दिवालियेकी दाख्वास्त लिये जांतरा नोटिस मिल जाने पर अदालत सदस्यकी जायदादकी नीलाम करनेसे नाचित रसे देखें—A. I. R. 1925 Lah 158

यह दफा उन्ही समय लागू समझना चाहिये जबकि इनाय करने वाली अदालतको इस बातके लिये दाख्वास्त दीगई हो कि वह जायदाद रितीवरकी सुपुर्दगीमें देदे । इससे यह प्रकट होता है कि दफा उन्ही समय लागू होगी जबकि कोई रितीवर नियत किया गया हो । इसी प्रकार यह तय किया गया था कि यदि दायिमानी (Interim) रिमाइनको दिवालिये की जायदाद पर कब्जा लेना जायदाद अदालत द्वारा नहीं दिया गया हो तो उस सूरत अदालत इसमामे कोई दाख्वास्त जायदादका कब्जा उससे देनेके लिये नहीं दी जासकती है देखें—A. I. R. 1926 Mad 606

इस दफामें जो नोटिसका मिलना अदालतके लिये कहा गया है उसके तात्पर्य यह नहीं बतलाया गया है कि नोटिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिये । ऐसा मान्य होता है कि इस प्रकारका नोटिस कोई भी व्यक्ति देसकता है । नोटिस इस बातका

माना चाहिये कि दिवालियेरी दायदास्त उठा गई है चाहे वह दायदास्त दिवालिये द्वारा उठा गई हो या उसके किसी कर्तव्यवाह द्वारा उठा गई हो इसने कोई भ्रम नहीं पैदा किया। यदि नोट्स मिल जाने पर तथा जायदाद पर रसीदबन्दी कम्ता दिये जानेकी दायदास्त द दिये जाने पर भी अदायत नीतिगत रूप से तो ऐसे मामलोंमें अनिवारित सम्पत्ति चाहिये तथा ऐसे मामलोंमें छरीदार नीतिगतमें कोई हक नहीं पहुँचना है क्योंकि इस दफ्तेके अनुसार अदालत रसीदबन्दी कम्ता लेनेका हकम दनके लिये बाध है। इस दफ्तेके अनुसार रसीदबन्दी उमा जायदाद पर कम्ता लेनेका हकम दिया जासकता जा अदायत कम्ताग होनेसे यह स्पष्टता है कि मनवूला (Moveable) जायदाद परकी कम्ता लेनेका हकम हो सकेगा देखो—A. I. R. 1926 Sindh. 199 में यह तथ हुआ था कि, चूँकि इस दफ्तेमें यह दिया हुआ है कि इस जायदाद पर कम्ता दिया जावेगा जो अदायतके कम्तामें होने इससे यह मान्य होता है कि दफ्तेके उम मनवूला (Movable) जायदादके लिये लागू है जिस पर अदायत कम्ता कर लेवे या जो इस प्रकार कुर्ककी गई हो। उम पर अदालत कम्ता लेसके। रोमनवूला (Immovable) जायदाद पर कम्ता दायदास्त कम्ताके तौर पर नहीं किया जाता है किन्तु उस पर बा बा लेनेके लिये पहिले मद्रूलेके नाम इस प्रकारका हकम जारी किया जाता है कि वह उसे किसी प्रकार अलहा न करे और इसी कारण इस प्रकारकी जायदाद (अर्थात् रोमनवूला जायदाद) इस दफ्तेके अन्तर्गत नहीं आती है देखो—A. I. R. 1924 Sindh 69

इस दफ्तेमें यह भी बताया गया है कि यदि इस दफ्तेके अनुसार नीतिगतके पहिले जायदाद पर रसीदबन्दी कम्ता होनेका हकम दे दिया जावे तो उम जायदादमें दायदास्त खर्च तथा उम घुक्रहमेस खर्च जिसमें इनसयदी जान वामी किसी प्राप्त हुई थी पहिले दियेबाया जावेगा तथा रसीदबन्दी इसकी पूर्तिके लिये यह अनिवार प्राप्त है कि वह उस जायदादकी या उसके किसी हिस्सेकी उस खर्चकी चुकानेके लिये बंध देवे। इन बातोंका अभिप्राय यह है कि यदि कोई किसीद्वारा बालामका पूरा जायदा उठाके लेक दिया जाव तो ऐसी दफ्तेमें उसका अमली खर्च न माग जाना चाहिये अर्थात् वह इनसयदीके खर्च को पावेगा तथा उस खर्चकी भी पावेगा जो उसे किसी हासिल करनेम करना पडा हो परन्तु साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह उम्मी खर्चोंका वास्तविकता जो कि कानून उमको दिलाय गय हो या कानूनन सिनेके पावेका वह अधिकारी समझा जाव अर्थात् प्राइड खर्च व वह खर्च जो कानून उसको नहीं मिल सके हैं नहीं दिलाय जा सकते हैं।

दफ्ता ५३ अपने आप किये हुए सौदाकी मंजूरी

अगर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मसे दो सालके अन्दर किया गया हो परन्तु जो किसी शरीक बदस्तम तथा पहिले न किया गया हो अथवा जो नेकनीयतीले किसी खरीदार या जाभिनदार (Incumbrancer) के हकमें समुचित मूल्य लेकर न किया गया हो तो ऐसा इन्तकाल जायदाद रसीदबन्दीके मुकाबले रह किया जा सकता है और अदालतको अधिकार है कि उसे मंजूरा कर दे।

व्याख्या—

कानून दिवालियाका एक प्रधान उद्देश यह है कि दिवालियेरी जायदाद उसके मर वर्जकतामें उचित रूपसे नदी जासके और इस उद्देशका पूर्तिके लिये यह आवश्यक है कि दिवालिया अपने आपकी (Voluntary) या धोलेके इन्तकाउ न कर सके। इसी कारण इस दफ्तेमें यह बताया गया है कि दिवालिया कला दिये जानेके हकमके कारण दिवालियेके किये हुए सिने इन्तकाल रह किये जायसके हैं और वह इन्तकाल अदालत मंजूर कर सकती है देखो—62 I. C 924 यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि अग्रणी एकमें 'Voidable' शब्दम प्रयोग किया गया हो इस कारण यदि उम इन्तकालको रह करानेका प्रयत्न न किया जावे और मंजूरीका हकम न दिया जावे तो वह इन्तकाल बेतक।

तेषां कायम रहेगा । किसी इतकाल जायदादके ठीक होनेका प्रश्न उसी वन उभारा जासकेगा जबकि दिवालिया जगह दिये जानेका हुक्म हो चुके और उससे पहिले अदालतसे कोई अधिभार नहीं है कि वह ऐसे प्रश्न पर विचार कर सके दफा—
A I R 1927 Lah 95 पुनर्निर्णयकी दफा ३६ इस दफामे मिलती हुई थी वस्तु उसमें (अमेनो एक्टमें) 'Void' शब्दका प्रयोग था जिसपर तात्पर्य यह था कि उस प्रत्येक इन्तकाल अपने आपसे रद्द समझे जाते थे वस्तु इस एक्टमें 'Voidable' शब्द इतिहास तात्पर्य यह है कि रद्द कथना जासकता है जसा कि ऊपर बताया जा चुका है ।

इस दफामे अदालतमें तात्पर्य अशुद्ध दिवालियाय समझना चाहिये जूनि अदायत दिवालियाकी दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें बर्गवार्ड बनेका अधिभार प्राप्त है इसलिये दिवालिये करार दिये जानेके बाद बड़ी अदालत दिवालियेके लिये हुए इन्तकाल जायदादकी रद्द भा कर सकती है । जबकि अदायत इस एक्टमें अनुभाग कोई बर्गवार्ड करे तो उसे चाहिये कि खास तौरसे इस एक्टके नियमोंका प्रयोग कर परंतु इसमें यह न समझना चाहिये कि वह आम कानूनी मामले मामूला दीवानों अंगतानों तरह तय नही कर सकती है दफा—41 All 71.

किंतु यदि दिवालियेका उपबार्ड करते समय कोई आम कानूनी मसला तय करना बहुत जरूरी न होने हो अदालत दिवालियेकी चाहिये कि वह दफा ५ क अनुसार आम दीवानों अदालतमें अधिभागोंसे न बन बल्कि उस सल्लेखी अदालत दावाना द्वारा तय किया जानने लिये छोड़ देवे देता—A I R 1923 Mad 631.

यदि कोई जायदाद अदालत दिवालियाका अधिभार सीमाये बाहर भी होवे तो अदालत दिवालिया वस्ते सम्बन्धमें किये हुए इतकाल जायदादका मसूजा कर सकती है देखो—7 I C. 765 परंतु विदित भारतमें अदालतका यह अधिभार नहीं है कि वह चार धुकका जायदाद सम्बन्धमें किये हुए इतकालका मसूजा कर सके देखो—A I R. 1922 Nag 221

इस दफाके अनुसार अदायत किसी भी इन्तकाल जायदादका रद्द करना लिये बाल्य नहीं है किंतु उसका रद्द करना न करना अदालतकी न्याय पर निर्भर है । अग्रणी एक्टमें 'May be annulled' शब्दोंका प्रयोग किया गया है जिससे यहां अभिप्राय निरलगा है कि यदि जाकिपाको दायन हुए उचित प्रतीत हो तो अदालत मसूजा कर देवे यदि अग्रणीमें 'May' शब्दके बजाय 'shall' शब्दका प्रयोग हुआ तो बात दूसरी था व अदालतका मसूजा करनेका हुक्म दना लाजिमी होता परंतु इस दफाका तात्पर्य यहां समझना चाहिये कि अदालत मामलेकी उचित रूपसे सुनन व समझनेके पश्चात् सम्बोधित कार्य करे ।

अदालतको चाहिये कि वह अपने इस दफामें दिए हुए अधिभागोंन रिमिबर या रिहा मानवत अदालतको न द देवे देखो—36 All 549 यह दफा उसा समय लागू हा सकेगा जबकि इन्तकाल जायदाद रजम वाला न्याय दिवालयका करार ददिया गया हा तथा इस दफाको लागू करनेके लिये नीच दी हुई बातोंकी आवश्यकता समझना चाहिये —

(१) यह कि जायदाद अलहदा नो गई हो,

(२) यह कि इतकाल जायदाद किसी विवादके बन्देमें तथा पहिले नहीं किया गया हो,

(३) यह कि वह इन्तकाल किसी ऐसे स्वरीदार या जामिनदार (In-umbrancer) व इन्में नहीं किया गया हो जिसने नवनायतास व सजुलिन मूल्य देकर जायदादको लिया हो, और

(४) यह कि वह इन्तकाल, दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले दो सालहके अन्दर किया गया हो अपाव उस इतकाल जायदादके बाद २ सालहके अन्दर वह दिवालिया करार दिया गया हो ।

दो सालके अन्दर—से तात्पर्य यह है कि यदि कोई इतकाल जायदाद, दिवालिया करार करने जाने बाद

हुकममे पहिले उसके दो सालों अदर किया गया हो ता वही १६ किया जा रहा और यदि वह इतनाल जायदाद दिवालिये का दायता दिये जाने पहिले दो सालके अदर किया गया हो ता ऐसा इतनाल जायदाद इस दस्तक अदर नहीं जाता है यदि किसी इतनाल जायदादको हुए दिवालिया करार दिये जाने पहिले दो सालके अतिरिक्त होय हों पान्तु जा दिवालिये की दायता दिये जानम दो सालके अदर पड़ता हो ता ऐसा इतनाल जायदाद इस दस्तके अर्थात नहीं जाता है देखो—
A 1 R. 1925 Bom 480, A 1 R 1926 All 470, A 1 R 1924 Lah 374, A. I. R 1927 Sindb 66, A I R 1928 Rang 148, A I R. 1928 Lah 381 (F B)

उपर कहे हुए सब धकदमों साथ तोलते गये तब किया गया है कि दो साल की मियाद दिवालिया करार मिले जाने वाले हुकममे ही लागत चाहिये वह मियाद दिवालिये की दायता दिये जानम के लिये नहीं ली जायता है। यदि कोई इतनाल २ सालके पहिले का इतनाल बनइत उस दस्तक अनुसार रद न किया जायता हो तो उस इतनालके लिये दफा ५३ कानून इतनाल जायदाद अनुसार समग्र मालिकमे रद करनेका याचिका जासानी है। अतः प्रत्येक दिवालिया यदि दिवालिये का याचिके मालिकमे रदना इतनाल जायदादको इस दस्तके अनुसार रद न कर सकता तो वह इतनाल अतः लीवालीसे समूल रखा जायता है दफा—A. I R 1928 All 470, A I R. 1922 All 443

बार सुवृत्त—जो व्यक्ति इतनाल जायदाद रद कराय चाहता हो उसे पहिले यह साबित करना पड़ेगा कि वह इतनाल जायदाद होने दो सालके अदर किया गया है और जब यह साबित कर दिया जाइ तो बार सुवृत्त उमेय हद जायगा और तब मित व्यापक इतनाल किया गया है उक्त कर्तव्य होना कि वह नेकनीयती तथा समुचित मूल्यका अदर किया जाना साबित करे दफा—A. I. R 1923 Nag 97, 39 All 90, 46 All 86।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब मोदे जो दिवालिया अपनी जायदादके सम्बन्धमे दिवालिया होनेसे गे साल अदर करे चाहिये अतः समग्र जाना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति इस विषय साबित किया चाहे तो उसको चाहिये कि उस सादेका नेकनीयता किया जाना तथा उक्त कि समुचित मूल्यका दिया जाना साबित करे दफा—A. I R 1924 Mad 860, A I R 1926 Lah. 307

जबकि यह इतनाल जायदाद इतने कष्ट का अत्यन्त लिये किया गया हो ता बार सुवृत्त इतनाल कराने वाले व्यापक पर नहीं रहेगा किन्तु अतिमल मालिकों यह साबित करना पड़ेगा कि वह इतनाल बदनीयती कराय गया है देखो—A I R 1926 Sindh. 140. अतः कर्तव्य है कि वह यह निश्चित करने समय कि वह इतनाल जायदाद नेकनीयतामे किया था है या नहीं उन सब बातों का ध्यान रखे जो इतनालम सम्बन्ध रखती हैं। अतः जो इतनाल जायदाद इतने समय उपस्थित हों तथा उमेय पहिले या उमेय बाद फर्निचर अन्यवास्ते समग्र पद देखा—26 Bom 571, A I R 1924 Mad 865

नेकनीयतासे सम्बन्ध रखने वाली हर एक बातको अलदहा अलदहा नहीं समग्रता कहिये किन्तु उन बातोंको एक दूसरेके सम्बन्धसे देखना चाहिये तथा सब बातों पर एक साथ ध्यान रखते हुए नेकनीयता या बदनीयतीके प्रश्नमा निश्चित करना चाहिये देखो—A. I R 15 27 Nag 166. जहाँ किसी दन मेहर (Dower debt) के ठार हानका प्रश्न उपस्थित हो तो दन बातों पर विचार करना आवश्यक समग्रता चाहिये (१) यह कि कितना मेहर दायता बारी था, (२) यह कि किम प्रभाव मेहर था, (३) यह कि इतनाल निम नीयत किया गया (४) यह कि जो जायदाद उमेय बदल्ये दो गई है उसका मूल्य क्या है, तथा (५) यह कि मेहर का रुपया अदा करने देर किम बाधा आई थी देखा—39 All 95 यदि इस दस्तके अनुसार किसी देनतामे रद करनेकी दायता दी जावे तो ऐसा दायतासे दिये जानेसे अलत दायताका अधिकार देनतामेका मुद्दा तथा कलेक सम्बन्ध नहीं जाता रहेगा। यदि कोई देनतामे

मुद्रमा चल रहा हो और आकिशत रितीवर उस रेहननामकी रद्द करनेके लिये अदालत दिवालियामें दाखल हो तो उचित तरीका यह होगा कि हम दाखलानके केसल लिये जाने तक वह मुद्रमा रोक दिया जाने दो—A. I. R. 1926 Mad. 1051.

इस दफाके अनुसार कार्रवाई उसी समय हो सकेगी जबकि दिवालियेमें कार्रवाई चल रही हो अर्थात् वह सम्पत्ति हो गई हो। यदि हम दफाके अनुसार किसी इतकाज जायदादमें रद्द करना हो तो इसकी सूचना उस व्यक्तिमें अवश्य दी जाना चाहिये जिसे हमें वह इतकाज दिया गया हो तथा उसे अपना मामला ठीक तौरसे अदालतके सम्मुख उपस्थित करनेका अवसर दिया जाना चाहिये देखो—50 I. O. 117. इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि पूरी कोर्ट कोस लगाकर अर्थात् दावाके तौर पर दाखला दी जाना चाहिये किन्तु इसका लिय जो दस्तावेज दी जाने उसमें माफ तौरसे उन सब बातोंको दिखला देना चाहिये जिसके आधार पर किसी इतकाज जायदाद पर दावा किया जा रहा हो। अदालत दिवालियाको यह अधिकार नहीं है कि वह इस दफाके अनुसार कार्रवाई करने समय सहकीमाले लि। म. म. २. सेसिक या किसी दूसरी मातङ्ग अदालतके पास भेज देवे किन्तु उसका कर्मण्य है कि ऐसी दाखलानके अति पर इसका सूचना उचित रूपसे उस व्यक्तिको देवे जिसके इकमें जायदाद लिखी गई हो तथा इसके परवतू लोगों औरके सूरु का मुद्रकर रखी उस दाखलानका केसल करे दो—36 All. 549. रिवाजकी भी हम दफाके अन्तर्गत १९ हरे दाखलानकी सुनन तथा उनके तब करना अधिकार नहीं है। केवल अदालत दिवालियाही इस दफाके अनुसार दाखलानके सती है तथा इतकाज जायदादको मसूख कर सकती है या उसके मसूख करनेमें इनकार कर सकती है। यदि रिवाज स्वयं या किसी दाखलानका केसल करे तो इसका अर्थ यह होगा कि वह स्वयं अपने मामलेके लिये जज बन गया है देखो—A. I. R. 1926 Mad. 1019

हम दफाके अनुसार कार्रवाई मामूली मुद्रमाओंका तरह की जाना चाहिये सरसदीकी कार्रवाई न करना चाहिये देखो—39 All 39. अर्थात् इस दफाके अनुसार यदि कोई प्रश्न उपस्थित होवे तो उनको सरसदीमें तय न कर देना चाहिये किन्तु उनको कानूनी तहजीबके बाद भली भाँति समझ कर तय करना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Mad 801.

रितीवरकी रिपोर्ट देने मामलोंके लिये कानूनी शाहस्त न सम्पत्ति चाहिये और न ऐसी रिपोर्टोंके आधार पर कोई प्रमाण इस दफाके अनुसार लभ हो कर देना चाहिये देखो—36 I. C. 906, 36 All. 549, 46 All 864.

यदि इस दफाके अनुसार कोई इतकाज जायदाद रद्द कर दिया जावे तो उसके बाद वह जायदाद रिवाजकी सम्पत्ति चाहिये और वह जायदादमें दिवालियेके कर्तव्यवाहोंको हिस्सा रखे उनकी और जायदादकी तरह दिखाना चाहिये। यदि कोई बयनामा इस दफाके अनुसार रद्द किया गया हो और उस बयनामामें जाये किसी निजके रेहननामका बयनामा मसूख किया गया हो तो वह रेहननामका बयनामा नकार करके सम्पत्ति जावेगा और बयनामामें मसूख हो जानेके बाद भी रेहननाम करने वालका वह मसूख जाे उसने रेहननामका अदागीमें दिया है नकार करके मसूख सकेगा अर्थात् वह जाे रेहननामका साथ उस करके लिये हिस्सा रखी पामकेगा देखो—A. I. R. 1925 Nag. 73.

इस दफाके अनुसार किया हुआ फैसला अत्र तन्त्राज्य युद्ध (Resjudicata) सम्पत्ति जावेगा और किं वही फौजैनक दायित्वान् उही मसलको तय करानेके लिये मामला नहीं चल सकेगा देखो—49 All 71, A. I. R. 1927 Cal 474.

यदि हम दफामें यह नहीं बनवाया गया है कि दाखलान किस समय दी जाना चाहिये हमने यह सम्पत्ति चाहिये कि हम दफामें अनुसार दाखलान दान कार्रवाई दिवालियामें किसी समय भी दी जा सकती है। देखो—दरार्निद नमः

कृजीनल A. I. R. 1924 Lah. 553. यदि इस दफाके अनुसार कोई इन्तकाल जायदाद मसूज किया जावे तो ऐसे इन्तकालीन जायदाद में दफा ७५ (२) के अनुसार कोशिका होती है ।

दफा ५४ कुछ मामलोंकी कीहुई तरजीहकी मसूखी

(१) अगर दिवालिया करार दिये जानेके तीन माहके अन्दर किसी एक कर्जश्वाहके हकमें उसको दूसरे कर्जश्वाहोंके मुकामके तरजीह देते हुए कोई इन्तकाल जायदाद या अदायगी या हक पैदा करना या कोई अदालती कार्यवाई उस कर्जदार द्वाराकी गई हो जो यह जानता हो कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकेगा तो यह सब कार्यवाहियां उस घफ धोखेदेहीकी कार्यवाहियां समझी जावेंगी जबकि तीन माहके अन्दर उसके खिलाफ दिवालीकी दरखास्त दी गई हो और यह दिवालिया करार दे दिया जावे और रिसीवरके मुकामके वह रह समझी जावेंगी और अदालत उनको मसूज कर देगी ।

(२) इस दफासे उस शायदके हकमें कोई अस्तर नहीं पड़ेगा जिसने नेकनीयतीके काफ़ी मुआविज़ा (Consideration) देकर दिवालियेके किसी कर्जश्वाह या उसके ज़रियेसे उस हकको हासिल किया हो ।

व्याख्या—

इस दफामें भी पिछली दफाकी तरह यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले इकमत जसर पिछले स्रोतों पर क्या पड़ता है । इस दफाके अनुसार उन कर्जदारोंके अधिकारोंकी रक्षा की गई है जिनके कर्जोंको मारनेके लिये कर्जदारने अपनी जायदाद किसी एक कर्जश्वाहके हकमें उसे देना फायदा पहुँचानेकी परकते करदी हो । परन्तु इस दफाके लिये इस बातका ध्यान रखा चाहिये कि वही स्रोत वह समझा जावेंगे जो दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किये गये हों अगर तीन माहसे पहिलेके कोई स्रोत होवे तो उन पर इस दफाका प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस दफाके अनुसार कोई स्रोत उसी समय रह समझा जावेगा जबकि नीचे दीहुई चारों बातें उपस्थित होवें (१) यह कि उस स्रोतके लिये जाने समय कर्जदारके पास अपने सब कर्जोंको अदा करनेका साधन न होवे (२) यह कि वह सादा किसी कर्ज-श्वाह या कर्जेश्वाहके दूरीके हकमें किया गया हो (३) वह स्रोत यह जानबूझ कर किया गया हो कि, उससे उस कर्जेश्वाहकी देना फायदा पहुँचे अर्थात् दूसरे कर्जेश्वाहोंके मुकामके उसे फायदा पहुँचानेकी इच्छासे वह स्रोत किया गया हो (४) यह कि वह स्रोत दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किया गया हो तथा उस दरखास्त पर कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे । देखो—A. I. R. 1928 Rag. 106

यह बात भी याति समझ लेना चाहिये कि अदालत इस दफाके अनुसार कर्तवाई उसी समय कर सकेगी जबकि कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे अन्यथा नहीं देखो—मूलसिंह बनाम लक्ष्मीदेवी 95 I. C 1055 यदि ऊपर दिखलाई हुई सब बातें उपस्थित होवें तो वह स्रोत रह समझा जावेगा और चूँकि वह स्रोत अपने आपमें रह होवेगा इसलिए अंगलतका कर्तव्य सप्रमना चाहिये कि वह ऐसे स्रोतको रह कर देवे । अमेसी एक्टकी इस दफामें (Void) शब्दका प्रयोग किया गया है जो इसमें पिछली कफा अर्थात् दफा ५३ में (Voidable) शब्दका प्रयोग किया गया है अतः इस नातसे यह स्वभावतः प्रकट है कि पिछली दफाके अनुसार बातोंके उपस्थित होने पर स्रोत रह करार दिया जासकता है परन्तु इस दफाके अनुसार बातोंके उपस्थित होने पर स्रोत अपने आपमें रह होता है । इस दफाके अनुसार यह आवश्यक है कि दिवालियेकी मशालोखादेहासे किसी एक कर्जेश्वाहकी दूसरे कर्जेश्वाहोंके मुकामके फायदा पहुँचानेकी रही हो यह आवश्यक

नहीं है कि जिसके इकमें सोदा किया गया हो उसकी मश इस प्रकारकी रही हो दखो—109 I C. 370, A. I R 1929 Lah 79

भोलादहीसे बेना लाभ पहुँचानेसे तात्पर्य यह है कि सोदा होने समय दिवालियेकी क्या इच्छा थी अर्थात् क्या वह सोदा किमा एक कर्जेश्वारको दूसरे कर्जेश्वारोंके मुकामके बेना फायदा पहुँचानेकी मशाके किया गया था देखो—42 Mad. 510, A. I. R 1928 Mad. 860

दफा ४४ में यह नहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इसके अनुसार सोदा किस समय मसूख किया जानाका है परन्तु दफामे यह बात अथ भाते प्रकट है कि दिवालिया करार देदिय जानेके बाद यह सोदा रद्द किया जाना चाहिये क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले अदाकर्ता कोई अधिकार इस दफाके अनुसार कार्यवाही करनेका नहीं है। जबकि अदाकर्ता मातहतने दिवालिया करार दिये जानका हुकम इसी बिना पर दिया हो कि दिवालियेने कोई सोदा धाऊ देनाका किया है तब दिवालिया करार दिये जानेका हुकम और धोखाधरीसे किये हुए सादरी मसूखीका हुकम एक साथ दिया हो और उस सोदेका मसूखीका हुकम पहिले लिख गया हो परन्तु दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम उसके बाद लिखा गया हो ता यह तय हुआ कि इस प्रकारकी चलती एक प्रकारसे लिखनेकी मशकी है और इस कारण अदाकर्ता मातहतका हुकम ठीक है अर्थात् अदाकर्ता सादेका मसूखी व दिवालिया करार दिये जानेका हुकम एक साथ दे सकती है तथा उनके आगे वंके लिख जानेसे हुकममें कोई असर नहीं पड़ता है तथा वह हुकम ठीक समझना चाहिये दखो—होमसिंह बनाम गोपालदास देसरान 109 I. O 370, A. I. R 1929 Lah 79.

सोदेके मसूखीकी दरख्वास्त इस दफाके अनुसार दिवालियाकी कार्यवाही मपात होनेसे पहिले किसी समय की हो जासकती है। इस बातका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि वहाँ सादे इस दफाके अनुसार रद ममसे जानने को दिवालियेकी दरख्वास्त दिय जानेसे पहिले तीन माहके, अन्दर किये गये हों तीन महीनेका समय जोइने समय वह दिन जिस दिनकी दरख्वास्त दायरे हो नहीं जोखा जावेगा।

१५ दिसम्बर सन १९२६ ई० को अमीराण्ट्स १ व २ न अपने एक कर्जेश्वारके दिवालिया करार दिये जानकी दरख्वास्त दी परन्तु उस कर्जेश्वारको जा कर्जो इन दोनोंको अदा करना था वह ५००) पाउन्ड रुपयेन कम था इस कारण २८ जनवरी सन १९२७ ई० को अफलाण्ट नं० ३ भी उस कर्जेश्वारके विरुद्ध दरख्वास्तमें शामिल होगया और वह कर्जेश्वार १८ फरवरी सन १९२७ ई० को दिवालिया करार देदिया गया। १ मार्च सन १९२८ ई० को अमीराण्ट्सन अदाकर्तामें दफा ५४ (१) के अनुसार उन सोदाकी रद्द करारदेनकी दरख्वास्त दी जो दिवालियेने १५ दिसम्बर सन १९२६ ई० से पहिले तीन माहके अंदर किये थे तो यह तय किया गया कि २८ जनवरी १९२७ ई० का अंतर्जो सारीज समझना चाहिये जबकि दिवालियेकी दरख्वास्त दीगई था और उसी दरख्वास्त पर कर्जेश्वार दिवालिया करार दिया गया था इस कारण वह सादे आ इस सारीजमें पहिले तीन माहके अन्दर नहीं हुए हैं इस दफाके अनुसार रद नहीं समझे जासकते हैं देखो—28 A. L. J. 941, A. I R 1928 All 676

जैसाकि ऊपर बतलाया जा चुका है इस दफाका प्रयोग होनेके लिये यह आवश्यक है कि सोदा किये जाने समय कर्जेश्वार अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ हो अर्थात् यदि कर्जेश्वार पास काफ़ी रुपया हो या ऐसा सुझाव हो कि जिससे वह अपने सब कर्जों चुका सकता हो और उस समय वह किसी एक कर्जेश्वारके इकमें दूसरे कर्जेश्वारोंके मुकामके कोई सोदा कर दब तो उस समय इस दफाका प्रयोग नहीं हो सकेगा क्योंकि ऐसी दशामें वह दिवालियादी करार दिये जाने योग्य न होगा परन्तु यदि उसके पास उस समय अपने कर्जोंको चुकानेका सुभीता न होव ता वह सोदा इस दफाके अनुसार और शर्तोंके पूरा होने पर रद होगा। असमर्थ होनेसे तात्पर्य यह है कि कर्जेश्वार उस समय अपने कर्जोंको अपने आप नहीं

धरा समता हो यदि पर्याप्त रुपये न होनेके कारण वह बड़े बतके रुपये कैसे होनेके कारण जिसकी वजहसे वह अपने कर्जोंकी अदायगीका प्रबन्ध उस समय न कर सकता हो। इस बात पर प्रमाण A. I. R. 1927 Lah 136 में डाला गया है इसी प्रकार इस बातकी भी आवश्यकता है कि सौदा होते समय दिवालिye की यह मंशा रही हो कि किसी एक कर्जस्वाहकी दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले विशेष लाभ पहुँचे वरना वह दफा लागू नहीं हो सकेगी देखो—दोस्तपम बनाम देवरीनन्दन A. I. R. 1924 Lah. 686.

कोई सौदा केबल इसी बातसे रद्द नहीं समझा जावेगा कि उसमें एक कर्जस्वाहकी दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले लाभ पहुँचा है जब तक कि यह साबित न हो जावे कि कर्जदारका ऐसा करनेकी मंशा थी देखो—मोतीलाल बनाम बीअरारा A. I. R. 1926 Lah. 281.

यह अनवरा साबित होना चाहिये कि किसी एक कर्जस्वाहकी अदायगी होने समय कर्जदारकी असल मंशा विशेष पर थी रही हो कि उस कर्जस्वाहकी ओंसेके मुकाबिले रुपया मिल जावे तथा उस कर्जस्वाहोंने उसका रुपया हिस्सा रखनेके दिवाले न पाया जानके देखो—37 I. C. 250.

यह मानिन रखनेके लिये कि किसी कर्जस्वाहकी धोखेसे लाभ पहुँचानेके लिये दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्जिह दी गई है केवल रतनाही साबित करना आवश्यक नहीं है कि एक कर्जस्वाहकी दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्जिह दी गई है किन्तु यह भी मानिन होना आवश्यक है कि उस सौदेमें करते समय कर्जदारकी मंशा उस कर्जस्वाहकी तर्जिह देनेकी थी और रही नीयतमें वह सौदा किया गया था। यह पर्याप्त नहीं है कि उस सौदेमें एक कर्जस्वाहकी दूसरे के मुकाबिले लाभ पहुँचा है किन्तु यह भी मानिन होना आवश्यक है कि एककी दूसरेके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशा रही हो देखो—42 Mad. 510; 44 Mad. 810.

यदि सौदा करते समय कर्जदारकी असल मंशा यह रही हो कि इससे स्वयं उसे लाभ पहुँचे न कि उस कर्जस्वाहकी निमित्त हकम वह सौदा किया जायगा तो तो ऐसा सौदा इस दफाके अनुसार धोखेसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा देखा—43 All 427; A. I. R. 1929 Lah 686 इस प्रकारके मामलोंकी समझनेके लिये यह देखना आवश्यक है कि आया वह सौदा कर्जदारके अपनी मंशाके लिये किया है या अपने किसी एक कर्जस्वाहकी लाभ पहुँचानेकी मंशा में किया है देखो—A. I. R. 1925 Mad. 1089 यदि किसी सौदेमें केवल इस बातका धारणा हो कि वह सौदा एक कर्जस्वाहकी दूसरेके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशासे किया गया है तो केवल धारणाके कारण यह दफा लागू नहीं होगी देखो—43 Cal 640

जबकि दिवालिया किसी दवालेके कारण कोई सौदा करता है या रुपयकी अदायगी करता है या कोई ऐसा सौदा करता है जिसका कि उद्देश्य इस दफामें है तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि उसने धोखेद्वारा किसीको तर्जिह देना चाही था देखो—37 I. C. 250. इस दफाके अनुसार जो तर्जिह देनेका क्रिम है वह तर्जिह किसी कर्जस्वाहके लिये होना चाहिये या जल्दके लिये नहीं इस दफाके लिये कर्जस्वाहका अभिप्राय महफूज कर्जस्वाहमें भी समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1922 Nag 233. पल्लु कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले में इसमें नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Cal 689 यदि कोई व्यक्ति उन सौदाओंके होनेकी वनहते ओ कि रद्द करया जानेको है कर्जदारका कर्जस्वाह बन जाके वा ऐसा दानकाम कर्जस्वाहकी इस दफाके अनुसार समझा जावेगा देखो—43 All 427

यदि कोई जामिनदार (Surety) किसी कर्जदारका बर्ज अपने पाससे धरा देवे तो वह जामिनदार भी उस कर्जदारका कर्जस्वाह बन जावेगा और यदि ऐसे जामिनदारके हकमें कोई गौदा उत्पन्न हो और कर्जस्वाहोंके मुकाबिले

बेना फायदा पहुँचानेकी मंशासे किया जावे तथा वह सौदा किसी खास दस्तावेज बन्धमे न किया गया हो तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे फायदा पहुँचानेका सौदा इस दफ्तेके अनुसार समझा जावेगा, देखो—A I R. 1923 Rang 149

तर्जिह (Preference) से तात्पर्य यह है कि एक कर्जदारको लाभ पहुँचि तब उसके कारण दूसरे कर्जदारको हानि उठाना पड़े । जैसा कि ऊपर कहा जाचुका है धोखादेहीमे तर्जिह देनेमे अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जो सौदा किसी एक कर्जदारको दूसरे कर्जदारकोके मुकाबिले लाभ पहुँचानेके लिये किया गया हो तथा सौदा होने सम कर्जदारकी ऐसीही मंशा रही हो ।

जबकि किसी सौदाके लिये यह कहा जावे कि वह इस दफ्तेके अन्तर्गत आता है तो इस बानके ठीक तरीके समझनेके लिये यह दफ्ता आवश्यक है कि जहाँ कर्जदारने उस सौदेको गेफनीपरीमे किया है या उसकी आँखमे उसने कोई बेना लाभ उठानेकी मंशाके किया है, देखो—A I R 1923 Nag 225. यदि कोई सौदा किसी मौजदारीमे मामलेमे बचनेकी चाहसे द्वायमे आकर किया गया हो तो ऐसा सौदा स्वयं किया हुआ सादा नहीं है और वह धोखादेहीमे तर्जिह देनेका सौदा नहीं है, देखो—59 I C 576 कानूनी चारमोहीका दबाव चाहे वह शीतानीके सामनेका होवे या मौजदारीके सामनेका दबाव (Pressure) का समझा जावेगा, देखो—53 Cal. 640 आर जबकि दिवालिया कानूनी कार्रवाई होनेके समयमे कोई सौदा कर देवे तो उसे तर्जिह (Preference) न समझना चाहिये, देखो—A. I R 1924 Cal 946

यदि कोई कर्जदार नालिशमे बचनेकी चाहमे तथा अपनी दशा दूसरों पर प्रभावित न होनेके लिये किसी कर्जदारको हकमे रहन कर देवे तो ऐसे रहनको धोखादेहीसे तर्जिह देना नहीं कहा जावेगा, देखो—A I R 1923 Lah. 602. यदि किसी कर्जदारको विपक्ष मुआहिदेके अनुसार कृपा अदा किया जावे तो उसमे धोखादेहीकी तर्जिह नहीं समझी जासकती है देखो—20 I C 398 यदि कोई कर्जदार अपने किसी समाया विधेदारको उसका कर्ज जाकि उस समय नजिबुलअदा नहीं है बुझा देवे तथा उस समय कर्जदार दिवालियाकी हालतमे होवे तो ऐसी अदायगीसे देना लाभ पहुँचानेकी मंशा समझी जावेगी, देखो—55 I. C 57, A I R 1925 Nag 225

यदि सौदा करने समय कर्जदारकी दरअमल यह मंशा न रहा हो कि उसने उसके किसी कर्जदारको और कर्जदारों के मुकाबिले फायदा पहुँचे किन्तु उसकी यह मंशा रही हो कि उस सौदाके करनेमे वह स्वयं फायदा उठावेगा तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा, देखो—48 All. 427

यदि यह बात साबित हो जावे कि कर्जदारने धोखादेहीमे फायदा पहुँचानेकी मंशासे किसी इन्तकाफ (Transfer) को किया है तो कर्जदार इस बातमे लाभ नहीं उठा सकेगा कि उसने वह इन्तकाफ नकलीपनासे काया है देखो—21 C. L J. 176 इसके यह प्रष्ट है कि कर्जदारकी मंशा या नेकनापनीका कोई अथ इस दफ्तेके अनुसार किये हुए सौदों पर नहीं पड़ता है यदि कर्जदारने अपने कर्जोंकी अदायगीमे पैसापानीको कोई इन्तकाफ रक्का हा तो उसमे यह नहीं माना जावेगा कि वह इन्तकाफ खरूदा है अगर यह साबित हो जावे कि दिवालियाकी मंशा उस कर्जदारको और कर्जदारकोके मुकाबिले अधिक लाभ पहुँचानेकी रही है, देखो—A. I R. 1926 Mad 338.

एक कर्जदारने जो अपने सब बच्चोंका अदा नहीं कर सकता था अपनी मर्द कीमती जगदादको अपने कुछ कर्जदारोंके पास उनका पूरा कर्ज अदा करनेके लिये रेंडन कर दिया और कुछ कृपा नकर अपन लिये ले लिया । इस मौदेमे तीन मासके अंदर दूसरे कर्जदारोंने उसके दिवालिया कुरार दिये ज्ञानके लिये दरखास्त देदी और वह कर्जदार दिवालिया कुरार देदिया गया तो यह तथ हुआ कि वह सौदा (रेंडनाया) कुछ कर्जदारोंको दूसरे कर्जदारोंकोके मुकाबिले

छात्र पट्टचानेकी मंशसि किया गया था और इसीछिये मसूख छिये जाने लायक है, देखो — 13 I. C 68. यदि कोई कर्जदार अपने पुराने कर्जदारोंमें कुछ और कर्ज लिया चाहता हो परन्तु वह कर्जस्वाह अपने पिछले कर्जोंके लिये समान रूपमें बिना दूसरा कर्ज देनेको तीसरा न होने और इस पर वह कर्जदार अपनी जायदाद पिछले कर्जोंके सम्बन्धमें उसके पास रहन कर देवे तो इसे धोखादेहीसे तर्जिह देना (Fraudulent preference) नहीं कहेंगे क्योंकि उसको बहुत अशुद्ध धी, देखो — A. I. R. 1924 Lah. 686.

इसी प्रकार यदि कोई कर्जदार घुसीपतमें पड़ा हो और उसकी कुछ और कर्जोंके लेनेकी आवश्यकता हो तथा उसका कोई कर्जस्वाह अपने पिछले कर्जों व इस नये कर्जके सम्बन्धमें उसकी जायदाद रहन का लेवे तो ऐसे सोदेको धोखादेहीसे तर्जिह (Fraudulent preference) देना नहीं सम्भवता चाहिये, देखो — A. I. R. 1920 Lah 291.

यदि कर्जदारने जायदादकी नीलामसे बचानेके लिये कर्जस्वाहके हकमें रहननामा कर दिया हो व हक बाद वह दिवालियेकी दारुलात देवे तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि धोखादेहीसे तर्जिह दी गई है, देखो — A. I. R. 1929 Lah. 159 यदि किसी दिवालियेके लिखाफ डिक्ली हो गई हो तो रिसीवर पर उसकी जाबदारी लाजिमी नहीं है क्योंकि घमकिन है वह डिक्ली कर्जदारने मिल कर कर्जगी होने या कर्जदारको इस बातकी कोई परवाह ही न होने कि उस पर चाहे जितनेकी डिक्ली हो जाने, देखो — A. I. R. 1925 All. 33. यदि रजामन्दीसे कोई डिक्ली कराई गई हो तो उसकी भी जाबदारी लाजिमी नहीं है और अदालत दिवालियाकी अधिकार है कि वह उस डिक्लीके ठीक होने की बात निश्चिन कर सके और यदि ऐसी डिक्ली इन दफ्तेके अनुसार रह कर दी जावे तो अदालतको चाहिये कि इस प्रश्न पर विचार करे कि कर्जदारकी असल मशा उस समय क्या थी देखो — 93 I. C 331. जबकि कोई सौदा धोखादेहीसे तर्जिह (Fraudulent preference) देना समित होनेके कारण रह करार दे दिया जावे तो रिसीवरको अधिकार होगा कि वह अधिक दिया हुआ बचता उस व्यक्तिसे वसूल कर लेव जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो ।

इसी प्रकार यदि उस व्यक्तिने जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो कोई बचता दूरअसल अदा किया हो तो उस सोदेकी मसूखी पर वह अपना बचता बापिस पानेका अधिकारी है देखो — 51 I. C 720. इस दफ्तेके अनुसार किसी सोदेकी मसूख करानेकी दारुलात रिसीवर के सक्त है देखो — 52 I. C 188

इस दफ्तेके अनुसार बर्खास्त चाद करनेमें पहिले रिसीवरको अधिकार है कि वह कर्जोंके सम्बन्धमें उस कर्जस्वाहसे बचता जमा कर लेवे जो उस सोदेकी मसूख करानेके लिये कहता हो और यदि अदालत दिवालिया इसे मजूर न करे तो वह अदालत जरीलमें इस मामलेको ले जासकता है । देखो — 47 Mad. 673 यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो तो कर्जस्वाहकी अधिकार है कि वह इस दफ्तेके अनुसार किसी सोदेके मसूख कर सकना है देखो — A. I. R. 1925 Nag. 225. जिसके हकमें मसूख कराया जाने वाला सौदा किया गया हो उन व्यक्तियों ऐसे मामलोंमें फरीक झकड़ना अवश्य बनाना चाहिये देखो — 52 I. C 761. यदि कोई सौदा दिवालियेकी दारुलात गुजरनेसे कुछही पहिले किया गया हो तो उससे यह शक अवश्य होता है कि वह सौदा धोखादेहीसे किसी कर्जस्वाहकी छात्र पट्टचानेकी मशाने किया गया होगा परन्तु इस बातको निश्चित करनेके लिये कि आपा दिवालियेकी दारुलात की क्या मशा थी सभी मौजूदा बातों पर ध्यान करना चाहिये अर्थात् केवल शकहींसे यह न मान लेना चाहिये कि वह सौदा इस दफ्तेके अनुसार रह है जब तक कि यह मशी साति न हो जावे कि कर्जदारने बेना कायदा पट्टचानेकी मशासे उस सोदेको किया है देखो — A. I. R. 1924 Rangoon 308

इस दफ्तेके अनुसार बर्खास्त सरसरी की बर्खास्त नहीं है परन्तु इस दफ्तेके अनुसार बर्खास्त उस समय की जाना चाहिये जबकि उस व्यक्तिने जिसके हकमें सौदा किया गया हो पूरा मौका जवाबदेहीका दे दिया जावे तथा इसक परचा

समझ वृक्ष कर हुनद दिया जाना चाहिये देखो—A I R 1922 Lah 214 अर्थात् इस दफाके अनुसार कार्यवाई उसा प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार कि दीवानीना मुकदमा तय किया जाता है और रिडीवरका मुद्दकी इमियतसे मामला साबित करना चाहिये तब सब मामला समझ कर अदालतकी फैसला देना चाहिये ।

जबकि कोई सोदा धात्वादेहीत तर्वाह देनेकी बिना पर रद कथया जानेमो होवे तो बार सुवृत् रिडीवर पर या उस व्यक्ति पर हागा जो उस सोदेकी रद कथना चाहे देखो—53 I C. 692, 21 C. L. J 167; A. I R 1924 Lah 686, A I. R. 1928 Rang 166, A I R 1929 Lah 159.

यदि दिवालिघेने किसी कर्जखवाहकी घोख्वादेहीसे बेना कायदा पहुचानेका मशामे कुछ अदायगीकी हो तो या पाहिले रिडीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह इस बातकी साबित करे कि इस मशआमे वह अदायगीकी गई है परन्तु यदि वह अदायगा दिवालिघा इमसे कुछही पहिलेकी गई हो और दिवालिघा इमके लिये कोई खास अबाब न दमके तो जहिरा यह मान लिया जावेगा कि घोख्वादेहीस बेना कायदा पहुचानेकी मशआसे वह अदायगी की गई है और तब इसके बिबद्द साबित करनेके लिये बार सुवृत् दिवालिघे पर होवेगा देखो—A I R. 1926 Sindh 128. इस दफाके अनुसार फैसला होनाम पर इस प्रश्नके लिये कोई नया मुकदमा चाद नहीं रिया जासकेगा देखो—42 Mad 322, 39 All. 626, 49 All 71.

यदि कानून दिवालिघेकी दफा ५४ के अनुसार दरखास्त दी जावे तो पहिले रिडीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि काहिरा दिवालिघेने धात्वादेहीसे बेना कायदा पहुचानेकी मशामे वह सोदा रिया है परन्तु यदि निमी पिच्छे कर्जका अदायगी दिवालिघा इमसे कुछही पहिले की गई हो तो यह साबित होने पर बार सुवृत् उस कर्जखवाह पर या उस व्यक्ति पर हो जावेगा जिसके हकमें वह सोदा किया गया हो । और यदि ऐसे सदिक होनेके कारण भली भांति अदालतकी न समझाया जावे ता अदालत यही मान लेगी कि बेना कायदा पहुचाने की मशआसे वह सोदा किया गया या देखो—107 I C 210.

दफा ५४ (ए) मसूखीकी दरखास्त कौन लोग देसकते हैं

दफा ५३ के अनुसार किसी इस्तकालके मसूखीकी दरखास्त या दफा ५४ के अनुसार किसी इस्तकाल अदायगी, बार या कानूनी कार्यवाईकी मसूखीकी दरखास्त रिडीवर देसकता है अथवा अदालतकी आज्ञा लेन पर वह कर्जखवाहभी देसकता है जिसने अपना कर्ज साबित कर दिया हो और जो अदालतकी इस बातका विश्वास दिलावे कि रिडीवरसे ऐसी दरखास्त देनेके लिये कहा जाचुका है परन्तु वह इसके देनसे इन्कार करता है ।

व्याख्या—

यह दफा निम्नलिखित है और सन १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बढ़ाई गई है यह संशोधित एक्ट “ The Amending Act of 1926 (XXXIX of 1926) कहलाता है । यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें कि यह प्रश्न ठाक तौरसे तय हो जाव कि आया कोई कर्जखवाह किसी सोदेकी मसूखीके लिये दरखास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है या नहीं यों तो पिच्छी नज्जोमें यह तय किया जाचुका है कि यदि रिडीवर निपुत्त न रिया गया हो वा कर्जखवाह किसी सोदेकी मसूखीके लिये अदालतमें दरखास्त दे सकता है देना—A I. R. 1925 Nag. 225; A I R. 1924 Nag. 361. परन्तु इस दफामें साफ तौरसे कर्जखवाहोंकी भी मसूखीकी दरखास्त देना अधिकार दिया गया है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कर्जखवाह ठाक उस आज्ञाशु साथ एमा दरखास्त

नहीं दे सकते हैं जसा कि रिसीवर कमें कि जर्ज ग्रामे उमरवार देगे पक्षिक नचि दी हुई देखो शर्तों में पुन होना चाहिये ।
(१) यह कि कर्जदार अदायगी इमारा २० ॥ दरखास्त दे सकता है, दूसरे (२) यह कि कर्जदार को चाहिये कि वह अदायगी इस बानका इच्छात दिनादि कि सितावने ऐसी दाखलास्त देनेके लिये कहा गया था परन्तु उसने दाखलास्त देनेसे इनकार कर दिया है । इसका कारण यह है कि रिसीवर को हर समय मसूखानी दाखलास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है परन्तु कर्जदार उसी समय दाखलास्त दे सकता जबकि रिसीवर ऐसी दाखलास्त देनेसे इनकार कर देने तथा अदायगी भी आता इसके लिये मिल जाने अथवा नहीं ।

47 Mad 073. में यह बतलाया गया है कि यदि रिसीवरने किसी सौदेकी मसूख कानूने लिये कहा जाने तो समस्त कर्तव्य है कि पहले वह करने आयेत यह सुगठे कि वह अपने दायित्व का सुबूत रखना है उक्त पक्षका कर्जदारको नाम मंजित निवाडे इमसे यह उस दरखास्ताका विरोध कर सके तब यदि रिसीवरने समझ पड़े कि दरअसल कोई सौदा भोलादेवीस किया गया है तो उसकी मसूखीके लिये अदायगी दाखलास्त देने और यदि उसे इस बातमें मसूखी न मादूम हो परन्तु कोई कर्जदार चाहे कि वह सौदा वास्तु मसूख कथा जाना चाहिये तो रिसीवर उससे पक्ष कायिक कराने वह बतानी मसूखीके लिये तब अदायगत बदे । अदायत दिवालियावा भी यह कर्तव्य मादूम होता है कि वह केवल मसूखानी दाखलास्तों को लेही न लेवे किन्तु उन पर न्याय पूर्वक विचार करे जहाँ यदि अदालतके सामने कोई मसूखीका प्रश्न उपस्थित किया जावे ता वन पर उस विचार करना चाहिये चाहे वह प्रश्न सितावर द्वारा उपस्थित किया गया हो अथवा उसे कोई कलखला उपस्थित करे । अदालत स्वयम् ऐसा प्रश्न सामने उपस्थित हो जाने पर विचार कर सकती है देखो—A. I. R. 1924 Nag 361.

दफा ५५ नेकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी रक्षा

इस एकटमें अबतक दिये हुए इजराय सम्बन्धी दिवाल परके असरको ध्यान रखते हुए तथा उन इन्तकालात व सरजीहातको ध्यानमें रखते हुए जो मसूख किये जासकते हैं और कोई यात दिवालके सम्बन्धमें नीच दिये हुए कामको रद्द नहीं कर सकेंगी ।

(ए) अगर दिवालिया किसी कर्जदारको कोई अदायगी करे ।

(बी) अगर दिवालियाको कोई अदायगी या सुपुर्दगी कीजावे ।

(सी) अगर दिवालिया काफी मुआविजा लेकर कोई इन्तकाल ('Transfer') करे ।

(डी) अगर दिवालियाके साथ कोई मुआहिदा या व्योहार काफी मुआविजेके पक्षमें किया जावे ।

परन्तु यह उसी वक्त ठीक होगा जबकि यह इन्तकालात दिवालिया द्वारा दिये जाने वाले हुएमसे पहिले किये गये हों और जिम शरुसके साथ यह सौदे हुए हों जिते सौदाके समय नहीं मालूम रहा हो कि कर्जदारने कोई दिवालिकी दाखलास्तदी है या उसके खिलाफ कोई ऐसी दाखलास्त दी गई है ।

व्याख्या—

इस एकटमें उन सौदोंमें उल्लेख है जो इस एकटके अनुसार रद्द नहीं किये जाना चाहिये । इस दफाके भाग (१), (बी), (सी) व (डा) में उन सौदोंकी दिवालिया गया है परन्तु साथही साथ यहभी बतला दिया गया है कि यह सौदे

उसी समय रद्द नहीं किये जासकेंगे जब कि नीचे दिये गये होती हों तथा वह पीछे नतलाये हुए किसी कानूनके अन्तर न आती हो अर्थात् इस एक्टकी दफा ५१, ५२, ५३, व ५४ के अनुसार जो सौदे रद्द हो सकते हैं वह यदि ब्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) के अन्तरभी आते हों तो भी वह गृह किये जासकते हैं ।

इसी प्रकार इन श्रांतिमें नतलाये हुए सौदे उसी समय रद्द होनेसे नच सकेंगे जबकि वह सौदे दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होनेसे पहिले किये गये हों तथा जिसके हकमें वह सौदे किये गये हों उसको उस वक्त तक इस बातका श्म न होने कि जो व्यक्ति सौदा कर रहा है उसने दिवालियेरी दारुप्राप्त देदी है वा उसके विरुद्ध किसी और ने दिवालियेकी दारुप्राप्त देदी है । यह दफा एक प्रकारसे नेक्नीयासे किये हुए सौदोंकी रखाकिये बनाई गई है अर्थात् इससे दिवालियेके कर्मदार व उसके कर्मचारि दोनोंकी रक्षा होती है यदि कोई सौदा नेक्नीयासे किया गया हो ।

कलाज़ (ए) में उन अदायगीकी बचतका उल्लेख है जो दिवालिया अपने किसी कर्मचारीको करे व बलात् (बी) में उन अदायगीकी बचतका उल्लेख है जो दिवालियेका कोई कर्मदार उसे करे । इसी प्रकार बलाज (सी) व (डी) में उन शीरो व इन्तकामातका उल्लेख है जो काफ़ी घुआविता (Valuable Consideration) लेकर दिवालिये द्वारा या उसके हकमें किये गये हों । परन्तु इन बलात्तोंकी देखते पहिले यह बतला दिया गया है कि इस दफासे पहिले जो नर्त बतलाई जाचुरी है उनकी अवहेलना नहीं की जावेगी अर्थात् उन सबका ध्यान रखते हुए ही इस दफाके अनुसार कार्यवाई हो सकेगी । इस एक्टकी दफा ५१ व ५२ में यह बतलाया गया है कि इनका पर दिवालियेकी कार्यवाईका क्या प्रभाव पड़ेगा तथा दफा ५३ व ५४ में यह बतलाया गया है कि कौन कौनसे सौदे व इतकालात् रद्द होंगे या रद्द किये जासकेंगे । इस प्रकार दफा ५१, ५२, ५३ व ५४ का ध्यान रखते हुए ही इस दफाके ब्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) में नतलाये हुए सौदोंकी बचत हो सकेगी और साथही साथ उन शर्तोंकी पूर्ति भी आवश्यकता है जो इस दफाके अन्तमें बतलाई गई है तथा जिसका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले सौदा होना तथा सौदा करने वाले व्यक्तिको सौदा होनेके समय दिवालियेकी कार्यवाई होनेसे श्म न होना इन दोनों शर्तोंकी भी पूर्ति होना चाहिये ।

यदि दिवालियेने कोई इन्तकाम जायदाद अपनी बीबीके हकमें उसके मरनेके पूर्वसमय कानून मोहम्मदी (Mohammed Law) के अनुसार कर दिया हो तो ऐसे इन्तकामकी रक्षा ब्राज (सी) के अनुसार हो सकती है । देखो—43 I. C. 280.

यदि इस्लामीने कर्मदारकी जायदादने दिया रसरीके हिसाबसे बांटेनेके लिये ले लिया हो तो ऐसे काफ़ी घुआविता समझना चाहिये तथा इस इन्तकामकी रक्षाकी जाचकती है, देखो—43 I. C. 602.

इस बातका भी भली भांति ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी सौदे इस दफाके अनुसार रक्षाके पात्र होंगे जो दिवालिये करार दिये जानेसे पहिले किये जाचुके हों अर्थात् दिवालिया करार दिये जानके पश्चात् यदि कोई सौदे हुए हों तो उनकी रक्षा इस दफाके अनुसार नहीं हो सकेगी, देखो—A. I. R. 1921 Bom 49.

जायदादका वसूल करना

दफा ५६ रिसीवरकी नियुक्ति

(१) अज्ञातको अधिकार है कि वह दिवालिया करार देते समय, उसके पश्चात् किसी समय दिवालियेकी जायदादके लिये रिसीवर मुक़रर करदे और उसके बाद वह जायदाद रिसीवर को मिलेगी ।

(२) नियत किये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको अधिकार है कि वह:—

[ए] रिसीवरसे उस कदर जमानत दाखिल करनेकी कहे जो उसे मुनासिब समझ पड़े इस चास्ते कि वह जायदादके सम्बन्धमें जो पवित्रता उसका हिसाब देगा ।

[बी] इस बातका आग्रह या खास हुक्म देवे कि रिसीवरको दिवालियेके लहनेसे कितना मतालवा उसके काम करनेके पवजमें उसे बतौर उज़रतके मिलेगा ।

(३) जबकि रिसीवर नियुक्त किया जावे तो अदालतको अधिकार है कि अगर जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिकी देखरेख या कब्ज़में होवे तो उस शख्सको हटा देवे। परन्तु इस एक्टके अनुसार अदालतको ऐसे शख्सको क़ब्ज़े या हिफ़ाज़तसे हटानेका इ़तिफ़ाअ न होगा जिसे हटानेका मौजूदा अधिकार दिवालियेको नहीं है ।

(४) जबकि इस दफ़ाके अनुसार नियुक्त किया हुआ रिसीवर:—

[ए] अपना हिसाब नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए ढंग पर दाखिल नहीं करे, या

[बी] अदालतके हुक्मके मुबाफ़िक़ बचा हुआ रुपया अदा नहीं करे, या

[सी] यह जानते हुए अपनी मालतीसे या बड़ी लापरवाहीसे जायदादको नुक़सान पहुँचता हो ।

तो अदालतको अधिकार है कि उसकी जायदादको कुर्क य नीलाम करादे और उस नीलामके रुपयेसे उस नुक़सानकी पूर्ति करे जो उसकी बजहसे हुआ है या उस वक़्तमें मुजरे से जो उसके पास रही है ।

(५) इस दफ़ामें दिये हुए नियम दफ़ा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दरमिथानी (Interim) रिसीवरके लियेभी लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफ़ाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया करार दिये जानेके फ़ैवाज़ अदालत दिवालियेकी सब जायदाद पर क़ब्ज़ा के लिये जिसके बिना उसके क़र्ज़दारोंमें हिस्सा रमदीके हिस्सामें बाँटी जासके और चूँकि अदालतके लिये स्वयं इस प्रकारका काम करना कठिन है इस कारण रिसीवरकी नियुक्ति कम रख दिया गया है । दफ़ा २० के अनुसार दिवालियेके जायदादकी रक्षाके लिये दरमिथानी (Interim) रिसीवर का नियुक्त किया जाना बनवाया गया है जो कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है । परन्तु इस दफ़ाके अनुसार रिसीवरकी नियुक्ति बाद दिवालिया करार दिये जानेके होगी तथा वह दिवालियेकी जायदादकी वसूल करने तथा उसके क़र्ज़दारोंमें हिस्सा रमदीके हिस्सामें बाँटनेके लिये नियुक्त किया जावेगा । रिसीवरकी नियुक्ति करनेमें अदालतको भी अधिकार प्राप्त है तथा उसकी नियुक्ति होनेके फ़ैवाज़ अदालतकी उसके क़र्ज़में हस्तक्षेप करनेके जो अधिकार प्राप्त है उनका उज़ल भी इस दफ़ामें किया गया है साथ साथ यह भी बनवाया गया है कि दरमिथानी (Interim) रिसीवरके लिये भी इस दफ़ामें बनलये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा जब तक कि उनका इन नियमोंसे सम्बन्ध न हो ।

उपदफा (१) रिश्वर, दिवालिया करार दिये जाने। हुकम होते समय या उसके पश्चात् हम उपदफाके अनुसार नियुक्त किया जा सकता है यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमको ७ साल का गय हो तो हम देखेंगे जनेहीके कारण रिश्वरकी नियुक्ति केनार नहीं किया जायगा अर्थात् हम समयकी दिवालियेकी जायदादके लिये आवश्यकता पड़ने पर रिश्वर नियुक्त किया जासकेगा देखो—A I R 1924 Cal. 849 ऐसा प्रगट होता है कि दिवालियेकी जायदादके कुछ हिस्सेकी के लिये रिश्वर नियुक्त नहीं किया जा सकता है अर्थात् रिश्वरकी नियुक्ति दिवालियेकी सन जायदादके लियेही होनी चाहिये उनके जुन हिस्सेकी के लिये नहीं देखो—A I. R. 1925 Rang 224.

अबकि रिश्वरकी नियुक्ति न की गई हो तो दिवालियेकी सन जायदाद दफा २८ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके समयसे अदालतकी समझा जावेगी अतः यदि रिश्वरकी नियुक्ति दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमके पश्चात् की जावे तो पहिले दिवालियेकी जायदाद अदालतकी होगी उसके पश्चात् रिश्वरकी नियुक्ति होने पर वह जायदाद अदालतसे रिश्वरकी समझा जावेगी ।

इस दफामें यह नहीं बताया गया है कि कौन व किस प्रकारका व्यक्ति रिश्वर नियुक्त किया जाना चाहिये । देखो—39 All. 159 में यह तय हुआ था कि बर्जम्बाहमें से कोई व्यक्ति रिश्वर नियुक्त किया जा सकता है परन्तु इसके पश्चात् देखो—L R 3 A. 85 में यह तय किया गया कि अदालतकी चाहिये कि वह दिवालियेके किसी वक्ताकी उसकी जायदाद वस्तु सर्वेक्षित लिये रिश्वर नियुक्त न रहे ।

यदि रिश्वरके बर्जियोंको करनेके लिये कानूनी योग्यताकी आवश्यकता है अतः वह उचित प्रतीत होता है कि कोई कानूनी योग्यता रखने वाला व्यक्ति रिश्वर नियुक्त किया जावे देखो—50 L. C. 117. रिश्वरकी नियुक्ति तथा उनका इशारा जाता देखो बान् अदालत पर निर्भर है अर्थात् दोनोंका अधिकार अदालतकी प्राप्ति है देखो—46 Mad. 405, A. I. R. 1923 Mad. 355

रिश्वरको अदालत नहीं समझता चाहिये किन्तु वह अदालतका एक अङ्ग है जिसके द्वारा अदालत दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा रखती है तथा उस पर अपने अधिकारका प्रयोग करती है देखो—42 IC 799 अदालत अपने कानूनी अधिकार (अर्थात् पैसला करनेके अधिकार) रिश्वरको नहीं दे सकती है किन्तु आवश्यकतानुसार वह रिश्वरको किसी मामलेका तहकीकात छुट्टी कर सकती है जिसमें रिश्वर बाद तहकीकात अपनी प्रिपर्टी अदालतके सामने पेश कर सके । प्राप्ति काय कामके लिये रिश्वरकी प्रिपर्टी बनाए जाइएके समझी जावेगी देखो दफा ३२ (२) तथा ३८ (३) 86 L. C 908.

दिवालियेके रिश्वर तथा दीवानोंके और मामलोंमें नियुक्त किये हुए रिश्वरके अधिकार एक्ट में नहीं हैं किन्तु उन दोनोंकी शक्तमें अंतर है देखो—A I R 1924 Pat 259, A. I R. 1924 All. 40 जिसमें कि यह बताया गया है कि जबकि दीवानोंके अनुसार किसी जायदादके लिये नियुक्त किया हुआ रिश्वर उस जायदाद पर अदालतकी तरफसे कब्जा रखता है । वह जायदाद उसकी नहीं हो जाती है और न वह उस जायदादका किसी प्रकार प्रतिनिधित्व है और यदि उसके फीक मुकद्दमा बनाए जायदाद पर पबलीक कानून हो तो अदालतकी आज्ञासे वह फीक मुकद्दमा इसके लिये बताया जाया चाहिये । परन्तु कानून दिवालियाके अनुसार जो रिश्वर नियुक्त किया जाता है वह उसके निष्कर्षोंके विषय है वह बस अदालतका अङ्ग नहीं है किन्तु दिवालियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और वह उस जायदादका प्रतिनिधि हो जाता है और सभी कारण यदि दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई मुकद्दमा चलाया जावे तो उसे अवश्य फीक मुकद्दमा बताया जाना चाहिये और उसका फीक मुकद्दमा बनाते समय अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है । इस एक्टके अनुसार रिश्वर नियुक्त किये जातेही दिवालियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि अदालत आज्ञा देने कि दिवालियेकी जायदाद रिश्वरकी हो गई है । मगर हाईकोर्टने यह तय किया है कि दिवालिया

प्रकार दिये जानेका हुक्म होतेही दिवालियेकी जायदाद आफिशल रितीवारकी नहीं हो जावेगी किन्तु इस दफ्तरके अनुसार उसे रितीवार नियुक्त करनेका हुक्म दिया जाना चाहिये अर्थात् दूसरे शब्दोंमें जायदादकी सुपुर्दगीका हुक्मही जाना चाहिये और बिना इसके वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य नहीं कर सकता है देखो—47 Mad. 462, A. I. R. 1924 Mad. 461.

इस कारण यदि ऐसी नियुक्तिका हुक्म न दिया गया हो तो आफिशल रितीवारसे खर्च देने वालका ठीक हुक्म जायदादमें नहीं पहुँचेगा देखो—A. I. R. 1927 Mad. 1 यदि इस प्रकारका हुक्म होनेसे पहिले आफिशल रितीवार किसी जायदादकी बेंच देवे तो बेंचनेके बाद भी ऐसा हुक्म दिया जासकता है तथा उस हुक्मके होने पर वह सौदा ठीक समझा जासकेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad. 249

जबसे कि दिवालियेकी जायदाद रितीवारकी सुपुर्दगीमें आनाभरी है वह उस दिवालियेके कर्जदारोंका एक प्रकारसे प्रतिनिधि हो जाता है और उसको चाहिये कि वह उनके हकोंकी रक्षा हर प्रकारसे करे। और यदि वह किसी मामलेकी उनके लाभके लिये बाध करेगा अवश्यक न समझे परन्तु कोई बर्जएवाह यह चाहता हो कि मामला अवश्य चालू किया जावे तो रितीवारकी चाहिये कि वह उस बर्जएवाहसे मुकद्दमोंके खर्चके लिये इत्तमीनान कर लेनेके बाद उस मामलेकी बाध कर देवे देखो—38 I. C 271.

उपधका (२)—रितीवारके सम्बन्धमें जो नियम ॥१॥ एक्टके लिये बनाये गये हैं उनका मानना आवश्यक है उन नियमोंका पालन करते हुए अदालतकी अधिकार है कि वह रितीवारसे जमानतकी लेलेवे जिसमें कि वह उस जायदादके सम्बन्धमें हिसाब दाखिल करा सके जोकि रितीवारके क़ाबज़में आई हो तथा अदालतका यह भी अधिकार है कि वह दिवालियेकी जायदादमेंसे रितीवारकी उसके काम करनेके हकमें कुछ क़यास मंतर उमरतके दिलवालेका हुक्म देदेवे। यदि अदालत जमानतकी शर्तके माफ रितीवार नियुक्त करनेका हुक्म देवे तो जब तक जमानत दाखिल न हो जावे रितीवारकी नियुक्ति पूरी रूपसे न समझना चाहिये और यदि रितीवार अदालतके हुक्मके अनुसार जमानत देदेवे तो उसकी नियुक्ति उस तारीखसे मानी जावेगी जबसे कि अदालतका हुक्म उसकी नियुक्तिके लिये हुआ है। और यदि अदालतके हुक्ममें जमानतके सम्बन्धमें कोई जिक्र न हो तो रितीवारकी नियुक्ति उसी तारीखसे पूरी मामली जावेगी।

रितीवारके श्रमफल (Remuneration) के बारेमें निश्चित करना अदालतका कर्तव्य है चाहे वह इसे अपने आप हुक्म द्वारा निर्धारित कर देवे अथवा वह इसके बारेमें कोई खास हुक्म कर देवे। इससे यह प्रगट है कि रितीवार एक प्रकारसे अदालतका अनुचर है और वह किसी दूसरे व्यक्ति अपना श्रमफल पानेका अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अदालतकी आज्ञा लिये बिना रितीवारकी उसका श्रमफल देनेका वादा कर देवे तो यह एक प्रकारसे बदा अनुचित कार्य होगा और इस प्रकारका समझौता करने वाले व्यक्ति अदालतका अपमान करनेके भागी होंगे देखो—22 Cal 648.

फ़ीस श्रमफल (Honorarium)—कितना होना चाहिये इस बातकी अदालतही तय करेगी। बहुधा यह श्रमफल सेरबा पीछे या कमीशनके तौर पर तय किया जाता है परन्तु अदालतकी अधिकार है कि वह इसके बजाय माहवारी बेंचनके रूपमें भी यह श्रमफल दिलवा देवे यह क़यास दिवालियेकी जायदादकी से दिलवाया जावेगा और दिवालियेके उत्तराधिकारी आता तीसरे इसके अदा करनेके जिम्मेदार नहीं हो सकेंगे देखो—26 I. C 583 जायदादके सब नफ़े (Charges) को चुकानेके पत्रचालू जो ज़ासता (Assets) रितीवारके पास रहेगा उस पर रितीवारके कमीशन या श्रमफलका भार रहेगा।

यदि रितीवारने दिवालियेकी जायदादकी वसूल किया हो तो वह उससे अपना कमीशन पानेका हकदार हो जावेगा और यदि दिवालिया क़ार दिये जावे बाधा हुक्म मसूखगी कर दिशा जावे तो भी वह अपना कमीशन पानेका हकदार बरा रहेगा देखो—8 Mad. 79

बनई हाईकोर्टके अनुसार रितीवरका कर्षाशन ५) रूपया बैंकसे अधिक नहीं नियत किया जाना चाहिये तथा यह कमीशन उन रूपयोंके अनुसार मिलना चाहिये जो बतौर हिस्सा रखनेके बाद जाने वाला होवे, देखो—A. I. R. 1925 Bom 172. रैतकी हुई जायदादमें रितीवरकी कमीशन उहाँ रूपयोंके अनुसार मिल सकेगा जो रैतके बारको निशान देनेके बाद बच पूरा जायदादकी कीमतके अनुसार नहीं मिलेगा, देखो—12 Bom. 272, 21 All 227, 36 Cal. 990, A. I. R. 1925 Nag 150, A. I. R. 1928 Rang. 23.

उपदफा (३)—इस उपदफाके अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह रितीवरकी नियुक्तिके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिके अधिकारमें होवे तो उसे उस व्यक्तिके अधिकारसे लेके परन्तु ऐसी जायदाद उसी व्यक्तिसे छुड़ाई जासकेगी जिससे कि दिवालिया स्वयं छुड़ा सकता हो अथवा नहीं इस बातके अनुसार जायदाद उस व्यक्तिसे कब्जेसे नहीं छुड़ाई जासकती है जो दिवालियेके कब्जा पतालिपतना (Adverse possession) रखता हो या जो बिना अदालती कार्यवाईके दिवालियेका भारी नहीं हटाया जासकता है, देखो—46 L. C. 377, 49 Mad. 762 यदि किसी व्यक्तिका कब्जा जायदाद पर किसी इतकाल जायदाद (Transfer) के जरिये हुआ हो और चाहे वह इतकाल दफा ५४ के अनुसार कबिल मसूली होवे तो भी ऐसे व्यक्तिमें जायदादका कब्जा इस उपदफाके अनुसार नहीं किया जासकता है, अब तक कि वह इतकाल रद्द न कर दिया जावे, देखो—A. I. R. 1925 Rang 224 इस उपदफाके अनुसार कार्यवाई करते समय अदालतको चाहिये कि दीवानाके माफकारी तरह समझ बूझ पर कार्यवाई करे और माफलेकी बाकायदा सुने जैसे कि दीवानाके मामले होने जाते हैं, देखो—37 All 65

इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कोई स्थाई रितीवर नियुक्त कर देवे अर्थात् इन्टरिया (Interim) रितीवरकी नियुक्त न बना रहने दे, देखो—A. I. R. 1926 Pat 291 यदि दिवालिया क्रयार दिये जानेके बाद तथा रितीवर नियुक्त किये जानेके बाद दिवालियेकी कोई जायदाद इनकारमें बँच दी गई हो तो रितीवरको अधिकार है कि वह ऐसे नीतिमयी मसूली तथा बँची हुई जायदाद पर कब्जा लेनेकी दरपवाशन इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियेकी दे सके, देखो—44 Mad. 524.

॥ उपदफाके अनुसार केवल रितीवर ही दाखलास्त नहीं दे सकता है किन्तु वह व्यक्ति भी दे सकता है जिसने रितीवरसे जायदादकी खरीदना इति, देखो—45 Mad 434, A. I. R. 1922 Mad. 147. यदि इस उपदफामें दी हुई शर्त (Proviso) का ध्यान न रखते हुए अदालत कोई फैसला कर देवे तो उस फैसलेके फौकैनके इक पूरा रूपसे निश्चित किये हुए नहीं माने जायेंगे, देखो—49 Mad. 762 अर्थात् जो अदालतको दफा ४ के अनुसार किसी एकको तय करनेका अधिकार प्राप्त हो, परन्तु इस उपदफा की शर्त (Proviso) उसमें बाधक पड़ती हो तो अदालतको दफा ४ के अनुसार कार्यवाई नहीं करना चाहिये । और इसी कारण ऐसे प्रयत्नोंको इल करना एक प्रयास अदालत दिवालियाके लिये समय नष्ट करता है और उसे चाहिये कि वह ऐसे प्रयत्नोंको नगरे नालिशमें तय होने देवे देखो—A. I. R. 1924 Mad. 387. इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि रितीवरको किस विधायके अन्दर कब्जा ले लेना चाहिये अर्थात् रितीवर दिवालियेकी कार्यवाईके दौरानमें किसी समय भी कब्जा प्राप्त कर सकता है ।

उपदफा (४) इस उपदफाके अनुसार अदालतको रितीवरके कार्योंमें हस्तक्षेप करने तथा उससे इना आदि वसूल करनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् अदालत आवश्यकताप्रकार रितीवरके उचित दण्ड दे सकती है इस उपदफामें रितीवर द्वारा की जाने वाली सब गलतियाँ नहीं दिखाई गई हैं केवल याचकी घानियोंके उल्लेख क्रम (ए), (बी) व (सी) में कर दिया गया है और न इस उपदफामें उन सब सम्पत्तियोंकी वर्णन है जो रितीवरका उसकी प्रशक्तियोंके धाम्य दी जासकती है क्योंकि इनमें सिर्फ रितीवरकी जायदादको वर्णन करने तथा उसमें उससे हुज्जती पूर्ण करनेकी का शिष्ट

है। जब अदालत रिसीवरको नियुक्त कर सकता है तो उसे उससे इत्यनेन भी अधिकार अवश्य प्राप्त सम्पत्ति चाहिये। इस प्रकार जिस प्रकार की भूमि रिसीवर के पास आती है उस प्रकार का दण्ड पाने का भागी होगा। इस उपद्रव में यह नहीं बनना या गया है कि रिसीवरकी गलतियाँ अदालतका सौन बनना सहेगा परन्तु यह बात प्रष्टही है कि अदालत यदि किसी गलतीसे दंड तो वह स्वयंही उस गलतीका पट्टा सकती है तथा उमक अनुसार रिसीवरको दण्ड दे सकती है और चूँकि रिसीवर एक पब्लिक सर्वेंट है इस कारण कोई भी व्यक्ति उसकी गलतियोंको अदालतके सामने रख सकता है। अर्थात् जिस किसी भी व्यक्ति को रिसीवरकी गलतियोंकी वजहसे हानि उठाना पड़े उसे अधिकार है कि वह रिसीवरकी उस गलतीको अदालतके सामने रख देवे जिसमें अदालत तद्वक्तानके बाद रिसीवरको उचित दंड दे सके। रिसीवरकी अदालतका एक अफसरही सम्पत्ति चाहिये वह स्वयं अदालत नहीं है और इसी कारण उसे कोई गलती काटने पर तब तक अधिकार प्राप्त नहीं है और न वह कानूनी अफसरोंकी तरह किसी मामलेकी कानूनी तद्वक्तता ही कर सकता है।

जो रिसीवर अदालत नहीं दे मन्तु उमके कार्योंमें हस्तक्षेप करनेमें अदालतकी तोहनीया हर्ष लगाया जासकता है चूँकि वह अदालतका एक प्रकारका एजेंट है इस कारण उमके कार्योंमें कडावट डालना या हस्तक्षेप करना एक प्रकारमें अदालतके हुक्मकी अवहेलना करना है और रिसीवर अदालतकी तोहनी (Contempt of Court) का हर्ष लगाया जासकता है, देखो—6 B. L. R 486, 9 1 C 485, 28 Cal 790; 26 C. L. J. 345.

उपद्रव (५) इस उपद्रवमें यह बनना गया है कि दण्ड २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दण्डियाँ रिसीवरके लिये भी वही बात लागू होंगी जो कि रिसीवरके लिये बनवाई गई है और जहाँ तक उसका तात्पर्य उनसे है।

दफा ५७ सरकारी रिसीवरोंको नियुक्त करनेके अधिकार

(१) प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह जिन लोगोंको उचित समझे किसी खास मुकदमा दंडके लिये इस एक्टके अनुसार रिसीवर बना देवे यह रिसीवर सरकारी रिसीवर (-Official Receivers) कह लायेंगे।

(२) अगर किसी अदालतकी अधिकार सीमाके लिये कोई सरकारी रिसीवर नियुक्त किया गया हो तो वह रिसीवर अदालतके रिसीवर या दरमियानी रिसीवर नियुक्त करने वाले सब हुक्मोंके अनुसार काम करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध किसी विशेष कारणवश कोई दूरी आज्ञा न दे।

(३) जो रुपया दफा ५६ (२ बी) के अनुसार सरकारी रिसीवरको उसके कामकी वजहसे मिलना चाहिये वह रुपया प्रान्तिक सरकार द्वारा निश्चित किये फंडमें जमा किया जावेगा।

(४) उस फंडसे या और किसी जगहसे सरकारी रिसीवरको उतनाही रुपया भ्रमफल के रूपमें मिलेगा जितना प्रान्तिक सरकार इस मदमें निश्चित कर देगी और उस निश्चित किये हुए रुपयेसे कुछ भी अधिक बतौर भ्रमफल (Remuneration) के सरकारी रिसीवरको न मिलेगा।

व्याख्या—

उपद्रव (१) इस दफा में सरकारी रिसीवर (Official Receiver) नियुक्त किये जानेका वर्णन है। प्रान्तिक सरकारको अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी रिसीवरको नियुक्त कर सके तथा ऐसे नियुक्त किये हुए रिसीवरकी

अधिवार सीमा भी निर्धारित कर सके । चूंकि अगोरेजी एक्ट की हम दफा १११ की नियुक्त मई में (May) शब्द प्रयोग किया गया है इससे यह प्रष्ट है कि सरकारी रिसीवर (Official Receiver) की नियुक्ति के लिये शक्ति सरकारी बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह चाहे तो नियुक्त कर सकती है और यदि न चाहे तो नियुक्त न करे ।

उपदफा (२) यदि किसी जगह के लिये सरकारी रिसीवर (Official Receiver) नियुक्त कर दिया गया हो तो अधिकतर वहाँ रिसीवर इस एक्ट की दफा २० व ५६ में बतलाने हुये रिसीवर का काम करना और बिना किसी छाप बन्दहके अदालत उन जगहोंमें आकिश्वर रिसीवरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त नहीं करेगा 46 Mad. 405. अर्थात् जिन जगहोंके लिये प्राधिकृत सरकार द्वारा आकिश्वर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया हो तो वहाँ रिसीवर दायित्वाली रिसीवर (Interim Receiver) या रेगुलर रिसीवर (Regular Receiver) नियुक्त किया जावेगा परन्तु अदालतको अधिवार है कि यदि वह किसी खास कारणसे किसी अन्य व्यक्ति को दायित्वाली या रेगुलर रिसीवर नियुक्त किया चाहे तो नियुक्त कर सकती है । यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दिवालिवा करार दिये जानेवाले हुकम होने ही दिवालिवा की जायदाद जमाने जायदाद आकिश्वर रिसीवरकी नहीं हो जायदाद किन्तु अदालतका हुकम होने पर वह दिवालिवा की जायदाद वास्तविक और ऐसा हुकम होनेमें पहिले उसे दिवालिवा की जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य करनेवाँ अधिवार नहीं है और न वह उसकी जायदाद बैंक का जमानेवाँ ही पूरा हर वस्तुवा मन्त्रा है देखो—63 I. C. 896; 1924 Mad 461. परन्तु यदि कोई आकिश्वर रिसीवर सुपुर्दगीवा हुकम होनेमें पहिले दिवालिवा की किसी जायदादकी बैंक देखे तो अदालत द्वारा दिये हुए बादके हुकममें वह सीधा ठीक किया जायसकता है अर्थात् जायदाद बैंक जाने समय तो एक प्रकारसे वह इन्टरल जायदाद घटकरही है और उसमें खरीदने वालों को कोई हक नहीं पहुँचना है परन्तु यदि अदालत बादमें उसकी मंजूरी दे देवे तो वह बचतवा सीधे समझना चाहिये देखो—43 Mad 869, A. I. R. 1925 Mad. 249.

आकिश्वर रिसीवरको वह सब अधिवार प्राप्त होंगे जो दायित्वाली रिसीवर या मामूली रिसीवरको जो दफा २० या दफा ५६ के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं प्राप्त हो सकते हैं इनके अतिरिक्त 'उने वह भी विशेष अधिवार प्राप्त हो सकते हैं जिनका उल्लेख दफा ८० में किया गया है और उस दफाके अनुसार वह जो काम करेगा या हुकम देगा उसे अदालतका काम या हुकम समझा जावेगा । इन प्रकार दफा ८० के अनुसार कार्यवाई करनेके सम्बन्धमें आकिश्वर रिसीवरको एक प्रकारसे अदालतके अधिवार प्राप्त हैं परन्तु हर मामलेके लिये उसे अदालत नहीं समझना चाहिये ।

उपदफा (३) आकिश्वर रिसीवर तथा मामूली रिसीवरकी हालतमें कुछ अन्तर है । मामूली रिसीवरको बड़ी मरफट (Remuneration) मिल सकती है जो अदालत उसके लिये दफा (२) (बी) के अनुसार निर्दिष्ट करे परन्तु आकिश्वर रिसीवरके सम्बन्धमें वह मरफट (Remuneration) एक फार्ममें जमा किया जावेगा तथा वह इस फार्ममें से वहाँ नियत किया हुआ वेतन प्राप्तवेगा जो प्रान्तिक सरकार उसके लिये निर्दिष्ट कर देवेगी । अदालतकी अधिवार है कि वह किसी खास कारणके उपरिष्ठ होने पर आकिश्वर रिसीवरको हटा देवे देखो—46 Mad 405

दफा ५८ अदालतके अधिकार ज्ञान कि रिसीवर नियुक्त न किया गया हो

अधिक कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया हो, तो अदालतको वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टमें रिसीवरके लिये दिये गये हैं तथा वह उन सब अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि किसी मामलेमें रिसीवरकी नियुक्ति न की जावे तो उस समय अदालतको

स्वयं वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत जो काम रिसीवरके कोठी वहाँ रिसीवरकी हैसियतमें कोठी अर्थात् इस दफ्तरके अनुसार अदालत जो काम करेगा वह अदालतकी हैसियतमें कोठी और उनके अदान्तका कामही समझना चाहिये देखो—62 I. C. 307. जो अदालतकी इस दफ्तरके अनुसार वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं परन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि अदालत उन सब अधिकारोंका प्रयोग अवश्य करे अर्थात् अदालत जिन अधिकारोंका प्रयोग किया चाहे कर सकती है तथा जिन अधिकारोंका प्रयोग न किया चाहे नहीं कर सकती है। उनका प्रयोग करना न करना आवश्यकता व अवसरके अनुसार समझना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टरी इस दफ्तरमें दिये हुए (May) शर्तमें प्रकट होता है। अदालत स्वयं दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा ले सकती है तथा दूसरेकी साबित होने पर उसे छेड़ सकती व इसी प्रकार वह किसी बर्जखवाइके कदमे पर किसी इतकाफ जायदादको मसूल कर सकता है अर्थात् वह तब काम कर सकती है जो नियुक्त किया हुआ रिसीवर कर सकता है देखो—A I. R. 1923 Nag 97, 78 I. C. 140.

दफा ५९ रिसीवरके कर्तव्य व अधिकार

इस एक्टमें दिये हुये नियमोंके अनुसार रिसीवर जितनी जरूरी हो सकेगा कर्जदारकी जायदाद वसूल करेगा व उन कर्जखवाहोंमें उसे तकसीम करेगा जो पानेके मुस्तहक हैं और ऐसा करनेके लिये वह —

- (ए) दिवालियेकी सब जायदाद या उसका कोई हिस्सा बेंच सकता है।
- (बी) जो रुपया उसे मिले उसकी रसीद दे सकता है और अदालतकी स्वीकृत लेकर भीच दिये हुये सब या कोई काम कर सकता है।
- (सी) दिवालिया का रोजगार उस हद तक चालू रख सकता है जिससे कि वह सुभीतेके साथ बंद किया जासके
- (डी) दिवालियेकी जायदादके लिये मुकद्दमा या कोई अदालती कारवाई शुरू कर सकता है या उसकी जवाबदेही कर सकता है या दायर हुये मामलोंको चालू रख सकता है
- (ई) अदालत द्वारा स्वीकृत प्राप्त हुये रोजगार या कारवाईके करनेके लिये वकील या कोई दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकता है
- (एफ) दिवालियेकी जायदाद इस शर्त पर बेंच सकता है कि उसकी सीमात आयन्दा मिलेगी लेकिन जमानत या दूसरे किसमकी उन शर्तोंके साथ ऐसा करना चाहिये जो अदालत उचित समझे
- (जी) दिवालियेकी जायदाद का कोई हिस्सा रहन या गिरवी रख सकता है जिससे उसके कर्जों की आवश्यकताके लिये रुपया वसूल किया जा सके।
- (एच) कोई भगड़ा पंच फैसलेके लिये दे सकता है और निश्चित की हुई शर्तोंके अनुसार सब कर्जों दावों व जिम्मेदारियोंमें राजीनामा कर सकता है

(आई) जब कि कोई जायदाद अपनी अजीब शकल या किसी दूसरे कारणसे फौरन या फायदेके साथ बेची नहीं जा सकती हो तो उसे उसकी मौजूदा शकलमें उसकी अम्दाज लगाई हुई कीमतके अनुसार कर्जखाहमें बांट सकता है ।

न्याय—

इस दफा में रिश्वरके बतौरों तथा उनके अभियोगोंका उल्लेख किया गया है । तथा यह बतलवाया गया है कि इस एकट सम्बन्धी नियमारा ध्यान रखते हुए रिश्वरको चाहिए कि वह अन्तर्गत जन्दा दिवालियाके लहना वसूल करके उसके उन कर्त-रुनाहोंमें बाट देने जा उस लहनेरी पावक हकदार हैं । रिश्वर लहनेरा अन्दावसूल करने तथा उसरा हिस्सा रसदाक हिस्सा वस बाटनेके सम्बन्धमें उन सब बाणोंरा या उचमेंसे किया बातरा प्रयोग कर सकता है जिसरा वर्णन प्राय (९) से लेकर प्राय (आठ) तक किया गया है । परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि वह प्राय (९) व (बी) के अनुसार बर्तवाई अपनी । अनुसार कर सकता है अर्थात् इसका किया उस अदालतका आज्ञा बिना रूपम लनकी आवश्यकता नहीं है परन्तु प्राय (सा) से लेकर प्राय (आठ) तक जो बाँव था बतलाई गई है उनके बरनेके लिये उसे अदालतसे आज्ञा लेना आवश्यक है । चूँकि रिश्वर एक सम्कारी अकमर है इसलिये उसको चाहिये कि वह अदालतकी आज्ञाके अनुसार ही बर्तवाई करे अपौर जिन कामोंके लिये अदालतकी आज्ञा लेना मतलाया गया है यदि वह उन कामोंसे भिला अदालतका आज्ञा करे तो वह काम ठाक नहीं माने जावेंगे । यदि रिश्वरके विरुद्ध कोई शिकायत अदालतमें इस विषयकी की जावे कि उसने किसी बयनामके लिये मञ्जूर नहीं दा है ता रिश्वरका कर्तव्य होगा कि वह अदालतके सामने उपस्थित होवे तथा उस विषयक सम्बन्धी सब बात उक्त सामने रखे—A. I. R. 1924 Mad 147

कलाज (९) रिश्वरकी दिवालियाकी जायदाद बेचनेसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है वह उसरी सब जायदादकी या उस जायदाद क किसी हिस्सेरी बेच सकता है ।

जायदाद (Property) सन्दरी परिभाषा दफा २ (२) (बी) में दी जाचुकी है रिश्वर का यह भी कर्तव्य है कि वह दिवालियाकी जायदादकी जितना जन्दा है सक बेच देवे । चूँकि रिश्वर स्वय अशक्त नहीं है इसलिए उसके द्वारा जायदादके बेच जाने में यह तात्पर्य न समझना चाहिये कि वह जायदाद अशक्त द्वारा बेची गई है और इसी कारण रिश्वर द्वारा किये हुए बयनामके सम्बन्धमें वह नियम लागू नहीं है जो अदालत द्वारा किये हुए नीलाममें लागू होते हैं देखो—50 Mad 135. यदि रिश्वरने किना जायदादको बेचा हो या वह बयनामा रिश्वरके साक्षिपद ही दा देने मानने पूरा नहीं है जाबदा निरु रिश्वरकी चाहिये कि उसके लिये बाकायदा दस्तावेज बयनामा तहरीर कर ओर उस पर कानून के अनुसार रूपम लगाया चाहिये तथा फायदेके अनुसार उनकी राजस्वी भा रवाई जाना चाहिये । बयनामाकी अनिवार्य बेंसी करी जायगा जेसी साधारण बयनामाकी दली—46 Cal 887.

रिश्वर जायदादको बचनेके लिय उसको आम नीलाममें बेच सकता है तथा यदि वह चाहे तो उसे प्रायः तीर पर भी बेच सकता है अगर जायदादरी धुनासिब खमिन लगे देखा—60 I C 745 रिश्वरके शिवाका या हुकशकाना मामला चलाया जा सकता है जबकि उसने जायदादको इस दफाके अनुसार बचा हो देखा—27 All 670

रिश्वर द्वारा किये हुए बयनामका प्रसूतीक किया आर्डर २१ रू १० जाबदा दीवानीके अनुसार दारवास्त नहीं दी जानगी है 44 I C 883 रिश्वर स्वय भा अपने किय हुए बयनामों की मम्ता नहीं कर सकता है वरोंक उस बयनाममें उसके तथा खरीदारके दम्भियाल एक प्रकार सुआदिदा पूरा हो जाना है और उस सुआदिदका तादन या उयक विरुद्ध कस का कोई अधिकार अपने आप रिश्वर के पास नहीं रह जाता देखो—1926 M W 688.

परन्तु यदि जायदादके बँचनेमें वतलीबीकी गई हो या कोई बदलीवर्तसे काम किया गया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे बयानों को मसूल कर देने देलो—A. I. R. 1923 Mad. 350, 40 All 582.

यदि आग्रिकल रितीवरने कोई समझौता अदालतकी आज्ञा लिये बिना कर लिया हो अर्थात् किसी मामलेकी कुछ वषर पयालेक तय कर लिया हो तो इस प्रकारका समझौता रद्द नहीं समझा जावेगा और जब तक कि यह समझौता रद्द न कर दिया जावे तब तक माननीय होगा इजाजत का लेना एक इतजामी हुक्म है व उसका सम्बन्ध रितीवरसे है देखो—A. I. R. 1929 Sindh 41.

फलाज (बी) रितीवरको अधिकार है कि वह दिवाखिये का खया बमूल करके उसके लिये रसीद दे सकता है इससे तात्पर्य यह समझना चाहिये कि यदि दिवाखियेके सम्बन्धमें कोई व्यक्ति कपया देकर रितीवरसे रसीद हासिल कर लेवेतो वह रसीद पर्याप्त होगी तथा दुबारा उस व्यक्ति से इस प्रकार जदा किया हुआ कपया नहीं माया जासकेगा। जिन कार्योंका उल्लेख ज्ञाज (सी) से लेकर ज्ञाज (आई) तकमें किया गया है उन कार्योंके करनेके लिये रितीवरका कर्तव्य है कि वह अदालतकी आज्ञा प्राप्त करे।

एकदम यह कहीं भी नहीं बतलाया गया है कि अदालतकी आज्ञा किस प्रकार लेना चाहिये परन्तु यह अवश्य तय किया गया है कि इससे लिये लिखित आज्ञाके लेनेकी आवश्यकता नहीं है और न इस बातकी आवश्यकता है कि वह आज्ञा किसी खास प्रकारकी होना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Nag 156

परन्तु अदालतकी आज्ञा काम करनेसे पहिलेही छी जाना चाहिये यदि काम करनेसे पहिले अदालतकी आज्ञा न ली गई हो तो केवल इसी कारण वह काम रद्द न समझना चाहिये क्योंकि आज्ञाका लेना रितीवर तथा अदालतके बीचका काम है और कामके बादभी यदि अदालत उस कार्यके लिये अपनी स्वीकृति देदेवे तो इसे शर्की आज्ञा समझी जावेगी यदि आग्रिकल रितीवरने बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए कोई मुकदमा चालू किया हो और वह उस मुकदमेमें हार जावे तो वह उस मुकदमेका खर्च दिवाखियेकी जायदाद पर नहीं डाल सकता है देखो—45 Mad. 167.

यदि रितीवर नियुक्त किये जाने समय उसे कानूनी दफसे कियया आदि बमूल किये जानेके अधिकार प्रदान किये गये हों तो इससे यह मान लिया जावेगा कि उसे मुकदमा दायर करनेके भी अधिकार दिये गये हैं देखो—18 Cal. 477.

रितीवरका कर्तव्य है कि वह सन जरूरी मामलोंमें अदालतका आदेश लेकर काम करे देखो—19 Bom 660.

यदि जाबता दीवानोंके अनुसार किसी मामलेके लिये रितीवर नियुक्त किया गया हो तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेके लिये सबसे पहिले अदालतकी आज्ञा लेलेना आवश्यक है परन्तु यदि कोई मामलाबिना आज्ञा लिये हुए चालू कर दिया गया हो तो उसके लिये बादमें भी आज्ञाकी आवश्यकता है देखो—41 I. C. 802 दिवाखियेके मामलोंमें जो रितीवर नियुक्त किये जाते हैं वह ऊपर कहे हुए रितीवरसे कुछ भिन्न हैं और उनके विरुद्ध मामला चालू करनेमें पहिले अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—53 I. C 973, A. I. R. 1924 All 40 वगैरह दार्कनेटका मत है कि चूंकि रितीवर एक पब्लिक आफिसर (Public Officer) है और इस कारण जाबता दीवानोंकी दफा ८० के अनुसार नोटिस दिये जानेकी आवश्यकता है देखा—44 Bom.895.

यदि रितीवर किसी मुकदमेके लिये जरूरी फीज न होने तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेमें आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है जैसेकि यदि कोई जायदाद रिमावर द्वारा बँचनी गई हो और कोई व्यक्ति उस जायदाद पर अपना हक साबित करनेके लिय मुकदमा चालू करे तो ऐसे मामलेमें रितीवरकी फीज मुकदमा बनाना बहुत जरूरी नहीं है। केवल इसी बातसे कि रितावरका नाम किसी मामलेमें बहसित पृक्षाअल्लेहके आता है तथा रितावरको फीज मुकदमा बनानेके लिये आज्ञा

नहीं ली गई है वह मामला कानून आरिन होनेके नहीं है अर्थात् मामला ऐसी दशामें भी चल सकता है देखो— 41 I. C 809, 48 All. 821

कलाज (सी) रितीवारको अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञा लेने पर दिवालियेके कारोबारकी चालू रख सके परन्तु उसे व्यापार इन्होंने कारण चालू रखना चाहिये तथा उसी हद तक चालू रखना चाहिये जिसमें कि वह फायदेके साथ समर्थ जासके देखो—40 Cal. 678.

कलाज (डी) रितीवारको अदालतकी आज्ञा लेने पर मुकदमे चालू करने तथा उनकी पैरवी करने रहनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् वह दिवालियेकी आज्ञाशुद्धि सम्बन्ध रखने वाले मुकदमोंको चला सकता है । इस तौर पर इस उपद्रव के अनन्तर यदि रितीवारकी सुपुर्दगीमें किसी दिवालियेकी वह जायदाद आई हो जो अनिमित्त हिन्दू परिवारकी जायदादका आभ्यासित भाग होवे तो रितीवारको अधिकार है कि वह बन्दोबस्त मुकदमा उस जायदादके लिये दावा कर देवे देखो—A. I. R. 1923 Oudh. 154.

रितीवार उनकी मामलोंको चालू कर सकता है या चालू रख सकता है जिनका सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे अन्यथा नहीं इसलिये यदि दिवालियेके विरुद्ध किसी रूपमें दावा दावे तथा उसी बीचमें वह दिवालिया करार दे दिया गया हो तो रितीवार उस मुकदमेमें फीक मुकदमा नहीं बनाया जाना चाहिये देखो—29 I. C 30. दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलोंमें रितीवार फीक मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है और यदि रितीवारकी अल्पपरिधिमें दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई हुकम दिया जावे तो उसे पर कानूनी समझना चाहिये और अपात्रमें यदि उसे फीक मुकदमा बनानेकी कोशिशकी जावे जब कि वह शुरूमें फीक न बनाया गया हो तो इससे वह कर्तव्यहीन ठीक नहीं हो सकेगा देखो—30 I. C 703; 41 I. C 802.

कलकत्ता हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि दिवालियेके विरुद्ध बकाया क्रियिका दावा किया जावे तो उसमें रितीवारको फीक मुकदमा बनाना जरूरी नहीं है देखो—46 I. C. 395.

यदि कोई रितीवार फीक मुकदमा बनाये जानेके बाद बदल जावे तो उसकी जगह जो दूसरा रितीवार नियुक्त होगा उसे फीक मुकदमा बनाया जाना चाहिये देखो—28 Mad. 157.

यदि रितीवार किसी मुकदमेमें हार जावे तो उसे उस मुकदमेका खर्च स्वयं उस वक्त तक बरदाश्त नहीं करना पड़ेगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जावे कि उसकी बेउममावियोंकी वजहसे वह मुकदमा खराब हुआ है देखो—A. I. R. 1925 Mad 786

यदि रितीवारने किसी बर्जन्दादके बहुत जोर देने पर कोई मुकदमा चालू किया हो तो अदालत उसे कर्तव्यवाहीसे मुकदमा तत्पक्ष वसूल किये जानेका हुक्म दे सकती है देखो—46 I. C 377

इन बातके लिये निश्चित रूपसे नहीं कहा जासकता है कि रितीवार मुकदमोंमें दावा कर सकता है या नहीं परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मालूम होता है कि मुकदमोंमें वह दावा कर सकता है इन्हाबाद हाईकोर्टने यह निश्चित किया है कि यदि कोई बर्जदार मुकदमोंमें कोई दावा लड़ रहा हो और उसी बीचमें वह दिवालिया घोषित कर दिया जावे तो रितीवार उस मामलेकी मुकदमोंमें बिना कौन्सिल अर्थात् किये चालू रख सकता है देखो—16 A. L. J. 440=47 I. C. 577.

कलाज (ई) इस कानूनमें रितीवारकी वहील या दूसरे एजेण्टोंको नियुक्त करके अदालत द्वारा वतखये हुए मामलोंके बरतना अधिकार दिया गया है अर्थात् यदि रितीवार किसी कर्तव्यी स्वयं न कर सकता हो अपना उसकी देखरेख न कर सकता हो तो उस वह कर्तव्य-दूतके व्याक्तिके द्वारा कर सकता है इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस कानूनके अनुसार कर्तव्यी कर्तव्य लिये भी अदालतकी आज्ञा लेना आवश्यक है ।

लाज (पक्ष) रितीवर दिवालियेकी जायदाद हम शर्त पर भी बँच सकता है कि इसे उपाय कीमत आयदा मिलेगी परन्तु ऐसे मामलोंमें वकील नामानव आदि लेगी जाना चाहिये और हमके विषे भी अदालतकी आज्ञानुसार ही कार्य किया जाना चाहिये ।

लाज (जी) इस कानके अनुसार अदालतकी आज्ञा लेने पर रितीवर दिवालियेके कर्जोंमें बुझानेके लिये उसकी जायदादको देन कर सकता है ।

लाज (पक्ष) अदालतकी आज्ञानुसार रिताजकी दिवालियेके समझमें तमझिया करनेका भी अधिकार प्राप्त है और इस हानमें उसके हमी अधिकारोंका उद्देश है ।

लाज (झाई) इस कानके यह बतलाया गया है कि यदि दिवालियेकी कोई जायदाद बेची न जासके या उसके बेचनेमें मुकसान होता हो तो अदालतकी आज्ञा लेकर गिम्बर उम जायदादकी कीमतका अन्दाजा लगा कर उसे दिवालियेके कर्जपवाहोंको उनके कर्जोंके अनुसार बाट मंगेगा ।

धारा ५९ (ए) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्शाप्त करनेके अधिकार

(१) यदि प्रान्तिक सरकार किसी अदालतकी या अदालतके किसी हाकिमको अपनी मन्शा द्वारा स्पष्ट औरसे अधिकार देवे तो वह अदालत या हाकिम किसीपर या किसी ऐसे उर्जपवाहके दखलवास्त देने पर जिसने अपना कर्ज मयित कर दिया है दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी समयकी किसी भी व्यक्तिको नियमित रूपसे तलब (Summon) कर सकता है । यदि यह मामल हो जाय कि उसके पास दिवालिये की जायदाद है या उसके कर्जमें दिवालियेकी जायदाद होने का शक है अथवा उस पर दिवालिये का कर्जदार होने का शक है या वह व्यक्ति अदालत या दूसरे हाकिमकी रायमें जैसा अबसर होवे दिवालिया, उसके व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्धमें सूचना दे सकता हो और अदालत तथा दूसरा हाकिम जैसा कि अबसर होवे ऐसे व्यक्तिसे दिवालिवासे सम्बन्ध रखने वाली अथवा उसके व्यवहार या जायदाद के सम्बन्ध रखने वाली किसी भी दस्तावेज को जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे पेश कर सकता है ।

(२) यदि कोई इस प्रकार तलब किया हुआ व्यक्ति जबकि उसे उचित व्यय दे दिया गया हो अदालत या हाकिमके सामने उपस्थित होनेसे इनकार करे या किसी दस्तावेजको पेश करनेमें इनकार करे और इसके विषे कोई जानूगी रकबाष्ट न होसी हो जिसकी सूचना अदालत को देदी गई हो तथा अदालतने उसे मंजूर कर लिया हो तो अदालत या हाकिमको अधिकार है कि उसके लिये धारण जारी कर देवे जिसमें वह व्यय देनेके लिये लाया जासके ।

(३) यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति अदालत या हाकिमके सामने लाया जावे तो अदालत या हाकिम उसका दखल दिवालियेके सम्बन्धमें तथा उसके व्यवहार या जायदादके सम्बन्धमें लेसकती है और ऐसे व्यक्ति की पैची वकील द्वारा की जा सकती है ।

व्याख्या—

यह दफा कानून विचालिया संशोधन ऐक्ट न० ६९ एन् १९२६ [Provincial Insolvency Amendment Act 1926 (XXIX of 1926)] द्वारा जोड़ा गई है

उपदफा (१) इस दफा में दिये हुए अधिसूचना प्रयोग उसी समय किया जा सकेगा जबकि प्रांतिक सरकारने इसके लिये खास तारने किसी अदालतको या अदालतके दूसरे हाजिमको आज्ञा दे दी हो अथवा किसी अदालत या हाजिमको इस दफाके अनुसार कार्य करनेका अभिप्राय प्राप्त न होया। दिवाणिया नगर दिया जानकर हुक्म होनेके पश्चात् हा अधिसूचना प्राप्तकी हुई अदालत या हाजिम इस दफाके अनुसार रस्तेवाई कर सकता है। इस दफाके अनुगम कार्यवाई कराने के लिये किसी दरबारन द सनका ह तथा वह कर्तव्यवाह भी दाखलान द सकता है जो अपना कस साबित कर लुका ह अथवा किसी तीसरे व्यक्ति का अथवा उस कर्तेवाहको निम्न कस साबित नहीं किया जा चुका ह इस दफाके अनुसार कार्यवाई कराने का अधिकार प्राप्त नहा है इस दफाके अनुसार वह व्यापक तत्त्व लिय जा सकता है मितक र-कम में इलाकियका जायदाद होने या निम्न क-कम में इलाकियकी जायदाद होनेवा हाहा हाह वह व्यक्ति या तत्त्व विद्यमान मत है जा दिवालयके कसदार समझ लाने इस प्रकार व व्यक्तिमी तत्त्व हो सकता है निम्नको दिवालयके सम्बन्ध या उसक व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्ध बाल मादप होने यही नहा कि ऐसे व्यक्ति तत्त्वहा किये जाव किन्तु उनमें दिवाणिये अथवा दिवाणियक व्यवहार व जायदाद सम्बन्धो दस्तविजेंभी पेश नहाई जातकनी है।

उपदफा (२) म उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कानूने दस्तावेज तत्त्व किया गया हो तथा उसे उसक अपने लिये उचित धनभी दिया गया हो और वह अदालतमें आनेमें इनकार कर दूँ अथवा दस्तावेज मश परावर्त इन्कार कर देवे तो अदालतने अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध वारण्ट जारी कर देवे तथा उस बयान देनेके लिये मकदून छुलका लेवे परंतु साथ साथ यहभी बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मकदून इलाक का तत्त्वम हाजिर न हा सनका हो या दस्तावेज पेश न कर सनका हा तथा वह अदालतमें अपना यह मनूरी वतनपर उसक मकदून ले लेव तो ऐसे व्यक्तिके हाजिर न हाल पर उसके विरुद्ध वारण्ट जारी नहीं किया जावगा। उचित धनने अधिसूचना यह है कि उनका उसकी लुका, हाइ सर्वे, आदिके सम्बन्धमें पेशा धन मितक चाहेय इसक लिय जातिवाचका या दवालीन जनरल रूल (General Rules Civil) देखना चाहिये तथा उनमें बतलाय हुए नियमोंके अनुसार तत्त्व हाय हुए व्यक्ति हैसियतका ध्यान रखने हुए उसकी पर्याप्त धनदिया जाना चाहिये अथवा म उपदफाके यह प्रवृत्त हा कि तत्त्वका हाया व्यक्ति पर्याप्त सर्व पानका अभिप्राय है और वह तत्त्व हा लानेके बाद भा अदालत या तत्त्व नरा बाल हाजिमम यह व्यय मनूत जन हा हुक्म पान का इन्कार हा हा उपदफामें बतलाय हुए वारण्टका कारवाहा तथा पिछी उपदफाके बतलाय हुए समनका कार्यवाई निर्धारित नियमोंके अनुसारनी जाना चाहिये अथवा तावना दवालीन में या इस एक्ट म बतलाय हुए नियमोंके अनुसार ही समन या वारण्ट तामील किये जाना चाहिये।

उपदफा (३) अदालत या दूसरा हाजिम म प्रसार तत्त्व लिय हुए व्यक्तिमें दिवाणियके सम्बन्धों तथा मक व्यवहार व जायदादके सम्बन्धों पूछताड कर सकता है अर्थात् इन बातोंके अनिलित जय नानके लिये उसक कुछ पूछने का अभिप्राय नहीं है इस उपदफामें यह भा बतला दिया गया है कि यदि इस दफाके अनुसार तत्त्व किया हुआ बयान आना मददके लिये बशेल किया चाह हा कर सकता है या बशेलके लिये जवाबदा कर सकता है।

दफा ६० गैर मनकूला जायदादके लिये खास नियम

(१) अगर किसी जगह सन् १९०८ ई० के जायदादीवानीकी दफा ६६के अनुसार घोषणा की गई हो और उसका अमल जारी हो सो उस गैरमनकूला जायदादको जिसपर सरकारी माल-

गुजारी अदाकी जाती हो या जिस पर कायत होती हो या जो कायतके लिये उठाई गई हो किसीपर नहीं बँचेगा, लेकिन जबकि विचालियेकी सब जायदाद वसूलकी जाचुकी हो तो अदालत तय करेगी कि

(प) जो रुपया वसूल किया जा चुका है उसके अलावा कितना रुपया इस एक्टके अनुसार साबित किये हुए कर्जोंकी चुकानेके लिये चाहिये

(वी) विचालिये की कितनी गैरमनकूला जायदाद बिकने से बची है

(सी) और अगर यार हो तो उस पर कितना यार है

और ऊपर दी हुई बातों की तफसील कलक्टरके पास भेजेगा और तब कलक्टर उस फोड़ (जायता दीवानी) की तीसरी सूचीके पैराग्राफ २ से लेकर १० तक में दिये हुए नियमोंके अनुसार उस कदर रुपया लेवेगा जिसकी जरूरत बतलाई गई है और उन अधिकारोंके प्रयोग करनेसे जो रुपया आयेगा यह सब जहाँ तक उन पैराग्राफोंके अनुसार काम करते हुए होसकेगा अदालतकी बाँटनेके लिये दे देगा

(२) अगर किसी अन्य प्रचलित कानूनोंके द्वारा गैरमनकूला जायदादके खिलाफ डिफ्टी इजाजत या हुक्मोंकालेकी कोई मुमानियत या रूकावट हो तो इस एक्टमें दी हुई बातोंका कोई असर उन कानूनोंके नियमों पर नहीं पड़ेगा और वह नियम इस एक्टके अनुसार विचालिया फ़ौरन दिये जाने वाले हुक्मके अमलमें उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कोई डिफ्टी या हुक्म ।

व्याख्या—

इस दफ्तमें एक खास प्रकारकी गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें नैन नियमोंका प्रयोग किया जाना चाहिये उनका उल्लेख है । यह नियम उस गैर मनकूला जायदादके लिये प्रयोग किये जासकेंगे जिनमें सरकारी मालगुजारी अदाकी जाती हो या उस जमीनके लिये किये जासकेंगे जिस पर कायत होती होवे या जो कायतके लिये उठाई जाती हो ।

इन नियमोंका प्रयोग केवल उन्हीं जगहोंमें होवेगा जहाँ कि दफा ६८, जायता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाइतीहो ।

दफा ६८ जायता दीवानीमें दिया हुआ है कि—“प्राप्तिक सरकारों अधिनियम कि वह सरकारी वसूल करनेवाले हिन्दकी आज्ञा लेनेके पश्चात् प्राक्तिक सरकारी गट्ट द्वारा यह घोषित कर देवे कि किसी खास जगह पर इजाजत डिफ्टीकी बर्तवई इजाजतके लिये उस जगहके कलक्टरके पास भेज दी जावगी वही इजाजत डिफ्टी इस दफ्तके अनुसार भेजी जावेगी जिनमें अदायतने किसी गैर मनकूला (Immovable) जायदादकी बँचनेका हुक्म दिया हो या जो किसी खास बिस्मकी ऐसी डिफ्टी होवे अथवा जिस डिफ्टीमें किसी खास बिस्म की जायदाद या उसका इका बँचा जानकी होवे ।”

इस दफ्तमें रतलाया गया है कि यदि किसी गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें दफा ६८ जायता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाचुकी तथा उसमें कलक्टर हुई बातोंका प्रयोग जारी हो तो स्थितिर उस जायदादकी नहीं बँचेगा किन्तु जब ऐसी जायदादके अनिश्चित दिनांककी ओर सब जायदाद बँची जाचुकी हो तो अदालतको चाहिये कि पाँचके इन तीन बातोंका निर्णय करे कि (१) विचालियेके बकाया कर्जोंकी अदा करनेके लिये कितने धनकी आवश्यकता है (२) विचालियेकी जितनी जायदाद बिकनेसे बची है (३) उस पर बितना यार है और यह निर्णय करनेके पश्चात् अदालत इसकी रिपोर्ट कलक्टरके पास भेज देवे और तब कलक्टर चाहे हुए रुपयेके वसूल करनेका प्रयत्न उस जायदादके जायता दीवानीके शिखूळ तीन (Schedule III) के पैराग्राफ (Paragraph) २ से १० तकमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार करेगा । और कलक्टरको उन नियमोंके प्रयोग करने पर जो रुपया वसूल होगा वह उस रुपयेमें अदालतके सुई पर देगा ।

जायदादीवाणीकी सूची नं० ३ (Schedule III) में कलक्टर द्वारा ज्ञान वाली इजराय डिक्रीके नियमोंका उल्लेख है बाबत दीवानगी तारीखी सूचा (Schedule III) क अतिस्त (Article) २ से १० तक कीचे दिय जात हैं ।

शिड्यूल नं० ३ कलक्टर द्वारा इजराय डिक्रीका होना

२ खास मामलोंमें कलक्टर की कार्यवाही—यदि कोई डिक्री धुआहिदके अनुसार किसी गैर मतवृत्ता जायदादकें बेंचे जानके सम्बन्धमें नहीं हो गई हो तथा वह १ का सदे रूपरेखा डिक्री द्वारा पण्डित उस डिक्री इजरायम कोहें गैर मतवृत्ता जायदादकें करा कर नामाममें चढ़वाई गई हो और एसा इजराय कलक्टरक पास भजा जाव ता कलक्टर उचित तहकाकानक बाद यह निश्चिन करेगा कि आपा जायदादरा बिना नामाम कराय हुए मद्रूतनस कुल कर्ते धुकाया जानकता है या नहीं और यदि उसे इन बातनस इस्वास्त हो जाव ता वह भाच दिऐ हुए हुक्मक अनुसार कार्यवाई करेगा ।

३ डिक्रीदारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादका दावा करते हों—
(१) वेगप्राक १ में बतलाय हुए मामलेके सम्बन्धम कलक्टर एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसकी पाबन्दाक लिय १० दिनका समय दिया जावगा तथा उस नोटिसक अनुसार —

(ए) हर शस्स गिराही सदि रूपरेखा गिरा मद्रूतनस गिराक हावे तथा जिस डिक्रीमें उसका जायदाद नामाम करवाई जासके तथा डिक्रीद्वारा जायदादका नामाम कराना बाइता हो अथवा किसी कलक्टरक पास पठा करे अथवा यदि बिनाने अफानी बाइता डिक्रीके इजरायमें जायदाद नामाममें चढवानका का बाइता हो ता वह अदालत इजरायका सार्थकिकेड पठा करेगा जिसम कि यह माझम हो मके रि ऐम डिक्रीके अनुसार कितना रूपया डिक्रीदार पानेना अधिकारी है ।

(बा) यदि उस जायदाद पर किसी शरतका कोई हक हाव तो उसे भी च दिऐ कि वह कलक्टरके यहां अपने इस हकक बारेमें बयान द्यावल करे तथा सापहस साय बाद कोई दस्तावेज हावे ता उस हकक सुगुमें पठा करे ।

(२) इस प्रकारका नोटिस उस अदालतके एक आम जगह पर चिराया जावेगा जिसन कि उस जायदादके बेंचे जानेस हुक्म शुरूमें दिया हो तथा उन जगहोंमें भा बिपकया जावगा जहा कि कलक्टर पुन सिब समन आर यदि किसी डिक्रीदार या दावदारका पना माझम हो ता नोटिसका नकल बेगिय गिराक या अर किसी ताहस उस डिक्रीदार या दावदारके पास भेजी जावगी ।

४ डिक्रीका मतलिया निदिचन करना और जायदाद गैर मतवृत्ताका उसने लिय मुहैय्या करना — (१) ता मिय दके समाप्त होवेके पश्चात् कलक्टर कोह तापल नियत करगा कि जल्ममें उा गिन डिक्रीदार दावेदार या मद्रूतन अपने अपने मतले पहा कर सकें तथा वह खय मद्रूतनका जायदादक सम्बन्धम जो बात जानना चाह जान सके ता जिस प्रकारकी जायदाद है तथा कतनी जायदाद है और यह भा जान सके कि उस पर डिक्रीदारों या दावेदारों का बड़ा तक हक पहुँचता है कलक्टर समय समय पर कपातका तथा तहकीकानकी ताहस भा बडा सकता है ।

(२) यदि इस बातक लिय कोई जगहा न होव कि मद्रूतनके वेकद बतलाई हुई जावगा या ताब डाक नहीं है तथा इस बातके लिय भी कोई जगहा न पड़ता हो कि कानमा कन पाहल धुकाया जाना चाहिय तथा कानमा न सम आर न इस बातका क लिय कोई जगहा हाव कि कौनसे कसानी पाबन्दा जायदाद पर है तो कलक्टर एक बयान तयार करेगा जिसम कि डिक्रीक सम्बन्धमें बसूल किया जान बाग सब कया दिक्काला बाइता तथा यह लपचलाया जावगा कि डिक्री या दावे किस कससे जगहा जावेग और जिस कदर पर मतवृत्ता जायदाद इन नकोंका चुकानन लिय है ।

(३) यदि कोई इस प्रकारका श्रमका उपस्थित होने तो कलक्टर श्रमदेना हवाला देने हुए तथा अपनी राय प्रकट करने हुए मामले में फ़ैसले के लिये उस अदालत के पास भेज देगा जिसे कि नीलापका हुक्म शुरूमें दिया हो और जब तक कि इसका जवाब नहीं आयेगा नीलापकी कार्यवाही को रोक देगा । यदि मामले अधिकार सीमा के अन्दर होगा तो वह अदालत इस मामले को तय कर देगी या उस मामले को किसी ऐसी अदालत के पास फ़ैसले के लिये भेज देगी जिसे उसके तय करनेका अधिकार प्राप्त है और उस मामले में जो आखिरी फैसला होगा उसे कलक्टर के पास भेज देवेगी और तब कलक्टर इस फ़ैसले के अनुसार ऊपर बतलाया हुआ कथन तैयार करेगा ।

५ जय जिलेकी अदालतने नोटिस जारी कर दिया हो—कलक्टर स्वयं नोटिस जारी करने या दफा ३ व ४ के अनुसार तद्विधान करने के बजाय एक कथन इस बातका तैयार करके कि मरुतकी क्या हालत है तथा उसकी पैर मरुतला जारदादकी जहा तक कि कलक्टरको स्वयं मालूम है या जहा तक भित्तिस से मालूम होता हो क्या हालत है लिख कर अदालत जिला (District Court) के पास भेज सकता है और तब वह अदालत नोटिस जारी करेगी तथा दफा ३ व ४ के अनुसार तद्विधान करेगी और उसका मरुतला कलक्टरको लिख भेजेगी ।

६ अदालतके फ़ैसलेका अंतर—दफा ४ व ५ के अनुसार यदि किसी श्रमदेनी अदालत निपटा देगी तो वह फ़ैसला कगैकै के दरमियान एक प्रकारकी टिकी समझी जावेगी और उसीकी तरह वह जारी कराया जासकेगा तथा इसकी अमील भी की जासकेगी ।

७ रुपया देनेके लिये विचार—(१) यदि पैराग्राफ ४ व ५ के अनुसार यह तय किया जायगा हो कि कितना मालिक है तथा कितनी जायदाद है तो कलक्टर—

(ए) यदि उसे यह मालूम हो कि जायदादको बिना बेचे हुए खरचा बसूल नहीं हो सकता है तो वह उसके बेचने की कार्यवाई शुरू करेगा ।

(बी) यदि उसे यह मालूम हो कि पूरा कथन व सूद जो डिफ़ॉर्म दिखाया गया हो या जो कायदेसे मिलना चाहिये जिला नीलाम जायदादके बसूल किया जासकता है तो वह जायदादको बिना बेचे हुए उस पर नीचे दिये हुए दग पर न्याय मय ब्याजके बसूल कर सकता है (1) यह कि कुछ जायदादको या उसके किसी हिस्सेको पैदाभी कथन लेकर हमेशाके लिये अपना किसी खास मियादके लिये उठा सकता है (ii) यह कि कम जायदादको कुछ या उसके किसी हिस्सेको रोक कर सकता है (iii) यह कि उस जायदादके किसी हिस्सेको बेच सकता है (iv) यह कि तारीख नीलामने २० साल तकके लिये खेती के लिये उठा सकता है तथा उसका इन्तजाम स्वयं या किसी दूसरेके लिये कर सकता है (५) यह कि ऊपर बतलाये हुए तरीकोंसे कुछ रुपया किसी तरीकेसे ब कुछ किसी दूसरे तरीकेसे या किसी अन्य तरीकोंसे बसूल कर सकता है ।

(७) कलक्टरको अधिकार है कि कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्सेको प्रत्यक्ष करते समय वह उस जायदादके मालिकके तौर पर काम कर सकता है ।

(२) कलक्टरको अधिकार है कि वह कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्सेको कर्षण बढ़ानेकी शरतसे अपना या इस नामके कि वह ज्यादा शर्तके लिये उठाई जायके या वह किसी बानके लिये नीलाम न की जासके बाका खरचा अदा कर सकता है या उसकी अदालतीके लिये समझौता कर सकता है चाहे उसकी अदालती उस समय होने बानी होवे या उसके बाद और ऐम बार्कन अदालतीके लिये वह जायदादके किसी हिस्सेको रोक या बच कर सकता है तथा उसे उठा भी सकता है जैसा कि मुनासिब समझ पड़े । यदि ऐसे बर (Incumbrance) की अदालतीके सम्बन्धमें कोई श्रमका खडा हो जावे तो उसे

, अधिकार है कि वह मुनासिब अदालतमें उसके बारेमें मुकदमा दायर कर देवे यह मुकदमा कलक्टर अपने नामसे या मद्दयूनके नामसे दायर कर सकता है या कलक्टर इसका हिसाब समझ सकता है अथवा छगडेकी निपटारके लिये दो पच्चोंके सुपुर्द कर सकता है जिन्हें कि दोनों फ्रीकैनेन एक एक अपनी तरफमें घुना हो या ऐसे सरपचके ऊपर छोड़ सकता है जिसे कि इन दो पच्चोंने चुना हो ।

(४) इस पैराग्राफके अनुसार कार्रवाई कलक्टर उन्हीं नियमोंके आधार पर करेगा जो कि प्रांतिक सरकारने इस विषयके लिये बनाये होंगे ।

॥ **वाकीफा बसूल करण**—यदि दफा ७ के अनुसार जायदाद उधार गई हो या उसका प्रत्यक्ष लिया गया हो और उसकी मियाद समाप्त होने पर यह बाध्म होवे कि कुछ वर्ष इस पर भी नहीं चुका है तो कलक्टर इस बातकी लिखित सूचना मद्दयूनकी या उसके उत्तराधिकारीको देवेगा और उसमें यह भी लिख देगा कि यदि बक्या मनालिखा है इन्हेन अदर नहीं चुका दिया जावेगा तो वह कुछ जायदाद या उसके किसी पर्याप्त हिस्सको बेच देवेगा । और यदि वह इन्के अन्दर रुपया अदा नहीं होगा तो कलक्टर नोटिसके अनुसार कुल या कुछ जायदादको बेच देवेगा ।

६ **कलक्टरका हिसाब देना अदालतको**—(१) कलक्टर समय समय पर उस अदालतकी जिसने जायदादके नीलाम किये जानेका हुक्म पेश्वर दिया है सब हिसाब भेजना रहेगा जिसमें कि रुपये की बसूली तथा इस शिद्दपूलके अनुसार प्राप्त अधिकारोंके आधार पर जायदादके लिये जो खर्च किये गये हों उनका उल्लेख होगा और नबतका कय्या उस अदालतकी सुपुर्दगीमें कर देगा ।

(२) उन खर्चोंमें सरकारी कर्ज व ज़िम्मेदारिया जो समय समय पर कुल या कुछ जायदादके सम्बन्धमें हो जावें शामिल समझी जावेगी तथा वह लगान भी शामिल समझा जावेगा जो कि उस जायदाद या उसके किसी हिस्सेके लिये अपनेसे अच्छा हक रखने वाले कामन्दारका निबलता होवे और यदि कलक्टर हुक्म देवे तो इन गवाहोंका खर्च भी जो उसने तत्तब किये हों लगाया जावेगा ।

(३) नया हुआ कय्या अदालत इस प्रकार ब्याय करेगी —

(ए) यहकि वह कय्या मद्दयूनके परवशिष्टे उन लोगोंकी परवशिष्टमें लगाया जावेगा जो उसकी जायदादकी आमदनी से परवशिष्ट किये जानेके अधिकारि हैं हर एक मन्बरके लिये उस बदर करना नतीर परवशिष्टके दिया जावेगा जिनका कि अदालत मुनासिब समझे ।

(बी) यदि कलक्टरने पैराग्राफ (Paragraph) १ के अनुसार कार्रवाई की हो तो उस डिक्तीके बुकनेमें लगाया जावेगा जिसके एन्वयमें जायदाद नीलाम कराई गई हो या फिर दफा ७३ के अनुसार जैसा कि अदालत अवित समझे ।

(सी) यदि कलक्टरने पैरा बी के अनुसार कार्रवाई की हो तो (१) जायदादके बार (Incumbrance) का सूद बुकनेमें देवेगी (II) यदि मद्दयूनके पास जीविकावा पर्याप्त साधन न होंवे तो उसकी जाविकोंके लिये उस बदर जितना कि अदालत मुनासिब समझे देवेगी (III) पहिले डिक्तीदार तथा अन्य डिक्तीदारोंका जिन्होंने नोटिसकी पावन्दगी की तथा जिनका मनालिखा बसूल किया जानेका हुक्म हो चुका हो उनका कय्या रसदी तौमि बुकनेमें देवेगी ।

(४) इस जायदाद भा बचे हुए खर्चमेंसे किसी सारी डिक्ती वाले दूसरे डिक्तीदार को कय्या बत बत तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उन डिक्तीदारोंको कय्या जिनके सम्बन्धमें हुक्म हो चुका है न चुकाया जा सके और अन्तमें बचा हुआ कय्या मद्दयूनकी या ऐसे शस्सको दिया जावेगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे ।

१० कैसे बचा जायगा—जबकि कलक्टर इस शिष्टाचार के अनुसार जायदादों पर कर तो वह जायदादों पर मुक्त या भिन्न २ भागों में आय नीलाम द्वारा संग्रहित करनी और उते यह भी अधिकार है कि वह —

(ए) उहा हिरसे (Lot) के लिये कोई उचित सीमा नियत कर देवे

(बी) नालामकी वचित समयके लिये उचित कारणोंके आधार पर जो उचित जाना चाहिये मुक्तता कर देने जबकि उसे यह मांग हो कि मतलबी होनेसे जायदादकी आधी सीमा आ सकेगी ।

(सी) नीलाममें जायदादों पर छद्म से और फिर दुबारा उसे नीलाम आम हाथ बेच देने या बादमें भी सीदेसे बेच देने जसा कि उसे उचित प्रतीत हो ।

उपरवी दफाओंमें दानेमें यह सभी भाति प्रकट है कि कलक्टर अपने यहां आई हुई इनपय निर्वाही कार्रवाई को किस प्रकार अग्रिम में ला सकता है । भिन नियमों का उपर वर्णन है कलक्टर उही नियमोंका प्रयोग करेगा । उस अदालत को जिसने जायदाद नीलामके लिये भेजा हो वही जजिस्टर हस्तक्षेपके श्राव होने जो इन नियमोंमें बतलाये गये हैं अर्थात् वह ऐसे ही क्षणोंको तब का सजेगी जो कलक्टर तब होनेके लिये उससे पास भेजे ।

यदि इस दफाके अनुसार कलक्टर द्वारा इनपरवी कार्रवाई हो रही हो तो अदालत दायिनीको कोई अधिकार नहीं है कि वह जायदाद नीलाम करने वाले शर्तियों पर ध्यान देकर करे । यदि जायदादों नीलाममें या उसके नीलामकी कार्रवाई में कोई शिष्टाचार होने तो वह शिष्टाचार उसी अदालतके सामने पेश की जाना चाहिये जो नीलामकी कार्रवाई कर रही हो और उसी अदालत अदालतको ऐसे प्रमाणों पर विचार करना अधिकार है देखो—49 A. 272. A. I. R. 1927 All. 203, यदि अदालत निर्वाह इस दफा में बतलाई हुई जायदादों को बेच देवे अर्थात् इस दफाके नियमोंके विरुद्ध काम करे तो वह बयनामा अत्रिबिन् होगा तथा वह अग्रिम में नहीं लाया जा सकता है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 299.

इस दफाका प्रयोग उन मामलोंके लिये भी हो सकेगा जो कलक्टर लिये उठाई जाती हों या भिन पर वास्तवी जाती है । नीलकी खेतीका हीन वास्तवादीका काम है परन्तु नीलकी शिष्टियोंका संग्रह किया जाना कलत्र नहीं है 31 Cal. 174. बागके लिये उठाई जाने वाली सीमा कायकी सीमा नहीं है देखो—24 Cal. 160. आरु वना व सरकारी आदि बोये जमीन जमीन वास्तवादीकी सीमा है देखो—25 Mad 627. परन्तु कलक्टर हरिद्वारे अनुसार सरकारी बोने तथा नास या फलोंके दूरस्थ छगन वाली जमीन वास्तवी सीमा नहीं है देखो—27 Cal. 205. यदि किसी प्रचलित कानूनमें अनुसार किसी और मनूका जायदादकी इनपयके सम्बन्धमें बतली रोकने आदिने लिये कोई नियम बनाये गये हों तो उन नियमों का ध्यान रखने दूधे ही इस पृष्ठका प्रयोग किया जा सकेगा ।

राहौर हरिद्वारे देखो—A. I. R. 1929 Lah. 66 में तब किया है कि अदालत दिवालिखा, उचित अवसर उपस्थित होने पर दिवालिखी जायदादोंको हमेशाके लिये भी अग्रहदा कर सकता है । इस मामलेमें एडमनप्रसाद अर्थात् ए इन् १९१५ ई० में दिवालिखा करार दिया गया था । वहाँ पास बहुत सा सीमा थी जिससे कृषा वसूळ करनेकी बहुत कोशिशवा गई परन्तु कुछ बसूळ नहीं हो सका तब वह जमीन उसके एक रिजिस्टारके पास देन कर दिये जाने का हुक्म हुआ इसी हुक्मकी अपालकी गई है अर्थात् जमीनें तब किया कि वही दिवालिखा नगरा कदाचित् बालता रहा है तथा अपने पास जीवकला दूसरा साधन भी उपस्थित है ऐसी दशामें उसकी वह सीमा रहनी जाना चाहिये दफा ६० (१) (सी) और दिवालिखी अपील खारिजी गई ।

तकसीम जायदाद

दफा ६१ कज़ोंका पेशतर चुकाया जाना

(१) दिवालियेकी जायदादको बांटने समय नीचे दिये हुए कज़ें और सब कज़ोंसे पहिले चुकाये जावेंगे :—

(ए) वह सब कज़ें जो गवर्नमेंट या स्थानिक सरकारको देना हों

(बी) क्लर्क नौकर या मजदूरकी वीस रुपयेसे कम वह सब तनखाह या उजरत जो उन लोगोंको दिये लेकी दरखास्त गुजरनेसे ४ महीने पहिले किये हुए कामके लिये चाहिये ह ।

(२) उपदफा (१) अर्थात् ६१ (१) में दिये सब कज़ें आपसमें बराबर हैलियतके समझे जावेंगे और पूरे पूरे चुकाये जावेंगे लेकिन अगर दियालियेकी जायदाद काफी न हो तो वह रसदी तौरसे सब कज़ें कम कम चुकाये जावेंगे ।

(३) अगर दियालियेकी जायदाद काफी हो तो उपदफा (१) में दिये कज़ें उन रुपयोंको अलहदा करनेके बाद जो इन्तजाम या दूसरे तर्जके लिये जरूरी हों फौरन चुका दिये जावेंगे ।

(४) जहां सामेका काम हो वहां पहिले सामेकी जायदादसे सामेके कज़ें चुकाये जावेंगे और सामेदारोंकी जुदागाना जायदाद पहिले उनके जुदागाना कज़ोंके चुकानेमें लगाई जावेगी । जब कि सामेदारकी जुदागाना जायदादसे कुछ बचे तो वह सामेकी जायदादका हिस्सा समझी जावेगी और सामेकी जायदादमें सामेदारके जो जुदागाना हिस्से होंगे उसीके अनुसार वह उस सामेदारके हिस्सेमें समझी जावेगी ।

(५) इन परबके नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब कज़ें जो सूचीमें दर्ज होंगे अपनी तादादके अनुसार तथा थिला कोई तरजीह दिये हुए रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे ।

(६) ऊपर दिये हुए कज़ोंकी अशायगीक याद अगर कुछ बचे तो उससे सूचीमें बदे हुए कज़ोंका सूद ६ १/२० सैकड़ा सावनाके हिसाबसे दिवालिया कतार देनेके बरस चुकाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादको बांटे जानेके नियम दिये हुए हैं तथा यह बतलाया गया है कि कौनसे कज़ें पहिले चुकाये जाना चाहिये तथा इनमें कज़ें बादमें सबसे पहिले यह दिया गया है कि दो प्रकारके कज़ें सबसे पहिले चुकाये जाना चाहिये (१) एक तो वह कज़ें जो सम्राट या स्थानिक सरकार (Local Authority) को अदा किये जाने वाले हों तथा (२) दूसरे २० रुपयेसे कम वह मजदूरी व तनखाह जो दिवालियेके प्रत्येक नौकर या मजदूरको उस कामके एवजमें मिलना चाहिये जो उसने दिवालियेकी दरखास्त गुजरनेके चार माहके अंदर किया हो ।

उपदफा (२) यह दोनों प्रकारके कज़ें एक ही हैलियतके समझे जाना चाहिये तथा पूरे पूरे चुकाये जाना चाहिये परन्तु यदि दिवालियेकी जायदाद इनको पूरा पूरा चुकानेके लिये पर्याप्त न होनी हो तो हिस्सा रखनेके हितानसे वह कज़ें कम करके चुकाये जाना चाहिये । यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि देनदारोंके कज़ोंमें बार देवदी हुई जायदाद पर समझे

पढ़े होता है अर्थात् सरकारी बजोको उस पर वर्जोह (Perference) नहीं दी जासकती है देवो—29 All. 537; 28 Mad. 420 दूसरे बजोहें मुकाबिले सरकारी बजोहें मन्ते पढ़िजे चुकाये जाना चाहिये। स्थानिक सरकार (Local Authority) से अधिप्राय प्युनिसिपलिटि, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदिमें दे।

उपदफ्ता (३) दिवाडियेकी जायदाद वसूल करने या समुक्त प्रबन्ध करनेके लिये जो सब आवश्यक हुंसा पढ़िजे वर निवाडा जाना चाहिये इसके पदफ्ता उपदफा (१) में बतलाये हुए बजोहें चुगानेका प्रबन्ध निगम पूर्वक किया जाना चाहिये।

उपदफा (४) जहाँ साझेका काम होये वहाँ पढ़िजे साझेकी जायदादसे साझेके बजोहें चुकाये जावेंगे और साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद पढ़िजे उनके जुदागाना बजोहो चुकाये जानमें रगार मानेगी। यदि साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद उसके जुदागाना बजोहो चुकाये जानेके बाद बचे तो उसे साझेकी जायदादके नीर पर इस्तेमाल किया जानकेगा इसी प्रकार यदि साझेकी जायदाद साझेका बजोहें चुकाये जानेके बाद बचे तो वह हिरसा रसदीका हिस्सामें साझेदारोंके जुदागाना बजोहो चुकाये जानेमाफकी जानकरी है।

उपदफ्ता (५) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि इस प्रकारके नियमोंका प्यान रखते हुए वह सब बजोहो बजोहोकी सूचीमें दर्ज किये गये हों हिरसा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें किन्ही प्रकारके दूसरेके मुकाबिले तर्जोह नहीं दी जावेगी।

उपदफा (६) दिवाडिया वगार दिये जानेके बाद भी सूद दिखानेकी व्यवस्था है। उपदफाके अनुसार की गई है क्योंकि अनुमन सूद बाद दिवाडिया वगार दिये जानेके नहीं मिलता है परन्तु इस उपदफाके अनुसार दिवाडिया वगार दिये जानेके बादसे वसूली तकका सूद ६ रुपया सेकड़ा सालानाकी दरसे दिलाया जासकता है यदि दिवाडियेकी जायदादमें उसका सब कर्तै पूर्ण रूपसे चुकाये जायके तथा उसके बाद कुछ समय तकमिल बच रहे देखो—A. I. R. 1926 All. 361 फलफला हाईकोर्टने एक मामलमें यह तय किया है कि यदि (अ) को (ब) का कोई कर्तै चुकाना हो परन्तु (अ) वह कर्तै (स) से वसूल कर सकता हो तो (अ) के दिवाडिया वगार दिये जाने पर (स) का (अ) का कर्तै वसूल किया जासकता है परन्तु उस वसूलमें से (ब) अपना बजोहें चुका पानेका अधिकारी है अर्थात् उस वसूलमें से पढ़िजे (ब) का बजोहें चुकाया जावेगा देखो—A. I. R. 1929 Cal. 205.

दफा ६२ डिवाइडेण्ड, हिरसा रसदीका लगाया जाना

(१) डिवाइडेण्डका अन्दाजा लगाने समय रिस्वीयर नीचे दिये हुए मर्होके लिये वांछी रकम हाथमें रख लेगा:—

- (ए) उन बजोहोके लिये जो इस एकटके अनुसार साबित किये जा सकते हैं और जिनको दिवाडियाने अपने ध्यानमें दिखलाया है या जो और किसी तरहसे मालूम हुए हैं लेकिन जिनके काजैप्याह इतनी दूर रहते हैं कि मामूली तौरकी इत्तिला पर उनको काफी समय अपने बजोहोके साबित करनेका नहीं मिला है
- (बी) जिन दावोंका मसला तब तक तय नहीं किया गया है लेकिन जो इस एकटके अनुसार साबित किये जा सकते हैं
- (सी) जिन मामलोंके साबित होनेमें या दावोंमें झगडा हो, और
- (डी) जायदादके इतनाम या दूसरे कामोंके लिये जिन खर्चोंकी ज़रूरत हो

(२) उपदफा (१) में दिये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रूपया जो हाथमें होगा डिवीडेण्डके तौर पर तत्कालीन कर दिया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफा में हिस्सा रखी (' dividend) बचने समय निज बालोंका ध्यान रखना तथा निज रक्मोंका रोकना आवश्यक है उनका उल्लेख दिया गया है अर्थात् दिवालियेकी आयदादसे बचूकनी हुई सब रकम एक साथ ही व ही कर्जोंके चुकानेमें न लगा दो जाना चाहिये जो साबित किये जा चुके हैं किन्तु और कर्जोंका या ध्यान रखना चाहिये ।

हिस्सा रखी (Dividend) बचनेमें पहिले रिसीवरकी चाहिये कि वह कौसी रकम उन कामोंके लिये रोक लेवे निजका उल्लेख उपदफा (१) के अंतर्गत (ए), (ना), (सी), व (डी) में किया गया है ।

क्लाज़ (ए) में उन कर्जोंको बतलाया गया है जो साबित किये जा सकते हैं परन्तु जिनको साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका है ऐसे कर्जों वही हो सकते हैं जिन्हें दिवालियेमें स्वयं तस्लाप किया हो या भिनके बारेमें अदालतको किसी दूसरे जरियेसे इतनीमान होजाये तथा साधदी माथ अदानतको यह भी माहूम होजावे कि उन कर्जोंको पानेके इक्यार इतना दूर रहने हैं कि मामूली तारकी इच्छा पर उनको आन कर्जोंके साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका है ।

क्लाज़ (बी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जो इस एकटके अनुसार साबित किये जा सकते हैं परन्तु उनकी तादाद उस वक्त तक निश्चित नहींकी जा सकी है ।

क्लाज़ (सी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जिनके साबित होने या दावेमें झगडा हैवे ।

क्लाज़ (डी) में दिवालियेकी आयदादके इन्तजाम आदिके सम्बन्धमें भिन लखोंके होनेकी सम्भावना है उनका उल्लेख किया गया है अर्थात् क्लॉज (ए), (बी), (सी) व (डी) में बचलाई हुई मदोंके लिये कौसी रकमा रोक लेनेके बाद रिसीवरकी चाहिये कि हिस्सा रखी तत्कालीन करे ।

उपदफा (२) में वह बतलाया गया है कि रिसीवर उपदफा (१) में बचलाये हुए कामोंकी लिये कनये रोक सकता है अथवा नहीं उसका कर्तव्य है कि वह कौसी सब रूपया कर्जखवाहोंमें तत्कालीन कर देवे अर्थात् रिसीवर अपन पास कोई काबिल रकम नहीं रोक सकता है ।

दफा ६३ डिवीडेण्ड जाहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्जखवाहने कर्ज साधित नहीं किया है उसके हक

अगर किसी कर्जखवाहने किसी डिवीडेण्ड जाहिर किये जानेसे पहिले अपना कर्ज साबित नहीं किया हो तो वह उस यक़ायी रूपसेले जो रिसीवरके पास होगा उस डिवीडेण्ड को पानेका हकदार होगा जो आयन्दा तत्कालीन किये जानेको है लेकिन वह उस डिवीडेण्डमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा जो उसके कर्ता साबित करनेसे पहिले तय किया जा चुका है ।

व्याख्या—

इस दफा में उस कर्जखवाहके लिये हिस्सा रखी पानेकी व्यवस्था बनवाई गई है जिसका कर्ज देमें साबित किया जावे । अर्थात् यदि उसका कर्ज साबित किये जातेसे पहिले हिस्सा रखी उन कर्जखवाहोंमें तत्कालीन किया जाचुका हो निजका कर्ज पहिले साबित किया जाचुका है तो वह उस तत्कालीनमुदा पतारकेमें गड़बड़ी नहीं जाल सकेगा और उसे उसमेंसे कोई

हिस्सा समझी नहीं मिल सकेगी पालु उसका बजो साधित होनेके बाद जो हिस्सा समझी (Dividend) बाग जावेगा उसमें उसे भी हिस्सा समझी मिल सकेगा बशर्त उसके कर्ज साधित होनेके बाद जो रकम गिरीवरके हाथमें बची होगी उसमें उसका भी हक होगा और वह बचल इतनी बराबरीमें कि उसका 75% देयमें साधित हुआ है वह रकम में अपना हक पानेमें बचित नहीं बनता जावेगा ।

दफा ६४ आखिरी डिवीडेण्ड

जब किसी बर दिवालियेकी कुल जायदाद या जायदादका घट हिस्सा जो अदालतकी शायमें बिना फिजूलकी देर गिरीवरमें किये हुए बसूल किया जा सकता है, बसूल करने, तो वह आखिरी डिवीडेण्ड घोषित कर देगा । लेकिन ऐसा करनेसे पहिले वह उन लोगोंको नोटिस दे देवेगा जिनके कर्जोंका जिक्र हुआ है लेकिन जो साधित नहीं किये गये हैं कि अगर वह लोग नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर अपने कर्ज साधित नहीं करें तो उनके हकोंका खिला लिहाज किये हुए आखिरी डिवीडेण्ड दे दिया जावेगा । नोटिसमें दी हुई मियादके समाप्त होने पर या उस मियादके समाप्त होने पर जो किसी कर्जवाहने अपना कर्ज साधित करनेके लिये अदालत से ली हो दिवालियेकी जायदाद उन कर्जवाहनोंमें बांट दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें दर्ज है और किसी दूसरे कर्जवाहने के दावोंका खयाल नहीं किया जावेगा ।

उपारण—

आखिरी हिस्सा समझी कौनसे समय जिन कर्जोंका ध्यान रहना चाहिये उनका उल्लेख इस दफ्तरे किया गया है । आखिरी हिस्सा समझी (Final Dividend) उनी समय बांटा जावेगा जब कि दिवालियेकी कुल जायदाद बसूल की जा चुकी हो अपना दिवालियेकी जायदाद उस कदर हिस्सा बसूल किया जा चुका हो जो अदालतकी शायमें बिना फिजूलकी देर किये हुए गिरीवर बसूल कर सकता है । परन्तु आखिरी हिस्सा समझी तत्काल करनेसे पहिले गिरीवरका बतव्य है कि वह ऐसे कर्जवाहनोंकी निर्धारित नियमोंके अनुसार सूचना देवे जिनके कर्जों का जिक्र तो दिवालियेकी दफ्तरास्तमें हुआ हो या तु जिनका कर्ज साधित न किया गया हो । अर्थात् जिन कर्जवाहनों का कर्ज साधित होकर दर्ज किये गये न हुआ हो उन कर्जवाहनोंकी आखिरी हिस्सा समझी बांटनेसे पहिले सूचना देनी जाना चाहिये । नोटिस इस बातका उनको दिया जावेगा कि वह नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर अपना कर्ज साधित करने अपना बिना उनके कर्जोंका खयाल किये हुए आखिरी हिस्सा समझी बांट दिया जावेगा ।

नोटिसमें दी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालियेकी जायदाद सूचीमें दर्ज युक्त कर्जवाहनोंके बीचमें हिस्सा समझीके हिस्सा बांट दी जावेगी और उस बात दूसरी कर्जवाहनोंका कोई ध्यान नहीं रखना जावेगा । या तु यदि किसी कर्जवाहने अपना कर्ज साधित करनेके लिये अदालतमें कुछ मोहलत लखी होवे तो उस मोहलतके समाप्त होनेके पश्चात् या अथवा हिस्सा समझी बांटनेकी वरिदाई अमरुत दर्ज जावेगी । इस दफ्तरे अनुसार नोटिस उन्हीं कर्जवाहनोंके दिने जावेगे जिनके कर्जोंका जिक्र आचका है परन्तु जिनके कर्ज साधित नहीं किये गये हैं । आप लोगोंको नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—10 I. C. 791. यदि किसी कर्जवाहने कर्ज सूचीमें दर्ज न किया गया है तो वह बिना सर्टीफिकेट बराबर शामिल किये हुए हिस्सा समझी पानेका हकदार है देखो—49 Mad. 952.

इस दफ्तरे अनुसार कर्जवाहनोंमें आखिरी हिस्सा समझी देने तक अपना कर्ज साधित करने तथा उस समयके बाद बाद जने वाले कर्जोंमें से हिस्सा समझी प्राप्त करनेका हक दिया गया है । यदि वह इस दफ्तरे अनुसार किये हुए नोटिसमें

मियादें अर्थात् भी अपना कर्ज मानित न करें तो फिर उनसे और कोई सूच 1 नहीं दी जावेगी और उनके कर्जों का दिवा
रघाल लिये हुए दिवालियों की वचा हुई जायजद आगिने तौर पर उड़ी कर्जकारोंमें नष्ट दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें
दर्ज है । (डीवीडण्ड (Dividend) शब्द अंग्रेजों हिस्सा सदासे हिस्सेसे बांटे जानका है । आमतौर रिशोधका
वर्तव्य है कि वह मोगिस केवल उन्हीं कर्जकारोंको नहीं देवे जिन्होंने अपना कर्ज आदिरे किया है किंतु उन कर्जकारोंको भी
देवे जिनका कत उससे दिवालिया या किसी कर्जकार द्वारा बनलाया गया है अर्थात् नोटिस केवल उन्हीं लोगोंको नहीं होता
चाहिये जिनका किंतु दफा ६२ (१) के (बी) व (सी) क्लॉजमें है किंतु उन लोगोंको भी होना चाहिये जो क्लॉज (६)
में भी हैं । देखा—A I R 1928 Sindh 100=107 I C 439

दफा ६५ डिबीडेण्डके लिये कोई दावा नहीं हो सकेगा

रिशोधके खिलाफ डिबीडेण्डके लिये कोई मुकद्दमा नहीं दायर किया जावेगा, लेकिन
अगर रिशोध किसी डिबीडेण्डके देनसे इन्कार करे तो सूचीमें दर्ज नाम धर्म कर्जकारोंके
वरदावारत उन पर अदालतको अधिकार है कि यह, रिशोधको डिबीडेण्ड अदा करनेका हुक्म
देवे और यह भी हुक्म देवे कि वह अपने पाससे सूच व सूच उस मुद्दतका अदा करे जिस मुद्दत
तक उसने अपना रोक रक्खा हो ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बनलाया गया है कि यदि रिशोध किसी डिबीडेण्ड (Dividend) न देवे और उसका नाम
कर्जकारोंकी सूचीमें दर्ज हो तो ऐसा व्यक्ति अदालतसे दारवाजत दे सकता है और अदालतसे उस वक्त अनिवार है कि
वह रिशोधको उस कर्जकारोंका हिस्सा रखे अदा करनेका हुक्म देवे तथा रिशोधसे रोक हुई क्रमका सूच व दारवाजतका
कर्ज भी उस कर्जकारोंकी दिवालिया इस दफामें यह भी बनलाया गया है कि डिबीडेण्डके लिये रिशोधके विरुद्ध कोई एकदुआ
दायर नहीं किया जा सकता है इस बातका ध्यान रखा जायज कि इस दफाके अनुसार दारवाजत केवल वही कर्जकारोंके दे
सकते हैं जिनका नाम कर्जकारोंकी सूचीमें दर्ज हो गया हो कोई दूसरा व्यक्ति इस दफाके अनुसार दारवाजत नहीं दे सकता है ।

दफा ६६ दिवालियों द्वारा इन्तजाम व उसका भत्ता

(१) अदालतको अधिकार है कि यह दिवालियोंकी उसकी कुल या गज जायदादका
इन्तजाम सुपुर्द करदे या अगर कोई रोजगार हो तो उसका चलनेका भार कर्जकारोंके फायदेके
लिये उसे सुपुर्द करदे या और किसी तौरसे जायदादके इन्तजाममें मदद करनेका भार जिस
किस्मसे या जिन शर्तोंके साथ चाहे उसे देदेवे ।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह समय समय पर दिवालियोंकी जायदादसे उस
क्रूर भत्ता दिवालियों या उसके सान्दानकी परवरिशके लिये नियत करदे जितना मुनासिब
मालूम हो या दिवालियोंके कामके पयजमें अगर वह अपनी जायदादके रुमदानमें काम कर
रहा हो कुछ भत्ता नियत कर देवे; लेकिन इस प्रकारका भत्ता किसी समय भी घटाया बढ़ाया या
बन्द किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार स्वयं दिवालियों ही को उसकी जायदादसे प्रवचन भाग दिया जा सकता है चाहे वह उसकी सन

जायदादके लिये होवे अथवा नह उसकी जायदादके किसी खास हिस्सेके लिये होवे इस प्रकार यदि दिवालिया क़ारार दिये जानेसे पहिले दिवालिया किसी रोज़गारकी करता रहा हो तो उस रोज़गारकी चाटू रखनेका कार्य भी उसी दिवालियेकी सुपुर्दगीमें दिया जा सकता है परन्तु इस प्रकार दिवालियेको जो काम सुपुर्द किया जावेगा वह अपने लाभके लिये नहीं करेगा किन्तु अपने कर्त्तव्यार्थके लिये करेगा अदालत दिवालियेसे जायदाद आदिके इन्तज़ाममें मदद भी ले सकती है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालत जिस प्रकार तथा जिन शर्तोंके साथ दिवालियेसे काम लिया चाहिगी ले सकती है अथवा दिवालिया मन माने इसके उस कामके नहीं कर सकता है बल्कि कि वह दिवालिया क़ारार दिये जानेसे पहिले करता रहा हो।

दिवालिया इस प्रकार सुपुर्द किया हुआ जो काम करेगा उसकी आमदनी कर्त्तव्यार्थके लाभार्थ समझी जावेगा और उस पर रिसीवरका अधिकार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार उसका अधिकार दिवालियेकी और सब जायदाद पर है उपद्रव (१) में बतलाया गया है कि यदि दिवालियेने उसकी जायदाद बसूल करनेके सम्बन्ध काम लिया जावे तो उस कामके पूर्वजामे उसे कुछ भत्ता दिया जा सकता है परन्तु इस भत्तेको घटाना बढ़ाना या बन्द करना अदालतके अधिकारमें है और अदालत समय समय पर ऐसे भत्तेकी योजना कर सकती है।

उपद्रव (२) में यह भी बतलाया गया है कि अदालत दिवालियेकी जायदादसे दिवालिया तथा उसके परिवारके पोषणके लिये समय समय पर कुछ भत्ता दे सकती है परन्तु यह भत्ता भी ऊपर बतलाये हुये भत्तेके समान हर समय घटाना बढ़ाना बन्द किया जासकता है इस दफ़ामे बतलाये हुए भत्ते (Allowance) को देनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है।

यदि दिवालियेको तनखाह मिलनी होवे तो उसे कोई खास भत्ता देनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी तनखाह में से कान्येके मुआवज़े काया पानेका इम्तदाह है देखा—21 I. C. 950, 38 I. C. 410, 40 All. 211. परन्तु इलाहाबाद हाईकोर्टने इसके विरुद्ध 45 All 384 में यह तय कर दिया है कि अदालतकी अधिकार है कि वह दिवालियेको उस इमरे अधिभूते भी उसके तथा उसके परिवारकी पारवर्तिका लिये कुछ भाग भत्तेके रूपमें दिलवा देवे अर्थात् आर्था तनखाहके अतिरिक्त नक़्का आधी तनखाहमें भी उसे भत्ता दिलवाया जा सकता है अदालतकी यह भी अधिकार है कि जब चाहे इस भत्तेको घटा बढ़ा भी देवे तथा जब चाहे उसे बन्द कर देवे।

दफ़ा ६७ बचे हुए पर दिवालियेके अधिकार

अब कि सब कर्त्तव्यार्थोंके कर्त्ते पूर्ण रूपसे मय सुद्धके जैसा कि इस एक्टमें दिया हुआ है अदा हो जावे और उसके अनुसार की हुई कार्रवायिकां सर्व भी चुक जावे तो जो कुछ इस अध्यायकी शर्त बचेगा वह दिवालियेकी मिलेगा।

व्याख्या—

यदि दिवालियेने सब कर्त्तव्यार्थोंका कर्त्ता उसकी जायदादसे अदा कर दिया जावे तथा उनका सूर भी जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है उस दिया जावे और वह खर्च भी जो दिवालियेकी कार्रवाईके खिलतिमें किया गया है निवाह लिया जावे तो उसके बाद जो रुपया या जायदाद बचेगी उसे दिवालिया पानेवा दिवालिया बचे हुये रुपये पानेका अधिकारी है परन्तु वह रुपया उसी समय मिल सकेगा जब कि ऊपर बतलाई हुई तीनों शर्तें पूरी हो गई हों अर्थात्

(१) कर्त्तव्यार्थोंका पूरा रुपया चुक जावे

(२) इस एक्टके अनुसार बतलाया सूद अदा कर दिया जावे, और

(१) दिवालियेके निम्नलिखित शी हुई कार्रवाइयोंका सर्वे यत्न कर दिया जावे

इस एक्टकी दफा ४८ में मूत्र दिशाये जावका उल्लेख है तथा दफा ६१ में भी नाइ अदागी मत कर्षा जानेके दवाविका कगार दिखे जानेके बादका सुद दिग्गप जानेका उल्लेख है इस प्रकृति मत कर्षायाहोला कर्षा एक्टमें मत सूत्रके निमतका शिखर दफा ४८ व ६१ में है इत्यये जानेके बाद आ कर्षा बचेगा वही बचा हुआ बरता समझा जायेगा पन्तु इस बातका भी ध्यान रचना चाहिये कि दिवालियेके कार्रवाइके सम्बन्धमें जो सर्वे होंगे उन सबकी अदापयी भी दिवालियेकी जायदाद ही से ही जायेगी और तभी बरतन उन खर्चोंकी भी ऊदा कर देनेके बाद जो कर्षा गिनावके हयमें रह जाइया वही दिवालियेके निम्न लकैका अंगेजी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है निम्नमे यह प्रकट होता है कि दिवालिया ही अजका उन बचे हुए बचयेके पानेका अतिरिक्त है नह कर्षा किमी तैर सबकी नही दिया जा सकना है । इतना अवगत होना कि दिवालियेके न रदये पर उसके कस्तानिकागी उस बच हुए बचयेके पानेके अतिरिक्त होंगे ।

दफा ६७ (ए) जांचकी कमेटी

(१) अंशालतको अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो उन कर्षायाहोको जिन्होंने अपने कर्षाको साधित कर दिया है एक जांच करने वाली कमेटी बनानेका अधिकार देवे जिसने कि यह कमेटी रिसीवर द्वारा दिवालियेकी आयदादके प्रपन्थका निरीक्षण कर सके ।

(२) जांच करने वाली कमेटीके सदस्य वही कर्षायाहान हो सकेंगे, जिन्होंने अपना कर्षा साधित कर दिया है या जो ऐसे कर्षायाहानके मुहतर आम होंगे ।

(३) जांच करने वाली कमेटीको रिसीवर द्वारा की हुई कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित कर दिये जावें ।

व्याख्या—

यह दफा प्रारम्भिक कानून दिवालिया सक्षीपन एक्ट १९, सन १९२२ के अनुसार बढाई गई है इस एक्टके क्रि १ सितम्बर सन् १९१६ ई० को गवर्नरजनरल हिन्दु प्रदोश्यने अपनी स्वीकृत प्रदावकी थी । यह दफा इस कारण बनाई गई है कि जिसमें रिसीवरके प्रपन्थका अन्तर्गत जाति निर्गुण किया जा सके । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है निम्नमे यह प्रकट है कि अदागत जाव कमेटी नियुक्त करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् जाव कमेटीकी नियुक्तिके लिये आज्ञा अदागत उसी समय देखे जब कि उसे ऐसी कमेटीके नियुक्त करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो । ऐसी कमेटी बनये जानेका आज्ञा होने पर वह कर्षायाहान इस कमेटीको बनायेगे निम्नके कर्षा साधित लिये जा चुक है अर्थात् दिवालियेके हर एक कर्षायाहोके ऐसी कमेटी बनानेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न किसी और शक्क हो का ऐसी कमेटी बनानेका कोई अधिकार है ।

यह कमेटी गिनावके प्रपन्थका निरीक्षण करनेके लिये बनाई जावे । जिसमें कि दिवालियेकी जायदादका ठीक ठीक प्रपन्थ किया जासके तथा उसके निम्नका अधिक कर्षा वसूल किया जासके वसूल किया जावे और वह किसी प्रकार बर्बाद न हो सके ।

उपदफा (२) में यह बात भी साफ कही गई है कि जाव कमेटीके मेम्बर भी वही कर्षायाहान होंगे जिसका कर्षा साधित किया जावता है या उनके पुनराजम होंगे अर्थात् कमेटीके मेम्बर चाके अनिरित और कोई भा ग्याते नहीं हो सकेंगे । अंग्रेजी एक्टका इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिसमें यह प्रकट है कि जाव कमेटीके नियमका पालनी अवश्यकी जाना चाहिये ।

उपदफा (३) में यह नतलया गया है कि जाच कंटीको रिसीवरकी कर्तव्य पर बड़ी अधिकार होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों ।

रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

दफा ६८ रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

अगर रिसीवरके किसी काम या फैसलेसे दिवालिवा या कोई कर्जखवाह या अन्य कोई व्यक्ति असंतुष्ट होये तो वह अदालतमें उसके विरुद्ध दारख्वास्त दे सकता है और उस पर अदालतको अधिकार है कि वह रिसीवरके उस काम या फैसलेको बहाल रखे या पलट दे या संशोधित कर दे और ऐसा हुक्म मुसालिय समझे दे देये ।

लेकिन इस दफाके अनुसार इस प्रकारकी कोई शिकायत किये जाने वाले काम या फैसलेसे २१ दिनके बाद न सुनी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाका प्रयोग ऊर्दी मामलोंके सम्बन्धमें किया जासकेगा जो रिसीवरने दिवालिवाकी आयदादके सम्बन्धमें दिवालिवा की दारखानेके सिद्धमिलेमें किया हो दख्ता—39. All. 204, A. I. R. 1925 Bom. 283.

इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील करनेका अधिकार रिसीवरके किसी खास काम या हुक्मके लिये ही नहीं है किन्तु रिसीवरके किसी भी काम या हुक्मकी अपील इस दफाके अनुसार अदालतमें की जासकती है । इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे रिसीवरके किसी काम या हुक्मसे हानि पहुंचती हो अर्थात् दिवालिवा स्वयं इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, दिवालिवासे कोई भी कर्जखवाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है इसी प्रकार कोई और शाख भी जिसे रिसीवरके कामसे या हुक्मसे हानि पहुंचती हो इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है । ऐसी अपीलके होने पर अदालतकी अधिकार है कि वह रिसीवरके वह काम या हुक्मको जिसके विरुद्ध अपीलकी गई हो जैसेका तैसा बहाल रखे या उससे पलटदे या उसमें कोई संशोधन कर देवे । और साथही साथ जैसी आज्ञा वाचित समझे उसके लिये देदेवे ।

अंग्रेजी एक्टकी इस दफाके (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह बली भाति प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार अपीलकी जाने पर किसी खास हुक्मके देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना अदालतकी आज्ञा पर निर्भर है । अदालत शिवायत लिये हुए काम या हुक्म पर विचार करनेके पश्चात् तथा उसकी जाँच करके बाद समुचित जे आज्ञा देना सुनिश्चित समझे दे सकता है अर्थात् रिसीवरके काम या हुक्मसे जेमका तैसा बना रहने दे या उसे पलट दे या उसे संशोधित कर देवे । साथही साथ यदि वह कोई हुक्म हुक्म दिया चाहदे तो दे सकता है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार अपील २१ दिनके अन्दरही की जाना चाहिये अर्थात् जिस काम या हुक्मके विरुद्ध शिकायत होवे तो उसके होनेके बाद २१ दिनही के अन्दर उसकी अपील अदालतमें कर देवे अन्यथा शिवायत करने वालेको इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार जावा रहेगा । यदि रिसीवरका कोई काम भेवर्तिय होवे और उससे कर्जखवाहोंके हितोंको आघात पहुंचाता हो वा अदालत रिसीवरके ऐसे हुक्मको रद्द कर सकती है देवे—73 I.O 374

यदि किसी व्यक्तिने दिवालिवाकी किसी आयदादको रिसीवरसे छेदी हो तो वह इस दफाके अनुसार अदालतमें दारख्वास्त दे सकता है कि उसकी कोई मजूकी जाने तथा दूसरी खरीदारीकी मोटी रक क्लार देकर मजूर न की जावे । अदालतको ऐसी

दाएस्त इन दफ्ते अनुसार सुननेका अधिकार है । इस लिये कोई नाकायदा मुकदमा चलानेकी आवश्यकता नहीं है देवो—
66 I. C. 524.

यह दफा ऊर्ध्व रिश्वरको कर्मा या हुक्मों का देवोगी जो इन एकडे अनुसार नियुक्त लिये गये हो और यदि कोई रिश्वर नाकायदा नियुक्त न किया गया हो तो उसके कर्मोंके सम्बन्धमें यह दफा लागू नहीं समझना चाहिये देखो—A. I. R 1924 Mad. 461.

यदि इस दफाके अनुसार अदालत कोई हुक्म देवे तो उन हुक्मोंकी अन्तिम हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसकी अपीलकी आवश्यकता है देखो—40 Mad 752.

यदि इस दफाके अनुसार करिवार्ड करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध नहीं है इसलिये यदि कोई व्यक्ति नियत किये हुये समयके अग्र इन दफाके अनुसार दिवे हुए काम या हुक्मकी अपील आशुक्रममें न करे तो वह उसके परवाह भी रिश्वरके विरुद्ध मामूली दीवानीका मुकदमा दायर कर सकता है यदि उसे उस हुक्म या कामसे हानि पहुँचती हो अथवा दूसरी इस दफाके (May) का दफा प्रयोग किया गया है निम्नमें यह प्रगट है कि यदि हानि उठाने वाला व्यक्ति चाहे तो इस दफाके लाभ उठा सकता है देखो—A. I. R 1924 All. 40-16 All. 16. जब कि दिवालियेकी करिवार्ड समाप्त हो चुकी हो तो हरिकोटको कोई अनिश्चय नहीं है कि वह आकिशुन रिश्वरके व्यवसायी या व्यवसायीकी दीवानी करिवार्डमें उठे अपिचार है कि किसी खास काममें वह जज दिवालियेको सहाय आदि देवे देखो—A. I. R 1927 All. 260.

यदि रिश्वर किसी कर्तव्यवाहके कहने पर कोई काम न करे या उसके करनेसे इन्कार कर देवे तो केवल अपनी ही बातकी दिवालियेका काम इस दफाके अनुसार नहीं माना जावेगा । देखो—47 Mad. 673.

यदि रिश्वर दफा ५३ या ५४ के अनुसार करिवार्ड करनेसे इन्कार कर देवे तो कर्तव्यवाहको इस दफाके अनुसार अपील करनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु वह स्वयं भी उन दफाओंके अनुसार अदालतसे करिवार्ड कर सकता है । देखो—
दफा ५४ (५) इस दफाके अनुसार करिवार्डकी अन्तिमके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई न कोई दाएस्त अवश्य हो जावे यदि अदालत चाहे तो स्वयं भी रिश्वरके किसी काम या हुक्ममें पकड़ सकती है या सहायित्व कर सकती है और ऐसा करनेमें इस दफाके कोई बाध नहीं पड़ेगी देखो—1 Lah. 307-58 I. C. 6.

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई भी व्यक्ति निम्न रिश्वरके काम या हुक्मसे हानि पहुँचती हो इन दफाके अनुसार अदालतसे अपील कर सकता है । हानि पहुँचनेसे अभिप्राय यह है कि उसे कानूनी हानि पहुँचती हो यह नहीं कि वह हुक्मके हो जानेकी वजहसे उसके आपदाके किसी लाभमें बाध पड़ेगी । यदि रिश्वरके किसी कामके कारण कोई व्यक्ति बाधग्रस्त पड़ेगा तो उसे इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार है, देखो—51 I. C. 118. इस कारण यदि कोई उल्लंघन न पकड़ी हो या कोई कानूनी हानि न होती हो तो दफा ५८ लागू न होगी ।

एक घुमटिनने अपनी डिग्रीमें रहनेकी हुई जायदादकी नीजाममें खरीद किया और इसके परवाह करनेदार मद्रास दिवालिया अदालतमें दायर किया गया तथा उसकी जायदादके लिये रिश्वर नियुक्त कर दिया गया । रिश्वरने उस घुमटिन द्वारा खरीदकी हुई जायदादकी बेचना चाहा तो यह तय हुआ है कि घुमटिनने रिश्वरके इस कामसे कोई कानूनी हानि पहुँचती है क्योंकि यह जायदाद दिवालियेकी नहीं है और यदि रिश्वर ऐसी जायदादको बेच भी देवे तो इसमें घुमटिन खरीदारके हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा अर्थात् इस प्रकार जायदादका बेच माना एक किञ्चन काम होगा देखो—20 I. C 683 यदि रिश्वर किसी कर्तव्यवाहके कर्मोंमें बाध न करे तो ऐसे कामसे उस कर्तव्यवाहकी हानि समझना चाहिये और वह कर्तव्यवाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, देखो—78 I. C. 857. यदि आकिशुन रिश्वर यह तय करे कि दिवालियेको कोई

करी अदा करना है तो ऐसे हुक्मसे दिवालियेको हानि पहुँचती है और इसकी अपील इत दफाके अनुसार की जा सकती है, देखो—62 I. C. 441.

यदि रितीवर किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादको दिवालियेकी जायदाद समझ कर ले लेवे तो वह व्यक्ति जिसकी जायदादकी कोई है इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है देखो—36 All 8, 35 All 410, 47 I. C. 62 (Cal)

परन्तु यदि रितीवर किसी दूसरेकी जायदादको दिवालियेकी जायदाद कतार देकर बँच देवे तो दिवालियाको इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार नहीं है क्योंकि उसको इस मामले कोई हानि नहीं पहुँचती है, देखो—41 All. 243, 49 Mad 461.

मराठ हार्बोर्टने एक मामलेमें यह भी तय किया है कि यदि मित्राक्षर परिवारके पिताने कोई जायदाद बँचती होवे और अदालत उस मरणागामी भंखूज कर देवे तो उसके रुककोंकी यह अपील नहीं होगी कि वह रितीवर द्वारा उस जायदादके सम्बन्धमें भी जाने वाली किसी कार्रवाईमें रुकावट काज सके, देखो—A. I. R. 1927 Mad. 282.

यदि रितीवर किसी और शख्सकी जायदाद पर मन्तीसे कब्जा कर लेवे तो उस और शख्सके लिये दो तर्गके खूले हुए हैं, वह इस दफाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है और अगर वह चाहे तो अदालत दिवालियामें कोई कार्रवाई न करे किन्तु वह मामूली दीवानी अदालतमें अपनी जायदादकी वापिसके लिये दावा उस प्रकार कर देवे जैसे कि अनधिकार कब्जा करने वालके विरुद्ध दावा किया जाता है, देखो—39 All. 626, 40 I. C. 122; 41 All. 378, A. I. R. 1924 Oudh 294

इस दफाके अनुसार अपील उसी अदालतमें की जाना चाहिये जिस अदालतने रितीवरकी नियुक्त किया हो यदि रितीवरने किसी जायदादको दिवालियेकी जायदाद कतार देकर उसने नौगणकी घोषणाकी हो और कोई दूसरा व्यक्ति जिसने दिवालिया कतार दिये जानेसे पहिले उस जायदादको दिवालिपमे खरीदा हो, इस दफाके अनुसार दरखास्त देवे परन्तु उनकी दरखास्त २१ दिनों बाद हानके कारण खारिज कर दी जावे तो इसने यह नहीं समझना चाहिये कि उस व्यक्तीने इस दफाके अनुसार कार्रवाई करली है किन्तु वह व्यक्ति अदालत दीवानामें रितीवरके विरुद्ध दावा दायर कर सकता है, देखो—44 All. 620. परन्तु 47 Bom 548. में यह तय किया गया है कि यदि रितीवर दिवालियेके कर्तव्योंके विरुद्ध कोई हुक्म दे देवे तो वह लोग इसी दफाके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं तो उनकी दूसरा मुकदमा चलेनेका अधिकार नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति इस दफाके अनुसार कार्रवाई करेगा तो उसे मुकदमा दायर करनेका हक नहीं रहेगा और यदि वह मुकदमा दायर करेगा तो उसे इस दफाके अनुसार कार्रवाईकी आवश्यकता नहीं है अर्थात् वो में से एकही प्रकारकी कार्रवाई की जा सकती है, देखो—41 All. 378.

यदि अदालत इस दफाके अनुसार किसी प्रश्नको तय कर देवे तो द्वारा उस प्रश्नको तय करनेके लिये कोई दूसरा मुकदमा नहीं चलाया जावेगा क्योंकि वह अमानतका फैसला आखिरी फैसला समझना चाहिये और उसे अन्न तन्वीन शब्दा (Resjudicata) समझना चाहिये, देखो—39 All 626, A. I. R. 1923 All 293. परन्तु इस प्रश्नके लिये सन हार्बोर्ट एक दूसरेसे सहमत नहीं हैं बल्कि हार्बोर्टने यह तय किया है कि यदि अमानत दिवालिया क्रिमी ऐसी जायदादके सम्बन्धमें किये हुए एग्राजकी नामजूर कर देवे जो दिवालियेकी जायदाद कतार देकर कुर्क व नौगणकी गई हो तो हाने वाले फीकको अधिकार है कि वह अपने हुक्मों तय करनेके लिये वाकयाद नालिया दायर कर सकता है, देखो—A. I. R. 1923 Lah. 224.

इस बातके लिये कोई मतभेद नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जिस रितीवरके काम या हुक्मसे हानि पहुँची होवे इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियासे अपनी शिकायत शुरू करनेको न करे तो उसे मामूली दीवानाका काम दायर करके अपनी

सिद्धांत दूर करनेका अधिकार है, देखो—46 All. 16 यदि दिवालिया किसी नायदादके बेंचे जानेमें एतदात करे और रिसीवर उस एतदातका बिला कुछ स्थान्त लिये उस नायदादको बेंच देवे और इसके पन्नात् रिसीवरके इस कामके विशुद्ध अदालतमें कोई एतदात न किया जावे तो दिवालिया दुबारा उसी बिना पर इस बयनामें के विरुद्ध यह नहीं कह सकता है कि यह बयनामा चरत किया गया था, देखो—A. I. R. 1924 Mad. 147.

इस दफाके अनुसार तहसीलान करने समय यह आवश्यक नहीं है कि अदालत दुबारा शहदत लेवे किंतु वह रिसीवर द्वारा ली हुई शहदत ही पर विचार कर सकती है और न रिसीवरको उस दुरवदास्तके विषे फरीक मुकद्दमा ही बगना करती है, देखो—A. I. R. 1924 Mad. 830.

परन्तु जहाँ तक होमके अदातको रिसीवर द्वारा ली हुई कॉर्वाइ पा विवाम न जाना चाहिये किंतु उसे स्वयं दोनों फरीकोंकी बात समझ चाहिये तथा आवश्यकानुसार तहसीलान भी करना चाहिये जिसमें कि ठीक इन्ताफ किया जासके देखो—39 All. 626. यदि कोई नाकायदा मुकद्दमा इस बातके लिये चलाया जावे कि जो नायदाद रिसीवरने बेंचा है उसमें दिवालिबेका कोई हक नहीं था तो रिसीवर उस मुकद्दमके लिये एक जरूरी करीक है और अदालत दिवालियाकी आशा लिये बिना वह फरीक मुकद्दमा बगना जासकता है, देखो—46 All. 16.

इस दफाके अनुसार दुरुजान देनेके लिये २४ दिनों मियाद नियत की गई है डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात् अदालत दिवा-
लियाको २४ दिनों पहिले रिसीवरकी रिपोर्ट मजूर करनेका अधिकार नहीं है परन्तु फरीकनकी सजाय पर इसमें पहिले भी रिपोर्ट मजूर की जासकती है २७ दिनों अन्दर यदि किसी कर्तबवाह आदि को कोई एतदात जाना हो तो वह एतदात कर सकता है जिसमें वह रिपोर्ट बदला जायके या उसमें समायोजन किया जासके, देखो—A. I. R. 1926 Cal. 826. अदालत दिवालियाकी कोई अधिकार नहीं है कि वह रिसीवर द्वारा किये हुए बयनामों पर समुच्च कर देवे जबनक कि प्रोसेकुटिव साजिश, खास बेनतीरी, बेंचनेमें बड़बड़ी या बेउतमानों न साबित होजावे जिसकी वजहसे नायदादों दुस्मान पहुँचता हो या जब कि रिसीवरने अपने अधिकारोंसे बाहर उस सीदेकी न किया हो, देखो—A. I. R. 1928 Rang 60; 107 I. C. 172.

चौथा प्रकरण

दण्ड (सजा)

दफा ६९ दिवालियेके जुर्म

अगर कोई कर्जदार दिवालिया कपार दिये जाने पाछे हुक्मके होनेसे पहिले या उसके बाद—

(ए) दफा २२ के अनुसार बताये हुए अपने कर्तव्योंको जानते हुए नहीं करता है या अपनी जायदादके किसी हिस्सेका कब्जा जो उसके कर्जवाहोंमें इस एक्टके अनुसार बचना चाहिये और जो उसके कब्जे या निगरानीमें है अदालतको या अदालत द्वारा कब्जा लेनेके लिये नियुक्त किये हुए किसी दूसरे व्यक्तिको नहीं देता है; या

(बी) घोखा देहीसे अपने कानकी हालत छिपानेकी इच्छासे या इस एक्टके अनुसार काम न होने देनेकी इच्छासे—

(i) किसी दस्तावेजको जिसका इस एक्टके अनुसार होने वाली सहकीकातसे सम्बन्ध हो बरपाद कर दिया हो या जान बूझ कर रोक दिया हो या जानते हुए पेग न होने दिया हो, या

(ii) झूठी किताबें रखी हों या रखवाई हों, या

(iii) किसी दस्तावेजमें जिसका सम्बन्ध इस एक्टके अनुसार होने वाली सहकीकातसे है ग़लत इन्द्राज कर लिये हों या किसी इन्द्राजको न किया हो या जान बूझ कर इन्द्राजको बदल दिया हो या ग़लत कर दिया हो, या

(सी) घोखा देहीसे अपने कर्जवाहोंमें तक़सीम किये जाने वाले रुपयेको कम करनेकी गरज़से या अपने किसी कर्जवाहको बेजा कायदा पहुँचानेकी गरज़से—

(i) उस कर्जवाहके कर्ज़को चुका दिया हो या उससे लेने वाले कर्ज़को छिपाया हो, या

(ii) अपनी किसी क्रिमकी जायदादको अलहदा कर दिया हो, या उस पर बार कर लिया हो या उसको छेद कर दिया हो, या छिपा लिया हो,

तो जुर्म साबित होने पर उसको एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी।

न्याय्य—

रिपेयिंग एक्ट १९२७ [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] के अनुसार अंग्रेजी देशमें इस दफाके आद्वारे "By the Court" यह शब्द हटा दिये गये हैं अर्थात् पहिले यह था कि जुर्म साबित होने पर (अदालत द्वारा) ब्रह्मणे एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी अब "अदालत द्वारा" यह शब्द नहीं रहे गये हैं।

इस दफ्ते दिवालिये द्वारा किये जाने वाले अपराधों तथा उनके होने पर जो दण्ड दिया जानेको है उसका वर्णन है । इस दफ्ते में उन सब कार्योंको उल्लेख है जो इस दफ्तेके अनुसार दण्डनीय अपराध समझे जाने चाहिये ।

इसमें दिये हुए अपराध एक प्रकारसे कायदेके अनुसार वर्णन करनेके अपराध हैं यह उन अपराधोंकी भांति नहीं हैं जैसे कि फौजदारीके लम्बे हमले हैं देखो—39 All. 171; 54 I. C 740. इस दफ्ते में बतलाये हुए अपराध यदि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किये गये हों चाहे वह दिवालिया करार दिये जानेके बाद किये जावे दोनों दशाओंमें सब दण्डनीय होंगे । यह बात भली भांति प्रकट नहीं है कि 'पहिले' से अभिप्राय कितने समय पहिलेसे है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेसे चाहे मितना पहिले इस दफ्ते में बतलाया हुआ अपराध किया गया हो वह दण्डनीय अपराध ही समझा जावेगा परन्तु जिन अपराधोंका उल्लेख है उनसे यह प्रकट होता है कि अधिकतर दिवालियेके मामलोंकी तत्कीर्तके सम्बन्धमें जो मसले पेश आयेगे वही दण्डनीय समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1927 All 352.

अदालतसे इस दफ्तेके अनुसार पारिवार्थिकी समय भी कहीं जासकती है और उस वक्त अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि आया दिवालियेके दण्डसम्बन्ध अपराध किया है या नहीं वह आवश्यकता नहीं है कि जब दिवालिया मसल होनेकी (Discharge) दस्तावेज देवे तभी उसके अपराधोंका फैसला किया जाना चाहिये, ऐसी—49 I. C 55

मसलान (ए) इस क़ानूनमें दो प्रकारके मामलोंका उल्लेख है एक तो यह कि दिवालिया जानबूझ कर पृष्ठा १९ में बतलाये हुए कर्तव्योंका पालन न करे व दूसरे यह कि वह जानबूझ कर जावदारीका क़ब्जा अदालत या रितीवरकी न देवे । जिन मामलोंका उल्लेख इस क़ानूनमें है वह वही समय अपराध समझे जासकेंगे जब कि दिवालियेके जानबूझ कर उस कामकी किया हो ।

जिस जायदादके क़ब्जा देनेका प्रश्न इस क़ानूनमें किया गया है वह ऐसी जायदाद होना चाहिये जो कर्तव्यस्थानमें बन्दी जासकती हो तथा वह जायदाद उस समय दिवालियेके क़ब्जे या अधिकारमें होवे पृष्ठा १८ में उन जायदादोंका जिक्र है जो कर्तव्यस्थानमें बन्दी जासकती हैं । जो क़ब्जा रखे पृष्ठा ६६ में जमा है वह इस प्रकार बांटा जासकता है इस लिये ऐसे क़ब्जेके सम्बन्धमें यह क़ानून लागू नहीं समझना चाहिये, देखो—44 Bom. 673. इसी प्रकारकी बात दूरकी जायदाद, पोलिटिकल पेशान तथा क़ानूनकारी ज़मीन आदिके लिये समझना चाहिये ।

क़ब्जा (बी) इस क़ानूनमें जिन कार्योंका उल्लेख है वह वही समय अपराध समझे जावेंगे जब कि दिवालियेके वकील आये अमली हालतकी डिप्लोमके मसाले किया हो या इस दफ्तेके अनुसार होने वाली कार्रवाईको रोकनेकी मसाले किया हो और वह काम घोषादेहीकी ओरतसे किये गये हों । इस क़ानूनके अनुसार यदि कोई ऐसी दस्तावेज बाधना करदी जावे या पेश न होने दी जावे जिसका सम्बन्ध दिवालियेके मामलोंसे हो तो यह अपराध समझा जावेगा । दस्तावेजका बर्बाद किया जाना उसी समय मान्य जासकता है जब कि उसका होना साबित कर दिया जावे इसी प्रकार किसी दस्तावेजके पेश होनेका प्रश्न भी उसी समय उपस्थित हो सकेगा जब कि यह साबित हो जावेकि कोई उस प्रकारकी दस्तावेज मौजूद है । इस क़ानूनके दूसरे भागमें यह बतलाया गया है कि यदि पृथी किनारे रखी या रखवाई जावे तो वह भी अपराध है । तीसरे खण्डमें ग़लत इन्दागना करना तथा किसी इन्दागनाक ग़लबक कर देना भी लम्बे मसाला मसाला है परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है यह सब बातें उसी समय लम्बे मसाला जावेंगी जब कि घोषादेहीकी मसाले दिवालियेके अपने मामलोंके डिप्लोम अपराध इस दफ्तेके अनुसार पारिवार्थिकी केकर कर्तव्यों मसाले किया हो ।

क्लाम (सी) इस क्लाममें बताया है कि कार्य उसी समय अपराध समझ जावगे जब कि दिवालिगन धोखादेहीकी मशाले करनेवालोंमें बाँटी जाने वाली रकमको कम करनेकी मशाले बिधा हो। अथवा इस मशाले किया हो कि जिसमें उसके किसी खास करनेवालों केना लाभ पहुँच जावे। इस मशाले पाँच मामलों यह बालाया गया है कि यदि दिवालिया अपने छाने या देने वाले कर्षक, डिपॉजि या ठम घुका देवे तथा दूसरे भागमें यह बताया गया है कि अगर वह अपनी जालदारकी बिधावे या उसे हथिये या उसे रेलन करद अथवा उस पर कोई बार हो जाने दे तो दोना दशाओंमें ऊपर बताये हुये गतेके पूरा होने पर इस प्रकारके काम दण्डनीय अपराध समझे जावगे। यदि कोई अपीक दिवालिगनकी दशा होवे या अपनी दूरानसे पाछ इस मशाले हथिये कि जिसमें उसके करनेवाहन उस पाछवा न पासेके तो ऐसे कामका अपराध समझना चाहिये, देखो—A. I. R. 1927 All. 352. यदि हा दफामें बताया हुआ कोई अपराध साबित होवे तो अपराधीको (बचते कारावास का दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बताया गया है कि वास्तवानका दण्ड कतार (Rigorous) दण्ड होना चाहिये अथवा साधारण (Simple) परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मान्य होता है कि दोनों प्रकारका दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बताया गया है कि जिसक कहने पर इस दफाके अनुसार कारावासी जावेगा। ऐसा मान्य होता है कि अदालत स्वय ही किसी कर्मचारीके कहने पर इस दफाके अनुसार कारावासी पाछ कर सकती है देखा—14 All. 145. रिजिस्टर भी अदालतन इस दफाक अनुसार दिवालिगनके निरुद्ध करानाई पाछ करेगा कह सकता है।

इस प्रकार अपराधी ठहरानेके लिये बाकायदा मामला चलाया जाना चाहिये और जो जुर्म छपाया जावे उसके साबित होने पर दिवालिया दोरी ठहराया जाना आर तभी वह दण्डका भागी होगा। उसको चहिले यह बतला दिया जाना चाहिये कि उसने कौनसा अपराध किया है जिसमें उसे बाका जमानदारीका पाका भिन्न जावे, देखा—17 Cal. 209

यदि अदालतकी इस बाइका विश्वास हो जाव कि दिवालिगने इतदफाके अनुसार जर्म किया है तो अदालत इन प्रकारका फैसला लिख सकती है तथा किसी कस्टे क्रास मजिस्ट्रेटके पास जिसकी अधिकार सीमा में वह मामला हुआ हा उस मामलाके थालू करनेके लिये भेज सकती है देखो दफा ५०।

दफा ७० दफा ६९ का जुर्म लगाने पर कार्रवाई

जब कि अदालतको आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक जांच करनेके पदचाल विधियास हो जावे कि दफा ६६ में बतलाये हुये अभियोगोंमें से किसी अभियोगकी जांच होना आवश्यक है और वह अभियोग दिवालिये द्वारा किया हुआ प्रतीत होता है तो अदालत अपनी तजवीज इस बातके लिये लिख सकती है और उस जुर्मका इस्तगाल लिखकर उस अग्रचल वर्जके (First Class) मजिस्ट्रेटके पास भेज सकती है जिसकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) होवे और वह मजिस्ट्रेट उस अभियोगका उसी ढंगसे सुनेगा जैसा कि सन् १८६८ ई० के जायदा फौजदारी (The Code of Criminal Procedure 1898) में बतलाया गया है।

दियालिया—

दफा ६९ में बताया है कि ठहरावों तहकीकत किय जानेवा नियम इस दफामें बताया गया है। यह दफा नहीं है और दिवालिया सशायन एक्ट सन् १९२६ ई० के अनुसार पुराना दफाके बजाय रखा गई है। इस दफाक बजाय जानसे पुराने नियममें एक कडा परिवर्तन सा हो गया है क्योंकि पिछली दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको भी अधिकार था कि

बहु दफा ६९ में मनगये हुए जुर्माने लिये जाने पर उनका तहकीकात कर लके तथा अधिपुनर्क होना निर्धारित होने पर उसे दण्ड दे सके परन्तु इस दफाके अनुसार उसे केवल प्राथमिक ज्ञान ही करनेका अधिकार है न इसके परवार्तु वह अधिकार रखने वाले फरमान्त मजिस्ट्रेटक पास मामलेको भेज सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे बात धर्मोनी जो पिछली दफामें थी वह यह है कि कानून दिवालयिके अनुसार किसी जुर्माने लगाये जानेसे पहिले उसमें नोटिस दिवालयिके दिया जाना आवश्यक था परन्तु इस नई दफाके अनुसार बिना ऐसे नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है यदि अदालत आवश्यकतानुसार प्राथमिक ज्ञान करनेके पश्चात् अतन समझे कि अभियोग चालमा जाना चाहिये तो वह मामलेकी चार्ज करनेके लिये मजिस्ट्रेटके यहा भेज सकता है। पिछली दफा नीचे दी जानी है जिसके देखनेम पाठकोंतो दोनों दफाओंका करक भली भाँति विदित हो जावेगा।

पिछली दफा ७० जो रद्द की जाचुकी है:—

दफा ७० दफा ६६ के अनुसार लगाये हुए अभियोगकी कार्रवाई

(१) जब कि अदालतको यकीन हो जाये कि दफा ६६ में दिये हुए किसी जुर्मानेकी तहकीकात करनेकी वजह (जकरत) है तो अदालत हुक्म देगी कि कर्जदारको नोटिस इस बातका दिया जाये कि यह वजह जाहिर करे कि उसके खिलाफ एक या उससे अधिक जुर्माने क्यों ल लगाये जायें तथा यह नोटिस इस प्रकार भेजे जावेंगे जिस प्रकार सम्मन ज़ाबता दीधानी के अनुसार भेजे जाते हैं।

(२) नोटिसमें जुर्माना (मुद्दआ) बताया जावेगा और एरुही नोटिसमें एकसे अधिक जुर्मानोंका हवाला दिया जासकता है।

(३) उस नोटिसके अनुसार समाप्त करते समय और उसके अनुसार लगाये हुए जुर्मानेकी समाप्त करते समय अदालत जहाँ तक हो सकेगा उस प्रकार कार्रवाई करेगी जैसा कि सन् १८६७ ई० के जायता फौजदारीके २१ वे प्रकरणमें चारण्ट क्लेज (मानलॉ) के लिये जिनकी सुनवाई हाइकोर्ट या लेगल कोर्टमें होती है दी हुई है।

(४) इस दफाके अनुसार चाहे जितने जुर्माने हों सब एक साथ लगाये जासकते हैं। परन्तु किसी कर्मदारको इकट्ठा दो सालसे ज्यादाके लिये सज़ा नहीं दी जासकेगी जबकि उसम उसी दिवालयिकी कार्रवाईके तिलसिलमें इस एन्रके अनुसार जुर्माने किये हों।

(५) अदालतको अधिकार है कि वह दफा ६६ के अनुसार किसी जुर्मानेकी तहकीकात स्वयं करनेके बजाय उसका इस्तगाला लिखकर सबसे नजदीकी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (दर्ज ऑफ़िस) के पास जिसे अधिकार समाप्त होवे भेज सकती है और उस हालतमें वह मैजिस्ट्रेट उस इस्तगालाको उसी प्रकार सुनेगा जिस प्रकार सन् १८६८ के ज़ाबता फौजदारीमें दिया हुआ है। परन्तु उसमें मुस्मगील (वादी Complaint) का बयान लेना जरूरी नहीं है।

व्याख्या—

पहिली जनवरी सन् १९२७ ई० से एक् ९ सन् १९२६ ई० गवर्नर जनरल हिन्दु मसौदामें आजातुमार कार्यान्वित किया गया था और तभीसे ऊपर दी हुई पुरानी दफाके बजाय नई दफाला प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

चूकि सिविल जस्टिस कमेटीने यह समझा कि हाईकोर्ट तथा अदालत चिलाना समय दफा ६९ में बतलाये हुए छठे मोटे प्रयोगी तहकीकातमें बहुत नष्ट होगा तथा यह बचिन समझा कि ऐसे खर्चोंकी जाव बन्धनी तारते फर्दे प्राप्त मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इस कारण तथा अन्य भी बहुत सा बातोंका सोचव हुए पुरानी दफाके बजाय इस नई दफाका प्रयोग में लाया जाना उन लोगोंकी अनुमतिमें उचित प्रतीत हुआ तथा यह नई दफा निर्माणितकी गई । चूकि दफा ६९ में बतलाये हुए खर्च एक प्रकारसे फाजदाराव खर्च हैं इस कारण उन खर्चोंका तहकीकात या जावना फाजदारीक नियमोंके अनुसार होना बतलाया गया है अदालत दिवालिया इस दफाके अनुसार किसी मामलेकी तहकीकात मजिस्ट्रेटके सुपुर्द करनेके लिये बाध्य नहीं है और जब उसको विश्वास हो जाव कि दिवालियाने दफा ६९ में बतलाये हुए खर्चों में से किसी खर्चको चाहिए तौर पर किया है तब वह मजिस्ट्रेटके पास मामला भेज सकती है । अपने विश्वास करनेके लिये अदालत दिवालियाकी अधिवार है कि वह प्रारम्भिक जाव कर उब इस दफाक अनुसार यह आवश्यक है कि अदालत दिवालिया तहकीकात शिवायन उस खर्चकी मजिस्ट्रेटके पास भेजे । मजिस्ट्रेट दर्जो फ्लवला होना चाहिये अर्थात् इस दफाके अनुसार दर्जो दीपम व सोषमके मजिस्ट्रेट तहकीकात नहीं कर सकते हैं और उभा मजिस्ट्रेटके पास मामला जाना चाहिये जिसका अधिवार सीमा (Jurisdiction) होवे । जब इस दफाके अनुसार कोई मामला मजिस्ट्रेटके पास भेजा जावे तो मजिस्ट्रेटका कर्तव्य होगा कि वह बतली जाव जावना फाजदाराके नियमोंके अनुसार करे । अमेजी एक्टकी इस दफा में "shall" शब्द प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि मजिस्ट्रेटकी ऐसे मामलोंकी जाव अवश्य करना चाहिये तथा उसकी जाव जावना फाजदारीमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है किमी दिवालियेके विरुद्ध मामला चाड करनेसे पहिले अदालतकी इस बातका विश्वास कर लेना चाहिये कि प्रकट रूपम उसन अवश्य उस खर्चको किया है केवल शरही पर यह फाजदाराका मामला चाड नहीं करना चाहिये, देखो—A. I. R. 1926 Mad 1159.

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि अदालतको इस प्रकार इस बातका विश्वास करना चाहिये कि दिवालिये द्वारा खर्च किया गया है इससे यह प्रकट होता है कि या तो अदालत मिलिक (Record) से ऐसी बातका विश्वास कर सकती है या किसी फरीकम इसका विश्वास कर सकती है प्रारम्भिक जाचमें वह दूसरोंसे भा पूछ ताड करके इस प्रकारका विश्वास कर कर सकती है । इस दफाके अनुसार फाजदारी बादायदा अमलमें लाई जाना चाहिये अर्थात् दिवालियेको लाहना हाइकोर्टके आधारकी पर अभियुक्त निर्धारित करना चाहिये जहाँ गवाहोंकी शहादत मानना चाहिये जिससे दिवालियेको जित करनेका अवसर दिया गया हो । इसीवरकी रिपोर्ट बी कि उसने दिवालियेके विरुद्ध दो हा दिवालियेको दफा निर्धारित करनेके लिये पर्याप्त नहीं है तो उस रिपोर्टके आधार पर तदवस्थके बहाल (Discharge) होने में तथा तत्समीपा आदि होने में अमर पक सकता है, देखो—46 All 864, A. I. R. 1926 All. 29, 37 All 429. फर्दे खर्च भी ताक उसी दफाकी भावमें लगाया जाना चाहिये जिसम इस जुमका उल्लेख है और उसमें दिवालियेके बस कामका निक होना चाहिये, जिसके अगर पर वह खर्च लगाया जा रहा हो देखो—A. I. R. 1927 All 852

अदालत दिवालियाका अधिवार है कि वह दफा ७० के अनुसार प्रारम्भिक जाव करे या न करे और अगर वह जाव करना निश्चित करे तो वह ऐसा जाव कर सकती है जिसमें उसे निश्चिन्त हो जावे कि दफा ६९ का कोई अपवाद किया गया है । मजिस्ट्रेट दफा ७० व अनुसार अदालत एवतका भी हुक्म दे सकता है तथा दिवालियेकी नामाचरणियों भी इस दफाक अनुसार हुक्म दिया जा सकता है जब कि जिस कर्त्तव्याहने शिवायतोंकी दखलान दी हा और जजन दानो फराकोक बगिनोंकी वाम सुनन तथा रिशिकरवा रिपोर्ट देखोकर पश्चात् दिवालिये पर मामला चलाये जाना हुक्म दे दिया हो तो ऐसी दशामें यह तय हुआ कि जजने जिस तरीकसे काम किया है वह जातान्व उचित तरीका है, देखो—55. Cal 783, A. I. R. 1928 Cal 211.

दफा ७१ बहाल होने या तस्फीया होजानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी

अगर दिवालिया दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंका मुजरिम है तो उसके खिलाफ ऐसे जुर्मोंकी कार्रवाई की जायेगी चाहे वह बहाल हो चुका हो या तस्फीया हो गया हो या स्कीम मानली गई हो या मंजूर हो गई हो ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियाके बहाल हो जाने पर या उसके मामलेश तस्फीया आदि हो जाने पर भी दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंकी तदर्थकार्रवाई नामकती है । अर्थात् यदि दिवालियेने कोई छप दफा ६६ के अनुसार किये हैं तो वह उनमें रिहा हलतमें नच नहीं सकता है चाहे वह बहाल ही क्यों न हो गया हो या उसका मामला आपसमें तय हो कर समाप्त हो क्यों न हो जावे ।

दफा ७२ बिला बहाल किया हुआ दिवालिया अगर कर्ज लेवे

(१) अगर कोई बिला बहाल किया हुआ दिवालिया किसी शख्ससे बिला बतलाये हुए कि वह दिवालिया है पचास रुपये या उससे अधिक कर्ज लेवे तो उसके खिलाफ यह जुर्म साबित होने पर उसे मजिस्ट्रेट छः महीने तदकी सज़ा या जुर्मानकी सज़ा या दोनों सज़ायें दे सकेगा ।

(२) जब कि अदालतको विश्वास हो जाये कि किसी बिला बहाल हुए दिवालियेने उपदफा (१) में दिया हुआ जुर्म किया है तो वह मुनासिब इस्तइरा तदकीकार्रवाई करनेके बाद मामले को फैसलेके लिये सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट दफा अव्वलके पास भेज सकती है और मुलाजिम को भी हिरासतमें भेज सकती है या उससे उस मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर होनेके लिये फाफ़ी जमानत ले सकती है और किसी दूसरे शख्सको भी उस मुकदमेमें हाज़िर होने या ध्यान देनेके लिये बाध्य कर सकती है ।

व्याख्या—

(१) इस दफामें यह बतलाया गया है कि बिना बहाल किया हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिने (५०) पचास रुपये या उससे अधिक उधार नहीं ले सकता है अब तक कि उधार देने वाले व्यक्तिने वह यह प्रष्ट न कर देने कि वह दिवालिया है तथा बहाल नहीं हुआ है । एक प्रकरणमें यह दफा उन लोगोंकी रक्षाके लिये बनाई गई है जिनको दिवालियेके दिवालिया करार दिये जाने अथवा उसके बहाल होने आदि का इन्ग नहीं हुआ हो अर्थात् जिनमें दिवालिया ऐसे व्यक्तियोंको धोरा देकर उत्ते रूपया वसूल नहीं कर सके । इस दफाके अनुसार जुर्म साबित होनेके लिये केवल इतना ही साबित होना आवश्यक है कि दिवालियेने बिना अपनी हालत बतलाये हुए (५०) पचास रुपये या उससे अधिक कर्ज किसीसे लिया है इस बातके साबित होनेकी आवश्यकता नहीं है कि दिवालियेकी मशत पोछादेनेकी थी या इस बातके साबित होनेसे वह बच नहीं सकता है कि उसे बहुत जरूरत थी इस बातमें उम्मेद इस प्रष्ट किया था । यदि बात भी इस दफामें प्रष्ट होती है कि यह पचास रुपयेका कर्ज किसी एकही व्यक्तिने लिया गया हो अर्थात् यदि दिवालियेने थोडा थोडा रूपया कई व्यक्तियोंसे लिया हो और वह सब मित्र कर (५०) पचास रुपयेमें उभर होने होवे तो यह बात इस दफाके अंतर्गत नही आवी है । इस दफाके

अनुसार जर्म साबित होने पर दिवालियेको ६ मास तकका कायवामका दण्ड दिया जासकता है या उस पर केवल जर्मानादा किया जासकता है अथवा कायवास व जर्माना दोनों सजायें साथ साथ भी दी जासकती है ।

(२) में यह नतलाया गया है कि अदालत दिवालिया प्रारम्भिक पाच करनेके बाद विश्वास होने पर कि दिवालियेने दरअसल जर्म किया है उसे फोजदारी सुपुर्द कर सजनी है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है और बिला उसके लिखे हुए इस दफाके अनुसार मामला चालू नहीं हो सकता है । ऐसे मामला सुनवाईका अधिकार अदालत दर्जेके मजिस्ट्रेट ही को प्राप्त है अर्थात् दर्जा दीयम व दर्जा सायमके मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते है । जब कोई मामला किसी मजिस्ट्रेटके सुपुर्द इस दफाके अनुसार किया जावे तो वह मजिस्ट्रेट मामलेकी तदबीबात करने के लिये बाध्य है और अधिक तर यह मामले सबसे समीप वाले फर्टे जज मजिस्ट्रेटके पास भेज जाना चाहिये । इस दफाके अनुसार कार्रवाई उस समय तक न की जावेगी जब तक कि मामला अदालत द्वारा न भेजा गया हो । किसी प्रारम्भिक व्याक्ति के कहने पर इस दफाके अनुसार अभियुक्त दोषी नहीं ठहराया जासकता है, देखो—53 Cal. 929, A. I. R. 1927 Cal 149. अदालत इस दफाके अनुसार मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजते समय दिवालियेका हिसाबमें भेज सकती है या उससे उसकी इज्जतके लिये पर्याप्त जमानत ले सकती है अदालतरी यह भा अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्तियोंको भी जिनके बयान होनेकी आवश्यकता हो मजिस्ट्रेटके सामने हाजिर होनेके लिये बाध्य करे जिसमें वह लोग बड़ा अपन नयान दे सकें । किसी फर्मने दिवालिया कलर दिये जानेकी दरखास्त दा तथा उसमें सन हिस्तेदारोंके नाम दिखला दिये गये । इस दरखास्त पर दिवालिया कलर दिये जानेका हुक्म हो गया । इसके बाद इस फर्मका एक अधीनदार दिवालिया कलर दिया गया । उस अधीनदारेके विरुद्ध दफा ७२ के अनुसार दरखास्त दी गई ता यह तय हुआ :—

(१) यह कि अदालतरी यह प्रश्न तय करेगा ये —

(ए) आया फाकिसानी बिला बहाल किया हुआ दिवालिया था ?

(बी) आया उसने ५०) या उससे अधिकका कर्ज लिया था ?

(सी) कि आया उसने दरअसल कर्ज ठेते समय कर्जदारहते यह प्रष्ट कर दिया था कि वह बिला बहाल किया हुआ दिवालिया है ?

(२) यह कि पहिले वाली दिवालियेकी कार्रवाईमें फर्मका तरफने दरखास्त था न कि किसी खास व्यक्तिकी तरफसे और इस कारण उस फर्मका हर एक मन्बर या हिस्सेदार दिवालिया कलर दिया गया था ।

(३) यह कि जब फर्मके किसी एक हिस्सेदारके विरुद्ध मामला चलाये जाना हुआ दिया गया हो तो इस बातका कोई असर नहीं पडगा कि आया वह फर्म उस हिस्सेदारने बेदसियत फर्मके हिस्सेदारका लया ह ।

(४) यदि कोई माल अमानतन इस बातके लिपिलिया गया हो कि उसे बच कर रुपया अदा कर दिया जावेगा तो ऐसे मालका लिया जाना भी इस दफाके अनुसार कर्ज लिया जाना समझा जावेगा, देखो—A. I. R. 1928 Sindh, 114, 107 I C. 442.

दफा ७३ दिवालियेकी असुविधायें (रुकावटें)

(१) जबकि कोई कर्जदार इस एक्टके अनुसार दिवालिया कलर दिया जावे या बुचारा दिवालिया कलर दिया जावे तो यह इस दफाके नियमोंका ध्यान रखते हुए नीचे दिये हुए कार्योंके लिये अयोग्य समझा जावेगा :—

- (ए) मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जानें या मजिस्ट्रेटीका काम करनेके लिये
 (बी) जबकि किसी जगहक शिष्ट चुनाव द्वारा नियुक्ति होती हो तो उस जगहको चुने जानेके लिये या कि नी ऐसी जगह पर नियुक्त होनेके लिये या वहा पर काम करनेके लिये जिसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है
 (सी) किसी लोकल पद (Local Authority) का मम्बर चुने जान या उसमें वोटर देनेके लिये ।

(२) इस दफाके अनुसार दिवालियोंको जो रुकावटें हैं वह हटा दी जावेंगी या जाती रहेंगी अगर :—

- (ए) दफा ३५ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख होजाय, या
 (बी) उसे अदालतसे मुस्तकिल या फायममुकामी बखालीका हुक्म इस सर्टीफिकेटके साथ मिल जाय कि वह अभिम्यवश दिवालिया होगया था इसमें उसकी कोई बचनमानी नहीं थी ।

(३) अदालतको अधिकार है कि जैसा वह मुनासिब समझे ऐसे सर्टीफिकेटको दे सकती है या उसके देनेसे इनकार कर सकती है लेकिन इनकार करने वाल हुक्मनी अपीलकी जा सकती है ।

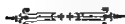
व्याख्या—

उपदफा (१) के क्राज (ए), (बी) व (सी) में दिवालियेकी अयाथता वर्णन है क्राज (ए) क अनुसार वह मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जासकता है और न वह मजिस्ट्रेटका कोई कामही कर सक्ता है क्राज (बी) के अनुसार वह किसी ज्वैतनिक जगह पर काम करनक लिय नहीं चुना जासकता है तथा क्राज (सी) क अनुसार वह किसी स्थानक पद का मम्बर नहा चुना जासकता है ।

इन दफाम जिन अयोग्यताओंका उल्लव किया गया है कबल वही अयाथता नहा है इनके जतिरित दिवालिया और भी बहुतसे कार्य नहीं कर सकता है इनका उल्लव दूसर कानूनोंमें किया गया है जस कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट क अनुसार बिला बहाल हुआ । दवालय काउन्सिलका मम्बर नहीं चुना सकता है । गान्धेय एण्ड वाई एक्ट क अनुसार वह नानालियरी आपदाक बला हानसे इयाजा जासकता है या किसी टांके रेली हानसे अगहदा किया जासकता है इ यदि ।

उपदफा (२) म बतलाया गया है कि उपदफा (१) का अयाथता दूर भा हा सक्ता है जब कि दिवालिया करार दिये जनि बाज हुक्म दफा ३५ क अनुसार मसूख कर दिया जाय अथवा दिवाळिया बहाल (Discharge) कर दिया जावे । बहाल हानेके लिये यह भी बतलाया गया है कि चाहे दिवाळिया पूरा रूपम बहाल कर दिया जाय अथवा बड किसी शर्तक साथ बहाल किया गया हो जब कि इस प्रस्तावा सर्टीफिकेट द दिया गया हो कि वह दिवाळिया अभिम्य वश हो गया था और उसक बचनमानाकी बजहसे ऐसा नहीं हुआ था । यदि दफा २ में नलगाया हुआ सर्टीफिकेट दनेसे अदाउन इन्वार कर देवे ता उसका अयाथती जासकती है ।

पांचवां प्रकरण



सरसरीकी कार्रवाई

दफा ७४ सरसरीकी कार्रवाई

जबकि दिवालकी दरखास्त किसी कर्जदारने दी हो या उसके खिलाफ दी गई हो और अदालतको हलफनामासे या दूसरे किसी तरहसे यह इतमीनान हो जाये कि कर्जदारकी आयदाद ५०० रुपयेसे अधिक मूल्यकी नहीं है तो अदालतको अधिकार है कि वह इस प्रकारका हुक्म देदेवे कि कर्जदारकी आयदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किया जावे और तब इन एक्टमें दी हुई कार्रवाई नीचे दिये हुए संशोधनके साथ की जावेगी:—

- (i) प्राप्तिक सरकारी गजट द्वारा नोटिसकी मुश्तहरी नहीं की जावेगी जैसा कि एक्टमें दिया हुआ है जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई आज्ञा न देवे
- (ii) कर्जदारद्वारा दी हुई दिवालकी दरखास्तके लेलिये जाने पर उसकी आयदाद अदालतकी सुपुर्देगीमें बहेसियत रिनीवरके समझी जावेगी
- (iii) दरखास्तकी समाप्त करते समय अदालत कर्जदारको कर्जे व लहनेको दरयाफ्त करेगी और निश्चित करके अपने हुक्ममें लिखेगी और दफा ३३ में दिये हुए नियमोंके अनुसार सूचीका तैयार करना जरूरी नहीं होगा
- (iv) कर्जदारकी आयदाद जितनी उचित जल्दी हो सकेगी घसूल की जावेगी और उसके बाद जब मुमकिन हो एकही डिघीडेएटमें बांट दी जावेगी
- (v) दिवालिया क़ारार दिये जानेके हुक्मसे छः माहके अन्दर दिवालिया महाल होनेकी दरखास्त देवेगा, और
- (vi) जो कुछ संशोधन, खर्च कम करने तथा कार्रवाईको साधारण घनानेके लिये बनाये जावे उनका अमल किया जायेगा ।

परन्तु अदालतको अधिकार है कि यह किसी समय भी कर्जदारकी आयदादके सम्बन्धमें इस एक्टमें दिये हुए साधारण नियमोंके बर्तनेका हुक्म दे सकती है और तब उसके बाद इस एक्टका नियम पूर्वक प्रयोग होगा ।

व्याख्या—

यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें छोटे मोटे मामलोंमें बहुत समय नष्ट न किया जावे तथा ऐसे मामलोंमें अधिक खर्च भी न हो सके और ऐसे मामले जल्दी समाप्त किये जा सकें दिवालियेरी दरखास्त चाहे कर्जदारने स्वयं दी हो या वह दरखास्त उसके विरुद्ध किसी कर्जदारद्वारा दी गई हो दोनों दशाओंमें यह दफा लागू हो सकती है यदि और शर्तें पूरी होती होंगी ।

इस दफाके अनुसार कार्यवाई उसी दशमिकी जायेगी जबकि दिवालियेकी जायदाद ५०० पावसी रुपयेमें अधिक मूल्य की न होवे इस मूल्य का योजन अदालत हलकन्यायाके दाखिल होने पर या अन्य श्रावतके डेन पर कर सकती है इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है ।

अर्थात् यदि दिवालियेकी जायदाद ५०० पावसी रुपयेसे कम मात्रा की होवे तो भी अदालतकी अधिकार है कि वह इस एक्टमें बतलाये हुए मामूली नियमोंके अनुसार कार्यवाई कर सकती है और सरसरीकी कार्यवाई अमलमें न लावे ।

इस दफाके अनुसार कार्यवाईकी जानकारी अदालतको जावनेके अनुसार हुक्म देना चाहिये कि कर्त्तव्यकारी जानदादा या नाम सरसरी तौरसे किया जावेगा ।

यदि सरसरी तौरसे कार्यवाई करकेका हुक्म हो जावे तो क्लॉज (i), (ii), (iii), (iv), (v) व (vi) में बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

क्लॉज (i) के अनुसार प्रान्तिक सरकारों या मजदद द्वारा बोकायाको जानेकी आवश्यकता नहीं रहेगी बरन् कि जदाउत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न दे देवे ।

क्लॉज (ii) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद उसी प्रकार अदालतकी सुपुर्दामें आनवेगी जैसे कि गिनीवरकी सुपुर्दामें आना चाहिये ।

क्लॉज (iii) में बतलाया गया है कि कर्त्तव्यकारीकी सूची आदि तैयार किये जानेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु अदालत स्वयंही दिवालियेके लहजे व कर्त्तव्यकारी निश्चित करेगी और उनके बारेमें निर्णयन होने जान समयही दरपान्न कर लेगा ।

क्लॉज (iv) के अनुसार दिवालियेके कर्त्ते जिनकी अच्छी हो सके श्रद्धा करके बाट दिय जाना चाहिये ।

क्लॉज (v) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेका बहाल होनेकी दरपान्न व माहके अन्दर द देना चाहिये ।

क्लॉज (vi) में बतलाया गया है कि यदि कोई जोर नियम का सम्बन्ध बनावे गए हो जिनमें खर्चमें कमी या कार्यवाई की और साधारण बनावे जासके तो ऐसे नियमोंका भी पालन किया जाना चाहिये । यह सब होने हुए भी अदालतकी अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकतालमार किसी समय भी इस एक्टके माहूली नियमोंके अनुसार कार्यवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है अर्थात् यदि सरसरीका हुक्म देनेके पश्चात् अदालतको माहूम होवे कि दिवालियेकी जायदादना मूल्य ५०० रुपयेसे अधिक है या दिवालियेकी जायदादना प्रबंध अपवाद वसूलीजोना सीसीवर द्वारा आवश्यक है तो वह एम्प दशाये गिनीवर नियुक्त कर सकती है तथा सरसरीके हुक्मसे। मसूम कर मामूली नियमोंके अनुसार कार्यवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है ।

छठा प्रकरण

अपील

दफा ७५ अपीलें

(१) अदालत जिलाके मातहत किसी अदालतके किये हुए फैसले या हुक्मके विरुद्ध जो उसने दिएला सम्बन्धी अधिकारको धरते हुए दिया हो, अपील अदालत जिलामें की जा सकती है और उस अपील पर जो हुक्म अदालत जिलाका होगा वह अन्तिम हुक्म होगा और ऐसी अपील दिवालिया, कर्जनाह, रिसीवर या और कोई शब्द जिसको कि फैसले या हुक्मसे मुक्तता पहुँचता हो कर सकता है। लेकिन हाईकोर्टको अधिकार है कि वह यह जानने के लिये कि अदालत जिलाने अपीलमें जो हुक्म दिया है वह कानूनन ठीक है मुकद्दमोंको मँग सकता है तथा उसे जो मुनासिब मालूम हो वह हुक्म उसकी वास्तविकता दे सकता है। और अगर कोई शब्द अदालत जिला द्वारा किये हुए अपीलके फैसलेसे संतुष्ट न हो जो उसने अपने मातहत अदालतके फैसले या हुक्मके वास्तविकता दिया हो तो उसे अधिकार है कि वह दफा ४ के अनुसार वास्तविकता दीवानीकी दफा १०० (१) में दी हुई बातोंकी बिना पर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

(२) अगर अदालत जिलाके उन फैसलों व हुक्मोंकी अपील जो पहिली सूची (Schedule I) में दिये हुए हैं और जिसे उसने अपने मातहत अदालतकी अपीलमें नहीं दिया है हाईकोर्टमें की जा सकती है।

(३) पहिली सूचीके अतिरिक्त जो फैसले या हुक्म अदालत जिलाने किये हों लेकिन जो मातहत अदालतकी अपीलमें न किये हों उनकी अपील अदालत जिला या हाईकोर्ट की आज्ञा लेकर हाईकोर्टमें की जा सकती है।

(४) अदालत जिलामें अपील तीस दिनके अन्दर व हाईकोर्टकी अपील ६० दिनके अन्दर की जा सकेंगी।

टिप्पणी—

इस दफा में अपील का वर्णन है। शिड्यूल (Schedule I) में वह फैसले व हुक्म दिए गये हैं जिनकी अपील हाईकोर्टमें की जा सकती है। इस दफा में यह नहीं बतलाया गया है कि अदालत जिलाके यहां किन किन हुक्मों या फैसलों पर अपील की जा सकती है। परन्तु यह प्रष्ट होता है कि मातहत अदालतके सभी फैसलों व हुक्मोंकी अपील अदालत जिलाके यहां की जा सकती है जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात इस एक्टमें न दी गई हो।

उपदफा (१) इस उपदफाके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे अदालतके फैसले या हुक्मके विरुद्ध शिकायत हो अपील करने का अधिकार है अर्थात् दिवालिया, रिसीवर, कर्जनाह या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसे शानि पहुँचती हो अपील कर सकता है। इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अपील करने के लिये बाध्य नहीं है किंतु करना करना न करना उसका इच्छा पर निर्भर है। इस उपदफा में यह भी बतलाया गया है कि इस उपदफाके अनुसार भी

हुई जरीलगा जो केसला होगा उसे अतिम कसला समझना चाहिये परंतु साथ साथ यह शर्त लगादी गई है कि यदि हाईकोर्ट चाहे तो अपन सुतोंके लिये सुत्र हमेशा अपने देखनेके लिये गया सकता है तथा उस पर अपना गुनासिम हुकम दे सकता है और इसा प्रकार दफा ४ के अनुसार कर्जकेतव भी जाबना दीवानीकी दफा १०० (१) के अनुसार अदालत जिलेके फैमलर विरुद्ध शर्ककोर्टमें अपील करनेका अधिकार है । इस उपदफामें हानि पहुँचनेसे अभिप्राय कानूनी हानिसे है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति का अदालत दिवालियाके किसी फैमले या हुकमसे किसी वस्तुमें अधिकार जाता रहे या उससे उसके किसी हुकम आघात पहुँचना हो तो ऐसे व्यक्ति के लिये यह माना जायगा कि उसे उस हुकम या फसलेसे हानि पहुँची है, देखो—46 Mad 403 यदि अदालतके किसी हुकम या फैमलेमें किसी व्यक्ति को केवल यही असंतोष होवे कि उस हुकम या फसले में होनेसे उसे कुछ भविष्यमें लाभ पहुँचोगी सम्भरना थी तो ऐसे हुकम या फैमलेसे उस व्यक्ति की कोई कानूनी हानि नहीं समझना चाहिये, देखो—41 I C 96.

दिवालिया कानून दिये जानेका हुकम हानिकर फलस्व दिवालियाका कोई एक आयदाद पर नहीं रह जाता है और इसीलिये उसका वसूल्य बाँके मिलसिलेमें यदि कोई हुकम दिया जावे तो उस हुकमसे दिवालियाको कोई हानि नहीं पहुँच सकती है । स प्रश्न यदि उसकी आयदादके किसी हिस्सेमें बैंक जानेकी मजूरी दी जावे तो इस मजूरीके विरुद्ध उसे अपील करनेका अधिकार नहीं है, देखा—49 Mad 461.

यदि अदालत किसी ऐसे कर्ज को मजूर कर लवे ना कि साबित नहीं किया जासकता है तो ऐसे हुकममें दिवालिया की हानि शून्य है और इसके विरुद्ध वह अपील कर सकता है, देखो—47 Mad. 120 यदि कोई कर्जस्वाह दिवालिया करार देकर जान बाल हुकमसे मसूचीकी दख्खानत दफा ४ के अनुसार देवे और वह दख्खानत वापस करी जावे तो ऐसे हुकमके विरुद्ध उस अपील करनेका अधिकार होगा, देखा—A I R 1924 Mad 685

यदि कोई शर्कदार आयदाद दफा ५३ के अनुसार मसूद कर दिया जावे तो वह व्यक्ति जिसके हुकमें वह इतनाल किया गया था इस फैमलेके विरुद्ध अपील कर सकता है क्योंकि ऐसे हुकममें उसे हानि पहुँची है, देखो—7 I C 765. यदि आधिकार एसानीरी किसी हुकमसे हानि पहुँचती हो तो वह भी अपील कर सकता है, देखो—33 Mad 134 शाहबाज हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियाकी आयदादके लिये किसीवर नियुक्त किया जानुश हो और कोई व्यक्ति उसकी किसी आयदादके लिये उसमें विरुद्ध दावा करे तो उसके कर्जस्वाहोंमें से किसी एक कर्जस्वाहको ऐसे मामलेमें अपील करनेका एक प्रास नहीं है क्योंकि उसका हान उठाने वाला व्यक्ति (Aggrieved person) नहीं वह सबसे है देखा—39 All. 152

हाला हाईकोर्टने भा ऐसीही बात तय की थी देखो—62 I. C. 924 (Lah) परंतु मद्रास हाईकोर्ट इस तय से सहमत नहीं हैं उनमें तय किया था कि यदि किसी हुकमसे किसी व्यक्ति पर कोई धारदाती आती हो और उसके हिस्सेमें आधाव पहुँचता हो तो वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझा जायेगा चाहे वह उसमें फ्रीक मुकदमा हो या न हो, देखो—49 Mad 794 यदि कोई कर्ज को स्मिति कर चुकने वाला कर्जस्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमसे मसूदा होने पर उस हुकमकी नजरानगी (Review) करे और वह नजरानगीकी दख्खानत खारिज हो जावे तो उसे हानि उठाने वाला व्यक्ति समझना चाहिये, देखा—A I R 1927 Mad 175 हाईकोर्टने यह किसी कर्जस्वाहकी दख्खानत जो दफा ५३ व ५४ के आधार पर दा गई हो खारिज हो जावे तो उसे अपील करनेका अधिकार प्राप्त है क्योंकि वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति हो जाता है, देखो—47 Mad 673. 44 All 71.

यदि किसी कर्जस्वाहकी दख्खानत पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दिया गया हो और वह मसूद कर दिया जायता उस कर्जस्वाहकी हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझना चाहिये और वह उसमें अपील कर

सत्य है, देखो—A. I. R. 1926 Lah. 24. किमी दिवालियेकी जायदाद बेतर्जनीते बेची गई व उमने उसके विरुद्ध दरखास्त दी परन्तु वह दरखास्त नामजूर की गई तब अपने अपील की परन्तु अपीलमें यह तथ हुआ कि वह कानूनी रूपसे हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं है अतः उसे अपीलका अधिकार नहीं है, देखो—41. All. 243 इसी प्रकार यदि अदालत दिवालियेके विरुद्ध की हुई शिनायतकी खारिज कर देवे तो उस फर्जीवाहका जिसने इस शिनायतको दफा ६९ के आधार पर किया या हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना और न वह अपील कर सकता है, देखो—39 All. 171, 40 Mad 680, A. I. R. 1924 Mad. 180.

इसी प्रकार यदि रिसीवरने दफा ६९ या ७० के अनुसार दिवालियेके विरुद्ध मामला चलाये जानेमें दरखास्त दी हो और वह दरखास्त खारिज हो जावे तो रिसीवरकी हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना चाहिये और वह अपील नहीं कर सकता है, देखो—61 I. C. 802. यदि अदालत आफिशल रिसीवरकी हटा कर इनके स्थानमें कोई स्पेशल रिसीवर नियुक्त करदे तो आफिशल रिसीवरको ऐसे हुक्मसे हानि पहुँचती है और वह इनके विरुद्ध अपील कर सकता है, देखो—40 Mad 405.

यदि रिसीवरने किसी फर्जीवाहके करने पर किसी फसलका कर्क किया हो और वह फसल कुरीसे बोज दी जावे तो इन हुक्मके विरुद्ध अपील की जा सकती है, देखो—47. All. 849. यदि किसी व्यक्ति को किसी हुक्मसे हानि पहुँचती हो तो उसे अपील करनेका अधिकार होगा चाहे वह अदालत मानहतमें फरीक घुबहमा न रहा हो, देखो—53 Cal. 866 यदि अदालत जिलाका मातहत किसी अदालतके, अदालत दिवालियाके अधिकारोंके वर्तने हुए कोई हुक्म दिया हो तो ऐसे हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें नहीं होगी किन्तु उसकी अपील अदालत जिलामें होना चाहिये, देखो—63 I. C. 848. गौक मातहत अदालतको दिवालिया सम्बन्धी मामलानामें वकील अधिकार प्राप्त है जो अदालत जिलाको हानि है परन्तु अपीलके लक्ष्य में इन अदालतोंको अदालत जिलाकी मातहत अदालत ही समझना चाहिये, देखा—A. I. R. 1923 Nag. 80 अतिरिक्त (Additional) जिला जन अपीलके लिये जिला जनके आधीन नहीं है, देखो—9 A. L. J. 371, 36 All. 576.

अदालत खर्फीकाके हुक्मोंके विरुद्ध जो उसने अदालत दिवालियाके अधिकार क्षेत्रमें किये हों अपील अदालत जिलामें की जायेगी, देखो—23 All. 56, 12 Mad 472, 21 Bom 45, 27 Bom. 604. दायित्वके डिस्ट्री कमिशनर द्वारा दिये हुए हुक्मके विरुद्ध अपील अदालत जिलामें की जायेगी, देखो—15 U. L. J. 239, A. I. R. 1925 Cal. 335. आफिशल रिसीवरकी इस दफाके अनुसार अदालत जिसके मातहत असलत नहीं माना जासकता है, देखो—40 Mac 752. अमेसी एक्टकी इस दफामें इन शब्दों 'Shall be final' का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलाके फैसलेके विरुद्ध अपील दोयम (Second Appeal) नहीं की जासकती है और उसके अपीलमें किये हुए फैसलेको अन्तिम फैसला समझना चाहिये परन्तु आगे चल कर इसी दफामें यह भी बतलाया गया है कि हाईकोर्टको अधिकार है कि वह तजवीजनामी (Revision) के तौर पर अदालत जिलाके फैसलेमें हस्तक्षेप कर सके इससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलाका अपीलमें किया हुआ फैसला एक प्रकारसे अन्तिम फैसला है क्योंकि उसकी अपील दोयम नहीं की जासकती है परन्तु उसमें भी हाईकोर्टको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है।

इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि कुछ मामलोंमें अपील दोयम अपात् हाईकोर्टमें भी अपील उस फैसलेके विरुद्ध की जासकती है जैसा कि इसी प्राक्के अंतर्गत जो शर्त लगाई गई है उनमें बतलाया गया है। इस दफाके अनुसार हाईकोर्टको रिवीजन (Revision) के जो अधिकार प्राप्त हैं वह कर्तव्य करीब उसी तरहके हैं जैसा कि उस अदालत खर्फीका द्वारा किये हुए फैसलोंमें प्राप्त हैं। जानना दीवानीकी दफा १९ के अनुसार जो अधिकार तजवीजनामी (Revision)

के हार्डवेयरों प्राप्त है उनसे यह अधिकार किसी इद तक अधिक है क्योंकि वह अधिकार केवल अधिकार सीमा (Jurisdiction) ही के मध्यममें बँटें जासकते हैं परन्तु इस दफाके अनुसार हार्डवेयरों उस वक्त हस्तक्षेप कर सकता है जब कि उसे यह मादृग पड़े कि कानून दण्डित करवाये नहीं की गई है ।

दफा ११५ जायसा दीवानी इस प्रकार है —“हार्डवेयरों अधिकार है कि वह अपने मातहत अदालतके तय किये हुए किसी मुकदमेकी मिसिलकी मगबाले जब कि उस फैसलेके विरुद्ध अपील न की जासकती हो और यदि ऐसा मादृग हो कि उस मातहत अदालतने (ए) उन अधिकारोंका प्रयोग किया है जो उसे कानून प्राप्त नहीं है या (बी) उसने उन अधिकारोंका प्रयोग नहीं किया है जो उसे कानून प्राप्त हैं या (सी) उसने अपने अधिकारोंको और कानूनी तरीके या बर्बा बेतरतीबसे प्रयोग किया है । और हार्डवेयरों अधिकार है कि वह जो हुक्म सुनासिब समझे ऐसे मामलोंमें दे सक्ता है ।”

इस दफाके अनुसार तनवीजसानी (Revision) के भी अधिकार हार्डवेयरोंकी प्राप्त हैं उनका प्रयोग करना न करना हार्डवेयरों इच्छा पर निर्भर है वह उनको प्रयोग करनेके लिये वाप्य नहीं है जैसा कि अमेरिका एक्टरी इन दफात प्रयोग किये हुए ‘May’ शब्दसे प्रकट होता है । यदि अदालत सिलाने आलम्में यह हुक्म दिया हो कि मनीद शाश्वत ही जाना चाहिये तो ऐसे हुक्मकी तनवीजसानी हार्डवेयरोंमें हो सकती है, देखो—61 I. C. 589. परन्तु यदि किसी मजबूरी अर्पीक की जासकती हो तो उसके लिये तनवीजसानी (Revision) नहीं सुनी जासकती है देखा—A. I. R. 1926 Mad. 128. यदि अदालत सिलाने अर्पीक दफा २२ या दफा ६९ के अनुसार काँबाई कराने इतफार कर देने तो इसका रिवीजन (Revision) नहीं किया जासकता है, देना—56 I C 744

इस हाराके अन्तमें जो शर्तें लगा दी गई हैं उसने अनुसार अपील दोषम भी की जासकती है । यदि अदालत जिलाने किसी मामलेको दफा ४ के अनुसार तय किया हो तो उसकी अपील दोषम हार्डवेयरोंकी जासकता है परन्तु ऐसे मामलोंकी अपीलें उन्हें बाँटोंके आधार पर की जासकती हैं जिनका उल्लेख दफा १०० (१) जायसा दायामीमें है ।

जायसा दीवानीकी दफा १०० (१) इस प्रकार है —“उन बाँटोंका प्यान रखने हुए जो इत एक्टमें या अन्य किसी प्रचलित एक्टमें बतलाई गई हैं नीचे दिये हुए मामलोंकी अपील हार्डवेयरोंमें उसके किसी मातहत अदालतके अन्तर्में किये हुए फैसलके विरुद्ध की जासकेगी । (ए) यदि फैसले किसी कानूनके विरुद्ध होवें या किसी चलन (Usage) के विरुद्ध होवें जो कानून कानूनके बरता जाया होवे (बी) यदि फैसलेमें कोई कानूनी तनवीज या कोई ऐसा चलन जो कानूनी तौर पर बरता जाया होवे तब न किया गया हो (सी) यदि इस कोडमें बतलाये हुए या अन्य किसी प्रचलित कानूनमें बतलाये हुए नियमके विरुद्ध खास गण्ठी हुई हो जिसकी बजहसे फैसलेमें ठीक तौरसे मसला असली बाधवातके अनुसार तय न किया जासका हो ।”

इस प्रकार अपील दोषम उही समय हो सकेगी जब कि अदालत जिलाने दफा ४ के अनुसार किसी मामलेको तय किया हो तथा उसमें दफा १०० (१) जायसा दीवानी भी अन्त होती होवे । इन प्रकार यदि दफा ५३ के अनुसार कोई हुक्म दिया गया हो तो कानूनी मामले पर उसकी अपील दोषम हो सकेगी, देखा—A. I. R. 1224 Nag- 361.

जब कि रीसीवरने किसी जायदादमें दिवालिपेकी जायदाद फुगर देकर कुर्क किया हो और उन जायदाद पर कोई तीसरा व्यक्ति अपना हक प्रकट करे तथा अदालत उमके हककी स्वीकार कर लेते तो इसके विरुद्ध दफा ७५ के अनुसार अपील की जासकती है, देखा—A. I R 1928. Lah 556.

यदि अदालतने यह हुक्म दिया हो कि कोई हकम आफिशन रीसीवरको मिलना चाहिये तथा इसके विरुद्ध किसी तीसरे व्यक्तिने अपना हक आहिर किया हो तथा अदालत उमने हककी मजूर न करे तो वह व्यक्ति इस हुक्मकी अपील कर

समता है क्योंकि यह हुक्म एक प्रमाण दे दफा ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म होगा यह भी तथ्य हुआ कि कर्जस्वाहान जल्दी फीक मुकदमा नहीं है, देखा—A. I. R. 1928 Lab. 423 यदि अदालत अगिल घरे मागलेगी सुननेके पश्चात् यह राय कायम करे कि अगिलखटका मामला दरअमल कानिल अपील है जिसके लिये इनाजत दी जासकती थी तो वह अपील की इनाजत दे सक्ता है, देखो—A. I. R. 1928 Pat 398.

उपदफा (२) इस उपदफाके अनुसार अदालत जिलेके फैमले या हुक्मके विरुद्ध हाईकोर्टमें अपील की जासकती है परन्तु उसके लिये शर्त यह है कि (ए) ऊन्हीं फैमला व हुक्मोंकी अपील हो सकेंगी जो सूची न० १ (Schedule 1) में दिये हुए हैं व (बी) वह फसले व हुक्म उन्हीं मामलोंमें दिये गये हों जो अदालत शिन्धने स्वयं सुने हों और वह किसी मातहत अदालतकी अपीलमें उस अदालत जिला द्वारा नहीं दिये गये हों ।

उपदफा (३) उपदफा (२) में बतनाया जाचुता है कि अदालत जिलेके ऊन्हीं फैमलों व हुक्मोंकी अपील हो सकेगी जिनका उल्लेख सूची न० १ (Schedule 1) में दिया गया है परन्तु इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि ऐसे हुक्मों व फैमलोंकी भी अपील की जासकती है जो कि सूची न० १ (Schedule 1) में न दिये गये हों वनों कि उनके लिये अदालतकी आज्ञा ले ली जावे । इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि इस उपदफाके अनुसार भी अयोग ऊन्हीं फैमलों व हुक्मोंकी की जासकेगी जिसकी अदालत जिलेने अपने सुने हुए मामलोंमें दिया हो व जिनको अपने अपीलके अधिकार बंते हुए न दिया हो, अपील यदि किसी मातहत अदालतके फसले या हुक्मके विरुद्ध अदालत जिलेने कोई फैमला या हुक्म दिया हो तो ऐसे फसले या हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें किसी भी दफामें नहीं की जासकती । अदालत की आज्ञा साधारण तौर पर प्रदान नहीं की जावेगी यह आज्ञा उन्हीं मामलोंमें दी जासकेगी जो लखर न हों या जिनमें कोई कानूनी मामला आता होवे वरना पिछली उपदफाके बतानेकी आवश्यकता ही नहीं थी । आज्ञाका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और यदि आज्ञा न दी जावे तो इस हुक्मके विरुद्ध अपील नहीं की जासकती है, देखो—38 I C 818. बिला आज्ञा लिये हुए इस उपदफाके अनुसार अपील नहीं की जासकती है अर्थात् इस आज्ञाके लेनेके लिये अपील करने वाला ध्यक्ति बाध है, देखो—36 All 8. अपीलमें वही लोग फीक मुकदमा बनाये जावेंगे जिनका सम्बन्ध अपील किये जाने वाले हुक्म या फैमलेसे होगा देखो—38 Mad 74. यदि किसी कर्जस्वारी दिवालिया करार दिये जानेकी दुरवास्त राजिज कर दी जावे तो उस हुक्मकी अपीलकी सूचना उसके कर्जस्वाहारी की काफी तादादसे दी जाना चाहिये न तबमें कि वह लोग नईसित रिपण्डेण्टके अपने घसलेसे पेश कर सकें, देखो—37 I C 391. दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध जो अपीलकी जावे उनका नोटिस आफिशल एगजन्टीने दिया जाना चाहिये, देखो—A. I. R. 1925 Cal. 1215 यदि दिवालियेकी रहनेके लिये मजान न दिया गया हो और वह ऐसे हुक्मकी अपील गिरीवरकी फीक मुकदमा बिठा बनाये हुए करे तो वह कानिल चलेनेके नहीं है, देखो—57 I C 971 (Lab) यदि कर्जस्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध अपील करे तो उसमें दिवालियेका फीक मुकदमा बनाया जाना जरूरी है, देखो—A. I. R. 1924 Bom. 472. यदि अदालत जिलेने दिवालियेकी बरतनेके सम्बन्धमें विधि हुए किसी बयानमेंकी मज्दुरी देदी हो व उसके विरुद्ध अपीलकी जावे तो उसमें खरीदार नजाम व रिडीवरकी फीक मुकदमा बनाया जासकती है, देखो—A. I. R. 1923 Lab 58, 68 I C 716 यदि कोई एक कर्जस्वाह अपील करे तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे कर्जस्वाह या फीक मुकदमा बनाये जावें, देखो—58 I C 10. यदि सूचीमें दर्ज कोई कर्जस्वाह मर गया हो और उसके वारिष्ठों ने नोटिस न दिया जावे तो केवल इतनी बातने अपील रह नहीं हो जावेगी, देखो—A. I. R. 1926 Cal. 1210.

यदि गिरीवर फीक मुकदमा न बनाया गया हो व अपीलमें कोई हुक्म दे दिया जावे तो केवल उसके फीक मुकदमा

न बनाए जानेही से वह हुक्म रद्द नहीं हो जावेगा जब तक कि यह साबित न हो कि उसके द्वारा उसके द्वारा प्रकटमा न होना है यह विशेष हानि उसे पहुँचना है, देखो—**1 I R 1922 Mad 437**

जब कि इन दफाके अनुसार अपीलकी गई हो तो साबित दावालाकी दफा ४२ में बतलाये हुए इन नियमाका प्रयोग किया जासकता है यदि वह इस एकटेके किसी नियमक विरुद्ध न पड़त हों **41 Mad 904** इसमें दिया हुआ है कि किसी अपालके दाखिल हानके बाद आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार क्रास अपाल दाखिलता जासकती है अपालन अपील साबित दावानीरु आर्डर ४१ रूल २० के अनुसार सर्वेके लिये अपीलान्से बयानत माग सकता है, देखा—**43 Cal 243.**

यदि कर्मन्वाहने किसी दिवालियेके विरुद्ध करिवाई करना दारखास्त दी हो और वह दारखास्त बिना तहकीकातेके या बिना रिसॉरका रपरि दखल बिना वाई कारण बतलाय हुए खारज कर दी गई हो ता उसका अपील हो सकता है, देखा—**79 I C 340**

यदि अदालतने बिना किसी तामर शर्तके त्रिय हुए एतग-तम फसल किये हुए कृषि आधुनादक बच दिये जानका हुक्म द दिया हो तो इस विरुद्ध अपालन जासकता है, देखा—**52 Cal 662**

यदि कोई ऐसा कर्ज जो साबित न किया जासकता हो साबित मान कर मचूर कर दिया गया हो ता उसका अपालन जासकता है, देखा—**47 Mad 120**

यदि किसी केसलका नजराना (**Revenue**) मचूर कर ली गई हो तो उसका अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हॉरिबोर्टमें हो सकनी है पालु ऐसी अपाल जाचना दीवानके आर्डर ४७ के अनुसारही होना चाहिये, देखा—**44 All 605.** यदि दफा ७७ के अनुसार हुक्म दिया गया हो ता एस हुक्मकी अपील हो सकती है, देखा—**100 I C 137 (Lab).** यदि दफा ७७ (२) के अनुसार समय बढानके लिय दारखास्त दा गई हो और वह दारखास्त खारिज हो जाने तो वसती अपील नहीं की जासकती है, देखा—**89 I C 959** यदि अदालत बिना दफा २२ व २९ के अनुसार करिवाई करेस हवार कर दव ता इसके विरुद्ध अपाल नहीं जा जासकता है, देखा—**56 I C 744, 61 I C 802, 40 Mad 680, 85 I C 717.**

यदि दफा ४२ के अनुसार दिवालिया करार दिये जावेका हुक्म मसूख कर दिया जावे ता अदालतकी इस अ हाके विरुद्ध अपाल नहीं जा जासकती है, देखो—**100 I C. 137**

बती प्रसारदफा ५४ (२) के अनुसार दिय हुए हुक्मके लिये भी आलायेकर अपीलकी जासकती है, देखा—**46 I C 377** यदि रितावरका नियुक्त करेना हुक्म न दिया जावे तो इसने विरुद्ध भी बिना आक्षेपके अपील नहीं की जासकती है देखो—**A I R 1924 Cal 849.** यदि किसी हुक्मकी अपाल अदालत तिलामें न होता होवे परतु अदालत तिला अपील सुन कर अपना फैसला दे देवे तो हॉरिबोर्टमें अपिहार है कि वह अपाल तिलाके किये हुए फसलेको रद्द कर देव, देखो—**42 I C 287**

यदि किसी मृतक कर्मन्वाहके वारिसेको मोहित न दिया गया हो तो इसकी बजइसे फेमला रद्द नहीं हो जावेगा परतु उन कर्मिसेको यदि इनका नाम मिसिलमें नहीं आया हो उस कर्मिवाकी इनाम चाट करनका अपिहार प्राप्त है, देखो—**A I R. 1926 Cal 1210.**

इस एक्टमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अपील बिनी काउंसिलमें की जासकनी है या नहीं इसमें यह प्रकट होता है कि यदि प्रवी काउंसिलमें अपील करनेका अपिहार प्राप्त हो तो उसके लिये इस एक्टके कारण कोई बफाउर नहीं पड़ेगी, देखो—**27 Bom 415**

यदि दफा २५ के अनुसार दिवाले की दरख्वास्त नामजूर कर दी गई हो और अपनी अपील भी इम्पेट्रो द्वारा आईर ४१ रूफ ११ के अनुसार सागिन कर दी गई हो तो प्रती काउन्सिलमें अपील होना उचित है, देखो—40 Cal 685.

उपदफा (४) में अपील की मियादें बतलाई हैं । अदालत जिलामें ३० दिनोंके अन्दर तथा इम्पेट्रोमें ९० दिनोंके अन्दर अपील दाखिल की जाना चाहिये यही मियाद दीवानों की अपीलोंके लिये भी रखी गई है । यदि अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रितीबरेने किसी घर शस्त्र की जायदादकी ड्रॉ कर लिया हो तथा उसका कुछ हिस्सा नीलाम कर दिया हो और जायदादके माउकानने अदालत सिटाके पड़ा ॥ कहीं व नीलामके विरुद्ध दरख्वास्त दी हो परन्तु वह दरख्वास्त मियादके बाद होनेके कारण नामजूर कर दी जावे तो यह तथ हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जजके इस फैसलेके विरुद्ध अपील की जासकती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजके इस फैसलेसे अपीलाप्टरी हानि पहुँचती है, देखो—A. I. R. 1928 Cal 263 (2), 107 I. C. 467.

सातवां प्रकरण

विविध (मुतफर्रिक)

दफा ७६ खर्चा

इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार की हुई कार्रवाईका खर्च तथा फर्जदारको दीवानो जेलमें रखनेका खर्च उस अदालतकी तबियत पर होगा जिसके सामने मामला पेश हो ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें किये हुए खर्चे तथा दिवालियेकी कारागारमें रखनेके खर्चके बारेमें यह बतलाया गया है कि अदालत इस सम्बन्धमें जैसा हुक्म देना उचित समझे दे सकती है दीवानोंके मामलोंमें मददगारों जेलमें रखनेका खर्च गिरफ्तार करने वाले टिकीदारों परदाय्य करना पड़ता है परन्तु दिवालियेके मामलोंमें ऐसा नहीं है । इस दफा के अनुसार हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है वह खर्चा दिलाने के लिये किसी मामलेमें बाध्य नहीं है परन्तु सम्प्रेषित व वाकियातका ध्यान रखते हुए ही अदालतको खर्च पानेका हुक्म देना चाहिये । जैसे कि बहुतसे मामलोंमें खर्च दिवालियेकी जायदाद पर ही पड़ना चाहिये परन्तु बहुतेरे मामलोंमें जिनमें कि गैर शस्त्र या कोई कर्जालाह व्यापारी कार्रवाई करके पोशान करे तो ऐसी कार्रवाईका खर्च उन्हीं लोगोंसे दिववाया जाना चाहिये ।

दफा ७७ अदालतें एक दूसरेकी मदद देवेंगी

वह सब अदालतें, जिन्हें दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाकिम एक दूसरेकी दिवालेके मामलोंमें मदद देंगे और अगर कोई अदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुक्म देगी तो उस दूसरी अदालतको उस मदद चाहने वाले मामलोंके लिये जिसका जिक्र हुक्ममें होगा वही अधिकार होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंको हो सकने हैं ।

व्याख्या—

इस दफा में यह बतलाया गया है कि यदि एक अशक्त निधी दूसरी अशक्तता दिवालिया सम्वन्धी कार्य करने के लिये लिखे तो उस दूसरा अशक्तको उस कार्यके करनेमें बड़ा आश्रय प्राप्त होगा जो पहिले अशक्तको उस कार्यवाहीके सम्बन्धमें प्राप्त है। और साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि दिवाला सम्बन्धी कार्य करने वाली अशक्तों तथा उनके हाकिमोंका कर्तव्य होगा कि वह एक दूसरेकी सहायता उन मामलोंके करनेमें करें।

दफा ७८ मियाद

(१) इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलें तथा दी हुई दरखास्तोंके लिये सन् १९०८ ई० के कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम लागू होंगे तथा ऊपर कही हुई दफा १२ के अनुसार इस एक्टकी दफा ४ का फ़ैलावा यतौर दिवरीके समझा जावेगा।

(२) अगर दिवालिया कतार दिये जाने वाला हुक्म इस एक्टके अनुसार मंजूर कर दिया गया है तो, दिवालिया कतार दिये जाने वाले बकासे मंजूरीके बहाने तकका समय, उन मुकद्दमे या दरखास्तकी हुक्म मियादमें से घटा दिया जावेगा जो उस तक चालू होते जब कि इस एक्टके अनुसार कोई हुक्म न दिया गया होता, लेकिन यह नियम उन मुकद्दमे या दरखास्तोंके लिये लागू नहीं होगा जिनके लिये अशक्तने दफा २८ (२) के अनुसार हुक्म दे दिया हो।

परन्तु अगर कोई कर्म जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जायकता हो अगर यह साबित न किया गया हो तो ऐसे कर्मों सम्बन्ध रखने वाले मुकद्दमे या दरखास्तके लिये इस दफाकी कोई बात लागू नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलें तथा दरखास्तोंमें लागू होंगे। इस दफाके बननेसे पहिले इस बातके लिये बड़ा मतभेद था कि कानून मियादकी दफा १२ व दफा ५ कानून दिवालियाके लिये प्रयोग की जायकती है या नहीं, परन्तु इस दफाके बननेसे यह सब मतभेद दूर हो गया है। चूंकि दफा ५, व १२ का सामान्यतः उल्लेख कर दिया है इतने यह प्रकट होता है कि कानून मियादकी और दफाके कानून दिवालिया सम्बन्धी कार्यवाहीके लिये लागू नहीं है यदि उनका लागू होना और किसी तरीकेसे न पाया जावे। यह भी जान लेना आवश्यक है कि कानून मियादकी दफा १ व १२ क्या है।

कानून मियादकी दफा ५ "यदि अपील या सम्वन्ध अशक्तको इस बात का विश्वास दिगदे कि वह किसी खास कारणकी वजहसे नियत किये हुए समयके जल्द अपील नहीं कर सका था या दरखास्त नहीं दे सका था तो उसको अपील या मन्तरासानी की दरखास्त (Review) मियादने बाद भी ली जायेगी अथवा अपील करनेके लिये जाना या कोई दूसरा दरखास्त जिसके लिये कानून यह दफा लागू होगी मियादके बाद दी जायेगी। विवेक—यदि कोई कोई ती किमो तजवीज, हुक्म या अपील आने वाली हार्जिसके कारण निधी अपील या दरखास्त बुझि दाने मियाद समयने जा तो कनेदे गवती की हो तो यह मियाद बढ़ानेके लिये काफी बजह समझी जासकती है।"

कानून मियादकी दफा १२ "निधी मुकद्दमे, अपील या दरखास्तके लिये मियाद ओझने समय वह दिन मित दिनसे कि मियाद ओझना चाहिये उसमेंसे छान्द दिया जावेगा अर्थात् उस दिनका शुक्रा उस मियादके अन्दर न दिया जावेगा।

(२) किसी अपील नज़रसानी (Review) या अपील करने में वज़ा देने वाली दरखास्त के लिये वह दिन निम दिया कि कैसला सुनाया गया हो मियादके अन्दर नहीं गिना जावेगा और जिस कैसले या हुक्मकी अपील की जाही हो या जिसन लिये दरखास्त दी जाही हो उसकी नक़्ते-हासिल करनेमें जो समय लगेगा वह भी मुकर्ररमें नहीं जोड़ा जावेगा।

(३) यदि किसी डिप्टी की अपील में जाय गा उसके नज़रसानी (Review) की दरखास्त दा जावे तो जो समय उस डिप्टी की नक़्ते लनेमें लगेगा वह मियादके अंदर नहीं जाड़ा जावेगा।

(४) यदि कोई दरखास्त किसी कैसला मालूम (Award) की मसूखीके लिये दी जावे तो जो समय उस कैसला साज़िमी में नक़्ते हासिल करनेमें लगेगा वह मियाद मुकर्ररमें छुटार नहीं जाड़ा जावेगा। "

ऊपर दी हुई कानून मियादकी दफा ४ व १२ की देखनेसे यह मालूम हो जावेगा कि यह दोनों दफ़ों मियादोंको बढ़ानेके समय धमें हैं। दफा ५ के अनुसार यदि कोई व्याक्त नियत लिये हुए समयके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई किसी ज़ात बकाबत बजहसे न कर सगा हो ता अदालत ऐसा बिन्दास दिन्ध जान पर मियाद समाप्त होनेके बाद भी उस कार्रवाईको मज़ूर कर सकती है।

दफा १२ कानून मियाद में यह बतलाया गया है कि जो समय नक़्ते हासिल करनेमें लगेगा वह भी अन्धवा मियादके अपील करने वाक़े या दरखास्त देने वालेको मिल सकेगा यदि उस नक़्ते हासिल करना आवश्यक हो ता ही साथ इस दफ़ामें यह भी बतलाया गया है कि जिस दिन कैसल या हुक्म सुनाया जावे उस दिनको भी मियादमें नहीं जोड़ेंगे अर्थात् उसके दूसरे दिनसे मियादका समय जाड़ा जावेगा।

कानून मियादकी दफा ४ वा देखनेसे यह प्रकट होता है कि उसके अनुसार मियाद बढ़ानेके लिये अदालत बाध्य नहीं है उसमा बढ़ाना न बढ़ाना अदालतमा स्वाध पर निर्भर है जल् कि ज़िम्मेदार एजमें (Attorney) शर्तके प्रयोगसे प्रकट होता है परन्तु कानून दिवालयकी बर्तवाइयोंके सम्बन्धमें उस दफ़ामें बत ही फ़ादा उठाया जासकता है जसा कि कायदा दीवानीके आर बायोंके लिये उठाया जासकता है।

दफा १२ कानून मियादके देखनेसे यह बात भली मानी प्रकट है कि नक़्तेका समय व कैसला सुनाया जाने वाला दिन मियादमें हर्गिज शामिल नहीं किया जाना चाहिये अर्थात् वह अपाल रुकने व खेले या दरम्मास्त देने वालेकी अवश्य छुटने लिये जावेगे। इस दफ़ामें दफ़ाओंके कानून दिवालय की कार्रवाईयोंमें लागू हो जानेसे दिवालेकी कार्रवाईयोंमें बड़ी सुविधा हो गई है। इस दफ़ामें यह भी साध कर दिया गया है कि दफा ४ के अनुसार दिये हुए हुक्मकी भी कानून मियाद की दफा १२ के अनुसार ठिक ही समझना चाहि।

उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई दिवालिख करार दिये जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया हो तो वह समय जो दिवालिख करार दिये जाने व मसूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता हो मियादमें बड़ा दिया जावेगा क्योंकि इन तारीखोंके दर्मियान किसी कर्मचारीको भालेज करनेवा इक नहीं रहता है तथा एक प्रगारसे उसकी कार्रवाई इस दामियानमें रोक दी जासकती है इस कारण इस मियादका अमली कानूनी मियादमें जोड़ दिया जाना जस्बि मतीन होता है और इसी मसालेसे तलेक बमेगने यह उपदफा इसमें जोड़ दा है। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि उपदफा इन दो प्रकारके मामलोंमें लागू नहीं हवेगो (१) जल् कि दफा २८ (२) के अनुसार गान्छि दापर करने या दरखास्त देने की आज्ञा दी जाबुरी हो तथा (२) जल् कि गान्छि या दरखास्त ऐसे कर्जेके सम्बन्धमें होवे जल् कि साविन किया जासकता हो परन्तु साविन नहीं किया गया हो। तबने यह प्रकट है कि नक़्ते कस्तरनाह इस उपदफामें लागू नठा सके है मिरहाने अपना कर्म इस एक्टके अनुसार साविन कर दिया है।

यदि दफा २८ (२) के अनुसार नालिया करने व डिब्री इनसाय कराने की आज्ञा ऐसी शर्तों साथ दी गई हो गिनकी वजहसे वह डिब्री जागी नहीं कराई जानती हो तो ऐसी आज्ञाकी कोई अतर नहीं रहता है और इस आज्ञाके होते हुए भी कर्मचारीको भिन्नार्थमें वह समय ओ दिवालिया करार देने व मसूख होने बाड़ी तारीखोंके बीचमें पड़ता है भिन्नार्थ दिया जानेवाला, देखो—A. I. R. 1925 All. 735.

II दफाके अन्तमें जो शर्त लगा दी गई है वह बड़े महत्व की है व उसका चिक उपर किया जायदा है अर्थात् यह कि यह दफा उहाँ कबोंसे सम्बन्ध रखने वाली नालियों व दस्तावेजोंके लिये लागू होगी जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जायकते हैं व साबित किये गये हों ऐसे कबोंके लिये नहीं जो साबित किये जासकते हैं पर साबित नहीं किये गये । यदि कोई व्यक्ति दिवालियाकी कर्तबाई जाती रहते हुए दिवालियाके विरुद्ध दावा कर देवे तो वह दफा ७८ से लाभ नहीं उठा सकता है । इस दफाना फायदा उठी शर्तसे भिन्न सकता है जो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके बाद करीबाने करे, देखो—A. I. R. 1928 Mad 977.

जो कि दफा ७८ के अनुसार कानून भियादरी दफा ५ अर्थात् व दस्तावेजोंके लिये लागू हैं परन्तु इस दफा ५ का प्रयोग दिवालिया करार दिये जाने वाली दस्तावेजोंके लिये नहीं होना चाहिये इस प्रकारका निर्णयन दफा ७८ क अनुसार दर्शावत नहीं है इस कारण यदि तीन महीनेसे अधिक की देर हो गई हो तो इस दफाके अनुसार करीबाने नही हो सकेगी देखो—A. I. R. 1928 Smd. 177.

दफा ७९ में कर्ता सम्बन्धित बरिना एक सीधा तरीका बता दिया गया है लेकिन उसकी वजहसे कर्ताके किसी दूसरे तरीकेसे साबित होने में बाधाबद नहीं पड़ता है इस कारण यदि दिवालियाके अपनी दस्तावेजोंमें कोई कर्म दिखला दिया हो तथा इसी प्रकार वह साबित हो चुका हो तो यह मान लिया जायेगा कि वह कर्ता साबित किया जायदा है अतः वह कर्मचारी वह समयको मुजरे पानेवा छुटकर है जो दिवालिया करार दिये जाने तथा दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके दामियान पड़ना हो अर्थात् बसे दफा ७८ के अनुसार लाभ उठानेवा अधिकार प्राप्त है, देखो—A. I. R. 1929 Cal. 169 (2)

दफा ७९ नियम बनानेके अधिकार

(१) कलकत्ता हाईकोर्ट (First Court of Judicative of Fort William in Bengal) सपरिषद गवर्नर जनरल हिन्दीकी आज्ञा लेनेके पश्चात् तथा दूसरे हाईकोर्ट प्रांतिक सरकार की आज्ञा लेनेके पश्चात् इस एक्टकी कार्य रूपमें परिचित करनेके लिये नियम बना सकते हैं ।

(२) पिछले अधिकारोंको मानते हुए तथा उनकी अवहेलना न करते हुए इन नियमोंमें नीचे दी हुई बातें हो सकती हैं:—

(ए) सरकारी रिसीवरों (Official Receivers) को छोड़ कर अन्य रिसीवरोंकी नियुक्ति तथा उनके भत्तेके लिये नियम तथा सब रिसीवरोंके हिसाब जांचनेके लिये प्रवन्ध व उस औचार्डके प्रवन्धका खर्च किस प्रकार होना चाहिये

(बी) कर्मचारीकी सभा किये जानेके नियम

(सी) जब कि कर्मदारके कोई दूकान (Firm) हो तो किस प्रकार कार्यवाई होना चाहिये

(डी) जिन जायदादोंका इन्तजाम सरकारीसे होना चाहिये उनमें किस प्रकार कार्यवाई होना चाहिये

(ई) किसी मामलेके लिये जो निर्धारित किया जानेको होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो ।

(३) इस प्रकार बनाये हुए सब नियम गजट आफ इन्डिया (Gazette of India) या प्राक्तिक सरकारी गजटोंमें जैसा कि मौका हो प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशित होनेके पश्चात् यह इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे कि यह इस एक्टमें शामिल हों ।

व्याख्या—

२म दफ्तेर अनुसार सब हार्डकोर्टों को अपने अपने अधिकार सीमाओं इस एक्ट का प्रयोग करने लिये नियमों के बनाने का अधिकार दिया गया है कलकत्ता हार्डकोर्ट गवर्नर जनरल हिंदू की समीपद आशा लेने पर नियम बना सकते हैं तथा दूसरे सब हार्डकोर्ट अपनी प्राक्तिक सरकारी आशा लेने पर नियम बना सकते हैं । यह नियम इस एक्टमें बर्नार्ड हार्ड कोर्टों की कार्यरूपमें परिचित करने के लिये बनाये जायेंगे । इन नियमों के बनाने के लिये हार्डकोर्ट बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए 'May' शब्द से प्रकट होता है अर्थात् नियमों का बनाना या न बनाना हार्डकोर्ट की इच्छा पर निर्भर है ।

उपदफ्ता (२) में दिखलाया गया है कि जिन बातों या समझें लिये यह नियम बनाया जाना चाहिये साथ साथ यह भी बतला दिया गया है कि इस प्रकार बनाये हुए नियमोंके इस एक्टमें दिये हुए अधिकारोंके विरुद्ध कोई अपर नहीं करना चाहिये । नियम ऐसे बनने जायेंगे जिनमें इस एक्ट के नियमोंमें कोई बाधा न पड़े ।

फलाज (५) के अनुसार नियम सिविलरी की निशुक्ति तथा उनके अन्तर्गत सम्बन्धमें होंगे व दिसादकी जाच व उस जाच सम्बन्धी जजोंके सम्बन्धमें होंगे परन्तु आधिशिष्य सिविलरीके सम्बन्धमें यह नियम नहीं होंगे ।

फलाज (६) के अनुसार नियम वर्कम्पाइजों की मार्टिंगके सम्बन्धमें बनाये जासकेंगे ।

फलाज (७) के अनुसार यह नियम बनाये जायेंगे जिसका प्रयोग किसी फर्मके दिवाल्या करार दिये जानेमें किया जासकेगा ।

फलाज (८) के अनुसार उन जायदादोंके हस्तगतके सम्बन्धमें नियम बनाये जासकेंगे जिनका इन्तजाम सरसरी तीसरे किया जानेकी है अर्थात् जिस जायदाद का प्रबन्ध अस्थायी है ।

फलाज (९) के अनुसार नियम किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें बनाये जासकते हैं जो निर्वाचित किया जानेकी होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो । यह फाल (९) मिलकुल नया है और यह प्राक्तिक कानून दिवाल्या सशोधक एक्ट न० २२ सन् १९२६ ई० के अनुसार जिसको गवर्नर जनरल हिंदू की स्वीकृति ५ सितम्बर सन् १९२६ ई० को प्राप्त हुई है, जोड़ा गया है ।

फाल (१०) से यह प्रकट है कि फर्म भी दिवाल्या करार दिये जासकते हैं इससे पहिले यह बात स्पष्ट नहीं थी । फर्म अपने शरीकदारोंका एक समुदाय नाम है मगर फर्मका नाम एक प्रकारसे एक जोड़ा नाम है जो उसके हर शरीकदारक अलहदा अलहदा नामोंके बजाय रख दिया गया है, देखो—100 I. C. 112

इस प्रकार फर्म कानूनन अपने हिसाबोंसे एक अलहदा चीज नहीं है फर्मका नाम उसके सब शरीकदारोंको एक साथ प्रकट करने के लिये रख दिया गया है । यदि कोई फर्म दिवाल्या करार दिया आवे तो उससे उसके हर मेम्बरकी दिवाल्या करार दिया जाना समझना चाहिये । देखो—A. I. R. 1926 Sind 31, 100 I. C. 112 यदि कोई फर्म कर्जदार होवे तो दिवाल्या करार दिये जानेका दरखास्त फर्मके नामसे होना चाहिये, देखो—72 I. C. 60.

उपदफ्ता (३) में यह बतलाया गया है कि इस दफ्तेरके अनुसार आ नियम बनाये जायें वह गजट आफ इन्डिया या प्राक्तिक सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाना चाहिये तथा इस प्रकार प्रकाशित किये जानेके समयसे वह नियम कानून के तौर पर समझे जायेंगे । अब तक हम प्रकार प्रकाशित न हुए वे न मान जायेंगे ।

दफा ८० सरकारी रिसीवरको अधिकारोंका दिया जाना

(१) हाईकोर्टे ऊपर दी हुई आश्वासनोंके लेनेके पश्चात् समय २ पर सरकारी रिसीवरों को नीचे दिये हुए सब या कोई अधिकार दे सकेगा लेकिन यह अधिकार ऊन्हीं मामलोंसे सम्बन्ध रखते हुए होंगे जिनके सुननेका अधिकार इस एक्टके अनुसार अदालतको होगा तथा अदालत रिसीवरके इन अधिकारोंमें परिवर्तन कर सकेगी :-

(बी) सूची तैयार करें और कर्जद्वाराओंके सुधूत मंजूर या खारिज कर सकें

(ई) ज़रूरी मामलोंमें दरमियानी हुक्म दे सकें

(एफ) एकतर्फीया धिला विरोध की हुई दरखास्तोंको सुन सकें तथा उनको तय कर सकें

(२) दफा ६८ में दिये हुए अपीलकें नियमोंका ध्यान रखते हुए सरकारी रिसीवर द्वारा दिये हुए हुक्म व उसके किये हुए काम जो उसने ऊपर दिये हुए अधिकारोंके अनुसार किये हों वह यतौर अदालतके किये हुए हुक्म व कामके समझे जायेंगे ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के भाग (ए), (सी) व (डी), प्रान्तिक दिवालिया कानून सशोधक एक्ट न० २९ सन् १९२२ (ई०) के अनुसार इस दफासे निष्काट दिये गये हैं । अब इस उपदफामें केवल कलत्र (बी), (ई) व (एफ) रह गये हैं ।

फलाज (ए) में दिया हुआ था “ कि वह दिवालियेकी दरखास्तोंसे सुन सकें तथा उसे दिवालिया कला दे सकें ” तथा भाग (सी) में दिया हुआ था “ कि वह बहाल (Discharge) का हुक्म दे सकें ” तथा भाग (डी) में दिया हुआ था “ कि वह तरफिया या समझते की स्वीम मंजूर कर सकें । ” इस प्रकार इन प्रांतीय अनुसार जो अधिकार रिसीवरको दिये जासकते थे अब सशोधित एक्टके अनुसार नहीं दिये जासकेंगे । इस उपदफामें उन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है जो हाईकोर्टे प्रान्तिक सरकार या भारत सरकारकी आज्ञा लेने पर आक्षेपिय रिसीवरको दे सकते हैं । जो अधिकार अब इस प्रकार दिये जासकते हैं वह इस उपदफाके भाग (बी), (ई) व (एफ) में दिये हुए हैं ।

फलाज (बी) में अनुसार सूची तैयार करनेमें रिसीवर कोई मामला कतई तौरसे बहिस्सियन अदालतके नहीं तय करता है 41 Ind. 30 अर्थात् यदि रिसीवर किसी बर्खान्नाहका नाम सूचीमें एक बार दर्ज करे तो उसमें दफा ५० के अनुसार परिवर्तन निया जासकता है या दफा ५३ के अनुसार भी कार्रवाई उस सम्बन्धमें की जासकती है । इस भागके अनुसार आक्षेपिय रिसीवरको सूची ही तैयार करनेके अधिकार नहीं दिये जासकते हैं किन्तु उसे कर्जद्वाराओंके सुधूत मंजूर करने तथा उनके खारिज करनेके अधिकार भी दिये जासकते हैं ।

फलाज (एफ) के अनुसार आक्षेपिय रिसीवरकी एकतर्फी दरखास्तें सुननेका अधिकार दिया जासकता है निम्न विधय न किया जासकता है तथा वह ऐसा दरखास्तोंका फैसला भी कर सकता है । परन्तु ऐसी दरखास्तोंका विरोध होताही उसे उस दरखास्तके सुनने या उसका फैसला करनेका अधिकार नहीं रहेगा भाग (ई) के अनुसार वह जरूरी मामलोंमें दरमियानी (Interim) हुक्म भी दे सकता है ।

रिसीवर तथा आक्षेपिय रिसीवरमें जो अन्तर इस दफासे प्रष्ट होता है वह यह है कि आक्षेपिय रिसीवर दफा ८०

के अनुसार दिये हुए अधिकारों के कारण अदालती (Judicial) अधिकार नहीं सच्चा है फलतः मामूली रितीवरों से प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है ।

उपदफा (२) दफा १८ के अनुसार आर्किशियल रितीवर के हुक्मों की अपील अदालतों की जासकती है उसकी अपील इर्दकैरमें नहीं की जाना चाहिये देखो—38 Mad. 15. यदि इस दफते के अनुसार दिये हुए अधिकारों के आधार पर आर्किशियल रितीवर कोई फैसला करे या हुक्म देवे तो उसे अदालत द्वारा दिया हुआ फैसला या हुक्म मानना चाहिये ॥ उस फैसले की या हुक्म की अपील अदालतमें अवश्य की जासकती है यदि अपील न की गई हो तो वह फैसला या हुक्म बदल करायम होगा व उसे अदालत द्वारा दिया हुआ हुक्म या फैसला मानना चाहिये ।

दफा ८१ प्रांतिक सरकार द्वारा कुछ नियमोंका प्रयोग कुछ अदालतोंके लिये रोक जाना

प्रांतिक सरकारको अधिकार है कि वह सपरिषद् गवर्नर जनरल (Governor General in Council) की स्वीकृति लेनेके पश्चात् प्रांतिक सरकारी गजट द्वारा यह घोषित कर देवे कि उसके शासित प्रदेशके किसी हिस्सेकी अदालत या अदालतोंके विवालीया सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये इस एक्टके शिड्यूल न० २ (Schedule II) में दिये हुए कौनसे नियम लागू नहीं होंगे ।

व्याख्या—

जुनि देशके सभी भाग एक प्रकारके नहीं होते हैं ॥ कारण यह उचित समझा गया है कि प्रांतिक सरकारोंकी अधिकार दे दिया जाये कि जिनमें वह अपने शासित प्रदेशके किसी भागमें यदि किसी नियमका प्रयोग किया जाना उचित न समझे तो उसका प्रयोग बन्द न होने देवे । परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि प्रांतिक सरकार इस दफ्तामें कतलमें हुए अधिकारका प्रयोग उसी समय कर सकेंगी जब कि वह इसके लिये सपरिषद् गवर्नर जनरलमें स्वीकृति ले चुकी हो अन्यथा नहीं । और इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि यह दफा कानून विवालीयाके हर नियमके लिये लागू नहीं है किन्तु इसका प्रयोग केवल उन्हीं नियमोंके सम्बन्धमें किया जासकता है जो सूची न० २ (Schedule II) में दिये हुए हैं । प्रांतिक सरकार अपने शासित प्रदेशकी अदालत या अदालतोंके लिये ही इस प्रकार की घोषणा कर सकत है । अंग्रेजी एक्ट की इस दफ्तामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि कोई प्रांतिक सरकार इस दफ्ताके अनुसार कार्यवाही करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह आवश्यक समझे व जिन नियमोंके लिये आवश्यक समझे इस दफ्ताकी शर्तों का ध्यान रखते हुए उक्त घोषणा कर सकती है अंग्रेजी एक्ट की इस दफ्तामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि इस दफ्ताके अनुसार जो हुई प्रांतिक सरकार की घोषणा मानना आवश्यक है अर्थात् उसकी अवहेलना नहीं की जासकती है । इस दफ्तामें बतलाने हुई घोषणा प्रांतिक सरकारों गजटमें प्रकाशित किया जाना भी एक आवश्यक बात है ।

दफा ८२ बचत (Savings)

इस एक्टमें बतलाई हुई—

(ए) किसी बातका प्रभाव प्रेसीडेन्सी टाउनस इन्सोल्वेन्सी एक्ट १९०६ (The Presidency Towns Insolvency Act 1909) या लोअर बर्मा कोर्ट्स एक्ट १९०० (Lower Burma Courts Act 1900) की दफा ८ पर नहीं पड़ेगा, अथवा

(बी) कोई बात उन मामलोंके लिये लागू नहीं होगी जिनके लिये दक्षिण एग्रीकल्चर-रिस्ट्रिक्ट रिलीफ एक्ट १८७३ (The Dekkhan Agriculturists' Relief Act 1879) का चौथा अध्याय (Chapter IV) लागू है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टका कोई प्रभाव प्रेसीडेन्सी याउन्स इस्ताब्लिशमेंट्स एक्ट पर नहीं पड़गा अर्थात् वह एक्ट इतने भिन्न है तथा उसका प्रयोग भिन्न प्रकार होना बतलाया गया है या भिन्न स्थानोंमें होना बतलाया गया है वहां उसी प्रकार किया जावेगा उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है । इसी दफा (ए) में यह भी बतलाया गया है कि छोटा बर्मा कोर्ट्स एक्ट १९०० की दफा ८ पर भी इस एक्टका कोई प्रभाव नहीं पड़गा अर्थात् उनका भी अवहेलना नहीं की जा सकती । दफा (बी) के अनुसार दक्षिण एग्रीकल्चररिस्ट्रिक्ट एक्ट १८७९ का चौथा अध्याय उन मामलों के लिये लागू होगा उन मामलोंमें भी यह एक्ट लागू नहीं हो सकेगा ।

दफा ८३ मंसूखी (Repeals)

(१) (मंसूख होगया)

(२) यदि इस एक्टके प्रारम्भ होते समय किसी प्रचलित कानून या दस्तावेजमें सन् १८७७ या १८८२ ई० के जाबता बीबानीके बीसवें प्रकरण (Chapter XX) का हवाला दिया गया हो या उन प्रकरणोंकी किसी दफाका हवाला दिया गया हो तो जहां तक हो सकेगा, उन हवालों के लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाले इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी दफाके हैं (ऊपर कहे हुए बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मर्यादका जिक्र है) ।

व्याख्या—

इस दफारी पहिली उपदफा रीपीलिंग एक्ट १९२७ [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] द्वारा रद्द कर दी गई है अर्थात् अब इस दफामें केवल उपदफा (२) ही रह गई है सन् १८७७ व १८८२ ई० के जाबता बीबानीके बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मर्यादका उल्लेख है । इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि इस बीसवें प्रकरणका हवाला कहीं दिया गया हो तो उन हवालोंके लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाले इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी दफाके हैं ।

सूची नं० १ (Schedule. I.)

देखो दफा ७५ (२).

यह फैसलें व हुक्म जिनकी अगल दफा ७५ (२) के अनुसार हार्डकोर्डमें हो सकती है।

दफा	फैसले व हुक्मोंका स्वभाव
४	हक (Title) (Priority) आदि सम्बन्धी प्रश्नोंका फैसला जो इन्सालवेमें पैदा हों
२५	विदेशनको खारिज करनेका हुक्म
२६	मुआवित्त (Compensation) दिलाये जानेका हुक्म
२७	दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म
२८	सूची (Schedule) के इन्दरानके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्म
२९	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूखीका हुक्म
३७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मसूख किये जाने पर दिवालियेकी जायदाद तिन शर्तोंके साथ दिवालियेकी मिलेगी वन शर्तोंके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्म
४३	बहाल (Discharge) होने वाली दुरवस्था पर हुक्म
५०	सूचीमें इन्दरान न किये जाने तथा उसके इन्दरानमें कमी किये जानेके हुक्म
५३	अपने आप (Voluntary) किये हुए इन्तकाल (Transfer) की मसूखीका हुक्म
५४	इस बातका फैसला कि कोई इन्तकाल किसी कजबदारको सर्जिड (Preference) देनेके लिये किया गया है
	नोट.—रिपीलिंग एक्ट सन् १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा इस सूचीका आखिरी इन्दरान जो दफा ६९ के बाधत था हटा दिया गया है उसमें हम प्रकाश दिया हुआ था।
६९	इस दफाके अनुसार किये जूमेके सम्बन्धमें जूम साबित होने तथा सजा दिये जाने पर (मसूख है)

सूची नं० २ (Schedule. II.)

देखो दफा ८१.

एक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोक जा सकता है ।

एक्टके नियम	विषय
दफा	
३६	सुभाषितेका दिलाया जाना (Award of Compensation)
३८ उपदफा (३)	दिवालियेको कइलाने वाली जायदाद
३४,	इस एक्टके अनुसार साबित हो सकने वाले कर्जें
३८, ३९, ४०	तस्वीया व तय करनेकी स्कीमें (Composition and Schemes of Arrangements)
४१ उपदफा १, २	पूर्ण रूपसे बहाल (Absolute Discharge) होनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें कतव्य
४५, ४६, ४७, } ४८, ४९, ५० }	कर्जों साबित करनेका ढंग
५१, ५२, ५३, } ५४, ५५ }	गिरले किये हुए सौदों (Antecedent Transactions) पर दिवालेका प्रभाव
६१ उपदफा (१) के लान (५) व उपदफा (४) को छोड़कर	कर्जोंका एक दूसरेसे पेशतर चुकाया जाना (Priority of debts)
६२, ६३, } ६४, ६५, }	हिस्सा रसदी (Dividends)
६६	दिवालिये द्वारा प्रकण्ड तथा उसको दिया जाने वाला भत्ता
७२	गिला बहाल हुए दिवालिये द्वारा कर्जें किये जाने पर उसके लिये दण्ड

सूची नं० ३ (Schedule. III.)

देखो दफा ८३.

यह सूची रिपीलिंग एक्ट १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा हटा दी गई है।

इस सूचीमें सन् १९०७ व १९१४ ई० के एक्टोंका उल्लेख था व यह बतलाया गया था कि वह किस हद तक मसूल कर दिये गये हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट रूलस (Calcutta High Court Rules)

निम्न लिखित रूलस (Rules) कलकत्ता हाईकोर्टने प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट नं० ५ सन् १९२९ ई० की दफा ७९ में दिये हुए अधिकारीके आधार पर बनाये हैं जिनके लिये भारत सरकार (Governor General in Council) की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है सर्व साधारणके भूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं —

प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट ५ सन् १९२० ई०

एक्ट ५ सन् १९२० ई० की दफा ७६ के अनुसार बनाये हुए नियम ।

१ नीचे दिये हुए नियम प्रान्तिक कानून दिवालाके रूलस कहलायेंगे । इन नियमोंमें जो नमूने (Forms) बतलाये गये हैं उनका प्रयोग सम्योचित परिवर्तनके साथ उन बातोंके लिये किया जावेगा जिनसे कि इनका सम्बन्ध भिन्न भिन्न रूपसे हैं ।

नोट : — नमून आगे चल कर भिविल प्रोसेस फार्म (Civil Process Forms) नं० ११७ से नं० १५० तक देने गये हैं ।

२ हर एक दिवालेकी दरवास्त दिवालेके रजिस्ट्रारमें चढाई जावेगी और यह रजिस्ट्रार दिवालेके सम्बन्धमें कार्रवाई कराने वाली हर एक अदालतके पास रखे आवेंगे । उस रजिस्ट्रारमें तर्तीबी सख्या (Serial Number) दी जायेगी और उस सामलेके सम्बन्धमें जो संय कार्रवाईया वादमें की जावेगी उनमें वही संख्या (Number) रखी जावेगी ।

३ दिवालिया सम्बन्धी सब कार्रवाईयाका मुआयना उन समयों पर तथा उन शर्तोंके साथ किया जासकता है जो डिस्ट्रिक्ट अज नियत करे और यह मुआयना रिमांडर, कर्जदार या कोई कर्जएवाह जिसका कर्ज साबित हो चुका है कर सकता है या इनका ओरसे इनके कानूनी मुसाहदे (Legal Representative) कर सकते हैं ।

४. जब कभी किसी नोटिस या किसी दूसरे सामलेका इस एक्ट या इन नियमोंके अनुसार सरकारी गजट (Official Gazette) में प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होने वाली तारीख व गजटका इवाला दिया हुआ होगा भित्तिलमें शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्टरजक्ट ऑर्डर शीट (Order Sheet) में भी भर दिया जावेगा ।

५ दफा १९ (२) के अनुसार पिटीशनके सुने जानेकी तारीख नियत किये जानेका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजट (Local Official Gazette) में प्रकाशित किया जावेगा तथा उन अखबारोंमें भी वह नोटिस मुद्रित किया जावेगा जिनके लिये अदालत हुजूम देवे । नोटिसको एक एक नकल रजिस्ट्रारके द्वारा सब कर्जदारोंके पास उनके उस पतेसे मानी जावेगी जो पिटीशनमें दिया गया हो । यही तरीका उन नोटिसोंके सम्बन्धमें भी प्रयोग किया जावेगा जो दफा २८ (१) के अनुसार वरक्रीयके प्रस्ताव या तय करनेकी स्कीम (Scheme of Arrangement) के लिये दिये जानेको होंगे ।

६. दफा २० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुजूम की सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है उन समाचार पत्रों

Newspapers) में भी प्रकाशित की जासकती है जिनके लिये अदाकत आज्ञा देवे । यदि कर्जदार सरकारी चाकिम (Government Servant) होवे तो इस हुक्मभी नकल उस आफिसके खबरे बडे हाकिम Head of the Office) के पास भेजी जावेगी जहा कि वह कर्जदार नौकर होवे ।

सही तरीका (Procedure) उन हुक्मोंकी सूचना (Notice) के सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा । दफा ३० (२) के अनुसार दिवालिया कारर दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके लिये दिये जावेंगे ।

७. दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदाकत द्वारा दिये जानेको हों उनकी सामील कर्जदारवाह या उसके कील पर की जावेगी या वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजा जावेगा ।

८. अन्तिम हिस्सा रसदी (Final dividend) बाटनेसे पहिले रिसीवर दफा ६५ के अनुसार जो नोटिस इन कर्जदारवाहोंके नाम जारी करेगा जिनका कर्जदारवाह होना उल्लेख किया जाचुका है परन्तु जिनके कर्ज आविश नहीं किये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजे जावेंगे ।

९. दफा ४१ (१) के अनुसार बहाल (Discharge) की दुरुखास्त सुननेके लिये जो तारीख तयत की जावे उसकी सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित की जावेगी तथा उन समाचार पत्रोंमें भी दी जावेगी जिनके लिये जज आज्ञा देवे और उसकी नकलें सब कर्जदारवाहोंके पास रजिस्ट्री खत द्वारा भेजी जावेंगी चाहे उन्होंने अपना कर्जा साधित किया हो या न साधित किया हो ।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें आकलानेकी रसीद हाजिर की जावे तथा अदाकतके किसी अकनर या आफिसलू रिसीवर का सर्वेफिरेट या किसी अन्य रिसीवरका इकतनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो वह इस बातकी कारी सहदात मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पक्षमें भेजे गये हैं उसकी ठीक तौरसे भेजे गये हैं ।

११. प्रकाशित किये जानेके निर्धारित नियमोंके आतिरिक्त अदालतकी आज्ञाबुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जासकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें छिपकवा देनेसे अथवा जिस गायमें दिवालिया रहता हो जहा सुनादी करा देनेसे ।

रिसीवर

१२. रिसीवरकी नियुक्तिका हुक्म फिल कर तथा अदालतके इस्ताहर होकर दिया जावेगा । इस हुक्म की नकल अदालतकी मोहर लगा कर कर्जदारके पास भेजी जाना चाहिये तथा वह नकलें नियुक्त किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जाना चाहिये ।

१३. (१) अदालतकी चाहिये कि वह रिसीवरका अम्बल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी लैकटाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे एक भाग सहपूज कर्जदारों (Secured Creditors) की जमानतों (Securities) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया बसूल किया जावे उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस रकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जो वह दिरसा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे ।

(२) जब कि रिसीवर सहपूज कर्जदारवाहोंकी जमानत (Security) का रखरखाव करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा कर्जदारवाहोंके लाभ में देवते हुए अधिक अम्बल (Remuneration) दिला सकती है ।

१४. रिसीवर शोकड या अन्य हिसाबकी किताबें तथा कागजात रक्केता जिसमे जायदाद सम्बन्धी वस्तुके प्रत्यक्षकी ठीक ज्ञान हो सके और वह हिसाब किताब उन समयों पर तथा उस प्रकार दायित करेगा जिस प्रकार कि अदालत हुक्म देवे । उन हिसाबोंकी जाच वह लोग करेंगे जिनके लिये अदालत हुक्म देवे । हिसाब की जाच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगी और वह दिवालिये की जायदादसे दिया जावेगा ।

१५. वह कर्जदार जो अपना कर्ज साधित कर चुका है अदालतमें इस बातकी दुरवास्त दे सकता है कि उसको रिसीवरके कुछ हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे और जो कि शोकटमें उस वक्त तक दिखलाया जा चुका हो और उसकी वह खर्चा अदा करने पर नकल दी जावेगी जो इस अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंके पास कर्जके लिये बतलाये गये हैं ।

१६. यदि किसी मामलेमें कर्जदारोंकी मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता हो और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तरफिया या तय किये जाने की स्कीम (Scheme) दफा ३८ के अनुसार ब्याहता हो तो रिसीवर ७ दिनका नोटिस कर्जदार व सब कर्जदारोंको इस बातके लिये देगा कि ऐसी मीटिंग किम तारीख पर तथा किस स्थान पर होगी। ऐसे नोटिस रजिस्ट्रीमुद्रा जत द्वारा दिये जावेंगे ।

कर्जोंका साधित किया जाना

१७. कर्जदारोंका सुनूब सिविल प्रोसेस फॉर्म नं० १२१ [Civil Process Form No 146 in Volume II] के अनुसार समयावधिक परिवर्तनके साथ होना चाहिये ।

१८. यदि किसी मामलेमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरों व दूसरे काम कामे वारों की बजत (Wages) के बहुतसे ढाबे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुनूब या उन सब कर्जदारों की तरफसे किसी दूसरे व्यक्ति का सुनूब बर्नाम समझा जावेगा । इस प्रकारका सुनूब सिविल प्रोसेस फॉर्म (Civil Process Form No. 147 in Volume II) के अनुसार होना चाहिये ।

यदि कर्जदार कोई फर्म (Firm) होवे तो उसका तरफिका ।

१९. यदि किसी सूचना (Notice), दखान (Declaration), दरवास्त (Petition) या किसी दूसरी दस्तावेजके जर्जर (Affidavit) की आवश्यकता हो और उस पर किसी कर्जदारों या कर्जदारोंके फर्म के दस्तखत कर्मक नामसे किये जावें तो जो हिस्सेदार फर्म की ओरसे दस्तखत करे उसको अपने भी दस्तखत करना पड़ेगा जिस कि प्रायः एण्ड कम्पनी वगैरिये जेरमनीय फर्मका एक शरीकदार " Brown & Co by James Green a Partner in the said firm "

२०. यदि किसी सूचना (Notice) या दरवास्त (Petition) की सामील जाती तोरसे होना आवश्यक हो और उसकी सामील अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर उस फर्मके स्वयं रोजगार की जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्मका प्रबन्ध या इस्तरेख करने वाले व्यक्ति पर की गई होगी तो वह मान लिया जावेगा कि उसकी सामील वाक्यावृत्ति फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है ।

२१. पिउली दफामें बतलाया हुआ नियम जहां तक मामलेके अनुसार सुमकिन होगा उस मामलेमें भी लागू होगा जब कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे नामसे अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर कारागार करता होवे ।

२२. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालिये की दुरवास्त देवे तो उस दरवास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होने और यदि उस दरवास्तमें फर्म की तरफसे किसी एक शरीकदारने दस्तखत किये हों तो उस

हर वामनके साथ उस शरीकरके एक हलफनामा लगाता रहेगा कि फर्मके सब शरीकरों की राय उस दरवानको देनेके लिये है ।

२३ यदि किसी फर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जाये तो यह समझा जायेगा कि फर्मके वह सब शरीकर जो हुक्म देत समय शरीकर हैं दिवालिया करार दे दिये गये हैं ।

२४ सत्रोंके मामलामें कर्जदार सत्रोंके मामलोंके सम्बन्ध की सूची (Schedule) पेश करेंगे और हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामले की सूची भी पेश करेगा ।

२५ संयुक्त कर्जदार तथा कर्जानाओं के अलहदा २ समूह अलहदा २ तरीक्या या तय होने की स्कीमको मंजूर कर सकते हैं । जइतक मुमकिन हो सकेगा संयुक्त कर्जदारों द्वारा मंजूर ठिया हुआ महान निर्धारित रूपसे स्वीकार किया जावगा बिल इस बातका खयाल किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जदार या कर्जदारान उस तरीक्या या स्कीम को स्वीकार नहीं किया है ।

२६ यदि तरीक्या या स्कीम का प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो अपना फर्म के शरीकरोंमें अलहदा २ तौर से किया हो तो संयुक्त कर्जदारों को किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और हमपर उनके बोड १५५५ आयेगे उस समय अलहदा कर्जदारोंके समूहोंका अलहदा ध्यान नहीं दिया जायेगा । और जो प्रस्ताव कर्जदारोंके किसी साथ सनून से किया गया हो उसपर यह समूह अलहदा से विचार करेगा व बोड देगा कुल कर्जदारों से उसका सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रस्ताव भिन्न २ रूपसे तथा भिन्न २ तरीक्येके लिख किये जा सकते हैं । जब कि तरीक्या या स्कीम स्वीकार करली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म अभी बंद तक मसूल होगा जहां तक कि उनका उस जयदाद से तात्लुक है जिसके कर्जदारों ने तरीक्या या स्कीम को मान लिया है ।

२७ यदि किसी शराकती फर्म के दो भा दे से अधिक मेम्बरान कोई जुदागाना फर्म चलाते हों तो उस जुदागाना फर्मके कर्जदारान एक जुदागाना कर्जदारोंका समूह समझा जावगा । और यह उसी मर्यादाको जाँचेगे जैसे कि फर्मके किसी मेम्बरके अलहदा से कर्जदारान होवे । यदि ऐसे जुदागाना फर्म (Assets) से कोई फाइल रकम बचे तो वह उस फर्मके शरीकरों में हिस्सा इसकी हिस्सापत इसकी अलहदाकी जायदाद में ल जाई जावेगी ।

दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद का धेवा जाना ।

२८ यदि कोई रितिवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं एक्ट की दफा ५८ के अनुसार दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद को धेवे तो उस जायदाद के लिये दस्तावेज बनाना शरीदार अपने खर्च तैयार करावेगा और उस अदालतके हाकिम के इस्तजत होंगे । यदि रीगुलरीको कोई रस्य होगा तो वह भी शरीदार बरदाश्त करेगा ।

हिस्सा रसदी (Dividends)

२९ हिस्सा रसदी (Dividend) का करवा कर्जदारोंके धारणा करने पर अपने भिमेदारी पर हाकके अरिये भेजा जासकता है ।

सरस्तीकी कार्रवाई

३०. यदि दफा ७४ के अनुसार किसी जायदादका इन्तजाम भारतीय तौरमें किये जानेका हुक्म होवे तो अदालतके किसी खास हुक्मका ध्यान रखते हुए हम एक्टके नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारसे संतापित होंगे ।

- (i) किसी कार्रवाईका प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या अन्य किसी समाचार पत्रमें नहीं किया जावेगा।
- (ii) दरखास्त (Petition) पर तथा बादकी सब कार्रवाइयोंमें 'सरसरी का मामला' (Summary Case) लिख दिया जावेगा।
- (iii) कर्जदाहोंकी दरखास्त (Petition) के सुने जानेकी सूचना (Notice) सिविल प्रोसेस फार्म न० १५० (Civil Process Form 150 Vol. II.) के अनुसार दी जाना चाहिये।
- (iv) अदालत कर्जदारका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें लेगी परन्तु वह कर्जदाहोंकी सीटिंग करनेके लिये बाध्य नहीं है जो कर्जदाहोंकी हक होगा कि उनकी जवाबदेही सुनी जावे तथा वह कर्जदारसे जिरह कर सके।
- (v) अधिकतर रसीदोंके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत दफा ५८ के अनुसार कार्रवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालियेकी कार्रवाईमें खर्चा कम हो जावे अर्थात् खर्चोंकी बचत हो सके।

खर्चा।

३१. उन सब कार्रवाइयोंका खर्च जो दिवालिया करार दिये जानेके हुकम तक होगा तथा जिसमें दिवालिया करार दिये जानेका हुकम भी शामिल है कार्रवाई करने वाले व्यक्ति पर रहेगा परन्तु जब दिवालिया करार दिये जाने वाला (Adjudication) हुकम हो जावे तो दरखास्त देने वाले कर्जदाहका उचित खर्च दिवालियेकी जायदादसे विलगाया जावेगा।

३२. यदि तत्कीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जावे तो तत्कीया या स्कीमकी दरखास्तके लिये तथा उसके सम्बन्धमें किये हुए कर्जदारके खर्चोंको उसकी जायदादसे नहीं विलगाया जावेगा।

सिविल प्रोसेस नं० १३७.

कर्जदारकी दरखास्त

दफा १३ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०
.....सायल

मैं (ए) अधिष्ठतर (बी) का रहने वाला हूँ (या मैं व्यापार करता हूँ या लाभके लिये काम करता हूँ अथवा (सी) के हुकमके अनुसार (बी) में हिरासतमें हूँ। अपने कर्जोंकी अदायगीमें असमर्थ होनेके कारण दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त देता हूँ। मेरे ऊपर कुल (डी) रुपयेका कर्ज है जिसका इन्दराज तफसीलवार इस दरखास्तके साथ दी हुई सूची (ए) में दिया है और उस सूचीमें मेरे सब कर्जदाहोंके नाम व पते जहाँ तक मुझको मालूम है या जहाँ तक मुझको मालूम हो सके हैं दिये हुए हैं। मेरे पास जितनी जायदाद है उसकी तादाद व तफसील सूची (बी) में जो इसके साथ दी जा रही है दिखलाई गई है और उस सूचीमें रख्योंके अतिरिक्त जो जायदाद है उसकी तफसील तथा जिस जगह या जिम्मे जगहोंमें वह जायदाद है उनका उल्लेख भी किया गया है।

मैं अपनी सब जायदाद अदालतकी मुसुदगीमें देने को तैयार हूँ केवल उन चीजोंको छोड़ कर जा कानून किसी इजराय डिक्लीमें कुक व विलियम होनेसे बरी हूँ (परन्तु हिसाबकी किताबोंको उन चीजोंमें नहीं समझना चाहिये) मैंने इससे पहिले कभी दिवालिया करार दिये जानेके लिये कोई दरखास्त नहीं दी है (या मैं सूची (सी) में दिवालिया करार दी जाने वाली दरखास्त या दरखास्तोंकी तफसील (ई) देता हूँ । तबरीक ह्वास्त उसी प्रकार होना चाहिये जैसे कि अभी दावाकी तस्दीक होती है ।

दस्तख्त " " " " " " " "

नोट :-जहां पर (ए) दिया हुआ है वहां कर्जदारका नाम व पता दिया जाना चाहिये ।

जहां पर (बी) लिखा हुआ है वहां जगहका नाम व पता होगा चाहिये ।

जहां पर (सी) लिखा हुआ है वहां अदालतका नाम तथा उस डिक्ली की तफसील व इवाला होना चाहिये जिसके इजरायमें वह गिरफ्तार हुआ हो या जिसके इजरायमें जायदाद कुक हुई है ।

जहां पर (डी) लिखा हुआ है वहां पर यह दिखलाना चाहिये कि कौनसे वर्ग मसफूत हैं व वह किस प्रकार मसफूत हैं ।

जहां पर (ई) लिखा हुआ है उसमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये ।

(१) यदि दरखास्त दिवालिया कारिम की गई हो तो वह किस कारण कारिम की गई थी ।

(११) यदि कर्जदार पहिले दिवालिया करार दिया जा चुका हो तो उसके दिवालिया करार दिये जानेका ध्येय और यह भी बतलाना चाहिये कि आपा कोई पिछड़ी दिवालिये की दरखास्त मसूल (Annul) की गई थी या नहीं और यदि मसूल हुई थी तो क्यों ।

सिविल प्रोसेस नं० १३८

दिवालिये की दरखास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जद्वाराओंको दिया जाना चाहिये

दफा १९ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० " " " " " " " "

दरखास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

जुंकि

ने इस अदालतमें प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त ता० सन् १९ को दी है और उस कर्जदारने जो कर्जद्वाराओंकी फिहरिस्त दाखिल की है उसमें तुम्हारा नाम भी दिखलया है तुमको इतका पता जाती है कि इस अदालतने ता० सन् १९ उस दरखास्तके सुने जानेके लिये तथा कर्जदारके बयानके लिये मुकदर की है । अगर तुम इस मामले की पैरवी किया चाहो तो या तो स्वयं हाजिर हो या पूरी हिरासत देकर किसी वकीलके जरिये हाजिर हो । तुम्हारा कर्ज जो दरखास्तमें दिखलया गया है उसकी तफसील इस प्रकार है ।

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १३६

दिवालिया कर्जदार दिये जानेका हुक्म

दफा २७ ग्रान्ठिक कानून दिवालिया

बमदास्त साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

इस दरखान्त मुबाराक सन् १९ जो खिलाफ (यहा पर कर्जदारका नाम व पता होता चाहिये) के गुजरी है व इस दरखास्त (यहा पर रिजिस्टर, कर्जदार या कर्जवाहका नाम होगा चाहिये) के व इस दरखान्तको पढ़ने व सुननेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जाये तथा वह दिवालिया करार दिया जाता है ।

यह भी हुक्म दिया जाता है कि कर्जदार मजदूर आज की तारीखसे के अन्दर अपने षहाल (Discharge) किये जाने की दरखास्त देवे ।

तारीख

सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४०

उस कर्जवाहकी दरखास्तका नोटिस जिसका नाम सूचीमें दर्ज नहीं है

दफा ३३ (२) ग्रान्ठिक कानून दिवालिया

बमदास्त साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

अमुकवामा

दिवालिया

नं०

सन् १९ ई०

बमाम

चुंकि इस अदालतमें

ने जो कि अपनेको एक कर्जवाह आदिर करता है एक

दरखास्त इस अग्र की गुजरानी है कि उसको अपना कर्जा साबित करने की आज्ञा दी जाये तथा उसका नाम कर्जवाहकी फिदरिम्में उस कर्जेके सरन्धर्भमें लिख लिया जावे जिसे कि वह साबित कर देवे इसलिये तुमको इत्तला दी जाती है कि वह दरखास्त ता० सन् १९ को इस अदालतमें सुनी जावेगी और यदि तुमको उसका विरोध करना हो तो तुम स्वयं या बरीलके जरिये उस तारीख पर हजर हो सकते हो ।

मैंने दरखान्त व अदालतकी मुहरसे यह नोटिस आज ता०

सन् १९ को जारी किया गया ।

द० डिस्ट्रिक्ट जज

सिविल प्रोसेस नं० १४१

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम की मंजूरीका हुक्म

दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जिन०

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

... ..के दरखास्त देने पर तथा उसको पढ़ने व सुननेके पश्चात् यह हुकम दिया जाता है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम सुननेवाला सन् १९ जा जिलाफ के दिया गया था मंजूर किया जावे व यह हुकम मंजूर किया जाता है।

तारीख सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४२

तस्फीया या तय करनेकी स्कीम पर गौर करनेके लिये जो तारीख नियत की गई हो उसकी

सूचना कर्जदारको देना

दफा ३८ (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज जिन०

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

तुमको सूचना दी जाती है कि इस अदालतमें तारीख जब तस्फीया या स्कीम पर गौर करनेके लिये सुननेकी है जो कर्जदारने इस अदालतमें दी है उस तारीखसे पहिले जिस कर्जदारका कर्जा साबित नहीं हो चुकेगा वह उक्त मामले पर विचार होते समय वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि तुम ऊपर बतलाई हुई सुनवाईके समय उपस्थित होना चाहो तो स्वयं या किसी ऐसे वकीलके जरिये हाजिर हो सकते हो जिनसे इस मामलेके सम्बन्धमें पूरी हिदायत देदी गई हो।

द० जज

इस फार्माकी पुश्त पर इस प्रकार दिया जाना चाहिये।

सम्मान दाखिल किये जानेकी तारीख

तारीख जब कि सम्मान मागिरके पास भेजा गया हो

वह तारीख जब कि सम्मान तामील करने वाले चपरासीको दिया गया हो

सम्मान तामील करने वाले चपरासीके लैट्रालनेकी तारीख

वह तारीख जब कि सम्मान मागिरने अदालतको लौटाया हो

सिविल प्रोसेस नं० १४३

उन कर्ज क़र्जवाहोंकीफ़हरिस्त जो कि तस्फ़ीया या तय करने वाली स्कीम पर
विचार करते समय होवे

दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

य अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

दरखास्त दिवालिया न०

सन् १९ ई०

सीटिंग

ता०

सन् १९ को हुई

मन्दी	उन सब कर्जवाहोंके नाम जिनके मुद्दत माने जानुके हैं	यहाँ यह दिखलाना चाहिये कि किन २ कर्जवाहोंने बोट दिये हैं सगा कर्जवाहोंने बोट स्वयं दिये हैं या बकीलके जरिये	असासा (लहनेकी सादाद)	साबित किये हुए कर्जोंकी तादाद

यह सत्या जो बहुमतके किये आवश्यक है.....

आवश्यक तादाद

ह०

सिविल प्रोसेस नं० १४४

कर्जवाहोंको बहाल होने की दरखास्तकी सूचना

दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

य अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

सुकदमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

.....सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि अब दिवालियाने इस अदालतमें अपने बहाल (Discharge) किये
जानेकी दरखास्त दी है और अदालतने ता० सन् १९ वक्त यजे यस
दरखास्तको सुननेके लिये नियत किया है ।

आज

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज

नोट :—इस फार्मकी पुस्त पर दफा ४२ (१) में बतलाये हुए नियम दिये जाना चाहिये ।

सिविल प्रोसेस नं० १४५

आपन्दा होने वाली आमदनी या मिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्त लगा कर
बहाल होनेका हुक्म दिया जाता

दफा ४१ (२) (ए), (बी), या (सी) प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्मा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

... .. सायल

दिवालियेके दरखास्त देने पर जो कि तारीख सन् १९ को
देवा किया करार दिया जा चुका है तथा रिसीवरकी रिपोर्ट पर विचार करनेके बाद व कर्जदारानके
तुलनेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि दिवालिया मुकद्मा (ए) बहाल किया जावे ।

या (बी) तारीख बहाल किया जावे । या (सी) आपन्दा होने वाली
आमदनी या आने वाली जायदादके सम्बन्धमें जो शर्तें दी हुई हैं उन शर्तोंके साथ बहाल किया जावे ।

दिवालियेकी धारदा होने वाली आमदनी या मुनाफा अथवा आने वाली जायदादसे सुरक्षित
रहना साक्ष्या उसकी तथा उसके परिवारकी परवरिशके लिये निकालनेके पक्षवात् याद्वे कोई रूपया बचे (या
इस अवतका कोई खास हिस्सा) वह अदालत या आर्कोर्ट रिसीवरको उसके कर्जदारानमें तकमिम करनेके
लिये दे दिया जावेगा । दिवालिया हर साक जनवरीकी पंद्रहवी तारीखको या उसके १४ दिनके अन्दर हुक्म
द्वारा अदालतमें दाखिल करेगा जिसमें उसकी आमदनी आपन्दा आने वाली जायदाद तथा साल मर्के
आमदनीका हाल दिखलाया जावेगा और इस दिवालेके अनुसार जिस कदर बचनका रूपया उसे अदालत
दाखिल करना चाहिये वह रूपया अदालतमें दाखिल किया जावेगा या रिसीवरको दिया जावेगा यह हरमा
द्वारा दाखिल होनेके १४ दिनके अन्दर दाखिल हो जाना चाहिये ।

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४६

कर्जा सावित किया जाना—आम तरीका

दफा ४९ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

दरखास्त दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

... .. सायल

में मुकद्मा नं० सन् १९ में हलफ लेता हूँ (या हलफिया व ठीक तीसरे बयान
करता हूँ) कि दिवालियेकी दरखास्त दिये जावे
वाली तारीख अर्थात् ता० सन् १९ को कर्जदार मेरा
कर्जदार या और अर को वापस र० के मेरा मही तीसरे कर्जदार है यह कर्ज हम दरखास्तके साथ

दाखिल किये जाने वाले हिस्साबमें दिखलाया गया है तथा यह कुछ कर्ज़ या इसका कोई हिस्सा मुझे या मेरे किसी आदमीको मेरे हकमें वसूल नहीं हुआ है और न उसके लिये कोई जमानत ही दी गई है सिवाय नीचे दिये हुए रूपों या जमानतके.....

रूपोंके लिये बंद
भाला गया }

इलक की जाने वाली जगह
तारीख
किसके सामने

{ इलकनामा दाखिल करने
वालेके दस्तखत

द० जज या आफिशल रिसीवर

द० कमिश्नर

सिविल प्रोसेस नं० १४८

रिसीवरके नियुक्ति का हुकम

दफा ५६ प्रान्तिक क्रानून दिवालिया

बम्बदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

समुकदमा दिवालिया

नं०

सन् १९ ई०

शुद्धि सुसम्मी

इस अदालतके हुकमके अनुसार ता०

सन् १९ ई०

को दिवालिया करार दिया गया है और अदालतको यह प्रतीत होता है कि दिवालिया मजकूरकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाने इसलिये दिवालियेके बिन्दु जायदादकी वसूलीका हुकम दिया जाने तथा जायदादकी वसूलीका हुकम दिया जाता है और (या आफिशल रिसीवर) दिवालिया मजकूर की जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुकम दिया जाता है (यदि वह आफिशल रिसीवर न होवे तो) कि रिसीवर मजकूर रूपोंकी जमानत दाखिल करे और उसका श्रमफल (Remuneration) प्रति सैकड़ा नियत किया जावे :-

तारीख

सन्

ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४८

अन्तिम हिस्सा रसदी पाटनेका नोटिस जो कर्जब्याह बतलाये जाने वाले लोगोंको दिया जाना चाहिये ।

दफा ६४ प्रान्तिक क्रानून दिवालिया -

बम्बदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

समुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

..... साबल

तुमको इतिला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए मामलोंमें अन्तिम हिस्सा रसदी (Final Dividend) बंटे जानेका विचार है और यदि तुम अपना मतालिख ता० सन् १९ तक या उससे पहले अदालतमें संतोषजनक रूपसे साबित नहीं करोगे (या उस तारीख तक जब तक कि मोहलत अदालत दे देवे) तो तुम्हारा दावा खारिज समझा जावेगा और तुम्हारे दावेका कित्ता लिहाज किये हुए मैं अन्तिम हिस्सा रसदी बंट दूंगा ।

तारीख

सन् ई०

द० रिसीवर (पता)

सिविल प्रोसेस नं० १५०

कर्जद्वाराहानको सरसरीकी कार्यवाहका नोटिस

दफा ७४ प्रान्तिक कानून दिवालिया

बमदात्म सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९

..... साधक

तुमको इसला दी जाती है कि एक कर्जदारने वा० सन् १९ को एक दरवास्त
 इस अदालतमें दिवालिया करा दिव जानेके लिये दी है और अदालतको वा० सन् १९ को
 इस बातका यकीन कर लिया है कि कर्जदार मजकूरकी जायदाद मुकल्लिग ५००) रुपयेसे जायद नहीं है और
 इसलिये अदालतने यह हुक्म दिया है कि दरवास्त मजकूर सरसरी तौर पर सुनी जाये और अदालतने वा०
 सन् १९ दरवास्त मजकूरकी मजिद समातके लिये मुकदर की है और उसी तारीख पर कर्जदारका
 ध्यान भी दिया जावेगा ।

तुमको इस बात की भी इतिला दी जाती है कि यदि अदालत चाहिगी तो इसी तारीख पर कर्जदार
 मजकूरको दिवालिया कार दे देवेगी तथा कर्जदार मजकूरके लहनेको तकसीम कर देवेगी । तुमको अधिकार है
 कि तुम इस तारीख पर हाजिर् हो तथा अपनी शहादत पेश करो । यदि तुम कोई कर्ज साबित किया चाहो तो
 वसका सुन तुमको इस तारीखसे पहिले या इस तारीख तक अवश्य दाखिल अर्दाकत कर देना चाहिये ।

मेरे दस्तखत व अदालतकी मोहर होकर
 जारी किया गया ।

आज वा०

सन् १९

है०

द० जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूलस

दफा ७९ प्रान्तिक कानून दिवाला सन् १९२० ई के अनुसार
बनाये हुए नियम

दफा ७९ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई० के अनुसार गवर्नमेंट की आज्ञा लेने के पश्चात्
सन् १९११ ई० के जनरल सिविल रूलस (General Civil Rules) में निम्नलिखित संशोधित किये गये हैं।

सेक्टर २६ में दिये हुए नियमों के स्थान पर निम्नलिखित नियम समझना चाहिये

१. इन नियमों को आगरा प्रान्तिक दिवालिया नियम (The Agra Provincial Insolvency Rules) कहा जावेगा। काम नं० १३८ से लेकर १५२ तकका प्रयोग समयावृत्त परिवर्तन के साथ इन मामलों के लिये किया जावेगा जिनमें कि उनका अलङ्घन अलङ्घ्य सम्भव होवे।

२. दिवालिये की हर एक दरखास्त (Petition) उम रजिस्ट्रार में चढ़ाई जावेगी जो दिवालिये या काम करेगे वाली अदालत दिवालिये की दरखास्तों के लिये रखेगी और उनमें तर्तीबी संख्या (Serial Number) दी जावेगी तथा उसके बाद की सब कार्यवाहियों में जो इसी मामले के लिये की जावेगी वही नम्बर डाला जावेगा।

३. दिवालिये के सम्बन्धी सब कार्यवाहियों का सुभाषना उन समयों पर तथा उन नियमों के अनुसार किया जा सकता है जिनके अनुसार कि अदालत की दूसरी सिमिकों का हो सकता है यह सुभाषना रिसीवर, कर्जदार, व वह कर्जदार जो अपने कर्जों को साबित कर चुका हो या उनके वकीली नुमायन्दे (Legal representative) कर सकते हैं।

नोटिस

४. जब किसी नोटिस या किसी दूसरे मामले का इस एक्ट के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता बतलाया गया हो या इस एक्ट के अनुसार बनाये हुए नियमों के आधार पर किसी स्थानिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होना वाली तारीख व गजट का हवाला दिया हुआ होगा मिलिट में शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्टरजक्ट ऑर्डर (Order Sheet) में भी कर दिया जावेगा।

५. दफा १९ (२) के अनुसार निदेशन के सुनने की तारीख नियत किये जाने वाले हुक्म का नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त उन दूसरे समाचार पत्र व पत्रा में भी प्रकाशित किया जावेगा जिनमें अदालत आज्ञा देवे। नोटिस की एक एक नकल सब कर्जदारों के पास राजशुी खतके द्वारा उस पत्रसे पहुँचाई जावेगी जो दरखास्त (Petition) में दिया हुआ हो। वही तरीका उन नोटिसों के लिये उपयोग में लाया जावेगा जो दफा ३ - (१) के अनुसार सरकारी या स्क्रीम पर विचार करने के सम्बन्ध में दिये जावेगे।

६. दफा ३० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म प्रान्तिक सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त जैसा कि एक्ट में बतलाया गया है उन दूसरे स्थानिक अखबार या अखबारों में प्रकाशित किया जावेगा जमा कि अदालत उचित समझे। यदि कर्जदार सरकारी मुलाजिम होवे तो हुक्म की एक नकल

उस आफिसके सचिव बड़े हाकिम (Head of the office) के पास भेजी जावेगी जहा कि वह काम करता हो। यह तरीका उन नोटिसों व हुजूमोंके सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा जो दफा ३७ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुजूमकी मसूचीके सम्बन्धमें दिये जावें।

७ दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदालत द्वारा जारी किये जावेंगे उनकी तामील कर्जदारों पर या उनके वकीलों पर की जावेगी या वह बजरिये रजिस्ट्री खतके भेजे जावेंगे।

८ दफा ६४ के अनुसार रिसीवर अन्तिम हिस्सा रमदी (Final Dividend) बाटनेसे पहिले जो नोटिस उन कर्जदारोंके नाम जारी होगा जिनका कर्जदार होना घोषित किया जा चुका है परन्तु जिनके कर्ज साबित नहीं किये गये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा दायवानेसे भेजे जावेंगे।

९ बहालकी दरदवास्त (Application for Discharge) सुननेकी तारीखके नोटिस जो दफा ४१ (१) के अनुसार दिये जावेंगे प्रान्तिक सरकारी गजटके अतिरिक्त उन समाचार पत्रोंमें प्रकाशित किये जावेंगे जिनके लिये आज आशा देवे और उनकी नकलें सब कर्जदारोंके पास रजिस्ट्री कार्रके जरिये भेजी जावेगी चाहे उन्होंने अपना कर्ज साबित किया हो या न साबित किया हो।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें डाकखानेकी रसीद दाखिलकी जावे तथा अदालतके किसी अफसर या अफिसल रिसीवरका सर्टीफिकेट या किसी अन्य रिसीवरका हलफनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो यह इस बातकी काफी गवाहदत मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पहले भेजे गये हैं उसको ठीक तौरसे भेजे गये हैं।

११. प्रकाशनके निर्धारित नियमोंके अतिरिक्त अदालतकी आज्ञानुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जा सकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें चिरकरा देनेसे अथवा जिस गांवमें दिवालिया रहता हो वहा मुनादी करा देनेसे।

रिसीवर

१२. रिसीवरकी नियुक्तिका हुजूम लिखकर अदालतके इन्स्पेक्टरोंसे दिया जावेगा। इस हुजूमके नकलकी तामील अदालतकी मोहर होकर कर्जदार पर की जावेगी तथा वह नकल जितुन किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जावेगी।

१३. (५) अदालतकी चाहिये कि वह रिसीवरका भ्रमफल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकडाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे कि एक भाग महफूज कर्जदारों (Secured Creditor) को जमानत (Security) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया वसूल किया गया हो उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस इकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जिसे कि वह हिस्सा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे।

(६) जब कि रिसीवर महफूज कर्जदारोंकी जमानत (Security) का रुपया वसूल करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा उससे होने वाले कर्जदारोंके लाभको देते हुए और अधिक भ्रमफल (Remuneration) दिला सकती है।

१३. रिसीवर रोकड़ घड़ी या अन्य हिमायकी कितने तथा कागजात रखेगा जिससे जायदाद सम्बन्धी उसके प्रत्येक एक शीक जांच हो और वह हिसाब किताब उन समयों पर तथा उस प्रकार दायित्व करेगा जिसे प्रकार कि अदालत हुकम देवे । उन हिमायकी जांच वह लोग करेंगे जिनके लिये अदालत हुकम देवे । हिमायकी जांच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगा तथा वह खर्च दिवालयिकी जायदादमें दिलाया जावेगा ।

१५. अधिकतर रिसीवर वह सब रुपये जो वह वसूल कर सरकारी खजानेमें जमा करेगा या जहाँ किसी खास राजहमे रुपये किसी बैंकमें जमा किया जावे जिसके लिये कि अदालतने स्वीकृत देदी हो जो बोधी हुई रकम (Fixed Deposit) में जिस पर कि ब्याज आता हो जमा किया गया हो तो ब्याज को रुपये दिवालयिकी जायदादमें जमा किया जावेगा ।

१६. रिसीवर उन सब मामलोंके जायदग्यका हिसाब जिनमें कि वह रिसीवर नियुक्त किया गया हो हर तिमाहीके तिमाही अदालतमें दाखिल करेगा और यह हिसाब तिमाही समाप्त होनेके बाद वाले महीनेकी १० तारीखसे पहिलेही दाखिल कर दिया जावेगा ।

१७. जबकि रिसीवरके हाथमें दिवालयिकी जायदाद का कोई रुपया न होवे और वह किसी कर्जवाह से रुपयेकी मदद लेव तो उसको बोलिये कि यह रुपये दिवालयिकी जायदादके हिसाबमें दिखलावे ।

१८. वह कर्जवाह जो अपना कर्ज माहित कर चुका है अदालतमें हम बातकी दुरव्वास्त दे सकता है कि उसको रिसीवरके कुछ हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालयिकी जायदादसे होवे और जो कि रोकड़ पहिले उस वन तक दिखलाया गया हो । यह नकल उसको वह खर्च अर्दी करने पर दी जावेगी जो अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंको प्राप्त करनेके लिये बतलाये गये हैं पेसी नकलों के लिये किसी कोर्ट फीसके अदा करनकी आवश्यकता नहीं है ।

१९. यदि किसी मामलेमें कर्जवाहोंके मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता होवे और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तरफ़ीया या तय किये जानेकी स्कैम (Scheme) रफ़ा ३८ के अनुसार चाहता हो तो रिसीवर कमसे कम १४ दिन पहिले नोटिस कर्जदार व सब कर्जवाहोंको मीटिंगके समय व स्थानके लिये देगा ऐसे नोटिस रजिस्ट्री प्लत द्वारा भेजे जावेंगे ।

कर्जोंका साधित किया जाना

२०. कर्जवाहोंका सुवृत अयोगिडक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म नं० १३३ के अनुसार समयानुसूत परिवर्तनके साथ दिया जायकता है । इसी फार्म नं० १३३ इसी दार्इकोर्टका ।

२१. यदि किसी मामलेमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरो या दूसरे काम करने वालोंकी उगरत (Wages) के बहुतसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुवृत या वन सब कर्जवाहोंकी तरफसे किता एक ब्याक्ति का सुवृत पर्याप्त समझा जावेगा इस प्रकार का सुवृत अयोगिडक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म नं० १३३ के अनुसार होना चाहिये ।

यदि कर्जदार कोई फर्म होवे तो उसका तरफ़ी

२२. यदि किसी सूचना (Notice) देलान (Declaration) दस्तवेस्त (Petition) या किसी दूसरी दस्तवेजके तम्बूक (Attestation) की आवश्यकता हो तब उस पर किसी कर्जवाहों या कर्जदारों

के फर्मके दस्ताखत फर्मके नामसे किये जायें तो जो हिस्सेदार फर्मकी ओरसे दस्ताखत करे उसको अपने मालिकाना दस्ताखत करना पड़ेगा जैसे कि "प्राउन एन्ड कम्पनी वरियर जेम्सग्रिन" एक शरीकदार फर्म भेंट कर।

२३. यदि किसी सूचना (Notice) या दारखास्तकी तामील जर्ती तौरसे होना आवश्यक हो और उसकी तामील अदालतकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) के बन्दर् फर्मके खास रोजगारकी जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्म का प्रबन्ध करने वाले या देख रेख करने वाले ब्यक्ति पर की गई हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी तामील बाकायदा फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है।

२४. पिछली दफामें बतलाया हुआ नियम जहाँ तक मुमकिन होगा वुम मामलोंमें भी लागू होगा जब कि कोई ब्यक्ति अपने नामके बजाय किसी दूसरे नामसे अदालतकी अधिकार सीमामें कारांवार करता हो।

२५. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालकी दरखास्त देवे तो उस दरखास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होंगे और यदि उस दरखास्त पर फर्मकी ओरसे किसी एक शरीकदारने दस्ताखत किये हों तो वम दरखास्तके साथ उस शरीकदारको एक हलफनामा भी इस बातका छगाना पड़ेगा कि फर्मके सब शरीकदारोंकी राय वम दरखास्तकी देनेके लिये है।

२६. यदि किसी कर्जदारने दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे तो यह समझा जावेगा कि फर्मके वह सब शरीकदार जो हुक्म दिये जाते हैं शरीकदार थे दिवालिया करार दे दिये गये हैं।

२७. साझे मामलोंमें कर्जदार साझे मामलोंके सम्बन्धकी सूची (Schedule) पेश करेंगे तथा हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामलोंकी सूची भी पेश करेगा।

२८. संयुक्त कर्जवाह तथा कर्जवाहोंके अलहदा अलहदा समूह अलग तस्फीया या तय होने की स्कीमकी स्वीकार कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन होगा संयुक्त कर्जवाहों द्वारा स्वीकृत हुआ प्रस्ताव ही निर्धारित रूपसे संजूर किया जावेगा बिना इस बातका स्थाक किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जवाह या कर्जवाहोंने उस तस्फीया या स्कीम (Scheme) को स्वीकार नहीं किया है।

२९. यदि तस्फीया या स्कीमका प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो और वम फर्मके शरीकदारोंने अलहदा अलहदा तौरसे भी किया हो तो संयुक्त कर्जवाहोंके लिये किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा और उन पर उनके वोट लिये जावेंगे वम समय अलहदा कर्जवाहोंके समूहोंका अलहदा ध्यात नहीं दिया जावेगा और जो प्रस्ताव कर्जवाहोंके किसी खास समूहके लिये किया गया हो उस पर वह समूह अलहदासे विचार करेगा व वोट देगा कुल कर्जवाहोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होगा। यह प्रस्ताव भिन्न भिन्न रूपसे तथा भिन्न भिन्न रादादके लिये किये जासकते हैं। जब कि तस्फीया या स्कीम स्वीकार कर ली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म वमी इद तक मंसूख होगा जहाँ तक कि उसका उस जायदादसे सम्बन्ध है जिसके कर्जवाहोंने तस्फीया या स्कीमको मान लिया है।

३०. यदि किसी बराकती फर्मके दो या दो से अधिक मेसजान कोई जुदागाना फर्म बलाते हों तो उस जुदागाना फर्मके कर्जवाहान एक जुदागाना कर्जवाहोंका समूह समझे जावेंगे और वह वमी प्रकार समझे जावेंगे जैसे कि किसी शरीकदारके अलहदामें कर्जवाहान होवे यदि ऐसे जुदागाना फर्मके लट्टने (Assets)

से कोई फ़ाजिल रकम बचे तो वह उस फ़र्मके शरीकदारोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे उनके हिस्सेके अनुसार उनकी श्लहदाकी जायदादमें खे बाँट जावगी।

दरखास्तें व नोटिस

३१ (ए) यदि इन नियमोंमें कोई बात अथ प्रक्रासे न चललाई गई हो अथवा अदालत किसी खास मामलेमें कोई अन्य हुकम न देवे तो अदालतमें दी जाने वाली वह सब दरखास्तें लिख कर दी जावंगी तथा उनकी ताईदमें मायल का हलफनामा भी दाखिल होगा जो कि रिसीवर द्वारा या किसी कज़ेवाइ द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जावे जो कज़ेदारके लहजेमें अपने को हुकद्वारा बतलाया हो या रिसीवरके किसी काम की शिकायत करे और जो खास कर इन नियमोंकी बिल अवहेलना किये हुए दफा ४, ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५ के अनुसार हुकम दिये जानेके लिये दी गई हो।

(बी) जिस हुकम या दादरसीके लिये दरखास्त दी जावे उसका उल्लेख पूर्ण रूपसे हर दरखास्त में किया जावेगा उनमें इस पुकटकी दफाओंकी जिनके अनुसार दरखास्त दी गई हो तथा उन वक्ताओं का जिनके कारण वह हुकम या दादरसी खासे जाता हो तथा अन्य किसी पुकटकी दफाओं का भी जिनके आधार पर दरखास्त दी गई हो उल्लेख किया जावेगा।

(सी) इस प्रकारकी हर एक दरखास्तमें यह भी लिखलाया जावेगा कि भाया सायल दरखास्त की ताईदमें गवाहान लख किया जाहवा है या नहीं और उसमें ~~यदि मौजूद हो~~ ~~दस्तावेजों~~ भी लिख दगा जिनके कि वह आधार मानना हो।

(डी) यदि रिसीवरके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकारकी दरखास्त देवे तो उस दरखास्त की नकल तथा उसकी ताईदमें दिये हुए हलफनामकी नकलकी तामील रिसीवर पर की जावगी और उन दस्तावेजोंकी नकल भी जिनका जिक्र ऊपर की (सी) क़ागमें किया गया है उसको दी जावेगी परन्तु यदि दस्तावेज बहुत सी हों अथवा बहुत बड़ी हों तो अथवा उनकी नकल अगवनेके नोटिस द्वारा रिसीवरको उनके बारेमें बतला दिया जावेगा और रिसीवरको दरखास्त सुन जानेस पहिले पूरे सत्त दिन का मौज़ा असल दस्तावेजोंका मुनायमा करनेके लिये दिया जावेगा।

(ई) यदि ऐसी दरखास्त रिसीवर द्वारा दी जावे तो उसकी ताईदमें जो हलफनामा लगाया जावेगा उसमें कज़ेदारके इस बयानका हवाला होगा जो या सा मिथिलमें दामिल होवे या रिसीवरके कज़ेमें होवे तथा जिसके आधार पर रिसीवरने दरखास्त दी हो।

(एफ) दरखास्तके हर एक फ़रीककी अधिकार होगा कि वह असल दस्तावेजका मुनायमा कर सके जो कि या तो दाखिलकी गई हो या दरखास्तकी ताईदमें दिये हुए हलफनामामें जिसका उल्लेख होव या जिसकी प्रकृष्टका हवाला हलफनामामें दिया गया हो।

(जी) उपदफा (ए) में बतलाई हुई ~~एक~~ ~~दरखास्त~~ व हलफनामके नकलकी तामील रिसीवर पर की जावेगी चाहे रिसीवरके विरुद्ध कोई हुकम या दादरसी चाही गई हो या न चाही गई हो।

दिवालियेकी ग़ैरमनक़ूला जायदादका बेचा जाना

३२ यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं इस पुकटकी दफा ५८ के अनुसार दिवालियेकी ग़ैरमनक़ूला जायदादको बेचे तो उस जायदादके लिये दस्तावेज बयानामा ख़रीदार अपने खर्चमें

‘या’ कायदा और अदालत हाकिमक दस्तखत उस पर हाने यदि रजिस्टा कर नेमें कोई खर्च पड़या तो
 18 भी खरादार बरदास्त कराया ।

१३ दिव्या रसीद का हप्पा (Dividend) वगैरह (Creditor) क प्रार्थना करने पर तथा
 इसकी निम्न तरी पर डाक जमिये भेजा जा सकता है ।

सरसरी की कार्रवाई

१४ यदि दफा ७४ क अनुसार किसी जायदाद का इन्तजाम सरसरी तौरसे किये जानेका हुक्म
 19 होय तो अदालतक खास हुक्मों का ध्यान रखते हुए इस एक्ट के नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारम
 धन पित हा जावेग ।

- (1) किसी कार्रवाई का प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या प्रत्येक किसी समाचार पत्रमें महीनिका मासिका ।
- (2) दरवास्त (Petition) पर तथा बाहरी खर्च कार्रवारोंमें सरसरी का मामला (Summary Case) लिख दिया जावेग ।
- (3) कौन बाहरी का दरवास्त (Petition) क सुन जानेकी सूचना (Notice) अर्गण्डिस (Appendix) के काम नं० १५१ के अनुसार दी जावेगी ।

19 ~~यदि कार्रवाई का पटाल उसके मामलोंके सम्बन्धम लगी परन्तु यह कर्तव्यों की मीटिंग~~
~~(Meeting) करने के लिये समीचीन नहीं है आ कार्रवाईमें रुक होगा कि इसकी सुझाईकी~~
~~जबे उम्मा यह कर्तव्य निरह कर सके ।~~

(४) अधिकतर रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत द्वारा
 अनुसार कार्रवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालिघा के कार्रवाईमें खर्चा कम हो जावे ।

खर्च

१५ उन खर्च कार्रवाइयों का खर्च जो दिवालिघा के लिये जायके हुक्म तथा जिसमें दिवालिघा
 20 कार्रवाई जाय का हुक्म और शामिल है कार्रवाई करने वाला व्यक्ति हर रकम परन्तु नव दिवालिघा द्वारा
 दिय जाना बाका (Adjunction) हुक्म हा जाय तो दरवास्ता वेच वाल कर्तव्यक का खर्च खर्च
 दिवालिघा की जायदादसे दितव्यता जावेगा ।

१६ यदि तस्वीफ या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जाय तो तस्वीफ या स्कीमकी
 दरवास्तक लिये तथा इसके सम्बन्धम किय हुए कर्तव्यक खर्चका जामदास्त नहीं दिवाया जावेगा ।

१७ यदि कर्तव्यक खर्च दरवास्त दोर पर यह दिवालिघा काल दिया गया हो और अदालत
 21 विचार्य हो प्राय कि वह प्रान्तिक सरकारी गजटमें उपबन्धित जाये का खर्च तथा एक्ट की दफा १० में बतलाय
 हुए नोटिस का खर्च बदास्त भर्वा कर सकता है तो अदालत इस बात का हुक्म दे सकती है कि उसका खर्च
 दिवालिघा की जायदादकी वीमत्तम अदा किया जाये । यदि दिवालिघा पास कोई जायदाद न होय अथवा उसक
 मिलाकी कीमत न काफी होय तो उसका खर्च या न बसूक दिया जा सके वाला मालिकम गण कर दिया जावेगा ।

फार्म नं० ६

रिसीवरकी नियुक्ति का हुक्म

दफा ५६ क्रानून दिवालिया सन १९२० ई०

य अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०

य मुकद्दमा दिवाकिया

न० सन् १९ ई०

धुंकि (नाम दिवालिया) अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार द दिया गया है और अदालतको यह अचित्त प्रतीत होता है कि दिवंगतये मजकूरकी लायदादके लिय रिसीवर नियुक्त किया जावे अतः यह हुक्म दिया जाता है कि रिसीवरके सिद्ध वसूलीक हुक्म दिया जावे और दिवालिये मजकूरके विरुद्ध रिसीवरको हुक्म दिया जाता है और (या आफिशल रिसीवर) दिवालिये मजकूरकी लायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुक्म दिया जाता है (यदि आफिशल रिसीवर नियुक्त न किया गया हो) कि रिसीवर मजकूर तरकी अमानत दायिल करे और उसका अमफल (Remuneration) हिलाबसे हासल ।

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज.

फार्म नं० ७

पार्जोंका सुदूत (Proof of Debts)

आम तरीका (दफा ४९ क्रानून दिवालिया)

उनवान (Title)

य अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०

हरकबास्त दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायल

मानला नम्बरी

(यहाँ पर नोटिसका नम्बर डोना पादिये) सन् १९ ई० में

(नाम व पता) हलफसे कहता हूँ (या ईमानदारी व दिलसे बयान करता हूँ)

कि (नाम व पता कर्जदार) तारीख सन् १९ ई० को मेरा

(लादाद) रुपयेका कर्जदार या व अब भी है जिसकी तकसील इसके साथ दाखिल किये जाने वाले हिसाबमें दिखलाई गई है इस रुपयेका कोई हिस्सा मुझ या मेरी ओरसे किसी आदमीको वसूल नहीं हुआ और न उसको कोई जमानत दी हुई है सिवाय नीचे दिये हुए रुपयेके

घोटेकिये जो लादाद रुपये मानी गई हो } हलफ जहा की गई हो { हलफ लेने वालेके दस्तखत
 गज या आफिशल रिसीवर } आज तारीख { कमिशनर
 जिसके सामने हलफ की गई हो }

फार्म नं० ८

मजदूरके कर्जोंका सुवृत्त (Proof of Debts of Workman)

उनधान (Title)

अभिलेखित साक्ष्य डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि० - - - - -

दस्तावेज दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

----- सायल

मैं (नाम व पता हलफनामा दाखिल करने वालेका) हलफसे कहता हूँ
(या ईमानदारी व दिलसे ऐलान करता हूँ) कि मैं तारीख
सन् १९ ई० को केहरिस्तमें दिये हुए लोगोंका उनके सामने दिखाये हुए दफ्तोंके लिये कर्जदार था व अब भी
हूँ और यह कर्जा उन लोगोंकी मजदूरीके बारेमें है जो उन्होंने किसीबरी नियुक्तिसे पहिले केहरिस्तमें दिखलाये
हुए समय तक हमारे पासकी थी। यह कर्जे या इन कर्जोंका कोई भाग अब तक नहीं चुकाया गया है और न उसके
लिये कोई जमानत दी हुई है।

बोटके लिये जो तादाद रुपया मानी गई हो } वह अगर जहा हलफनामा किया गया हो { हलफ लेने वालेके
जज या आफिशल किसीदर { शरीख हलफ लेनेकी दस्तावेज
जिसके सामन हलफ ली गई हो { कमिश्नर

फार्म नं० ६

तस्फीया या तय होनेकी स्कीमका नोटिस जो कर्जस्वाहोंको दिया जाना चाहिये

दफ्ता ३८ (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अभिलेखित साक्ष्य डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि० - - - - -

दस्तावेज दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

----- सायल

हमको इतना ही ज्ञाती है कि अदालत हाजाने कर्जदारके तस्फीयेकी दरखास्त पर विचार करनेके लिये
सारांश सन् १९ ई० नियतकी है। वह कर्जदार जिसका कर्जा एक तारीख तक या उससे पहिले
साधित नहीं हो जायेगा इस तस्फीये पर बोट देनेका अधिकारी नहीं होगा यदि तुम उस तारीख पर हाजिर होना
चाहो तो स्वयं या किसी बकीलके जरिये मय सुन्नेके हाजिर हो सकते हो।

द० जज

फार्म नं० १०

कर्ज़व्याहोंकी फेहरिस्त जो तत्कीया या रसीम पर विचार करने समय बनाई जावे

दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

मअदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज सहादुर जि०

बसुकरहमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

संदिग्ध तारीख

सन १९

ई० को

(जगहका नाम)

में की गई

नम्बर	उन सब कर्ज़व्याहोंक नाम जिनके कर्ज़ साबित हो चुके हैं	इसमें उन कर्ज़व्याहोंकी दिवखाना चाहिये जिनोंने वोट दिये हैं और यह भी दिखलाना चाहिये कि स्वयं वोट दिये हैं या बरालके जरिये	रहनेकी तादाद	वह तादाद जिनका सुधून माना गया है

बहुमतके लिये होने वाली संख्या

चाही हुई कीमत

रखे

फार्म नं० ११

अन्तिम हिस्सा रसदी यांजनेसे पहिले कर्ज़व्याहोंको दिया जाने वाला नोटि

दफा ६४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

मअदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज

बसुकरहमा दिवालिया नं०

सन १९

ई०

.....सायक

तुमको इतला दी जाती है कि उक्त मामलेमें अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जान्के लिये तारीख सन १९ ई० नियतकी गई है और यदि तुम उस तारीख पर या उससे पहिले अदालतमें अपना कर्ज़ साबित न कर दोगे या मोहरत दी जाने पर मोहरत वाली तारीख तक न साबित कर दोगे तो तुम्हारा कर्ज़ निकाल दिया जावेगा और उसका बिला स्थाल किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा ।

तारीख

सन १९ ई०

द० रिडीबर

फार्म नं० १२

दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंस्खीका हुक्म
दफा ३७ प्रान्तिक क़ानून दिवालिखा १९२० ई०

..... (नाम व पता दरखास्त देने वालेका) की दरखास्त पर तथा
उसे सुनने व पढ़नेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि (दिवालियेका नाम) के
विश्व दिवालिखा करार दिये जानेका हुक्म जो तारीख सन् १९ ई० को दिया गया था
मंस्ख किया जाने तथा वह मंस्ख किया जाता है ।
तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १३

बहाल होनेकी दरखास्तका नोटिस जो क़र्जद्वारोंको दिया जाना चाहिये
दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिखा १९२० ई०

उनवान (Title)

मुमको इत्तला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए दिवालियाने बहाल होनेकी दरखास्त इस अदालतमें दी है
और अदालतने इसके सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई० नियतकी है ।
तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १५

सरसरीकी कारवाई (Summary Administration) दफा ७४

उनवान (Title)

मुमको इत्तला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए कर्जदारने ता० सन् १९ ई० को
एक दरखास्त दिवालिखा करार दिये जानेके लिये इस अदालतमें दी है और ता० सन् १९ ई०
को अदालतने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि उक्त कर्जदारकी जायदाद ५०० रुपयेसे अधिक कीमतकी
नहीं है और इसी कारण उसकी जायदादका प्रबन्ध सरसरी तौरसे किया जाना भिश्चित किया है इस अदालतने
तारीख सन् १९ ई० फिर उस दरखास्तको सुननेके लिये नियतकी है और उसी
तारीख पर कर्जदारके भी बयान होंगे ।

मुमको इस बातकी भी इत्तला दी जाती है कि मुमकिन है अदालत इसी तारीख पर उस कर्जदारकी
दिवालिखा करार द देने व उसका लहजा बाट देये । मुम यदि चाहो तो उस तारीख पर हजर होकर गवाहदत दे
सकते हो यदि मुम कोई कर्ज साबित किया चाहो तो उस तारीख पर या उसके पहिले साबित कर सकते हो ।

इस अदालतकी मोहर व मेरे दस्तखतमे आज

तारीख सन् १९ ई० को जारी किया गया द० जज

प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई० (The Provincial Insolvency Act) के अनुसार जिन वस्तुओं का दिया जाना बतलाया गया है उनमेंसे कुछ नमून नीचे दिये जाते हैं ता कि समयाचित परिवर्तन के साथ प्रयोग किये जा सकें हैं । एक्ट के नियमों का ध्यान रखते हुए दखलाते इन नमूनों के अनुसार विशेष बातों का उल्लेख करते हुए दी जाना चाहिये:—

(नमूनेका फार्म) नं० १

कर्जदार का पिटीशन अर्थात् कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दखलास्त

वफा १० (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया एक्ट ५ सन् १९२० ई०

बध्नायत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बदायुन जिले.....

मुकदमा दिवालिया सन् १९ ई०

दखलास्त वफा १० (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

(नाम) वरद साकिन सायल

सायल निम्नलिखित मार्गना करता है —

१. यह कि म्याबल अधिकतर (निवास स्थान का नाम) का रहने वाला है और अब तक (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता रहा है और यह स्थान इस अदालतकी अधिकार सीमामें स्थित है ।

२. यह कि सायल को अपने व्यापारमें बड़ी हानि उठानी पड़ी है क्योंकि (यह पता हानि होनेके कारणों का बखलेल दिया जाना चाहिये) व ते वज यह है और इसी कारण सायल पर बहुत सा कर्ज लद गया है ।

३. यह कि सायलको एक व्यापारसे अब कोई लाभ नहीं है और सायलके पास कोई दूसरा लाभका शस्ता भी निशाय (यदि कोई आमदनी का जरिया हो तो उसका बखलेल किया जाया चाहिये) नहीं है और इसी कारण सायल अपना कर्ज चुकानेमें असमर्थ है ।

४. यह कि सामल पर जो इस बात कर्ज हैं वह सब मिलकर इनपेके हैं (यह कर्ज पांच सौ रुपयेसे अधिकके होना चाहिये कमके नहीं) या

सायल किसी इजराय मन्त्री सन् १९ ई० अदालत मुसिक या (अथ अदालत) सादर

मुकदमा (नाम डिस्ट्रिक्टर) को खिलाफ मुस सायलके है इसके

अनुसार दिलास्त या जेलमें हैं या

सायलकी जायदाद मुकदमा इजराय मन्त्री सन् १९ ई० (मुकदमें व अदालत का नाम व पता दिया जाना चाहिये) के अनुसार कुं किया जायका हुकम हुआ है और यह हुकम अब भी जायदाद सायलके खिलाफ जारी है ।

५. यह कि सायलके कर्जों का ब्योरा इस पिटीशनके साथ दायिलकी जाने वाली सूची ए में दिया हुआ है और उस सूचीमें सब कर्जोंवालों का नाम व पता जहाँ तक सायलको मालूम है व जहाँ तक सायल उनका पता लगा सका है दे दिया गया है ।

६. यह कि सायलकी जायदाद व रुइनेकी तादाद व उसका ब्योरा सूची (बी) में दिया गया है और उस सूचीमें जायदादकी कीमत व उन स्थानों का भी उल्लेख कर दिया गया है जहां पर वह जायदाद स्थित है।

७. यह कि सायल अपनी सब जायदाद अदालतकी सुपुर्दगामी देनेके लिये प्रस्तुत है (सिवाय उन चीजोंके जो जायदाद दीवानी या अन्य प्रचालित कानूनके अनुसार कुछ व नौकाम नहीं की जा सकती है परन्तु उनमें हिसाबकी किताबोंको नहीं समझना चाहिये।

८. यहकि सायलने इससे पहिले कोई दरखास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये नहीं दी है या उसके विरुद्ध कोई दरखास्त दिवालिया करार दिये जानक लिये नहीं दी गई है।

अथवा

सायलने एक दरखास्त (अदालत का नाम व पता) में दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी या उसके विरुद्ध दरखास्त दी गई थी और वनके अनुसार सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और तारीख सन् १९ ई० को सायल बहाल हो चुका है या दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया गया था (यहाँ पर अपनी कारवाही दिवालिया की तफसील तथा मसूखी आदिके कारण सब दिखल दिये जाना चाहिये)

अतः कारणोंस सायल सबिनस्य प्रार्थना करता है कि सायल दिवालियर करार दे दिया जाये या अदालत इस सम्बन्धमें कोई दूसरी उचित आज्ञा देनेकी कृपा करे और सायल सदैव इसके लिये कृतज्ञ होगा।

नाम हस्ताक्षर सायल " " " "

मैं (नाम व पता) तस्दीक करता हू कि समझून दफा १ में तक सब मेरे इल्ममें सही है और समझून दफा का सही होना उम इत्तला पर मन्गी (निर्भर) है जो मुझे मिली है।

तारीख व जगह का नाम नहीं पर तस्दीक इशारतकी गई हो

हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नम्बर २

कर्मचारी का पिटीशन अथवा कर्मचारी द्वारा कर्मक्षरके विरुद्ध दी जाने वाली दिवालियकी दरखास्त

दफा १ (१) व १३ (२) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया

सन् १९ ई०

(नाम व पता)

साकिन

..... = सायल

अतः सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि सायल अधिकतर (स्थान का नाम व पता) का रहने वाला है या (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता है अथवा लाभके लिये काम करता है।

२. यह कि सायल का व्यापारिक सम्बन्ध (दिवालिया करार दिये जाने वाले व्यक्ति का नाम व पता) से इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर था या (जम कर्जदार का नाम व पता) जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर रहता करता व्यापार करता है सायलमे सौदा लिया करता था (अथवा अपने सायलमे कर्ज लिया है)

३. यह कि घसिलखिल व्यवहार सायलको उक्त (कर्जदार) से (तादाद) रखा होता है जिते कि उसने जब तक अदा नहीं किया है ।

४. यह कि उक्त कर्जदारने कर्जन्वाहका कर्जों मारनेकी इच्छामे अपना हगोकार बंद कर दिया है या तारीख सन् १९ ई० से अपनी दुकान बंद कर दी है और जम वन्दे कराकर छिपा हुआ है जिसमे कि कोई कर्जन्वाहान उससे पत्र व्यवहार नहीं कर सके या उसने आजकी तारीखसे तीन माहके अन्दर अपनी जायदादको बदनीयतीमे कर्जन्वाहानका कर्ज मारनेकी मन्नामे अकाहिदा कर दिया है (अथवा दफा ९ में बतलाई हुई किमी बातका प्यो पार दिखलाना चाहिये जिससे कि कर्जदार का दिवालिये का काम साबित हो सके ।

छिद्दाना दूरवास्त हाजा गुश्रान कर उम्मेदवार हूं कि (१) उक्त कर्जदार दिवालिया करार दिया जाये,

(२) उक्त कर्जदारकी जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये दूरवासी रीसीवर नियुक्त किया जाये ।

(३) उक्त कर्जदारसे उसको सब ठिसाबकी किताबें वापिस करवाई जायें व उससे सब कर्जोंकी तहसील गौरा दाखिल कराई जाये ।

इबारत तर्दीक मय सारीख व जगह तर्दीकके की जाना चाहिये ।

तारीख सन् १९ ई० दस्तखत

नोटः—कर्मचारी ताथद ५०० से अधिक होना चाहिये । दूरवास्त कई कर्जन्वाह साथमें होकर भी दे सन्थे हैं ।

(नमूने का फार्म) फार्म नं० ३

दूरवास्त वास्ते वापिस लेने मुकद्दमा (दफा १४)

दूरवास्त हरत्र दफा १४ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर गि० -

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

अन सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुस सायलने इस अदालतमें तारीख सन् १९ ई० को एक दूरवास्त दिवालिया करार दिये जाने के लिये दी थी । कर्जन्वाहान के नाम नोटिस जारी किये आचुके हैं और दूरवास्त अभी जे तजवीज है (या उसके सुने जाने के लिये ता० सन् नियत की गई है)

२. यह कि वन दूरवास्त को देने के बाद मुस सायलको (नाम व रिकना) से वसीयतन (या अन्य किमी कारण जिसका तबखल बहा किया जाना चाहिये) पथोस्त घन प्राप्त होने की सम्भावना है जिसमे कि सब

इस्ताज़र

(नमूने का फार्म) नं० ५

दरखास्त हस्त दफा २१ प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

च अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

..... सायल

म (नाम) कर्जवाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ कर्जवाहने एक दरखास्त लिखा (नाम व पता कर्जदार)

के तारीख सन् १९ ई० को वास्ते दिवालिया करार दिये जानेके इस अदालतमें दी है ।

२. यह कि अदालतने उस दरखास्त को सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई०

नियतकी है और दरखास्तकी सूचना नियम पूर्वक कर्जदार मजकूरको मिल चुकी है ।

३. यह कि सूचना पानेके बाद जत कर्जदारने अपनी वर्षा खुशी जायदादको कर्जवाहानसे बचानेके लिये अपने रिस्तेदारोंके पास हटा दिया है और वह स्वयं भी इस अदालतकी अधिकार सीमाने बाहर जाने वाला है जिनकी सूचना मुझ कर्जवाहको बिद्वस्त सूत्रसे मिली है और मुझ कर्जवाहको विश्वास भी है कि वह सूचना सच है ।

४. यह कि उक्त कर्जदार का तारीख मुकररा पर हाजिर होना परम आवश्यक है इस कारण मुझ कर्जवाहकी प्रार्थना है कि वक्त कर्जदार वायण्टके जरिये गिरफ्तार किया जावे जिसमें कि वह नियत तारीख पर हाजिर किया जा सके अथवा उससे पचास अमानत उसकी हाजिरीके लिये ली जावे जिसमें कि वह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम तक अदालतमें शक्ति व आवश्यक अवसरों पर हाजिर हो सके आशा है कि वक्त प्रार्थना स्वीकारकी जावेगी जिसके लिये मैं कर्जवाह बड़ा कृतज्ञ होऊंगा

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:— यदि वक्त दरखास्तके लिये अदालतमें विज्ञापित दिखानेके लिये इलफनामकी आवश्यकता है तो वह भी दाखिल किया जाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० ६

कर्जदार के मुक्त किये जाने के लिये दरखास्त दफा २३

दरखास्त हस्त दफा २३ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

च अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकद्दमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

..... सायल

वक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि मुझ सायल ने माली इन्तज बहुत खराब होजाने के कारण इस अदालतमें दिवालिया करार दिये जाने के लिये दरखास्त देखली है और वह दरखास्त तारीख सन् १९ ई० को अदालत द्वारा लेली गई थी उस दरखास्त के सुन जान के लिये तारीख सन् १९ ई० नियत हुई है ।

२. यह कि मुझ सायल की वत दरखास्त ल लिये जानेके बाद (नाम डिब्रीदार) ने मुझ सायलको इजराय डिब्री न० इजलासी अपनी सादा रूपयेकी डिब्री गिरफ्तार कराया है मैंने डिब्रीदार मजकूरका नाम अपनी दाखिलकी हुई कर्जवाहानकी फहरिस्तमें दखल दिया है और वनमें उसका कर्ज भी सब दिखला दिया गया है अब मैं उस डिब्रीकी इकलतमें गिरफ्तार हूँ ।

३. यह कि वत डिब्रीदारने मुझ सायल पर नाजायज दबाव डालने व बेजा फायदा उठानेकी गरज मुझ सायलको गिरफ्तार कराया है जिसमें कि उसका कत बमुकामले और कर्जवाहानके वसूल हा सके डिब्रीदार मजकूरको मुझ सायलकी दरखास्त दिवालिय व माली हालत का पूरा इल्म है ।

४. यह कि अगर मैं सायल कौरम आजाद न कर दिया गया तो दरखास्त दिवालियकी पैरवी भली भाँति न हो सकेगी और मुझ सायल का लड़ना भी वसूल न हो सकेगा (मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदालत द्वारा नियत किये हुए रिसविरके सुपुर्दे कर दी है या सुपुर्दे करनेके लिय तैयार है) सायल यह भी चाहता है कि उसके सब कर्जवाहानको हिरसारमदी उसकी जायदादसे मिल सके इसलिये सायल का गिरफ्तारिस मुक्त किया जाना आवश्यक है ।

५. यह कि सायल अपनी दरखास्त दिवालियमें सब बातें दिखला चुका है कि अनायासी इसकी माली हालत गड़बड़ हो गई है व इस पर उसका कोई बस नहीं था ।

६. यह कि सायल अपने मुक्त किये जानेके लिये नियमानुसार अविल जमानत भी देनेके लिये तैयार है व कारणोंसे प्रार्थना है कि अदालत सायलका गिरफ्तारी या जेलमें मुक्त किय जानेकी आज्ञा प्रदान करे या अन्य कोई उचित आज्ञा देनेकी कृपा करे जिसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख

सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:— आवश्यकतानुसार इल्फनाया भी इस दरखास्तकी तर्जमें लगा देना चाहिये —

(नमूने का फार्म) न० ७

दफा ३१ के अनुसार प्रोटेक्शन ऑर्डर (Protection Order) की दरखास्त
दरखास्त हस्त दफा ३१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायल

वत सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ सायलने इस अदालतमें एक दरखास्त न० सन् १९ ई० दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी और अदालत द्वारा वत दरखास्तको सुनने व उस पर विचार करनेके बाद मुझ सायलको अपने हुक्मसे तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया है ।

२. यह कि मुझ सायलके एक कर्जवाहाने जिनका नाम दरखास्तके साथ दाखिलकी हुई फहरिस्त कर्जवाहानमें दिखला दिया गया है मुझ सायलके खिलाफ अपने कर्जके लिये अदालतसे

डिफेंस नं० सन् १९ ई० हासिल कर रखी है और अब वह उस डिफेंसकी इजरायमें मुस सायलको गिरफ्तार कराना चाहता है जिसके लिये उसने उक्त अदालतमें दरखास्त दे रखी है जो कि अभी जर तजवीज है ।

१ यह कि मैं सायल अपनी मजबूतकी वजहसे इस दिवालियेकी दशाको पहुंचा हूं और मुस सायल ने अब तक कोई भी उतमानी अपने कर्जम्बाहान का कर्ज भाने या किसीको बेना फायदा पहुंचानेके लिये नहीं की है । मुस सायलने अपनी सब जायदाद भा बहुम अदालत तिसीवरकी सुपुर्दामें दे दी है ।

२ यह कि ऊपर बतलाये हुए कारणसे मैं सायल किसी डिफेंसमें गिरफ्तार न किया जाना चाहिये और इसीलिये प्रार्थना करता हू कि दफा ३१ प्राप्तिक कानून दिवालियाके अनुसार इस अदालतसे एक हुक्म इस प्रकार का दे दिया जावे कि मैं अपने किसी कर्जकी डिफेंसमें गिरफ्तार न किया जाऊं या कोई अन्य उचित भला दी जावे जिसमें कि मुस सायलको बेना तिसीवर परधान न किया जा सके अथवा कमसे कम ऊपर बतलाई हुई डिफेंसकी इकलतमें गिरफ्तार किये जानेसे बचने का हुक्म दिया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोट :—आवश्यकानुसार समर्पित हुक्मनामी यी ऐसी दरखास्तके साथ दाखिल करना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० =

ज़मानतनामा

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि०***

मुकदमा दिवालिया नं०,

सन् १९

ई०

***** सायल

यूकि उक्त मुकदमेमें अदालतने कर्जदार (नाम व पता) से जिनके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त पर अदालत विचार कर रही है अन्तिम हुक्म होने तक उसकी हाजिराके बावजूद रुपयेकी जमानत तलबकी है इस लिये मैं अपनी इच्छासे उक्त कर्जदार के लिये जामिनदार होता हूं और इस बातके लिये जिम्मेदारी लेता हूं कि जब कर्जदार अदालतकी आज्ञानुसार जब अदालतमें आइगी उपस्थित होगा तथा अदालत जिन हुक्मोंको करनेके लिये उसे आज्ञा देगी इनको वह करेगा और यदि वह हाजिर न होवे या हुक्मकी पाबन्दी अन्तिम हुक्म होने तक न करे तो मैं रुपयेके लिये स्वयं व अपने वारिसान व क़यम मुकामानको जिम्मेदार करता हूं और अदालत मुझसे मेरे वारिसान या क़यममुकामानसे रुपये तक जिस तरह पर चाहे वसूल कर सकती है ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

गवाह (१)

गवाह (२)

(नमूने का फार्म) नं० ६

अर्जी मिनजामिब कर्जदार वावत दिलख जाने दर्जा हस्य दफा २६

दरखवास्त हस्य दफा २६ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

... .. सायल

उक्त कर्जदार निम्नालिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि (नाम व पता दरखास्त देने वाले कर्जदार का) ने एक दरखास्त खिलाफ मुस कर्जदारके इस अदालतमें वाचन दिवालिया करार दिये जानेके दो थी उसने उस दरखास्तमें अपनेको मुस सायल का एक कर्जदार अर्थात् किया था व बिलकुल गलत बयानीके साथ दरखास्तको दिया था जो कि बर्दाश्त अदालत तारीख सन् १९ ई० को खारिज कर दी गई है ।

२ यह कि दिवालियेकी उक्त दरखास्त बिलकुल कर्जों व मुस सायलको परेशान करने व सीडीन करनेकी गरजसे दी गई थी (या इस अवधिमें दी गई थी जिसमें मैं प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाका मेम्बर बन सकूँ)

इस लिये सायलकी प्रार्थना है कि मुस सायलको १०००) रुपया वाचत इन्हीं उक्त दरखास्त बुनिम्दा (कर्जदार) से दिलया जावे क्योंकि उनकी वजहसे मुस सायलको किराने खर्चा करना पडा है तथा एवामी व निम्नानी कुल्लाम उठाना पडा है या अदालत जो बुद्धिम मुतासिब समझे सादिर कर्माये सायल इसके लिये रका हुवा होगा ।

तारीख सन् १९ ई० हरशाहर

इसके साथमें एक हलफनामा भी तस्दीक होकर दाखिल किया जायकता है ।

(नमूने का फार्म) नं० १०

दरखवास्त वास्ते गिरफ्तार किये जाने दिवालियाके दफा ३२.

दरखवास्त हस्य दफा ३२ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

... .. सायल

... .. कर्जदार (या रिखार)

उक्त कर्जदार निम्न लिखित प्रार्थना करता है ।

१. यह कि उक्त मुकदमेमें..... कर्जदार तारीख सन् १९ ई० को पहिलम अदालत दिवालिया करार दे दिया गया है ।

१ यह कि उक्त दिवालियाको इस अदालतने यह हुक्म दिया था कि यह अपनी हिस्साका कितनोंको दाखिल करे ॥ अपनी सब सनकूला (Moveable) जायदादको कहरिस्त तैयार करके उसको रिमीनर (या किसी व्यक्ति के सुपुर्द करे ।

३ यह कि दिवालियाकी सनकूला जायदाद अधिकतर पैसी है औ बिना उसकी मददके पैसा नहीं जासकती है ।

४ यह कि दिवालिया इस अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर इस संशय यथायक भला गया है जिसमें कि उसको हिस्सावरी कितनों में दाखिल करना पड़े या अदालतके हुक्मकी तामील करनेसे बच जावे । इसके इस कामसे मुझ कर्जवाह तथा बाकी अन्य कर्तारवाहोंको नुकसान पहुँचता ।

इस लिये मुझ कर्जवाहकी मायना है कि दिवालिया मजदूर बजतिये शाण्ट गिरफ्तार करा लिया जावे जिसमें वह इस अदालतके सामने पैसा किया जायके या अदालत जो हुक्म मुनाविद समझे मादिर फर्माव ।

तारीखें सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:—उक्त दरखास्त रिमीनर या कोई भी कर्जवाह दे सकना है उक्त दरखालके साथ इरफनामा दाखिल । जाना भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं० ११

कर्ज साधित करनेकी दरखाम्त दफा ३३

अर्जी हस्त दफा ३३ कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् ११ ई०

.....सायल

मैं कर्ज कर्तारवाह

मैं (नाम व पता कर्जवाह) बहलक ध्यान करता हूँ कि (नाम कर्जदार) ने

मुझसे तारीख सन् १९ ई० को रुपया धनौर कर्ज लिया था वह रुपया अवतक अदा नहीं हुआ है दिवाय कर्ज का इस दरखाम्त के साथ दाखिल की जाने वाली कहरिस्त में दिखलया गया है यह कर्ज सब सचवा है बार इसमें मे एक पैसा भी मुझे या मेरे किसी आदमी को अदा नहीं किया गया है और । इस कर्ज की कोई खामत ही की गई है ।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

जिस अगद हलफ की गई हो उसका नाम वतारीफ और हलफ देने वाले कसिद्वरके दस्तखत होना चाहिये ।

(नमूनेका फार्म) नं० १२

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके लिये दी जाने वाली
करजदारकी दख्खास्त (दफा ३५)

दख्खास्त हस्व दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर त्रि०

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है:—

१ यह कि मुझ सायलके बिरुद्ध वे जो कि अपनेको मुझ सायलका एक कर्जदार
बतलाता है इस अदालतमें एक दख्खास्त दिवालिया करार देनेके लिये दी थी वरत दख्खास्तके अनुसार
मैं तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया हूँ ।

२ यह कि उक्त कर्जदारने बिलकुल गलत बयानीके साथ दख्खास्त की थी उसका कर्त मुझ सायल पर
५००) स कहीं कम है ।

३ यह कि उक्त कर्जदारने अपनी दख्खास्तमें यह गलत बतलाया है कि मैंने अपना कारोबार बन्द कर
दिया है या उसके बन्द किये जानक बात कोई सूचना इसके दी है ।

४ यह कि मुझ सायलका कारोबार बाहर चल रहा है व मैं अपने सब कर्त मकी प्रकार चुका सकता हूँ ।

५ यह कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् सब कर्जदारोंके कर्त चुकाये जाचुके हैं ।

इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म जो खिलाफ मुझ सायलके हुआ है
मसूख किया जावे या अखिल आ हुक्म मुनासिब समझे दे दवे । सायल इसके लिये बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट, — इस दख्खास्तके साथ यदि मुनासिब हो ता हुक्मनामा भी दालिज करना चाहिये । अधिकतर हक्मनामोंके
दालिज किया जाता ही अछा है ।

(नमूनेका फार्म) नं० १३

दख्खास्त करजदारके आस्ते मंजूरी हुक्म दिवालिया (दफा ३५)

अर्जो हस्व दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

मिन्नामिब

कर्जदार

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर त्रि०

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

सायल

उक्त कर्जदार निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि उक्त दिवालियेके ह्वाय एक दख्खास्त इस अदालतमें देकर अपनेको दिवालिया करार दिला लिया है ।

२ यह कि उक्त दिवालिया अधिकतर मैं रहता है जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके

बाहर स्थित है और इसी कारण इस अदालतका उक्त दिवालियेकी दख्खास्त मुननेका अधिकार प्राप्त नहीं है ।

३ यह कि मुक्त कर्जस्वादा पर किसी जेजिसकी तामील नहीं हुई जिसके कारण मैं कर्जस्वादा पैदा मुकदमा नहीं कर सका और अधिकार सीमाका विरोध भी नहीं कर सका ।

४ यह कि उक्त दिवालियाने अपने कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिककी दिखलाई है जो दरअसल उसने जो कर्ज दरखास्तमें दिखलाये हैं अधिकतर कर्जों व नुमायशी हैं और यह असली कर्जस्वादानका कर्ज मारनेकी शरतसे दिखलाये गये हैं ।

५ यह कि उक्त दिवालियाकी माली हालत काफी अच्छी है और वह बभासानी अपने असली कर्जोंको चुका सकता है ।

६ यह कि उक्त कारणोंसे यह भली भाँति प्रकट है कि दिवालिपने इसी दरखास्त लेकर और प्रसक्तियतको छिपाते हुए अदालतसे बेजा तरीके पर यह हुजम साँ ३९ ई० को हासिल कर लिया था जो कि काबिल मंजूरी है ।

इसीलिये प्रार्थना है कि दिवालिया करार दिये जाने बादा हुजम मसूख किया जाने अथवा कोई अन्य मुनासिब हुजम दिया जाने जिसके किये में फर्जेस्वादा बका क़तर होऊगा ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोटः—स दरखास्तके साथ भी इसकी पुष्टि इलक़नामा तदीक़तुदा दाखिल किया जाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० १४

तस्वीया या तय करनेकी स्वीमका प्रस्ताव पेश करनेकी दरखास्त (दफा ३८)

अर्ज़ी हर्ष अर्दिर ३८ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

यमहाकत सादर डिस्क्रिट आज बहादुर सि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९

ई०

.....सायल

एक सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदालतके हुजम द्वारा मैं सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया हू ।

२. यह कि मुक्त सायलको दिवालिया करनेकी नौबत इस कारण पहुँची कि बाजारकी हालत आम और पर गदबद है व मुक्त सायलकी क्षाम तौरसे अपने व्यापारमें नुक़सान उठाना पडा था । मुक्त सायलकी ओतमें कोई येउनमानी अमलमें नहीं लाई गई थी और न मुक्त सायलने किसी या सब कर्जस्वादों का कर्ज मारनेकी को गरजसे कोई बेजा काम किया है कोई फिज़ूल खर्ची भी अलममें मुक्त सायलकी ओतसे नहीं आई है ।

३. यह कि अब मुक्त सायलका विचार है कि मैं सायल फिरसे अपने व्यापारको करूँ और मुक्त सायलको पूरी उम्मेद है कि उसमें जरूर फायदा होगा ।

४. यह कि इसी कारण मुझ सायलने यह तय किया है कि अपने सब कर्जस्वाहानके कर्मे का समझौता करके कठोबार अपना बंदस्तूर शुरू करके। कर्जस्वाहानने भी कसरतरायसे मुझ सायलका प्रार्थनाको मंजूर कर लिया है और वह लोग रुपयेमें सात भागे अपने पूरे कुर्सेकी अदायगीमें लेनेको तैयार हैं।

५. यह कि जबकि मुझ सायलकी जायदाद व लहानसे इस समय रुपयेमें खार भाने भी बसूल होता मामुमकिन है और मुझ सायलके यकीन दिलानमें कर्जस्वाहानने तय शुदा सात भागे दो विरतोंमें ओ छमाही २ में अदाकी जावेगी लेना मंजूर कर लिया है इसलिये समझौतेकी यह स्कीम अदाकत द्वारा मंजूर किया जाना बहुत सुनासिच है।

इसलिये वक्त कारणोंसे प्रार्थना है कि मजालत ऊपर बतलाये हुए समझौतेके प्रस्तावको रूपया स्वीकार करे और दिवालिया कुरार बिये जाने वाले हुकमको असूल फर्मावे जिसके लिये सायल बचा कृतज्ञ हांगा।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

(नमूनेका फार्म) नं० १५

दरखास्त वास्ते बहाल किये जाने (दफा ४१)

दरखास्त हस्त दफा ४१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

वधदाकत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकद्मा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

.....सायल

जब सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदाकतने मुझ सायलको तारीख दिया था व सापही साथ यह भी हुकम दिया था कि मैं सायल की दरखास्त दे दू।

सन् १९ ई० में दिवालिया कुरार माइके अन्दर बहाल (Discharge)

२. यह कि मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदाकत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरकी सुपुर्दगीमें देदी थी और रिसीवर मजकूरने मुझ सायलका सब लहना व जायदादसे बसूल करके डिबिटेंट (हिसाब रसदी) कर्जस्वाहानमें तफसील कर दिया है जिससे उनका कर्मे रुपयेमें भी भागेके हिसाबसे चुका दिया गया है।

३. यह कि मुझ सायलने कोई जायदाद या कर्मे बर्बर छिपाया था और न मुझसायलकी ओरसे कोई व सनमानो या हुकम उद्दकी ही कमी दौरान मुकद्दमेमें की गई है।

४. यह कि व्यापारम घाटा होनेके कारण मुझ सायलको बुकमान उठाना पड़ा था और उस वक्त कर्जों केनेके समय मुझ सायलकी उनकी अदायगीके लिये शराभी शक नहीं था व वह पूरी तौरसे चुकाये जा सकते थे। इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि वह पूर्ण रूपसे बहाल किया जावे।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

रिसीवरकी रिपोर्टका पेश होना भी आवश्यक बात है कर्जस्वाहान इस दरखास्तका विरोध भी कर सकते हैं।

नोटः - इस दरखास्तके होने जानेकी सूचना सब कर्जस्वाहानको उसी तरीके पर दी जाना चाहिये जिस तरीके पर दरखास्त दिवालियाकी दी जाती है।

(नमूने का फार्म) नं० १६

दरखास्त वास्ते बहाल किये जानेके (दफा ४१)

दरखास्त हस्त दफा ४१ प्रान्तिक कानून दिवालिखा सन् १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर नि०.....

मुकदमा दिवालिखा न० सन् १९ ई०

..... सायल

वक्त सायल निम्न लिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मैं सायल बहुमम अदालत तारीख सन् १९ ई० को दिवालिखा करार दिया गया

था और अदालतने बहाल (Discharge) की दरखास्त देनेके लिये ६ माहकी मुदत दी थी।

२. यह कि मुझ सायलके पास कोई आयदाद नहीं थी और इसलिये किसी रितीवरकी निवृत्ति भी नहीं की गई थी।

३. यह कि मुझ सायलकी रोजगारमें यकायक घाटा पड़ जाने या अवनति होमारी एक साल तक अपने कामकी पूरी देख भाल व कानेकी वजहसे इस हालत पर पहुँचना पड़ा था।

४. यह कि मुझ सायलने जिस वक्त यह कर्जें लिये थे उस वक्त सब अदायगी का पूरा जुभीता मुझ सायलके पास था और कमी मुझ सायलकी नियत कमी किमी कर्जोंके मारनेकी नहीं रही है।

५. यह कि मुझ सायलके पास बराबर बरगपदा हिसाब किताब रहा है व मुझ सायलने किमी कर्जवाहको दूसरे कर्जवाहों पर तर्जौह नहीं दी है और न कोई बेतनदानी अवलमें कमी लाई गई है और न कोई आयदाद बाव दिवालिखा होने मुझ सायलके पास नहीं आई है।

६. यह कि ऊपर दिखलाई हुई बातोंसे अली भालि प्रकट है कि दिवालिखा बननेके लिये मैं किसी प्रकार योग्य नहीं हू किन्तु अचानक व अभाग्यवश ही मुझ सायलको दिवालिखा बनना पड़ा था।

इसलिये प्रार्थना है कि मैं सायल पूर्ण रूपसे बहाल किया जाऊँ जिसमें कि फिरसे अपना काराबार शुरू कर सकूँ क्योंकि दिवालिखा होनेके बादमे बराबर तकाद हूँ।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० १७

बहालकी दरखास्तके विरोधमें दी जानी वाली दरखास्त (दफा ४२)

अर्जी हस्त दफा ४२ प्रान्तिक कानून दिवालिखा सन् १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर नि०.....

मुकदमा दिवालिखा न० सन् १९ ई०

..... सायल

मैं कर्जवाह निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ

१. यह कि सायलने जो इस अदालतसे तारीख सन् १९ ई०

को दिवालिखा करार दिया गया था बहाल होनेकी दरखास्त इस अदालत में दी है जिसमें सूचना मुझ कर्जवाहको मिली है।

२. यह कि उन सायलजी यह दरखास्त इन कारणोंसे हार्मिज काबिल मंजूरी नहीं है ।
- (ए) यह कि दिवालिये मजकूर का लहना उसके कर्जोंके रुपयेमें आठ आठ चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है या उससे कर्जोंकी अदायगीमें सिर्फ रुपयेमें एक आठ हो बसूल हो सकी है ।
- (बी) यह कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले उसने अपनी बहुतसी आयदादकी छिपा दिया था या अपने रिस्तेदारों से गौरहके पाम्प छुटा दिया था ।
- (सी) यह कि उसने (दिवालिये) मुझ सायलका कर्ज भारनेकी गारंजसे बहुतसे कर्जों कर्ज अपने रिस्तेदारों व कोसोंके दिखला दिये थे ।
- (डी) यह कि दिवालिये अपने लहनेक बसूल किये जानेमें कोई अद्द रिस्तेदारकी नहीं ही जिससे कि उसका बहुत सा लहना बसूल होनेसे रह गया ।
- (ई) यह कि बाद दिवालिया करार दिये जानेके उसने बराबर छिपकर दूसरोंके नामसे कारोबार किया है जिसमें कभी रकम पैदाकी है और वह उस रकमको छिपाये हुए है ।
- (एक) यह कि उसने दिवालियेकी दरखास्त देनेसे पहिले अपनी गरमनकुछा आयदाद के एकमें कर दी थी वह इस तौर पर उसने को बेना तर्जो दूसरे कर्जग्राहों पर दी थी (और यह कि वह इस्तकाल जायदाद कभी करार दिया जाकर रह किया जा चुका है)
- (जी) यह कि दिवालिया मजकूर बराबर हिम्माच किताब रक्वता या लेकिन अपने बराबर हस्तम करने रकम कर्जग्राहान अपनी हिस्साकी किताबोंकी छिपा रक्वता है उनको पत्र नहीं किया है ।
- (एन) यह कि दिवालिया मजकूरने तमाम रुपया फिजल प्रथम बर्गद कर दिया है ।
- (आर्) यह कि दिवालिया मजकूरने बहुतसे कर्ज यह जानेसे छुप लिये थे कि वह उनको अदा नहीं कर सकेगा ।
- (ओ) यह कि दिवालिया मजकूर तरह २ की बेवतमानी शुरूसे अब तक अमलमें लावा रहा है जिनके कारण वह हार्मिज बहाल किये जान योग्य नहीं है ।

३. यह कि अगर दिवालिया बहाल कर दिया गया तो आयदाद उससे किसी एकमें बसूल होने की उम्मेद नहीं रहेगी ।

४. यह कि रिस्तेदारकी रिपोर्टसे भी ऊपर बनलाई हुई बहुतसी बातें साफ तौर पर जाहिर होंगी । इसलिये मार्गना है कि दिवालिया मजकूर हार्मिज बहाल न किया जावे । या वह ऐसी बातों साथ बहाल किया जावे जिसमें कि उसकी आयदाद आमदनी या जाने वाली आयदादसे कर्जग्राहानको कुछ धरपा आर बसूल हो सके)

तारीख

सन् १९

ई०

हरनाथर

नोटः—(१) ऊपर उज्जदारीकी ताईदमें यदि उचित हो तो इन्फनामा भी दाखिल किया जाना चाहिये —

(२) दरखास्तकी दफा २ में जो बख्शहात दिखलये गये हैं उनमेंसे सब या धानी जो मुन्नामिब मासूम हो दिखलाई जाना चाहिये ।

(३) बहाल पूर्ण रूपसे होका जा सकता है व आयदाद देने वाली आमदनी या जाने वाली आयदादके समय में इन्फन देकर बहाल किया जा सकता है अथवा किंगी निमतमी हुई अनधिके बाद बहाल हुनेकी आशा दी जा सकती है ।

(नमूने का फार्म) नं० १८

दरखास्त वाचत मंजूरी इत्तकाल जायदाद (दफा ५३ व ५४ ए)
 दरखास्त हस्ब दफा ५३ व ५४ ए कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

सायल

उक्त मायलेमें निम्नलिखित प्रार्थना है

१. यह कि दिवालिया स्वयं अपनी दरखास्त पर इस अदालत द्वारा ता० सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था ।

२. यह कि अदालतके हुक्म द्वारा ये उक्त दिवालियाकी जायदादके लिये विसीवर नियुक्त किया गया है

३. यह कि दिवालिया भजकुरने अपनी जायदाद वगैरहें दस्तावेज रजिस्ट्रीया मुबर्कि

अपने एक रिस्तेदार मुसम्मि के नाम दरखास्त दिवालिया देनेके बाद साह पडिहें (अयान् अन्वर दो सालके) कर दी है और यह दरवायेज बिलावदल व कर्जी यी व अपनी जायदादको बचाने व उसकी अपने कर्जखानाने बचानेकी गरजसे लिखा था जो कतबिल कायम रहनके नहीं हैं ।

४. यह कि मुझ रिसीवरने को जिनके हुक्में दस्तावेज भजकुर लिखी गई थी हत बातकी हलका दे दी थी कि वह जायदाद का कब्जा मुझ रिसीवरको दे देंगे लेकिन उन्होंने बसकी कोई मुनवाई नहीं की और न जायदाद पर कब्जा ही दिया ।

५. यह कि उक्त कार्योंसे ऊपर बतलाया हुआ इत्तकाल जायदाद बिल्कुल कर्जी है व मुझ रिसीवरके बिहद कोई असर नहीं रहता है और जायदाद भजकुर का कब्जा मुझ रिसीवरको मिलना चाहिये जिसमें वह कर्जखानाबनमें तकसीमकी जा सके ।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त इत्तकाल जायदाद कर्जी व बिलावदल करार देकर मसूल कनोया जावे । मुझ रिसीवरके डिक्ला बिल्कुल बेअसर बरार दिया जावे या कोई अन्य मुनासिब हुक्म दिया जावे ।

सातक

सन् १९

ई०

इस्ताफर

नोटः—जायदादकी पूरी तकसीम दी जाना चाहिये और यदि मुनासिब हो तो इत्तहा देने वाले व्यक्ति का इल्फनामा भी हत दरखास्तमें पुरटेम बाबत रिता बगैराके लगा देना चाहियेः—

(नमूने का फार्म) नं० १९

धोखादेहीसे तर्जिह देने वाले इत्तकाल जायदादकी मंजूरीके लिये दी जाने वाली
 दरखास्त (दफा ५३ व ५४ ए)

दरखास्त हस्ब दफा ५३ व ५४ ए. प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

सायल

रिसीवर

पिटिशनर बनाम कर्जखाना

फौकसानी

उक्त पिटिशनर (रिसीवर) की निम्नलिखित प्रार्थना है,—

१. यह कि सायल अपनी ही दरखास्त पर इस अदालतके हुक्म द्वारा सातक सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था व मैं पिटिशनर उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२. यह कि उक्त दिवालियाने तारीख
हस्ताकाल करके वसमेंसे मुकदमा २००७)
मुकदमा तर्जिह देकर द दिया है । जायदादके हस्तकालकी तत्काल इस दरखास्तके साथ दाखिलकी जाने वाली
फिररिस्तमें दिखलाई गई है ।

३. यह कि उक्त हस्तकाल जायदाद व नीज अदावगी रुपया ऐस समयमें की गई थी जब कि
दिवालिया मजकूर अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ था और यह काम दिवालियकी दरखास्त दिव जानसे तीन
माहके अन्दर किया गया है ।

४. यह कि ऐसी दशामें यह सौदा कानूनन नाजयज है और मुक्त रिस्तिवरके विरुद्ध कालि कायम
रहनेके नहीं है और इसी कारण मसूख किया जाना चाहिये ।

५. यह कि मुक्त रिस्तिवरने फरीकमानवी (कर्जखाह जिसके हकमें रुपया अदा हुआ था) को इसकी
पुचवा देवी भी व इससे इस रुपयेको वापिस होने या सादाको मसूख करानेको कहा था परन्तु उसने उसे नहीं माना ।
इसलिये माधना है कि उक्त सौदा नाजायज करार दिया जावे या कोई अन्य उचित हुकम दिया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोटः—इस पिदाशनके साथ जायदादकी तत्काल दाखिलकी जाना चाहिये व यदि आवश्यकता हो तो जानने वाले
प्रतिश्रुत हलकनामा वाक्यतकी पुष्टिमें लगाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० २०

दरखास्त कर्जखाह धामते मसूखी हस्तकाल जायदाद (वफा ५४ व)

वरखास्त हस्त वफा ५४ ए प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९१० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

..... सायक

मिनशानिब

कनेल्वाह

यथा कनेल्वाह विन्यासित मार्गना करता है:—

१. यह कि उक्त सायक स्वय अपनी दरखास्त पर इस अदालतके हुकम द्वारा तारीख
सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और इसकी जायदादके लिये
अदालत द्वारा रिस्तिवर नियुक्त किये गये हैं ।

२. यह कि दिवालिया मजकूर अपनी जायदादको बजरिये दस्तावेज फर्जी सुवरक्षा
अपने एक रिस्तिदारके हुकम बिला बदल लिख दिया है जिसे तखमिनन माहके (दो सालके अन्दर) समझ
होना चाहिये) हुप है ।

३. यह कि हस्तकाल जायदाद दिवालिया मजकूर अपनी जायदादको बचानेके लिये इस गरजसे किया है
कि जिसमें वह इसके कनेल्वाहानको न मिल सके व जिस समय यह हस्तकाल किया गया था दिवालिया अपने स्वय
कर्जोंको चुकानेके लिये समर्थ नहीं था व दरखास्त बिला बदल व फर्जी तारसेकी गई थी जो हातमें काबिल मसूखी है ।

४. यह कि मुक्त कनेल्वाहने उसकी मसूखीके बावत रिस्तिवर साहबसे बारहा कहा व उनको
तारीख सन् १९ ई० को नोटिस भी इसके बावत दिया था लेकिन वह इसके
लिय तैयार नहीं हुए लिनाम मजकूर मुक्त कनेल्वाहको उसकी मसूखीके लिये दरखस्त देना पड़ी ।

५. यह कि चूंकि कानूनन मुक्त कर्जवाहक विहा इजाजत अदा करत ऐसे इन्तकालके मसूख कराने एक नहीं है इस कारण उसकी इजाजतके लिये यह दरवास्त दी जाती है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत मुक्त कर्जवाहको उक्त इन्तकाल जायदादकी मसूख करानेकी इजाजत दी जावे या अन्य-कोई उचित हुक्म दिया जावे और साथ ही साथ प्रार्थना है कि उक्त इन्तकाल मसूख फर्माया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोट: — दरवास्तकी पुष्टिके लिये हक्कनामा भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं० २१

दरखास्त याचक लहकरीकात जुर्म दिवालिया (दफा ७०)

दरखास्त हसब दफा ७० प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत स हब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि०.....

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९

ई०

..... सायत

मिलजानिब

रिसीवर

उन रिसीवर निम्न लिखित प्रार्थना करता है —

१. यह कि सायल अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया फरार दिया गया था और मैं उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२. यह कि मुक्त रितीवरने दिवालिया मसकूरसे बारहा अपनी सब हिसाबकी किताबें पेश करने व सूचीमें दिखलाई हुई जायदाद पर कब्जा देनकी कड़ा मगर दिवालियेने उसकी कोई परनाह नहीं की । मुक्त रिसीवरने उसको कारतेसे इसला भी तारीख सन् १९ ई० को ददी है इस पर भी न तो दिवालिया खुद मरे पास आया है और न मरे कहनेकी इसला ही की है ।

३. यह कि दिवालिया मसकूर अपनी जायदादको कर्जवाहानसे बचानेकी नीयतही से यह सब कारवाइया कर रहा है । या

दिवालियाने अपनी हिसाबकी किताबोंको बन्द कर दिया है या उसे अपनी हिसाबकी किताबोंमें गुलत हुन्दराज बगारा असली हालतकी छिपानेकी मन्नासे कर लिये हैं । या

अपनी हिसाबकी किताबोंको पेश नहीं कर रहा है । या

दिवालियेने सूचीमें दिखलाई हुई जायदादमें अपनी बहुतसी जायदाद नहीं दिखाई है या उनमेंसे कुछको रेशन वय भादिते मलहदा कर रखा है और यह सब कारवाइ अपने कर्जवाहको नुकसान करने व बेजा लाभ उठानेकी मन्ना ही से की है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत ऊपर दिखलाये हुए जुर्मकी लहकरीकात करे और हसब दफा ७० प्रान्तिक कानून दिवालिया कारवाइ अमकलमे लावे या कोई अन्य मुमानिष हुक्म सादर फर्मावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

प्रेसीडेन्सी टाउन्स क्रानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०९ ई०

Presidency Towns Insolvency Act, No. 3 of 1909.

यह क्रानून सिर्फ
कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून और कराची शहरोंमें लागू है

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र
नज़ीरों एवं उदाहरणों तथा अन्य
क्रानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :—

बाबू रूपकिशोर टागोर

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एस० परबोकेट

प्रकाशक :—

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :—

क्रानून प्रेस, कानपुर

Presidency Towns Insolvency Act.

Act No. III of 1909.

प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नम्बर ३ सन १९०९ ई०

१२ मार्च सन १९०६ ई० को गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति प्राप्त हुई,

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) व रंगून के कानून दिवालियाको संशोधन करनेके लिये बनाया गया है

प्रस्तावना (Preamble)

इसके यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंसी टाउन्स तथा रंगून के कानून दिवालिया में संशोधन किया जावे अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

[यह एक्ट विर्ग कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची इन ५ शहरोंमेंही लागू होगा इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानमें यह एक्ट लागू नहीं होगा]

दफा १ नाम व प्रारम्भ .

(१) यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया सन १९०६ ई० (The Presidency Towns Insolvency Act 1909.) कह लायगा ।

(२) यह एक्ट पहिली जनवरी सन १९१० ई० से लागू होगा ।

व्याख्या—

जो कि इस एक्ट का नाम प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया है किन्तु प्रेसीडेंसी टाउन्सके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानोंमें भी इसके प्रयोग किये जाने की व्यवस्थाकी गई है अर्थात् प्रेसीडेंसी टाउन्स के अतिरिक्त इसका प्रयोग एत शहर व कराचीमें भी किया जाता है । एत का उल्लेख तो इस एक्ट के प्रारम्भ भा में कर दिया गया है किन्तु कराची (Karachi) के लिये इसका प्रयोग एक्ट ९ सन् १९२९ ई० के अनुसार किया जाना निश्चित हुआ है उससे पहिले कराचीमें प्राक्तिक कानून दिवालिया लागू था वन्तु उस एक्टके नियमोंका प्रयोग कराची टाउनके लिये उपयुक्त नहीं समझा गया इस कारण सिविल जस्टिस कमिटी की सिफारिश पर उस एक्ट का प्रयोग कराचासे उठा दिया गया और उसके स्थान पर वहाके लिये इस एक्ट अर्थात् प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया का प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया । इस एक्ट (प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्साल्वेंसी एक्ट १९०९) के पास होनेके पादेके प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) में इन्डियन इन्साल्वेंसी एक्ट १८४८ (11 & 12 Vict Ch 21) लागू था और दिवालियोंके अधिकारों का प्रयोग प्रेसीडेंसी टाउन्समें इन्डियन तथा ग्नूनमें चीकनर्ट किया करते थे ।

प्रांतिगत कानून दिवालिवासे भेद—प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्सोल्वेंसी एक्ट तथा प्रांतिगत कानून दिवालिवा (Provincial Insolvency Act) एक दूसरे में भिन्न हैं तथा उनके अनुसार दिवालिवाके सम्बन्धमें जो अधिकार नियत किये गये हैं वे भी भिन्न हैं इस कारण यदि कोई दिवालिवाके दाखवास्त प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिवाके अनुसार हाईकोर्टमें चलाया जाय तो वह प्रांतिगत कानून दिवालिवाके अनुसार कार्य करने वाले अदालत जिला (District Court) में नहीं चलाया जा सकता है। देखो—38 Mad 472; 53. Cal. 928.

इस एक्टका पिछले कार्यों पर प्रभाव—इस एक्ट का कोई प्रभाव पिछले किये हुए कार्यों पर नहीं पड़ेगा सिवाय उसके जिसका उल्लेख इस एक्टमें कर दिया गया हो। जो एक्ट बनाये जाते हैं उन सबका प्रयोग भविष्यमें होने वाले कार्योंके लिये होता है पिछले कार्योंके लिये नहीं। इस सम्बन्धमें यहाँके हाईकोर्टों तथा विलायतनी बहुतनी नजारे हैं जिनमें यह साफ तौरसे तय किया गया है कि कानून पिछले कानूनोंके अनुसार किये हुए कार्योंका नहीं पड़ेगा किन्तु भविष्यमें किये जाने वाले कार्य उसके अनुसार किये जावेंगे। देखो—(1890) 15 A. C. 384, (1894) Q. B. 725 (737), 31 C. L. J. 463.

दफा २ परिभाषायें

यदि कोई बात विषय व महाद्वारेके विरुद्ध न पड़ती हो तो इस एक्टमें दिये हुए नीचेके शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये:—

- (ए) कर्जदार (Creditor) से अभिप्राय डिक्रीदार (Decreeholder) का भी है।
- (बी) कर्जा (Debt) से अभिप्राय डिक्री के कर्मेसे भी है और कर्जदार (Debtor) से अभिप्राय मदीयून (Judgement debt) का भी है।
- (सी) आफिशल एसायनी (Official Assignee) से अभिप्राय कायम मुकाम आफिशल एसायनी (Acting Official Assignee) से भी है।
- (डी) निर्धारित किये हुए (Prescribed) अभिप्राय उन बातों का है जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हों।
- (ई) जायदाद (Property) से अभिप्राय उस जायदाद का भी है जिस पर या जिससे होने वाले लाभ पर किसी व्यक्तिको व्यय करनेका अधिकार होवे और जिससे वह अपने लाभके लिये प्रयोग कर सके।
- (एफ) नियमों (Rules) से अभिप्राय उन नियमों का है जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों।
- (जी) महाकृत कर्जदार (Secured Creditor) से अभिप्राय उस ज़मींदार (Land Lord) का भी है जिसका किसी प्रचलित कानूनके आधार पर ज़मीनके लगानके लिये किसी ज़मीन पर हार होवे।
- (एच) अदालत (The Court) से अभिप्राय उस अदालत का है जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करनी हो।

(आर्द्र) इन्तकाल जायदाद (Transfer of Property) से अभिप्राय उस इन्तकाल से भी है जो उस जायदादके किसी हक या उस पर पैदा हुए किसी हारके सम्बंधमें किया गया हो ।

व्याख्या—

अधिकतर ऊपर दी हुई परिभाषामें पूर्ण परिभाषाये नष्ट है क्योंकि उनमें केवल यह बतला दिया गया है कि किसी अन्य विषय का प्रयोग किसी खास अर्थमें समझना चाहिये जैसा कि प्रायः (ए) में कर्जवाह (Creditor) शब्दों की परिभाषा नहीं दी हुई है किन्तु केवल यही बतलाया गया है कि डिक्लर (Decree holder) को भी कर्जवाह (Creditor) समझना चाहिये ।

फलाज (ए) में केवल यह बतलाया गया है कि डिक्लर (Decree holder) को कर्जवाह समझना चाहिये इतलिय इस हू तबे यह बात प्रष्ट नहीं होता है कि कर्जवाह किसे किसे समझना चाहिये । इस बातके समझनेमें दफा ४६ तथा उसका व्याख्या सहजता प्राप्त हो सकती है क्योंकि उस दफामें कर्जा स्तित्त किये जानका उल्लेख किया गया है । किन्तु कर्जवाहके बेनामीदारका कर्जवाह नहीं समझना चाहिये, दली—नवमी बनाम सूत 20 C W N 995

फलाज (बी) में भी फलाज (ए) के भाति न ता कर्जकी आर न कर्जदारकी परिभाषा दी गई है किन्तु बतला दिया गया है कि फलाज (बी) की (Judgement Debt) को कर्ज (Debt) व फलाज (Judgement debtor) का कर्जदार (Debtor) समझना चाहिये । इस कारण इन दो अर्थों के या कर्जदारकी परिभाषा भा इस एक्टकी ११ दफाओं में पढ़ने तथा हाईकोर्ट द्वारा दी हुई दफाओं का ध्यानमें समझा जा सकता है । इन दफाओंके लिये विशुद्ध परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु समय समय पर इन दफाओंका प्रयोग जिन बातोंके लिये किया गया है या हाईकोर्टके फरमानोंमें इन शब्दोंका प्रयोग जिन बातोंके लिये होना, बतलाया गया है उ की बात से तात्पर्य इन शब्दोंसे समझना चाहिये । यदि कोई दफा दरमल व हर हालतमें अज्ञात विषय जानिका है चाहे उसकी अद यगी उस समयका ज नका हवे अथवा भविष्यमें किसी समय उसकी अद यगी हान वाला हवे तो उस दफाकी कर्ज समझना चाहिये दली—36 Cal 94 उधार देने वाल व उधार लेने वालका सम्बन्ध आपसमें कर्जवाह व कर्जदारका होता है और जब तक इनके बिच्छु कोई बात सुझाईदेमें न होवे, कर्जदारको दली नहीं समझना चाहिये आफिशल दयादना बनाम लिप 32 Mad 108 यदि कोई व्यक्ति अपनी कपया किसी दूसरे व्यक्तिको इस बातक लिये दन कि वह कपया किसी तीसरे व्यक्तिको द दिया थाव तो पहिले व्यक्तिका सम्बन्ध दूसरे व्यक्तिमें फर्जवाह न कर्जदारका नहीं होगा क्योंकि इस दफामें वह दूसरा व्यक्ति एक प्रकारमें एजेंटका काम करता है दली—36 Mad. 499

फलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी (Official Assignee) से तात्पर्य उन व्यक्तिओं को समझना चाहिये जिन उसकी जगह पर काम करनेके लिये नियुक्त किया जावे अपना जो काम पदवी पर काम करता हो । आफिशल एसायनीकी नियुक्ति सम्बन्ध आग चल कर बचन दिया हुआ है ।

फलाज (डी) में अंजली एकाग्र प्रयोग किय हुए (Prescribed) शब्दके बरतमें दिया हुआ बचन उसक उल्लेख (Prescribed) से दल ता पय इन बातोंका समझना चाहिये जो नियमांक अनुसार निर्धारित हैं ।

फलाज (ई) में जायदाद (Property) शब्द शोमें लिखा हुआ है, परन्तु इस शब्दका पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है एक्टकी दूसरी दफाओंमें जहां जहां पर बतलाया गया है कि दिवालियेकी सैनसा न दयाद

उसके कर्जस्वारोंमें प्राथी जा सकती है या जौसो बायदाद पर अफिशल एसायर्न कन्जा ले सकता है इत्यादि । इसका विवरण ऊन्हीं दफाओंमें मिलेगा जैसे कि दफा ५२ तथा दफा १७ आदि ।

फलाज (एफ) में यह बतलाया गया है कि जहा पर नियमों (Rules) का उल्लेख मिले वहा उनसे तात्पर्य वन नियमोंका समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों ।

फलाज (जी) में मद्दूज कर्जस्वार्होंका उल्लेख है परन्तु इस क्लानून इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा नहीं दी हुई है । नार्थ हार्कोर्टने भी A. I. R. 1929 Bom. 107. में भी यही मत प्रकट किया है उसमें यह तथ हुआ था कि मद्दूज कर्जस्वार्ह (Secured Creditor) की परिभाषा पूर्ण परिभाषा नहीं है और किंग्स इंग्लिश बैंकसी एक्ट (English Bankruptcy Act) के शब्दोंका अधिकतर प्रयोग इस एक्टमें किया गया है इस कारण उन एक्टों (Acts) में जो परिभाषा दी गई हो वह माननीय समझना चाहिये अर्थात् उन परिभाषाओंको इस एक्टके लिये लागू समझना चाहिये ।

फलाज (एच) में अदालत शब्दका विवरण है और यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें जहा कहीं अदालत (The Court) शब्दका प्रयोग पाया जावे वहा उस शब्दका तात्पर्य उस अदालतसे समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिसूचना प्रयोग कर रही हो । इस प्रकार अदालत शब्द उस अदालतके लिये भी प्रयोग किया जाना समझना चाहिये जिसके दफा ६ के अनुसार एक्टकी दुरुस्वास्तोंको सुनने या बयान लेने आदिके अधिकार प्रदान कर दिये गये हों ।

फलाज (आई) में इन्जुनक्श जायदादका शिफ्ट है परन्तु इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा इस क्लानूनमें नहीं दी हुई है केवल इतना बतला दिया गया है कि वस्तुसे तात्पर्य उस इन्जुनक्श (Transfer) से भी है जो उस जायदादके किसी एक या पक्ष पर पैदा हुए किसी भावके सम्बन्धमें किया गया हो । हार्थवॉर्टने इस बातको तय कर दिया है कि क्लानून दिवालियाके सम्बन्धमें इंग्रेजी फैसले (English Decisions) भी माननीय हैं क्योंकि यह क्लानून इंग्लिश बैंकसी एक्ट (The English Bankruptcy Act) से बहुत कुछ मिलता मिलता हुआ है, देखो—40 Mad. 810. इसी प्रकार परिभाषाओंके लिये भी वह एक्ट लागू है अर्थात् माननीय है । देखो—A. I. R. 1929 Bom. 107.

नोट ८—इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि जिस शब्दकी परिभाषा इस एक्टमें न मिले वस्तुके लिये जनरल इन्जुनक्श एक्टमें दी हुई परिभाषा लागू होगी ।

पहिला प्रकरण

अदालतोंकी व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

दफा ३ वह अदालतें जिनको दिवालियाके अधिकार प्राप्त हैं

निम्न लिखित अदालतोंको इस एक्टके अनुसार दिवालियाके सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त हैं ।

(ए) कलकत्ता हार्थकोर्ट, मद्रास हार्थकोर्ट तथा बम्बई हार्थकोर्ट ।

(बी) लोअर बर्माका चीफकोर्ट ।

व्याख्या—

इस एक्टके बननेके पश्चात् बहुतसे परिवर्तन तथा संशोधन हुए हैं । काण इस दफाको भी उन्हीं संशोधनोंका प्थान रखते हुए पटना चाहिये । लोअर बर्माके चीफकोर्टसे तात्पर्य एन हार्थकोर्टका समझना चाहिये और इस दफामें बतलाई हुई

अदालतोंके अतिरिक्त सिन्धके इंडियन कमिश्नरको भी दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करने वाली अदालत मानना चाहिये वृत्ति एक्ट ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार कराची (-Karachi) टाउन (Town) में भी इस एक्ट अन्तर्गत प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्स्टीट्यूट एक्टका प्रयोग प्रारम्भ हो गया है इस कारण सिन्धकी अदालत आग (Highest Tribunal) को भी वही अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो पेंटर मिर्क इस दफामें बतलाई हुई अदालतोंको प्राप्त थे ।

दफा ४ अकेला एकही जज इस एक्टके अधिकारोंको बरत सकता है

इस एक्टके अनुसार मामलों को सुनने या तय करनेका जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग ऊपर बतलाई हुई अदालतों का कोई एक जज कर सकता है और चीफ जस्टिस या चीफ जज समय समय पर किसी एक जजको इस एक्टके अनुसार कार्य करनेके लिये नियुक्त करेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिये का अधिकार रखने वाले हाईकोर्ट या चीफोर्टके चीफ जस्टिस या चीफ जज का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अदालतके किसी एक जजको दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुननेके लिये नियत कर देवे और ऐसे नियत किये हुए जजको अकेले ही दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुनने तथा उनको तय करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

दफा ५ कमरोंमें जजोंका काम करना

इस एक्टकी बातों तथा उसके लिये बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतके जजको अधिकार है कि वह दिवाल सम्बन्धी मामलोंकी सब बातें या उनमेंसे कुछको कमरोंमें सुन सकता है अर्थात् वह अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंका प्रयोग कमरोंमें बैठे हुए कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करने वाला जज उन अधिकारोंको अपने कक्षमें बैठे हुए भी प्रयोग कर सकता है अर्थात् उन्हीं लिये वह खुली अदालतमें सुननेके लिये बाध्य नहीं है परन्तु इसका तात्पर्य यह न समझना चाहिये कि वह दिवालिया सम्बन्धी सब कामका कमरोंके अन्दर ही करेगा । आवश्यकतासुमार वह दिवालिया सम्बन्धी सब बातोंको या उनमेंसे कुछको कमरोंमें बैठे हुए भी सुन सकता है कि तु साथ ही साथ उसका इस एक्टकी बात व इस एक्टके सम्बन्धम बनाये हुए नियमोंकी भी अवहेलना न करना चाहिये अर्थात् यदि किसी बातको खुली अदालतमें सुनना या तय करनेके लिये एक्ट या नियममें बतलाया गया हो तो उसे खुला अदालतमें ही सुनना चाहिये इसी प्रकार यदि कोई और बात कमरोंमें किसी मामलेके सुने जातेके विरुद्ध पड़ती हो तो उसका ध्यान रखना चाहिये ।

दफा ६ अदालतके अपसरोंको अधिकार प्रदान करना

(१) चीफ जस्टिस या चीफ जजको अधिकार है कि वह समय समय पर अदालतके किसी अपसरको जिसे उसमें स्वयं इसीलिये नियत किया हो, इस दफामें बतलाये हुए सब या उनमेंसे कुछ अधिकारोंके प्रयोग करनेका अधिकार दे देवे और यह अधिकार उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें दिये जावेंगे जिनके लिये इस एक्टके अनुसार अदालतको अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रकार नियत किया हुआ अपसर ऊपर बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए जो हुक्म देगा या काम करेगा वह हुक्म या काम अदालत ही का हुक्म या काम समझा जावेगा ।

(२) उपदफा (१) में जिन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है वह अधिकार निम्न लिखित हैं—

- (ए) कर्जदारों द्वारा दिये जाने वाली दिवालियेकी दरद्वारोंका सुनना तथा उन पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देना
- (बी) दिवालियेका सरेआममें घयल लेना (To hold public examination)
- (सी) जिन अधिकारोंका प्रयोग किया जाना कमरेमें बैठे हुए उचित निर्धारित किया गया है उनका प्रयोग करते हुए किसी हुक्मका देना या उनका प्रयोग करना
- (डी) किसी ऐसी दरद्वारत, जिसका विरोध न किया जा रहा हो या जो एक्स्पार्ट (Ex parte) होये उसका सुनना तथा उसका निदिबल करना
- (ई) अदालत द्वारा दफा २६ के अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिका घयान लेना
- (३) इस दफाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरको अदालतकी तौहीनी (Contempt of Court) के लिये मामला चालू करनेका अधिकार नहीं होगा

व्याख्या—

वर्षिका सुननाके लिये उस दफाके उपदफा (१) के अनुसार चीफ्जस्टिश या चीफ् जजमें यह निर्धारित किया गया है कि तब अदालतक किसी अफसरको कुछ मामलोंके सुनने या तय करना अधिकार दे सके जिन मामलोंके सुनने या तय करना अधिकार इस दफाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरका है उनका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि चीफ्जस्टिश या चीफ् जज वहाँ मामलोंके सम्बन्धमें पूरा अधिकार दे सकते हैं जो उनका अदालतका तय करने के अनुसार प्राप्त हों उन अधिकारोंके अतिरिक्त वह जज वहाँ के डिप्युटी जजों को दे सकते हैं ।

उपदफा (२) में जिन अधिकारोंका उल्लेख है वह सब एक साथ ही दिये जानेके आवश्यकता नहीं है चाफ्जज या चाफ्जस्टिश आवश्यकतानुसार समय समय पर उनमेंसे कुछ अधिकारोंको ग्राह्यतः प्रयोग करने पर सभी अधिकारोंको दे सकते हैं । चाफ्जस्टिश या चीफ्जज स्वयं इस कामके लिये बिना अफसरको नियुक्त करना और ऐसी नियुक्ति किये हुए अफसरका जा आधार प्रदान करने के प्रभाव करनेके लिये वह अफसर पूरा रूपसे अधिकारी होगा । उन अधिकारोंका प्रयोग करते हुए वह अफसर जा हुक्म देगा या जा कार्य करेगा वह अदालतकी वात या हुक्म समझा जायगा ।

उपदफा (३) के अनुसार इस दफाके नियुक्त किये हुए अफसरको तौहीनी अदालतका मामला चालू करनेका अधिकार प्राप्त नहीं होगा । यह दफा (६) के अनुसार रजिस्ट्रारको अधिकार दे दिये गये हैं दफा ३८ के अनुसार उस अदालत समझना चाहिये अपाउ रजिस्ट्रारको इस दफाके अनुसार अधिकार दिये जासकते हैं—A. I. R. 1928 Cal 786

दफा ७ दिवालियेके सम्बन्धमें पैदा हुए सब प्रश्नोंको तय करनेके अधिकार

इस अक्टमें दी हुई बातोंका ध्यान रखते हुए अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उन सब प्रश्नोंको तय करे जो कर्जोंकी पेश्तर अदायगीके सम्बन्धमें पैदा हों और भी हर प्रकारके प्रश्नों को तय करे चाहे वह कानूनी होंवे या वाक्याती होंवे जो कि अदालतके सामने उपस्थित किसी दिवालियेके मुकद्दममें पैदा होंवे या जिनको अदालत पूर्ण न्याय करनेके लिये उचित या आवश्यक समझे अथवा जिनको वह किसी मामलेमें जायदादको पूर्ण रूपसे वांटनेके लिये उचित या आवश्यक समझे ।

व्याख्या—

इस दफा में अदालत के अधिकारों का वर्णन है उसके अधिकार सीमा का वर्णन नहीं है। अदालत दिवालिया की उन प्रश्नों के तय करने का अधिकार है जो आफिशल एसायनी व गैर प्रश्नों (Strangers) के बीचों पड़ा हो। जैसे—20 Mad. L. T. 311 अदालत दिवालिया के दिये हुए हुक्म की रद्द किये जाने के लिये कोई मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता है, देखो—40 Mad. 1178 उक्त मुकद्दमे में आफिशल एसायनी के अपीलान्ट्स के कन्वेंस को कुछ जायदाद को यह कह कर ले लिया था कि वह जायदाद बरगल दिवालिया की जायदाद है क्योंकि उसके सम्बन्ध में जा बेनामा किया गया था नह दिखल कर्सी व तुमायशी था और भिन्न कर लिया गया था। अपीलान्ट्स ने पहिले अदालत दिवालिया में इस बात की दरख्वास्त की कि वह माल उन्का करार दिया जावे अदायगने इस मामले की अस्तित्व को सुन कर अपीलान्ट्स की बात दरख्वास्त को खारिज कर दिया अपीलान्ट्स ने अदालत दिवालिया के इस फैसले की कोई अपील नहीं की किन्तु उसकी मसूला के लिये अदालत दीवाना में गारिश दायर कर दी थी उस पर यह तय किया गया था कि अदालत दिवालिया के दिये हुए हुक्म की रद्द करने के लिये कोई दीवाना मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है यदि कोई हक सम्बन्धी कन्वेंस प्रस्त उपस्थित होवे तो अदालत दिवालिया की चाहिये कि वह आफिशल एसायनी को ऐसे प्रश्न दीवाना की अदालतों द्वारा तय करने का आदेश कर दे। देखो—20 Mad. L. T. 311.

इसी फैसले में यह भी तय हुआ था कि अदालत दिवालिया अपने अधिकार सीमा से बाहर स्थित जायदाद के सम्बन्ध में भी फैसला दे सकती है इस दफा में एक प्रकार की सहूलियत के लिये अदालत दिवालिया को अधिकार दे दिये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इसके कारण अदालत दीवाना के उस मूल अधिकार का अपहरण होता है जो उसे उन प्रश्नों के सम्बन्ध में प्राप्त है जो कि आफिशल एसायनी व गैर लोगों के दासियान पैदा होवे देखो—35 Bom 478.

यदि इस एक्ट में किसी प्रश्न को तय करने के लिये कोई नियम दिया हुआ हो तो उसकी मानने तथा उसके अनुसार कार्य करने के लिये अदालत दिवालिया बाध्य है। इस दफा के अनुसार अब सब प्रश्नों के तय करने के लिये अदालत दिवालिया को अधिकार प्राप्त है चाहे वह कानूनी हानि या बाधपाती। क्योंकि वेक्टर अदायगी के सम्बन्ध में नितने प्रश्न उपस्थित होवे वह सब बिना किसी बाधा के अदालत दिवालिया द्वारा तय किये जा सकते हैं। इसी प्रकार दिवालिया के मुकद्दमों के सम्बन्ध में यदि और कोई प्रश्न उपस्थित होवे अथवा अदालत इसाफ के लिये किसी प्रश्न का तय करना अचित व आवश्यक समझे तो वह ऐसे भी सब प्रश्नों को तय कर सकती है और अदालत दिवालिया द्वारा दिये हुए फैसले की दीवाना के मुकद्दमों द्वारा रद्द नहीं करायी जा सकती है। अर्थात् एक प्रकार से उनकी अग्र तबवान खुदा समझना चाहिये अदालत दिवालिया को इस दफा के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि कोई जस्टिस प्रश्न हक के सम्बन्ध में उपस्थित हो जाय तो उस मामले की बजाय खुद तय करने के अदालत दीवाना द्वारा तय किये जाने का आदेश कर देना चाहिये जिसमें पूर्ण रूप से इसाफ हो सके व किसी फरीज को शिनायत का अवसर प्राप्त न होवे।

अदालत दिवालिया की अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जो दिवालिया की जायदाद का कर्जदार समझा जाता हो और जो २०० माल के अधिक दूरी पर रहता हो उसके विरुद्ध उसकी हाजिरी तथा बयान के लिये सम्मन जारी कर सके देखो—A. I. R. 1928 Mad. 806 दफा ७ के अनुसार हाईकोर्ट को गारिश दीवाना मामलों के सम्बन्ध में भी अधिकार प्राप्त है यदि गारिश उसकी अधिकार सीमा से बाहर भी रहता हो देखो—51 Mad. 540, A. I. R. 1928 Mad. 752 ('गारिश' यह शब्द मदगल प्राप्त है)।

यदि दफा ७ के अनुसार निम्न गवाह के वयन लिये जावे तो उसको वह सब सुविधायें प्राप्त होंगी जो कानून शहादत (Law of Evidence) के अनुसार गवाहों को प्राप्त होनी चाहिये और वह उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं

निया जा सकता है जिनका उत्तर वह कानून शब्दावलीके अनुसार देनेसे इनकार कर सकता है। अदालत इस दफाके अनुसार दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें किसी भी व्यक्ति का बयान ले सकती है और कोई शबाह इस कारण कि उसका मापिसाल तब तक उस मापिसालसे है शबाही देनेसे इनकार नहीं कर सकता है देखो—A. I. R. 1920 Mad. 188.

अपील

दफा ८ दिवालियेके मामलोंकी अपील

(१) अदालत अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करते हुए जिन हुक्मोंको दे चुकी हो उन हुक्मोंकी यह नजरसानी कर सकती है उनको पलट सकती है अथवा उनमें रद्दोपलट कर सकती है।

(२) कोई भी व्यक्ति जिसने हानि पहुँचती हो दिवालिया सम्बन्धी मामलोंमें दिये हुए हुक्मोंकी अपील निम्न प्रकारसे कर सकेगा:—

(ए) दफा ६ के अनुसार अधिकार प्राप्त किये हुए अदालतके अफसर द्वारा दिये हुए हुक्मकी अपील उस जजके यहां की जावेगी जो दफा ४ के अनुसार दिवालियेके मामले सुनने या तय करनेके लिये नियुक्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त कोई आपम्दा अपील यिला उस जजकी भत्ता लिये हुए, नहीं की जावेगी।

(बी) क्लार्क (ए) में बतलाई हुई धारोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार दिये हुए दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करते हुए किसी जज द्वारा जो हुक्म दिये जावे उनकी अपील उसी प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार उन हुक्मोंकी अपील की जाती है जो दीवानीक मूल अधिकारोंका प्रयोग करने हुए किसी एक जज द्वारा दिये गए हों।

व्याख्या—

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि अदालत दिवालिया अपने हुक्मों पर दुबारा और कर सकती है तथा उनपर पलटने व बदलनेका अधिकार भी अपने पास है। इन अधिकारोंसे शीघ्र उसी प्रकार समझकर चाहिये जिन प्रकारके अधिकार जजका दायानीके अनुसार अदालत दीवाना द्वारा प्रयोग किये जाया बतलाया गया है। अदालत अपने हुक्मोंकी नजरसानी (Review) कर सकती है तथा वह अपने मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए उन हुक्मोंको रद्द कर सकता है अथवा आवश्यकतानुसार उनमें रद्दोपलट कर सकती है किसी हुक्मकी नजरसानी (Review) उसी हाकिम द्वारा की जाती है जिसने उस हुक्मको दिया हो पन्तु यदि वह हाकिम बदल गया हो या किसी वजहसे उस जगह पर काम न करता हो और उसकी जगह पर कोई दूसरा हाकिम नाम करता हो तो ऐसा हाकिम भी पहिले हाकिम द्वारा दिये हुए हुक्मोंकी नजरसानी सुन सकता है। नभे कि यदि किसी रजिस्ट्रारने कोई हुक्म दिया हो तो उसकी जगह पर आने वाला व्यक्ति उस हुक्मकी नजरसानी सुन सकता है। यदि हुक्म किसी एक जज द्वारा दिया गया हो तो दूसरा जज जो दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करता हो पहिले जज द्वारा दिये हुए हुक्मकी नजरसानी (Review) सुन सकता है, देखो—A. I. R. 1925 Cal 786 (F. B.) यदि रजिस्ट्रारने दफा ३६ के अनुसार किसी शबाहकी तलबना हुक्म दिया हो और वह हुक्मके विषय कोई दरखास्त दिवालियेका काम करने वाले जजके सामने दी जावे तो दरखास्त की उपरदफा (२) के क्लार्क (ए) के अनुसारकी हुई अपील समझना चाहिये, देखो—A. I. R 1928 Cal 786 इसी मामलेमें यह भी तय किया गया था कि यदि किसी जजने ऐसी दरखास्तकी नजरसानी (Review) समझ कर सुना हो और सुन कर एपिल

कर दिया हो तो जन महोदयके हुक्मसे उपदफा (१) के अनुसार दिया हुआ हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसका एक प्रमाणसे उपदफा (२) क्राज (बी) के अनुसार दिया हुआ हुक्म माना जासकता है । और उस हुक्मकी अपील विधीशन बीच में की जासकती है ।

उपदफा (२) के क्राज (ए) में यह बतलाया गया है कि दफा ६ के अनुसार नियुक्त किया हुआ कोई अग्रजत या अफसर हुक्म देने तो उस हुक्मकी अपील दिवालयके मामलोंका सुनने वाले जजके सामगरी जा सकती है परन्तु उस हुक्मका अपीलमें जब जो फेसला देगा उसे एक प्रमाणसे अंतिम फैसला समझना चाहिये उसकी दुबारा अपील नहीं की जा सकती है गो माथही साथ यह भी बतला दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपीलमें गिये हुए जजके फैसलेसे असन्तुष्ट होव और उसका दुबारा अपील किया चाहे तो उसे अपील करनेमें पाईले उस जजकी आज्ञा ले लना चाहिये जिसन अपील अन्वलयसे सुना या तब दुबारा अपील दाखर की जा सकती है । क्राज (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि हाईकोर्ट का कोई जज अपने इस्त्रालियके अधिकारों का प्रयोग करते हुए पाइ फैसला करे तो उसकी अपील उसी प्रकारकी जा सकेगी जिस प्रकार जायदादी दीवानीके जजगार उन फैसलोंकी अपीलकी जासकती है जो उसन अपने दीवानीके मामूली मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए गिये हों । क्राज (ए) व (बी) में जो अगर ह उसे अले प्रकार समझ लेना चाहिये अर्थात् क्राज (ए) के अनुसार जजोंमें गिये हुए फजकी दुबारा अपील नहीं हो सकती है परन्तु क्राज (बी) के अनुसार किये हुए फैसलोंकी अपील हो सकती है दोनों हालतोंमें फैसला करने वाला जज वही है परन्तु पहिली हालतमें जजन फैसला अग्रजलन अपीलकी भावे दिया है व दूसरी हालतमें अभी जज का फजका अपील का फैसला नहीं है किन्तु वह फैसला उसका स्वय फसला है मित इन्नाइने फैसला कह सकते हैं ।

दूसरा प्रकरण



दिवालयिके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाहयां

दिवालयिके काम

दफा ९ दिवालयिके काम

कजईशर नीचे दिये हुए कामोंमेंसे किसी कामको करे तो माना जायेगा कि उसने दिवालयिके का काम किया है—

- (ए) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी कुल जायदादको या क्रीय २ स्वय जायदादको अपने कजईखाहोंके लाभार्थ किसी तीसरे व्यक्तिके हकमें कर देवे ।
- (बी) यदि वह ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा अपने कजईखाहोंके हक मारने या उनके कजोंकी अदायगीमें देर करने की मंशासे अलहदा कर देवे ।
- (सी) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी जायदाद या उसके किसी

भागके सम्बन्धमें कोई ऐसा इन्तकाल करे जो इस एक्टके अनुसार अथवा किसी अन्य प्रचलित एक्टके अनुसार घोषा देहलसे तर्जिह देने का सौदा समझ कर उसके दिवालिया करार दिये जाने पर रह समझा जा सके ।

(४) यदि वह अपने कर्जकर्त्ताओं का कर्ज मारने या उसमें देर करनेकी नियतसे

(i) ब्रिटिश इण्डिया (British India) के बाहर चला जावे या वहां बना रहे

(ii) अपने रहनेके स्थान या अपने अधिकतर व्यापार करनेके स्थानसे चला जावे या किसी जगहसे वहां न रहे

(iii) छिप जावे जिसमें कि उसके कर्जकर्त्ताहानको उसकी खबर न मिल सके

(ई) यदि उसकी जायदाद रुपयेकी अदायगीके लियेकी हुई डिक्लीके आधार पर कुर्की की गई हो और कुर्की का हुक्म कमसे कम २१ दिनसे बना हुआ हो ।

(एफ) यदि वह दिवालिया करार दिये जानेंके लिये दरखास्त देवे ।

(जी) यदि वह अपने किसी कर्जकर्त्ताको इस प्रकारका नोटिस देवे कि उसने अपने कारोबारको बंद कर दिया है अथवा वह उसे बंद करने वाला है ।

(एच) यदि वह रुपयेके अदायगीके सम्बन्धमेंकी हुई किसी डिक्लीके आधार पर कैद होवे

व्याख्या (Explanation) इस दफाके लिये एजेंटका काम उसके मालिकका काम समझा जावेगा चाहे उस एजेंटको अपने मालिक (Principal) की ओरसे उस कामकी करनेके लिये कोई अधिकार प्राप्त न होवे ।

व्याख्या—

इस दफामें दिव लियेके कामों का उल्लेख किया गया है अर्थात् वह काम बताने के लिये हैं जिनके होने या न होने पर मान लिया जावेगा कि कर्जदारने दिवालीके का काम किया है । इस दफामें या इससे पहिले कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि कर्जदार किस व्यक्ति की सम्पत्ति चाहिये । दफा ४ के प्राक् (बी) में केवल इतना बतलाया गया है कि मर्चेंट (Merchant debtor) को भी कर्जदार समझा चाहिये अर्थात् उस दफामें ही ईहे कर्जदारकी परिभाषा पूर्ण परिभाषा हीन नही सम्पत्ति का सही है । तथा उधार देने वाले व कया उधार लेने वालेसे जो सम्बन्ध होता है वह कर्जकर्त्ता है व कर्जदार का सम्बन्ध हुआ करता है । कर्जदार मुद्र का अं नो बहुत लोभ समझा करते हैं वही समझना चाहिये । हाई-कोर्टने अपने फैसलामें कहा तभी इस शब्दके अर्थमें कभी २ कुछ प्रस्ता बाज है अर्थात् उनमें यह निश्चित किया गया है कि व्यापारी व्यक्ति विशेष कर्जदार है अथवा नहीं है ।

जैसे कि मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिमें किसी तीसरे व्यक्ति में अदा करनेके लिये कोई वस्तु लेवे तो तथा इस प्रकार लेने वाले व्यक्तिको कर्जदार नहीं समझना चाहिये देखो—36 Mad 494. इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि कोई कर्ज कर्त किसी मूलरक्त खानदारके कारोबारके लिये किसी व्यक्ति की संपत्तिमें लिया गया हो तो वह संपत्ति ऐसे कर्जके लिये दिवालिया करार नहीं दिया जा सक्ता है देखो—41 Mad 824.

गैर मुद्र का रहने वाला (Foreigner) भी दिवालिया करार दिया जा सकता है यदि उस एकदमसे रहलार्ह हुई हो परी दाती होवे । मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया था कि यदि कोई गैर मुद्र का रहने वाला जो ब्रिटिश इण्डियामें बाहर रहता

हो ब्रिटिश इण्डियामें कारोबार करता हो और वह कारोबार किसी एजेंटके जायिे बम्बईमें किया जाता हो तो बम्बईमें उसके तबदल कारोबार हो सकता है । चीफ जास्टिस मि० सारिजेट मर्यादने इस सम्बन्धमें अपनी यह राय प्रकट की थी कि बार मुल्क का माशुदा अगर स्वयं कारोबार ब्रिटिश इण्डियामें न करता हा तो वह आती तोरसे यहांके कानूनाकी पाबन्दाके लिये बाध्य नहीं है लेकिन अगर वह अपना कारोबार यहां करे और उस कारोबारसे लाभ उठाना चाहता है वह मान लिये जावेगा कि वह अपने उस कारोबारके सम्बन्धमें यहांके कानूनाकी माननेके लिये तैयार है और इसी कारण यहां की अदालतें उसके विरुद्ध हारनाई करनेकी अधिकारिणी है । देखो—17 Bom 662

कर्तदार इस दफाके अनुसार कोई व्यक्ति भी हो सकता है तथा कोई फर्म भी हो सकता है जो लोग सही मुआहिदा कर सकते हैं वह लोग इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जा सकते हैं यदि इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंकी पूर्ति होती है । जैसे कि दिवाहिदा रमी कर्जदार हो सकती है नवालिष बन्ने दिवालिषा करार नहीं दिये जा सकते हैं देखो—43 Cal. 1157 इसी प्रकार पागल भी दिवालिषा करार नहीं दिये जाने चाहिये ।

क्लाज (ए) में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्जदार अपनी सब जायदाद या करीब २ सय जायदादकी मुन्त किल कर दे यदि वह अपनी जायदाद का कोई कुछ हिस्सा ही इस क़ाबमें बतलाव हुई शर्तके साथ अलहाद कर दे तो इस क़ाबकी पूर्ति नहीं समझना चाहिये इस क़ाबके अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्तिने इन मशयसे देना चाहिये जिसमें कि वह उसके सब कर्जस्वादानका दंड जा सक । जैसे कि अपनी सब जायदाद के लिये दूरियोंका मुक़रर कर देना जिसमें कि वह दूसरा उसकी जायदादकी उसके कर्जस्वादानमें बाध सके । इस क़ाबके लिये यह आवश्यक नहीं है कि जायदाद केवल ब्रिटिशभारत (British India) ही में इस प्रकार अलहादकी गई हो उसकी बलवर्गी ब्रिटिशभारतके अनिश्चित अम जगहोंमें भी हो का सकती है । इस प्रकार इस क़ाबसे यह तात्पर्य निकलता है कि दिवालिषा का काम ब्रिटिश भारतके बाहर भी हो सकता है । जायदादका इन्तकाल इस क़ाबके अनुसार बाकायदा किया जाना चाहिए सिर्फ़ जबानी कह देनेसे या अधूरी तहरीसे काम नहीं चल सकता है ।

क्लाज (बी) के अनुसार यदि कोई कर्जदार अपनी सब जायदाद वा उसके किसी भागको इस जीवतस हटा देने कि जिसमें उसके कर्जस्वादाकी वसूलमें देर हैवे अपना उनकर कर्ज माग आवे तो कर्जदारके इस कामको भी दिवालिषा का काम माना जावेगा । इस क़ाबके अनुसार भी जायदादका हटाया जाना ब्रिटिश भारतमें अपना उसके बाहर किया जा सकता है अर्थात् इस प्रकारका इन्तकाल जायदाद ब्रिटिश भारत ही में किये जानेकी आवश्यकता नहीं है । इस क़ाबके भी बहू तात्पर्य निकलता है कि दिवालिषा का काम ब्रिटिश भारतके बाहर भी किया जा सकता है इस क़ाबमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जायदाद कुछ या उसका कोई हिस्सा हटाया जा सकता है वो क़ाब (ए) में ऐसा नहीं था उसके अनुसार सब जायदाद या करीब २ सय जायदाद अलहादकी जाना चाहिये इस क़ाबके अनुसार जो इन्तकाल किया जाने वह कर्ज मान या उसकी अदायगामें देर करनेकी मशयसे किया जाना चाहिये पल्लु क़ाब (ए) के अनुसार जो इन्तकाल किया जावेगा वह कर्जस्वादानके लाभमें किया जावेगा ।

क्लाज (सी) के अनुसार भी इन्तकाल जायदाद चाहे ब्रिटिशभारत में किया जावे चाहे उसके बाहर । इस क़ाबके अनुसार वह इन्तकाल जायदाद ऐसा होना चाहिये जो घोरतदेहीसे तनोद देने वाला इन्तकाल समझा जावे अर्थात् यदि इन्तकाल जायदाद करने वाला कर्जदार दिवालिषा करार दे दिया जावे और उसके बाद वह इन्तकाल जायदाद किसी एक कर्जस्वादानके दूसरे कर्जस्वादानके मुक़ाबिले तर्नीह (Preference) देवे

ज्ञाना इन्तजाल करार देकर रह गया जाके तो ऐसे इन्तकाल जागदाके किये जाने पर दिवालिया का समझना चाहिये । इस क्राजके अनुसार भी यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुंज जायदाद अन्तः कर देने वह अपनी कुल जायदाद या उसका कोई हिस्सा अन्तः कर देने पर इस क्राजके अन्त आचरण । यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस कलाजके अनुसार दिया हुआ इन्तकाल तर्जिह देने ज्ञाना होना चाहिये अर्थात् किसी कर्जदारके इन्तकाल यानी बंध दूसरे कर्जदारोंके मुकदमे लाने पर पूर्वनिश्चय मशालसे किया जाना चाहिये ।

फलाज (डी) यह तीन उपकलाओंमें विभक्त है पहिले उपकलाज (१) के अनुसार यदि कर्जदार मिटिशमातसे बाहर बना जावे अथवा यदि वह पहिलेसे बाहर गया हुआ हो और बाहरही बना रहे तो उसका यह काम दिवालिया काम समझा जावेगा । परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार बाहर जाना या बाहर रहने कर्जदारोंका कर्ज मारने या उसकी अदायगीमें देर करनेकी मशालसे किया गया हो । दरम्याल दिवालियामें कर्जदारकी इस प्रकारकी मशाल साफ तौरसे दिखाना देना चाहिये परन्तु यदि दरम्याल दिवालियामें इस प्रकारकी मशाल न दिखलाई गई हो तो वरकलासती तर्जिहमें जो हलफनामा लुक्खल किया गया हो उसे दखल चाहिये और यदि हलफनामामें इस प्रकारकी मशाल बनवाई गई हो तो उसे पर्याप्त समझना चाहिये अर्थात् तब उस दरम्यालके आधार पर कर्जदार दिवालिया करार दिया जासकता है, देखो—37 Mad 505 अधिकतर इस प्रकारकी मशाल कर्जदारके नामों द्वारा ही साबित हो सकती है । यदि किसी कर्जदार एक शरीकदार कोई बाहर बना जावे तो केवल उसकी चले जानेके कारण कर्ज दिवालिया करार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि एकके चले जानेसे सब कर्जदारोंका चला जाना नहीं माना जासकता है अपने व्यापारीकी जगहसे कर्जदारोंका कर्ज मारनेकी शरतसे बाहर जाना दोनों शरीकदारोंका होना चाहिये तभी यह कलाज लागू होगा, देखो—24 Bom L R 861. इस कलाजके उपन्यास (11) के अनुसार यदि वह कर्जदारोंका कर्ज मारने या उसमें देर करनेकी मशालसे किसी प्रकार भी रीर हासिल रहे तो उसका यह काम दिवालिया काम समझा जावेगा इस उपकलाजमें, रहने वाले मकानसे बाहर रहना या व्यापार करनी जगहसे हट जाना इन दो बातोंका उल्लेख है लेकिन साथही साथ उसमें यह भी लिख दिया गया है कि अगर वह इन जगहोंसे हट जावे अथवा किसी प्रकार भी रीर हासिल रहे तो दिवालिया काम काम मान लिया जावेगा । इस उपकलाजमें रहने वाले मकानका जो जिक्र है उससे अभिप्राय पुरस्किन् (Permanent) रहने वाली जगह ही से नहीं है किन्तु वह जगहसे भी समझना चाहिये जहां कर्जदार रहने लगा हो क्योंकि इस कलाजमें पुरस्किन् कोई उल्लेख नहीं है । रोजगारकी जगहसे तात्पर्य उस जगहका समझना चाहिये जहां अधिकतर कर्जदार रोजगार करता हो क्योंकि अंग्रेजी एकटके इस कलाजमें (Usual) शब्दका प्रयोग किया गया है । इस शब्दसे यह भासित होता है कि यदि कर्जदारने किसी जगह कोई एक आव सोंदा खरीदा या बेचा हो तो उस जगहकी उसकी रोजगारकी जगह नहीं मान लेना चाहिये । अगर वह किसी खास जगह पर दूकान खोल कर अपना कारोबार करता हो । इस क्राजके उपकलाज (11) के अनुसार कर्जदारका छिपाना जिससे कि उसके कर्जदार उसकी खबर न पासके एक प्रकारसे दिवालिया काम है । यह छिपाना भी कर्ज मारने या उनके अदायगीमें देर करनेकी मशालसे किया जाना चाहिये और साथ ही साथ यह छिपाना ऐसा होना चाहिये कि उसके कर्जदार उसमें पर ओझार न कर सके यानी जिसमें उनकी उसकी खबर न मिल सके ।

फलाज (ई) के अनुसार कर्जदारकी किसी जायदादका इजाजत किसी इच्छामें बना जाना दिवालिया काम है । इसी प्रकार यदि कर्जदारकी कोई जायदाद इजाजत, डिममें दुर्क दुई हो और वह कुर्की २६ दिन या इससे

अधिक दिनोंसे कायम हो तो भा दिवालियेका काम समझा जावेगा । डिमी जिसका निकटम छाजमें दे वह रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें हाना चाहिये । फसलना साकारा ठिकाना दे और उमर अनुसार यादें कुर्मी हों हा तो वह दफा (१) के अनुसार नहीं जायकता है देखा—A I R 1928 Cal, 840.

यदि कर्जदार स्वयं दिवालिया करार दगाई दस्तखस्त देवे तो कर्जदारका यह काम बलाज (एक) के अनुसार समझा जावेगा ।

फलाज (जी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार अपने किसी कर्जकाराहको इस बातका नोटिस देवे कि उसने अपने कर्जकाराहको चुकाना बन्द कर दिया है या वह बन्द करने वाला है तो उसका यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा । इस बलाजमें यह कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि नोटिस लिखकर ही दिया जाना चाहिये या नोटिस किसी खास किरमका दिया जाना चाहिये । इस कारण नोटिसके लिखकर ही देनेकी आवश्यकता नहीं है और न यह आवश्यकता है कि वह किसी खास तपाके (Forum) ही जा देवे । इस बलाजमें बतलाया हुआ नोटिस सब कर्जकाराहोंको एक साथ देनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु नोटिस किसी एक कर्जकाराहको भी दिया जासकता है ।

फलाज (एच) के अनुसार यदि कान्येके अदायगीके सम्बन्धमें जा हुई डिमीके इनगाममें कर्जदार बन्द किया गया होतो इसको भा दिवालियेका काम समझना चाहिये । इस बलाजके अन्तमें जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसके अनुसार एजेण्ट द्वारा किया हुआ काम भी मालिक (Principal) द्वारा किया हुआ काम समझना चाहिये चाहे उसके उम काम कान्येका आकार बसोत रूपसे न दिया गया हो । यदि एजेण्ट बसोत एजेण्टके कोई काम अपने मालिक (Principal) के लिये करे तो एजेण्टका वह काम मालिकका काम मानकर वह दफा ९ के अनुसार दिवालियेका काम समझा जावेगा और मालिक ऐसे दिवालियेके कामके आधार पर दिवालिया करार दिया जायकता है ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

दफा १० दिवालिया करार देनेके अधिकार

इस एन्टमें दी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए यदि कर्जदार किसी दिवालियेके कामको करे तो दिवालियेकी दरखास्त उसका कोई कर्जकाराह या वह स्वयं देसकता है और अदालतको अधिकार है कि वह ऐसी दरखास्त (Petition) पर उस कर्जदारके दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे देवे । यह हुकम दिवालिया करार दिये जानेका हुकम (Order of Adjudication) कहलायेगा ।

व्याख्या—

कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरखास्तका दिया जाना दिवालेका काम समझा जावेगा और अदालत उम दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे सकती है । दफा ९ में बतलाये हुये दिवालियेके काम करने या होने पर तथा इस एन्टमें बतलाई हुई आर शर्तोंकी पूर्ति होने पर कर्जदार स्वयं या उसके विरुद्ध उसका कोई कर्जकाराह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त अदालत दिवालियेमें दे सकता है और ऐसी दरखास्त शुजुने पर अदालतको अधिकार है कि वह

कर्जदारको दिवालिया करार दे देवे । इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेका जो हुक्म दिया जावगा उसे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म (Adjudication order) कहेंगे । इस दफ्तर यह भली भांति प्रकट है कि अदालत दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है । अर्थात् एक्टकी इस दफ्तरमें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है । इस दफ्तरमें यह बात भी साफ तौरसे बतला दी गई है कि दरखास्त दिवालिया कर्जदार स्वयं या उसका कोई कर्जस्वाह दे सकता है नर्तने कि उस एक्टमें बतलाई हुई राब शर्त पूरी होती होवे । दरखास्त दिवालिया उसी समय कर्जदार मजदुरी हावेगी जब कि दफ्तर ९ में बतलाया हुआ कोई दिवालेखा काम हुआ हो । पण्डित इस दफ्तरके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसके अनुसार कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरखास्तका दिया जाना है दिवालेखा काम है इसलिये कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह दफ्तर ९ में बतलाए हुए किसी दिवालियेके कामके आधार ही पर दी जाव । कर्जस्वाह द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दफ्तर ९ में बतलाये हुए दिवालियेके कामोंमें से कोई काम अवश्य दिखलाया जावे और ऐसे कामके होने पर ही कर्जदार अपने कर्जस्वाहको दिवालिया करार दिवानेका अधिकारी होगा अन्यथा नहीं । व्याख्यासे यह भली भांति प्रकट है कि कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्त पर भी अदालत उसको दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है क्योंकि ऐंजली एक्टकी इस दफ्तरमें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात् उस दरखास्त पर भी अदालत अपनी इच्छानुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दे भी सकती है और देनेसे इनकार भी कर सकती है । यदि कोई कर्जदार अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर दिवालियेका काम करे तो अदालतको अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध जायदाद वसूल करनेका हुक्म दे सकती है और इस बातमें कोई भी शक नहीं रहेगी कि वह कर्जदार इंग्लैण्ड (England) में दिवालिया करार दिया जाइगा है अर्थात् इंग्लैण्डमें दिवालिया करार दे दिये जानेका कोई अंतर यहाँ की दिवालिया सम्बन्धी कानूनोंमें स्थावत नहीं बालेगा देखो—331 Cal. 761.

दफ्तर ११ अधिकारोंमें रुकावट

अदालतको दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देनेका अधिकार उस समय तक न होगा जब तक कि—

- (ए) दिवालियर करार दिये जानेकी दरखास्त दाखिल करते समय कर्जदार अपने सम्बन्धमें की हुई डिक्रीके इजरायके अनुसार किसी ऐसे कारावासमें न होवे जहाँ कर्जदार दिवालीके मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए अधिकतर रहने जाते हैं । या
- (बी) दिवालियेकी दरखास्त देनेसे पहिले कर्जदार एक साल तक अदालतकी मामूली दीधानीके अधिकारोंके अनुसार बतलाई हुई अधिकार सीमामें न रहा हो या उसके रहनेका मकान न होवे अथवा उसने स्वयं या किसी एजन्टके ज़रिये उस सीमाके अन्दर रोजगार न किया हो । या
- (सी) कर्जदार स्वयं अपने लामार्थ कोई काम अदालतकी सीमाके अन्दर न करता हो । या
- (डी) यदि किसी फर्मने दिवालियेकी दरखास्त दी होवे अथवा किसी फर्मके विरुद्ध दरखास्त दी गई हो तो जब तक कि उस फर्मका कारोबार दिवालियेकी दरखास्त दाखिल करनेसे पहिले एक सालसे अदालतकी ऊपर बतलाई हुई अधिकार सीमाके अन्दर न रहा हो ।

व्याख्या—

यदि किसी बिक्रीमें यह हुक्म होवे कि कपड़ेकी अदायगी न की जाने पर रहनेकी हुई जायदाद मौलायकी अवधिगी तो ऐसी बिक्रीका कपड़ेकी अदायगीके सम्बन्धमें ही हुई किसी समझना चाहिये 28 Mad 473 इस दफ्तमें यह बातलया गया है कि किन्तु २ दफाओंमें अदायगीसे दिवालिया करार देनेका अधिकार न हुआ। ज्ञान (ए) के अनुसार दिवालियेकी दख्खास्त दिये जाने समय कर्जदारका जेल दानानामें दाना एक आवश्यक बात है। कलाज (बी) के अनुसार दिवालियेकी दख्खास्त दिये जानेसे पाहल एक सालके अंदर तक कर्जदारका अदालतमें अधिहार सीमाके अंदर रहना आवश्यक है अथवा चाहे (कर्जदारने) इस अवधि तक उस सीमामें स्वयं या किसी एजेंटके आये करोंका बरिफ हो अथवा उसका रहनेका मकान उस सीमाके अंदर होवे। कलाज (सी) के अनुसार कर्जदारका अपने लाभके लिये अदालतमें अधिहार सीमा के अंदर काम करना आवश्यक बातलया गया है ज्ञान (डी) के अनुसार यदि किसी कर्मके विरुद्ध या उसमें औरसे दिवालिया करार दिये जानेकी दख्खास्त दी जावे तो उस कर्मका कामका अदालतकी अधिहार सीमाके अंदर दख्खास्त देनेसे पहिले कमसे कम एक सालतक दाना आवश्यक है।

फलाज (ए), (बी), (सी), च (डी) में बतलाई हुई शर्तोंका एक साथ होना आवश्यक नहीं है इन शर्तोंके बीच में ' या ' लिखा हुआ है। मतमें यह भली भांति प्रकट है कि उन शर्तोंमेंसे किसी एकका होना आवश्यक है अर्थात् अदायत किसी कर्जदारमें उस समय तक दिवालिया घोषित नहीं करगी जब तक ज्ञान (ए) (बी), (सी) या (डी) में बतलाई हुई कोई न कोई बात उपरिगत न जावे। इस दफ्तकी पाचवीं अदालतके लिये आवश्यक है अर्थात् अदालत उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है अथवा एक्टकी इस दफ्तमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया जिससे ऊपर लिखी हुई बातों का पूर्ण प्रकार पुटि होती है।

फलाज (बी) के अनुसार दख्खास्त दिवालियाके दिये जाने पर एक सालके अंदर कर्जदारका अदालतके अधिकार सीमामें रहना या रहनेका मकान रखना अथवा व्यापार करना आवश्यक बातलया गया है व्यापार करनेके सम्बन्धमें यह भी बातलया गया है कि कर्जदार स्वयं व्यापार करता हो या किसी एजेंटके लिये करता हो परन्तु एजेंटसे तारतम्य उस एजेंटका समझना चाहिये या वाक्यानुसृतताविषय तर्कमें उसका एजेंट होवे अर्थात् जो व्यापार एजेंट द्वारा किया जाया है उसकी देव रेत स्वयं वह एक प्रमाण करता जावे एजेंटने तारतम्य ऐसे आम एजेंटसे न समझना चाहिये कि जो अपने नामसे बहुतोंके लिये कारोबार करता हो और उन लोगोंसे बर्फीलाने लगा होवे देखो—23 Mad. 458, A. I R 1929 Sind 24 अधिहार सीमाके अंदर रहना या ठममें रहना मकान हालमें तारतम्य यह है कि तकनीयतामें उसका सम्मान अधिकार सीमामें हाव यह नहीं कि रहने वाला कहीं का जावे और मित्र दख्खास्त देनेकी नीयतसे अधिकार सागका अंदर चन्द दिनोंके वास्तुपञ्चा आब पग्लु यदि बाहरका कोई आदमी कागजारक मिलासनेमें अदालतकी अधिहार सीमाके अंदर आ गया हो और वहीं वह रहने भी लगे अथवा उस समय कहीं बाहर उसके रहनेका स्थिति न होवे तो ऐसे व्यक्तिकी वहीश रहने वाला समझना चाहिये तथा ऐसे व्यक्तिके लिये सज्जती मकानका रहना भा कदा जा सज्जता है कलकत्ता हाईकोर्टने 21 Cal. 63 में यह तय किया गया था कि कर्जदार इन्ड्रलेण्डसे कलकत्ता आया था और वहां वह चन्द माह तक एक होम्में ठहरा रहा और रोजगारकी तन्त्रायमें रहा और उसके पश्चात् उसकी कानून दिवालियामें लाभ उठानेकी आवश्यकता पड़ा तो वह तय हुआ कि वह नेकनीयतीसे वहां आना था जिस समय कि दिवालियेकी दख्खास्त दी गई थी और उसीके साथ २ इस बातका ध्यान रखना गया था कि उसकी सज्जती जिसका दूसरी जगह नहीं थी।

एक पुरोहित दूसरी अपीलमें ११ अगस्त तक पिय २ शि यॉरे पास बन्धनमें रहा तो उसके लिये यह तय हुआ था कि उसका बन्धनमें रहना नहीं समझा जायेगा 111 Bom. 290. घूमेने मात्रके लिये जाना बहुत। रहनेके बन्धन नहीं हो सकता है। रहनेके तौर पर उस जगहसे माफूम होता है जहां वह खाना पीता या सोता होवे या जहां उसने खानदानी या नौकर खान पाये या सोते होवे 38 Cal. 394. यदि किसी आबन्धक हिन्दू परिवारका कर्तो किसी अगढ़ मरीवार करता हो तो यह नहीं मान लिया जायेगा कि उस परिवारका दूसरा मेम्बर भी वहां कामकाज करता है देखो—23 Mad. 458.

क्लाज़ (डी) में उन मामलोंके बारेमें बतलाया गया है जब कि किसी कर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जाने की दारखास्त दी जाय अथवा किसी कर्मके अपने दिवालिया करार दिये जाने की दारखास्त दी हो तो कर्मके दिवालिया करार दिये जाने के सम्बन्धमें यह बतलाया गया है कि कर्मका नाम दिवालियागी दारखास्त दिये जानेसे पहिले एक सालके अन्दर अदालतकी अतिरिक्त सोमाक्रैन्टर होना आवश्यक है अन्यथा अदालत, कर्म को दिवालिया करार नहीं देगी। इस दफ्तेके चारों क़ाज़ बिनाभिन्न है एक दूसरेके आधार पर नहीं है और उनमेंसे किसी भी क़ाज़में बतलाई हुई बातके होने पर अदालतकी अधिकार सामा प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं अदालत इस दफ्तेमें बतलाये हुए नियमको माननेके लिये बाध्य है इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है।

दफा १२ यह शर्तें जिनके अनुसार कर्ज़स्वाह दिवालिया करार दिलानेकी दारखास्त दे सकता है

(१) किसी कर्ज़स्वाहको अपने कर्ज़दारके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेकी दारखास्त देनेका अधिकार उस समय तक न होगा:—

(ए) जब तक कि कर्ज़दारसे लिया जाने वाला कर्ज़स्वाहका कर्ज़ पांच सौ रुपये ५००) न होवे परन्तु उस समय जब कि दारखास्त देने वाले एकसे अधिक कर्ज़स्वाह होवे तो उन सब कर्ज़स्वाहोंके कर्ज़का जोड़ पांच सौ रुपये होना चाहिये।

(बी) जब कि अदा किया जाने वाला कर्ज़ एक निश्चित धन राशिके रूपमें न होवे जो उसी समय अथवा भविष्यमें किसी निश्चित समय पर चुकाया जाने वाला होवे।

(सी) जब तक कि यह दिवालियेका काम जिसके आधार पर दिवालियेकी दारखास्त दी गई हो दारखास्त देने समयसे तीन माहके अन्दर न हुआ हो।

(२) यदि दिवालियेकी दारखास्त देने वाला सहफूज़ कर्ज़स्वाह (Secured Creditor) होवे तो वह अपनी दारखास्तमें यह बतलायेगा कि वह अपनी ज़मानतकी कर्ज़दारके सब कर्ज़-क्यादानके लामार्थ छोड़ देवेगा यदि कर्ज़दार दिवालिया करार दे दिया जावेगा अथवा उसे उस ज़मानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत भी बतला देना चाहिये। जब कि वह अन्दाज़ा लगाई हुई ज़मानतकी कीमत बतलावेगा तो उसकी दारखास्त उस रुपयेके लिये मानी जावेगी जो उसके असली कर्ज़में से ज़मानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत घटानेसे बचे और इस प्रकार निकले हुए रुपयोंके लिये वह बिला सहफूज़ (The Secured Creditor) मान लिया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफ्तेमें इन बातोंका विवरण है निम्नके आधार पर कर्ज़स्वाह अपने कर्ज़दारके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेकी दारखास्त दे सकता है। यह दफा दो भागोंमें विभक्त है पहिले भागमें आम कर्ज़स्वाहोंका उल्लेख है तथा दूसरे भागमें

महजूस कर्जस्वाहका वर्धन है । पहिले माममें तीन शर्तें बतलाई गई हैं जिनके उपरिधन होने पर ही कर्जस्वाह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त देनेका अधिकारी हो सकता है । जैसेकी एकटा इस दफ्तमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दरजेके लियेकी गानना आवश्यक है और उनकी अवइलना नहीं की जासकता है इस भागक ज्ञात (ए) में यह बतलाया गया है कि अगर कोई एक कर्जस्वाह अपने कर्जदारक विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त देवे ता उस कर्जस्वाहका बका (५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये और यदि एक्स अधिक कर्जस्वाह मिउतर कामा कर्जदारक विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त देवे तो उन सब कर्जस्वाहोंके कर्जेका जाऊ (५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये ।

कलाज (धी) के अनुसार जिस कर्जेके आधार पर दरखास्त दी गई हो वह एक निश्चित धन राशिके रूपमें होना चाहिये और चाहे वह धन पशि उसी समय अदारी जानेकी होवे अथवा उसकी अदायगी मन्थियमें किसी निश्चित समय पर की जानेका होवे ।

कलाज (सी) के अनुसार जिस दिवालयिके कामके आधार पर दरखास्त दी गई हो वह दरखास्त दिये जानेकी तारीखके ताल माहके अन्दर होना चाहिये अथात् दरखास्त देनेमें पाहिले तीन माहक अंदर कर्जदारने दफा १ में बतलाई हुए कामोंमें से निर्मा कामको किया हो । तीन माहके अन्दर ही दिवालयिके काम किया गया हागा तबक अदारी पर दिवालयिके दरखास्त नहीं चल सकनी है । हा यह अवश्य हो सकता है कि कोई काम ताल महीनेसे पहिले प्रारम्भ हुआ हो और वह ताल माहक अंदर तक जारी रह जसे कि यदि कर्जदार पहिले बाहर गया हो न वहाँ बना रह ।

उपदफा (२) में महजूस (Secured) कर्जस्वाहोंके बाबते मसला साक किया गया है उसके अनुसार महजूस कर्जस्वाहोंके लिये दो शर्तें हैं एक ता यह वह महजूस कर्जस्वाह अपनी खमान सब कर्जस्वाहानके लाभाप छूट देने अपोंद वह अपनी दरखास्तमें यह बतला देवे कि यदि कर्जदार दिवालयिका करार दे दिया जावे ता उसका कर्ज भी और निम्न महजूस कर्जस्वाहोंकी भुजि समझा जावेगा तथा वह अपनी खमानस सब कर्जस्वाहानके लाभाप छूट देगा । दूसरा शर्त ता यह है कि वह खमानसकी हुई नायदासकी खमानस अदालत दे सकता है परन्तु जब वह ऐसा करेगा तब दिवालयिके दरखास्त देनेके लिये उसका उतना ही कर्ज समझा जावेगा ज् उसके अपनी कर्जों से खमानसकी अदालत लगाई हुई कामन पशनेक बाद बचता । दरखास्त देने बाद कर्जस्वाहका यह कर्तव्य होता कि वह इस उपदफाम बतलाई हुई दो बातोंमें से किसी एक बातकी अवज्ञा अपना दरखास्तमें बतला देने बला उसकी दास्तास्तके पूर्ति नहीं होगा । इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि उसका कर्ज दोनो ही दफाओंमें (५००) रुपये अथवा उससे अधिक होना चाहिये ।

दफा १३ कर्जस्वाहकी दरखास्त पर कार्यवाई तथा उस पर हुकम

(१) कर्जस्वाहकी दरखास्तके साथ उसकी पुष्टिके लिये हलफनामा दाखिल किया जावेगा और वह हलफनामा चाहे कर्जस्वाह स्वयं दाखिल करे अथवा उसकी ओरस काइ अन्य व्यक्ति दाखिल करे जिसे हालात मालूम हों ।

(२) दरखास्त सुनते समय अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुधून लेगी—

(ए) दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहका कर्ज, और

(बी) दिवालयिके काम या यदि दरखास्तमें एकसे अधिक दिवालयिके काम बतलाये गये हों तो उनमेंसे कोई एक दिवालयिके काम

(३) अदालत दिवालियेकी दरखास्त सुननेकी तारीख बढ़ा सकती है और यह हुक्म दे सकती है कि उसकी इच्छा कर्जदारको दी जावे ।

(४) अदालत नीचे दी हुई बातों पर दरखास्तको स्वीकृत कर देगी ।

(ए) यदि वह उपदफा (२) में बतलाये हुये सुवृत्तसे सन्तुष्ट न होवे, यां

(बी) यदि कर्जदार हाज़िर होकर अदालतको विश्वास दिला दे कि वह अपने कर्जों को अदा कर सकता है या उसने कोई दिवालियेका काम नहीं किया है या किसी अन्य पर्याप्त कारणसे कोई हुक्म उसके विरुद्ध नहीं दिया जाना चाहिये ।

(५) यदि ऊपर बतलाये हुए सुवृत्तसे अदालत सन्तुष्ट हो जावे तो वह दिवालिया क्रार दिये जाने का हुक्म दे सकती है और उस समय भी वह हुक्म दे सकती है जबकि उपदफा (३) के अनुसार तारीख बढ़ाई गई हो और उस तारीख पर काफी तामील हो जाने पर भी कर्जदार हाज़िर न होवे परन्तु वह ऐसा हुक्म उस समय नहीं देगी जबकि उसकी रायमें दिवालियेकी दरखास्त किसी दूसरी अदालतमें दाखिलकी जाना चाहिये ।

(६) जब कि कर्जदार दरखास्त पर हाज़िर होवे और दरखास्त देने वाले कर्जद्वाराहके कर्जोंको मंजूर न करे अथवा यह मंजूर न करे कि उस कर्जद्वाराहका कर्जा उतना है जिसके आधार पर वह दिवालियेकी दरखास्त दे सकता है तो अदालतको अधिकार है कि वह कर्जदारसे कर्जद्वाराहके बरामद होने वाले कर्जोंके निस्वत तथा कर्जा साबित करनेमें होने वाले खर्चके निस्वत जमानत (यदि वह कोई ऐसी जमानत लिया चाहें तो) लेकर उतने समयके लिये कार्रवाईको रोक देवे जितने समयमें कर्जोंके सम्यग्बका प्रश्न तय किया जासके ।

(७) अब कि कार्रवाई रोक दी गई हो उस समय अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्जद्वाराहकी दरखास्त पर दिवालिया क्रार दिये जानेका हुक्म दे सकती है लेकिन वह ऐसा उसी समय करेगी जब कि कार्रवाई रुक आनेकी बराबरी देर हो रही हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण उपरिष्ठ होवे । और अब वह ऐसा करेगी तो उस दरखास्तको जिसके द्वारा कार्रवाई शुरू हुई थी जिन शर्तोंके साथ चाहेंगी स्वीकृत कर देगी ।

(८) कर्जद्वाराहकी दरखास्त दाखिल हो जानेके बाद विला अदालतकी आज्ञाके त्रापित नहीं ली जासकेगी ।

टिप्पणियाँ—

इस दफ्तेमें अब सब वर्गवायोंन विचार दिए हुआ है जो किसी कर्जद्वाराह द्वारा भी हुई दरखास्तके त्रापितमें आवश्यक है । यह दफा C वायोंमें विभक्त है और उनमें दरखास्त दिये जानेके समयांत के अदालतमें अन्तिम अधिक हुक्म होने तक हाउ एव दूनोंके पक्षवात् दिया हुआ है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्जद्वाराह द्वारा मंजूर जाने वाली दरखास्तके त्रापितमें उमरी पुष्टि के लिये एकनामाय दाखिल किया जाना आवश्यक है क्योंकि अथवा एवमही एक उपदफाम (Shall) उद्धृत योग्य दिया गया है इल्लुस्ट्रेशन तबधम यह दिया हुआ है कि दरखास्त देने वाला कर्जद्वाराह या तो स्वयं उसे दाखिल कर सकता है

अथवा उसकी ओर से कोई ऐसा व्यक्ति उसे दाखिल कर सकता है जिसे हज़ारत पाउंड हो अर्थात् कर्जस्वाह स्वयं ही हज़ारनामा दाखिल करनेके लिय बाध्य नहीं है परन्तु हज़ारनामा दाखलानेकी ताददेमें दाखिल अवश्य किया जाना चाहिये ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि दरखास्त सुनते समय जिन जिन बातोंका सुन आवश्यक है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदालत दरखास्त सुननेके समय इस उपदफाके क्लॉज (ए) व (बी) में बतलाई हुई बातोंका सुन अवश्य लेवेगी अर्थात् दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके कर्जे व दरखास्तमें दिखलाई हुई दिवालियेकी कार्रवाई होनेका सुन अवश्य लिया जाना चाहिये । क्लॉज (ए) में दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके कर्जेका उल्लेख है तथा क्लॉज (बी) में दिवालियेके क्लॉज उल्लेख है जिसके आधार पर दिवालियेकी दरखास्त दी गई हो क्लॉज (बी) में यह भी लिख दिया गया है कि यदि दिवालियेकी दरखास्तमें एकसे अधिक दिवालियेके कामोंका किया जाना या होना बतलाया गया हो तो सुनत उन कार्यों से किसी एक ही दिवालियेके कामके सम्बन्धमें दिया जा सकता है अर्थात् यदि इनमेंमें एक ही दिवालियेका काम साबित कर दिया जावे तो इस उपदफाके लिये पर्याप्त समझा जावेगा । कर्जस्वाहके कर्जेमें तारीख यह माहूम होता है कि आया कर्जस्वाहका कर्ज दायमल है या नहीं और अगर है तो वह किनासा है जिससे कि यह माहूम हो सके कि वह इस एक्टके अनुसार दरखास्त दे सकता है या नहीं और दिवालियेके कामोंका वर्णन दफा १ में दिया हुआ है ।

उपदफा (३) के अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किया हुआ (May) शब्दसे प्रकट होता है । अदालत यदि चाहे तो सुननेकी तारीखको बढ़ा सकती है और यदि न चाहे तो उसे न बढ़ावे । यह तारीख इस कारण बढ़ाई जा सकती है जिसमें कि उसकी तापील कर्जदार पर हो सके ।

उपदफा (४) में उन बातों का वर्णन है जिसके कारण अदालत कर्जस्वाहकी दरखास्तको खारिज कर सकती है । यह उपदफा दो क्लॉजोंमें विभक्त है । क्लॉज (ए) में यह बतलाया गया है कि यदि अदालत उपदफा (२) में बतलाये हुए सुनसे समुचित न होवे तो वह दरखास्तको खारिज कर देगी ।

क्लॉज (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपस्थित होकर अदालतकी इस बातमें विश्वास दिला दे कि वह अपने कर्जोंकी अदा कर सकता है अथवा इस बात का विश्वास दिला दे कि उसके विरुद्ध दी हुई दरखास्त में जिस दिवालियेके काम का उल्लेख किया गया है वह उसने नहीं किया है अथवा अन्य किसी बातमें उस बात का विश्वास अदासतको कर देने कि उसके विरुद्ध कोई हुक्म न दिया जाना चाहिये तो अदालत ऐसी अवस्थामें कर्जस्वाह द्वारा दी हुई दरखास्तको खारिज कर देगी ।

उपदफा (५) के अनुसार यदि अदालतकी ऊपर बतलाये हुए सुन पर विश्वास हो जावे तो अदालत कर्जदार को दिवालिया कर दे सकती है इस उपदफामें प्रयोग किया हुआ 'May' शब्दसे प्रकट है कि अदालत इस उपदफाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी क्षमता पर निर्भर है । इस उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि यदि उपदफा (३) के अनुसार नवाई हुई तारीख पर भी कर्जदार हाजिर न होवे और उस पर नोटिसकी तापील होना साबित होवे तो अदालत उसे दिवालिया करार दे देवेगी परन्तु ऐसा करनेसे पहिले अदालत इस बातकी अवश्य देख लेगी कि आया वह दरखास्त किसी दूसरी अदालतमें तो न दी जाना चाहिये ।

उपदफा (६) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपस्थित होकर कर्जस्वाह का कर्ज मजूर न करे अथवा यह कह कि उस कर्जस्वाह का कर्ज उसे दिवालिया करार दिलानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो अदालत इस प्रश्नकी तय करनेके लिये कार्रवाई शायित कर सकती है बजाय इसके कि वह उस दरखास्तको खारिज कर देवे और शायित कर्जके समय यदि अदालत उचित समझे तो कर्जदारसे कर्जस्वाहके आयन्दा बरामद होने वाले कर्जके सम्बन्धमें तथा कर्ज साबित करनेमें जो

सर्व होगा उसके सम्बन्धमें उसके उचित सामान्य मांग सक्ती है । इस उपदफाके अनुसार हुकम देना अदालतका हुकम पर छोड़ दिया गया है ।

उपदफा (७) में इस बातसे साफ कर दिया है कि कर्जदार स्मृति होने पर अदालत जब चाहे कर्जदारको दिवालिवा करार दे सकती है अर्थात् वह देा होनेकी वजहसे अपना अन्य किसी पर्याप्त कारणों बिना दूसर कर्जदारकी दारुवास्तके आधार पर कर्जदारको दिवालिवा करार दे सकती है और उस समय वह उचित बातोंके साथ पाहिले दो हुई दिवालिवाकी दारुवास्तकी खारिज कर देगी ।

उपदफा (८) एक महत्व पूर्ण दफा है जसमें यह बनवाया गया है कि कर्जदारकी दारुवास्त बिला अदालत आह्वाके बाधिम नहीं ली जा सकती है अजसमें एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग लिये हुए 'Shall' शब्दमें यह भी भाति पकट है कि इस उपदफामें बतलाई हुई शर्तकी आवश्यकता जाना चाहिये दारुवास्त का बाधिम किया जाना उसी समय तक हो सकता है जब तक कि उसके आधार पर कर्जदार दिवालिवा न करार दे दिया गया हो क्योंकि दिवालिवा करार लिये जानेका हुकम होने ही कर्जदार दिवालिवा बन जाता है और जब तक कि दिवालिवा करार दिये जातेका हुकम मसूमा न किया जावे अथवा दिवालिवा बहाल न हो आवे तब तक वह दिवालिवा ही बना रहेगा । मगर हाईकोर्टने यह तय किया था कि दारुवास्त इजाजत लेने पर भी बाधिम नहीं ली जा सकती है और यह उपदफा खर्ची दारुवास्तके लिये लाए समझने चाहिये जिन पर फैसला नहीं हुआ है सुझावतानान मुहम्मद देखो—88 Bom. 200.

दफा १४ वह शर्तें जिनके अनुसार कर्जदार दारुवास्त दे सकता है

कोई कर्जदार उस समय तक दिवालिवाकी दारुवास्त नहीं दे सकेगा जब तक कि नीचे दी हुई बातोंमेंसे कोई बात उपस्थित न होवे ।

(ए) उसके कर्जोंकी तादाद ५०० रुपये न होवे, या

(बी) वह किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके आधार पर गिरफ्तार होकर कैद न किया गया हो, या

(सी) किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके आधार पर उसकी जायदाद कुर्क करानेका हुकम दिया गया हो तथा वह हुकम उसकी जायदादके विरुद्ध कायम न होवे ।

व्याख्या—

क्लाज़ (ए), (बी) व (सी) में बतलाई हुई सब बातोंके एक साथ उपहित होनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि इन क्लोजोंमें किसी क्लोजमें बतलाई हुई बात उपस्थित होवे तो उसके आधार पर कर्जदार दिवालिवाकी दारुवास्त दे सकता है अथवा नहीं अथवा यदि उसके कर्ज ५०० या उससे अधिकके हों तो वह दारुवास्त दे सकता है, या यदि वह किसी इलाय डिक्रीके सम्बन्धमें गिरफ्तार होकर कैद हुआ हो तो वह दारुवास्त दे सकता है अथवा यदि उसकी जायदाद कुर्क होवे तो वह दारुवास्त दे सकता है । इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि क्लान (बी) व (सी) में गिरफ्तारी या कुर्क चर्ची डिक्रीयोंके आधार पर होना चाहिये या रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी गई हों यदि इस दफामें बतलाई हुई तीन शर्तोंमेंमें एकरा भी शर्त न होनी होवे तो कर्जदारके दिवालिवाकी दारुवास्त देनेका हकही पंश नहीं होगा ।

दफा १५ कर्जदारकी दरखास्त पर कार्यवाई व उस पर हुक्म

(१) कर्जदारकी दरखास्तमें यह दिखलाया जावेगा कि वह अपने कर्जोंको अदा करने में असमर्थ है और यदि कर्जदार अदालतके सामने यह साबित कर देवे कि वह दरखास्त देनेका हुक्मदार है तो अदालत उस पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दे सकती है परन्तु वह ऐसा उस समय नहीं करेगी जब कि उसकी रायमें वह दरखास्त दिवालियेके अधिकार रखने वाली किसी दूसरी अदालतमें दी जाना आवश्यक हो ।

(२) कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्त दाखिल होनेके पश्चात् बिला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके सम्बन्धमें की जाने वाली कार्यवाहियां विवर्ण हैं। पहले पहिले उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्जदारकी दरखास्तमें यह दिखाना परम आवश्यक है कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेमें असमर्थ है । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें इस बातकी पुष्टि होती है । साथ ही साथ अदालतके सामने यह भी साबित किया जाना चाहिये कि वह दरखास्त देनेवाला कर्जदार है । दरखास्त देनेवाला कर्जदार होगा इस बातके विषयमें दफा १४ में दिया हुआ है । ऊपर बतलाई हुई दोनों बातोंके होने पर अदालत, दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दे सकती है अर्थात् उस समय भी अदालत दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु ऐसा करना उसकी इच्छा पर निर्भर है । अदालतकी हुक्म देनेमें पहिले इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि आया उस अवस्था अन्य किसी अदालतके उस कर्जदारके सम्बन्धमें दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करना चाहिये कर्जदारकी दरखास्तके अन्तर्गत अन्तर्गत असमर्थताका सूचित होना चाहिये । देखो—A. I. R. 1928 Mad 394

उपदफा (२) में उही बात बतलाई गई है जो दफा १३ की उपदफा २ में कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्तके सम्बन्धमें बतलाई जा चुकी है अर्थात् अर्ज दाखिल होनेके बाद दरखास्त बिला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकती है । इस उपदफाकी पाकटा की जाना आवश्यक है जैसे कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट होता है । इस दफामें भी इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दरखास्तकी वसतिपूर्वक प्रत्येक अवस्था में समय तक उठ सकता है जब तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म न दिया जा चुका हो क्योंकि उसके पश्चात् दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदा अथवा नशा होने पर ही कर्जदार दिवालिया नहीं होगा यह उपदफा उर्ध्व दरखास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये जिन पर हुक्म नहीं हुआ है व जो और तमबीज हैं, देखो—C.B. Bom 200

दफा १६ दरमियानी रिसीवरकी नियुक्तिके लिये अदालतको स्वतंत्र अधिकार

यदि जायदादकी रक्षाके लिये आवश्यकता बतलाई जावे तो अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेकी दरखास्त लिये जानेके बाद तथा दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले किसी समय भी आफिशल पसायनी (Official Assignee) को कर्जदारकी कुल जायदाद या उसके किसीके हिस्सेके लिये दरमियानी रिसीवर (Interim Receiver) नियुक्त कर देवे और इस बातका हुक्म दे देवे कि उसकी सब जायदाद या उसके किसी हिस्से पर फौरन कब्जा ले लिया जावे और इस पर आफिशल पसायनीको निर्धारित किये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १९०८ ई० के ज्ञान्ता दीवानीके अनुसार नियुक्त किये हुए रिसीवरको प्रदान किये जा सकते हैं ।

व्याख्या—

यद्यपि इस दफ्ते में दायिगाना रितीवर की नियुक्ति विषय में किसी हुआ है कि अदालत दायिगाना रितीवर नियुक्त करने में नियो बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना न करना अदालत की इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अमेज़ा एक्ट का २२ दफ्ते में प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रकट होता है । दायिगाना रितावर दिवालिया का दारुबस्त दाखल होने के बाद तथा दिवालिया करार दिया जाने का हुआ होने से पहिले नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि दफ्ता १७ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालिया की सम्पत्ति आधिकारिक एसायनी की सुपुर्गा में आ जाती है अर्थात् दिवालिया करार दिये जाने के बाद किसी दायिगाना रितीवर को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है । दायिगाना रितीवर उसी समय नियुक्त किया जा सकता है जब कि कर्नर की आयदाद के बर्षाद हुनका अदेश होकर और ऐसा रितीवर उसकी पूरी आयदाद या उसके जिस भाग के लिये नियुक्त किया जा सकता है । इस दफ्ता के अन्तर्गत एसायनी की के लिये दिया हुआ है कि वह दायिगाना रितीवर नियुक्त किया जा सकता है । इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस दफ्ता के अनुसार नियुक्त किये जाने पर आधिकारिक एसायनी को वह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो उसे आधिकारिक एसायनी की समीप से प्राप्त हो सकते हैं किन्तु जब वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हैं और यह अधिकार वही होंगे जो जबतक दीवाना के अन्तर्गत नियुक्त किये हुए रितावर को दिये जा सकते हैं । रितीवर की नियुक्ति का विषय सन् १९०८ ई० की जायता दीवाना के आर्टर ४० में दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

आर्टर ४० जायता दीवाना रितीवरों की नियुक्ति

नियुक्ति कल १—(१) जब कि अदालत को उचित व सुविधा जनक प्रतीत हो अदालत अपने हुक्म द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है—

- (ए) किसी होने से पहिले या उसके बाद किसी आयदाद के लिये रितीवर नियुक्त कर सकती है
- (बी) किसी भी व्यक्ति को हटा सकती है जिसका कम्पना या अधिकार किसी आयदाद पर होने
- (सी) उस आयदाद की रितीवर को कम्पने उसकी सरसुता में अथवा उसके श्रवण में दे सकती है
- (डी) रितीवर को आयदाद के सम्बन्ध में मुकद्दमा दायर करने उसकी जवाब देही करने तथा उसको वसूल करने प्रवृत्त करने बचाने और उसकी वृद्धि करने के अधिकार दे सकती है, उसका किसी या मुनाफा वसूल करने आदि इस प्रकार वसूल किये हुए रितावर व मुनाफा को सर्व करने के अधिकार भी दे सकती है और आयदाद के सम्बन्ध में ऐसी दस्तावेजों के लिखने का अधिकार भी दे सकती है जैसे कि स्वयं मालिक लिख सकता है । या इन अधिकारों में से कोई भी अधिकार दे सकती है जो उसे उचित प्रतीत होवे ।

(२) अदालत को इस कल के अनुसार यह अधिकार न होगा कि वह आयदाद के कम्पने या अधिकार से किसी ऐसे व्यक्ति को हटा देवे जिसके हटाने का मौजूदा अधिकार मुकद्दमे के किसी फलफले में प्राप्त न होवे ।

अमफल कल २—अदालत अपने आम या खास हुक्म द्वारा रितीवर को उसके कार्य के लिये दिये जाने वाले श्रमफल को नियत कर सकती है ।

कर्तव्य कल ३—इस प्रकार नियुक्त किया हुआ रितीवर नीचे दिये हुए कामों को करेगा—

- (ए) यदि अदालत कोई जमानत उचित समझे तो वह जमानत उस आयदाद के सम्बन्ध में होने वाली आमदनी के हिसाब के लिये देवेगा

(बी) अपना हिसाब अदालतके हुक्मके अनुसार नियत समय पर तथा निश्चित ढंगसे देवेगा

(सी) अदालतके हुक्मके अनुसार वह कृपा देवेगा जो उसे देना है

(डी) उस नुकसानके लिये जिम्मेदार होगा जो उसका जान बूझ कर या अनि करके या बड़े लापरवाहीके कारण हुआ हो

हिसाब न देना कूल ध—(ए) यदि रजिस्टर अदालतके बगाने अनुसार तथा उसके द्वारा नियत किये हुए समय पर हिसाब न दाखिल करे, या

(बी) यदि भद्र करने हुक्मके अनुसार बंद कृपा अथ न करे जो उसके पास है, या

(सी) यदि वह जमान बूझ कर वापसी करेगा या अपना बचा लपरवाहीके कारण नुकसान हो जाने दे तो अदालत उसका जायदादके कुर्क किये जानेका हुक्म दे सकती है न उनको बच सकना है तथा बेचने पर आई हुई कीमतसे उस वसीरो पूरा कर सकती है जो उसके कारण हुई हो या उस कारणसे मुजो ले सकती है जो उससे निकलता होवे और बचा हुआ करेगा यदि कुछ होगा बर्द रजिस्टरको दे देवेगा ।

कलक्टर कूल ध—जब कि कोई जायदाद ऐसी होवे जिसकी माजुबगी सरकारका आधी जाती होवे या ऐसी जमीन होवे जिसकी माजुबगी जिस दी गई हो या उदासी गई हो और अशलतको यह माजुब पके कि उससे सम्बन्ध रखने वालोंका फायदा उस समय होगा जब कि उनका प्रबन्ध कलक्टरके हाथसे किया जावे तो अदालत कलक्टरकी अनुमति लेकर उसे उस जायदादके लिये रिसावर नियुक्त कर सकती है । रजिस्टरके मन्त्र इस को अधिहार ऊपर दिखलाये गये हैं अर्थात् जिसका अट्रैल आर्डर ४० वाक्या दीवानामें होना बतलाया गया है वह सब अधिकार अपना उससे कुछ अधिकार इस दफाके अन्वयानुसार नियुक्त किये हुए दायित्वानी रजिस्टरको दिये जासकते हैं ।

दफा १७ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रभाव

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जाने पर दिवालियेकी आयदाद चाहे वह जिस जगह पर होवे अफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजाबेगी और वह जायदाद उसके कर्जदारोंमें बांटी जाने योग्य होगी और उसके पश्चात् इस एक्टमें बतलाई हुई बातों को छोड़ कर दिवालियेका कोई भी कर्जदार जिसका कर्ज इस एक्टके अनुसार स्वीकृत किया जासकता है दिवालियेकी कार्रवाईमें चालू रहते हुए दिवालियेकी आयदादके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न वह कोई सुरुदमा या कोई अदालती कार्रवाई ही करने कर्जके सम्बन्धमें बिला अदालत की आज्ञाके तथा अदालत द्वारा निर्धारितकी हुई शर्तोंके कर सकेगा । परन्तु यह दफा महफूज कर्जदारके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और उसे अपनी जमानत बख्श करने या उससे अपना कर्ज वसूल करनेमें वही स्वतन्त्रता प्राप्त होगी जो कि उसे इस दफाके पार्ल न होने पर प्राप्त हो सकती थी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेकी सब जायदाद अधिकृत एसायनीकी सुपुर्दगीमें आ जावेगी और उनी समयमें वह सब जायदाद कर्जदारोंमें बांटी जाने योग्य भी हो जावेगी । दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेमें पहिले अफिशल एसायनीको उस बात तक दिवालियेकी जायदादमें कोई सम्बन्ध नहीं होगा । जब तक कि वह दफा १६ के अनुसार दायित्वानी रजिस्टर नियुक्त न किया जावे । इसी दफ्तर्बद्ध भी बताया गया है कि दिवालिया करार

दिये जानेके बाद दिवालियाकी जायदादों विरुद्ध कोई कर्जपत्राह अपने कर्जेके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न बिना अदालतकी आज्ञाके कोई मुकदमा या अन्य अदालती कार्रवाई कर सकेगा परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऊपर बतलाई हुई बात उन्हीं कर्जोंके लिये लागू होगी जो दिवालियाकी कार्रवाईमें साबित किये जा सकते हैं। इस दफ्तरेमें जो अन्य कानूनी कार्रवाई का उल्लेख है उससे दीवानीकी कार्रवाइों सम्बन्धना चाहिये फ़ाजदारीका नहीं अर्थात् इस दफ्तरेमें बतलाये हुए नियमों का पालन केवल उन्हीं कार्रवाइयोंके लिये आवश्यक है जो दीवानीके तौर पर होने और फ़ौजदारीके इतरासे होने वाले सम्बन्ध नहीं हैं। देखो—मरगाद बहादुर बनाम मूलशङ्कर 35 Bom 63 परन्तु जब कि जोड़ी कायमान शक्ति किये गये हों तो जब फ़ौजदारीके अनुसार फ़ौजदारी का मामला चालू करनेके लिये अदालतकी आज्ञा लिये जानेकी आवश्यकता है देखो 37 Mad. 107

इस दफ्तरेके साथ जो शर्तें लगा दी गई हैं वह भी नहीं मरहूम की हैं और उसका ध्यान रखना आवश्यक है उस शर्तके अनुसार मरहूम कर्जपत्राह अपनी जमानतकी जिस प्रकार चाहे वमूल कर सकता है और उसके लिये यह दफा लागू नहीं होगी। कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार अदालतकी आज्ञा मुकदमा दायर करनेके लिये दिये जानेमें पहिले दिवालियाके नाम नोटिस जारी किया जावे। नोटिसका दिया जाना व न दिया जाना हर एक मामलेके उद्भागाना बाकपात पर निर्भर है। स्थल हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियाके नाम नोटिस दिला नहीं गये हुए ही अदालतकी आज्ञा दी गई हो तो वह उचित आज्ञा समझी जावेगी, देखो—6 R. 533, A. I. R. 1928 R. 326 यदि किसी मरहूम हिन्दू परिवारका जिसके लिये कि विवाहका कानून लागू हो पिता दिवालिया करार दिया जावे तो उस परिवारकी सब संपत्ति जायदाद जिसमें कि उसके लड़कोंका भी हिस्सा शामिल है अकिशल एसायरीकी सुपुर्गीमें आजावेगी। परन्तु लड़कों को अधिकार है कि वह अपना हिस्सा यह साबित करने पर तैयार रहते हैं कि बापके कर्जे पर कानूनी व बेका तौरसे किये गये थे और उन कर्जोंके लिये उनके हिस्से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, देखो—11 B. 37, 19 M. 14, 42 C. 225; 8 Lah 329.

यदि किसी मुकदमेके दौरानमें कोई कर्ज दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह अपने दिवालिया हो जानेके कारण अपील करनेके अयोग्य हो जाता है। दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मसूख हो जाने पर वह अपनी अपील कर सक्त है, देखो—A. I. R. 1929 Bom 20. इस दफ्तरेमें यह भी बतलाया गया है कि दिवालियाकी जायदाद जहां बही होवे अकिशल एसायरीकी सुपुर्गीमें आजावेगी अर्थात् उसका होना केवल ब्रिटिश इण्डिया ही के लिये प्रतिष्ठित नहीं है। बल्कि हाईकोर्टने यह तय किया था कि मन्तव्य जायदाद या शपार्हके बास्कर कोर्ट (Consular Court) की अधिकार सीमामें स्थित है बल्कि अकिशल एसायरीकी सुपुर्गीमें हुक्म हो जाने पर आजावेगी देखो—33 Bom 462 इस एकके अनुसार साबित किये जावे योग्य कर्जोंका उल्लेख दफा ४६ में तफ़्सीलवार किया गया है। अदालतकी आज्ञा देने पर जो कार्रवाई चालू की जावेगी उसके लिये अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों में भी पालन आवश्यक है।

दफा १८ कार्रवाईका रोक जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी मुकदमेमें या अदालती कार्रवाई को जो दिवालियाके विरुद्ध किसी जज या जजों अथवा अन्य किसी अदालतके सामने चल रही हो रोक देवे जिसमें कि वह अदालतके निरीक्षणमें चल सके।

(२) उपदफा (१) के अनुसार दिये हुए हुक्म की मरकल अदालत की मोहर लगाकर टाकने जरिये मुद्दई या मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तिके पतेसे अदालत द्वारा भेजी जासकती है और

ऐसे हुक्मका नोटिस उस अदालतके पास भेजा जावेगा जिसके सामने यह मुकदमा या कार्यपत्र चल रही हो ।

(३) कोई भी अदालत जिसके सामने किसी कर्जदारके दिवङ्ग मामला चल रहा हो तो इस बापका सुबूत पहुँचने पर कि वह इस एक्टके अनुसार दिशालिया करार दे दिया गया है या ना अपने यदा चगने वाले मामलों को रोक देगी अथवा उसको उन शर्तोंक साथ चालू रहने देगी जो उसे उचित प्रतीत हों ।

व्याख्या—

अज्ञात दिशालिया अस्कार है कि यह दिशालिया करा दिने जाने वाले हुक्मक पक्का यदि वह चाहे तो मुकदमा व दूसरी दिशालिया का रोक दे कर चाह कर अज्ञातों या अज्ञातों गलत भाव किसी अज्ञातों होती होने । और त प्रचार रोनेना जो हुक्म दिया जावेगा वह वजहों का मुद्दे का मुकदमा चलाने जाते निहा अप वास्तिके पास भेजा जायता है अर्थात् मुद्दे या मुकदमा गलत वाले वास्तिके पास हुक्मका नफर भेजनेके लिये अदालत बाय नहा दिनु उमर गनना न गेनना अदालती इच्छा पर निर्भर है परतु इस हुक्मकी मूलतः उस अदालतक पास अज्ञात भेजी अने ही जिनके ता ने वह मुकदमा या मामला चल रहा हो जैसा कि अज्ञाती एक्टका उपदका (२) में अयोग दिव हुक्म (Dagall) द इसे प्रकट होता है ।

उपदका (१) व (२) में अज्ञात दिशालिया द्वारा जो जाने वाला कार्यवाह्यता लक्ष्य है अर्थात् उमर वह बन गया है कि अदालत दिशालिया दिशालिया दिवङ्ग चलने वाल मुकदमा या किना अथ अदालती का वा यात्रा रोक मरना के लिये उपदका (३) में मगद बल्ल ग गया है कि अज्ञात दिशालियाक उचित उग लक्षणता भी निगने सामन दिशालियाके दिवङ्ग नहीं ममल चल रहा हो उम ममलको रोक देने या निही खाय शप के साथ चालू रखनेका आदेश है । यह हुक्म अज्ञात मामलोंके उरी समय लोक । जब कि उस यह सविन हो आव दिशालिया करार दिव जानना हुक्म हो चला है ।

उपदका (३) में अज्ञात यह भी प्रकट होता है कि यदि दिशालिया करार दिने जानेका हुक्म होने समय कोई ममल चल रहा हो तो भी अदालत उम ममलको यह हुक्म होने पर त दिशालिया करार दिव जानना हुक्म हो गया है । यह सच है अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि राजा जान बाग ममल दिशालिया करार दिने जानेक पहिले हुक्म चल रहा हो, कदा—41 Bom. 112 चलना द हुक्मने यह तय किया है कि हाईकोर्टको कोई जज दका १६ मराठेना दजत दिशालियाके एक्टके अज्ञात कार्यवाहे रत हुक्म दिशालिया जननी उम कार्यवाही नहीं रोक सकता है जा वह प्रतिक एक्ट दिशालियाक अनुसार उरी उद्देशक दिवङ्ग कर रहा हो । इस दफामे वलार्ड ईई दूसरा कानून कार्यवाहीमें दिशालियाके कार्यवाही नहीं जाना है दूसरी दिशालिया में उरी रकत उ ही दिशालियाका सन्ध्या चाहिये जा मुकदमक ताए पर होव या इन तय अथवा एसा ही कोई दूसरी वादुत कार्यवाही होये दको—A I R 1928 Cal 782 इसा सभ धर्म कर्ज हाँको ही भी ऐसी ही गय रही है निमम ता यह भी कहा गया है कि वह दूसरी दिशालियाके कार्यवाही कोई ऐसा प्रकदमा या कार्यवाही नहीं है जो दिशालियाके दिवङ्ग चल रही हो इस कारण दिशालियाका कार्यवाही इस दफामे अज्ञात नहा गता जा सकता है, कदा—24 Bom L R 872 A I R (1921) Bom 390

दका १९ विशेष मेनेजरकी नियुक्तिके अधिकार

(१) यदि किरात मालगोमें अज्ञात कर्जदारकी जायदादको या उत्तरे यागनको अथवा

आम क्रमपूर्वाधिकारों के लाभको देखते हुए यह राय कायम करे कि कर्मदारकी जायदाद या व्यापार के अस्तकालमें आफिशल एसायनीकी मददके लिये किसी विशेष मैनेजरकी नियुक्तिकी जाना चाहिये तो उसे अधिकार है कि वह ऐसे मैनेजरकी नियुक्ति किसी निश्चित किये हुए समय तक काम करनेके लिये जिसे वह मुनासिब समझे कर देवे और उस मैनेजरको आफिशल एसायनी को प्रदान किये जाने वाले वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे आफिशल एसायनी अथवा अदालत सुपुर्द करे।

(२) विशेष (Special) मैनेजरको उस प्रकारकी जमानत देना पड़ेगी तथा हिसाब बाखिल करना पड़ेगा जैसा कि अदालत हुक्म देवे और उसको यह धमकड़ा (Remuneration) मिलेगा जो अदालत निश्चित करे।

व्याख्या—

उपध्दा (१) में विशेष मैनेजरकी नियुक्ति के विषयमें दिया हुआ है कि यह विशेष मैनेजर उसी समय नियुक्ति किया जा सकेगा जबकि कर्मदारकी जायदाद किसी विशेष प्रश्नकी होने जिसका प्रबन्ध आफिशल एसायनी भले प्रारम्भ कर सकता हो अथवा कर्मदारके व्यापार या आम क्रमपूर्वाधिकारों के लाभार्थ आफिशल एसायनीकी सहायताके लिये किसी ऐसे व्यक्तिके नियुक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होने पर। इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि विशेष मैनेजर की नियुक्ति करना करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अनेकी एकरी इस दफ्तामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रष्ट होता है—इस प्रकार नियुक्ति किया हुआ मैनेजर उतनेही समय तक काम कर सकता है जितने समयके लिये वह अदालत द्वारा नियुक्त किया जाने लायक वह आफिशल एसायनीकी भाति दिवालियेकी कुछ बाँटवार्थके लिये नहीं रहेगा आफिशल एसायनीकी मदद की के लिये ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाने समर्थ नियुक्ति आफिशल एसायनीकी जगह पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् उसकी नियुक्तिसे यह न समझ लेना चाहिये कि आफिशल एसायनीके सब बाँटवों वह विशेष और आफिशल एसायनी की उसकी नियुक्ति के पश्चात् दिवालियेकी बाँटवोंमें कोई सम्मिलित नहीं रहेगा एक प्रकारसे ऐसा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति आफिशल एसायनी का मातहत समझना चाहिये जिसे आफिशल एसायनीके लिये निर्धारित किये हुए कार्यमें कुछ बरबोंके करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाने विशेष मैनेजरकी आफिशल एसायनीकी मदद किसे जाने वाले अधिकारोंमें से वह अधिकार प्राप्त होंगे जो आफिशल एसायनी अथवा अदालत सबके लिये तय कर दे।

उपध्दा (२) के अन्तर्गत इस प्रकार नियुक्ति किये हुए मैनेजरसे अदालत जिस प्रकारकी जमानत चाहे ले सकती है और उसमें हिसाब भी जिस प्रकार वह चाहे बाखिल कर सकती है अथवा एकदम प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें यह प्रष्ट है कि विशेष मैनेजरकी जमानत या हिसाब सम्मती हुक्मोंकी पालनी करना आवश्यक है अदालत इस प्रकारके मैनेजर के लिये धमकड़ा (Remuneration) भी नियत कर देगी और वह मैनेजर इस प्रकार नियत किये हुआ धमकड़ा ही पावेगा उतने अधिक या उतने अविरत कुछ नहीं प्रायेगा।

ध्दा २० दिवालिया कर्गार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा

दिवालिया कर्गार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा गज़ट आफ इण्डियामें (Gazette of India) स्थापित सरकारी गज़टमें (Local Official Gazette) तथा निर्धारित किये हुए अन्य दूसरे दंगस प्रकाशितकी जावेगी और उस घोषणामें दिवालियेका नाम पता व पेशा, दिवालिया कर्गार देनेकी तारीख उस अदालतका नाम जिसने दिवालिया कर्गार दिया हो और दिवालियेकी दृष्ट्यात्म दिने जानकी तारीख प्रकाशितकी जावेगी।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन गन्त आप्रसविद्या न स्थानिक सरकारी गन्तमें किया जानेगा तथा निश्चित किये हुए अथ प्रकाशे भी किया जावेगा अथवा एकदम इस दफ्तरमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि-प्रकाशन उक्त प्रकारसे अवश्य किया जाना चाहिये । प्रकाशनमें जिन जिन बातोंका दितलाया जाना आवश्यक है वह भी इस दफ्तरमें बतलाई गई है अर्थात् दिवालियेका नाम, पता न पेशा दिया जाना चाहिये दिवालिया करार दिये जानेकी तारीख दी जाना चाहिये दिवालियेकी दास्वास्त दाखिलकी जाने वाली तारीख तथा दिवालिया करार देने वाली अदालतका नाम भी दे दिया जाना चाहिये । इस दफ्तरमें यह प्रकट है कि दिवालिया करार देनेके पश्चात् भली भाँति-मुसदर न दिया जाना आवश्यक है ।

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

दफा २१ कुछ मामलोंमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अधिकार

(१) जब कि अदालतकी रायमें किसी कर्जदारको दिवालिया करारहीं नहीं दिया जाना चाहिये था अथवा अदालतको यह संतोषजनक रूपसे साबित हो जावे कि दिवालियेके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जासकते हैं तो अदालतको अधिकार है कि-वह किसी सम्बन्धित व्यक्तिकी दृष्टिवात् जाने पर अपने हुक्म द्वारा दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंजूर कर देवे ।

(२) यदि कोई कर्जों जिसे कर्जदार तस्लीम न करता हो परन्तु जिसकी अदायगीके लिये वह दस्तावेज मय उन जमानतोंके जिसे अदालत मंजूर करे लिख देवे तो इस दफ्तरमें लिये यह मान लिया जावेगा कि वह कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाया जाचुका है और ऐसे कर्जद्वारा कर्जों जिसका पता न लगता हो अथवा जिसकी शनासत न की जासकती हो यदि अदालतमें अमर कर दिया जावे तो वह भी पूर्ण रूपसे चुकाया हुआ कर्ज माना जावेगा ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंजूर करनेके लिये अदालतकी दो प्रकारसे अधिकार प्राप्त हैं एक तो यह जब कर्जदारकी दिवालिया करार ही न दिया जाना चाहिये था न दूसरे उस समय जब कि कर्जदारके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जाचुके हैं । इस दफ्तरमें अनुसार मसूखीके लिये कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति दास्वास्त दे सकता है अर्थात् स्वयं कर्जदार बतला कोई सम्बन्धी या कर्जदार आदि अदालत इन दफ्तरके अनुसार मसूखीका हुक्म दे देनेके लिये वाच्य नहीं है जैसा कि कानूनी एक्टकी इस दफ्तरमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है । उक्तका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् ऊपर कानूनी हर्ष दो बातोंमें से किसी एक बातके उपरिष्ठ मान हो से मसूखीका हुक्म नहीं हो जावेगा किन्तु अदालत और भी वाक्याल पर विचार करेगी अर्थात् दिवालियेके जोहार आदि पर यदि दिवालिया अपने कर्जोंका अदा करनेमें धनमय नहीं था तो दिवालियेका हुक्म इन दफ्तरके अनुसार मंजूर किया जाना उचित है, देखे—A. I. R. 1928-Mad. 395. 1082. C. 208.

दिवालियेके कर्जोंकी पूर्ण रूपसे अदायगी हो जाना चाहिये और अदालतको संतोषजनक रूपसे यह बात साबित भी हो जाना चाहिये तथा यह माना जावेगा कि कर्जों चुकाये जाचुके हैं दिवालिया वा उससे पिछकर उक्तका कोई कर्जदार इस एक्टके

(२) ऊपर घतलार्ह हुई सूची निम्न लिखित समयके अन्दर दाखिल की जावेगी:—

(ए) यदि कर्जदारकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हुआ है तो उस हुक्मसे ३० दिनोंके अन्दर

(बी) यदि कर्जस्वाहकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हुआ है तो उस हुक्मकी तारीख होनेसे ३० दिनोंके अन्दर

(३) यदि दिवालिया चला किसी उचित कारणके इस दफ्तामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबन्दी न कर सकेगा तो अदालतको अधिकार है कि वह आफिशल एसायनी अथवा किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त आने पर उस दिवालियेको जेल दीवानीमें सुपुर्द किये जानेका हुक्म देदेवे।

(४) यदि दिवालिया ऊपर घतलार्ह हुई सूचीको तैयार न करेगा या उसे दाखिल न करेगा तो आफिशल एसायनी उसकी जायदादके खर्चसे निर्धारित किये हुए ढंग पर सूची तैयार करा सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्ताके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेका कर्जदारको यह निर्धारित ढंग पर अपने मामलोंके सम्बन्धमें एक सूची दाखिल करे जिसकी पुष्टिके लिये उसे इल्फनामा भी देना पड़ेगा और उस सूचीमें वह सब बातें भी देगा जिनके लिये बतलाया गया है।

उपदफा (१) में (Shall) शब्दका प्रयोग अंग्रेजी एक्टमें किया गया है जिससे यह भली भाँति प्रकट है कि दिवालिया अपनी इस सिमेटारीको टाल नहीं सकता है इसी दफ्ताके उपदफा (३) में बतला दिया गया है कि हुक्मकी तारीख न करने पर वह दीवानीकी जेलमें भेजा जासकता है। सूची दाखिल करनेके लिये समय भी निर्धारित कर दिया गया है उपदफा (२) के क्लॉस (ए) के अनुसार यदि दिवालिया अपनी ही दरखास्त पर दिवालिया करार दिया गया हो तो दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म होनेकी तारीखसे ३० दिनोंके अन्दर सूची दाखिल करना जाना चाहिये। क्लॉस (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त पर कोई कर्जदार दिवालिया करार दिया गया हो तो जिस तारीखसे उस पर दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी तारीख हुई है। उस तारीखसे ३० दिनोंके अन्दर सूची दाखिल करना जाना चाहिये।

उपदफा (३) में जो इल्फनामा देनेकी आवश्यकता रखी गई है वह इस कारण समझना चाहिये कि जिसमें दिवालिया सूचीमें गलत सभ्य बातें न दिखाने देवे किन्तु वह सब बातोंको ठीक ही ठीक दिखाने देवे क्योंकि राकट इल्फनामा दाखिल करने पर वह गलत इल्फनामा दाखिल करनेका दोषी निर्धारित किया जाकर दण्डका भागी हो सकता है।

उपदफा (३) में जेल दीवानी भेजनेका उल्लेख है उससे यह भी समझ लेना चाहिये कि दिवालिया सूची न दाखिल करने मात्रही से जेलमें भेज दिया जावेगा। जेलमें भेजना न भेजना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और अदालत समय न आवश्यकताअनुसार इस प्रकारका हुक्म देवेगी। इस प्रकारका हुक्म आफिशल एसायनी अथवा अन्य किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त देने पर हो सकता है परन्तु इस बातका भी ध्यान साथ साथ रखना चाहिये कि यदि किसी उचित कारणसे दिवालिया उस सूची दाखिल न कर सके अथवा उस सूची नियत किये हुए समयके अन्दर न दाखिल हो सके तो इस उपदफाके नियमका प्रयोग नहीं किया जावेगा जैसे कि दिवालिया दोषार पड़ गया हो अथवा जिन बातोंके सुचामें दिखाने की आवश्यकता हो उसके लिये दिवालियेको कुछ अवकाश मिलना चाहिये तो दोनों हान्डोंमें नियत किये हुए समयसे कुछ अधिक समय दिवालियेको मिल सकता है इसादि

उपपृष्ठा (४) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया उक्त नियमोंके अनुसार सूचा तैयार न करे या दाखिल न करे तो आफिशल एसायनीमें अधिकार है कि यह उसकी आवश्यकते छवेंमें निर्धारित त्रिप हूप दंग पर सूचा तैयार करे दे।

पृष्ठा २५ रक्षाका हुक्म

(१) कोई भी दिवालिया जिसने कि ऊपर बतलाये हुए दंग पर सूची दाखिल कर दी हो अदालतमें अपनी रक्षाके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्त पर दिवालियेकी गिरफ्तारी या कैदसे रक्षाके लिये हुक्म दे सकती है ।

(२) रक्षाका हुक्म सूचीमें दिखलाये हुए सय कजोंके लिये अथवा उनमेंसे किसी कजोंके लिये जैसा कि अदालत मुतासिब समझे लागू हो सकता है और यह अदालत द्वारा बतलाये हुए घण्टेसे शुरू हो सकता है तथा उसके बतलाये हुए समय तक कायम रह सकता है और जैसा अदालत मुतासिब समझे उसके अनुसार खारिज किया जासकता है अथवा फिरसे जारी हो सकता है ।

(३) रक्षाका हुक्म दिवालियेको गिरफ्तारी या कैदसे उन कजोंके सम्बन्धमें बचायेगा जिनके लिये हुक्म हुआ हो और यदि कोई दिवालिया ऐसे हुक्मके विरुद्ध गिरफ्तार या कैद किया गया हो तो वह झुटकाग पानेका अधिकारी होगा । परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे हुक्मसे कर्जहवाहके हकमें उस समय कोई टकावट नहीं पड़ेगी जब कि वह हुक्म खारिज कर दिया गया हो अथवा दिवालिया कपार दिये जानेका हुक्म मंजूर कर दिया गया हो ।

(४) कोई भी कर्जहवाह हाज़िर होकर रक्षाके हुक्मका विरोध कर सकता है परन्तु जाहिस तौर पर वह दिवालिया रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी होगा जो आफिशल एस यनी का दहशतती सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश कर दे कि उसन इस एफ्टके निपमोंका पालन उस समय तक बराबर किया है ।

(५) अदालतको अधिकार है कि यदि वह कर्जहवाहोंके हुक्मके लिये उचित समझे तो दिवालिये द्वारा सूची दाखिल किये जानेसे पहिले भी रक्षाका हुक्म दे देय ।

व्याख्या—

इस दफ्तेमें दिवालियेकी शर्तके लिये हुक्म दिये जानेका बर्णन है । उपपृष्ठा (१) में बतलाया गया है कि सूची दाखिल होनेके पश्चात् दिवालिया रक्षाका दरखास्त दे सकता है । अगली एक्टरी इस उपपृष्ठाके प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि रक्षाका हुक्म देना न देना अदालतको रक्षा पर निर्भर है परन्तु आगे चल कर उपपृष्ठा (४) व (५) में देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि अदालत अपनी इच्छानुसार प्रयोग इस सम्बन्धमें अवसर बचा आवश्यकता समझने हुए करेगी और उपपृष्ठा (४) में यह स्पष्ट होकर बतला दिया गया है कि यदि दिवालिया आफिशल एसायनीका सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश करे कि उसने एक्टमें बतलाये सब कर्तव्योंको उस समय तक पालन किया है तो अदालत तौर पर यह रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी समझा जावेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात माहित न हो जावे । उपपृष्ठा (५) के अनुसार सूची दाखिल करनेसे पहिले भी दिवालिया रक्षाका हुक्म प्राप्त कर सकता है । यह न समझ लेना चाहिये कि उपपृष्ठा (४) से अदालतका रक्षाका हुक्म देने न देनेका अधिकार छीन लिया गया है बल्कि उक्त उपपृष्ठाके वचन यह बतलाया गया है कि यदि कोई कर्जहवाह रक्षाकी दरखास्तका विरोध करे तो अदालतको किस तर्कके पर काम करना चाहिये अर्थात् अदालतकी रक्षा पर हुक्म देना न देना उस दृष्टिकोणों पर निर्भर है, देखो—35 Bom. 47.

(५) अदालत, दिवालियासे यह प्रश्न पूछ सकती है, जो उसे अति आवश्यक होवे।

(६) दिवालियेके बयान हलफसे लिये जावेंगे और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले सब प्रश्नोंका उत्तर देवे तथा उन प्रश्नोंका भी उत्तर देवे जिनके लिये अदालत आज्ञा दे देवे। बयान की कुछ बातें जो अदालत उचित समझे लिख लेंगी और वह या तो दिवालियेको पढ़ कर सुना दी जावेगी या वह स्वयं पढ़ लेगा और उस पर दिवालिया इरस्तखत करेगा और उसके पश्चात् वह बयान उसके विरुद्ध शहादतमें पेश किये जा सकते हैं और उसका मुआयना कोई भी कर्जख्वाह उचित अवसरों पर कर सकेगा।

(७) जब कि अदालतकी रायमें दिवालियेके मामलोंकी पर्याप्त रूपसे जांच पड़ताल हो चुकेगी तो अदालत यह हुक्म देवेगी कि उसका बयान समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे हुक्मसे अदालत यदि वह फिर कभी उसका अधिक बयान लेना उचित समझे तो बञ्चित नहीं रहेगी।

(८) जब कि दिवालिया पागल होवे अथवा वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष या अयोग्यतासे पीड़ित होवे जिसकी वजहसे वह अदालतकी रायमें खुला बयान देनेके लिये अयोग्य है या वह ऐसी औरत होवे जो अपने देशके रीति रिवाजके अनुसार खुले तौर पर बयान देने के लिये मजबूर न की जाना चाहिये तो अदालतको अधिकार है कि वह ऐसे लोगोंका खुला बयान न लिये जानेका हुक्म दे देवे या ऐसा हुक्म दे देवे कि दिवालियेका बयान किसी निश्चित रूपसे तथा निश्चित समय पर लिया जावे जैसा कि अदालत आवश्यक समझे।

व्याख्या—

दिवालिया कसूर दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् अदालतका कर्तव्य होगा कि वह दिवालियेके बयानोंके लिये कीड़े तारीख नियत करे और दिवालियेका बयान खुली अदालतमें लेवे। इसकी सुचना कर्जख्वाहानको निर्धारित दिने हुए दफा पर दी जावेगी।

उपदफा (१) की पाबन्दी आवश्यक है उसके विधियोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अमली एवढी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे जो दो मतवा इस्तमाल किया गया है प्रकट होता है दिवालियेका भी कर्तव्य होगा कि वह अपने बयानके लिये नियत किये हुए दिन पर हाजिर होवे जैसा कि इस सम्बन्धमें भी अदालत किये हुए अमली एवढे (Shall) शब्दमें भागित होता है। दिवालियेका बयान उक्त व्यवहार चलन व जापदके सम्बन्धमें लिया जावेगा।

उपदफा (२) में वह समय बतलाया गया है जब कि उपदफा (१) के अनुसार बयान लिया जाना चाहिये अर्थात् दिवालिये द्वारा सूची दाखिल किये जानेके लिये जो समय नियत किया गया है उसक खत जाने पर मिनती मन्दी हो सके उसके बयानके लिये ताराख नियत की जाना चाहिये। अदालत स्वयं सवालदा पूछ सकती है। वह कर्जख्वाहान को अपने कर्जे का सुदूत दाखिल कर चुक हो स्वयं या किसी वकीलके आये सवालान पूछ सकते हैं आदिमल एसायनी भी उस समय की बरिवाइमें माग लयेगा अर्थात् उक्त कर्तव्य है कि वह उस समय उपस्थित होवे व अधिन पेशी करे। पेशी के लिये वह स्वयं भी परवा कर सकता है तथा उक्त लिये अपने और से वकील को भी लवा कर सकता है। इस दफाके अनुसार दिवालियेका जो बयान लिय जावेगा वह हुक्म देकर लिये जावेगा और दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले तथा पुछराय जाने वाले सवा सवालान का जवाब देवे अदालत हर सवाल का जवाब या पूरा बयान लिखने के लिये बाध्य नही है कि नु वह जिन मनीसों में उचित समझ रख सकती है परन्तु अदालत वह नहीं कर

सकती है कि वह कुछ भी न लिखे अदालत का कर्तव्य होगा कि वह न्याय की सच्ची बातों को लिखे जैसा कि अमेज एक्ट की उप दफा ६ में प्रयोग किये हुये (Shall) शब्द से प्रकट है । जो न्याय अदालत नोट करेगा वह दिवालिये को पढ़ कर सुनाये जावेगा और उस पर दिवालिये के दस्तखत लिए जावेगा । इस प्रकार लिखे हुये न्यायों का पृष्ठान्न ही एक कर्जस्वाह बन सकता है तथा इस प्रकार दिये हुये न्याय दिवालियेके विरुद्ध शहान्त में प्रयोग किये जा सकते हैं । एक दफा उसका न्याय हो जानेके बाद भी अदालत दुबारा दिवालिये का न्याय उप दफा (७) के अनुसार ले सकती है शब्दा (८) के अनुसार अदालत पदमार्जन औरतों पागलों व अन्य किसी रोग से पीडित पुरुषों को इस दफा के अनुसार न्याय देनेसे बरी कर सकती है या अगर वह चाहे तो उनका न्याय जिस तरीके से सुनामिब समझ उस तरीके से ले सकती है जैसे कि कमीशन से न्याय लिखे जा सकते हैं । इस उपदफा के अनुसार कार्य करना अदालत की इच्छा पर निर्भर है ।

तस्फीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

दफा २८ प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका कर्जस्वाहों द्वारा स्वीकार किया जाना

(१) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुफमके पश्चात् दिवालिये को अधिकार है कि अपने कर्जों के चुकाने के सम्बन्धमें तस्फीये का प्रस्ताव अथवा अपने मामलों को तय किये जाने की स्कीम का प्रस्ताव निर्धारित किये हुये ढंग पर पेश करे और वह प्रस्ताव आफिसल एसायनी कर्जस्वाहों की मीटिंग में पेश करेगा ।

(२) आफिसल एसायनी दिवालिये के प्रस्ताव की नकल मय उस पर दी हुई रिपोर्टके सूची में दिखलाये हुये सब कर्जस्वाहों या ऐसे कर्जस्वाहोंके पास भेजेगा जो अपना सुवृत्त मीटिंग में दाखिल कर चुके हैं । और यदि उस पर विचार करने पर कसरत लादाव तथा सब कर्जस्वाहों के फर्जों के तीन चौथाई कीमत के कर्जवालों की राय से जिनके कर्जों साबित किये जा चुके हैं प्रस्ताव स्वीकार किया जावे तो वह प्रस्ताव कर्जस्वाहों द्वारा ठीक सीरसे स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव माना जावेगा ।

(३) दिवालिया मीटिंगके समय अपने प्रस्तावकी शर्तोंको संशोधित कर सकता है यदि आफिसल एसायनी की रायमें उस संशोधन से उसके आम कर्जस्वाहों को लाभ पहुंचता होवे ।

(४) कोई भी कर्जस्वाह जो अपना कर्जा साबित कर चुका है अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति पत्र द्वारा आफिसल एसायनीके पास नियत किये हुये दिनसे एक दिन पहले भेज सकता है अर्थात् उस दिन तक आफिसल एसायनी के पास वह पहुंच जाना चाहिये और इस प्रकार की स्वीकृति या अस्वीकृति का वही प्रभाव होगा जैसे कि यह मीटिंग में मौजूद रहा हो और उसमें वोट दिया हो ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके मामलोंका तयकीया किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है । दिवालिया करार दिये जानेका हुफम होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अपने कर्जोंको तय करनेके लिये प्रस्ताव पेश कर सकता है । यह प्रस्ताव निर्धारित ढंग पर होना चाहिये और यह प्रस्ताव आफिसल एसायनी द्वारा कर्जस्वाहानों की मीटिंगमें रखा जावेगा । इस प्रकारका

प्रस्ताव आगे पर आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह प्रस्ताव की नकल तथा अपनी रिपोर्टकी सूचना उन सब कर्जस्वादानक पास भेजे जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं या जिनका नाम सूचीमें दिया हुआ है इस प्रकारके प्रस्तावका कर्जस्वादान दाय स्वीकार किया जाना उस समय माना जावेगा जब कि बहुमतसे कर्जस्वादानने उस प्रस्तावको स्वीकार किया हो तथा साथही साथ उन कर्जस्वादानका कर्जों कुल कर्जके तीन चौथाईसे कम न होने । दिवालिया अपने प्रस्तावका संशोधन भी मॉर्टिगेज समय कर सकता है पणु यह संशोधन उती समय हो सकेगा जब कि आफिशल एसायनी की रायमें वह संशोधन आम कर्जस्वादोंके लाभके लिये समझा जावेगा । कर्जस्वादानकी सुविधाके लिये उपद्रवा (४) में यह दे दिया गया है कि वह अपनी राय लिखकर आफिशल एसायनीके पास भेज सकते हैं और इस प्रकार लिखी हुई रायका नही प्रभाव होगा जो स्वयं उपस्थित होकर बोट देनेका होता है । इस बातका प्यान रहना चाहिये कि इससे पहिले आफिशल एसायनीके पास पहुँच जाना चाहिये अर्थात् मॉर्टिगेजसे पहिले बाचा दिन इस प्रकारकी राय पहुँचनेके लिये आखिरी दिन हवेगा ।

दफा २९ अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति

(१) जब कि प्रस्ताव कर्जस्वादों द्वारा मंजूर किया जाचुके तब दिवालिया या आफिशल एसायनी अदालतमें उसकी स्वीकृतिके लिये दरखास्त दे सकता है । इस दरखास्तके सुने जाने की सूचना उन सब कर्जस्वादोंको दी जावेगी जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं ।

(२) दिवालियेके खुले आम बयान लिये जानेसे पेश्तर ऐसी दरखास्त नहीं सुनी जावेगी किन्तु उससे पेश्तर उस दशमें सुनवाई हो सकती है जब कि सरसरीमें उसकी जायदादका इन्तज़ाम किया जानेको होवे अथवा अदालतसे उसके लिये विशेष आज्ञा लेली गई हो । कोई भी कर्जस्वाद जो अपना कर्ज साबित कर चुका है दरखास्तका विरोध कर सकता है चाहे वह कर्जस्वादोंकी मॉर्टिगेजमें उस प्रस्तावके स्वीकार किये जानेके लिये बोट दे चुका हो ।

(३) अदालत उस प्रस्तावके लिये स्वीकृत प्रदान करनेसे पहिले आफिशल एसायनीकी रिपोर्ट उसकी शर्तों तथा दिवालियेके बर्तावके बाबत सुनेगी और उन पेश्तराजोंको भी सुनेगी जो कोई कर्जस्वाद करे या जो उसकी ओरसे किये आवें ।

(४) यदि अदालत की रायमें प्रस्तावकी शर्तें उचित न प्रतीत हों अथवा उनसे आम कर्जस्वादोंको लाभ पहुँचने की सम्भावना न हो या कोई इस प्रकारका मामला होवे जिसके कारण अदालत बहाल करनेसे इनकार कर सकती हो तो अदालत प्रस्तावको मंजूर नहीं करेगी ।

(५) जब कि कोई ऐसी बातें साबित की गई हों जिनके साबित होनेके कारण दिवालिये के बहाल किये जानेसे इनकार किया जासके या वह रोका जासके अथवा उसमें शर्तें लगाई जा सकें तो अदालत प्रस्तावको स्वीकार करनेसे इनकार कर देगी परन्तु वह उस सूरतमें मंजूर किया जासकेगा जब कि उसमें उचित ज़मानत उन बिला महफूज़ कर्जोंकी रूपयमें चार आने अदायगी की गई हो जो इस एकटके अनुसार साबित किये जासकते हों ।

(६) यदि दिवालियेकी जायदादसे कोई कर्जों औरोंके मुकाबले पहिले अदा किये जाना चाहिये और तसकिये या स्कीममें उनके इस प्रकार पहिले अदा किये जानेकी व्यवस्था न की गई हो तो ऐसा प्रस्ताव या स्कीम स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(७) अन्य किसी मामलेमें अदालत या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है अथवा उसको अस्वीकार कर सकती है ।

व्याख्या—

दफा २० के अनुसार कर्जस्वादान द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव उस समय तक कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक कि अदालत उसे मजबूर न कर देवे । कर्जस्वादान द्वारा स्वीकार किये जानेके पश्चात् आक्षिप्त एरायनी या दिवालिया अदालतमें उस प्रस्तावके मजूर निये जानेके लिये दम्बस्वत दे सकता है और इस प्रकार दी हुई दम्बस्वतको सुनोके लिये जो तांगेज नियतकी जावेगी उसकी सूचना उन तब कर्जस्वादानको दी जावेगी जो अपना कर्ज सादित कर चुके हैं । इस उपदफामें बतलाई हुई सूचना अवश्य दी जानी चाहिये जमा कि अग्रणी एवटर्की इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य मालूम होता है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि जब कोई कॉन्ट्राई सरसमिमें को गई हो या जब कि अदालतने प्रमाण तोरसे आशा दे दी हो तो सरसमि या प्रस्ताव दिवालिया कथार दिये जानेके बाद किसी समय भी सुना जा सकता है परन्तु और मामलोंमें इस प्रकारकी दम्बस्वत उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि दिवालियेका प्रमाण खुदो अदालतमें न हो जावे । इसी उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जस्वादानने प्रस्तावके लिये अपनी स्वीकृति दी भी या शर्तें दी यह इस दफाके अनुसार दी हुई दम्बस्वतका विरोध कर सकता है परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वही कर्जस्वादान विशेष करनेके अधिकारी होंगे जिनके कर्ज सादित किये जा चुके हैं ।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस दफाके अनुसार पेश किए हुए प्रस्तावके लिये अपनी मजबूरी देनेसे पहिले आक्षिप्त एरायनीका रिपोर्टकी देखे तथा पुनराज करने वाले कर्जस्वादानके एतराकोई सुने ।

उपदफा (४) में उन दशाओंका वर्णन है जिनके उपरिष्ठ होने पर अदालत प्रस्तावको स्वीकार कर देनेसे इनकार कर देवेगी अदालत इन दशाओंमें प्रस्ताव स्वीकार करेगी—

(i) जब कि प्रस्ताव उपरिष्ठ प्रतीत न होने, या

(ii) जब कि प्रस्तावसे आश कर्जस्वादानकी लाभ पहुचनेकी सम्भावना न होनी होने, या

(iii) जब कि ऐसी शिष्टि होके जिसके अनुसार अदालत दिवालियेको दफा कनेसे इनकार कर देनेके लिये बाध्य होवे । अग्रेजी एवटर्की इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग है जिससे यह समझना चाहिये कि इस उपदफामें बतलाई हुई बातोंके होने पर प्रस्ताव हमिल मजूर नहीं किया जावेगा ।

उपदफा (५) में उन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत प्रस्ताव उस समय तक मजूर नहीं करेगी जब तक कि दिवालिया मजूर कर्जस्वादानके कर्ज रुपयेमें चार आने चुकाने जायेका उचित प्रबन्ध जयान्त आदिसे न कर दिया गया हो । इस उपदफाका प्रयोग सही समय किया जावेगा जब कि वाञ्छयात ऐसे अवस्थित होवें जिनके उपरिष्ठिके कारण अदालत दफालका हुक्म देनेसे इनकार कर सकती हो अथवा उसके लिये जूट लगा सकती हो अथवा समझ-बूझ सकती हो ।

उपदफा (६) में पेशा अदा किये जाने योग्य कर्जोंकी अदमनीका प्रबन्ध पेशर ही किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है यदि इस व्यवस्था प्रबन्ध तरकीबी या रसीममें न होने तो बह मसूला नदी किया जावेगा अग्रणी एवटर्की प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दने यहाँ समझना चाहिये कि उनका प्रबन्ध पेशर किया जायाही पण आवश्यक है । उपदफा (८) से लेकर ९ तक जिन नियमोंका वर्णन है उनका ध्यान रखते हुए यदि मामला अन्य किसी प्रधानका होवे तो अदालतकी अधिकार है जिस मताका हुक्म चाहे दे देने अर्थात् अवसर न बाक्यातको देखते हुए वह अपनी रज्जनुसार वांछित हुक्म दे सकती है ।

दफा ३० प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुकम

(१) यदि प्रस्ताव मंजूर किया जावे तो उसकी शर्तें अदालत अपने हुकममें लिख देवेगी और दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम की मसूखीका हुकम दिया जावेगा और दफा २३ की उपदफा (१) व (३) के नियम इसके पश्चात् लागू होंगे और वह तसफीया या तय होने की स्कीम स्वयं कर्जख्वाहों पर उस हद तक लागू होगी जहां तक उसका सम्बन्ध उनके उन कर्जोंसे है जो दिवालिये की कार्यवाही के सम्बन्धमें साबित किये जा सकते हैं ।

किसी सम्बन्धित व्यक्ति के दूरव्वास्त देने पर तसफीया या तय किये जाने वाले स्कीमके नियमोंकी पाबन्दी अदालत द्वारा कर्ण आसकती है और ऐसी दूरव्वास्त पर दिये हुए किसी हुकमकी उलूती करने पर अदालत की तौहीन (Contempt of Court) समझी जावेगी ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मसूखी या तो पूरा कर्जों का दिया जाने पर अथवा तसफीया जिसका उल्लेख दफा २८, २९ व ३० में है उसके अनुसार हो सकती है । इसके विपरीत यदि कोई नाइमी सप्तसात हो जावे तो उसके न तो कर्जोंकी पूरी अदायगीही सम्झी जावेगी और न वह तसफीयाही सम्झा जावेगा, दफा—43 Mad 71. इस दफाके अनुसार यदि तसफीया अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जावे तो उसकी सब शर्तें अदालतके हुकममें दे दी जावेगी अमली एक्तरकी इस दफाके प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें यह धरती भानि प्रकट है कि उन शर्तोंका अदालतके हुकममें दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार तसफीया स्वीकार करने पर दिवालिया करार दिया जाने वाला हुकम मसूखी कर दिया जावेगा । दफा २३ के उपदफा (१) व (३) में बतलाये हुए नियम मसूखीका हुकम होने पर लागू होंगे अर्थात् दफा २३ की उपदफा (१) के अनुसार मसूखीका हुकम होनेसे पहिले किये हुए सब रोदे व हुकम जैसेके जैसे बच रहेंगे तथा आयादाद दिवालिये या अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्देगीमें अदालतके हुकमके अनुसार आयावेगी और दफा २३ की उपदफा (३) के अनुसार मसूखीके हुकमकी मुतादबी की जावेगी । इस दफाकी यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मसूखीका हुकम हो जाने पर तसफीया या स्कीम जिसके आधार पर मसूखीका हुकम दिया गया हो दिवालियेके सब कर्जख्वाहों पर लागू होगा अर्थात् उन कर्जख्वाहोंके उन सब कर्जोंके सम्बन्धमें लागू होगा जो दिवालियेके कार्यवाहीमें साबित किये जा सकते हैं । ऊपर बतलाये हुए बातका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि वह कर्जख्वाह जि होने तसफीयाके स्वीकार न किया हो अथवा वह कर्जख्वाह जो हाजिर हो व हुए हो तसफीयाके बावद होंगे । दफा २८ के अनुसार तसफीयाके प्रस्तावका मोटिस उन् सब कर्जख्वाहोंके पास भेजा जाना बतलाया गया है जिनके नाम कर्जख्वाहोंकी सूचीमें दिखलाये गये हों तथा उन कर्जख्वाहोंके पास भी भेजा जावेगा जिन्होंने अपना कर्जा साबित किया हो इस प्रकार तसफीयाके प्रस्तावकी सूचना दिवालियेके सब कर्जख्वाहोंके पास पहुँचानेकी व्यवस्था की गई है और इसी कारण उन कर्जख्वाहोंके बादेमें एतादाद करनेका कोई अवसर नहीं है । दफा २८ में यह भी बात बतला दी गई है कि यदि बहुमतसे कर्जख्वाहान प्रस्तावकी स्वीकार करल और स्वीकार करने वालोंका जहाँ कुल कर्जोंके हानि चौथाईसे अधिक होवे तो मान लिया जावेगा कि सब कर्जख्वाहानने प्रस्तावकी स्वीकार कर लिया है । दफा ३८ में बतलाये नियमोंके अनुसार कर्जख्वाहों द्वारा प्रस्तावका स्वीकृति हो जाने पर फिर अदालतके सामने वह प्रस्ताव पेश होगा और यह दफा २९ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जख्वाहानकी सूचना देनेके बाद अदालतकी मजूरी पावेगा । इसलिये यह उचित समझा गया है कि अदालतकी मजूरी होने पर तसफीया या स्कीमकी पाबन्दी सब कर्जख्वाहों पर उस हद तक होना चाहिये जहाँ तक उनके उन कर्जोंसे सम्बन्ध है जो अदालत दिवालियामें साबित किये जा सकते हैं । उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तसफीयाके सम्बन्धमें दिये हुए हुकमको न माने तो उसके अदालत की तौहीन सम्झी जावेगी ।

दफा ३१ दिवालियेको दुबारा दिवालिया करार देनेके अधिकार

(१) यदि ऊपर लिखे अनुसार स्वीकार की हुई स्कीम या प्रस्ताव में बतलाई हुई किसी क्रिस्त की अदायगी में ग़लती की जावे या अदालत को मालूम होवे कि बिला वेदन्साफीके या बिना देर किये हुए वह तस्फीया व स्कीम अमल में नहीं लाई जा सकती है या अदालत की स्वीकृति थोड़ा देदी से ले गई है तो अदालत यदि वह उचित समझे तो किसी सम्बन्धित व्यक्ति के दरखास्त पर कर्जदार को दुबारा दिवालिया करार दे सकती है और तस्फीया या स्कीम को रद्द कर सकती है। और इस पर दिवालिये की जायदाद आफिशल एसायनी की सुपुर्दगी में आ जायेगी परन्तु इसका कोई प्रभाव उन ट्रान्सफरों (Transfer) पर या उन अदायगियों पर विद्यमान रूप में नहीं पड़ेगा जो बाकायदा मंजूरकी हुई स्कीम या तस्फीयेके अनुसार किये जा चुके हों।

(२) जब कि कोई कर्जदार उपदफा (१) के अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो साबित किये जाने योग्य यह सब कर्जें जो दुबारा दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले लिखे गये हैं दिवालियेकी कार्रवाईके सिलसिलेमें साबित किये जायेंगे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया तरायेकी शर्तों की पाबन्दी न की अथवा तस्फीया थोड़ा देदी में प्रचल करारा गया हो या वह क्रायिक पाबन्दी न समझा जावे तो अदालत तरायेकी मंजूरीके हुक्मके मंसूख कर कर्जदारको फिरसे दिवालिया करार दे सकती है क्योंकि कर्जदार अपनी चालाकियोंसे काम नहीं उठा सकता है और न कर्जदारोंकी हक़तान ही किसी खास ग़लतीकी वजहसे पहुँचाया जा सकता है। दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर कर्जदार उन्हें शर्तों की पाबन्द समझा जावेगा जिन शर्तों की पाबन्द वह पहिले मर्तबा दिवालिया करार दिया जाने पर हुआ था। उसकी जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आगबग परन्तु तस्फीयेकी मसूखीका हुक्म होनेसे पहिले तस्फीयेके अनुसार जो काम या सोदे किये गये होंगे वह सब बदस्तूर बन रहेंगे व ठीक समझे जायेंगे।

उपदफा (२) के अनुसार यह सब कर्जें भी दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर साबित किये जा सकेंगे जो तराये या स्कीमकी मंजूरीके पश्चात् तथा उस मंजूरीके हुक्मकी मसूखीसे पहिले किये गये हों। इस प्रकार तरायेके बाद बाले कर्जेंकाही भी दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा तस्फी प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे।

दफा ३२ तस्फीये या स्कीमका प्रभाव

तस्फीये या स्कीमके स्वीकार किये जाने पर भी उसका कोई प्रभाव किसी कर्जेंद्वाराके ऐसे कर्जों या जिम्मेदारियों पर नहीं पड़ेगा जिनसे बहाल होने पर भी इस एक्टके नियमोंके अनुसार उद्धार नहीं हो सकेगा जब तक कि वह कर्जेंकाही तस्फीया या स्कीममें अपनी स्वीकृति न दे देवे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि तस्फीया या स्कीमके मंजूर होने पर भी उसकी पाबन्दी ऐसे कर्जों पर लागू नहीं होगी जो दिवालियाके नज़ाम होने पर भी जिनके ऐसे कर्जें रहेंगे क्योंकि उनसे हुए नहीं माने जायेंगे जब तक कि उनके कर्जेंकाही तस्फीया या स्कीममें मंजूर न कर लें। दफा ४५ में उन कर्जोंका उल्लेख है जिनसे दिवालिया बहाल होने पर भी बर्हि

नहीं समझा जावेगा । दफा ४५ वी उपदफा (१) के प्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) में द्रो कर्ते बतलाये गये हैं सूक्ष्ममें वह कर्ते यह हैं सरकारी कर्ज, घांतेसे लिया हुआ कर्ज, घांसेने डूहाया हुआ कर्ज न जानना कौनदारीने अनुसर दिखाने मुजबिदा कर्जों । परंतु इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि एन कर्जका पाने वाला कर्जाल्वाह तरकीब या रबीमको मनूर कर लेवे तो उस पर उस तरकीब या रबीमरी पाने दी मनूर कर लनेके बाद उसी प्रकार हागी गित प्रकार अन्य कर्जवाहों पर ।

दिवालिघेकी ज्ञात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

दफा ३३ जायदादके बतलाने व उसको वसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालिघे के कर्तव्य

हर एक दिवालिघेका कर्तव्य होगा कि वह बीमारी अथवा किसी दूसरे पर्याप्त कारणसे न रुक जावे तो वह कर्जख्वाहोंकी उस मीटिंगमें हाजिर होगा जिसमें आफिशल एसायनी उसकी उपस्थिति आवश्यक समझे और मीटिंग जिस प्रकार चाहेगी उसको उस प्रकारका बयान या इत्तला देना पड़ेगा ।

(२) दिवालिघेका कर्तव्य होगा कि वह निम्न लिखित कामोंको उस प्रकार करे जिस प्रकार आफिशल एसायनी या विशेष मैनेजर उससे कराना चाहे अथवा जिस प्रकार निर्धारित किया गया हो या जिस प्रकार अदालत अपने विशेष हुकम द्वारा किसी विशेष मामलेंके सम्बन्धमें करनेका हुकम देवे या जिस प्रकार करनेका हुकम आफिशल एसायनी, विशेष मैनेजर किसी कर्ज-ख्वाह अथवा किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर दिया जावे:—

(ए) अपनी जायदादकी फिहरिस्त देवे कर्जख्वाहों व कर्जधारोंकी फिहरिस्त दाखिल और अपने लेन व देन वाले कर्जोंकी फिहरिस्त भी दाखिल करे ।

(बी) अपनी जायदाद अथवा अपने कर्जख्वाहोंके सम्बन्धमें बयान देवे ।

(सी) आफिशल एसायनी या विशेष मैनेजरके सम्मुख बतलावे हुए समय व स्थानों पर हाजिर होवे ।

(डी) मुफतारनामें, दस्तावेज इन्तकाल जायदाद और दूसरी दस्तावेजें सहरीर करे ।

(ई) अपनी जायदाद तथा उसको कर्जख्वाहानके धीचमें बांटे जानेके सम्बन्धमें की जाने वाली सब बातों व कामोंको करे ।

(३) दिवालिघा अपनी शक्ति भर अपनी जायदादको वसूल कराने तथा उसकी क्रीमत अपने कर्जख्वाहोंमें बांटे जानमें मदद देवे ।

(४) यदि दिवालिघा जानते हुए इस दफामें बतलाये हुए कर्तव्योंको पालन नहीं करेगा या वह अपनी जायदादके किसी हिस्सेका कब्जा जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे और जो उसके कर्जख्वाहोंमें बांटी जासकती हो आफिशल एसायनीको नहीं देवे तो वह अल्लावा और सज़ाओंके जो उसको दी जासकती हों अदालतकी तौहीन करनेका दोषी होगा और उसको उसके अनुसार दण्ड दिया जासकेगा ।

व्याख्या—

इस दफा में दिवालिये के उन कर्तव्यों का उल्लेख है जो उसे अपनी जायदाद पर तब तक करने तथा उसके बर्तन करने के सम्बन्ध में करना आवश्यक है तथा निम्न न करने पर वह दोषी समझा जा सकेगा और दण्ड का अधिकारी होगा। अथवा एकदम उपद्रव (१), (२) व (३) में (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें यह तात्पर्य समझना चाहिये कि दिवालिया उन उपद्रवों में बतलाये हुए नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है किन्तु उनकी पाबन्दी उसने लिये आवश्यक है।

उपद्रव (१) के अनुसार यदि आकिशक एसायनी दिवालिये से कर्मस्वाहों की किसी मीटिंग में उपस्थित होने के लिये तो उस उस मीटिंग में उपस्थित होना पड़ेगा तथा मीटिंग में उससे जो बयान या इतरा चाहें जावगी वह उसे देना पड़ेगा।

उपद्रव (२) में यह बतलाया गया है कि दिवालिये को क्लार्क (ए), (बी), (सी), (डी) व (ई) में बतलाई हुई बातों का जवाब देना होगा तथा उनमें बतलाये हुए कामों को करना होगा। इन शब्दों में बतलाये हुए कामों को करने के लिये आकिशक एसायनी, व विशेष मैनेजर कह सकता है अथवा अदालत स्वयं इसके लिये हुक्म दे सकती है।

फलाज (ए) के अनुसार जायदादी केहरिन्, कर्मस्वाहों व कर्मदायों की केहरिस्त तथा उनकी दिये जाने वाले या बनने बसूठ किये जाने वाले कर्मों का प्रयोग मा ॥ जासकता है।

फलाज (बी) के अनुसार जायदाद तथा कर्मस्वाहों के सम्बन्ध में दिवालिये के बयान लिये जासकते हैं।

फलाज (सी) के अनुसार दिवालिये को आठ घण्टा एसायनी अथवा विशेष मैनेजर के पास चाहें हुए समय व बतलाई हुई जगह उपस्थित होने की वहा जासकता है।

फलाज (डी) के अनुसार दिवालिये से क्लार्क नाम के, क्लार्क इन्टरकाज जायदाद तथा दूसरे क्लार्क का उल्लेख जासकते हैं।

फलाज (आई) के अनुसार दिवालिये से उसकी जायदाद बसूठ किये जाने तथा उसके कर्मस्वाहों में बांटे जाने के सम्बन्ध में सभी काम व बातें जो आवश्यक समझ पड़ कहें जासकते हैं।

इस उपद्रव में बतलाये हुए कामों को करने के लिये अदालत में कर्मस्वाह या अन्य कोई सम्बन्धित व्यक्ति भी दखलाने से बचा है। आकिशक एसायनी या विशेष मैनेजर भी यदि अपने अधिकारों से बाहर कोई काम इस दफा के अनुसार करेगा तो अदालत में दखलाने से बचा है और तब अदालत अपने हुक्मों के अनुसार दिवालिये को उस काम के करने के लिये मजबूर कर सकती है।

उपद्रव (३) में दिवालिये का यह कर्तव्य बतलाया गया है कि जिसकी ससे हो सकेगी उसकी मदद अपनी जायदाद व बसूठ करने तथा उसके कर्मस्वाहों में तकलीफ किये जाने में करेगा।

उपद्रव (४) में यह दिया हुआ है कि यदि जाने वृत्त कर दिवालिया इस दफा में बतलाये हुए कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या वह अपने कर्तव्यों को कुछ या कुछ जायदाद से नहीं छोड़ेगा तो वह इस प्रकार किये हुए अपराध का निर्दोषी नहीं होगा और दण्ड पर दण्ड पावेगा और साथ ही साथ वह अदालत की तौहिन (Contempt of Court) का दोषी समझा जावेगा और इस अपराध का भी दण्ड पासवेगा। यदि आकिशक एसायनी दिवालिये से कोई काम बचना चाहें तो वह जाननी भी कर सकता है परन्तु यदि वह अदालत से दिवालिये का काम न बनने का बयान देना चाहिये तो लिख कर हुक्म देना चाहिये और उसके साथ साथ यह भी नोटिस देना चाहिये कि यदि हुक्म की तामीन नहीं की जावेगा तो अदालत तौहिन देने की वहाँ पर अमलमें लार्ड जावेगा। (दो—47 Cal. 56.)

दफा ३४ दिवालियेकी गिरफ्तारी

(१) निम्न लिखित बातोंके उपस्थित होने पर अदालतको अधिकार होगा कि वह स्वयं ही या आफिशल एसायनी अथवा किसी कर्जव्याहक दरखास्त देने पर दिवालियेकी पुलिस आफिसर द्वारा अथवा अन्य किसी नियुक्त किये हुए अफसर द्वारा चाएटके जुरिय गिरफ्तार करा लेंगे और उसे दीवानीकी जेलमें भेज देंगे या यदि वह जेलहीमें होवे तो उसको उस समय जब तक कि अदालत उचित समझे वहां बन्द रखनेका हुक्म दे देंगे ।

(ए) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये है कि वह भाग गया है या वह इस कारण भागने वाला है कि जिसमें उसका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें न लिया जा सकें या वह अपने विरुद्ध फीजाने वाली दिवालियेकी कार्याहोंको डाला चाहता है या उनमें देर करवा चाहता है या उनमें उलझन पैदा कराना चाहता है, या

(बी) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये उपस्थित है कि वह अपनी जायदादको इस नीयतसे हटाने वाला है जिसमें आफिशल एसायनी द्वारा उस पर कब्जा लिये जानमें रुकावट पड़े या देर होवे या इस बात पर विश्वास करने के लिय पर्याप्त कारण होवे कि उसने अपनी किसी जायदाद या कित्तियों या दस्तावेजों या अन्य सहरीयोंको जिनसे उसकी दिवालियेकी कार्याहोंके सम्बन्धमें उसके कर्जमुद्दाह कायदा उठा सकते हैं छिपा दिया है अथवा छिपाने वाला है ।

(सी) यदि वह यिला आफिशल एसायनीकी आज्ञाके अपनी पचास रुपयेसे ऊपरकी कीमत वाली जायदादको हटा देंगे ।

(२) इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जानेके पश्चात् यदि कोई अदायगी कीजाये या कोई तस्फीया किया जावे या जमानत दी जावे और वह धोखादेहीने तर्तीह देने वाले सौदे इस एन्टके नियमोंके अनुसार होवे तो वह बरी नहीं होंगे अर्थात् वह धोखादेहीसे की हुई अदायगी, तस्फीया या जमानत समझी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें बड़े वज्रात बतलाये गये हैं जिनके होने पर अदालत, दिवालियेकी गिरफ्तार करा सकती है या यदि बड़े जेलमें हीन हो उते किसी नियत समय तकके लिये वहां भेके जानेका हुक्म दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कानूनी रवय ही कर सकती है अथवा आफिशल एसायनी या किसी कर्जवाहके दरखास्त देने पर कर सकती है । इस दफाके अनुसार नारण्ट किसी पुलिस आफिसर अथवा किसी दूसरे विधीयति किये हुए अफसरके नाम दिया जासकता है इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जाने पर दिवालिया दीवानीकी जेलमें रखा जावेगा ।

उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (बी) व (सी) में वह नौ नरखई गई हैं जिनके होने पर या किये जाने पर अदालत गिरफ्तारीका हुक्म या जेलमें भेके जानेका हुक्म दे सकती है ।

क्लॉज (ए) में यह बतलाया गया है कि जब दिवालिया भाग गया हो या भागने वाला हो जिसमें उसका बयान न हो सके

या अप किसी प्रकार से उस विरुद्ध होने वाली दिवालियेकी कार्रवाई रुकने पर सब से अधिक ऐसा बात का निश्चय होने पर न्याय जागे करनी कार्रवाई कर सकता है ।

पंजाब (बी) वे अनुसार यदि दिवालिये जायदादकी हथ दिया हो । तथा दिया हो या हथान वाला हथे अपना उम्मे अपनी हिस्सेकी दिवाली या दूसरेकोती या दूसरी तरफकी छिद्र दिया हो या नष्ट कर दिया हो निम्न एक आफिशल एसायनीको कम्पा न मिल सके या निम्न उस विरुद्ध दिवालियेकी कार्रवाई सम्पन्न हो न उठाया जाय तो अधिकतम ऐसा बातों का निश्चय दिवले जाने पर निम्नतादीकी कार्रवाई कर सकती है ।

पंजाब (सी) के अनुसार यदि दिवालिये बिना आफिशल एसायनीको गुप्त पक्षन हथेकी कार्रवाई करिष्य गुप्त हथ रवे तो भी अधिकतम बात परम्पर वगैरा जासकता है ।

उपपंजा (२) में यह बतलाया गया है कि हम दाक अनुसार निम्नता किये जानेके बाद यदि दिवालिप्या कार्रवाई करी तस्वीया करे या जमानत दवे और वह अपायगी, तरफिया या अमानत धातादेईस तर्गई दिया जाने वज से सौदा हथे तो वह सौदा बसा प्रकारका याता धोखादेईस तर्गईका सौदा ही माना जावेगा अर्थात् काबिल मसूदा होगा ।

दफा ३५ खतोंका दूसरी जगहके लिये भेजा जाना

जब कि आफिशल एसायनी दरमियानी, रिस्तीपर नियुक्त किया गया हो या जब दिवालिप्या करार दिये जाने वाला हुक्म दे दिया गया हो तब आफिशल एसायनीकी दरखास्त पर अदालत को अधिकार है कि वह समय समय पर नियत समयके लिये जो तीन महीनेसे अधिक न होगा जैसा अदालत मुनासिब समझे यह हुक्म दे देवे कि दिवालिप्येके नाम आने वाले सब रजिस्ट्रीगुदा या विला रजिस्ट्रीवाले खत, पार्सल या मनीआर्डर ओ फर्जदारके नाम किसी जगह या जगहोंके पतेसे आवें यह ब्रिटिश भारतमें स्थित डाकघराने वालों द्वारा आफिशल एसायनीके पास भेज दिये जावेंगे या अन्य किसी व्यक्तिको दे दिये जावेंगे जैसा अदालत हुक्म देवे और तब ऐसा ही किया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालिप्येके खत, पार्सल व मनीआर्डरके लिये आफिशल एसायनीको दिये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है । इन दफाके अनुसार हुक्म दरमियानी रिस्तीपर नियुक्त किये जाने अथवा दिवालिप्या करार दिये जानेपर हुक्म होनेके पश्चात् दिया जायसकता है । अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म दे न मई नम अधिक समयके लिये नहीं दे सकता है । अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म दनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टों में इस दफामें प्रयोग दिये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार अदालत इस प्रकारका हुक्म बाख्तानेके अफमयके नाम दे सकती है कि दिवालिप्येके नामसे जाने वाले रजिस्ट्री गुदा व विला रजिस्ट्री गुदा खत, मनीआर्डर या पार्सल किसी निश्चित अवधि तक बजाय दिवालिप्येके आफिशल एसायनी अपना अन्य किसी व्यक्ति को दिये जाने अथवा उनके नाम करके भेज दिये जावें । इस प्रकार दिये हुए हुक्मकी पाबंदी दाक खाने वालोंकी बरना होगी जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें दिये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य निश्चयता है ।

दफा ३६ दिवालिप्येकी जायदादका पता लगाना

(१) दिवालिप्या करार दिये जानेके पश्चात् किसी समय भी आफिशल एसायनी या ऐसे कर्मचारीके दरखास्त देने पर जिसेने कि अपना फर्ज सीबत कर दिया है अदालत निर्धारित

नियमोंके अनुसार दिवालिये या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिको तलब कर सकती है जिसके कर्जमें दिवालिये की जायदाद होनेका शरु होवे या जो दिवालिये की कर्जदार समझा जावे अथवा जो अदालतकी रायमें दिवालिये या उसकी जायदाद या उसके व्यवहारके सम्बन्धमें इत्ला दे सके और अदालत उस व्यक्तिमें उन दस्तावेजोंको भी जो दिवालिये उसकी जायदाद या व्यवहारके सम्बन्धमें होवे तथा जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे दाखिल करा सकती है ।

(२) यदि इस प्रकार तलब किया हुआ कोई व्यक्ति समुचित द्रव्य दाखिल किये जानें पर नियत किये हुए समय पर अदालतके सम्मुख आनेसे इनकार करे या ऐसी दस्तावेज दाखिल करनेसे इनकार करे और उसके लिये कोई ऐसी कानूनी दवावट पेशीके समय न बतलावे जिसे अदालतने स्वीकार कर लिया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिको चारण्ड द्वारा गिरफ्तार करा कर ध्यानके लिये लाये जानेका हुक्म दे देवे ।

(३) इस प्रकार लाये हुए व्यक्तिसे अदालत, दिवालिये तथा उसकी जायदाद व व्यवहारके सम्बन्धमें ध्यान ले सकती है और ऐसा व्यक्ति अपनी पैरवी बमौल द्वारा करा सकता है ।

(४) यदि ऐसे व्यक्तिके ध्यानसे अदालतको विश्वास हो जावे कि वह दिवालियेका अग्रणी है तो वह आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर ऐसे व्यक्तिको यह हुक्म दे सकती है कि वह व्यक्ति अपने कर्जका रुपया नियत किये हुए समय पर व नियत ढंगसे जैसा कि अदालत उचित समझे अदा कर देवे या उस कर्जका कोई हिस्सा उस कर्जकी पूरी अदायगीमें या योंही जैसा अदालत उचित समझे मय उसके धनानोंके सम्बन्धमें पड़े हुए सचेंके या विला उसके आफिशल एसायनीको अदा कर देवे ।

(५) यदि उस व्यक्तिके ध्यानसे अदालत को यह विश्वास हो जावे कि उस व्यक्तिके कर्जमें दिवालिये की कोई जायदाद है तो अदालत आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर यह हुक्म दे सकती है कि वह व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद या उसके कोई हिस्सा नियत किये हुए समय पर व नियत किये हुए ढंगसे नियतकी हुई शर्तोंके अनुसार जैसा अदालतको उचित प्रतीत हो आफिशल एसायनीको दे देवे ।

(६) उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील उसी प्रकार करायें जायेंगी जिस प्रकार जाबता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री या जायदाद पर क़ाज़ा देने वाली डिक्री इजराय करायें जासकती है ।

(७) यदि कोई व्यक्ति उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील करते हुए कोई अदायगी करे या जायदाद सुपुर्दगीमें देवे तो वह इस प्रकारकी अदायगी या सुपुर्दगीसे उस कर्ज व उस जायदाद सम्बन्धी सब ज़िम्मेदारियोंसे बरी हो जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदाद बरामद किये जानेके सम्बन्धमें नियम दिया हुआ है । अदालत उपदफा (१) के अनुसार बर्तारद आफिशल एसायनी या ऐसे कर्जकारोंके दाखला देने पर बरेगी जितने कि अपना कर्ज सवित कर दिया होवे । उपदफाके अनुसार बर्तारद दिवालिआ करार दिया जाने वाला हुक्म होनेसे पश्चात् बीनासकेंगी ।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत, दिवालय अथवा अथ किसी व्यक्ति को जिसके कर्जमें दिवालियेरी जायदाद होवे या जो दिवालियेरी कर्जदार होवे अथवा जो दिवालिये उसके व्यवहार या उसकी जायदादके सम्बन्धमें हस्तान् दे सकता है तलब कर सकता है और इस प्रकार तलब किये हुए व्यक्तिसे दिवालिये उसके व्यवहार अथवा उसकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली दरावेजोंके भी अदालत दाखिल करा सकती है ।

उपदफा (२) में यह दिशा हुआ है कि यदि नियमानुसार तलब किये जाने पर कोई व्यक्ति न आवे या हस्तान् न पेश करे तो अदालत उसके लिये वारण्ट जारी कर सकती है परन्तु साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि यदि किसी पक्षीस कारणसे उसके आनेमें रुकावट पड़े गई हो जैसे कि भागी आदिसे अथवा यदि किसी कारणसे वह तलबरी हुई दस्तावेज पेश करनेमें असमर्थ हो तो उसके विरुद्ध इस उपदफाके अनुसार वारण्ट नहीं जारी किया जाना चाहिये ।

उपदफा (३) के अनुसार अदालत उस प्रकारसे तलब किया हुआ व्यक्ति का बयान दिवालिये उसके व्यवहार तथा उसकी जायदादके सम्बन्धमें ले सकती है । इसी उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किया हुआ व्यक्ति अपनी पेशगीके लिये बचाल भी कर सकता है ।

उपदफा (४) में दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किये हुए व्यक्ति के बयानसे यदि यह माहूम होवे कि उस दिवालियेरी कर्ज चुकाना हे तो अदालत आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर उस व्यक्ति लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह दिवालियेरी कर्ज नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए दग पर आफिशल एसायनी को चुका दे । उस व्यक्तिसे पूरा कर्ज या पूरे कर्जों अदायगीमें कुछ कम भी अदालतके हुक्मक अनुसार लिया जासकता है । उस व्यक्तिने तब प्रसार बयान लिये जानिक सम्बन्धमें जा खर्च हुआ है वह भी वसूल किया जासकता है ।

उपदफा (५) में यह मतलब गया है कि इस दफाके अनुसार तलब किये व्यक्ति के बयानसे यदि यह माहूम होवे कि उसके कर्जमें दिवालियेरी कोई जायदाद है तो आफिशल एसायनी की दरखास्त पर अदालत उस व्यक्ति के लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह नियत किये हुए समयमें व नियत दग पर कुल या कुछ जायदाद आफिशल एसायनी को दे देवे ।

उपदफा (६) में यह मतलब गया है कि उपदफा (३) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तात्कालिक प्रसार कराई जायगी जैसे कि जायता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिका या जायदाद पर क्रान्ता लन वाजी डिक्रीकी इजायत कराई जासकती है जायता दीवानीके आर्डर २१ में डिक्रीके इजायत करनेका वर्णन है और तब आर्डरके रूल ३० में रुपयेकी अदायगाक सम्बन्धमें दी हुई डिकाके इजायत उल्लेख किया गया है । और रूल ३१, ३५ व ३६ में जायदाद पर क्रान्ता देन वाली डिक्रीके इजायत करनेक नियम दिये हुए हैं ।

जायता दीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३० इस प्रकार है—

“ रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिकाके इजायतमें यदि तब दीवानीकी जेलमें बन्द किया जासकता है अथवा उसकी जायदाद कुर्क व नीलाम कराई जासकती है या दोनों प्रकार की कार्रवाई की जासकती है । वह डिका जिसमें कि कोई दूसरा दारदारी (Relief) दी हुई हो परन्तु साथ साथ यह भी दिया है कि उसके न करने पर रुपयेकी अदायगीकी जायदाद रुपयेका अदायगाक सम्बन्धमें दी हुई डिका समझा जायगा ”

जायता दीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३१ इस प्रकार है मनकूला जायदादके कर्जके सम्बन्धमें—

• (१) जब कि डिका किसी खास मनकूला जायदाद या उसके किसी हिस्सेके सम्बन्धमें होवे तो उसकी इजायत उस जायदाद या उसके उस हिस्से पर क्रान्ता लेने व उसका बच्चा उस व्यक्ति को देने जिसने हुक्म डिक्री हावे या उसकी आस

किसी अन्य व्यक्ति को देने में की जा सकती है या यदियूनियो दीवानी की जलमें बद करने या उसकी जायदाद कुर्क करने या दोनों प्रकारसे कार्यवाई करनेसे की जा सकती है ।

(२) जब कि कूल (१) के अनुसार कुर्क की हुई जायदाद ल याह तक कुर्क रही हो और यदियूनियो किसी की तागील न की हो तो डिफेंडरके नीलामके नियम दरखास्त देने पर वह जायदाद नीलाम कर दी जावेगी और उस नीलामके दायरेमें डिफेंडर बतलाई हुई तादादके अनुसार या अदा तादाद न बतलाई गई हो तब तक उसके इन्के दिखसे जता अदायत वचित समझे डिफेंडरको दिया सकता है और वकील कया दरखास्त देने पर यदियूनियो दिया जावेगा ।

(३) जब कि यदियूनियो किसी तागील करदी होवे और किसी इतराया नह मर्च जो उसे अदा करता चाहिये या अदा कर दिया हो या जब कि ज महीने बीतने पर डिफेंडरके नीलामके नियम दरखास्त न दी होवे या उसकी या हुई दरखास्त नामजूर करदी गई हो तो कुर्क समाप्त हो जावेगा ।"

जायदादीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ कूल ३५ इस प्रकार है गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें—

" (१) जब कि किसी किसी गैर मनकूला जायदाद पर कृपा देनेके सम्बन्धमें होवे तो जिनके हकमें किसी है उसकी सम पर कृपा दिलाया जावेगा या उसकी जायते निष्कृत करके हुए किसी अन्य व्यक्ति को कृपा दिलाया जावेगा और यदि आवश्यकता होगी तो ऐसे व्यक्ति को हटा कर कृपा दिलाया जावेगा जो डिफेंडरके लिये पावद हो वास्तु ब्रह्मा देनेसे इनकार करे ।

(२) जब कि किसी समुक्त कृपाके सम्बन्धमें होवे तो ऐसा कृपा जायदादके किसी आम जगह पर कृपाके वारंथ की नकल चिपकवा देनेसे तथा मुनादी का देने या अन्य किसी प्रचलित ठगरी कार्यवाई करनेसे दिखवाया जावेगा ।

(३) जब कि किसी समाप्त या बद जगहका कृपा देना होवे और जिस व्यक्ति का उस पर कृपा होरे और वह किसी की पाव दीके नियम वाप्य होने परतु आमानीमें अदर न पुखने देने को अदायत अपने अकसोंके लिये परधानशीन औरतोंको जो आम लोगमें न निकलनी होवे निजलनेवा मोरुा देने तथा कृपा देने वाले व्यक्तिसे लखित आगारी देनेके बाद तादाद तुडवा कर या निजलनी तुडवा कर या निजल तुडवा कर या अन्य किसी आवश्यक दगसे डिफेंडरको क ज दे सकती है ।"

जायदादीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ कूल ३६ इस प्रकार है—

" जब कि किसी किसी गैर मनकूला जायदाद पर कृपा देनेके लिये होवे और वह जायदाद डिफेंडरको कानेमें होवे या अन्य किसी व्यक्तिके सम्बन्धमें होवे जो वह हक सकता हो और वह हम डिफेंडरके अनुसार जगह खाली करनेके लिय वाप्य न होने तो ऐसा कृपा अदालत जायदादकी किसी आम जगह पर कृपाके वारंथ चिपकवा कर या मुनादी कृपाके अथवा अन्य किसी प्रचलित दगसे कानेकी घण्टा करा देगी और उसमें जायदादके सम्बन्धमें दी हुई किसीका काफ़ी हवाला होगा । "

अब ऊपर दिये हुए आर्डर २१ के कूल ३०, ३१, ३५ व ३६ की देखनेसे यह मालूम हो जावेगी कि इस दफा की उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुकम भी इसी प्रकार तागील बताये जायेंगे ।

उपदफा (७) में यह दिया हुआ है कि दफाके हुकमके अनुसार यदि कोई काम किया जावेगा या अदायती की जावेगी अथवा कृपा दिया जावेगा तो वह पर्याप्त समझा जावेगा और काम करने वाला व्यक्ति उस कामके सम्बन्धमें आपदा कर निम्नदायिते नही समझा जावेगा अथवा यदि उसने कर्जा चुका दिया है तो उससे दुबारा कर्जा नहीं सम्भू किया जासकता या यदि उसने जायदाद पर कृपा दे दिया है तो दुबारा कृपा जायदाद पर नहीं माया जावेगा । मगरा हाईकोर्ट ने यह तय किया या कि इस दफाके अनुसार अदालत दिवालय तथा किसी लॉकर व्यक्तिके मायम होने वाले हक सम्बन्धी झगरी को तब नहीं छोड़ी, देखा—27 May 60 इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये अदायतमें जो दरखास्त

दी जाने वसमें सूक्ष्म तरीके यह दिला देना चाहिये कि तबन किये जाने वाले व्यक्तित्व पूरा जावेगा और उस घातमे दिवा-
लियेके व्यवहार या जायदादका क्या सम्बन्ध है, देखो—44 Cal. 374 इस दफ्तेके अनुसार दिवालियेके जो बयान किये
जावेंगे वह उसके विरुद्ध चलाये हुए कानूनीके मामलेमें उसके विरुद्ध प्रयोग किये जासकेंगे, देखो—46 Cal. 996

दफा ३७ कमीशन जारी करने के अधिकार

किसी व्यक्ति के बयान लेने के लिये कमीशन व प्रार्थना रूप में पत्र जारी करने के सम्बन्ध
में अदालत को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो १६०८ ई० के जायदादीयानी की दफा २६ के
अनुसार गवाहों के बयानों के सम्बन्ध में अदालत दीयानी को प्राप्त हैं ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार अदालत दिवालिया गवाहों के बयान वसलिये कमीशन के करवा सकती है । कमीशन उसी प्रकार
जारी किये जासकेंगे जिस प्रकार जायदादीयानीके अनुसार जारी किये जासकते हैं । जायदादीयानी (१९०८) के आर्डर २६
में कमीशन जारी करने का हाल दिया हुआ है इस आर्डर के रूल १ से लेकर ८ तक गवाहोंके बयान के सम्बन्ध में जो कमीशन
जारी किये जासकते हैं उनका उल्लेख है इसके पश्चात् इसी आर्डर के रूल १५ से लेकर १८ तक कमीशन के अधिकारों आदि
का उल्लेख किया गया है ।

जायदादीयानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २६ के उक्त रूल इस प्रकार हैं:—

रूल १—अदालत अपनी अधिकार सीमा के अन्दर सवागत दालिम किये जाने पर अथवा बिना उसके कमीशन
उन गवाहों के बयान के लिये जारी कर सकती है जो इस एक्ट के अनुसार अप्रकृत में आने से बरी है या जो बीपी
अथवा कमजोरी के कारण अदालत में हाजिर होने से असमर्थ है ।

रूल २—अदालत स्वयं ही अथवा किसी फ्रीक की या खुद गवाह की दख्खानत आने पर जितकी ताईद में
हलफनामा दालिम किया गया हो या जो यों ही दी गई हो कमीशन जारी करने का हुक्म दे सकती है ।

रूल ३—यदि कमीशन किसी ऐसे गवाह के बयान के लिये जारी किया गया हो जो अदालतकी अधिकार सीमा के
अन्दर रहता है तो वह कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो अदालत की रायमें उसके लिये उपयुक्त होवे ।

रूल ४—(१) कोई भी अदालत किसी भी मामलेमें निम्न लिखित लोगों के बयान के लिये कमीशन जारी कर
सकती है:—

(ए) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा के बाहर रहता हो ।

(बी) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा की उस तारीख से पहिले छोड़ना चाहता हो जिस तारीख
पर उसका बयान देने की है । और

(सी) किसी भी सरकारी सिविल या मिलिटरी अफसर के लिये जो अदालत की राय में बिना अपने सरकारी काम
को उल्लंघन पहुँचाये हाजिर न हो सकता हो ।

(२) इस प्रकार के कमीशन हाईकोर्ट के अतिरिक्त किसी ऐसी अदालत के नाम जारी किये जा सकते हैं जिसकी
अधिकार सीमा में गवाह रहता होवे अथवा किसी वकील या ऐसे व्यक्तिके नाम जारी किये जा सकते हैं जिसे कमीशन जारी
करने वाली अदालत नियुक्त कर देवे ।

(३) कमीशन जारी करनेवाली अदालत यह भी हुक्म दे देवेगी कि आया कमीशन उसी अदालतमें लौटाया जावेगा
या उसकी मानहत किसी अदालत में ।

कल ५—यदि कमीशन जाये करनेवाली अदालत से किसी ऐसे व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन जारी कराया जावे जो बुराई इच्छा से बाहर रहता हो और उसका यह विश्वास दिया दिया जावे कि उस व्यक्ति की शहादत सच है तो अदालत कमीशन या प्रार्थना पत्र (Letter of request) जारी कर सकती है ।

कल ६—जिस अदालत के पास किसी व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन भेजा जावेगा वह अदालत उस व्यक्ति का बयान लेवेगी या उसका अनुसार बयान लिये जाने का प्रार्थन करदेगी ।

कल ७—जब कि कमीशन नाकाम्यदे गूरा कर दिया गया हो तो वह वापिस भेज दिया जावेगा और उसके साथ में उसके अनुसार ली हुई शहादत भी कमीशन जारी करनेवाली अदालत की भेज दीजवेगी यदि उसके विरुद्ध कमीशन के साथ में कोई आज्ञा न देयी गई हो और अगर ऐसा हुआ हो तो उन शर्तों के अनुसार भेजा जावेगा जो लगायी गई हैं और आगे दिये हुये कल का ध्यान रखते हुए कमीशन उसको दीया जाना तथा उसके अनुसार ली हुई शहादत मुकदमों में मिसिल में सम्मिलित समझा जावेगा ।

कल ८—कमीशनमें लिये हुए बयान उस वक्त तक सूत्रमें बतौर शहादत के नहीं पढ़े जायेंगे जब तक कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह पढ़े जानेवाले हैं अपनी सहमत न देवे परन्तु इसकी आवश्यकता निम्न लिखित मामलों में नहीं रहेगी—

(ए) यदि बयान देने वाला गवाह अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर रहता है या मर गया है या बीमारी अथवा कमजोरीकी वजहसे अदालतमें आनेसे असमर्थ है या वह ऐसा सरकारी सिविल या मिलिटरी अफसर है जो बिना अपने सरकारी कामों मुकसान पहुँचाये हुए शक्ति नष्ट हो सकता है, या

(बी) यदि अदालत आज (ए) में बतलाई हुई किसी बातके पाने जानेका हुक्म दे देवे तथा इस बातका हुक्म दे देवे कि कोई शहादत सूत्रमें पढ़ी जावेगी बिला इस बातका लिहान बिधे हुए कि बयानोंके पढ़ जाते समय वह बात जानी रही है जो बयानोंके लिये जाते समय उपस्थित थी ।

कल १५—किसी कमीशनके जारी करनेसे पाहिले यदि अदालत चाहे तो उसके खर्चके लिये कमीशन जारी करने वाले फरीकसे कतिपय खर्चके लिये रुपये दाखिल करा सकती है यह कपया नियम लिये हुए समयके अन्दर अदालतमें दाखिल कराया जासकता है ।

कल १६—इस आर्डरके अनुसार नियुक्त किया हुआ कमिश्नर यदि नियत करने समय दिये हुए हुक्मके साथ कोई बात इसके विरुद्ध न लिख दी गई हो तो निम्न लिखित काम कर सकता है—

(ए) कर्बिनेके बयान ले सकता है और किसी ऐसे गवाहके बयान भी ले सकता है जिसके वह खेद या उनमेंसे कोई पेश करे और वह किसी ऐसे अन्य व्यक्तिका बयान भी ले सकता है जो उसकी रायमें उस मामलेके सम्बन्धमें अपने बयान दे सकता हो ।

(बी) तहकीकातके लिये जो दस्तावेज आवश्यक हों उनको तलब कर सकता है व उनका मुजायना कर सकता है ।

(सी) हुक्ममें जिस जमीनका बडेल हो वहां किसी उपयुक्त समय पर जासकता है ।

कल १७—(१) इस एक्टमें गवाहोंकी तलबी इजिजी व बयानोंके सम्बन्धमें जो नियम दिये हुए हैं और उनके लिये जो सूरत व खर्च और जो दण्ड बतलाये गये हैं वह सब बातें उन लोगोंके लिये भी लागू होंगी जिनकी शहादत कमिश्नर लिया चाहे या जिनसे दस्तावेज तलब कराया चाहे । यह सब बातें उन सब कमीशनोंके लिये लागू होंगी जो चाहे इजिजी इजिजी अदालतसे या उसके बाहरकी किसी अदालतसे जाते किने गये हों इस कलमें लिये कमिश्नरकी अदालत दीवानी मान लिया जावेगा ।

(२) कमिश्नर, इन्फेन्टोंके अतिरिक्त अन्य किसी अदायगीमें किसी अधिकार सीमामें गवाह रहता हो गवाहके लिये सम्मन जारी करा सकता है। उसके जारी करनेकी उस आवश्यकता प्रतीत होने और वह अदालत अपनी इच्छाके अनुसार जमा उसे वाचन व ठीक प्रतीत होगा वैसा इसलानामा जारी करेगी।

कूल १८—(१) जब कि इस आर्डरके अनुसार कमीशन जारी किया गया हो तो अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि फर्तिन रख या अपन एजेंट या वकीलके जरिये कमिश्नरके सामने हाजिर होंगे।

(२) जब कि फर्तकैममें से सब या कोई इस प्रकार कमिश्नरके सामने हाजिर न होवे तो कमिश्नर उनकी नामानुरूपी ही में कार्रवाई कर सकता है।

कमिश्नरकी विपुल आदिने सम्बन्धों कायता शैतानीके जिन नियमोंका ऊपर उद्धृत किया गया है वही नियम इस एक्टके अनुसार नियत लिये जान वाले कमिश्नर व कमीशनके सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये। इस दफ्ते यह भली भांति प्रष्ट है कि अदालत दिवालिया दफ्ता ३६ के अनुसार किसी गवाहका बयान लेनेके लिये कमीशन भी जारी कर सकती है।

दिवालियेका बहाल किया जाना

दफा ३८ दिवालियेका बहाल किया जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अदालतमें अपने बहाल होनेके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्तके सुने जानेके लिये कोई तरीका नियत करेगी। परन्तु यदि इस एक्टके नियमोंके अनुसार उसका आम बयान छोड़ दिया गया हो तो वह दरखास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि वह बयान न हो जावे दरखास्त खुली अदालतमें सुनी जावेगी।

(२) इस दरखास्तको सुनते समय अदालत आफिशल एसायनी की रिपोर्ट जो उसने दिवालियेके व्यवहार तथा उसके मामलेके सम्बन्धमें दी होये ध्यानमें रखेगी और दफा ३६ के नियमोंका ध्यान रखते हुए—

(ए) पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है या उसके देनेसे इनकार कर सकती है या

(बी) बहाल किये जाने वाले हुक्मका प्रयोग निर्धारित समयके लिये रोक सकती है, या

(सी) बहाल होनेका हुक्म उन शर्तोंके साथ दे सकती है जो उसकी आयन्दा होने वाली आयन्दगी या जुनाफाके सम्बन्धमें होवे या उसको आयन्दा मिलने वाली जायदाद के सम्बन्धमें होवे।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके बहाल किये जानेका वर्णन है। उपदफा (१) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया बहाल किये जानेकी दरखास्त दे सकता है और ऐसी दरखास्तके आने पर अदालत यह कर्तव्य होगा कि वह उसका सुननेके लिये कोई दिन नियत कर देवे जैसा कि अमेची एक्टकी इस उपदफा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रष्ट है। परन्तु साथही साथ इस उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि

दिवालियाका आम बयान किता बजहमे नहीं लिया गया हो तो जब तक उत्तर आम बयान न हो जावे तब तक उत्तरी दर-
ख्वास्त नहीं सुनी जावेगी । बहाल किये जानेका दरख्वास्त सुली अदालतमें सुनी जावेगी अर्थात् उत्तरी समान कमरे (Cham-
ber) में नहीं ही जासकती है जेसा कि अंग्रेजी एक्टमें ॥ सम्बन्धमें प्रयोग मिले हुए (Shall) शब्दमें भासित होता है ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि बहालकी दरखास्त पर विचार करते समय अदालत अफिशल एसायनीकी
रिपोर्ट जो उत्तरी दिवालियेके व्यवहार व मामलेके सम्बन्धमें दी हो देखेगी और दफा २९ क नियमोंका ध्यान रखते हुए तीन
मन्त्रके हुक्म जो प्राज (ए), (बी) व (सी) में दिये गये हैं दे सकती है ।

बहाल (ए) के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है अथवा उसके देनेसे इनकार कर सकती है ।

बहाल (बी) के अनुसार बहालके हुक्म विनियमित किये हुए समयके लिये सुलतबी कर सकती है ।

बहाल (सी) के अनुसार बहालका हुक्म आपदा होने वाली आपदनी या जाने वाली जगहोंके सम्बन्धमें दे सकती है ।

यदि दिवालिया किर्मा कर्ज-बाहके कर्जोंका कैल्ला इस शर्तके साथ कर केने कि वह उसकी दिवालियेकी दरवारका
विरोध नहीं करेगा तो इस प्रकार किया हुआ इकरारनामा यह समझा जावेगा क्योंकि यह अथ कर्जबन्दाको बाधता देते हुए
तथा कानून दिवालियाके मन्तव्यके विरुद्ध है, देखो—20. Bom. 636.

**दफा ३९ वह मामले जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे
इनकार कर देना चाहिये**

(१) यदि दिवालियेमें इस एक्टमें बतलाया हुआ कोई जुर्म किया हो या लाजीमान हिन्दू
की दफा ४११ से ४२४ तकका कोई जुर्म किया हो तो अदालत ऐसे सब मामलोंमें बहाल (Dis-
charge) करनेसे इनकार कर देगी और आगे दिये हुए किसी बातके साबित होने पर, या

(ए) बहाल करनेसे इनकार कर देगी, या

(बी) किसी नियत किये हुए समय तकके लिये बहाल रोक देवेगी, या

(सी) बहालके हुक्मको उस वक्त तकके लिये रोक देवेगी जब तक कि कर्जप्राप्तियोंको
रूपमें चार आने अर्थात् कर दिये जावे, या

(डी) दिवालियेके बहाल करनेमें यह शर्त लगा देवेगी कि उसके विरुद्ध उस मतालियेके
लिये अफिशल एसायनीके दफ्तरमें डिफ्री कर दी जावे जो उस वक्त साबित किये
जाने योग्य कर्जोंके सम्बन्धमें देना बाकी निकलता होवे । और वह बचा हुआ कर्जा
या उसका कोई हिस्सा दिवालियेकी आयन्दा होने वाली आमदनी या उस आयन्दा
प्राप्त होने वाली आयदादसे उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ चुकाया जावेगा जो
अदालत मुनासिब समझे । परन्तु ऐसे मामलोंमें डिफ्री बिना अदालतकी आज्ञाके
इकरार नहीं की जावेगी और अदालत की ऐसी आज्ञा उस वक्त प्राप्त हो सकती
जब कि यह साबित होजावे कि बहालके बाद दिवालियेको कोई आयदाद मिली है
या आमदनी हुई है जिससे उसके कर्ज चुकाये जासकते हैं ।

(२) उपदफा (१) में आगे आने वाली जिन बातोंका हवाला दिया है वह यह हैं—

- (५) यह कि दिवालिघेके लहनेकी कीमत उतनी नहीं है जिससे कि उसके पिला महकूत कज़ोंका एक रुपयेमें चार आना न चुकाया जासके अथ तब कि वह अदातको इस बातका विश्वास न दिला ऐसे कि उसके लहनेकी कीमत ऐसी घजहोंसे कम है जिनके लिये यह उचित रूपसे किसी प्रकार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।
- (६) यह कि दिवालिघा उस प्रकारके देसायकी कितायें नहीं रखता रहा है जैसी कि उसके व्यापारके लिये रचना आपश्यक है और जैसा कि रहने जानेका चलन है और जिनसे कि उसके दिवालिघा होनेसे पहिले तीन सालके बीचके व्यापारिक सौदे या माली दास्तत जानी जासके।
- (७) यह कि दिवालिघा अपनेको दिवालिघा जानते हुए भी व्यापार करता रहा है।
- (८) यह कि दिवालिघेने इस एकदके अनुसार साबित किया जानें योग्य कोई सौदा यह जानते हुए किया हो कि उसे उस सौदेके अदायगी की सम्भावना, सौदा करते समय नहीं थी। इस बातका भार सुबूत दिवालिघे पर होगा कि वह सौदा करते समय उसकी अदायगी की उम्मेद रखा था।
- (९) यह कि दिवालिघा अपनेलहनेकी कमी या उसका नुकसान सन्तोषजनक रूपसे नहीं समझ सकता है।
- (१०) यह कि दिवालिघेने अपने देतहाया व खतरनाक सहेके खोखे को करनेकी घजहसे अथवा रहन सहनमें अनुचित ध्यय करनेकी घजहसे या जुपकी घजहसे या अपने व्यापारके भारोंको जानबूझ करन देखनेकी घजहसे अपनेको दिवालिघा बना लिया है।
- (११) यह कि दिवालिघेने अपने किसी कर्ज़वहाहका बंजा खर्च किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें कर दिया है जो उसने सही तरीकेसे उसके विरुद्ध दायर किया हो और जिसमें कि उस दिवालिघेने कर्ज़वहाह को परेशान करनेके लिये बंजा तौरसे जवाबदेही की हो।
- (१२) यह कि दिवालिघे की दरपयास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर दिवालिघेने किसी बंजा व परेशान करने वाले मामलेको खला कर अनुचित ध्यय किया होव।
- (१३) यह कि दिवालिघेने दरपयास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर जब कि वह अपने कर्ज़ोंको मश करनेमें असमर्थ था अपने किसी कर्ज़वहाह को बंजा तरीके पर तर्जिह दी है।
- (१४) यह कि दिवालिघेने अपनी हिसाब की किताबों या जायशुद को या उसके किसी हिस्से को दिया दिया है या हटा दिया है अथवा वह अन्य किसी धोखादेहीका या धोखादेहीसे किये हुए अमानतमें दयानत का दोषी हुआ है।
- (१५) यहालके हुकम को मुअतिल करने (Suspend) या उसमें शर्तोंके लगानेके अधिकार एक साथ प्रयोग किये जासकते हैं।

(४) बहाल की दरमवास्तके लिये आफिशल एसायनी की रिपोर्ट आहिरा सौर पर सुपूत होवणी और अदालत उस रिपोर्टमें की हुई बातों को सच्चा मान सकती है ।

ब्याख्या—

इस दफामें उन सब बातोंका उल्लेख है जिनके अनुसार अदालत पूरी रूपसे बहाल करनेसे इनकार कर देगी व साथ ही साथ वह भी अवसरयें बतलावेगी हैं जिनके होने पर शकसे साथ बहालका हुक्म दिया जासकता है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि दिशालिखे इस एक्टमें बतलाये हुए किसी अपराधको किया हो जगता ताकीरत हिन्दी दफा ४२१, ४२२, ४२३ वा ४२४ के अनुसार अपराध किया हो तो अमानतका कर्तव्य होगा कि वह बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे । अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस उपदफामें बतलाये हुए नियमोंकी अवहेलना नहीं कीजाना चाहिये । इस एक्टके अनुसार किये जाने वाले अपराधोंका उल्लेख दफा १०३ में किया गया है जिसके अनुसार अपने मायकेकी जमकी हाजतकी छिपानेसे अपना किसी कर्तव्य छिपाने या घोसोदा तौरसे कुछ देने पर या अपनी जगदाद हटा देने या उन पर किसी प्रकारका भार पैदा कर देनेसे दिशालिख अपराधी कथार दिया जासकता है । तामीरत हिन्दी दफा ४२१ से लेकर ४२४ तकमें भी जोखते लिखी हुई इसायेकों व जगदादके सम्बन्धमें दिये हुए शीर्षोंका उल्लेख है ।

ताजीगत हिन्दू एक्ट नं० ४५ सन् १८६० ई० की दफा ४२१ इस प्रकार है—

दफा ४२१—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे या घोसादेहीसे किसी जगदादका हटा देवे, छिपा देवे या दूसरे व्यक्ति को दे देवे या किसी शकसे इकट्ठा इतकाक कर देवे या जमकाक कर देवे और उसके लिये कर्षाप्त मुआविका न लेवे तथा इस मसाले ऐसा काम करे कि जिसमें उसकी जगदाद कानूनके अनुसार उसके कर्तव्यदानमें भागी न जासके या वह किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्यदानमें न भाग्ये जासके तो उस व्यक्ति को दो साल तकके कारावासका सजा या कठोर दण्ड अथवा जमीनेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड एक साथ दिये जासकेंगे”

दफा ४२२—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अपना घोसादेहीसे अपना या किसी अन्य व्यक्ति का कर्षाप्त मुआविका लेके कि जिसमें वह कानूनके अनुसार उसके कर्षाप्त या उन दूसरे व्यक्ति के कर्षाप्त की जगदादगीमें न दिया जासके तो उस व्यक्ति को दोनों प्रकारके दण्ड यानी कारावासका दण्ड दो साल तकके लिये दिया जासकेगा या उस पर जमीनेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जासकेंगे ।”

दफा ४२३—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अपना घोसादेहीसे किसी ऐसी दस्तावेज या कागज पर दस्तावेज करे उसे छिपे या उसके लिखने जानेमें भाग लेवे जिसके अन्वि कोई जगदादका इतकाक किया जाना होता होवे या उस जगदाद पर भार पैदा होता होवे या उस जगदादका कोई एक उसमें जाता हो और उसमें मुआविकेका राजत बयान लिखा गया हो या जिस व्यक्ति के इकट्ठे या जिसके शायदेके लिख वह लिखा गया हो, या वह गुप्त लिखा हो तो वह व्यक्ति दो साल तककी दोनों प्रकारकी सजा या जुर्माने की सजा या यह दोनों सजायें साथ साथ पावेगा”

दफा ४२४—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अपना घोसादेहीसे अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की जगदादको छिपा दे या हटा दे या उसके छिपाने अथवा हटानेमें मदद देवे या बेईमानीसे अपने किसी इकट्ठे या भागको छोड़ देवे जिसका वह मुआविके है तो उस व्यक्ति को दो साल तकके सजा या कठोर कारावास या जुर्माने का सजा या दोनों प्रकारके सजायें दी जावेंगी”

उपदफा (२) में कुछ शर्तोंका वर्णन है और उनके सामिन होने पर अदालत उपदफा (१) के शर्त (१), (२), (३) व (४) के अनुसार हुक्म देवेगी ।

उपदफा (१) फलाज (ए) के अनुसार बहाल होनेवा हुकम देनेसे अदालत इनकार कर सकती है ।

फलाज (बी) के अनुसार नियत समयके लिये बहालकम हुकम मुलतबी कर सकती है और उसी हुकममें यह भी दिया जासकता है कि नियत की हुई तारीखसे दिवालिया बहाल होनेवा इस प्रकारके नियमका यह अर्थ उपपन्न चाहिये कि नियत की हुई तारीखसे बहालके हुकमका प्रभाव आरम्भ होगा, देता—44 Bom. 555.

फलाज (सी) के अनुसार बहाल किये जाने वाले हुकमको उस समय तकके लिये मुलतबी किया जासकता है जब तक कि बर्चस्वाहोंको अपने कर्जमें वपयेमें फार आना न मिल चुके ।

फलाज (डी) के अनुसार दिवालियेके ऊपर बहाल किये जानेवा हुकम होनेके साथ साथ बर्कीया मतालिकेके लिये बिक्री दी जासकती है यह बिक्री आफिशल एसायनीके हुकमों की जानेगी और उसका मतालिका दिवालियेकी आय या होने वाली आयदानी या मिलने वाली आयदादसे उन शर्तोंके अनुसार बसूल किया जासकेगा जो अदालत लगा देना मुनासिब समझे । इस क़ाज़में यह भी दिया हुआ है कि इस प्रकार दी हुई बिक्री बिना अदालत की आज्ञाके जारी नहीं कराई जावेगी और अदालत इस प्रकारकी बिक्रीके इनराय किये जानेके लिये उसी वक्त आज्ञा देवेगी जब उसको यह साबित हो जावे कि दिवालियेने बहाल होनेके बाद बर्कीया आयदाद पाई है या उसको काफी आयदानी हुई है जिससे कि उसके कर्ज चुकाये जासकते हैं ।

उपदफा (२) इस क़ाज़में विभक्त है इस उपदफाके क़ाज (ए) के अनुसार यदि बिला मशूज बर्जें वपयें और ओने न चुकाये जासके तो अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकती है जब तक कि उसको समीपजनक रूपसे यह साबित न हो जावे कि दिवालिया इस दशको ऐसे कारणोंसे पहुँचा था जिस पर उसका कोई बस नहीं था अर्थात् जिसके लिये वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता हो ।

फलाज (बी) के अनुसार यदि दिवालिया अपने व्यापारके सम्बन्धमें प्रचलित हिदायती कितानें न रखती रहा हो जिससे कि उसके सौदाग पता व पानी हालत दिवालिया होनेसे तीन साल पूर्व तककी जानी जासके तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकती है । इस क़ाज़में यह भली भाँति मकट है कि केवल हिदायती कितानोंका रखनाही पर्याप्त नहीं है किन्तु उनसे दिवालियेके व्यापार व धन सम्बन्धी हालत भी मादूम होना चाहिये । हिदायती कितानें उस प्रकारकी होना चाहिये जैसी कि बाजारके चलनके मुवाफ़िक उस प्रकारका व्यापार करने वाले रखते हैं जिस प्रकारका व्यापार दिवालिया करता रहा हो और उन कितानोंसे दिवालियेके व्यापारका वता दिवालिया होनेसे पहिले तीन साल तरका मादूम किया जासके ।

फलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनेको दिवालिया जानते हुए व्यापार करता रहा हो तो वह व्यक्ति भी उपदफा (१) के अनुसार हुकम पानेवा अधिकारी है ।

फलाज (डी) में यह दिया हुआ है कि यदि दिवालियेने कोई कर्ज यह जानते हुए लिया हो कि उसके पास उस कर्जकी चुकानेवा कोई साधन नहीं है और वह कर्ज इस एवजके अनुसार साबित किया जासकता हो तो ऐसी बातके साबित होने पर भी अदालत उपदफा (१) के क़ाज़के अनुसार हुकम दे सकती है ।

फलाज (ई) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया समीपजनक रूपसे यह न साबित कर सके कि उसका अक्षरों वसके कर्जोंको चुकानेके लिये पर्याप्त क्यों नहीं है या उसके अक्षरोंमें कमी क्यों हो गई है तो अदालत उपदफा (१) के क़ाज़के अनुसार हुकम दे सकती है ।

फलाज (फर) के अनुसार यदि यह साबित हो जावे कि अनुबिन खर्च करने या सेवा सहेवाधीसे दिवालियेने जानी यह

हालत कर ली है या जुर्माने अपना व्यापारिक ढीक तौल न देखने के कारण अपना कारबार विगड़ दिया है तो अदालत उपदफा (१) के शर्तोंके अनुसार हुकम देवेगी ।

फलाज (जी) के अनुसार दिवालिया यदि किसी कर्षेस्वाद्वया नेत्रा खर्च घुड़ी व नेत्रा नवाबदेसके कारण किसी मुकदमे के का देव जा सदा तगवसे ससक लवइ चान्द किया गया हा तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकता है ।

फलाज (एच) क अनुसार यदि दिवालियेने दिवालियेका हालत होनेसे पहिले तान माहक अदर बेना मुकदमे शर्म में खर्च दिया हो तो भी अदालत उपदफा (१) का प्रयोग कर सकती है ।

फलाज (आई) क अनुसार यदि दिवालियेकी दरखास्त सुननेसे पहिले तीन माहक अन्दर दिवालियेन किसी कर्जनाहको घोखान्दसि तर्गीह (Preference) दी हो तो अदालत उपदफा (१) क अनुसार बरवाई कर सकती है । घोखान्दसि तर्गीह देनेका उल्लेख दफा ५५ में किया गया है ।

फलाज (जे) के अनुसार यदि दिवालियेने अपना इस्साब बी कितानों को हयया हो या किया दिया हो अथवा उसने अपनी आपदाद व इसका बहरे हिस्सा लुपताया या हनाया हो अथवा उसने कोई भारता दिया हो या भारोसे अमा मतमें खयामत किया हा हा वह उपदफा (१) क अनुसार ही हुकम पानेध अधिकायी होगा ।

उपदफा (२) के अनुसार सुलतना का हुकम तथा शर्तों का रकामया जाना एक साथ किया जासकता है ।

उपदफा (४) में यह नतकिया गया है कि आधिकृत एसायनी का रिपॉन् आदेश तत् पर सुपूत मानी जावेगी और अदालत उसको बिलकुल दाक मान सकती है ।

दफा ४० बहालकी दरखास्तका सुना जाना

अदालत द्वारा बहाल की दरखास्त सुनने जानेका नोटिस निधारित रूपसे प्रकाशित किया जायेगा और उसकी खूबना निश्चित कीहुइ तारीखसे कमसे कम एक माहके पहिले उन कर्जस्वाहोंक पास भेजी जायेगी जो अपना कर्जा साधित कर चुके हैं और अदालत आधिकृत एसायनी तथा कर्जस्वाहों की बी यातें सुनेगी । सुनने वाली तारीख पर अदालत दिवालियेसे वह प्रश्न पूछगी और वह गहादत सेवगी जो उसे उचित समझ पड़े ।

ध्याख्या—

इस दफामें यह मतकिया गया है कि बहाल होने की दरखास्त सुने जानेके लिये जो तारीख नियत की जाने उसकी सुनकारी सुनहुए निर्धारित किये हुए दिन पर की जायगा । इस मुकदमे की अवकलना नहीं कीजासकती है जैसा कि अंग्रेजी मुकदमें प्रथाग ग्रेगे हुइ (Shall) शब्दस मान्य हाता है । कर्जा साधित कर देने वाले कर्जस्वाहोंको भी उनकी सुचना नियत की हुई तारीखसे कमसे कम एक माह पहिले दा जना आवश्यक है । बहाल की दरखास्त सुनत समय अदालत आधिकृत एसायनी व किसी कर्जस्वाहकी नवाबदेस की भा सुन सकती है । अदालत दिवालियेसे ऐसे सवालान्द एव सकती है व उनके जवाब ले सकती है जा उस सुनाधिन समझ पड़े ।

दफा ४१ बहाल होनेकी दरखास्त न देने पर दिवालिया करार देने वाले हुकमकी मंजूरी

यदि बहाल की दरखास्त सुननेके लिये नियत किये हुए दिन पर दिवालिया हाजिर न होवे अथवा दिवालिया निर्धारित किये हुए समयक अन्दर बहाल की दरखास्त न देवे तो अदालत

रात अकिशाल पसायनी या किसी कर्जस्थान की दरखास्त पर या स्वयं ही विधालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंजूर कर सकती है या और कोई हुक्म जो उसे मुनासिब मालूम हो वे सकती है और इस प्रकारकी मंजूरी होने पर दफा २३ में बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

व्याख्या—

यदि दिवाणिया बहाल होने की दरखास्त छने अनेके दिन हाजिर न होवे या अदालत द्वारा नियत किये हुए समयके बाद बहाल की दरखास्त न देवे तो अदालत की अधिभार है कि वह दिवाणिया बहाल दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूर कर देवे । इस प्रकारके मंजूरी का हुक्म अदालत स्वयं दे सकती है अथवा अकिशाल पसायनी या किसी कर्जस्थान की दरखास्त आने पर दे सकती है । यह भी बतलाया गया है कि इस दफाके अनुसार मंजूरीके हुक्म पर दफा २३ के नियम लागू होंगे अर्थात् दफा २३ में बतलाये हुए सौदे आदि का इस हुक्मसे पहिले किये गये हों बदस्तुर बने रहेंगे व दिवाणिये की जायदाद बसे या अन्य किसी व्यक्ति को अदालत की आज्ञाके अनुसार मिल जावेगी । दिवाणिया यदि जेलसे केजा गया हो तो वहां भेज दिया जायके व मंजूरीके हुक्मकी इच्छाही की जावेगी । दफा २३ को देखनेसे यह सब बातें भली भण्डि समझमें आसकती है ।

दफा ४२ बहाल होनेकी दरखास्तका दुबारा दिया जाना

(१) जब कि अदालत बहाल किये जाने की दरखास्त नामंजूर कर देवे तो उसको अधिकार है कि वह नियत किये हुए समयके भीत जाने पर तथा उन बातोंके उपस्थित होने पर जो निर्धारित कर दी गई हों विधालिये को फिरसे अपनी दरखास्त देने का अधिकार दे देवे ।

(२) जब कि बहाल किया जानेका हुक्म किसी शर्तोंके साथमें दिया गया हो तो उसके हुक्मके पश्चात् दो साल भीत जानेके बाद किसी समय भी विधालिया अदालतको उस बात का विद्वान दिला देवे कि कोई उचित सम्मथना इस बात की नहीं है कि अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पूर्ति की जासकेगी तो अदालत अपने हुक्म की शर्तोंमें संशोधन कर सकती है अथवा धाड़में दिये हुए हुक्म का संशोधन कर सकती है और यह संशोधन उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ किये जावेंगे जो उसे उचित प्रतीत होवें ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार बहाल होने की दरखास्त एक बार खारिज किये जाने पर भी दुबारा दी जासकती है यद्यपि दुबारा दरखास्त अदालत द्वारा निर्धारित किये हुए समयके बाद तथा उसके द्वारा बतलाई हुई शर्तोंके उपस्थित होने पर नहीं दी जासकेगी यदि अदालतने ऐसे समय या शर्तोंके लिये कोई हुक्म दिया होवे । और अदालत की आज्ञा देने पर यह दुबारा दी जाने वाली दरखास्त की जासकती है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी शर्तोंके अनुसार दिवाणिया बहाल किया गया हो तो उसके पश्चात् दो साल बीतने पर दिवाणिया अदालतको यह विद्वान दिला सकना है कि अब आयन्दा कोई सम्मथना नहीं है कि वह लगाई हुई शर्तोंकी तामील कर सके इसलिये उन शर्तोंको या तो हटाना चाहिये या उनमें उचित परिवर्तन कर देना चाहिये । अदालत ऐसा विद्वान होने पर या तो शर्तोंको हट सकती है या उनमें उचित परिवर्तन करके अपना दूसरा हुक्म दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अबकी प्रथममें प्रयोग किये हुए (MAY) करते मालूम होजा है ।

दफा ४३, बहाल किये हुए विधालियेका जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य

बहाल किया हुआ विधालिया, बहाल हो जाने पर भी आफिशल एसायनी द्वारा चाही हुई मददको अपने उस लहने व जायदादके वसूल करने तथा उसके बांटनेमें जरूर देवेगा जो आफिशल एसायनी की सुपुर्दगीमें भागई हो और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अदालत की सौदीन करने का दोषी होगा और यदि अदालत उचित समझे तो उसके बहाल किये जानेके हुक्म को भी मंजूर कर सकती है परन्तु इस प्रकार मंजूरीके हुक्मसे पहिले तथा बहाल होनेके पश्चात् जो धननामे, इन्तकालात या अदायगी बाकायदा की गई हों या जो काम किये गये हों उन पर इस मंजूरीके हुक्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् वह जैसेके तैसे बने रहेंगे ।

व्याख्या—

विधालिया बहाल किये जानेके बाद भी आफिशल एसायनीको अपनी जायदादके वसूल किये जाने तथा उसे कर्म-बनारोंमें बांटे जानेमें मदद देवेगा । अंग्रेजी एक्टकी III दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि विधालिया इस दफाके नियमकी अवहेलना नहीं कर सकता व इसी दफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि वह उसकी अवहेलना करेगा तो दोषी निर्धारित किया जाकर दण्ड्य अधिकारी होगा । इस प्रकारका दोष अदालतकी सौदीन करना समझा जावेगा और उसके अनुसार विधालिया दण्ड पासकता है । इनकाही नहीं है किन्तु बहाल होनेका हुक्म भी मंजूर किया जा सकता है परन्तु इस प्रकारका मंजूराम पहिले तथा बहाल किये जानेके बाद या सौदे आदि किये गये हों वह सब बदस्तूर बने रहेंगे । मंजूरीका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ४४ धोखेदिहीसे किये हुए सौदे

(१) यदि कोई जायदाद विवाहसे पहिले विवाहके एवजमें लिख दी जावे और लिखते समय लिखने वाला पिला इस जायदादको भी शामिल किये हुए अपने सब कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ होवे, या

(२) यदि कोई सौदा या मुवाहिदा विवाहके सम्बन्धमें किया जावे जिससे कि कोई रुपया या जायदाद लिखने वाले व्यक्ति की स्त्री या बच्चों को अधिष्पत्य मिलने वाली होवे परन्तु वह रुपया या जायदाद विवाहके समय उपस्थित न होवे या उसमें देने वाले का उस समय कोई हक न होवे (इसमें उस रुपये या जायदादसे तात्पर्य नहीं है जो उसकी स्त्री की दौध अथवा जिसमें उसकी स्त्री का हक पहुँचता हो) तो ऐसी दोनों हालतोंमें यदि लिखने वाला व्यक्ति विधालिया द्वारा दे दिया जावे या वह समझौता कर लेवे अथवा वह अपने कर्नेरवाहोंसे तस्फीया कर लेवे और अदालतको यह मालूम हो कि जायदाद का उस प्रकार दिया जाना या सौदा अथवा मुवाहिदा कर्नेरवाहोंके कर्जों को मारने या उसमें देर करने की भंशसे किया गया था या ऐसे सौदे किये जाते समय की हालत को देखते हुए वह सौदा अनुचित प्रतीत होवे तो अदालत बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे इनकार कर सकती है या उससे कुछ समयके लिये मुलतवी कर सकती है या शर्तों के साथ बहाल का हुक्म दे सकती है अथवा तस्फीये या तप किये जाने वाले मसल को स्वीकार करनेसे इनकार कर सकती है ।

व्याख्या—

इस दफा में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य किसी गायबदार को अपनी स्त्री या बच्चों के हक में इस मंदागि मिल देवे कि जिसमें उसके वर्ज्यप्राप्ति के वसूल करने में देर होने या उसका कर्त्ता वसूल न किया जा सके या ऐसी ही अन्य कोई सौदा या तरहीर कर देवे तो अदालत को अधिकार है कि वह या तो दिवालिये के बहाल होने का हुक्म न देवे अथवा बहाल होने का हुक्म प्रस्तुती कर देवे या शर्तों के साथ बहाल का हुक्म देवे या तरहीर अथवा स्वीकार का हुक्म न करे। इस प्रकारसे गायबदार के लिखे जाने की धोखे किया हुआ काम समझा जा सक्ता है और इसी कारण दिवालिया अपने दिष्ट हुए भोखानेवाले कागसे बन जाने नहीं उठा सकता है। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि यदि इन दफा के अनुसार बहाल हुए सौदे अपनी स्त्री की निजी आयदाद या रुपये या इन्हें सम्बन्धमें दिये गये हों तो वह सौदे इस दफा के अनुसार दिये हुए धातों के सिद्ध नहीं माने जा सकते हैं।

दफा ४५ बहाल के हुक्म का प्रभाव

(१) बहाल का हुक्म दिवालिये को नीचे दी हुई बातों से बरी नहीं करेगा—

(ए) सरकार को चुकाया जाने वाला कर्ज़।

(बी) कोई भी कर्ज़ या ज़िम्मेदारी जो धोखादेही से या धोखादेही से की हुई अमानत में खपानत से पैदा हुई हो और जिसमें दिवालिये का भी हाथ रहा हो।

(सी) कोई भी कर्ज़ या ज़िम्मेदारी जिसके लिये धोखा देकर माफी ले ली गई हो और जिसमें दिवालिया का भी भाग रहा हो।

(डी) कोई भी ज़िम्मेदारी जो सन् १८६८ ई० के ज़ाबत फौजदारी की दफा ४८८ के अनुसार दिये हुए हुक्म के आधार पर हुई हो।

(२) उन मामलों को छोड़ कर जिनका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है दिवालिया बहाल होने पर उन सब कर्ज़ों से बरी हो जावेगा जो दिवालिये की कार्यवाही से साबित किये जा सकते हैं।

(३) बहाल किये जाने का हुक्म दिवालिये की कार्यवाही का पूरा सुवृत्त होगा और उसके सम्बन्धमें की हुई सब कार्यवाहियों का भी पूरा सुवृत्त होगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति दिवालिये की दरखास्त दाखिल किये जाते समय दिवालिये का साक्षीदार या उसके साथ दूस्ती रहा हो या संयुक्त रूपसे किसी सौदे की अदायगी का ज़िम्मेदार रहा हो या यह ज़ाबिनदार या ज़ाबिनदार के तौर पर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दिवालिये के बहाल हो जाने पर बरी नहीं होगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) में वह कर्ज़ बतलये गये हैं जिनमें बहाल होने पर भी दिवालिया बदल नहीं हो सकेगा यह कर्ज़ प्रायः (ए) (बी), (सी) व (डी) में दिसलाये गये हैं।

फलाज (ए) के अनुसार सरकारी कर्ज़ों में बरी नहीं हो सकता वह उसे बहाल होने पर भी देना पड़ेंगे।

कलाज (बी) के अनुसार यदि दिवालियेन घोखते या घोखादेईसे अमानतमें खयानत करके कोई सेदि निय हो अथवा होने दिने हो ता उन सेरोरु सग्न कर्मे जो कच होन वह भी बन्दूर नग रहेंगे और दिवालिया बहाल होने पर भी उनका जिम्मेदार बना रहेगा ।

कलाज (सी) के अनुसार यदि दिवालियेन धात्ता दफर जिंसा कर्जे या जिम्मेदारीका मुआफ मग्ना किया हा ता ऐसे कर्जे की अदायगीका मा वह जिम्मेदार बना रहेगा ।

कलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि यदि घोखता कोनदाग का दफा ४८८ के अनुसार गुजारा देनेके सम्बन्धमें उस पर कोई कर्ज हो जावे ता एम कर्जेस भी वह बहाल हो जान पर भी उदर नहीं बखगा ।

उपदफा (२) में यह दिया हुआ है कि उपदफा (१) में बतलाई हुई बातोंका छाड कर दिवालिया बहाल होने पर उन सब कर्जोंसे उकान हो जावेगा जा दिवालिय का कार्रवाईमें माफन निय जासकत है अर्थात् यदि किसी कर्जदाराने अपना कर्ज साबित न किया हा ता भी वह बहाल होनक बाद दिवालियेमें अपना कर्ज समूच नर्मे कर सकेगा ।

उपदफा (३) में यह बात साफ कर दा है कि जमा व्यक्ति के बहाल होने पर उसका समीदार या उसके साथ का दूस्री या अय कौन समुच जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति या उनका कामिन्दार बहाल नही हावेगा इस नियमकी पाब दी भी अवश्य की जावेगी जैसा कि अगली एक्काई इस दफामें प्रयोग क्रिय हुए (Shall) शब्दका भाव मादप होना है ।

तीसरा प्रकरण



जायदादका प्रकरण

कर्जोंका साबित किया जाना

दफा ४६ दिवालियेके सम्बन्धमें साबित किये जाने योग्य कर्जें

(१) वह मांगें जो मुघाहिदे या अमानतमें खयानतके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारसे पैदा हुई हों तथा जो अनिश्चित हज्जेके रूपमें होयें दिवालिया की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित नहीं की जासकेगी ।

(२) यदि किसी कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की दस्त्यास्त दी गई हो और उसकी सूचना मिलनेक पश्चात् किसी व्यक्तिन कर्ज दिया हो या कोई दूसरी जिम्मेदारी कर्जदार पर जापम की हो तो वह व्यक्ति अपना इस प्रकारका कर्ज दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित नहीं कर सकेगा ।

(३) उपदफा (१) व (२) को छोड कर वह सब कर्जें व जिम्मेदारियां दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित क्रिय जान योग्य कर्जें समक जावेंगे चाहे वह मोहुरा दोयें या सति-प्यमें अदा किये जाने वाले हों अथवा चाहे वह निश्चित होयें या उनका होना किसी बातके

होने पर निर्णय होवे जिनकी जिम्मेदारी दियालिया करार दिये जाने का हुक्म होते समय कार्य दार पर होवे अथवा जिसकी जिम्मेदारी उस पर दियालिया करार दिये जानेसे पहिले नियं दृष्ट किसी कामके कारण बहाल होनेसे पहिले हो जावे ।

(४) यदि ऊपर बतलाये अनुसार कोई कर्ज या जिम्मेदारी याचित किये जाने योग्य होवे परन्तु उसकी कोई निश्चित सीमा न हो कारण न हो सकती हो कि उसका होना किसी बात या बातोंके होने पर निर्भर है अथवा किसी अन्य कारणसे उसकी सीमा निश्चित न हो सकती हो तो व्यापारिक पसायनी ऐसे कर्ज या जिम्मेदारी की सीमा का अन्दाजा लगा लेगा परन्तु यदि यह है कि अगर व्यापारिक पसायनीकी सहायता उस कर्ज या जिम्मेदारीकी सीमा का अन्दाजा हो सके तो उसे न लगाया जाना चाहता हो तो यह इसके लिये एक सर्टिफिकेट जारी करेगा और उसके जारी होने पर यह कर्ज या जिम्मेदारी न याचित किया जान योग्य कर्ज या जिम्मेदारी समझा जासकेगा ।

व्याख्या—

इस दफवि नियं जिम्मेदारी (Liability) शब्द का अर्थ उस मुकदमे के समझा जावेगा जो किसी वस्तु या मालके धिये जाने पर मिलना चाहिये, व उस जिम्मेदारी में भी समझा जावेगा जो निम्न बातें मुवाहिद, इकरारनामा या वाचक बहाल होनेसे पहिले न करे पर कर्ज या कर्ज की सीमा अथवा कर्जक निम्न पत्र होने चाहें उसे यदि मुवाहिद इकरारनामा या वाचक बहाल होना तो न किया गया हो अपना उम्मेद किये जाने का पावनी ऊपर लाहने का गई हो चाहें वह मुवाहिद शिकन हई हो या न हई होवे या हानि न हो या न हानि बारी हानि अथवा हानि न हो या न हो सकती होवे । और बहुरा इन पत्रों द्वारा इकरारनामा व वचन या समझा जावेगा जो मुलायम सीमा की गई हो या निम्न पाव या अन्य किसी प्रकारसे हो जावे और जो कर्ज की सम्पत्ति सम्पत्ति हवे या निम्न बातें कर्ज का आवश्यकता यह धरती हो यदि और किये जाने बालि केये की तादत निश्चित या अनिश्चित होवे और चाहें बतमानके लिये होवे या यदि यह किये और चाहें कर्ज निश्चित समयके लिये होवे या उसका होना किसी कामके होने पर निर्भर होवे, और एवं मामलोंकी किये निश्चित किये हुए नियमोंके अनुसार या कार्य अनुसार न हो जानकेगी ।

नोट—इस दफवि उन कर्जों का वर्णन है जो दिवाळी की कारोबारिक सम्पत्ति में याचित किये जासके हैं तथा उन कर्जों के भी उल्लेख है जो याचित नहीं किये जासके हैं ।

उपदृष्ट (१) में यह बतलाया गया है कि वह सीमा जो अनिश्चित हुयेके रूपमें होवे याचित नहीं की जा सकती परन्तु माय हो साथ यह भी दिना हुआ है कि यदि ऐसा माय किया मुवाहिद या अनिश्चित खयलतने का पत्र हई हो तो वह याचित किये योग्य कर्ज हो सकती है । प्रत्येक उपदृष्ट (१) अनुसार माय या किया जाना आवश्यक है जैसा कि ऊपर की उपदृष्ट (१) में एक उपदृष्ट में बताया गया है (Shall) का अर्थ यह उपदृष्टाओं किये हुए नियमों में बहरेलना नहीं की जासकती है ।

उपदृष्ट (२) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह अपने दिवाळीकी सम्पत्ति दे रही है अथवा उसके विरुद्ध किये गये व दस्तावेज हैं, गई है उसे वह इस बात का कर्ज या याचित नहीं किया जासकेगा ।

उपदृष्ट (३) में यह बतलाया गया है कि उपदृष्ट (१) व (२) में बतलाये हुए नियमोंका पालन रखते हुए अर्थात् उनमें बतलाये हुए कर्जों के अतिरिक्त अन्य सब कर्ज व जिम्मेदारियां दिवाळीकी कारोबारिक सम्पत्ति में याचित की जान योग्य समझी जावेगी । इस उपदृष्ट में यह भी साफ कर दिया है कि इस प्रकार रखे जावे वह आशुता हवे अथवा यदि यह

होने वाले होने व चीह बह निश्चिन होने अपना बनका होना किसी बातक होने पर निर्भर होने साविन निये जाने योग्य स्थिति जावेगे। इस बातका भी ध्यान इस उपद्रफके सम्बन्धमें रखना चाहिये कि यह कर्जों या ती दिवालिया करार देने जाते समय होने अपना इसत पहिले वा हुई लिखेदारके बाण, बहाल होनेसे पहिले दिवालिया इनके लिये लिखेदार हो जावे।

उपद्रफा (४) में उन कर्जोंके बारेमें बतलाया गया है जिनकी कीमत निश्चित न होवे। अर्थात् यदि किसी बातके होने पर किसी वस्तुका होना निर्भर होने अपना अन्य किसी कारणसे निजी कर्जे या लिखेदारकी कीमत निश्चित पत्र साक्षिक रूपमें न होवे तो आधिकार प्राप्तपना उन कर्जोंकी कीमतका तदानीका लगावेगा। इस उपद्रफके साथ यह भी नर्तक होगा जो यह है कि यदि आधिकार प्राप्तपना की बातमें किसी वस्तु या लिखेदारकी कीमतका अनुमान ठीक तौरसे न लगाया जा सकता हो तो यह इस भावका सर्वाधिकृत देगा जहाँमें यह लिखेगा कि उस कर्जकी कीमत ठीक तौरसे तब नहीं हो जा सकती है और ऐसे सर्वाधिकृत देने पर यह वस्तु न साविन दिया जाने योग्य कर्ज समझ जावेगा। इस दफाके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसमें लिम्बेदारी (Liability) शब्द जिन २ बातोंके लिये प्रयोग किया जातकता है उन बातोंका उल्लेख है। इस व्याख्यासे यह प्रकट है कि चाहे वह काम बर्तमानमें होने वा भविष्यके लिये दान अपना बनका होना किसी बातके होने पर निर्भर होने उन सब मामलोंके सम्बन्धमें होने वाले कर्ज साविन निये जान योग्य समझे जातकता है।

इसी व्याख्यामें यह भी बात साक्ष्य कर दी गई है कि चाहे मुदादिदा वा वादा साक्ष्य तौरसे किया गया हो वा उपद्रफे पाषण्डी निजी और इगते वेदा हो गई हो अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि मुदादिदा आदि मुदादिदेक इगते चुन्नासा तौर जा ही निये गये हों। इस दफामें यह भी भावि प्रकट है कि दिवालियाकी चर्चाईमें साविन किया जाने योग्य कर्ज निश्चित भन साक्षिक रूपमें होना आवश्यक नहीं है किन्तु उक्त अनुमान निर्धारित बिधियोंके अनुसार अपना रायके अनुसार भी किया जा सकता है।

उपद्रफा (४) के अनुसार साविन किया जाने योग्य कर्जों की न साविन किया जाने योग्य कर्जों करार दिया जा सकता है यदि उस उपद्रफामें बतलाया हुए निर्धारित अनुसार चर्चाई की गई हो अर्थात् आधिकार प्राप्तपना सर्वाधिकृत उस कर्ज पर न साविन करने योग्य बतला देवे परन्तु यह भी बात ध्यानमें रखना चाहिये कि सब कर्जोंके लिये ऐसा नहीं किया जा सकता है केवल उन्हीं कर्जोंके लिये ऐसा हो सकता है जिनकी निश्चित कीमत न होवे तथा निम्नका होना किसी दृश्य कान या बातोंके होने पर निर्भर होने अपना कोई अप देगा कारण उपस्थित हो जाने।

दफा ४७ आपसमें व्यवहार व उसकी मुजराई

यदि किसी ऐसे कर्जबन्धकके जो इस एक्टके अनुसार अपना कर्ज साविन करता हो वा साविन किया चाहें और दिवालियाके दुरक्षियान एक दूसरेसे व्यवहार रहा हो तो इन बातका हिसाब किया जावेगा कि आपसके व्यवहारके सम्बन्धमें एकको दूसरेसे क्या लेना है और एकका लेने वाला कृपा दूसरेमें से मुजरा दिया जावेगा और इस प्रकार मुजराईके बाद जो बाकी निकलेगा उसीके लिये दावा एकका दूसरेके खिलाफ समझा जावेगा व उसकी अदायगी कीजावेगी।

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति उस कर्जों की मुजराई दिवालिया की जायदादसे कराने का अधिकारी नहीं होगा जो उसने इन बातकी सूचना होते हुए दिवालिया का दिया हो कि उसके निरुद्ध दिवालिया की दुरक्षास्त नहीं गई है या उसने स्वयं दिवालिया की दुरक्षास्त दी है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया वा कर्ज किसी व्यक्तिमें होता हो तथा उस व्यक्ति की भी दिवा-

नियम कुछ रूपया वसूल करना हो तो जिसका कर्ज कम होगा वह दूसरों से घटा दिया जावेगा और इस प्रकार जो कर्ज जिसके जिम्मे थादा निरलेगा वह उससे वसूल किया जावेगा । अंग्रेजी एक्ट की इस धारणा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि जहाँ पर एक दूसरेसे लन व देने का व्यवहार हो वह इस दफ्तर नियमों की पाबन्दी आवश्यक है इस दफ्तर में यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि कर्ज दते समय देने वाला कर्जदार के विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दिवालिया की दरखास्त की सूचना देवे तो ऐसा कर्ज पुनः नहीं दिया जावेगा । दिवालिया के एक कर्जदारने आफिशल एसायनासे कुछ रुपये यह वह कर मागे कि वह दिवालिया का काम का इतना उछ सार्ने तक करता रहा है जिसके कारण उसका सुनाफे कुछ हिसाब मिलना चाहिये लेकिन दिवालिया ने आफिशल एसायनासे यह बयान किया कि वह कर्जदार उसके रोजगार को खरीदना चाहता था परन्तु उसने अपना सुवाहिदा पूरा नहीं किया जिसकी वजहसे उस कर्जदारने इन्के तौर पर एक अच्छी रकम वसूल की जाना चाहिये अदालतने यह तय किया कि यदि यह बात ठीक है तो इस प्रकार के व्यवहारको दफ्तर ४७ के अनुसार एक दूसरे का व्यवहार समझा जावेगा और यदि कर्जदारने अपनी जिम्मेदारियों सम्बन्धमें कोई जवाब न देवे कि उसके लहने से कितना रुपया कम कर दिया जावे तो आफिशल एसायना ऐसे कर्जदारके दायरे में नामा कर सकता है, देखो—आर्डी कानून आफिशल एसायना एक्ट A. I. R. 1928. Bangor 49. ज वसके व्यवहारका हिसाब उस रिपोर्टके अनुसार लिया जाना चाहिये जो रिपोर्टिंग आर्डरके समय अर्थात् आफिशल एसायना द्वारा कर्जदार की पाबन्दी पर कर्ज लेने का हुक्म होते समय होवे देखो—19 Bom. 546 इस दफ्तर कर्जदार व आफिशल एसायना दोनों को लाभ है क्योंकि आफिशल एसायना दिवालिया व कर्ज आसानीसे वसूल कर सकता है जो किसी कर्जदारसे लेना है और कर्जदार भी दिवालियाके कर्ज की पुनर्दाई अर्थात् लहने देकर उससे सहूलियतके साथ करण हो सकता है यहाँ नहीं सिन्तु उदागमन से वसूल करने में जो खर्च आदि किये जाना आवश्यक है वह सब बच जाते हैं इसी प्रकार यह दफ्तर दिवालिया सम्बन्ध कोवाई वे इल्का बरने तथा योग्यत पाय हो जानके लिए बनाई गई है और इसी अवस्था नहीं की जा सकती है ।

दफ्तर ४८ कर्जों साबित करनेके नियम

दूसरी सूची (Second Schedule) में दिये हुए नियमोंकी पाबन्दी कर्जों साबित करनेके तरीक़ोंमें, महफूज तथा अन्य कर्जदारोंके कर्जों साबित करनेके हक़में सुवृत्तके मानने या न माननेमें तथा उन सब अन्य मामलोंमें की जावेगी जिनका उल्लेख उची सूचीमें किया गया है ।

व्याख्या—

इस दफ्तर में यह बतलाया गया है कि इस एक्टकी दूसरी सूची (Second Schedule) में वह नियम बतलाये गये हैं जिनके अनुसार कर्ज साबित किये जा सकते हैं । यह नियम उस सूचीके १ से लेकर ८ वें नियम तकमें दिये हुए हैं । उसी सूचीमें यह भी बतलाया गया है कि महफूज कर्जदारों तथा अन्य कर्जदारोंका कर्ज साबित करनेके सम्बन्धमें क्या हक़ है । सूचीके ९ से लेकर १७ वें नियममें महफूज कर्जदारोंके कर्जों साबित किये जानेका वर्णन है । सूचीके २५ वें नियमसे लेकर २७ वें नियम तकमें सुवृत्तके मानने व न माननेका उल्लेख है तथा उसके १८ वें नियमसे २४ वें नियम तक अन्य मामलोंका वर्णन है जैसे कि देहकी हुई जायदादका हिस्सा लिया जाना (१८ से लेकर २१ तकमें) व सुद और भविष्यक कर्ज आदि इस प्रकार इस दफ्तरके अनुसार दूसरी सूचीमें दिये हुए सब नियमोंकी पाबन्दी दिवालियाके मामलों सम्बन्धमें लागू होगी बतलाया गया है अंग्रेजी एक्टकी इस धारणा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि दूसरी सूचीके नियमोंका अवलम्बन नहीं की जा सकता है ।

दफा ४९ कर्जोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना

(१) दिवालिये की आयदाद बांटेते समय नीचे दिये हुए कर्जों और कर्जोंके मुकामिले पहिले बांटे जावेंगे —

(ए) वह सब कर्जों जो सरकार को अथवा किसी अन्य स्यानिक हाकिम को दिये जाने वाले होवें ।

(बी) किसी क्लर्क (मुहारिर) नौकर अथवा मजदूर की तनख्वाह या उजरत जो उसे दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके चार माहके अन्दर काम करनेके पयजमें मिलना चाहिये परन्तु क्लर्ककी तनख्वाह ३००) रुपये तक व नौकर और मजदूरकी उजरत हर व्यक्तिके लिये १००) रुपये तक दिलावाई जायकेगी ।

(सी) वह किराया जो मालिक मालिकान को दिवालियेसे मिलना चाहिये परन्तु इस क्लार्कके अनुसार एक महीनेसे ज्यादा का किराया नहीं मिलेगा ।

(२) उपदफा (१) में जिन कर्जों का उल्लेख है वह आपसमें एक दूसरेके बराबरके कर्जों समके जावेंगे और वह सबके सब पूरे पूरे चुकाये जावेंगे यदि दिवालिये की आयदाद उसके चुकानेके लिये पर्याप्त होवे और यदि दिवालिये की आयदाद कम पड़ती होवे तो वह हिस्सा रसदीके हिसाबसे सबके सब कम करके चुकाये जावेंगे ।

(३) उतना रुपया रोक कर जो सम्बन्धके लिये अथवा और किसी कामके खर्चके लिये आवश्यक होवे बाकी सब रुपयसे जहां तक वह पर्याप्त होगा उपदफा (१) में दिखलाये हुए कर्जों चुका दिये जावेंगे ।

(४) जहां सामे का मामला होवे वहां सामे की आयदादसे पहिले सामेके कर्जों चुकाये जावेंगे और सामीदारों की जुदागाना आयदादसे पहिले उनके जुदागाना कर्जों चुकाये जावेंगे । यदि सामीदारों की जुदागाना आयदाद उनके जुदागाना कर्जों चुकाये जानेके बाद कुछ बचे तो वह सामे की आयदादके तौर पर सबके की जायगी और यदि सामे की आयदाद सामे का कर्ज चुकाये जानेके बाद बचे तो उससे सामीदारोंके जुदागाना कर्ज उनके हिस्सेके अनुसार हिस्सा रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे ।

(५) इस पञ्चके नियमों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्जों जो दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये गये हों, हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एकको दूसरेसे तर्जिह नहीं दी जायगी ।

(६) यदि उपर बतलाये हुए सब कर्जों को चुकानेके बाद कुछ बचे तो उससे दिवालिया करार दिये जानेके बाद का खुद साबित किये हुए सब कर्जोंके सम्बन्धमें छः रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे चुकाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी आयदादसे उसके कर्जोंके उपाये जानेका बर्णन है । उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि तीन प्रकारके कर्जें भिन्ना अहेतु श्राव्य (ए), (बी) व (सी) में रिया गया है सबसे पहिले चुकाये जावेंगे । अगली,

एवम् इम उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह भली भाँति प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है। प्राजा (ए) में सरसरी कर्जोंका उल्लेख है तथा प्राजा (बी) में नोटों व मजदूरोंकी तनखाद व वरदा का भिन्न है इस प्राजमें इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कर्जोंकी तनखाद २०० रुपये तक मिल सकती है व नोट और मजदूरोंको उनका १०० रुपये की आदमी तक अधिकसे अधिक मिल सकती है। प्राजा (सी) के अनुसार एक माइस किराया भी और कर्जोंसे मुकामके मिल सकता है। इस दफाओं अन्य उपदफाओंमें भी (अवश्य एवम्) (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे इस दफामें बतलाई हुई सभी बातोंका मानना आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात् इसके निषेधों अवहेलना नहीं की जासकती है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि उपदफा (१) के प्राजा (ए), (बी) व (सी) में जो कर्जें बतलाये गए हैं वह सब एक दूसरेसे समानता रखते हैं और सबके सब या तो पूरे व चुकाये जाना चाहिये यदि जायदाद काफी होवे अथवा यदि जायदाद उनको चुकानेमें कम पड़े तो हिस्सा रसदीके हिसाबसे वह कम करके चुकाये जाना चाहिये।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदादमें उनके प्रत्यक्ष आदि के लिये आवश्यक क़ान निकालनेके बाद उपदफा (१) के अथवा अन्य कर्जें चुकाये जाना चाहिये। साथैके माध्यमके सम्बन्धमें उपदफा (४) के अनुसार साक्षेकी जायदादसे पहिले साक्षेके कर्जें चुकाये जाना चाहिये व उनके चुकाये जानेके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साक्षी-दारोंके जुदागाना कर्जें उनके हिस्सा रसदीके अनुसार चुकाये जाना चाहिये अर्थात् साक्षेके चारोंबारमें जिस क्रमर हिस्सा मिल साक्षीदार का होवे उसीके अनुसार बचे हुए कर्जोंमें से उसका जुदागाना कर्जें चुकाया जाना चाहिये। वही प्रकार साक्षीदारोंकी जुदागाना जायदादमें पहिले उनका जुदागाना कर्जें चुकाये जावेंगे व उसके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साक्षेके कर्जें चुकाये जावेंगे।

उपदफा (५) में यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें बतलाये हुए निषेधों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्जें जो साबित किये गये हों - हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एक को दूसरेसे कोई तर्जौह नहीं दी जावेगी। यदि दिवालिये की जायदादसे उसके सब कर्जें चुका दिये जानेके बाद कुछ धन बचे तो उसके लिये उपदफा (६) में बतलाया गया है कि उससे सूद छ. रुपया सैकड़ा सालाना की दरसे साबित जुदा कर्जोंके लिये अदा किया जावेगा और यह सूद दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म होनेके पश्चात् अदा किये जाते समय तक दिया जासकता है। कानून दिवालिये का यह नियम है कि सब कर्जें बराबर समझे जावें और यदि अफिशल एसायनीने कुछ कर्जेंलवाहोंसे यह सपष्टांता कर लिया है कि यदि वह कर्जेंलवाह खर्चके लिये अपना देवेंगे तो उनका कर्जें सबसे पहिले पूरा पूरा दिया जावेगा तो इस प्रकारका समझौदा कानूनन रह समझना चाहिये और उस पर अगल नहीं किया जासकता है, देखो पुनरीतपदास एक्ट नम्बर 55 M. L. J. 657.

इस दफासे यह बात भी प्रकट है कि हिस्सा रसदी केवल साबित किये हुए कर्जों पर ही मिलेगा बिल्ग साबित किये हुए कर्जों पर नहीं। इस दफाका सुलासा इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले प्रत्यक्ष आदि के आवश्यक कर्जों को निकालनेके पश्चात् उनसे उपदफा (१) के कर्जें चुकाये जावेंगे इसके बाद और सब कर्जें हिस्सा रसदीके अनुसार चुकाये जावेंगे तब भी यदि कुछ बचे रहे तो उससे सूद दिवालिया करार दिये जानेके बाद छ रुपया सैकड़ा सालाना की दरसे दिखवाया जावेगा। साक्षी साथ बंधा कर्जें चुकाये जावेंगे जो दिवालिया की चर्चाहके सम्बन्धमें साबित कर दिये गये हों।

दफा ५० दिवालिया करार दिये जानेसे पहिलेका किराया

दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेके पश्चात् उस हुक्मसे पहिलेके किरायेके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या लहना कुर्क नहीं किया जावेगा जब तक कि दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म मंजूर न कर दिया गया हो, परन्तु भालिक भकाल या अन्य कोई व्यक्ति जिसने कि वह किराया लेना होवे उस किराये को और कर्जों की भाँति साबित कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्ते उस विषय की समझी जा सकती है कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेसे पहले समर्थके लिये नार्क होवे । वह विषय नार्क और कर्नोने साबित किया जासकता है अर्थात् हिस्सा सदा दिवालियेकी जायदादमे उस बकाया विषयके लिये वसू किया जासकता है । यदि दिवालिया करार दिया जाने वा हुक्म ममूज कर दिया जाय तो उस विषयके लिये दिवालियेकी जायदाद कुर्के बर्ताने जासकती है जयथा नहीं अर्थात् दिवालिया करार दिया जानका हुक्म होनेके पश्चात् उसमें पहिलेके विषयके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या बसका रहना कुर्के नहीं कहा जासकता है । इस दफ्ते नियम की भी अवहेलना नहीं की जासकती है जैसा कि ऐमजी एक्ट की इस दफ्तेमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है ।

वह जायदाद जिससे कि कर्जे चुकाये जासकते हैं

धफा ५१ दिवालियेकी कार्यवाहीका सम्बन्ध

जिसका कर्जदारका दिवालिया होना नीचे दिये हुए समयसे प्रारम्भ होना माना जायगा तथा उसका सम्बन्ध उसी समयसे होगा जाहें वह अपनी दरम्बास्त पर प्रयत्न अपने किसी कर्जदारवाह या कर्जदारवाहों की दरम्बास्त पर दिवालिया करार दिया गया हो ।

(ए) जिस दिवालियेके कामके आधार पर वह दिवालिया करार दिया गया हो उस कामके होनेके समयसे

(बी) यदि यह साबित होवे कि दिवालियेने एकसे अधिक दिवालियेके काम किये हैं तो दिवालिये की दरम्बास्त दायित्व किये जानेके तीन माहके अन्दर जो दिवालियेका काम सबसे पहिले किया गया हो उस समयसे

परन्तु शर्त यह है कि कोई दिवालिये की दरम्बास्त अथवा दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म केवल इस ही कारण रद्द नहीं हो जायेगा कि दरम्बास्त देने वाले कर्जदारवाहके कर्जेके वाद दिवालियेका काम हुआ है ।

व्याख्या—

इस दफ्ते अनुसार दिवालियेकी कार्यवाही वा प्रारम्भ दिवालिये का काम होनेसे समयसे माना जायेगा अर्थात् आदि-काल एतापनी का हुक्म दिवालियेकी जायदाद पर कमी समयसे माना जायेगा जब कि दिवालिये का काम हुआ हो इस दफ्तेमें दिवालियेके कार्यमें तात्पर्य उस कामका सम्बन्ध चाहे दिवालियेके आधार पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो ।

धफा ५१ (बी) में भी मानकी शर्त कर दिया है कि यदि एकसे अधिक दिवालियेके काम साबित हों तो दिवालिये की दरम्बास्त दिये जायेके तीन माहके अन्दर जो काम सबसे पहिले हुआ हो उसके होनेके समयसे दिवालियेकी कार्यवाही का प्रारम्भ माना जायेगा । ऐमजी एक्टकी इस दफ्तेमें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफ्तेमें विषयों की अवहेलना नहीं की जासकती है । इस दफ्तेमें नियमोंका प्रयोग हर एक दिवालियेके सम्बन्धमें समझना चाहिये अर्थात् यदि कोई कर्जदार अपनी दरम्बास्त पर दिवालिया करार दिया जाने अथवा यदि वह किसी कर्जदारवाह या कर्जदारवाहों की दरम्बास्त पर दिवालिया करार

दिया गया हो तो दोनों दशाओंमें हम दफाके निगमों को लागू सम्झना चाहिये इसी दफाके अन्तमें यह भी बात बतला दी गई है कि यदि दिवालिये की दरखास्त देने वाले कर्जेंखाहके कर्जोंके बाद कोई दिवालिये का काम होवे तो केवल इस ही कारण दिवालिवा फगर दिया जानेका हुक्म या दिवालियेकी दरखान्त रद्द नहीं हो जायेगी । अर्थात् उस दिवालियेके कामके आधार पर भी दिवालिवा फगर दिया जाने वा इसमें दिवालिवा है और दिवालिये की दरखास्त चल सकती है ।

दफा ५२ जो जायदाद कर्जेंखाहोंमें बांटी जासकती है उसका विवरण -

(१) नीचे लिखी जायदादको उस जायदादमें शामिल नहीं समझना चाहिये जो कर्जेंखाहानामें बांटी जा सकती है और जो इस धर्कमें दिवालियेकी जायदाद बसलाई गई है:—

(ए) वह जायदाद जो दिवालिवा बतौर अमानत (Trust) के किसी दूसरे शब्दकी धरकसे लिये हुए होवे ।

(बी) इसकी तिजारतके सम्बन्धके औजार और आवश्यक पहिन्ने वाले कपड़े, बिस्तर, खाना पकानेके घरतन और उसका व उसकी चीजी व बच्चोंके लकड़ी काठका सामान (Furniture) परन्तु यह सब औजारों, कपड़ों व दूसरी ज़रूरी चीज़ोंके कुल तीनसौ रुपयेसे ज्यादा का न होना चाहिये ।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातों का ध्यान रखते हुए नीचे बतलाई हुई तकसील की चीज़ें दिवालियेकी जायदादमें समझी जायेंगी:—

(ए) वह सब जायदाद दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भमें दिवालियेकी है या जो उसको प्राप्त हो सकती है अथवा जो दिवालियेको बहाल होनेसे पहिले दिवालियेको मिल सकती है या दिवालिवा जिसको प्राप्त कर सकता है ।

(बी) वह अधिकार जो दिवालिवा, दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भसे अथवा बहाल होनेके समयसे पहिले किसी जायदादके सम्बन्धमें प्रयोग कर सकता है या प्रयोग करनेके लिये कार्रवाई कर सकता है, और

(सी) वह सब माल जो दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भके समय दिवालियेके कर्जोंमें होवे या उसके अधिकारमें होवे और जिसे वह अपने व्यापार या कारोबारके सम्बन्धमें असली मालिक की रज़ामन्दी व इजाज़तसे इस प्रकार रखे हुए होवे जिसमें कि वह स्वयं उस मालका मालिक प्रतीत होता होवे ।

परन्तु शर्त यह है कि क्लार्क (सी) के अनुसार उन कर्जोंके अलावा जो वसूल किये जाने वाले होवें अथवा जो उसके व्यापार या कारोबारके सिलसिलेमें वसूल किये जाने की होवें और होने वाली बातें माल नहीं समझे जायेंगे । और यह भी शर्त है कि वह माल जो क्लार्क (सी) के अनुसार कर्जेंखाहोंमें बांटा जाने योग्य समझा गया हो उस मालका असली मालिक उस मालकी कीमतको साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफा में यह मतलब गया है कि दिवालिये की वीन वीन सी जगदाद इसके कर्जखानों में बाँटी जा सकती है वीन वीन सी जगदाद वीन नई जा सकती है प्रत्येक उपदफा (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०) (५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०) (६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०) (७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०) (८१) (८२) (८३) (८४) (८५) (८६) (८७) (८८) (८९) (९०) (९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

उपदफा (१) में यह जगदाद बतलाई गई है जो दिवालिये के कर्जखानों में नहीं गयी जायेगी । यह उपदफा दो ३ जो में विभक्त है पहिले द्वाय अर्थात् प्रात (५) के अनुसार यह जगदाद जो दिवालिया अमानत अर्थात् बतौर दूरी के लिये हुए होवे उमरों नहीं समझी जायेगी और न वह कर्जखानों में बाँटी जा सकती है ।

अन्तर्जा (४) के अनुसार दिवालिये की कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी कर्जखानों में बटि जाने से रोक कर दिया है अर्थात् उस द्वात के अनुसार व्यापार सम्पत्ती, विस्तार, खाना पकाने के बर्तन तथा आवश्यक छकरी बाँट की चीजें छोड़ दो गई हैं परन्तु रसी द्वाय में यह भी बतलाया गया है कि इन चीजों में कुछ कोषाधिक (१००) रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये अर्थात् ऊपर बतलाये हुए क्रियक सामान हीन सौ रुपये की सीमा तक कब होना जा सकती है । गृहजन्यों का एक फर्मे एक इन्सुरेंस कम्पनी का सेक्टर तथा खाना भी था । उक्त इन्सुरेंस कम्पनी के कार्टर के कम्पनी का कुछ रुपया गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्स में लगा देना हुक्म दिया और गृहजन्यों के लिये कुछ देर करके वह रुपया प्रोमिसरी नोट्स में लगा दिया परन्तु उसके बाद हीन ही वह फर्मे दिवालिया करार दे दिया गया तो यह तथ हुआ कि वह खाना (अर्थात् गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्स) उस फर्मे के पास बतौर अमानत (Trust) के थी और हम लिये इस दफा के अनुसार कर्जखानों में नहीं बाँटी जा सकती थी, देखो—समस्त वस्तु आधिकार एसायनी 35. Mad. 712. यदि कोई सोना जवाहरानों के लिये किसी व्यक्ति को दिया गया हो और वह उसके बाद दिवालिया करार दिया जाय तो वह सोना यदि उसका ठीक तौर से पता न लगना हो उस व्यक्ति का जगदाद समझा जावेगा देखा—28 Mad. 403.

उपदफा (२) में यह तकलीफ बतलाई है जिसके होने पर जगदाद कर्जखानों में बाँटी जाने योग्य समझा जावेगा । अन्तर्जा (५) के अनुसार दिवालिये की कर्जखानों के आरम्भ में तथा बहाल होने से पहिले जो जगदाद दिवालिये की होने या उसकी मिल सके वह सब दिवालिये की समझा जावेगी और वह उसके कर्जखानों में बाँटी जा सकती है । यह रुपया जो दिवालिये की वस्तुओं में किसी समय मिलने वाला होवे आधिकार एसायनी की विधि का जो कि वह रुपया उसी समय अदा किया जाने वाला नहीं है । देखो—26. Mad. 440 इस दफा के अनुसार किसी घुआदि के वह अधिकार आधिकार एसायनी की प्रात हो सके जो दिवालिये की उसके अनुसार मिल सकते हैं, देखो—अ वनाम वाकर 40 Cal. 253. आधिकार एसायनी एक दिवालिये की रिपोर्ट पर पॉलीसी (Policy of Insolvency) नीति की ओर एक खतरा है उस दिवालिये की ताकत खोद दिया । इसके बाद दिवालिया पर गया उसके बाद पर खरीदारने पॉलीसी का रुपया वसूल किया आर उसे एडमिनिस्ट्रेटर अमानत को दे दिया । यह तथ किया गया कि आधिकार एसायनी के घुआदि के वह रुपया दिवालिये की वस्तुओं में ही मिलना चाहिये । देखो—18. Mad. 24 एक कर्जखाने के लोको न बोलाम कानून का हुक्म एक जमीन के निम्नत हामिल किया और इसके बाद दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म ॥ गया तो यह तथ किया गया कि आधिकार एसायनी का वह उस जमीन पर होगा, देखो—42 Cal. 72 29, Mad. 903. यदि किसी घुआदि के रुपया घुआदि के सिलसिले में जमा किया गया हो और बाद में किसी दो गई हो तो उस रुपये पर कर्जखाने अधिकार का ॥ घुआदि, देखो—35. Mad. 355. यदि कोई वनने के

क्रिये सेना दिया गया हो और दिवालिया करार दिये जाने पर उस सेने का ठीक ठाक पता न लगा सके तो वह सेना दिवालियरी जायदाद सम्पत्ति जावेगी और सोनेके मालिकका कोई ज्यादा हक न सम्पत्ति जावेगा अर्थात् वह माफूली कर्जेस्वाहोंकी तरह अपभा कर्ज समित कर सकता है, देखो—28 Mad. L. I. 403. तनस्वाद भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है, देखो—34. Mad 183. मयास हाई-कोर्टने यह तथ किया था कि किसी समुक्त हिन्दू परिवारके कर्ता को उस परिवारकी जायदाद की अनश्वर करनेके जो अधिकार हैं वही अधिकार आफिशल एसायनीके उस जायदादके सम्बन्धमें सम्पन्न चाहिये। देखो—26. Mad. 214.

यदि काम होनेके समयमें (During business hours) किसी गोदामकी चार्ज निममें माल भरा हो दिवालियेके कब्जेमें रहता है। परन्तु उसके बादके वक्तमें वह चार्ज उस शक्त्तके पास रहता है। जिसके पास गोदाममें रखा हुआ माल रहन हो तो वह माल दिवालियेकी हिकाजमें रहने वाला माल सम्पत्ति जावेगा, देखो—22 Mad. L. I. 441. यदि दिवालियेके लानर छपुर्दार या किरायेदारके कब्जेमें कोई माल होवे तो वह दिवालिये में। के कब्जेमें सम्पत्ति जावेगा क्योंकि दिवालियेकी की तरफमें वह माल उसके कब्जेमें रहता है। इस दफाकी अन्तर्गत उपरका का मानना आवश्यक है अर्थात् उनकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

पिछले सौदों पर दिवालिया होने का प्रभाव

दफा ५३ इजरायके सम्बन्धमें डिक्रीदारोंके अधिकारोंमें रुकावट

(१) यदि किसी कर्जदारकी जायदादके विरुद्ध डिक्री जारी कर्गई गई हो तो उस इजरायसे फायदा कोई भी व्यक्ति आफिशल एसायनीके मुकामिले नहीं उठा सकेगा परन्तु यदि उस कार्रवाईके चालू करनेसे पहिले उसको दिवालिये की दरब्यास्त दी जाने की कोई सूचना न रही हो और वह दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले नीलामसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे बख्तली की जायके तो उसके पाने का वह व्यक्ति अधिकारी होगा।

(२) इस दफा का कोई प्रभाव महफूज कर्जेस्वाहके उन अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जो उसे महफूज जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिक्री की इजरायके लिये प्राप्त है।

(३) यदि कोई व्यक्ति नेकनीयतीसे इजरायके सम्बन्धमें नीलाम की हुई किसी जायदाद को खरीद करे तो उसको आफिशल एसायनीके विरुद्ध हर प्रकारके अधिकार उस जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त होंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् सब जायदाद आफिशल एसायनीकी सम्पत्ति जावेगी और उसे खदामाना तौर पर कोई कर्जेस्वाद नहीं प्राप्तकेगा।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि इजराय करने वाले डिक्रीदार की दिवालियेकी दरब्यास्त दिये जाने की कोई सूचना न रही हो और दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेसे पहिले कुछ जायदाद बख्तली जायके तो वह डिक्रीदार उसके पाने का हकदार होगा अन्यथा नहीं किन्तु उस सब जायदाद का हकदार आफिशल एसायनी सम्पत्ति जावेगा।

इस प्रकार यदि सौदा रुपयेके लिखित इनाममें कोई जायदाद कुर्क होकर नीलाम पर चढ़ाई गई हो परन्तु नीलामसे पहिले मरियून दिवालिया क़ार दे दिया जावे और उसके बाद नीलाम होने पर कोई व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद को ख़रीदे तो ऐसे ख़रीदारको कोई हक़ नहीं पहुचता है, देखो—31. Mad. 493. यदि हिस्सा सस्ती पानेके लिये किसी इनाममें दाख़्वास्त दी गई हो तो वह दाख़्वास्त इस दफ़्तेके अनुसार इनामकी दाख़्वास्त नहीं समझी जासकती है, देखो—39 Mad. 25. यदि मरियून अदालतमें दाख़िर न होवे विन्तु उसकी इतिहासके लिये कोई रूपया जमा किया जावे तो वह रूपया डिमीदार पाने का अधिकारी है, देखो—39. Cal. 1048.

उपवफा (२) में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस दफ़्ता का कोई प्रभाव मरियून कर्तव्यवालोंके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा अर्थात् वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिमी को नियम पूर्वक इनाम कर सकता है ।

उपवफा (३) के अनुसार नेकनीयतीके साथ जायदाद ख़रीदने वालोंकी बचत कर दी गई है अर्थात् यदि किसी व्यक्तिने किसी इनामके सम्बन्धमें नीलामकी हुई जायदाद को ख़रीदा हो तो वह व्यक्ति उस जायदादके पाने का पूर्ण हक़से अधिकारी समझा जावेगा और आधिकार्य एसायनों उसके अधिकारोंमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा । इस दफ़्तेके नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि सैम्युली एक्ट की इस दफ़्ता की प्रत्येक उपवफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे साबित है ।

वफा ५४ इजराय करने वाली अदालतोंके दिवालिये की जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य

यदि नीलाम की जाने योग्य जायदादके विवरण डिमी जारी कराई गई और उसके मीलाम होनेसे पहिले अदालत को यह नोटिस दे दिया जावे कि मरियून विधालिया क़ारार दे दिया गया है तो इजराय करने वाली अदालत दाख़्वास्त दिये जाने पर जब कि यह जायदाद अदालतके कब्ज़ामें होवे जायदादको आधिकार्य एसायनीके सुपुर्दे किये जाने का हुक्म दे देगी परन्तु इजराय का ख़र्च उस जायदादसे सबसे पहिले वसूल किया जावेगा और आधिकार्य एसायनी को अधिकार है कि यह कुल जायदाद को या उसके किसी हिस्से को बेच कर उस ख़र्च को चुका देवे ।

व्याख्या—

इस दफ़्तेके अनुसार यदि नीलाम होनेसे पहिले इनाम करने वाली अदालत को मरियूनके दिवालिया क़ारार दे दिये जाने की सूचना मिल जावे तो वह इनामकी जायदाद ख़रीदने की ग़ैर देवगी और दाख़्वास्त खाने पर अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि वह जायदाद आधिकार्य एसायनोंके सुपुर्दे कर दी जावे । इस नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि सैम्युली एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार इनाम का ख़र्च भी उस जायदादसे सबसे पहिले वसूल किया जासकेगा अर्थात् वह खर्च पर सबसे पहिले वार माया जावेगा । इस दफ़्तेमें आधिकार्य एसायनों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह इस नारके उद्देश्यके लिये इस जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेच सकता है शर्तु आधिकार्य एसायनों ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि सैम्युली एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है ।

वफा ५५ स्वयं किये हुए इन्तकाल जायदाद की मसूखी

यदि किसी इन्तकाल जायदाद होनेके पदचात् दो सालके अन्दर इन्तकाल करने वाला व्यक्ति दिवालिया क़ारार दे दिया जावे और वह इन्तकाल जायदाद पहिले तथा किसी विधायक

पक्षमें अथवा किसी खरीदार या बार रखने वाले मूल्यवान मुवाविजा लेकर नैकनीयतीके साथ न किया गया हो तो वह इन्तकाल जायदाद आफिशाल पसायनीके विरुद्ध रह समझा जावेगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार केवल वही इन्तकाल जायदाद जो दिवालिया करार दिये जानेके दो साल पहिले दिये गये हों भले प्रकार सुरक्षित समझना चाहिये। दो सालके अन्दर किये हुए वही इन्तकाल जायदाद सुरक्षित होंगे जो नैकनीयतीके साथ पर्याप्त कीमत लेकर दिये गये हों। विवाहके सम्बन्धमें तथा पहिले दिये हुए इन्तकाल भी सुरक्षित समझना चाहिये। इसके विरुद्ध यदि दो सालके अन्दर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार दिये गये हों तो वह अफिमल पसायनीके विरुद्ध रह समझा जावेगा। इस दफाके नियम माननाय समझना चाहिये जैसा कि अंग्रेज एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। इस दफामें जो नैकनीयतीसे इन्तकाल जायदादके दिये जाने की व्यवस्था बतलाई गई है उसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति के हकमें इन्तकाल जायदाद दिया गया हो उसमें नैकनीयतीसे इन्तकालको कराया हों यही धुन 16 Mad. 397. से निकलती है। यदि कोई घुर्तद्दिन किसी रैकनामे को जो दो सालके अन्दर दिया गया हो पेश करे तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि रैकनामा नैकनीयतीके साथ मुआविजा देकर लिखाया गया था, देखो—43 Mad. 739.

दफा ५६ कुछ मामलोंमें तरजीह का रह किया जाना

(१) यदि कोई कर्जदार अथवा कि वह अपने कर्जोंको अपने रुपयेसे न चुका सकता हो किसी एक कर्जखवाहके हकमें कोई इन्तकाल जायदाद करे या कोई अदायगी करे या कोई ज़िम्मेदारी लेवे और कोई अशालती कार्रवाई करे या होने देवे और उसकी यह नियत होवे कि उस कर्जखवाह को और कर्जखवाहोंके मुकाबिले तरजीह मिल जावे और ऐसे सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दिवालिये की दरखवास्त दीजाने पर यदि वह कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह सब सौदे आफिशाल पसायनीके लिये धोखाधड़ीसे किये हुए सौदे माने जावेंगे तथा वह समझ जावेंगे।

इस दफा का कोई प्रभाव ऐसे व्यक्तिके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जिसने नैकनीयतीसे दिवालियेके किसी कर्जखवाहसे मूल्यवान मुआविजा देकर किसी अधिकारको प्राप्त किया हो।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यह सब सौदे जो दिवालिया किसी एक कर्जखवाह को और कर्जदारोंके मुकाबिले तरजीह देनेके लिये करे ता वे वह समझ जावेंगे किन्तु इस दफाके अनुसार वह समझ जाने वाले सौदे वही समझ रह होंगे जब कि सादा करन वाला व्यक्ति दिवालिया करार दे दिया जावे और दिवालिया करार दिये जाने की दफ्तरान उक्त सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दी गई हो। उपदफा (१) के नियमों का मानना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेज एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार उपदफा (२) के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जासकता है।

उपदफा (१) के लिये इस बात का सा ध्यान रहना चाहिये कि सादा होने समय दिवालिया अपने कर्जों को अपने रुपयेसे न चुका सकता हो। मगरा हाईकोर्टने यह तय किया है कि अंग्रेजी एक्टमें इस दफाके प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द का तात्पर्य (Vedable) शब्दसे समझना चाहिये और सादा बात का तात्पर्य इस से वह सादा रह नहीं है किन्तु उस समयसे रह है जब कि आफिशाल पसायनी का हक उस पर पहुँच गया। देखो—25 Mad. 308. महानगरका एक कर्म एक इनरारसे कम्पनीके अद्वैकटोंने उस कर्मके पास बच हुए रुपयेसे उस सरकारी बांगन खरीदने का हुकम दिया। कुछ देर होनेके पश्चात् वह कायब खरीद गये और उसमें बाद फौरन ही वह महानगर दिवालिया करार दिया गया तो यह तय किया

गया कि कोई धोखारेसे तभीह ऐसे मामलेमें नहीं दी गई थी. देखो—35 Mad. 712. यदि दिवालिया क़ारर दिये जानेसे कुछ ही पक्षोंमें कोई इतकाल जायदाद दिवालियेने अपनी सौ के हकमें किया हो तो उसकी सौ को चढ़िये कि वह साबित करे कि सौदा कायम रहा जाना चाहिये अर्थात् वह रद्द नहीं होना चाहिये, देखो—24 I. C 518.

इस दफाके लिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वहाँ सौदे जो एक कर्जस्वाह को दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्गह देनेके लिये दिये गये होंगे रद्द समझे जायेंगे। कर्जदार की नीयत केवल उस ही बातमें नहीं समझ लेना चाहिये कि किसी सौदेके एक कर्जस्वाह को लाभ पहुच गया है व दूसरे कर्जस्वाह याँही रद्द गये हैं इसके लिये सब हम्पनों पर ध्यान करना चाहिये तथा इसके लिये इन्क़्लण्डके कानून तथा उसके पैमानों पर भी ध्यान दिया जासकता है अर्थात् उनके आधार पर यहांके फैसले किये जा सकते हैं, देखो—42 Mad. 510. इसी मामले में यह भी तय किया गया था कि दिवालियेने अपने कामके लिये तथा अपने कारोबार की बाजू रखनेके लिये किसी सौदेको किया था तो वह सौदा दरम्यान धोखारेसे तर्गह देने वाला सौदा नहीं समझा जावेगा। तीन माहरी जो अवधि इस उपदफाके तर्गहर् गये है उसमें यह तर्गह नहीं है कि सौदा होनेसे तीन माहके अंदर सौदा करने वाला व्यक्ति दिवालिया क़ारर दे दिया गया हो किन्तु उसका तर्गह यह है कि सौदा होनेसे तीन माहके अंदर उसके विरुद्ध दिवालिये की दम्बाल दे दी गई हो इस उपदफाके अनुसार केवल इतकाल जायदाद ही रद्द नहीं समझेंगे किन्तु दूसरे प्रकारके सौदे भी जैसे कि अदायगी या कोई बिम्बेदारी जो दिवालियेने किसी एक कर्जस्वाहके लिये की हो।

उपदफा (२) में सब लोगोंके बचनकी व्यवस्था बतलाई गई है नियंतेने नेकनीयतीसे कोई अधिकार दिवालियेके किसी कर्जस्वाहसे या उसके मार्फ़त प्राप्त किया हो। इस कानून की ध्यान रहना चाहिये कि वह सौदा केवल दिवालिया सौदा ही न होवे किन्तु वह मूलबाल मुकदमोंके दिये जाने पर किया गया हो।

दफा ५७ नेकनीयतीसे किये हुए सौदों की बचत

कुछ इन्क़ालात (Transfers) तथा तर्जिहात (Preferences) के लिखे जाने तथा उनको रद्द किये जानेके सम्बन्धमें जो नियम उपर दिये जाचुके हैं उनका ध्यान रखते हुए नीचे दिए हुए सौदे दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें इस दफाके अनुसार किसी बात से रद्द नहीं होंगे:—

- (५) यदि दिवालिये ने अपने किसी कर्जस्वाह को कोई अदायगी की हो,
- (६) यदि कोई अदायगी या सुपुर्दगी दिवालिये को की गई हो,
- (७) यदि दिवालिये ने कोई इन्क़ालात जायदाद पर्याप्त मुआधिज़ा लेकर किया हो,
- (८) यदि कोई मुबाहिदा या सौदा दिवालिये के साथ कीमती मुआधिज़ा लेकर किया गया हो।

परन्तु शर्त यह भी है कि ऊपर बतलाया हुआ सौदा, दिवालिया क़ारर दिया जानेका हुकम होनेसे पहिले हुआ हो तथा जिस व्यक्ति के हाथ सौदा किया गया हो उसको सौदा किये जाते समय कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की दम्बालास्त दिये जाने की सूचना न रही हो।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार नेकनीयती से किये हुए सौदों की शर्त या प्रस्थ किया गया है। इस दफा में उन्हीं सौदों की शर्त या विधान है जो दिवालिया क़ारर दिये जाने का हुकम होने से पहिले किये गये हों तथा यह भी बात ध्यान में रहना

चाहिये कि सौदा होते समय उस व्यक्ति का जिसके हक में सौदा किया गया हो कर्जदार के विरुद्ध दिवालिये की दरखास्त दिये जाने की सूचना न हो अर्थात् यदि पञ्चदश दिवालिये की दरखास्त दे रली हो अपना उसके विरुद्ध दिवालिये की दरखास्त दे गई हो और इसके बाद कर्जदारने कोई सौदा किया हो तो उस सौदे के किये जाते समय उस व्यक्ति को दिवालिये की दरखास्त की सूचना न होना चाहिये जिसके हकमें सौदा किया गया हो वरना उस सौदे की रक्षा इस दफा के अनुसार नहीं हो सकेगी।

इस दफा के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है जिस कि अंग्रेजी एक्ट में प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्द से प्रकट है। नैक-नीयतासे किये हुए सौदेही इस दफाके अनुसार सुरक्षित हैं वह सौदे जो कानून दिवालियासे बेसा काम उठाने की नीयतसे किये गये हो अपना या स्वयंही दिवालिये का काम समझे जा सकते हैं इंग्लिश दफा के पान नहीं हो सकते हैं देखो—39 Mad. 250 यदि कोई कर्जा सौदा किया गया हो तो उससे किसी व्यक्ति को हक नहीं पड़ूँ सक्ता है यदि दस्तावेज लिखकर रजिस्ट्री भी कर दीगई हो, देखो—34 L. C. 435 जिन सौदोंकी रक्षाका उल्लेख इस दफामें किया गया है वह चार भागोंमें विभक्त किये गये हैं तथा उनका वर्णन क्रम (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है।

फलाज (ए) में उस अदायगी का जिक्र है जो दिवालिया ने अपने भिन्नी कर्जस्वाह की की हो।

फलाज (बी) में यदि दिवालिये को कोई अदायगी की गई हो या कोई कर्जा दिया गया हो तो उनकी भी रक्षा इस दफा के अनुसार की जा सकती है।

फलाज (सी) के अनुसार यदि दिवालिये ने क्रीमत पर्याप्त लेकर कोई इन्तकाल वायदाद किया हो तथा कठान (डी) के अनुसार यदि कोई सौदा या प्रवाहिता पर्याप्त धन लेकर किया गया हो तो ऐसे सौदे इस दफा के अनुसार सुरक्षित समझना चाहिये। इस दफा से पहिले जो नियम किसी सौदे के रद्द किये जानेके सम्बन्ध दिये जा चुके हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है अर्थात् दफा ५३, ५४, ५५ व ५६ में बतहाये हुए नियमों का ध्यान रखने हुए इस दफा के नियमों का प्रयोग समझना चाहिये।

जायदाद का वसूल किया जाना

दफा ५८ आफिशल एसायनी द्वारा जायदाद पर कब्जा लिया जाना

(१) जितनी जग्दी हो सकेगा आफिशल एसायनी दिवालियेके कांफ़ज़ात, किताबों तथा दस्तावेज़ों पर कब्ज़ा करेगा तथा उस सब जायदाद पर भी कब्ज़ा करेगा जिस पर दस्तवी कब्ज़ा लिया जासकता है।

(२) दिवालिये की जायदाद पर कब्ज़ा लेने तथा उस पर कब्ज़ा रखनेके सम्बन्धमें आफिशल एसायनीके वही अधिकार होंगे जो सन् १९०८ ई० के ज़ाबता दीवानीके अनुसार किसी जायदादके सम्बन्धमें नियुक्त किये हुए रिस्तीवरके होते हैं और अदालत उसकी दरखास्त पर इस प्रकार का कब्ज़ा दिलाने तथा कायम रखने की कार्रवाई कर सकती है।

(३) यदि दिवालिये की कोई जायदाद स्टॉक (Stock), सहजजके शेअर्स (Shares in Ships), अथवा अन्य किसी प्रकार की भूँसी जायदाद होवे जो किसी कम्पनीके दफ़तर अथवा किसी व्यक्तिके कागज़ातमें एकसे दूसरेके नाममें की जासकती हो तो आफिशल एसायनी इस

प्रकारकी जायदादके इतकालके सम्बन्धमें वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया स्वयं इस अवस्थामें जब कि वह दिवालिया नहीं हुआ था बरत सकता हो ।

(४) जोय कि दिवालिये की कोई जायदाद दांच की शकलमें होवे तो इस प्रकारकी बातोंके लिये यह मान लिया जावेगा कि वह बाकायदा आफिशल एमायनीके हकमें कर दी गई है ।

(५) यदि किसी खजाञ्ची या दूसरे अफसरके अथवा किसी महाजन एटार्नी या पजण्टके कजमें दिवालिये की तरफसे कोई रुपया या जमानतें होवें जो कि वह दिवालिये या आफिशल एमायनीके विरुद्ध नहीं रोक सकता है तो वह रुपया आफिशल एमायनी को अदा करेगा अथवा उसको आफिशल एमायनीके सुनुई करेगा यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिये यह माना जावेगा कि उसने अदालत की तै हीन की है और इसके लिये आफिशल एमायनी की दरखास्त आने पर दण्ड का भागो होगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालिये की जायदाद पर आफिशल एमायनी द्वारा कब्जा लिये जाने का उल्लेख है । उपरका (१) के अनुसार आफिशल एमायनी का कर्तव्य है कि वह निजनी जन्मी हो सके दिवालिये की ऐसी जायदाद पर कब्जा ठे छेदे जिस पर दली कब्जा । क्या जासकता है उसमें दस्तावेजों व हिस्सों की किताबें भी शामिल है । अंग्रेजी एक्टमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रस्ट है कि आफिशल एमायनी को ऐसी वस्तुओं पर कब्जा लेनेमें देर नहीं करना चाहिये और न इस उपद्राके नियमों की अवहेलना ही करना चाहिये ।

उपद्रा (२) में आफिशल एमायनीके कानूनी अधिकार का वर्णन है । इस उपद्राके अनुसार आफिशल एमायनीके बड़ा अधिकार सम्पत्ति चाहिये जो कायदा दीवानीके अनुसार जायदादके लिये नियुक्त किये हुए रितीरके होते हैं और आफिशल एमायनीके दरखास्त देने पर अदालत कब्जा केन तथा कायदा रखनेके लिये दूसरोंको मजबूर कर सकती है ।

उपद्रा (३) में शार्स (Shares) आदि ऐसी जायदाद का वर्णन है जो किसी कम्पनी आदि की किताबोंमें एकके नामसे दूसरेके नामसे की जासकती है उनके बारेमें यह बतलाया गया है कि आफिशल एमायनी वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया होनेसे पहिले बतत सकता था । इस नियम की पाबंदीके लिये आफिशल एमायनी बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस उपद्रा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रस्ट है अर्थात् वह आवश्यकतातुल्य कार्य कर सकता है ।

उपद्रा (४) के अनुसार आफिशल एमायनी को दिवालियेके मामलोंके सम्बन्धमें दावे आदि दायर करनेके पूर्ण अधिकार हैं ।

उपद्रा (५) में बतलाया गया है कि यदि किसी व्यक्तिगत या जो खानाबी महाजन, एटार्नी या ऐमेन्ट होवे इस हिसीवतसे दिवालिये का कोई रुपया या दस्तावेजें होवें जो बावदले दिवालिये की बर्षित मिलना चाहिये तो उन लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वह रुपया या दस्तावेजों आफिशल एमायनी को द देने अथवा वह अदालतकी ताहीन करनेके दोनों समझे जावेंगे और उसको आफिशल एमायनीके दरखारान देने पर उस जुर्मे का दण्ड दिया जासकता है अगला एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रस्ट है कि इस उपद्राके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है ।

दफा ५९ दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेना

(१) अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिये की किसी जायदादके लिये जो दिवा-

लिये अथवा अन्य किसी व्यक्ति के कब्जे या देखरेख में होवे कब्जा लेने का वारण्ट नियत किये हुए अफसरके नाम अथवा कानिस्टेबिलसे ऊपरके ओहदे वाले पोलिस अफसरके नाम दे देवे और इस प्रकार कब्जा लेनेके लिये दिवालियेके मकान इमारत या कमरे का दरवाजा तोड़ने का अधिकार दे सकती है जहां कि दिवालियेकी मौजूदगी का अनुमान होवे अथवा जहां पर उसकी जायदाद होने का अनुमान होवे ।

(२) जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालियेकी जायदाद किसी ऐसे मकान या जगहमें छिपाई गई है जो कि दिवालियेकी नहीं है तो अदालत उचित समझने पर ऊपर बतलाये हुए अफसरके नाम तलारी का वारण्ट जारी कर सकती है जो उस वारण्ट की मंशाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

व्याख्या—

मेसीडी एक्ट की १४ धारामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दतः प्रकट है कि इस धाराके विषयों की प्रावधानों के लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयाचित कार्रवाई कर सकती है ।

उपधारा (१) में दिवालियेके मकान या कमरेमें हुमर तलारी लेने व कब्जा लेने का वट्टा है तथा उपधारा (२) में दिवालियेके मकानके अतिरिक्त अन्य जगहमें पुनः तलारी लेने तथा कब्जा करनेके अधिकार का वर्णन है । इस धाराके अनुसार वारण्ट इस धराके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये नियत किये हुए अफसरके नाम दिया जाना चाहिये अथवा ऐसे पुलिसके अफसरके नाम दिया जाना चाहिये जिसका ओहदा कानिस्टेबिलसे बड़ा होवे अर्थात् जो पनिदार, इन्स्पेक्टर आदि उस उद्योग का पुलिस अफसर होवे । वारण्ट केवल कब्जा लेने ही के लिये नहीं दिया जा सकता है किन्तु इमारत या कमरेका किबाड़ तोड़ कर पुनः व उसके अन्दर कब्जा लेने का अधिकार दिया जा सकता है । उपधारा (१) के अनुसार वारण्ट मामूली तौर पर हर मामलेमें दिया जा सकता है क्योंकि दिवालियेके मकान या कमरेमें उसी की चीजोंके होने का अनुमान किया जा सकता है किन्तु उपधारा (२) के अनुसार वारण्ट तभी वक्त दिया जा सकेगा जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालियेकी जायदाद दरअसल किसी अन्यके मकान आदिमें छिपाई गई है वारण्ट दोनों उपधाराओंके अनुसार एका अफसरके नाम दिये जावेगे जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है तथा वह अफसर वारण्ट की मंशाके अनुसार ही कार्रवाई करेगा अर्थात् मन्सूनी न कर सकेगा नौ यह आवश्यक नहीं है कि वारण्ट की अग्रगण्यताओं की जावे अपितु वारण्ट की मंशा को समझे हुए समयाचित काम करेगा इस प्रकार इस धाराके अनुसार अदालत दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा उसके मकान तथा अन्य जगहमें अतिरिक्त वारण्टके मकान का ताजा आदि अथ वस्तुओं की दूर करके दिया सगती है ।

धारा ६० दिवालियेकी तनख्वाहका कर्जस्वाहोके लिये लिया जाना

जब कि दिवालिया फौज या जहाजी पेड़ का अफसर होवे या शाहन्शाह की हिन्दुस्थानी सामुद्रिक नौकरी में होवे या केशरीहिन्द की नौकरी में अफसर फ्लर्क या अन्य किसी प्रकार से काम करता होवे तो अफिशल पसायनी उसकी तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिक्रीमें कुर्क किया जा सकता हो तथा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे कर्जस्वाहों में बांटे जाने के लिये ले लेवेगा ।

(२) यदि ऊपर बतलाये हुए मामलों के अतिरिक्त दिवालिया कोई तनख्वाह या आमदनी पाता होवे तो अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिया फरार दिये जाने का हुक्म होने के पश्चात् किसी समय भी और उस समय पर जिस प्रकारका हुक्म मुनासिब समझे अफिशल

पसायनीकी अदायगीके लिये दे सकती है जिसमें दिवालिये की आमदनी या तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिमीमें कुर्क किया जा सकता हो अथवा उसका कोई हिस्सा कर्जपूवाहोंमें बाँटे जानेके लिये आफिशल पसायनी बसूल कर सके ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी तनखाह तथा अन्य आयदनी के कुर्क किये जाने तथा उसके कर्जपूवाहानमें बाँटे जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है ।

उपदफा (१) में कौनी या जहानी बँहके अद्वार तथा सरकारी सिविल सर्विसेके अफसर या क्लर्क या दूसरे प्रकारसे काम करने वालोंके दिवालिया करार दिये जाने पर उनकी तनखाहके कुर्क किये जानेका उल्लेख है । इस उपदफाके अद्वारा इन अफसरोंकी तनखाहका बड़ा हिस्सा कुर्क किया जासकता है जो कितां डिमीमें वापस कुर्क किया जा सकता है परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि उतना हिस्सा अवश्य कुर्क किया जाना चाहिये उससे कम भी कुर्क किया जासकता है किन्तु उससे अधिक कुर्क नहीं किया जाया चाहिये । अदालत जिस हिस्सेके लिये हुक्म देने बड़ी हिस्सा कुर्क होगा अदालत अपनी इच्छानुसार इसके लिये हुक्म देसकती है ।

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यामित होता है कि इसके नियमों की अवज्ञा नही की जाना चाहिये अर्थात् इस उपदफामें बतलाये हुए अफसरोंकी तनखाहका कुर्क किया जाने योग्य अथवा कोई हिस्सा कुर्क होकर कर्जपूवाहानमें अवश्य बाँटा जाना चाहिये ।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की तनखाह तथा आमदनीके कुर्क किये जानेका वर्णन है इसके लिये हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रकट है इस प्रकारका हुक्म दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् दिया जा सकता है और उतने समयके लिये दिया जा सकता है जिनकेके लिये अदालत प्रस्तावित समझे इस उपदफाके अनुसार भी उसकी ही तनखाह या आमदनी कुर्क की जासकती है जितनी कितां इनमें डिमीमें कुर्क की जासकती है वसने अधिक नहीं किन्तु उससे कम कुर्ककी जासकती है यह आमदनी या तनखाह कुर्क होकर आफिशल पसायनी की इस्तियेमिलेगी कि वह कर्जपूवाहानमें बाँटी जासके । इस दफाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया स्वयं ही अपनी दिवालियेकी दशा होने पर पूरी आमदनी या तनखाहको लाभ व वट्टा इसके लिये कि एम्क कर्जपूवाहान परदे की रहे किन्तु कर्जपूवाहानों की इसकी आपस में आपसमें जो तनखाह आदिकी शकल में दिवालिया पावे लाभ पहुँच सके । अदालतकी इच्छा पर उस दफाके अनुसार बर्तवारा करता निर्भर है ।

दफा ६१ जायदादका एकके पाससे दूसरेके पास जाना या एकमे दूसरेको मिलना

दिवालिये की आयदाद एक आफिशल पसायनीके पाससे दूसरे आफिशल पसायनीके पास पहुँच आबगी और आफिशल पसायनी जब तक कि वह उस हैसियतसे काम करेगा दिया-लिये का जायदादका अधिकारी होगा तथा इसके लिये किसी हन्तकाल किये जानेकी अवश्यकता न होगी ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि आफिशल पसायनी बिना किसी हन्तकालके अर्थात् बिना दस्तावेज आदि बिछे व रजिस्ट्री कराये दिवालिये की जायदाद का अधिकारी होगा । यदि दिवालिये की जायदाद किसी आफिशल पसायनीके अधिकारमें रहे और उस आफिशल पसायनीके स्थानमें दूसरा आफिशल पसायनी नियुक्त किया जावे या अर्थात् रूपस कम करे तो पहिले आफिशल पसायनीके पाससे दिवालिये की जायदाद दूसरे आफिशल पसायनीके पास पहुँच आबगी । आफिशल पसायनी

दिवालिये की जायदाद का अधिकारी उस समय तक रहेगा जब कि वह उस दिवालिये की जायदाद से लिखे आधिकार प्राप्त न रहेगा अथवा एक्ट की इस दफा में (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफा के नियमों की यावदा आवश्यक है ।

दफा ६२ बिला लाभ की व भारी बार वाली जायदाद को छोड़ दिया जाना

(१) यदि दिवालिये की कोई जायदाद ऐसी जमीन होवे जिस पर भारी बार होवे या जो किसी कम्पनी के शेयर अथवा स्टॉक (Stock) होवे या जो बिला मुनाफे वाले मुवाहिदे होवे या इस प्रकार की जायदाद होवे जो बेची न जा सकती हो या जल्दी इस कारण न बेची जा सकती हो कि ये चने चाल पर भारी काम के करने का अथवा किसी रुपये के अदा करने का भार आजाता हो तो आधिकार प्राप्तानी दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होने के बावजूद महीने के अन्दर ऐसी जायदाद को, उन नियमों का ध्यान रखते हुए जो आगे दिये हुए हैं छोड़ सकता है बिला इस बात का खयाल रखते हुए कि वह उस जायदाद को बेच सकता था या उस पर क़ब्ज़ा ले सकता था या मालिकाना कायम करने की कोई कार्रवाई कर सकता था परन्तु शर्त यह भी है कि यदि दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होने के एक माह के अन्दर आधिकार प्राप्तानी को ऐसी जायदाद का हक न हुआ हो तो वह उस समय से जब कि उसको हक होवे बावजूद महीने के अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है ।

(२) जिस तारीख से जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीख से दिवालिये तथा उसकी जायदाद का सम्बन्ध हट कर जिम्मेदारी उस छोड़ी हुई जायदाद से समाप्त हो जावेगी और आधिकार प्राप्तानी भी उस जायदाद के सम्बन्ध में उस वक़्त से जाती जिम्मेदारी से बरी हो जावेगा जब से कि जायदाद उसको मिली थी । परन्तु किसी दूसरे व्यक्ति के हक पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतना ही असर पड़ सकता है जितना सम्बन्ध दिवालिये उसकी जायदाद तथा आधिकार प्राप्तानी को जिम्मेदारी से बरी करने के लिये आवश्यक होगा ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार आधिकार प्राप्तानी को अधिकार प्राप्त है कि वह जगहों को अथवा भारी बार वाली जायदाद को छोड़ देवे इस प्रकार वह स्वयं जाती जिम्मेदारी से बच सकता है तथा दिवालिये व उसकी जायदाद को भी बचा सकता है । इस दफा के अनुसार कार्रवाई करने के लिये बावजूद महीने की अवधि बतवाई गई है परन्तु साथ साथ यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होने के एक माह के अन्दर आधिकार प्राप्तानी को ऐसी जायदाद का हक न होवे तो वह इस हाने पर उसके १२ माह के अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है अथवा एक्ट में प्रयोग किये हुए (May) शब्दों में प्रकट है कि इस दफा के अनुसार कार्रवाई करना न करना आधिकार प्राप्तानी की इच्छा पर है । यदि आधिकार प्राप्तानी इस दफा के अनुसार कार्रवाई करे तो वह इस बात का दर्शा नहीं उठाया जा सकता है कि उसने जायदाद को बेचा नहीं या उसने उस पर क़ब्ज़ा लेने या मालिकाना हक कायम करने की वांछ नहीं की ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि जिस तारीख से ऐसी जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीख से दिवालिये या आधिकार प्राप्तानी अथवा दिवालिये की जायदाद से उसका सम्बन्ध छूट जावेगा और इस सम्बन्ध का छूटना उसी तारीख से माना जावेगा जब कि जायदाद आधिकार प्राप्तानी को मिली हो । इस उपदफा में यह भी साफ कर दिया गया है कि इस दफा के

अनुसार कार्रवाई होने पर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतनाही प्रभाव पड़ सकता है जितना कि आदेशित एसायनी, डिवायलिये या उसकी जायदाद को बर्त करलेके लिये आवश्यक होगा अंग्रेजी एक्ट की इस उप-दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि इस उपदफा के नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ६३ ठेकेंका छोड़ा जाना

इस सम्बन्धमें बनाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी दिला अदालत की आज्ञा लिये हुए किसी ठेकेके हक को नहीं छोड़ सकेंगा और अदालत को अधिकार है कि वह इस प्रकारकी आज्ञा देनेसे पहिले अथवा आज्ञा देते समय सम्बन्धित व्यक्तियोंको जैसा नोटिस चाहे दे सकती है या आज्ञाके साथ जो शर्तें चाहें लगा सकती है और न हटाई जाने योग्य चीजों कायतकारकी बदलाई हुई चीजों तथा कायतकारीसे पैदा हुई और वार्तोंके सम्बन्धमें जैसा हुक्म मुनासिब समझे दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी अपनी इच्छानुसार किसी ठेके की या पट्टेके हक को नहीं छोड़ सकता है उसे ऐसा करनेके लिये अदालत की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार अदालत का अधिकार है कि वह आज्ञा देनेसे पहिले या आज्ञा देते समय जो शर्तें चाहे अपनी आज्ञाके साथ लगा सकती है तथा साथ ही साथ जिस जमीनके ठेके का मामला हो उस जमीन पर कालकार द्वारा बढ़ाई हुई चीजों तथा न अजहदा की जाने योग्य चीजों तथा इसी प्रकारकी अन्य वार्तोंके लिये जो हुक्म मुनासिब हो दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसाकि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है परन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार जसा चाहे वैसा हुक्म दे सकती है ।

दफा ६४ आफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छोड़ाया जाना

यदि किसी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्तिने लिखकर आफिशल एसायनीक पास यह दखवास्त दी हो कि वह तय करे कि जायदादको छोड़ेंगा या नहीं और उसने दखवास्त साने के २८ दिनों के अन्दर अथवा अदालतकी आज्ञानुसार बढ़ाई हुई अवधि के अन्दर इस बातका नोटिस देनेसे इनकार किया हो कि वह जायदाद को छोड़ेंगा या लापरवाही की हो तो आफिशल एसायनी को दफा ६२ के अनुसार उस जायदादको छोड़नेका हक नहीं होगा । और मुवाहिदेके मामलेमें यदि आफिशल एसायनीने इसी मियादके अन्दर या अदालतकी आज्ञानुसार बढ़ाई हुई अवधि के अन्दर मुवाहिदे को नहीं छोड़ा हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसने मुवाहिदे को मान लिया है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह प्रकट है कि जोई जमीन योग्य जायदादमें सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति आफिशल एसायनीके पास इस बातके जाननेके लिये दाखवास्त दे सकता है कि वह जायदाद को छोड़ेंगा या नहीं और ऐसी दाखवास्तके आने पर आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह कुछ न कुछ जवाब देवे और यह जवाब २८ दिनोंके अन्दर दिया जाना चाहिये परन्तु यदि

जवाब देने के लिये आफिशल एसायनीने अदालतसे कोई मोहलत ले ली हो तो उस मोहलतके अन्दर जवाब देना चाहिये । यदि ऊपर मतलाई हुई मोहलतके अन्दर आफिशल एसायनी जायदाद को लेब्नेसे इन्कार करे या जवाब देनेमें लापरवाही करे अथवा कोई ठीकजवान न देवे तो यह आपनदा उस जायदादकी नहीं छोड़ सकेगा इसी प्रकार यदि दरख्वास्त किसी मुवाहिदेके सम्बन्धमें दी गई हो और वह ऊपर मतलाई हुई मियादके अन्दर जेद न दिया जावे तो यह मान लिया जावेगा कि वह मुवाहिदा आफिशल एसायनी को मजूर है अर्थात् उसे उस मुवाहिदे को पूरा करना होगा । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है आफिशल एसायनी अदालतसे २८ दिनों बरतकर हुई मियादको बढ़वा सकता है परन्तु मियादके अन्दर या बड़वाई हुई मियादके अन्दर उचित उत्तर दिया जाना चाहिये ।

दफा ६५ अदालत द्वारा मुवाहिदोंके तोड़े जानेके अधिकार

यदि विधालियेके साथ किये हुए किसी मुवाहिदेके अनुसार कोई व्यक्ति आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी त भके उठाने का अधिकारी होवे या किसी मुवाहिदेके धारके अनुसार उस लाभके उठाने का अधिकारी होवे, तो ऐसे व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर अदालत जैसा कि उसे उचित समझ पड़े उस मुवाहिदेके तोड़ने का हुक्म ऐसी शर्तोंके साथ दे सकती है कि किस फरीक को मुवाहिदेके अनुसार काम न करने की वजहसे कितना हर्जा देना चाहिये और इस प्रकार दिये हुए हुक्मके अनुसार जो हर्जा दिया जाने को होगा वह बतौर क़ाज़ेके दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार क़ाज़ाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार मुवाहिदा पूरा न करनेके कारण अदालत हर्जा दिलवा सकती है और इस प्रकार दिलवाया हुआ हर्जा नतौर बर्नेके साबित किया जासकता है । इस दफा के अनुसार करिबाई अदालत अपने आप ही नहीं करेगी किन्तु ऐसे व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर करेगी जिसे उस मुवाहिदेसे लाभ पड़ता हो । मुवाहिदे को तोड़ने तथा हर्जा दिलाने का हुक्म सम्भावित तथा फ़ीकेनके लाभ हानि का विचार रखते हुए दिया जाना चाहिये ।

दफा ६६ छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सुपुर्दगीका हुक्म देना

(१) यदि कोई व्यक्ति जो किसी छोड़ी हुई जायदादमें अपना हक़ जाहिर करता हो या छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें जिसकी ज़िम्मेदारी न पूरी की गई हो, अदालतमें दरख्वास्त देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह जिन लोगोंके ध्यान लेना इस सम्बन्धमें मुनासिब समझे उन्हें सुननेके बाद जायदादकी सुपुर्दगी अथवा उस पर क़ब्ज़ा लेनेका हुक्म किसी व्यक्तिके हक़में कर सकती है जिसे वह उसका अधिकारी समझे, या जिसे ऊपर मतलाई हुई ज़िम्मेदारीके कारण वह जायदाद बतौर मुआवितेके मिलना चाहिये । यह जायदाद उस व्यक्तिके ट्रस्टीको भी दी जासकती है और अदालत जो शर्तें चाहे अपने ऐसे हुक्म होनेके साथ लगा सकती है । और ऐसे हुक्म होने पर वह जायदाद बिला किसी इन्तकालके उस व्यक्तिकी हो जायेगी जिसके हक़में हुक्म दिया गया हो । परन्तु शर्त यह है कि यदि जायदाद ठंके (पड़े) के योग्य होवे तो अदालत उस जायदादकी सुपुर्दगीका हुक्म किसी ऐसे व्यक्तिके हक़में नहीं देगी जो दिवालियेकी औरसे

उसके शिकमी ठेकेदारकी हैसियतसे या मुतंहिनकी हैसियतसे उस जायदादके लिये अपना हक जाहिर करता हो। लेकिन ऐसा हुक्म उन जिम्मेदारियोंके साथ दिया जासकता है जिनकी पाबन्दी दिवालिये पर उस वक्त लाजिमी रही हो जब कि दिवालियेकी दरखास्त ही गई हो और यदि कोई शिकमी ठेकेदार या मुतंहिन उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे जायदाद को लेनेसे इन्कार करे तो उसका उस जायदाद पर कोई हक या जमानत नहीं रह जावेगी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो दिवालिये की तरफसे अपना हक तो जाहिर करता हो परन्तु अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तोंके साथ जायदाद को लेनेके लिये तैयार न होवे तो अदालत उस जायदादको किसी ऐसे व्यक्तिको दिये जानेका हुक्म दे सकती है जो ज्ञाती तौरसे या वारिसकी हैसियतसे अकेले या दिवालियेके साथ उस पट्टेके सम्बन्धमें पट्टेदारीके इकरारनामोंकी पूरा करने का जिम्मेदार होवे और वह जायदाद ऐसे व्यक्तिको दिवालिये द्वारा पैदा किये हुए सब वार व हकोंसे साफ मिलेगी।

(२) अदालत यदि मुनासिब समझे तो ऊपर बताई हुई शर्तोंको संशोधित कर सकती है जिसमें कि उस व्यक्ति पर जिसके हकमें जायदाद मिलनेका हुक्म हुआ हो वही जिम्मेदारियां लागू हों जो उस वक्त होतीं जब कि पट्टा उसके हकमें दिवालियेकी दरखास्त दिये जाते समय लिखा गया हो और जैसे कि वट्टेमें बही जायदाद दिखलाई गई हो जिसका उल्लेख सुपुर्दगीके हुक्ममें किया गया है (यदि ऐसा अवसर होवे) ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार कार्य करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार हुक्म देसकती है जैसा कि अमेजा एक्टकी। इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्द स प्रकट है इस दफाकी योजना। इस कारण कीगई है कि यदि किसी हुई जायदादके मिलनेके लिये कोई व्यक्ति दरखास्त देवे और उस पर अपना हक या अपनी कोई जमानत आदि द्वारा पैदा हुआ अधिकार जाहिर करे तो अदालत उचित तदकानातके बाद उसकी सुपुर्दगीका हुक्म उस व्यक्ति या अन्य किसी इकरारके हकमें कर सकती है। वह जायदाद इकरारके दुरहीरी भी दी जासकती है। अदालत इस प्रकारका हुक्म देते समय उचित शर्तें भी लगा सकती है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसा हुक्म देने पर जिस जायदादका शिक हुक्म में होवे तथा जिसके हकमें जायदाद मिलने का हुक्म होवे उसे वह जायदाद मिल जावेगी व इसके लिये किसी छुदागाना वक्तकाल जायदादके लिये जानेकी आवश्यकता नहीं है।

उपदफा (१) के साथ में यह भी शर्तें लगायी गई है कि इस प्रकार जायदाद दिये जानेका हुक्म दिवालियेके शिकमी पट्टेदार या मुतंहिनके हकमें नहीं किया जावेगा जो ऐसा हुक्म उस दफामें दिया जा सकता है जब कि शिकमी पट्टेदार या मुतंहिन उन सब जिम्मेदारियोंको बरदाश्त करे जो कि दिवालिये पर दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने समय लागू थीं। इसी शर्त में यह भी बतला दिया गया है कि यदि शिकमी पट्टेदार या मुतंहिन ऐसी शर्तोंके साथ जायदाद न लिया चाहता हो तो उसके सब हक उस जायदादसे जाने रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अकेले ही या दिवालियेके साथ उस पट्टेके किसी इकरारनामोंकी पूरा करनेका पबन्द होवे तो अदालत ऐसे व्यक्तिसे हुक्म उस जायदादको, मिलनेका हुक्म दे सकती है और उस व्यक्ति को वह जायदाद सब जिम्मेदारियों व बारात पाक व साफ मिल जावेगी।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत को ऊपर बतलाई हुई शर्तोंके संशोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है और संशोधन द्वारा जायदाद उस दफामें बतली भिन्नो जैसे कि दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने समय वह जायदाद उतने हक

में कर दी गई हो अर्थात् केवल उसी समयकी विम्वेदाशियां व नारकी पाषादी उस पर लागू समझी जावेगो छोटी हुई जायदाद के सम्बन्धमें इस दफाके अनुसार अदालत समवानुकूल हुक्म किसी भी ऐसे व्यक्ति के हकमें दे सकती है जो दाजसल उस जायदादकी पति का अधिकारी समझा जावे तथा शक्ति शर्त भी अपने हुक्मके साथ छूटा सकती है और ऐसा हुक्म होने पर इत्तफाक जायदादकी कर्तव्य अर्थात् दस्तावेजोंके लिखे जाने पर उनके रजिस्ट्री किये जानेकी आवश्यकता भी जाती रहेगी।

दफा ६७ छोटी हुई जायदादसे जिसे हानि पहुंचती हो वह साबित कर सकता है

यदि ऊपर बतलाए हुए नियमोंके अनुसार किसी जायदादके छोड़े जाने पर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती होये तो वह व्यक्ति दिवालियेका कर्जखवाह उस तादादके लिये समझा जावेगा जिसकी उसे हानि हुई हो और इसीलिये वह उस तादादको यतौर कर्जके दिवालियेकी कर्तव्य के सम्बन्धमें साबित कर सकता है।

व्याख्या—

अंशजा एकटरी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये। यदि किसी जायदादके छोड़े जानेसे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती हो तो वह अपनी हानिको दिवालिये की जायदादसे उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे कि और कर्ज उस जायदादसे वसूल किये जासकते हैं और वह और कर्जस्थानों की भांति अपने इस कर्ज को साबित कर सकता है।

दफा ६८ जायदादकी वसूलीमें आफिशल एसायनीके कर्तव्य व अधिकार

(१) इस एकटमें बतलाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी सहलियतके साथ जितनी जल्द हो सकेगा दिवालियेकी जायदादको वसूल करेगा और उस सम्बन्धमें वह निम्नलिखित कार्यों को कर सकता है:—

(ए) दिवालिये की सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेंच सकता है।

(बी) जो रुपया वह वसूल करे उसकी रसीद दे सकता है तथा वह अदालतकी आज्ञा लेकर नीचे दिये हुए सब कामोंको या उनमेंसे किसी कार्यको कर सकता है।

(सी) दिवालियेके कारोबारको उस हद तक चालू रख सकता है जिस हद तककि दिवालिये के कामको समेटनेके लिये आवश्यक प्रतीत होवे।

(डी) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें मुकदमा या कोई दूसरी क्रानून कारवाई चालू कर सकता है या उसमें अबाधदेही कर सकता है या उसे चालू रख सकता है।

(ई) अदालत द्वारा इजाजत दिये हुए काम या कारवाई को करनेके लिये किसी वकील या दूसरे एजेंट को नियुक्त कर सकता है।

(एफ) किसी जायदादकी कीमतमें भविष्यमें मिलने वाला वह रुपया मंजूर कर सकता है जो किसी लिमिटेड कम्पनीके पूरे अदाकिये हुए शेअर्स अथवा डिबेंचरके सम्बन्ध में या डिबेंचर स्ट्राकके सम्बन्धमें मिलना चाहिये परन्तु उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे ऐसे सौदेको कर सकता है।

(जी) दिवालिये के काजों को चुकाने के लिये अथवा उसके कारोबार को चालू रखने के लिये दिवालिया की जायदाद को या उसके किसी हिस्से को रهن कर सकता है या गिरवी रख सकता है ।

(एच) किसी भगड़े को पंच फैसले के लिये सुपुर्द कर सकता है और सब कर्जों, दावों व जिम्मेदारियों को तय शुद्ध शर्तों के साथ तय कर सकता है ।

(आई) यदि कोई जायदाद अपनी मूल स्थिति के कारण अर्द्धी व फायदे के साथ बँबी न जा सकती हो तो उसको उसी शर्तों में उसकी कीमत का अन्दाजा लगा कर दिवालिये के कर्तव्यार्थों में बाँट सकता है ।

(२) आफिशल एसायनी अदालत को अपना हिसाब समझावेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार अथवा अदालत के आदेशानुसार सब रुपया अदा करेगा तथा सब जमानतों के सम्बन्ध में कारवाई करेगा ।

न्यायका—

आफिशल एसायनी कपदको (१) के अनुसार दिवालिये की जायदाद को जितनी जल्दी हो सकेगा बँटव करने के लिये बाँट है अर्थात् कि अग्रेजी कपदकी इस कपदकामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रष्ट है इस कपदकामें यह भी बतलाया गया है कि जायदाद बँटव करने के लिये वह कुछ काम बिना अदालत की आज्ञा किये हुए जिस प्रकार चाहे कर सकता है जिनका उल्लेख कानून (ए) व (बी) में है तथा कुछ काम अदालत की आज्ञा लेने पर कर सकता है जिनका जिक्र कानून (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) व (आई) में है जायदाद को या उसके किसी हिस्से को बँटवने का काम तथा बँटव किये हुए कपदों की रसीद देने का काम वह बिना अदालत की आज्ञा के कर सकता है परन्तु कानून (सी) के अनुसार वह दिवालिये की कारोबार चालू रखने का काम आज्ञा लेने पर कर सकता है । इसी प्रकार धुकदमी का व अर्द्धली का काम वह आज्ञा लेने पर कर सकता है । कानून (डी) में सब प्रकार के अदालती कामों का एक प्रकारसे बर्णन दिया हुआ है अर्थात् यदि कोई कारोबार दिवालिघा करार दिये गये समय कर रहा हो तो आफिशल एसायनी उसे चालू रख सकता है तथा दूसरे हुए मामलों में जवाबदेही कर सकता है व उसे आदालत चालू कर सकता है ।

फलाज (सी) व (डी) में बतलाये हुए कामों में कामें कल्पमें परिष्कृत करने के लिये वह अदालत की आज्ञा लेकर कानून (ई) के अनुसार बकील या अन्य एग्नेटों को नियुक्त कर सकता है ।

फलाज (एफ) के अनुसार किसी जायदाद की उन शेअर्स आदिके एवजमें भी बँटव सकता है जिनका बयान प्रतियमों में मिलने बाका होवे परन्तु ऐसा करते समय अदालत द्वारा बतलाई हुई अधातव आदि की शर्तों का प्यान रखना चाहिये ।

फलाज (जी) के अनुसार अदालत की आज्ञा लेने पर दिवालिये की जायदाद रहन की जा सकती है तथा वह गिरवी रखी जा सकती है जिसमें बंधन बन्दूक होने पर कर्जें चुकाने या बँटव के या कारोबार चालू रखा जाना है ।

फलाज (एच) के अनुसार पंच फैसला व बाइयो तारते तरफिया करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन अदालत की आज्ञा लेने पर ही ऐसा किया जावेगा ।

फलाज (आई) के अनुसार अदालत की आज्ञा लेने पर न बँबी जाने योग्य जायदाद को उसकी मौजूदा शर्तों में खर्चवाहों में बाँट सकता है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि निर्धारित नियमोंके अनुसार जज या अदालतके आदेशके अनुसार आफिशल एसायनी अदालतमें हिस्सा सम्प्राप्तिगा व रुपये जमा करेगा तथा जमाननोंमें बसूल करेगा । अमेजी एक्टमें शिरे हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी पारबन्धी आवश्यक है उनमें अवहेलना नहीं की जा सकती है ।

जायदादका बांटा जाना

धफा ६९ हिस्सा रसदीका ऐलान व उनका बांटा जाना

(१) आफिशल एसायनी जितनी जरूरी सहूलियतके साथ हो सकेगा हिस्सा रसदीका ऐलान करके उसे उन कर्जव्याहोंमें बांटेंगा जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं ।

(२) पहिला हिस्सा रसदी (यदि कोई होगा) विधालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर ऐलान करके बांटा जावेगा यदि आफिशल एसायनीने पर्याप्त कारण दिखला कर अदालतको यकीन दिलाकर समय ऐलानके लिये बढ़ाया न लिया हो ।

(३) इसके बाद घाले हिस्सा रसदी यदि कोई बजह इसके विरुद्ध न दिखलाई गई हो तो वह छः छः महीनेसे ज्यादाका बीच न डालकर बांटे जावेंगे ।

(४) हिस्सा रसदीका ऐलान करनेसे पहिले आफिशल एसायनी इस इच्छाका नोटिस निर्धारित ढंग पर प्रकाशित करेगा और उसका उचित नोटिस विधालियेकी फेहरिस्तमें दिखलाये हुए उन हर एक कर्जव्याहोंके पास भेजगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है ।

(५) जब कि आफिशल एसायनीने किसी हिस्सा रसदीका ऐलान किया हो तो वह उन कर्जव्याहोंके पास जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना भेजेगा कि उनको कितना हिस्सा रसदी मिलेगा और कब व किस प्रकार दिया जावेगा और यदि कोई कर्जव्याह चाहेंगा तो उसको निर्धारित रूपमें विधालियेकी जायदादका न्योरा भेजा जावेगा ।

व्याख्या—

अमेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पारबन्धी आवश्यक है तथा उनकी अवहेलना आफिशल एसायनी की नहीं करना चाहिये ।

उपदफा (२) में ज. मर्हनेके लगभग एक सालकी अवधि पर दी गई है यह संशोधन प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्स्टीट्यूट एक्ट सन् १९२९ ई० एक्ट नं० ३ के अनुसार किया गया है जिसको गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति २९ मार्च सन् १९२९ ई० को प्राप्त हुई थी । इस संशोधित एक्टके अनुसार दिखलिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर पहिला हिस्सा रसदी घोषित किया जावेगा जब तक कि अदालतकी कोई पर्याप्त कारण इस अवधिके बढ़ानेके लिये न दिखाया जावे तबसे पहिले पूरा एक्टके अनुसार पहिला हिस्सा रसदी छः मर्हनेके अन्दर बांटा जानेका नियम था । हिस्सा रसदी जहाँ कर्जव्याहोंमें बांटा जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो दूसरे कर्जव्याहों की नहीं चाहे उनका नाम कर्जव्याहों की फेहरिस्तमें दिखलाया गया हो ।

विधालिया करार दिया जाने का हुक्म देनेके पश्चात् पहिले हिस्सा रसदी का ऐलान छः मर्हनेके अन्दर किया जाना आवश्यक है यदि इसके विरुद्ध अदालतकी कोई आज्ञा न छे ली गई हो तबसे आफिशल एसायनी पर्याप्त कारण दिखलाकर

अदालतसे समय बढा सक्ता है । इसके बाद बाहे हिस्सा रसदी भी छ छ महीनेके अवकाशमे बाटे जाय चाहिय इसमे अधिक अवकाश उनक बटे जानये न पटना चाहिये जब तब कि इसके विपक्ष कोई अज्ञा अदालत द्वारा न दी गई हो ।

उपदफा (४) में आदिशक्त एसायनीके लिये यह वक अवश्यक है कि वह हिस्सा रसदीके ऐलानकी सूचना निर्धारित रूपसे प्रकाशन कर देवे तथा ऐसे कर्जदारों को भी उचित रूपसे सूचना दे देवे जिनका नाम कर्जखानाहोकर फिहरिमें आया हो परंतु नि होने अन्ता कर्ज साबित न किया हो ।

उपदफा (५) के अनुसार आदिशक्त एसायनी का यह कर्तव्य होगा कि वह हिस्सा रसदी का ऐलान करने पर इन कर्जखानों को जिनहोंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना देवे कि उनकी किन्ता हिस्सा रसदी मिलेगा तथा वह वक व किस प्रकार दिया जावेगा इसी उपदफामे यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई कर्जखाना यदि तो वह अधिकशक्त एसायनीसे दिवालयके जायदादकी तफ्तील माग सकता है और उसके मागने पर निर्धारित रूपमें वह तफ्तील उसको मिल जावेगी ।

दफा ७० संयुक्त तथा अलगकी जायदाद

यदि किसी कर्म का एक शरीकदार दिवालय कसम दिया जावे तो वह कर्जखाना जिसका कर्ज दिवालियेको फर्मके सब शरीकदारों अथवा उनमेंसे किसी शरीकदारके साथ चुकाना हो, उस वक्त तक दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे अपना कर्जबसूल करनेका हक्कदार नहीं होगा जबतक कि दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे उसके जुदागाना का पूर्णरूपसे न चुकाय गये हो ।

व्याख्या—

इस दफाके अन्तर्गत हा अर्थात् जुदागाना कर्ज पहिले उसकी जुदागाना जायदादसे चुकाये जावेगे तब उसकी जायदाद बेचने पर उसके मयुक्त कर्ज चुकाये जा सकेगे । इस प्रकार कर्मका कर्जखाना उस वक्त तक फर्म एक शरीकदार का जुदागाना जायदादम फर्मका कर्ज बसूल नहीं कर सकता जब तक कि उसके जुदागाना कर्ज पूर्ण रूपसे न चुकाये जा चुके । अग्रेजी एन्टर्मी इस दफा में (Shall) शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे यह अर्थ है कि इसके नियमोंकी पारबन्दी आवश्यक है ।

दफा ७१ हिस्सा रसदीका अन्दाजा लगाया जाना

(१) हिस्सा रसदी लगाने व उनको बाँटनेसे पहिले आदिशक्त एसायनी निम्नलिखित कामोंके लिये पर्याप्त धन अपने हाथमें रोक लेवेगा:—

(ए) उन कर्जोंके लिये जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनके लिये दिवालियेके बयानों अथवा अन्य प्रकारसे यह साबित होय कि वह ऐसे लोगोंके हैं जो इतनी दृढ़की जगह पर रहते हैं कि मामूली सौर पर खबर भेजे जाने पर उनको पर्याप्त अवसर अपना कर्ज साबित करनेके लिये न मिल सका हो ।

(बी) वह कर्ज जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनका दावेका मसला तब नहीं हुआ है ।

(सी) वह सुझत व दावे जिनका विरोध किया गया हो ।

(डी) जायदादके प्रवचन तथा दूसरे मामलोंके खर्चके लिये जो आवश्यक सूच्य होवे ।

(२) उपदफा (१) के नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रुपया जो हाथमें होगा बतौर हिस्सा रसदीके बांटा जावेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि हिस्सा रसदी बांटेसे पहिले आफिशल एसायनी क्राउ (ए), (बी) (सी) व (डी) में बतलाये हुए कामोंके लिये रुकवा रोक कर हिस्सा रसदी बांटेगा । अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि आफिशल एसायनीको सब क्राजोंमें बतलाये हुए कामोंके लिये पर्याप्त धन रोक लेना आवश्यक है ।

फलाज (ए) के अनुसार यदि किसी कर्जखवाहको अपना कर्ज साबित करनेके लिये पूर्ण अवकाश न मिला हो तो ऐसे कर्जखवाहके कर्जके अन्दाजेसे कगवा रोक लेना चाहिये ।

फलाज (बी) व (सी) के अनुसार झगड़के कर्जोंके सम्बन्धमें भी रोक लेना चाहिये । जायदादका इतनाम करनेमें जो खर्च आवश्यक पड़े उसके लिये भी रुपया रोका जासकता है ।

उपदफा (२) के अनुसार ऊपर बतलाये हुए कामोंके लिये रुपया रोक लेनेके पश्चात् बाकी जो रुपया बचे वह सब हिस्सा रसदीके तीर पर कर्जखवाहोंमें बांट दिया जाना आवश्यक है अर्थात् वसमेंसे और कुछ नहीं रोका जासकता है ।

दफा ७२ उस कर्जखवाहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले, अपना कर्ज साबित न किया हो

यदि किसी कर्जखवाहने किसी हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले अपना कर्ज साबित न किया हो तो वह उस बाकी बचे हुए रुपयेसे हिस्सा पावे या जो उस समय आफिशल एसायनीके हाथ में होवे तथा जिससे भविष्यमें हिस्सा रसदी बांटा जानेको होवे तथा जो पहिले उसको नहीं मिल सकता था परन्तु उसका कर्ज साबित किये जानेसे पहिले जो रुपया बांटा जा चुका हो उसमें किसी तरहकी गड़बड़ी उसके कारण नहीं पड़ सकेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार उन कर्जखवाहों की भी हिस्सा रसदी मिल सकती है जो बादमें अपना कर्ज साबित करें परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ऐसे कर्जखवाह का कर्ज साबित होनेसे पहिले जो हिस्सा रसदी बांटा जा चुका हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जासकता है किन्तु उसका कर्ज साबित होनेके बाद जो रुपया बांटा जावेगा उसमें उसकी हिस्सा रसदी मिलसकेगी । इस दफा का तात्पर्य यह स्पष्ट करना चाहिये कि यदि कोई रुपया बांटा जानेसे पहिले किसी कर्जखवाहने अपना कर्ज साबित कर दिया हो तो वह उस रुपयेमें हिस्सा रसदा पाने का हकदार होगा । इस दफाकी योजना भी आवश्यक है ।

दफा ७३ अन्तिम हिस्सा रसदी

(१) जब कि आफिशल एसायनीने दिवालियेकी सब जायदाद वसूल करली हो या उसका उतना हिस्सा वसूल कर लिया हो जितना उसकी रायमें, बिला फिजूलकी बेर कार्रवाईमें किये हुए, वसूल किया जा सकता है तो वह अदालतकी आज्ञा लेने पर अन्तिम हिस्सा रसदीका ऐलान करेगा परन्तु ऐसा करनेसे पहिले वह निर्धारित ढंग पर उन लोगोंको नोटिस देवेगा जिनके कर्जखवाह होनेकी सूचना उनको दी जा चुकी है लेकिन उन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है कि

यदि वह अदालतके सम्मुख संतोषजनक रूपमें अपना कर्ज नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर साबित न कर दंगे तो उनके दावेका बिलालिहाज्ज किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

(२) इस प्रकारकी दी हुई मियादके समाप्त होने पर अथवा यदि किसी दावेदारकी दरखास्त पर उसको अवकाश दे दिया गया हो तो उस अवकाशकी समाप्त होने पर दिवालियेकी जायदाद उन कर्जखानोंके दायियां बांट दी जावेगी जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो और अन्य लोगोंके दावोंका उस समय कोई भी ख्याल न रखना जावेगा।

व्याख्या—

हाल दफाके अनुसार अन्तिम हिस्सा रसदी बांट जानेसे पहले उन कर्जखानों को जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया हो एक मौका मिलेगा अपना कर्ज साबित करनेके लिये दिवालेजा और यदि उससे भी वह खोप लाभ न उठाया जाये अपितु नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर कर्ज साबित न करे तो वह किसी हिस्सा रसदीके पानेके हकदार नहीं रहेगा। अंग्रेजी पुरतरी इस दफामें प्रयोग लिये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये।

उपदफा (१) से यह भी प्रकट है कि नोटिसमें दी हुई मियादके अन्तिम यदि कोई व्यक्ति मोहूत किया जाये तो उसे अत्यन्त मोहूत दे सकती है परन्तु मियाद या मोहूतके अन्दर यदि कोई कर्ज साबित न किया जावे तो बिल्कुल उसका निहाल लिये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी उन कर्जखानोंके दायियां बांट दिया जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो। इस दफाके अनुसार लिये हुए नोटिसमें यह दिखाना देना चाहिये कि इस मियादके अन्दर तुमको कर्ज साबित कर देना चाहिये वरना बिना निहाल तुम्हारे कर्जके अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

उपदफा (२) में यह साफ का दिया गया है कि मियादके या बढ़ाये हुए समयके अन्दर कर्ज साबित न किया जाने पर अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

दफा ७४ हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता

आफिशियल एसायनीके विरुद्ध हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं किया जावेगा परन्तु यदि आफिशियल एसायनी किसी हिस्सा रसदीके चुकानेसे इनकार कर दंगे तो उस कर्जखानेके दरखास्त देने पर जिसे इस इनकारसे हानि पहुंचती हो अदालत आफिशियल एसायनीको उसके कर्ज कानूनेके लिये हुकूम दे सकती है और उससे रोक हुए समयके लिये विधायित की हुई दरसे खुद तथा दरखास्तके सम्बन्धमें किया हुआ खर्च दिलवाया जावेगा।

व्याख्या—

आफिशियल एसायनीके विरुद्ध हिस्सा रसदीके लिये कोई उदात्ताना दावा नहीं किया जा सकता है किन्तु अदालतमें दरखास्त इस बातकी सूचना देगी कि उसने हिस्सा रसदी नहीं दिया है ऐसी दरखास्तके आने पर अदालत आफिशियल एसायनीसे यह बयान दिलाना सक्ती है तथा ऐसे हुए सबबोंसे खुद व दरखास्तकार खर्च भी दिलवा सकती है। अदालत इस प्रकार का हुकूम देगी कि उसे सत्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग लिये हुए (May) शब्दसे प्रकट है किसी प्रकारका हुकूम देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है।

दफा ७५ दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तज़ाम कराया जाना तथा उसे उसके एवज़में श्रम फल मिलना

(१) निर्धारितकी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए आकिशल एसायनी स्वयं दिवालियेको उसकी जायदाद या उसके किसी हिस्सेका प्रबन्ध करनेके लिये नियुक्त कर सकता है या उसके द्वारा उसका व्यापार कर्जद्वारा करनेके लाभार्थ कर सकता है या उससे उसकी जायदाद के प्रबन्धमें और तरहसे सहायता अपनी वतलाई हुई शर्तोंके अनुसार ले सकता है ।

(२) ऊपर लिखी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए अदालत समय समय पर उस जायदादसे जैसा उसे नुनासिय समझ पड़े दिवालियेको गुज़ारा उसके तथा उसके परिवारकी परधरिशके लिये या उसके कामके मुचायजिके तौर पर दिला सकती है यदि उससे उसकी जायदादके समेटनेमें सहायता ली जावे परन्तु इसक्रिस्मका गुज़ारा किसी समय भी बढ़ाया घटाया या बन्द किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालियेसे स्वयं आवश्यकता पड़ने पर उसकी जायदाद या रोजगारके प्रबन्धमें सहायता ली जासकती है अदालत उसकी इस कामके एवज़में बतौर गुज़ारा उसकी जायदादसे कुछ रुपया दिला सकती है परन्तु इसका दिल्ना न दिखाना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा वह जब चाहे उसे बन्द कर सकती है अथवा घटा बढ़ा सकता है दिवालियेको नाम दिया जावेगा वह उसके कर्जद्वाराके लाभार्थ श्रम आकरगा वह स्वयं केवल अदालत द्वारा दिल्वाये हुए गुज़ारे की के पाने का हकदार होगा । आकिशल एसायनी की इच्छा पर दिवालियेसे बात ऐना न छना निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ७६ बचे हुए हिस्सेके पानेका हकदार दिवालिया है

यदि कर्जद्वाराहोंका सब रुपया मय सूदके जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है चुका दिया जावे तथा इसके अनुसारकी हुई कार्यवाहियोंका खर्च चुका दिया जावे तो दिवालिया बचा हुआ रुपया पानेका हकदार होगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि सब कर्जद्वाराहोंका रुपया मय सूदके अदा हो चुके तथा दिवालियेके सम्बन्धमें की हुई कार्यवाहियोंका खर्च भी चुकाया जाचुके आर इसके बाद भी दिवालियेकी जायदादमें कुछ बचे तो वह बचा हुआ हिस्सा दिवालिये की मिलेगा अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों परबन्दी आवश्यक है तथा उसकी अवहेलना नहीं की जावेगी ।

चौथा प्रकरण



आफिशल एसायनी

दफा ७७ दिवालियेकी जायदादके लिये आफिशल एसायनीकी नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना

(१) फोर्ट विलियम (कलकत्ता), बम्बई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिस तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजको अधिकार है कि वह अपनी अपनी अदालतके लिये मुस्तकिल तौरसे अधवा कायम मुकाम तौरसे दिवालियेकी जायदादके लिये उपयुक्त व्यक्तिको आफिशल एसायनी नियुक्त कर दें और यदि कोई पर्याप्त कारण मालूम हो तो और जजोंके सहमतके साथ किसी व्यक्तिको जो उस अगह काम करता हो अलगहटा कर दें।

(२) प्रत्येक आफिशल एसायनी निर्धारितकी हुई जमानत देवेगा तथा उसको उन नियमों की पाबन्दी करना पड़ेगी व वह काम करना पढ़ेगा जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों।

(३) यदि इन्डियन इन्साल्वेन्सी एक्ट १८५८ के अनुसार कलकत्ता बम्बई और मद्रासमें कोई व्यक्ति कर्जदारोंके हुदकारे के लिये मुस्तकिल तौरसे या कायम मुकाम तौर पर आफिशल एसायनीकी जगह पर काम करता हो या लोअर वर्माके चीफ कोर्टमें सन् १९०० ई० के लोअर वर्मा कोर्टल एक्टके अनुसार उस प्रकारसे काम करता हो तो वह व्यक्ति बिना दुधारा नियुक्तिके मुस्तकिल या कायम मुकाम आफिशल एसायनी जैसा कि मामला हो इस एक्टके अनुसार कलकत्ता बम्बई व मद्रास हाई कोर्टों तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके लिये हो जावेगा और उस बहू उपदफा (१) से कोई छकावट न पड़ेगी।

ट्यारया—

कलकत्ता, बम्बई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिस तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजके इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्ति सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त है। पातु इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये यह हीन बाध्य नहीं है किन उसका करना न करना उनकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अप्रती एम्बवा उपदफा (१) में प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस उपदफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्ति मुस्तकिल तौरसे की जासकती है अथवा वह कायम मुकाम तौर पर ही नियुक्त किया जासकता है इस उपदफाके अनुसार नियुक्त किया हुआ आफिशल एसायनी अलगहटा भी किया जासकता है परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात बर्दाद ध्यानमें रखने की है कि चीफ जस्टिस या चीफ जज अपने ही उस अपने आप अलगहटा नहीं करेगा किन्तु वह अपनी अदालतोंके और जजों का मत लेवगा और उनके बहुमतसे सद्मत होकर आफिशल एसायनी को अलगहटा कर सकता है किसी पर्याप्त कालक उपरिगत होने पर ही नियुक्त किये हुए आफिशल एसायनीका हटाया जाना चाहिये।

उपदफा (२) में बताया गया है कि आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि यदि उसमें जमानत मागी जावे तो वह मागी हुई जमानत दायित्व की इसी प्रकार उस निर्धारित किये हुए नियमोंकी पाबन्दी करना पड़ेगी तथा निर्धारित

किये हुए काम करना पड़ेगे। इस दफ्ते के नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अमेजी एक्ट की इस उपदफ्ते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है।

उपदफा (३) के अनुसार पेशरसे कानूनन नियुक्त किया हुआ आफिशल एसायनी अपनी जगह पर बसतुर काम करता रहेगा अर्थात् उसके द्वारा नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दफ्ते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है कि इस उपदफ्ते के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

दफा ७८ हलफ देनेके अधिकार

आफिशल एसायनीको अधिकार है कि यह हलफनामोंके लिये व सुव्रत पिटीशन तथा इस एक्टकी अन्य कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें ठस्दीक इवारतक लिये हलफ दे सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्ते के अनुसार आफिशल एसायनी को हलफ देनेके अधिकार प्राप्त है। अमेजी एक्ट की इस दफ्ते में प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रकट है कि उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है तथा हलफ अदालत व अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी दी जा सकती है।

दफा ७९ दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्त्तव्य

(१) आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तथा उसकी जायदादके प्रबंधके सम्बन्धमें होंगे।

(२) आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य विशेष कर निम्न लिखित होंगे :—

(ए) यह कि दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तहकीकात कर और बहाल किये जानेकी दरखास्त आनेपर रिपोर्ट दाखिल करे जिससे मालूम होसके कि आया दिवालियेने इस एक्टके अनुसार अथवा ताजीरात हिन्दीकी दफा ४२१ से लगाकर ४२४ तकका कोई जुर्म तो दिवालियेकी कार्यवाईके सम्बन्धमें नहीं किया है या कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि जिसकी वजहसे अदालत बहाल किये जानेका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे, रोक देवे, या उसके साथ कोई शर्तें लगा देवे।

(बी) दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें उन बातोंकी रिपोर्ट दाखिल करे जो अदालत मांगे या जो निर्धारितकी गई हों।

(सी) घोखा देने वाले दिवालियेके चालानके सम्बन्धमें भाग लेवे तथा यह काम करे जिसके करनेके लिये अदालत हुक्म देवे या जो निर्धारित किये गये हों।

व्याख्या—

इस दफ्ते के अनुसार आफिशल एसायनी का कर्त्तव्य केवल दिवालिये की जायदादके प्रति नहीं है किन्तु उसका कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहार पर भी ध्यान रखने का है तथा दोनोंके लिये रॉरिवार्द करने का है। अमेजी एक्ट की इस दफ्ते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है कि इस दफ्ते के नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

उपदफा (२) में आकिशल एसायनी द्वारा ज्ञात काम विशेष रूपसे निर्भर माना चाहिये अथवा वर्णन प्रदान (ए), (बी) व (सी) में किया गया है ।

क़लाज़ (ए) व अनुसृत आकिशल एसायनी को चाहिये कि वह विशालियके व्यवहारका वर्णन प्रदान करे और जब उसका वर्णन विशेष जानकारी द्वारा जाना जाये तब वह उसके व्यवहारक नाममें अपना निष्कर्ष अंगुलीय द्वाारा करने जिससे बाहिर हो कि उसने कोई काम या नहीं किया हुआ यदि ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण वह बदल न किया जाये या उसका बदल किया जाये मूलकी कर दिया जाना अथवा यदि शर्तें नष्टकर दुरुपयोगे साथ लगा दा जाये ।

क़लाज़ (बी) के अनुसार यदि अंगुलीय आकिशल एसायनीमें दिवालिघाके व्यवहारके सम्बन्धमें और बातोंक नाममें रिपोर्ट माग सकता है ।

क़लाज़ (सी) में बताया गया है कि यदि दिवालिघा घोषणासे काम करने का दोष हो और उसका विवेक कार्य को बाध करे तो आकाश एसायनी का उसमें भाग लेना चाहिये तथा अंगुलीय निष्कर्ष प्रसारका सहायता इस सम्बन्धमें उससे चाहिये ल सकता है ।

दफा ८० कर्ज़रवाहोंकी फिहरिस्त दाखिल करनेका कर्त्तव्य

यदि कोई कर्ज़रवाह मर जाये तथा वह निर्यातिलकी हुई फीस दाखिल करे तो आकिशल एसायनी उस कर्ज़रवाहको कर्ज़रवाहोंकी फिहरिस्त देना तथा उसे बजसिये डाक रखाना करेगा और उस फिहरिस्तमें वह कर्ज़री दाखिलये जायेंगे जो प्रत्येक कर्ज़रवाहको मिलना चाहिये ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्ट में इस दफा (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह सन्नि है कि आकिशल एसायनी का किसी कर्ज़रवाह द्वारा दाखिल जाना पर तथा बजसिये फीस दाखिल कर देने पर कर्ज़रवाहोंका फिहरिस्त बनकर दाखिलये तथा इस दफाके निष्कर्षमें व्यवहारका न हो जाना चाहिये । जिसमें कर्ज़रवाहोंके कर्ज़री भी तफ़्सील दी जाना चाहिये ।

दफा ८१ श्रमफल (मेहनतकी फीस)

(१) आकिशल एसायनी उस श्रमफल (Remuneration) को पावगा जो इसके लिये निश्चित किया गया हो ।

(२) आकिशल एसायनी उपदफा (१) में दिखलाये हुए श्रमफलके अतिरिक्त और कोई श्रमफल इस रूपमें नहीं पावगा ।

व्याख्या—

इस दफाके नियमोंका भी अंग देना नहीं हो जाना चाहिये जहां कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किए हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । आकिशल एसायनी का श्रमफल प्रकट उसका लब्ध प्रत्येक अंगुलीय अपनी अपनी अंगुलीय सीमाके लिये दफा ११० के अनुसार अनुमान बनायेगा । आकिशल एसायनीके श्रमफलके लिये नियम दफा ११२ की उपदफा (२) के प्रावधानों के अनुसार बनाये जायेंगे ।

दफा ८२ आकिशल एसायनीकी बेरनवानी

यदि आकिशल एसायनीने दियायमें या दूसरे प्रकारसे उसकी बख्तवानी लापरवाही या

किसी काम का न करना मालूम हो तो अदालत उसके समझानेके वारेमें कहेंगी और यदि उसकी घंउनवानी लापरवाही या काम न करने की वजहसे दिवालिये की जायदाद को कोई नुकसान पहुँचा हो तो उससे उस नुकसान को पूरा करा सकती है ।

व्याख्या—

अदालतका कर्तव्य है कि वह आफिशल एसायनीमें उसकी गळनीके बोममें पूछे जेगा कि इन सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है तथा अदालत यदि चाहे तो आफिशल एसायनीसे उसके द्वारा किये हुए नुकसान की पूर्ति करा सकती है अर्थात् दफाके इस हिस्सेके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये असमन्त बाध्य नहीं है किन्तु उसके अनुसार करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेज एक्टमें मयाग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ८३ किस नामसे दावा दायर किये जाना चाहिये या दावा उसपर होना चाहिये

‘दिवालिये की जायदाद का आफिशल एसायनी’ (The Official Assignee of the property of an insolvent.) इस नामसे आफिशल एसायनी को दावा दायर करना चाहिये तथा इसी नामसे उसके विरुद्ध दावे किये जाना चाहिये और उसमें दिवालियेका नाम दिखला देना चाहिये । और इसी नामसे हर प्रकार की जायदाद पर कब्जा रखा जा सकता है, सुबाहिद किये जा सकते हैं, अपने ऊपर तथा अपने उत्तराधिकारियोंके ऊपर ज़िम्मेदारी लेने वाले वादे किये जा सकते हैं तथा अपने ओहदेके कामों को पूरा करनेके लिये, जिन कामोंका किया जाना आवश्यक तथा अनिवार्य प्रतीत हो उनको किया जा सकता है ।

व्याख्या—

आफिशल एसायनी अपने नामसे कोई कार्रवाई नहीं करेगा किन्तु वह ‘दिवालियेकी जायदादका आफिशल एसायनी’ इस नाममें घुसनेमें दायर कर सकेगा तथा इस नामसे उसके विरुद्ध भी दावे किये जाना चाहिये जिस दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कार्रवाई हो रही हो उसका नाम दे देना चाहिये । आफिशल एसायनी इसी नामसे जायदाद पर कब्जा रख सकता है तथा इसी नामसे सुबाहिदे या भय कर्षण में आवश्यक प्रतीत हो कर सकता है और इसी नामसे किये हुए कार्योंत वह स्वयं तथा उसके उत्तराधिकारी जा उसके आहूद पर काम करें भविष्यमें पावद किये जा सकते हैं । अमेठी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि ऊपर बतलाये हुए नामसे कार्रवाई करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है किन्तु कार्रवाई आर भी नामसे की जा सकती है अर्थात् ऐसे नामसे की जा सकती है जिससे इसी प्रकारका अर्थ निश्चलता हो तथा जिससे भासत हो जावे कि कार्रवाई किसी दिवालियेके आफिशल एसायनी की ओरसे बनौर आफिशल एसायनीके की जा रही है या उसके विरुद्ध की जा रही है ।

दफा ८४ दिवालिया होने पर आफिशल एसायनी अपनी जगहसे हट जावेगा

यदि आफिशल एसायनीके विरुद्ध दिवालिया क्रार दिये जानेका हुक्म हो जावे तो ऐसे हुक्मके होनेसे वह आफिशल एसायनीके पदसे हट जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया आफिशल एसायनी नहीं रह सकता है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके नियमोंमें अवदेना नहीं भी जावेगी किन्तु आफिशल एसायनीके खुद दिवालिया घरा दिये जाते हैं वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा ।

दफा ८५ मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा अदालत द्वारा दी हुई आज्ञाओं को मानते हुए आफिशल एसायनी दिवालिये की आयदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जखवाहोंमें बाँटे जानेके सम्बन्धमें कर्जखवाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए प्रस्ताव पर ध्यान रखेगा ।

(२) आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह समय समय पर कर्जखवाहों की संज्ञा जाननेके लिये उनकी मीटिंग करे तथा उसका कर्तव्य होगा कि वह कर्जखवाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए समय पर या अदालत की आज्ञा दिये हुए समय पर या कर्जा साबित किये हुए कर्जखवाहोंके चौथाई कर्जा वाले कर्जखवाहोंके लिख कर कहने पर मीटिंग अवश्य करे ।

(३) दिवालिये की कारवाईके सम्बन्धमें पैदा हुए किसी मामलेके लिये आफिशल एसायनी अदालतसे सलाह भोग सकता है ।

(४) इस एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी आयदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जखवाहोंमें तकनीम किये जानेके सम्बन्धमें अपनी रायका प्रयोग करेगा ।

उपदफा—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि यदि कर्जखवाहों की मीटिंगमें कोई प्रस्ताव दिवालिये की आयदादके प्रबन्ध अपना उसका बाद आनेके सम्बन्धमें पास किया गया हो और प्रस्ताव इस एक्टके किसी नियमके विरुद्ध अथवा अदालतकी आज्ञाके विरुद्ध न पड़ता हो तो आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रस्तावको कार्य कर्म परीक्षित करनेकी शक्ति पर तथा उसे पूरे प्रस्तावकी अवदलना नहीं करना चाहिये जैसा कि अग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द प्रकट है ।

उपदफा (२) में आफिशल एसायनीके लिये बतलाया गया है कि वह समय २ पर कर्जखवाहोंकी मीटिंग किया करे परन्तु ऐसा करनेके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है परन्तु यदि कर्जखवाहोंने अपना किता मीटिंगमें किसी कार्यके निर्णयके लिये मीटिंग करना पास किया हो अपना अदालत मीटिंग करनेके लिये कर्ज अथवा साबित किये हुए कर्ज वाले कर्जखवाहोंमें से चौथाई कर्ज वाले कर्जखवाह लिख कर देने ता आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह मीटिंग अवश्य करे जैसा कि अग्रेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (३) में बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी यदि चाहे तो वह अदालतमें दिवालियेके किसी मामलेके सम्बन्धमें राय ले सकता है इसके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (४) के अनुसार आफिशल एसायनी को पूर्ण स्वतन्त्रता आयदादके प्रबन्ध करने तथा उसके बादमें प्राप्त है केवल उसका इस एक्टमें बतलाये हुए किसी नियमकी अवदलना ऐसा करनेमें नहीं करना चाहिये ।

दफा ८६ अदालतमें अपील

यदि आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेसे किसी कर्जखवाह दिवालिया या अन्य किसी व्यक्तिको हानि पहुँचती हो तो वह अदालतमें अपील कर सकता है । और अदालत शिकायत किये हुए काम या फैसले को मजूर कर सकती है, पलट सकती है अथवा संशोधित कर सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीके किसी कार्य या पैमकेके विरुद्ध अपील अदालतमें की जासकती है अदालत को अधिकार है कि वह अपील होने पर आफिशल एसायनीके कार्य या पैमकेको जैसे का तैसा बना रहने दे अथवा उसे रद्द कर देवे या उसमें उचित संशोधन कर देवे । यदि अपीलमें जन लोग एक दूसरे की रायसे सहमत न हों तो दिवालियेकी रायवाईके सम्बन्धमें लेटर्स पेटेंट अपील (Letters patent appeal) दाखिलकी जासकती है, देखो—34 Mad. 121.

दफा ८७ अदालतका दवाव

(१) यदि कोई आफिशल एसायनी दफादारीके साथ अपने कर्तव्य का पालन न करे और वह कानून, कूल या अन्य प्रकारसे अपने लिये धतलाये हुए नियमोंका जो उनके कर्तव्यके पालनके लिये बनाये गये हों ध्यान न रखे या उसके बारेमें किसी कर्मरवाह द्वारा शिकायत कीगई हो तो अदालत उस मामलेमें तहकीकात करेगी तथा उसके लिये आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

(२) यदि अदालत आफिशल एसायनीसे किसी समय उस दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें कुछ दुर्याप्त किया चाहे जिसमें वह आफिशल एसायनी होवे तो वह पूछ सकती है तथा दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें उसके अथवा अन्य किसी व्यक्तिके हलफत बयान ले सकती है ।

(३) अदालत आफिशल एसायनी की किताबों व पत्रों (Vouchers) की जाँचके लिये हुकम दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालतका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आफिशल एसायनीके मामलोंकी तहकीकात करे जो अपना कर्तव्य पालन न करता हो या जो किसी कानूनकी अवहेलना करता हो जिसकी पाबंदी उसके लिये आवश्यक होवे । केवल तहकीकात ही की आवश्यकता नहीं है किन्तु यथोचित कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जाना चाहिये । कर्मरवाहकी शिकायत पर भी ऊपर बतलाई हुई कार्रवाई आफिशल एसायनीके विरुद्ध की जावेगी ।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत आफिशल एसायनीसे दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें कोई भी बात दर्शाव कर सकती है तथा उसका या अन्य किसी व्यक्ति का बयान हलफते ले सकता है ।

उपदफा (३) के अनुसार आफिशल एसायनीकी किताबों व पत्रोंके सम्बन्धमें भी जाच कराई जासकती है । अदालतकी इच्छा पर ऐसा करना न करना निर्धार है जैसा कि अमेरिकी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

पांचवां प्रकरण

जांच कमेटी

दफा ८८ जांच कमेटी

अदालतको अधिकार है कि मुनासिब समझने पर वह उन कर्जतवाहों को जो अपने कर्ज साबित कर चुके हैं इस बातका अधिकार दे देवे कि वह कर्जतवाहोंमें से या उनके प्रोक्सी (Proxies) अथवा उनके मुकतारआममें से एक जांच कमेटी आफिशल एसायनी द्वारा दिवालियाकी जायदादके प्रबन्ध का निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त कर सके। परन्तु शर्त यह है कि जो कर्जतवाह जांच कमेटी का मेम्बर बनाया गया हो वह उस वक्त तक उसमें कार्य करने योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपना कर्ज साबित न कर देवे।

व्याख्या—

जैमेनी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार कार्यवाही करनेके लिये शाय नहीं है किन्तु इसके अनुसार हुकम देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है इस दफाके अनुसार अन्य कमेटी बनानेके अधिकार केवल उन्हीं कर्जतवाहोंको प्राप्त हो सकते हैं जो अपना कर्ज साबित कर चुके हों परन्तु कमेटीके मेम्बर वाई भी कर्जतवाह बनये जासकेंगे चाहे उन्होंने मेम्बर बनाये जाते समय तक अपना कर्ज साबित किया हो या न किया हो कर्जतवाहोंके अतिरिक्त उन्हीं ओग्रेटे बोट देनेवाले अधिकार वाले हुए व्यक्ति तथा उनके मुस्तार आस भी कमेटीके मेम्बर बनाये जासकेंगे हैं यह बात ध्यानमें रहना चाहिये कि कर्ज न साबित किया हुआ कर्जतवाह कमेटीका मेम्बर तो बनाया जासकेगा परन्तु कमेटीमें काम करना अधिकारी उन्ही समय होगा जब कि वह अपना कर्ज साबित कर देवे। इस वष नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जिसके अंतर्गत एक्टमें इन सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है।

दफा ८९ जांच कमेटीके आफिशल एसायनीकी जांचके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनी की कार्यवाहियों पर जांच कमेटीको नियन्त्रणके बड़ी अधिकार प्राप्त होंगे जो इस सम्बन्धमें निर्धारित किये जावें।

व्याख्या—

जांच कमेटी निर्धारित किये हुए जांचके नियमोंकी पाबंद होगी अर्थात् उनके विपरीत नहीं कर सकेंगी जिस कि जैमेनी एक्टमें किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य है।

दफा ९२ एकके स्थानमें दूसरे कर्जस्वाह द्वारा कार्रवाईका किया जाना

यदि दरखास्त देने वाला व्यक्ति उचित मेहनतके साथ दरखास्तकी परखी न करता हो तो अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्जस्वाहको उसकी जगह पर दरखास्त देने वाला मानले परन्तु इस दूसरे कर्जस्वाहके कर्जेकी तादाद वही होना चाहिये जो दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके लिये इस एक्टमें बतलाई गई है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत किसी मामलेकी पैरवीमें न्यूनता देखकर उसकी उचित पैरवीके लिये अपनी दरखास्त देने वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरे कर्जस्वाहको मान सकती है परन्तु ऐसा करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अमेरिकी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार कार्रवाई करते समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दूसरा शायद कितना आना कर्जस्वाह भी कर्जदारसे कमसे कम (५००) रुपयेका कर्ज पतिका हकदार होवे।

दफा ९३ कर्जदारके मरजाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना

यदि कोई कर्जदार जिसके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त दी गई होवे अथवा जिसने दरखास्त दी होवे मर जावे तो उसके मामलेकी कार्रवाई जारी रखी जावेगी जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कर्जदारके मर जाने पर भी दिवालियेकी कार्रवाई बाद रस्ता जावेगी व इस नियमकी अवहेलना नहीं की जा सकती है जैसा कि अमेरिकी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे भासता है। परन्तु अनुमनकी अधिकार है कि इस नियमके विरुद्ध भी वह आज्ञा दे सकती है यदि कोई आज्ञा उक्त नियमके विरुद्ध न दी गई हो तो इस नियम की पाबंदी अवश्य की जावेगी।

दफा ९४ कार्रवाईको रोकनेके अधिकार

अदालत किसी समय भी उचित कारणके उपस्थित होने पर दिवालियेकी दरखास्तके सम्बन्धमें होने वाली किसी कार्रवाईके स्थान पर कुछ समयके लिये किन्हीं शर्तोंके साथ बंद स्थगित कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कार्रवाई करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अमेरिकी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियेकी कार्रवाईका किसी नियत समयके लिये अथवा सर्वदेके लिये रोक सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे। जैसा कि दिवालियेके मामले पर या दिवालियेके विरुद्ध किन्हीं दूसरी अदालतमें कार्रवाई होने पर अपना अन्य किसी ऐसे ही अवसरके उपस्थित होने पर अदालत मुत्तरी का हुक्म दे सकती है।

दफा ९५ किसी शरीकदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्तका दिया जाना

यदि किसी कर्जस्वाहका कर्ज किसी फर्मके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त देनेके लिये फार्मा होवे तो उस कर्जस्वाहको अधिकार है कि वह उस फर्मके किसी एक या अधिक हिस्से-

द्वाराके विरुद्ध दरखास्त उस कर्जेके आधार पर दे सके अर्थात् यिला सब कर्जद्वाराओंको उस दरखास्तमें शामिल किये हुए वह दरखास्त दे सकता है।

व्याख्या—

यदि किसी हिन्दू मेषकी नाबालिगीमें आनदाना वसोएके लिये कोई कर्ज लिया गया हो तो बालिग होने पर वह व्यक्ति ऐसे कर्जेके आधार पर दिवालिया कार नहीं दिया जासकता है देखो—41 Mad 821. इस दफाके अनुसार सयुक्त कर्जोंके लिये सयुक्त कर्जेके जिम्मेदार बालिगोंके लिये एक साथ या अलगहटा अलगहटा दरखास्त दिवालिया दी जासकती है व अलगहटा दरखास्त दिये जाने पर वह व्यक्ति पूरे लयुक्त कर्जेके लिये कर्जदार समझा जावेगा अर्थात् हिस्सा रसदके दिवाबन्धे उस पर उस कर्जेकी जिम्मेदारी नहीं संपादी जावेगी।

दफा ९६ कुछ रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दरखास्तका खारिज किया जाना

यदि किसी दिवालियेकी दरखास्तमें एकसे अधिक रिस्पान्डेंट्स होवें तो अदालत उनमेंसे किसी एक या अधिक रिस्पान्डेंटके विरुद्ध दरखास्तको खारिज कर सकती है और इस प्रकार खारिज किये जानेका कोई प्रभाव बाकी बचे हुए रिस्पान्डेंट या रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दिये हुए पिटीशन पर नहीं पड़ेगा।

व्याख्या—

इस दफाके नियमोंका प्रयोग अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसे कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है। इस दफाका प्रयोग उसी समय हो सवेगा जब एक्से अधिक व्यक्तियोंके विरुद्ध कोई दरखास्त दी जावे। यदि ऐसी दाय्वाला पर अदायत किसी एक या एक्से अधिक व्यक्तियोंका संग कर दवे तो बारी बच हुए व्यक्तियों पर भी बारी किये जानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके विरुद्ध वह दरखास्त बदलाव बना रहेगा।

दफा ९७ शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटीशनोका दिया जाना

जब कि फर्मके किसी शरीकदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जावे तो उसी फर्मके किसी दूसरे शरीकदार या शरीकदारोंके विरुद्ध या उनके द्वारा दी हुई दिवालियेकी दरखास्त उसी अदालतमें दी जावेगी या उसी अदालतमें भेज दी जावेगी जहां कि पहिले बतलाई हुई दरखास्तकी सुनवाई हो रही हो। और वह अदालत उन दरखास्तोंको शामिल कर दिये जानेके लिये वह हुक्म देसकती है जो उसे उचित प्रतीत होयें।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि एक ही मामलेमें सबबदलते वाले एक्से अधिक मामले होवें तो उनको एक ही अदालत द्वारा सुना जाना उचित बतलाया गया है जिसमें उचित प्रतीत होने पर वह एक साथ शामिल कर दिये जायेंगे। जेम्मे कि यदि फर्मका एक शरीकदार किसी अदालत द्वारा दिखसतिया करार दिया गयाहो तो उसी फर्मके अन्य शरीकदारोंके विरुद्धकी अन्य दिवालियेकी बारीवाई उसी अदालतमें ही जाना चाहिये और यदि किसी दूसरे अदालतमें दरखास्त दी गई हो तो वह भी उसी अदालतमें भेज दी जाना चाहिये।

दफा ९८ आफिशल एसायनी तथा दिवालियेके शराकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमें

(१) यदि फर्मका कोई शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो अदालत आफिशल एसायनीको उस दिवालियेके नामसे तथा उस दिवालियेके शरीकदारके नामसे कारवायके जारी रखने या शुरू करने व उसकी पैरवी करनेका अधिकार दे सकती है । और जिस मामलेके सम्बन्धमें कारव है चल रही हो यदि उस सम्बन्धमें कोई शरीकदार कुछ छोड़ देंतो ऐसा छोड़ा जाना रह होगा ।

(२) यदि उपदफा (४) के अनुसार मुकदमा जारी रखने या शुरू करनेकी आज्ञा देने के लिये दरखास्त दी जाये तो उसकी सूचना दूसरे शरीकदारको दी जावेगी जिसमें कि वह उसका विरोध कर सके और उसकी दरखास्त पर अदालत यह हुकम दे सकती है कि उसे उस मामलेसे उसका मुनासिब भाग मिल सके और यदि वह उससे कोई लाभ न उठाया चाहें तो उसको उस सम्बन्धमें दिलाये जाने वाले उस खर्चका मुआविजा मिलेगा जिसके लिये अदालत हुकम देवे ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार फर्मके किसी एक शरीकदारके दिवालिया करार दिये जाने पर आफिशल एसायनीकी उस शरीकदारके नामसे तथा उसके दूसरे शरीकदारके नामसे मामला जारी रखने या नया मामला दायर करनेका अधिकार दिया जा सकता है । अदालत ऐसा करनेके लिये बाध नहीं है कि नु इसका करना न करना अदालतकी आज्ञा पर निर्भर है नैमा कि जेम्सी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है । यदि उपदफा (१) के अनुसार किसी बन्ने या मांगके सम्बन्धमें कोई मामला चल रहा हो और फर्मका कोई शरीकदार उस बन्ने आदिमें छेद देवे तो इस प्रकारका जोराना अविविध हागा तथा वह रह सम्पदा जावेगा ।

उपदफा (२) में बतलायागया है कि फर्मके दूसरे शरीकदार इनानकी दाय्वालाका विरोध कर सकते हैं तथा अदालत द्वारा उनकी उनका किसी मामलेकी कामगामी पर दिव्याया जासकती है और यदि वह शरीकदार मामलेसे कुछ सम्पदा न रखताछाहे तो दफा ही वह उस मामलेके खर्चे भी नहीं लादा जावेगा । जो अदालतकी मुनासिब हुकम देना अधिकार इस प्रकारके मामलोंमें है कि नु फिर भी विरोध करनेका अवसर तथा खर्चे आदिमें बचनेकी आज्ञा अदालतकी अवश्य देना चाहिये जैसा कि जेम्सी एक्टकी १७ उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है ।

दफा ९९ साझेके नामसे मामलेका चलाया जाना

(१) यदि दो या दो से अधिक साझीदार होंवे, अथवा कोई व्यक्ति साझेके नामसे कारोबार करता हो, तो वह लोग इस एक्टके अनुसार फर्मके नामसे कारवाय कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि ऐसे मामलोंमें किसी सम्बन्धित व्यक्तिके दरखास्त देने पर फर्मके शरीकदारोंका नाम अथवा उस व्यक्तिका नाम जो फर्मके नामसे काम करता हो जाहिर करनेका हुकम अदालत दे सकती है और यह उस प्रकार चलाये जावेगा तथा हलफसे उनकी तस्दीक उस प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार अदालत हुकम देवे ।

(२) यदि किसी फार्मा कोई शरीकदार नावालिग होवे सो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म उस नावालिग शरीकदारके अतिरिक्त फार्मे विरुद्ध दिया जासकता है।

व्याख्या—

जिस नामसे बारोबार होता हो उस नामसे दिवालियेके सम्बन्धमें फार्माही जासकती है चाहे उस नामसे बारोबार कोई व्यक्ति अकेले ही किया हो अथवा उसमें कई शरीकदार हों। परन्तु यदि कोई सम्बन्धित व्यक्ति यह जानना चाहे कि उस फार्मे नाममें क्या वृत्ति कायदाई कर रहा है अथवा फार्मे सब शरीकदारोंके क्या नाम हैं तो अद्वारत उन लोगों नाम बतलाये जानना हुक्म देसकता है और अब समय अदालतकी आज्ञाके अनुसार उन लोगोंके नाम बतलाये जायेंगे तथा उसकी तस्दीक हुक्म की जायेगी।

उपदफा (२) के अनुसार किसी फार्मा नावालिग शरीकदार दिवालिया करार नहीं दिया जावेगा परन्तु वह फार्मे अथवा उसके दिवालिया करार दिया जासकता है इस दफाके अनुसार फार्मे बानके लिप बोई व्यक्ति बाध्य नहीं है जसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग दिये हुए (May) शब्दमें प्रकट है नावालिग सल्लेख दफा ९ में किया जासकता है।

दफा १०० अदालत दिवालियाके वारण्ट

(१) अदालत दिवालिया द्वारा जारी किये हुए वारण्टों की तामीन उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार सन् १८६८ ई० के क़ायदा फौजदारीके अनुसार जारी किये हुए वारण्टोंकी जाती है।

(२) दिवालियेकी आयदादके किसी हिस्से पर कब्जा लेनेके लिये दिया हुआ वारण्ट जो दफा ४६ की उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो निर्धारित फार्ममें होगा और ऊपर बतलाये हुए एक्ट की दफायें ७७ (२), ७६, ८२, ८३, ८४ तथा १०२ जहा तक होगा ऐसे वारण्ट की तामीनके सम्बन्धमें लागू होंगी।

(३) यदि दफा ४६ (२) के अनुसार तलाशीका वारण्ट जारी दिया गया हो तो उसकी तामीन उसी प्रकार होगी ज वही शर्तें लागू होंगी जो ऊपर बतलाये हुए एक्टके अनुसार जोरी की आयदादके लिये जारी किये हुए तलाशीके कारण वारण्टमें लागू होती है।

व्याख्या—

इस दफामें वारण्टकी तामीनके नियम बतलाये गये हैं। बोई नये नियम इन एक्ट के लिये इस सम्बन्धमें नहीं बनाये गये हैं। उपदफा (१) में यह बतला दिया गया है कि सन् १८९८ ई० के समय क़ायदा फौजदारीका नियम वारण्टों की तामीनके लिये दिये हुए हैं जहाँ प्रयोग इस एक्टके अनुसार नाम दिये हुए वारण्टोंके सम्बन्धमें किया जावेगा। उक्त समय अथवा फौजदारीके अन्तर्गत क़ायदोंमें यह नियम दिये हुए हैं और वह दफा ७५ से लेकर दफा ९१ तक मिलेगा तथा इसके बाद दफा ९६ से दफा १०३ तक भी सार्वत्रिक प्रकरणमें कुछ नियम वारण्ट तलाशी आदिके सम्बन्धमें दिये हुए हैं।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि दिवालियेकी आयदाद पर कब्जा लेने वाले वारण्टोंकी तामीनमें वह नियम लागू होंगे जो समय क़ायदा फौजदारी की दफायें ७७ (२) ७९, ८१, ८३, ८४ और १०२ में दिये हुए हैं।

क़ायदा फौजदारीकी दफा ७७ (२) के अनुसार यदि बाण्ट एक्टसे अधिक पुलिस अधिकारी या दूसरोंके नाम जारी किया गया हो तो उसकी तामीन सब लोग मिलकर या उनमेंमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ७६ के अनुसार यदि वारण्ट किसी पुलिस अफसरके नाम जारी किया हो तो उसकी तामील कोई दूसरा पुलिस अफसर भी कर सकता है जिसका नाम पहिले पुलिस अफसरने वारण्ट पर लिख दिया हो ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ८२ के अनुसार गिरफ्तारी का वारण्ट ब्रिटिश भारतके किसी भी हिस्सेमें तामील किया जासकता है ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ८३ के अनुसार यदि वारण्ट जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमासे बाहर तामील किया जानको होवे तो अदालत ऐसे वारण्टको बजाय किसी पुलिस आफीसरकी देनेके उस डिस्ट्रिक्ट मागिस्ट्रेट सप्ली-मेंट पुलिस या पुलिस कमिश्नरके पास भेज सकती है जिसके अधिकार सीमामें उस वारण्टकी तामील दरकार होवे और इस प्रकार वारण्टके भेजे जाने पर पावे वाला हाकिम अपने दस्तखत करके जहा तक हो सकेगा उसकी तामील करवेगा ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ८४ के अनुसार यदि किसी पुलिस आफिसरको कोई ऐसा वारण्ट तामीलके लिये दिया जावे जिसकी तामील जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमामें बाहर की जाने की होवे तो वह उस वारण्ट पर उस मजिस्ट्रेट या थानेदार या उससे ऊंचे किसी पुलिस आफिसरके दस्तखत करवेगा जिसके हल्केमें उस वारण्टकी तामीलकी जाने की होवे और ऐसे अफसरके दस्तखत होने पर तामील करने वाले पुलिस आफिसरको उसके तामील करने का अधिकार प्राप्त हो जावेगा तथा वह भी छोड़ल पुलिस भी आवश्यकता पड़ने पर उसे मदद देगी यदि दस्तखत आदि करनेमें देर होनेकी सम्भावना हो जिसके कारण फिर वारण्टकी तामीलही नामुमकिन हो जाती हो तो पुलिस आफिसर बिना दस्तखत करायेही तामील कर सकता है ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा १०२ के अनुसार यदि किसी बन्द जगह की तलाशी ली जाने की होवे तो उस जगह का मालिक या कब्जा उस जगहकी तलाशी वारण्ट दिखाने जाने पर देने देवेगा, यदि वह उसकी तलाशी नहीं छेन देवे तो जबरन उसकी तलाशी ली जावेगी और यदि कोई आदमी किसी चीजको अपने निस्पमें छिपाये हुए होवे तो उसके निस्पमें भी तलाशी ली जासकती है ।

उपदफा (३) के अनुसार तलाशके वारण्ट भी समूह जावना कानूनधर्ममें बतलाये हुए चौरोंके मालकी तलाशी वाले नियमोंके अनुसार तामील किये जावेंगे तलाशीके वारण्टका जिक्र दफा ९६ से लेकर दफा १०३ तक किया गया है दफा ९८ में चौरों की जायदाद वाले मकानकी तलाशी । जिक्र है अर्थात् हर प्रकारके वारण्टकी तामील जावता कानूनधर्ममें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार की जासकेगी ।

सातवां प्रकरण

मियाद

दफा १०१ अदालतके लिये मियाद

आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील अथवा अदालतके किसी अफसर के हुक्मकी अपील जिसे दफा ६ के अनुसार अधिकार दिया गया हो उस कामसे अथवा हुक्म या फैसलेसे जैसा कि मामला होव वीस दिनके अन्दर की जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील उस काम या फैसलेके होनेके बाद २० दिनोंके अन्दर की जासकती है। उस अफसरके नाम अथवा फसलेकी अपील भी इसी मियादके अन्दर की जासकती है जो इस एक्टकी दफा ६ में बतलाये हुए नियमके अनुसार नियुक्त किया गया हो—देखो पिछली दफा ६ व उसकी व्याख्या यदि दिवा-लिया का काम करने वाले जनके हुक्मकी अपील की गई हो तो अदालत अपीलकी अपेक्षा है कि वह खर्चों जमानत लिये जनके सम्मुखमें दो हुई दरवाजोंके ले सके तथा उस पर विचार कर सके देखो—43 Cal 243 इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालतकी दफा १० (५) के अनुसार मियाद बढ़ाने का अधिकार शासक है अर्थात् अदालत मियाद समाप्त होनेके बाद अथवा उसमें पहिले यदि वह उचित समझे तो गिन गणोंके साथ चाहे उस एक्ट अथवा कानूनके अनुसार नियमकी हुई मियादसे बढ़ा सकता है—देखो पिछली दफा १० (५) इस दफामें बतलाई हुई २० दिनोंकी मियाद काम या फैसला होनेके समयमें सुधार की जावेगी इस प्रकार यदि आफिशल एसायनीके किसी सुवृत्तमें न माना हो तो इसके अपीलकी मियाद उस दलके समझी जावेगी जबकि आफिशल एसायनीके वसूह लिखकर सुवृत्तमें नामावृत्त किया हो जैसा कि उसे दूसरी सूचीके पचासवें कलके अनुसार करना आवश्यक है।

आठवां प्रकरण

दण्ड

दफा १०२ विला बहाल हुआ दिवालिया यदि कर्ज लेवे

यदि विला बहाल हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिसे विला उसको यह बतलाये हुए कि वह विला बहाल किया हुआ दिवालिया है पचास रुपये या इससे अधिकका कर्ज लेवे तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी निर्धारित किये जाने पर उसको छः महीने तकके कारावासका दण्ड या जुर्मानाका दंड अथवा दोनों प्रकारके दंड साथ साथ दिये जासकेंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कोई दिवालिया गण तक कि वह बहाल न कर दिया जाने पचास रुपये या इससे अधिकका कर्ज

उपदफा (५) में दिशावर्षा विताओं तथा अन्य तद्वर्गी बाधनाओंका उल्लेख है वह उपदफा तीन प्राणोंमें विभक्त का नहीं है । (१) पहिले प्राणके अनुसार किताबी आदिना न पक्ष किया जाना जब कि उनका पक्ष किया जाना आवश्यकता इस प्रकारके अनुसार होने दण्डनीय बनलाया गया है (११) दूसरे प्राणके अनुसार यदि छुटी हिमावर्षा विताओंमें गवती गई हो तो वह दण्डनीय है (१११) तसारे प्राणके अनुसार यदि छुटे इन्दान किय गये हों वा बाई इन्दान किये ही न गये हों तो ऐसे काम भी दण्डनीय मतलब गये हैं ।

उपदफा (बी) में किसी कर्मन्वादीको नेजा तर्जिह देनेके लिये अपना कर्मन्वादीमें मारी जाने योग्य आपदाको कम करनेकी मशारे यदि कोई कर्म लिखाया गया है या छुटा दिया गया हो अपना कोई आपदा लिखाई गई हो या उस पर बार पड़ा गया हो तो ऐसा काम ऊर्ध्व समझा जावेगा यह उपदफा भी दो प्राणोंमें विभक्त है पहिले प्राणके अनुसार कोई वा वस्तु मशारे लिखाया जाना या छुटाया जाना ऊर्ध्व है दूसरे प्राणके अनुसार आपदाका इरादा होने उसे रोक कर देना या उस पर बार पड़ा कर देना ऊर्ध्व है । ॥ दफाके अनुसार ऊर्ध्व साबित होने पर दो साल तककी सजा दी जावेगी इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि सजा सारी कैद होगी या सरल कैद इसलिये यह समझना चाहिये कि सारी व सरल दोनों प्रकारकी सजाएँ दी जासकेंगी । यदि किसी रेलवे प्राविडेंट कण्डस दिवालयका कुछ कथ्या मिलने वाला होने और वह उस रुपयेको उठा लेवे तो वह ऊर्ध्व नहीं समझा जावेगा क्योंकि प्राविडेंट कण्डस कथ्या बलीक है और उसका उठालना प्राजेकी कार्रवाई नहीं है वर्यो दि वर्षावाधानका बस पर एक नहीं होता है देखो—45 Bom 694 मशारे बाईकेरने यह तथ किया था कि दफा १०३ के अनुसार १५ रुपये ऊर्ध्वमें सुमानका बाई अधिवार प्रसीडेंसी पनिरट्टको नहीं है यह ऊर्ध्व एकदमे अनुसार ऊर्ध्व मतलब गये हैं और बनवा फसला करनेका अधिवार कनक अदालत दिशालयको है जो कि ऐसे मामलोंकी सुननेके लिये एक विश्व अदालत है व उसका कार्यक्रम भी भिन्न है देखो—लकी बनाप नरसिंहाणी 25 Mad L. I 577 ॥ दफाके अनुसार दोषी निर्धारित करनेके लिये सुदरईका कर्तव्य होगा कि वह दिवालयकी नियतको साबित करे । और जब तक कि किये हुए मामले स्वाभाविक पीणाम यहा न निकलना हो तब तक नीयत नहीं मानी जावेगी देखो—अनुपराधीन बनाम आदिशाल एमायना 27 I. C 753, किसी कर्मन्वादी दिवालयिया दरखास्त दी इसका बाद उसके किसी कर्मन्वादीने प्रेसी-डे ही मेनिरट्टके यहा धोलादहा (Cheating) का मामला दायर किया तो यह तथ हुआ कि दिवालयकी दरखास्त दे दिने जाने ही से प्रेसीडेंसी मेनिरट्टके अधिवार कर्मन्वादीके विरुद्ध मामला सुननेके नहीं जाते रहते हैं दफा १० में जो सदी कानुनी कार्रवाईका सिद्ध है वे दावाना कार्रवाया समझना चाहिये 25 Bom 63 परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसे मामलोंमें जब कि बाधक अदालत दिवालयियोंमें दाखिल किये गये हों आर उसके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई ही जानेकी होने तो अदालत दिवालयियोंकी आज्ञा होने उचित मनीत होता है देखो—37 Mad. 107. इस दफामें छुमाता किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है आर इसलिये यदि ॥ दफाके अनुसार ऊर्ध्व किय जाने पर छुमाते का वह दिया जाव तो वह साफ तौरसे गलत है, देखो—मोत्याल विश्वास बनाम सरकार बहादुर 32 O W N. 1140.

यदि दफा १०३ (बा) (११) क अनुसार कोई कर्मन्वादी खारिज हो गई हो तो वह सजे ताजपाद हिन्दकी दफा ४२२ व ४२४ के अनुसार कार्रवाई किये जानेमें रुकावट नहीं पडगी, देखो 61 Rang 664 वह व्यक्ति जो दिवालयी करार दिया जायगा हो तथा जिसकी आपदाद आफिशाल एसायनाकी सुदरईमें आरई हो तो वह ऐसी छिन्नेके हवायमें जेल नहीं भना जाना चाहिये जिसमें कि वह पहिल ही शागो की जमानत दे चुका हो चाहे उसने अपनी निताबें पेश न की हों वा रखाका हुक्म (Protection Order) उमका न मिला हो । निताबें न पेश करने पर उसके विरुद्ध कानून दिवालयियोंके अनुसार कार्रवाई की जासकता है, देखो—नगरपाल मोदी बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता A. I. R. 1929. Cal 1144.

दफा १०४ दफा १०३ के जुर्मोंके लिये कार्य क्रम

(१) जब कि आफिशल एसायनी अदालतमें इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालयियेने

दफा १०३ के अनुसार कोई जुर्म किया है या न कि अदालतको किसी क्रॉन्प्राइज कहने पर यह विश्वास हो जावे कि दिवालियेने कोई ऐसा जुर्म किया है तो अदालत इस बातका हुक्म दे सकती है कि दिवालियेके पास नोटिस निर्धारित किये हुए डंग का भेजना चाहिये कि जिसमें वह बजह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे।

(१) नोटिसमें जुर्म की असलियत दिखलाई जावेगी और एक ही नोटिसमें अनेकों जुर्म दिखलाये जासकते हैं।

(३) ऐसे नोटिसके सुने जानेमें तथा इस नोटिसके अनुसार अदालत द्वारा लगाये हुए जुर्मके सुने जानेमें जहां तक मुमकिन होगा वही तरीका अमलमें लाया जावेगा जो सन् १८६८ ई० के जायदा फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरमें मजिस्ट्रेटों द्वारा चारण्ड कसेज करनेके लिये बतलाया गया है और उस कोर्टके तेईसवें चैप्टरमें बतलाया हुआ हार्दकोर्ट तथा सेशन्स कोर्टमें होने वाले मामलों का तरीका ऐसे मामलोंमें लागू नहीं होगा।

(४) इस दफाके साथ अनेकों जुर्म एक साथ लगाये जासकते हैं।

व्याख्या—

इस दफामें दफा १०३ के अन्तर्गत किये हुए छपीसी बरिवाइ विषे जार्जेके नियम बतलये गये हैं बरिवाइ उही वक्त चाहू की आसकेगी जब कि आफिशल एसायनी इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालियेने दफा १०३ में बतलाये हुए किसी छपीके दिया है अथवा किसी फर्कवाहके दरखास्त देने पर अदालतको विश्वास हो जावे कि दिवालियेने दफा १०३ में बतलाये हुए जुर्मकी किया है इस प्रकार आफिशल एसायनी की रिपोर्ट तथा किसी फर्कवाहके दरखास्त देने पर यानी दोनों शक्तोंमें अदालत मामला चाहू कर सकती है।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत निर्धारित ढंगमें एक नोटिस दिवालियेको इस बातका दे सकती है कि वह नबह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे।

उपदफा (२) में बताया गया है कि ऐसे नोटिसमें जुर्म लगाये जातेका कारण दिखलाया जावेगा तथा एक ही नोटिसमें बहुतसे जुर्म एक साथ दिखलाये जासकते हैं अर्थात् अनेक जुर्मके लिये अलग-अलग आवश्कता नहीं है।

उपदफा (३) में बताया गया है समझ जायता फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरके अनुसार बरिवाइ की जावेगी परन्तु यह दफा सन् १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बदल गई है और अब अदालत दिवालिया बनाय इसके कि वह स्वयं मामलोंको सुने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटोंके पास भेज सकती है परन्तु ऐसा वह उसी समय करेगी जब कि उसको प्रायः रूपमें यह मान्य हो कि दिवालियेने दफा १०३ के अनुसार किसी जुर्म की जिगा है व उसके विरुद्ध बरिवाइ की जाना चाहिये। अदालत दिवालिया यदि उचित समझे व जिस प्रकार उचित समझे मामला भेजेगा पहले प्रागम्भिक जाच भी कर सकती है। यह संशोधन इसलिये किया गया था कि जिसमें हार्दकोर्टके जजों का मुख्यान समय छोटे छोटे मामलोंकी तहकीकात व सुनवाईमें बुरा नष्ट न होवे व बरिवाइ फौजदारीक अन्य मामलों की भांति नियम पूर्वक सुननेके बाद की जासके अर्थात् जुर्म साबित होने पर अदालत फौजदारी दिवालिये की दण्ड दे सके। सन् १९२६ ई० के संशोधन एक्टके जारी होनेसे पहले दिवालिपर्वा बरिवाइ चाहू हो चुकी थी परन्तु इसके जारी होनेके पश्चात् नजने इत्तरासा मजिस्ट्रेटोंके पास भेजा तो यह तय हुआ कि तद-कीकत संशोधन एक्टके अनुसार होना चाहिये इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दफा २७ के अनुसार दिये हुए दिवालि-येके बयानों पर विचार किया जासकता है। देखो—मोतीअल विश्वास बनाम सरकार नं० 32, C. W. N. 1140 (The Yearly Digest 1928 P. 1141.)

दफा १०५ बहाल होनेके बाद या तस्फीहा होनेके बाद भी जिम्मेदारी

जब कि दिवालिया दफा १०२ या दफा १०३ में बतलाये हुए किसी जुर्माना दोषी निर्धारित किया गया हो और वह बहाल हो चुका हो अथवा उसका तस्फीहा या स्कीम स्वीकार करती गई हो तो इन कारणोंसे उसके विरुद्ध कार्रवाई रोकी नहीं जावेगी अर्थात् बहाल होने पर या तस्फीहा हो जाने पर भी उसके विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई चालूकी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी व्यक्तिके बहाल हो जानेके बाद अथवा उसके द्वारा पेशकों हुई रकम या तस्फीहाके स्वीकार किये जानेके बाद-उसके विरुद्ध कोई जुर्माना जिसका उल्लेख दफा १०२ व १०३ में किया गया है मादित होवे तो उसके विरुद्ध उस जुर्माने कार्रवाई जरूरीकी जावेगी अर्थात् मामला चला दिया जावेगा और वह हमसे बरी नहीं समझा जावेगा । यद्यपि हुए दिवालियोंके अथवा उस दिवालियोंके निमेषा तस्फीहा स्वीकार कर लिया गया हो अपनेको बरी नहीं समझना चाहिये अर्थात् उन जुर्माने सम्बन्धमें उनकी जिम्मेदारी उस समय भी बनी रहेगी ।

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाइयां

दफा १०६ छोटे मामलोंमें सरसरी की कार्रवाइयां

(१) जब कि अदालतको हजरतनामेले अथवा अन्य किसी प्रकारसे यकीन हो आवे या आफिशल एसायनी अदालतमें रिपोर्ट दे देवे कि दिवालियेकी जायदादकी कीमत तीन हजार रुपयेसे या इससे कम निमतकी हुई तादादसे अधिक न होगी तो अदालत दिवालियेकी जायदाद का प्रबन्ध सरसरी तीरसे करनेका हुक्म दे सकती है और तब इस पदकके नियमोंमें निम्नलिखित संशोधन होगा :—

- (५) अदालतके किसी हुक्मके विरुद्ध बिला उसकी आज्ञा लिये हुए कोई अपील नहीं की जावेगी ।
- (७) बिला आफिशल एसायनीके अथवा किसी कर्जदारके दरखास्त दिये हुए दिवालियेका ध्यान नहीं लिया जावेगा ।
- (८) जब कि मुमकिन होगा जायदाद एक ही हिस्सा रसदीमें बांट दी जावेगी ।
- (९) उर्ख कम करने तथा कार्य क्रमको सुगम बनानेके लिये जो दूसरे संशोधन निर्धारित किये जावें परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की किसी बातसे दिवालियेके बहाल होनेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम संशोधित नहीं किये जावेंगे ।

(२) अदालत किसी समय भी यदि उसे उचित प्रतीत हो दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें सरसरीके इन्तज़ाम का हुकम दे सकती है ।

न्याय्या—

इस दफ़ा में दिवालियेके छोटे मोटे मामलोंमें अधिक समय न लगाने तथा फ़िजूल खर्चों की बचतकी नीयतसे उनकी कार्रवाई को सरसरी तौर पर करनेके नियम बताये गये हैं सरसरीकी कार्रवाई उसी समय की जासकेगी जब कि आफ़िशल एसायनीने रिपोर्टकी हो कि दिवालियेकी जायदाद तीन हज़ारसे अथवा अथर्विंशति निश्चितकी हुई रकमसे अधिककी नहीं होगी अथवा अदालतको हलफ़नामासे अन्य किसी प्रकारसे विश्वास हो जावे कि जायदाद उक्त क्रमसे अधिककी नहीं है । अदालत सरसरीकी कार्रवाई करनेके लिये वाज्य नहीं है । इसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा उपदफ़ा (५) से यह भी प्रस्ट है कि अदालत जब चाहे तो सरसरीकी कार्रवाई किये जानेके हुकम भी कर सकता है और उस वर्क मामूली कार्रवाई अमलमें लाई जावेगी । सरसरीकी कार्रवाई किये जाने का हुकम होने पर मामूली कार्रवाई जो तत्पश्चात् बतलाई जाइगी है किसी हद तक सशोधित होकर सरसरी वाले मामलोंमें लायी होगी । सशोधनों का उल्लेख उपदफ़ा (१) के क्लॉज (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है ।

क्लॉज (ए) के अनुसार बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए अदालतके किसी हुकमकी अपील नहीं की जावेगी जो एक्स्टेक्युटिव अपील जिल्ला आशके की जासकती है ।

क्लॉज (बी) के अनुसार दिवालियेके बचतकी आवश्यकता नहीं है परन्तु आफ़िशल एसायनी या कर्जदारके दरख़ास्त देने पर अदालत सरसरीके मामलोंमें भी दिवालियेके बचान ले सकती है ।

क्लॉज (सी) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद एक ही बार हिस्सा रसदीमें बांटी जासकेगी यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई हिस्सा रसदी होवे व अन्तिम हिस्सा रसदीके लिये बतलाई हुई नोटिस आदि की कार्रवाई अमलमें लाई जावे, देखो—दफ़ा ७२ खर्च कम करने तथा कार्रवाई को सादा बनानेके लिये ।

क्लॉज (डी) के अनुसार और भी सशोधन जो इस सम्बन्धमें बताये गये हैं प्रवीण किये जावेंगे ।

उपदफ़ा (१) के अन्तर्गत् यह भी बतला दिया गया है कि ऊपरके सशोधनका कोई प्रभाव बढ़ाव होने की कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा अर्थात् बढ़ाव होनेके सम्बन्धमें वह सब नियम उसी प्रकार प्रयोग किये जावेंगे जितना प्रकार तत्पश्चात् एक्स्टेक्युटिव मामूली कार्रवायोंकेलिये बतलाई गये हैं अर्थात् दफ़ा ३८ से लेकर ४५ तकमें बतलाये हुए नियम बरस्तूर लागू समझना चाहिये ।

दसवां प्रकरण



विशेष नियम

दफा १०७ कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना

दिवालियेकी दख्खास्त किसी प्रचलित एक्टके अनुसार रजिस्ट्री की हुई किसी कम्पनी, सम्प्रदाय (Association) या कारपोरेशन (Corporation) के विरुद्ध नहीं दी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार रजिस्ट्री हुआ कम्पनी व सम्प्रदाय (Association) दिवालियेकी कार्रवाईसे बचाये गये हैं इसी प्रकार कारपोरेशन (Corporation) भी बचाये गये हैं चूंकि उनकी एगस्टमें (Against) एक्ट कारपोरेशन के लिये एक मर्तवा तथा बादमें एगोभियेशन व कम्पनीके लिये एक साथ दूसरी मर्तवा इस्तेमाल किया गया है व (Registered) राज्यवा प्रयोग कम्पनी व एगोभियेशन ही के सम्बन्धमें किया हुआ मान्य होता है इससे यह प्रस्ट है कि कारपोरेशनके रजिस्ट्री होनेका कोई बिक नहीं है किन्तु कम्पनी व एगोभियेशनका किसी प्रचलित कानूनके अनुसार रजिस्ट्री होना आवश्यक है तब वह बरी हो सकते हैं अर्थात् उस समय उनके विरुद्ध दिवालियेकी दख्खास्त नहीं दी जा सकेगी । रजिस्ट्री हुआ ऐसी कम्पनी आदिके लिये कम्पनी एक्टके अनुसार डिक्लेजेशन (Liquidation) की कार्रवाई अमलमें अवैतनी ।

दफा १०८ दिवालियेकी हालतमें मरनेवाले कर्जदारकी जायदादका दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें प्रबन्ध

(१) यदि किसी मरे हुए कर्जदारके कर्जदख्खाहका इतना कर्ज होवे कि जिसके आधार पर वह कर्जदारकी जिन्दगीमें उसके विरुद्ध दिवालियेकी दख्खास्त दे सकता हो तो वह उस अदालतमें जिसकी अधिकार सीमामें कर्जदार मरनेसे छ माह पहिले अधिकतर रहा हो, या व्यापार करता रहा हो निर्धारित किये हुए ढंग पर एक दख्खास्त इस बातका हुक्म होनेके लिये दे सकता है कि उस मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध इस एक्टके अनुसार किया जावे ।

(२) मरे हुए कर्जदारके कानूनी वारिसको नियंत्रित नोटिस दिये जानेके बाद पिटीशनरके कर्ज साबित होने पर अदालत मृतक कर्जदारकी जायदाद का प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें करनेका हुक्म दे सकती है अथवा बजह ज़ाहिर किये जाने पर पिटीशनरको मय खर्चके या बिला खर्चके खारिज कर सकती है परन्तु यदि अदालतको इस बातका विश्वास हो जाय कि मृतक कर्जदारके कर्जोंके उसकी जायदाद द्वारा चुका दिये जानेकी अवैत सम्भावना है तो वह उसकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें किये जानेका हुक्म नहीं दे सकती है ।

(३) इस दफाके अनुसार जायदादके प्रबन्धकी दख्खास्त अदालतमें उस समय नहीं दी जावेगी जब कि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके लिये कार्रवाई चालू की जा चुकी हो, परन्तु यह दूसरी अदालत ऐसे मामलोंमें इस बातका सुवृत्त होने पर कि

मृतक कर्जदारकी जायदाद उसके कर्जोंको चुकानेके लिये अर्पयार्त है उस दरखास्तकी कार्रवाई को उस अदालतके पास भेज सकाया है जिसे इस एक्टके अनुसार दिवाणियेकी कार्रवाई करनेके अधिकार प्राप्त हैं और तब अन्तमें बतलाई हुई अदालत (अदालत दिवाणिया) मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म दे सकती है और यही नतीजा उस समय होगा जो किसी कर्जद्वारा द्वारा दी हुई दरखास्त पर प्रबन्धका हुक्म होने पर होता है।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार मो हुए कर्जदारकी जायदादके विरुद्ध दिवाणियेकी कार्रवाई बर्नासम्ती है। वह कर्जद्वारा ऐसी दरखास्त दे सकता है जो कर्जदारकी ज़िन्दगीमें अपने कर्जके आधार पर दिवाणियेकी दरखास्त दे सकना ही ऐसी दरखास्त के जाने पर मो हुए कर्जदारके कानूनी उत्तराधिकारियोंको नोटिस दिया जावेगा तथा उनका विशेष सुननेवाला इस बातमें विश्वास होने पर कि मृतक कर्जदारके सब कर्ज उसकी जायदादसे नहीं चुकाये जा सकते हैं अदालत दिवाणियेकी कार्रवाई निये जानेका हुक्म दे सकती है। अदालतको यदि यह यकीन होजावेगा कि मृतक कर्जदारके सब कर्ज उसकी जायदादसे उठाये जासकते हैं अथवा कर्जदारके वारिसोंकी उत्तरदायी किसी अन्य कारणसे कभी समझ पड़े तो अदालत दरखास्तकी जातिन कर सकती है अर्थात् वैसी दशामें अदालत मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध दिवाणियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं होने देवेगी। यदि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें कार्रवाई चाहनी आ रही हो तो अदालत दिवाणियामें इस दफ्तेके अनुसार प्रबन्ध निये जानेकी दरखास्त नहीं दी जावेगी अर्थात् ऐसी दरखास्त दिये जाने पर वह रर्जिस चाह नहीं होगी।

उपदफा (३) में यह भी बतला दिया गया है कि यदि अदालत दिवाणियेकी अतिरिक्त अन्य किसी अदालतमें ऊपर बतलाये अनुसार प्रबन्धकी कार्रवाईकी जा रही हो आर उस दूसरी अदालतकी यह शायद पड़े कि मृतक कर्जदारकी जायदाद उसका कर्ज चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरी अदालत अपने यहाँकी कार्रवाईके सम्बन्धन दिवाणियामें भेज सकती है। इस प्रकार भेजे जाने पर अदालत दिवाणिया अपने अधिकारोंके अनुसार उस जायदादके प्रबन्धको कार्रवाई करेगी य इस एक्टके नियम लागू होंगे। यदि मृतक कर्जदारका लड़ना उमके कर्जोंमें कम थी होवे तो लेटर ऑफ़ाडमिनिस्ट्रेशन (Letters of administration) मिल सकते हैं वही कि वैसी हालतमें केवल इन्हीं दफ्तेके अनुसार कार्रवाई असम्भवे नहीं छाई जाना चाहिये अर्थात् कर्जस्वाद या अन्य व्यक्ति दूसरे कानूनोंके अनुसार जा लागू होते हैं कि कार्रवाई कर सकते हैं देखो—15 Cal. W. N 350

दफा १०९ जायदादका मिलना तथा उसके प्रबन्धका तरीका

(१) दफा १०८ के अनुसार मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म होने पर जायदाद अदालतके आफिशल एसायनरीके प्रबन्धमें आजावेगी और यह इस पर इस एक्टके नियमोंके अनुसार जायदादको वसूल करेगा या बांटेगा।

(२) आगे दिये हुए संशोधनोंके साथ तीसरे भागके सब नियम जिनका सम्बन्ध दिवाणियेकी जायदादके प्रबन्धसे है उस हद् तक लागू होंगे जहां तक वह लागू होसकते हैं तथा इस प्रकारका हुक्म उसी प्रकार माना जावेगा जैसा कि इस एक्टके अनुसार दिया हुआ दिवाणिया क्रार दिया जानेका हुक्म।

(३) आफिशल एसायनी, प्रबन्धका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करते समय मृतकके कानूनी वारिसके उस दिवाणिया ध्यान रखेगा जो वह उचित मृतक संस्कार

कार्तिक सम्बन्धमें तथा मृतक कर्जदारकी जायदादकेलिये कानूनी खर्च करनेके सम्बन्धमें करेगा। और यह दावे इस हुक्मके अनुसार तर्जोह वाले कर्जे समझे जायेंगे और दूसरे कर्जोंके मुकाबिले सबसे पहिले पूर्ण रूपसे चुकाये जावेंगे।

(४) यदि मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करने पर उसके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जानेके पश्चात् आफिशल एसायनीके पास कुछ रकम फाजिल बचे तथा प्रबन्धना खर्च या दिवालियेके सम्बन्धमें इस एन्टमें बतलाया हुआ खर्च भी अदा कर दिया गया हो तो बचत मृतक कर्जदारकी जायदादके कानूनी वारिसको दो जायगी अथवा अन्य किसी निर्धारित ढंग पर उसका प्रयोग किया जावेगा।

व्याख्या—

दफा १०६ के अनुसार दाखलानेके मजूर किये जाने पर अर्थात् मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेकी वारिसाईके अनुसार किये जानेका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदाद आफिशल एसायनीके प्रबन्धमें आजावेगी और वह सब जायदादको मितनी एन्ट हो सकेगा बसूत रहेगा तथा बाद बसूनी कानूनके अनुसार उसी कर्जकारोंमें बांट देगा।

उपदफा (२) के अनुसार इस एन्टके तालीम भरणमें बतलाये हुए नियम जहाँ तक कि उनका तात्त्विक समझा जायेगा इस दफाके अनुसार वारिसाई किये जानेमें लागू होंगे।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि यदि मृतक कर्जदारके किसी वारिसने मृतक संस्कारमें अथवा मृतक कर्जदारकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कानूनी खर्च किया हो तो आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे खर्चोंकी समीक्षा करे और तब उसकी पूर्ण रूपसे मृतककी जायदादसे सबसे पहिले चुका देवे। इस प्रकार इस उप दफाके अनुसार इन वारिसोंके खर्चोंकी रक्षाई गई है जो वारिस होनेके कारण उनकी मृतक कर्जदारके सम्बन्धमें करना पड़े हो।

उपदफा (४) में बतलाया गया है कि यदि मृतककी जायदादसे उसके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जा चुके तथा फिर भी इस एन्टमें बतलाया गया है चुकाया जा चुका हो और प्रबन्धके लिये किये हुए खर्च भी अदा किये जा चुके हों और इसके बाद कोई जायदाद या रकम बचे तो वह मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसोंको दिया जावेगा या किसी अन्य निर्धारित किये हुए ढंग पर लगाया जावेगा। जायदादका प्रबन्ध आफिशल एसायनी इस दफाके अनुसार उसी प्रकार कर सकेगा जिस प्रकार कि किसी व्यक्ति के दिवालिया करार किये जाने पर उसकी जायदादका प्रबन्ध वह इस एन्टके अनुसार कर सकेगा।

दफा ११० कानूनी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना

(१) दफा १०८ के अनुसार दी हुई दखलास्तके दिये जानेकी सूचना होनेके पश्चात् कानूनी वारिसने यदि कोई अदायगीकी हो या उसने कोई इन्तकाल जायदाद किया हो तो उससे यह कोई छुटकारा नहीं पावेगा जहाँ तक उसका वह आफिशल एसायनीका एक दूसरेसे सम्बन्ध है।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातको छोड़ कर दफा १०८ दफा १०६ या इस दफाकी कोई बात कानूनी वारिस द्वारा नेकनीयतासे किया हुआ कोई काम कोई बात अथवा कोई अदायगी रह नहीं करेगी यदि यह काम प्रबन्धका हुक्म होने से पहिले किया गया हो इसी प्रकार यदि डिस्ट्रिक्ट जज ने दि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एन्टकी दफा ६४ के अनुसार दिये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए कोई अदायगी का काम या बातकी हो तो वह भी रह नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार यदि मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबंधके लिये दफा १०८ के मुअफिक दख्खास्त दीगइ हो और ऐसी दख्खास्तकी सूचना हो जानेके पश्चात् उस कर्जदारका कानूनी वारिस कोई अदायगी करे या कोई इन्तज्जुअ जायदाद करे तो उससे वह आकिसल एसायनके विरुद्ध लाम नहीं उठा सकता है अर्थात् ऐसी अदायगोमे उसे दृष्टकारा नहीं मिलेगा ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि प्रबन्धका दृष्य होनेमे पहिले यदि नेन्नीयतामे मृतक कर्जदारके वारिस ने कोई अदायगीकी हो या अन्य कोई काम किया हो तो वह अदायगी या काम ठीक समझा जावेगा और इस दफाके अन्सार अथवा दफा १०८ व १०९ के अनुसार वह रद्द नहीं हो सकेगा । इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि डिस्ट्रिक्ट जजने अपने कानूनी अधिकारोंको बतते हुए कोई अन्वयगीकी हो या काम किया हो तो वह भी रद्द नहीं समझा जावेगा किन्तु वह ठीक माना जावेगा । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहींकी जावेगी किन्तु उसको पाबन्दी आवश्यक है । एडमिनिस्ट्रेटर जनरलस एक्ट १८७४ जिसका थिक उपदफा (२) में है रद्द किया जा चुका है और उससे स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरलस एक्ट ३ सन् १९१३ चाड़ है ।

दफा १११ एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा

यदि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलको किसी मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके लिये किसी मामलेमें प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया हो तो उस मामलेमें दफा १०८, १०९ व ११० के नियम लागू नहीं होंगे ।

व्याख्या—

इस दफाके अन्सार मृतककी जायदादका प्रबंध एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके हाथ आने पर उस जायदादका प्रबंध दिया-लियेकी कार्रवाईके अनुसार नहीं किया जावेगा पल्लु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलने उस जायदादका प्रबंध प्रोबेट (Probate) अथवा लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के सिन्सिडेमें मिला हो । इस दफासे यह भी प्रकट है कि जब जायदादका प्रबंध प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशनके आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल द्वारा किया जा रहा हो तो दफा १०८, १०९ व ११० के कोई नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् कानूनी वारिस द्वारा की हुई अदायगी या इन्तज्जुअ आदिवा रद्द होना या उनका ठीक माना जाना इस दफाओंमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार नहीं समझा जावेगा अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है ।

(के) दिवालय तथा उनकी जायदादके सम्बन्धमें दी हुई दरखास्तों तथा उनके मामलों क सुने जानेमें आफिशल पसायनी द्वारा हस्तक्षेप किया जाना ।

(पल) बिला बहाल हुए दिवालियेके हिसाबकी किताबों व कामगजातकी आफिशल पसायना द्वारा जांच की जाना ।

(एम) इस एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाईयोंमें नोटिसकी तामील

(एन) जांच कमेटीकी नियुक्ति उनकी मीटिंग तथा उनके कार्य करनेका तरीका

(थो) इस एक्टके अनुसार किसी फर्मके मामले कार्रवाईका किया जाना

(पी) इस एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाईयोंमें जो फार्म प्रयोग किया जाना चाहिये ।

(एम्) जो जायदाद सरसरी तौर पर देखी जाना चाहिये उनके प्रबन्धमें किस प्रकार कार्रवाई करना चाहिये ।

(आर) भरे हुए कर्जदारों की जायदादका प्रबन्ध जो इस एक्टके अनुसार किया जावेगा किस प्रकार किया जाना चाहिये ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार इस एक्टके कामोंके कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये अदालतें समय समय पर नियम (रूल) बना सकती हैं ।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अनुसार बनाये जाने योग्य रूलसका वर्णन किया गया है । इस उपदफामें यह नहीं बताया गया है कि कौन २ से रूलस होंगे किन्तु यह बतलाया गया है कि किन किन मामोंके सम्बन्धमें ऐसे रूलस बनाये जाना चाहिये यह उपदफा १८ डायमें विभक्त है तथा उन सब बातोंका उल्लेख इन डायमें कर दिया गया है गिनके सम्बन्धमें कुछ नियमोंके बनाए जानेकी आवश्यकता है जैसे कि कर्जदारोंकी मीटिंग किस प्रकार होना चाहिये, नोटिस किस प्रकार जाना चाहिये, उसकी जांच किस प्रकार होना चाहिये, आफिशल पसायनी को क्या अपकल मिलना चाहिये इत्यादि के बारे में ।

दफा ११३ रूलसके लिये स्वीकृति मिलना

इस भागके नियमोंके अनुसार बनाये हुए रूलसके लिये स्वीकृति, कलकत्ता हाईकोर्टके लिये सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दुसे हासिलकी जाना चाहिये तथा अन्य अदालतोंके लिये उनकी प्रान्तिक सरकारसे हासिल की जावेगी ।

व्याख्या—

कमेटी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये । सिवाय कलकत्ता हाईकोर्टके अन्य अदालतों द्वारा बनाये हुए रूलसके अन्य स्वीकृति प्रान्तिक सरकारों द्वारा ली जावेगी । कलकत्ता हाईकोर्टके रूलसके लिये स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा दी जाना चाहिये । ऐसी स्वीकृति मिलनेके पश्चात् वह रूलस कार्यरूपमें परिणत नियम जासकेग अन्यथा वह अपूर्ण समझे जावेगे ।

दफा ११४ रूलसका प्रकाशित किया जाना

इस प्रकार बनाये हुए तथा स्वीकृति प्राप्त किये रूलस गज़ट आफ़ इण्डिया या प्रान्तिक

सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जावेंगे जैसा कि मामला होवे और इससे बाद उस अदालतमें जिसने द्वारा वह बनाये गये हैं इस एक्टकी कार्रवाईके लिये वही असर रखेंगे जैसे कि मानो वह इस एक्टके साथ बनाये गये हों ।

व्याख्या—

अपेक्षी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग है निम्ने यह प्रकट है कि कम्पक सराफा एक्टमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक है । कलकत्ता हाईकोर्टके कम्प गजट भाग इण्डियामें प्रकाशित किए जावेंगे तथा अन्य अदालतोंके कम्प प्रान्ति क सराफा गजटमें प्रकाशित किये जावेंगे और प्रकाशित इनके पक्षपर यह कम्प जिते बरकरार द्वाग बनाये गये होंगे उनमें किये वही प्रकार प्रयोग किये जावेंगे निम्न प्रकार इस एक्टके नियम किये वने वने एक प्रकारसे इस एक्टके साथ बनाया हुआ कानून मान किया जावेगा ।

वारहवां प्रकरण



दफा ११५ इस एक्टके अनुसार किये हुए इन्तकाल आदिका स्टाम्प या करसे बरी होना

(१) अदालतके सामने तथा अदालतके हुक्मके अनुसार किये हुए हर एक इन्तकाल जायदाद, रहन सामा, जायदादका किसीके नाम किया जाना मुस्ताफानामा, सादीका कागज (Proxy Paper), सर्टीफिकेट, हलफनामा दस्तावेज या दूसरी कार्रवाई दस्तावेज या दख्खिर या इनकी कोई नकलमें स्टाम्प या दूसरे किसी प्रकारका कर नहीं लगता ।

(२) इस एक्टके अनुसार आधिकार एसायनी द्वाग ही हुई बरकरारमें कोई स्टाम्प ड्यूटी या दूसरी कीस नहीं ली जावेगी या अदालत द्वारा ऐसी दस्तावेज पर दिये हुए कि " आदिक किये जाने या जारी करने पर भी स्टाम्प, ड्यूटी या कोई फीस नहीं ली जावेगी ।

व्याख्या—

आधिकार एसायनी की तरफसे काय बनवाने द्वागकी भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी या आधिकार एसायनी दस्तावेजमें इस दफाके अनुसार प्राप्त है । इस कारण यह जगह दिवायिक अधिकारका प्रयोग किये हुए किसी आदिक होना उसकी नकलमें किये कोई स्टाम्प नहीं देना पड़ेगा, दफा ११३ Mad ७४७.

उपदफा (१) के अनुसार दिवायिकी कार्रवाईके समयमें अदालतके हुक्म द्वारा किये हुए इन्तकाल जायदाद आदि दस्तावेजों पर स्टाम्प नहीं लगवा जावेगा । इसी प्रकार इन दस्तावेजोंकी नकलमें या कोई स्टाम्प प्राप्त नहीं होगा ।

उपदफा (२) के अनुसार आधिकार एसायनी दस्तावेजों पर दस्तावेजों तथा उनके अनुसार दिये गये बाटे हुक्म स्टाम्प या फीस नहीं लगेगी ।

दफा ११६ गज़ट, शहादत होगा

(१) वह सरकारी गज़ट जिसमें इस एक्टके अनुसार दिया जाने वाला नोटिस प्रकाशित हुआ हो नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका शहादत होगा ।

(२) वह सरकारी गज़ट जिसमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन किया गया हो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके लिये तथा उसकी तारीखके लिये पूरी शहादत माना जावेगा ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किो हुए (Shall) शब्दसे प्रारंभ है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये तथा उनकी पाबंदी की जवगी । यदि नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका सुन्दर देना हो तो उपदफा (१) के अनुसार वह सरकारी गज़ट जिसमें नोटिस प्रकाशित किया गया हो काफी शहादत माना जावेगा ।

उपदफा (२) के अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म देने में बाने तथा उसके दिये जानेकी तारीख उस सरकारी गज़टके अनुसार मानी जावेगा जिसमें दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म प्रकाशित किया गया हो । इस प्रकार इस दफामें अदालतक अगली दृष्टिके पेश करने अथवा किसी नोटिसमें दी हुई बातोंके साबित करनेके लिये सिविल व डिजिटने वाले को तत्त्व परानेकी आवश्यकता नहीं है किंतु सरकारी गज़ट सुद्धमें पेश किया जायकता है ।

दफा ११७ हलफनामेकी तस्दीक

निम्न प्रकारसे तस्दीक किये हुये हलफनामे इस एक्टके अनुसार अधिकारोंको धर्तने वाली अदालतोंमें प्रयोग किये जासकते हैं :—

(ए) ब्रिटिश इण्डियामें

(१) किसी भी अदालत या मजिस्ट्रेट, या

(११) जायता दीवानी सन् १६०८ ई० के अनुसार हलफ देनेका अधिकार पाया हुआ कोई अफसर या दूसरा व्यक्ति द्वारा तस्दीक किये हुए ।

(बी) इंग्लैंडमें किसी भी ऐसे व्यक्तिके सामने जिस शाहंशाहके हाईकोर्टमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो, या लॉकास्टर की काउण्टी पैलेटाइनके चान्सेरी अदालतमें, या किसी बैरन्फी अदालतके सामने, या बक्रप्सी कोर्टके किसी अधिकार प्राप्त अफसरके सामने जिसे लिखकर उस अदालतके किसी जजने इसके लिये अधिाार दिया हो या किसी ऐसे काउण्टी अथवा जगहके जस्टिस अफ दि पीसके सामने जहा कि वह हलफनामा तस्दीक किया गया हो ।

(सी) स्काटलैण्ड व आयरलैण्डमें किसी आरटिंगरी जज मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ दि पीसके सामने, और

(डी) किसी दूसरी जगहमें किसी मजिस्ट्रेट जस्टिस आफ दि पीस या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिके सामने जिस उक्त स्थानमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो (ऐसे व्यक्ति

लिये किसी ब्रिटिश मिनिस्टर या ब्रिटिश कौन्सल या ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट या नोटैरी पब्लिकको इस बातका सर्टीफिकेट देना चाहिये कि वह मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दी पीस या उक्त प्रकारसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति है ।

व्याख्या—

इस दफामें इल्फनामोंके तस्दीक किये जानेकी व्यवस्था नती गई है । हर जगह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबंदी कले हुए इल्फनामोंके तस्दीक किये जासकते हैं । ब्रिटिश भात इन्फैण्ड, स्टाट्यूट न व्यापलैण्डके लिये अदालत या अन्य व्यक्तिके नाम बतला दिये गये हैं जो इल्फनामा तस्दीक कर सकते हों । इनके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति या अदालतें इल्फनामा तस्दीक कर सकती हैं पन्तु ऐसे व्यक्ति या अदालतोंकी तस्दीक ऊपर उपद्रका (४) के अन्तमें बतलाये हुए ब्रिटिश आकितों द्वारा ही जाना चाहिये ।

दफा ११८ व्यवहारिक गलतीके कारण कार्रवाईयां रह नहीं होनी चाहिये

(१) दिवालियेके सम्बन्धमेंकी हुई कोई कार्रवाई किसी व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवीके कारण उस वक्त तक रह नहीं होनी जब तक कि वह अदालत जिसके सामने किसी कार्यवाईके लिये एतराज किया गया हो यह राय न कायम करे कि उस व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवीके कारण बड़ी बेइन्साफी हो गई है और वह बेइन्साफी अदालतके किसी हुक्म द्वारा नहीं सुधारा जासकती है

(२) आफिशल एसायनी या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें यदि कोई गलती या वेतर्तीवी हुई हो तो किसी ऐसी गलतीसे उसके द्वारा नेक्नीयसीसे किया हुआ कोई काम रह नहीं होगा ।

व्याख्या—

यदि कोई व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवी हो जावे जेमे कि लिखने आदिमें कुछ रह जावे परंतु उसमें कोई बिशेष बेइन्साफी न होती हो अथवा जो बेइ साफी होती हो वह अदालत अपने हुक्म द्वारा ठीक कर सकती हो तो ऐसी गलती या वेतर्तीवीके कारण अदालतकी कार्रवाई उपद्रका (१) के अनुसार रह नहीं होगी । ऐसा कार्रवाई उसी समय रह होगी जब कि एतराज सुनने वाली अदालतकी रायमें उक्त गलती या वेतर्तीवीसे बड़ी बेइ साफी हुई हो या वह बेइ साफी किसी दूसरे हुक्म से न सुधारा जासकती हो ।

उपद्रका (२) के अनुसार यदि आफिशल एसायनीकी नियुक्ति या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें कोई गलती या वेतर्तीवी हुई हो और इस प्रकार नियुक्ति किये हुए व्यक्तने नेक्नीयसीसे कोई काम किये हों तो उसके द्वारा किये हुए काम रह नहीं होंगे अर्थात् ठीक समेत जावेंगे । अमेनी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है कि इस दफा के नियमकी पाबंदीकी जावेगी तथा उसकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ११९ ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे एक्टका लागू होना

यदि इण्डियन ट्रस्टीज़ एक्ट १८८६ के अनुसार कोई ट्रस्टी होवे और वह दिवालिया कारार दिया जावे तो उस एक्टकी दफा ३५ लागू होगी जिससे आवश्यकता प्रतीत होने पर उस दिवालिये के स्थान पर नया ट्रस्टी नियुक्त किये जानेका अधिकार दिया जासकता है (चाहे वह दिवालिया स्वयं इस्तीफा देवे या न देवे) और उस एक्टके तथा उस एक्टसे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे एक्ट के सब नियम इसके पश्चात् लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफ्तरमें इंग्लिश ट्रस्टीज एक्ट १८६६ के अनुसार ट्रस्टी होने वाला यदि कोई व्यक्ति दिवालिया कारा दिया जावे तो ट्रस्टीज एक्ट की दफा ३५ का लागू होना मतलब गंगा है अर्थात् उसका स्थान पर दूसरे ट्रस्टीकी नियुक्त होना चाहे ट्रस्टीज एक्ट (Trustees Act 1866) की दफा ३५ इस प्रकार है :—

“ उन सब मामलोंमें जिनमें नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंमें नियुक्त किया जाना आवश्यक हो और ऐसा करना निम्न हाई-कोर्टकी मददके उचित न माना जाता हो अथवा कठिन हो या किया ही न जा सकता हो तो अदालत कानूनन नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंको नियुक्त कर सकती है चाहे ऐसा हुक्म दिये जाने समय कोई ट्रस्टी होवे या न होवे और यदि कोई ट्रस्टी होवे तो नये ट्रस्टी उनके स्थान पर अथवा उनके अतिरिक्त बनाने जा सकते हैं। ऐसे हुक्मके अनुसार होने वाले ट्रस्टी या ट्रस्टियोंकी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उनको रिक्त बाकायदे दायर किये हुए मामलोंमें डिकी होने पर प्राप्त हो सकते थे” । इस दफ्तरमें यह प्रष्ट है कि किसी ट्रस्टीके दिवालिया करार दिये जाने पर उसके स्थानमें दूसरा व्यक्ति कानूनन नियुक्त किया जा सकता है ।

दफा १२० सरकारको पाबंद करने वाले कुछ नियम

केवल उन बातोंको छोड़ कर जो बतलाई गई हैं इस एक्टके नियम जो किसी दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कार्रवाईके सम्बन्धमें होंगे, कर्जोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना, तरफिया या तय होनेकी स्वीमका प्रभाव और बहाल होनेका प्रभाव इन सब बातोंकी पाबन्दी सरकार पर होगी ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए शब्द (Shall) का अर्थ प्रष्ट है कि इस एक्टके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जायेगी तथा बहाल होनेका प्रभाव आदि अन्य दिसलाई हुई बातोंकी पाबन्दी सरकार पर भी होगी ।

दफा १२१ मुलाकातके अधिकारोंकी बचत

इस एक्टकी कोई बात या इसके अनुसार किये हुए अधिकार परिवर्तनके होने पर कोई बात किसी व्यक्तिके मुलाकातके अधिकारोंको जो उसे इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले प्राप्त हों नहीं लागू होगी या यदि दिवालिये कर्जदारोंके हुदकारोंके लिये दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त न रहा हो तो वह अधिकार वहीं दिया जावेगा ।

दफा १२२ उन हिस्सा रसदीका, जिनका कोई दावेदार न होवे सरकारको मिलना

यदि आफिशल प्रसायनीके हाथमें कोई ऐसा हिस्सा रखदी होवे जो प्लानसे १५ साल तक या इससे कम नियत किये हुए किसी समय तक न लिया गया हो तो वह उस स्थानकी गवर्नमेंट आफ़ प्रोपर्टीके हिस्सावमें उसके नाम जमा कर देवेगा अगर इसके विरुद्ध अदालत कोई दूसरा हुक्म न देवे ।

व्याख्या—

हिस्सा रसदीका मर्यादा ऐलानके बाद १५ सालके अंदर अथवा अन्य निर्धारितमें हुई मर्यादके अन्दर न लिया जाने पर इस दफ्तरके अनुसार सरकारी हो जावेगा परन्तु अदालतकी अधिमता है कि वह इसके विरुद्ध भी कोई आज्ञा दे देवे व ऐसे हुक्मके होने पर वह स्थान मर्यादा सरकारी हो जावेगा जानेके उस हुक्मके अनुसार लपटा जावेगा ।

दफा १२३ दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दावे

यदि दफा १२२ के अनुसार कोई रुपया भारत सरकारके हिसाबमें दे दिया गया हो और कोई व्यक्ति उस रुपये पानेका अधिकारी अपनेको यत्नावे तो वह उस रुपयेके मिलनेके लिये अदालतमें दरखास्त दे सकता है और अदालत जब कि उसे विश्वास हो जाये कि दावा करने वालेका हक उन रुपये पर पहुँचता है उस रुपयेके दिये जानेका हुक्म देवेगी परन्तु शर्त यह है कि भारत सरकारमें आम किये हुए रुपयेके दिये जानेका हुक्म देने से पहिले अदालत गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा इसी लिये नियुक्त किये अफसर पर इस बातका नोटिस तामील करेगी कि वह अफसर एक महीनेके अन्दर वजह जाहिर करे कि रुपयेके दिये जानेका क्यों न हुक्म दिया जाये ।

व्याख्या—

यदि कोई दफा न लिये जानेके कारण भारत सरकारसे दफा १२२ के अन्सार पर मिल गये हों और इसके बाद उन रुपयोंका दावीदार खरा हो तो वह अदालतमें दरखास्त देकर तथा अदालतसे जाने हुकूम यत्नाव दिलाकर उस रुपयेके वापिस पानेका हुक्म अदालतसे ले सकता है परन्तु अदालत कत्तय होगी कि वह ऐसा अज्ञानसे पाविल भात सरकार द्वारा नियत किये हुए अफसरको रुपये पानेकी दरखास्तके विरोध करनेवा अवसर देवे तथा नागितकी तामील पर १ माहका मोका दिय जानेक बाद रुपये वापिसका हुक्म देवेगी रुपये वापिसका हुक्म देनेके लिये अदालत हर हालतमें बाध्य नहीं है किन्तु हुकूम यत्नाव होने पर रुपये वापिसका वह हुक्म देवेगी ।

दफा १२४ दिवालियेकी किताबोंका मुआयना व क़ब्ज़ा

(१) आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी व्यक्तिको दिवालियेकी किताबोंको रोकनेका अधिकार नहीं होगा और न उन पर उनका कोई वार ही होगा ।

(२) दिवालियेका कोई भी कर्जदारवाह अदालतकी आज्ञाके अनुसार तथा इस सम्बन्धमें निर्धारितकी हुई फीसके अक्षर करने पर स्वयं या अपने एजेंटके जरिये उचित समयों पर आफिशल एसायनीके कर्जमें होने वाली ऐसी किताबोंका मुआयना कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफासे यह प्रकट है कि दिवालियेके हिमायती किताब पर सबसे पहिले आफिशल एसायनीका हक होगा और वही दूसरी पक्षावत उन किताब पर कब्ज़ा पानेवा हुकूमदार होगा । अपनी एकधम (Shall) शब्दके प्रयोग से पाने से यह समझना चाहिये कि इस आदमाक नियमना ज़रूरतना नहीं की गयीगी ।

उपदफा (२) के अनुसार वजहवाहोंको दिवालियेके हिमायती किताबना जो आफिशल एसायनीके कर्जमें होने फीस देने पर मुआयना करनेवा अधिकार प्राप्त है परन्तु अदालत इस सम्बन्धमें इसका कर सकता है ।

दफा १२५ फीस व..... फी सैकड़ा

वह फीस व..... फी सैकड़ा इन एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें लिया जावेगा जो निर्धारित किया गया हो ।

दफा १२६ अदालतें एक दूसरेकी सहायक होंगी

इस एक्टके अनुसार अधिकार रखने वाली सब अदालतें ऐसे हुकम देंगी व ऐसे काम करेंगी जिससे बैंकप्टसी एक्ट १८८३ (विक्टोरिया चैप्टर ४६ व ४७) की दफा ११८ तथा प्रांतिन कानून दिवालिया १६०७ (एक्ट ३ सन् १६०७ ई०) की दफा ५० कार्य रूपमें परिणित की जा सकें ।

व्याख्या—

सन् १९०७ ई० का प्रांतिन कानून दिवालिया (एक्ट ३ सन् १९०७ ई०) बदल गया है अब उसके स्थानमें सन् १९२० ई० का प्रांतिन कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन् १९२० ई०) प्रचलित है । पिछले एक्टकी दफा ५० जिसका हवाला इस दफामें है उसे एक्टकी दफा ७७ के रूपमें बदल दिया गई है व वह इस प्रकार है—“ वह सब जदालतें जिन्हें दिवालियेक मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाजिर एक दूसरेकी दिवालिने मामलोंमें मदद देने और अगर कोई जदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुकम देगी तो उस दूसरी अदालतमें उस मदद चाहने वाले मामलेके लिये जिसका शिक हुकममें होगा वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंकी हो सकते हैं । ” बैंकप्टसी एक्टकी दफा ११८ जिसका शिक इस दफामें है वह भी इसी आधार की है अब पुनः बैंकप्टसी इस एक्टके स्थानमें बैंकप्टसी एक्ट १९१४ (Bankruptcy Act 1914) प्रचलित है और नये एक्टकी दफा १०९ में वह बतें दी गई हैं जो पिछले एक्टकी दफा ११८ में थीं । इस दफाके पांच दायी भी आवश्यकता है जिसका कि अमेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है ।

दफा १२७ कानूनोंकी मंजूरी

(१) तीसरे सिद्ध्युक्तमें दिखलाये हुए कानून उस हद तक मंजूर किये जाते हैं जिस हद तक उसके चौथे कालमें दिखलाये गये हैं ।

(२) इस एक्टके अनुसार की हुई मंजूरीके होते हुए भी दिवालियेकी उन दफावास्तों की कार्यवाहियां जो इण्डियन इन्साल्वेंसी एक्ट १८८८ (विक्टोरिया चैप्टर २१ के ११ व १२) के अनुसार इस एक्टके प्रारम्भ होते समय चल रही हों जारी रहेंगी अगर इस एक्टका कोई नियम साफ तौर पर चालू कार्यवाहियोंके लिये न दिया गया हो । और उस हुकमके सब नियम ऊपर बतलाई हुई बातोंकी छोड़कर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह पास हो न हुआ हो ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि तीसरे सिद्ध्युक्तमें दिखलाये हुए एक्ट मंजूर किये गये हैं तथा उनकी मंजूरी उस हद तक समझना चाहिये जिस हद तक कि उस तीसरे सिद्ध्युक्तके चौथे वाक्य (खानि) में दिखलाया गया है ।

उपदफा (२) के अनुसार पिछले कानून दिवालियाके अनुसार होने वाली कार्यवाहियां बदलती नहीं रहेंगी परन्तु यदि इस एक्टमें खास तौरसे दे दिया हो कि किसी विशेषकी कार्यवाही मंजूर हमसी जायगी वा वह दूसरे दफासे की जायगी तो इस प्रकार बतलाये हुए नियमकी पालनीकी जायगी । अर्थात् यदि कोई खास बात इस एक्टमें न दी जावे तो पिछले एक्टके अनुसार होने वाली कार्यवाही उसी प्रकार होती रहेंगी तथा उसी एक्टके नियम भी लागू होंगे इस एक्टमें उस कार्यवाहीमें कोई रूकावट नहीं पड़ेगी ।

पहिली सूची

(The First Schedule.)

कर्मचारीकी मीटिंग

१ कर्मचारीकी मीटिंग

आफिसल एसायनी जब चाहे कर्मचारीकी मीटिंग कर सकता है और वह कर्मचारीकी मीटिंग उस वक्त तैयार करेगा जब कि ऐसा करनेके लिये अदालत कहे या कर्मचारीगानने ऐसा करनेके लिये किसी मीटिंगमें प्रस्ताव पास किया हो या जब कि कर्त्ता साबित कर चुकने बाद कर्मचारीगानसे इतने कर्मचारी किछ कर मीटिंग करनेके लिये कहें जिनके कुल कुलके एक चौथाई कीमतके बराबर होने होवें ।

व्याख्या—

तीन दशाओंमें आफिशल एसायनी कर्मचारीकी मीटिंग करनेके लिये बाध्य है— (१) यह कि जब अदालत मीटिंग करनेका हुक्म देवे, (२) यह कि जब किसी मीटिंगमें कर्मचारीगानने मीटिंग किये जानेके लिये दोर प्रस्ताव पास किया हो (३) यह कि जब एक चौथाई कीमत वाले कर्मचारीगानने जिनके कर्त्ते साबित हुये हो लिख कर किसी मीटिंगके करनेकी प्रार्थना करें । इसके अलावा आफिशल एसायनी जब चाहे कर्मचारीकी मीटिंग आवश्यकता समझने पर कर सकता है ।

२ मीटिंगका बुलाया जा ना

मीटिंग किये जानेके समय तथा स्थानकी सूचना सब कर्मचारीके पास भेजी जावेगी, कर्त्ता साबित कर चुकने बाद कर्मचारीगानके पास यह सूचना उस पतेसे भेजी जावेगी जो उन्होंने कर्त्ता साबित करनेमें बतलाया हो दूसरे कर्मचारीगानके उस पतेसे भेजी जावेगी जो दिखालियेने कर्मचारीगानकी सूचनामें दिखलाया हो या किसी दूसरे पतेसे जो आफिशल एसायनीको मालूम हो ।

व्याख्या—

मीटिंगकी सूचना सब कर्मचारीगानके पास भेजी जावेगी चाहे उन्होंने बर्जे साबित किया हो या न साबित किया हो । सूचनामें मीटिंगकी जगह तथा उसके किये जानेका समय बतलाया जावेगा । सूचना उस पतेसे दी जावेगी जो कर्त्ता साबित करने में कर्मचारीगानने अपना र पता बतलाया हो परन्तु जिन्होंने कर्त्ता साबित हा न किया हो उसको उस पतेसे भेजा जावेगा जो दिखालियेने अपनी किहरियेने दिखलाया हो अथवा जो आफिशल एसायनीको अन्य किसी प्रकारसे मालूम हो सके ।

३ मीटिंगके नोटिस

मीटिंगके लिये नियत किये हुए दिनों, कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस भेजे जावेंगे और वह या तो स्वयं कर्मचारीगानके दिये जासकते हैं या स्टाम्न लगाने हुए छुट्टीसे भेजे जासकते हैं जैसेमें सुभीता होवे । आफिशल एसायनीको यदि शकित प्रतीत होवे तो वह स्थानीय अखबार अथवा शान्तिक आफिशल मजदूरों मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना प्रकाशित कर सकता है ।

व्याख्या—

मीटिंगके होनेसे कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस जारी करनेकी आवश्यकता है नोटिस जारी तौर पर दिये जा

सत्रों हैं अथवा टिकट लगाकर खतके द्वारा पर भेजे जासकते हैं अर्थात् वेग नहीं भेज जाना चाहिये। आनिशुल एसायनारी इन्ज पर निर्भर है कि वह यदि सुनासिव समझ तो मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना स्थानाय अत्रवारमें अथवा प्रातिक सरकारी गजटमें प्रकाशित कर देवे। ऐसा उसी समय आवश्यक हो सकता है जब कि बहुतसे कर्मचारी हों या अधिकतर कर्मचारी एकही स्थानों हों अथवा एक ही प्रांतके हों अथवा आफिशुल एसायनारीको अन्य किसी पर्याप्त कारणसे ऐसा करना उचित प्रतीत हो।

४ यदि आवश्यकता हो तो दिवालियेके हाजिर होनेका कर्तव्य

यदि आफिशुल एसायनारी किसी मीटिंगमें हाजिर होनेकी सूचना दिवालियेको देवे तो उसका कर्तव्य होगा कि वह इन मीटिंगमें अथवा यदि वह किसी कारीखके लिये बका बर्गई हो तो उस बर्गई हुई तारीख पर हाजिर होवे। इस प्रकारका नोटिस या तो स्वयं उसे ही दिया जावेगा या मीटिंगसे कमसे कम तीन दिन पहिले डाकके जरिये उसके पतेसे भेजा जावेगा।

व्याख्या—

दिवालियेको मीटिंगमें हाजिर होनेका नोटिस जारी होने का तारीखसे कमसे कम तीन दिन पहिले दिया जाना चाहिये। नोटिसकी जारी तारीख कीमतसक्ती है अथवा वह डारुने जरिये उसके पतेसे भेजा जासकता है पुछाय जाने पर मीटिंगमें इन दिन तथा बर्गई हुई तारीख पर हाजिर होना दिवालियेका कर्तव्य है।

५ नोटिस न पहुंचने पर मीटिंगकी कार्रवाईका रद्द न होना

यदि किसी कर्मचारीका भेजा हुआ नोटिस उसको न भी मिला हो तो किसी मीटिंगमेंकी हुई कार्रवाईका व उसमें पास किये हुए प्रस्ताव ठीक माने जावगे जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी कर्मचारीको नोटिस भेजा गया हो परन्तु उसे न मिला हो और मीटिंग होकर कोई प्रस्ताव आदि पास किय गये हों तो नोटिसकी तारीखी हुए बिना मीटिंगकी कार्रवाईका किया जाना रद्द नहीं समझा जावेगा परन्तु यदि अदालत चाहे तो ऐसे मीटिंगकी कार्रवाई या उसमें पास किये हुए प्रस्तावका रद्द कर सकता है।

६ नोटिसके जारी होनेका सुबूत

यदि आफिशुल एसायनारी इस बातका सर्टीफिकेट दे देवे कि किसी मीटिंगका नोटिस बाकायदा दिया गया है तो यह काफ़ी शहादत इस बातकी होगी कि नोटिस जिसके पतेसे भेजा गया है उसका ठीक तौर से भेजा गया है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशुल एसायनारी जिस पतेसे नोटिस भेजा होगा उस पतेसे उसका भेजा जाना पुरास माना जावेगा अर्थात् नोटिसके बाकायदा भेजे जानका बात आफिशुल एसायनारीके तस्दीक करने पर ठीक माना जावेगी और वह तबतक शहादत इस्तेमाल हो जासकेगी।

७ मीटिंगका खत

जब कि कर्मचारीकी प्रार्थना पर आफिशुल एसायनारी कोई मीटिंग करे तो तद्विषयी प्रार्थनाके साथ हर चीस कर्मचारीको हिसाबसे पांच रुपये मीटिंग किये जानेके खर्चेके तौर पर जमा किये जावंग जिसमें सब खर्चे शामिल समझना चाहिये, परन्तु शत यह भी है कि आफिशुल एसायनारी मीटिंगके खर्चेके लिये जो उसकी रायमें सुनासिव मालूम पड़े और भी अधिक रुपया जमा करा लगा।

व्याख्या—

कर्मन्वाह जब मागिंग कराना चाहें तो उनको पांच रुपया की बीस कर्मन्वाहके हिमावसे बतौर खर्चके दस्तावेजों के साथ जमा करना चाहिये। आकिसर एमपनी को पुनर्निष मालूम पड़ने पर और भा अधिक रुपया बतौर खर्चके जमा करना चाहिये।

८ खरमेन

भाषिशल मुसायनी हर मीटिंगका खरमेन (सभापति) होगा।

९ घोट देनेके अधिकार

कोई कर्मन्वाह जब तक कि वह अपना कर्म जो दिवालयकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें आवेष्ट किया जा सकता हो आकायदा संचित न कर देवे मीटिंगमें घोट देनेका अधिकार न होगा और कनका सुवृत्त मीटिंग होनेके लिये नियत किए हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले हो चुकना चाहिये।

व्याख्या—

बर्ता संचित कर चुकने वाले कर्मन्वाह ही घोट दे सकेंगे। इस बातका भी ज्ञान रहना चाहिये कि मीटिंगके लिये नियत शिथे हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले कर्म संचित हो जाना चाहिये अर्थात् जहाँ कर्मन्वाह मागिंग कराने के लिये संचित किया चाहें वह घोट देनेका अधिकार नहीं होगा। जिन कर्मन्वाहोंका कर्म संचित नहीं किया गया है वह घोट नहीं दे सकेंगे।

१० कुल कर्मोंके सम्बन्धमें घोट नहीं दिया जासकेगे

किसी मीटिंगमें कोई ऐसा कर्मन्वाह योग नहीं दे सकता जिसका कर्म निश्चित भवराशिसे रुपय न होवे या जिसका कर्म किसी बातके होन पर निर्भर होवे अथवा कोई ऐसा कर्म होवे जिसकी कीमत तय न हुई हो।

११ महफूज कर्मन्वाह

यदि किसी महफूज कर्मन्वाहने अपनी जमानत में छोड़ दी हो और वह घोट देना चाहे तो वह अपने सुवृत्तमें अपनी जमानतकी तफसील बतलावना वह तरीका ज्ञात कि जमानतकी राह है और इसकी अदावा लगाई हुई कीमत और वह अदावा लगाई हुई कीमत कर्मोंके घटानेका वाद जा कर्म संचित उपाय करिये वाद दे सकता। यदि वह अपने पूरे कर्मोंके सम्बन्धमें घोट देवे तो यह मान लिया जावगा कि उसका जमानत छोड़ दी है जब तक कि अदालतको इसके दस्तावेज देने पर यह पक्की न हो जावे कि वह गलती से अपने जमानतकी कीमत नहीं दिखला सका है।

व्याख्या—

महफूज कर्मन्वाह अपने पूरे कर्मोंके सम्बन्धमें जमानत छोड़ देने पर घोट दे सकता है तथा वह जमानतका कामदे अर्थात् कर्मों से पगवर बाकी कर्मोंके लिये योग दे सकता है।

१२ उन दस्तावेजोंका सुवृत्त जो कायिल वय व तवादलेके होवें

यदि कोई कर्मन्वाह किसी बिल आक एक्चेंज (Bill of Exchange) प्रोमिसरी नोट (Promissory Note) या अन्य किसी दूसरी दस्तावेजकी जो बयनामा, हवालगी या किसी इश्तारते बनी जा सकती हो (Negotiable Instrument) या किसी जमानतका जिसके लिये दिवालिया पाबन्द हो संचित किया चाह तो वह बिल आक एक्चेंज प्रोमिसरी नोट, निगाशियोरल इन्स्ट्रुमेंट या जमानत आकिसल दस्तावेजोंके सामन परा भी जाना चाहिये याइल इसके कि उसका सुवृत्त घाटक लिये माना जावे परन्तु अदालत इसके विरुद्ध कोई विशेष हुक्म भी दे सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार जिन दस्तावेजोंका कर्ज बतलाया जाता हो वह आफिशल एसायनीके सामने पेश की जाना चाहिये और उसके पेश होनेके बाद कर्जका सुधूत बोट देनेके लिये पर्याप्त माना जावेगा। अदालतकी अधिकार हैं कि वह इसके विरुद्ध कोई विशेष आज्ञा दे देवे और ऐसा होने पर अदालतकी आज्ञाके अनुसार किया जावेगा।

१३ कर्जस्वाहसे जमानत छोड़ देनेके लिये कहनेका अधिकार

यदि किसी महफूज कर्जस्वाहने अपनी जमानतकी कीमतका अन्दाजा देनेके बाद किसी मीटिंगमें बोट देने के अधिकारका प्रयोग किया हो तो आफिशल एसायनीकी अधिकार होगा कि वह उस सुधूतमें २४ अट्टाईस दिनोंके अन्दर उस महफूज कर्जस्वाहसे अन्दाजा लगाई हुई कीमत लेकर सब कर्जस्वाहोंके लामार्थ जमानत छोड़ देनेको कहे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी महफूज कर्जस्वाह द्वारा जमानता लगाई हुई कीमतको अदा करने पर उसके उसकी जमानतको अब सब कर्जस्वाहोंके लामार्थ ले सकता है परन्तु ऐसा २४ दिनोंके अन्दर ही किया जाना चाहिये। इस दफाका तात्पर्य यह है कि यदि कोई महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानतकी कीमत कम लगाकर देना फायदा उठाया चाहि यानी अपने बर्किया कर्जेरो और कर्जस्वाहोंके साथ मसूल किया चाहि तो उसके उसके अन्दाजा लगाई हुई कीमत पर उसकी जमानत आफिशल एसायनी द्वारा ली जा सकती है। इस प्रकार जमानत कम कीमतमें ले लिये जानेके बरस कोई महफूज कर्जस्वाह कम कीमत लगाकर देना फायदा उठानेकी हिम्मत नहीं कर सकेगा।

१४ शरीकदारका सुधूत

यदि किसी फर्मका एक शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो उस शरीकदारका कोई कर्जस्वाह जिसका कर्ज उस फर्मके अन्य शरीकदार या शरीकदारोंके साथमें दिवालिये से लेना होवे अपना कर्ज मीटिंगमें बोट देनेके लिये साबित कर सकता है और ऐसा करने पर वह बोट देनेका अधिकारी होगा।

व्याख्या—

फर्मका कर्जस्वाह या एक से अधिक शरीकदारोंका समुक्त कर्जस्वाह अपने कर्जेको उन शरीकदारोंमें से किसी एक के दिवालिया करार दिये जाने पर अपना कर्ज उसके विरुद्ध साबित कर सकता है तथा उसके आधार पर कर्जस्वाहोंकी मीटिंगमें बोट दे सकता है।

१५ आफिशल एसायनीके कर्जा साबित मानने या न माननेके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनीको बोट देनेके सम्बन्धमें दिये हुए सुधूतको मानने या न माननेका अधिकार हासिल होगा परन्तु उसके फैसलकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। यदि आफिशल एसायनीको इस बातका शक होवे कि आया सुधूत माना जाना चाहिये या खारिज कर देना चाहिये तो वह उस सुधूतमें यह लिख देवेगा कि सुधूतमें पुराना है और कर्जस्वाहको बोट देनेका अधिकार प्राप्त हो जावेगा परन्तु तब यह रहेगी कि अगर पुराना कायम बना रहेगा तो उसका बोट ग़ुलब करार दिया जा सकेगा।

व्याख्या—

बोट देनेके सम्बन्धमें सुधूतका मानना या खारिज कर देना आफिशल एसायनी पर निर्भर होगा परन्तु उसके फैसलकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। शक वाले मामलोंमें बोट देनेका अधिकार कर्जस्वाहको इस बात पर प्राप्त रहेगा कि उसके विरुद्ध दिये हुए एतराफके ठीक साबित होने पर उसका बोट रद्द माना जावेगा।

१६ प्रोक्सी

कर्मचारी स्वयं वोट दे सकता है तथा वह किसी क़ायम मुक़ाम (प्रोक्सी) के जरिये भी वोट दे सकता है ।

व्याख्या—

प्रोक्सी तो तत्पर्य उस व्यक्ति से समझना चाहिये जिसे किसीने अपनी तरफ़ से वोट देने का अधिकार दिया हो ।

१७ प्रोक्सी की दस्तावेज़

अपनी तरफ़ से वोट देने का अधिकार (प्रोक्सी) देने वाली दस्तावेज़ निर्धारित क्रिये हुए ढंग (फॉर्म) पर होगी और आफिशल एसायनी द्वारा जारी की जावेगी ।

१८ प्रोक्सी का आम अधिकार (General Proxy)

कर्मचारी को अधिकार है कि वह अपने सुत्तारको, मैनेजरको, क्लर्कको अपना अपनी वाक़ाफ़दा नौक़ारोंमें रखे हुए किसी मुनीम या अन्य व्यक्ति को आम अधिकार वोट देने का (General Proxy) दे देवे । ऐसे मामलमें प्रोक्सी की दस्तावेज़में यह लिखलना आवश्यक होगा कि वोट देने वाले व्यक्ति का कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है ।

व्याख्या—

हम इसके अन्वय कर्मचारी अपने किसी आदमी की आम इज़ाज़त वोट देने का दे सकता है परन्तु ऐसी हालतमें प्रोक्सी के वाक़ाफ़दा यह लिखल जावेगा कि वोट देने वाले का असली कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है ।

१९ मीटिंग की तारीख़ से एक दिन पहिले प्रोक्सी का दाख़िल किया जाना

यदि हम मीटिंग होने से ज़िम्में कि प्रोक्सी इस्तेमाल की जाने को होवे कम से कम एक दिन पहिले प्रोक्सी का काग़ज़ आफिशल एसायनी को न दे दिया जावे तो वह प्रोक्सी इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी ।

व्याख्या—

मीटिंग होने से कम से कम एक दिन पहिले वोट देने का अधिकार देने वाला क़ायम आफिशल एसायनी को दे दिया जाना चाहिये वरना वोट देने का अधिकार उस क़ायम के ज़िये प्राप्त नहीं माना जावेगा ।

२० आफिशल एसायनी का स्वयं प्रोक्सी होना

के हूँ भी कर्मचारी आफिशल एसायनी को अपनी ओर से वोट (Proxy) देने के अधिकार को दे सकता है ।

२१ मीटिंग का बढ़ा दिया जाना

आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह किसी मीटिंग को एक समयमें दूसरे समय के लिये तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में किये जाने के लिये हटा सके और ऐसे बढ़ाये जाने का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

व्याख्या—

मीटिंग ही में समय या स्थान के बढ़ाये जाने की सूचना हो जाने के लिये उस के लिये नोटिस की आवश्यकता हम दफ़्तर के अनुसार नहीं रखी गई है ।

२२ कार्रवाई का विवरण

आफिशल एसायनी मीटिंग में कार्रवाई का विवरण तैयार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

दूसरी सूची

(The Second Schedule)

कजोंके सुवृत



मामूली मामलोंमें सुवृत

१ सुवृत दाखिल करनेका समय

दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् त्रितनों तबद हो सकेंगा हर एक कर्जस्वाह अपना अपना सुवृत दाखिल करेगा ।

२ सुवृत दाखिल करनेकी तरीका

कर्जकी तस्दीक करने वाला हलफनामा आफिशल एसायनीकी देनेसे या उसके पास बगरिये रजिस्ट्री क्व के डाक द्वारा रवाना करनेसे सुवृत दाखिल किया जा सकता है ।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार कर्जकी तस्दीकमें लिखा हुआ हलफनामा आफिशल एसायनीके पास पहुंचनेसे कर्जेश सुवृत करना माना जावेगा । यह हलफनामा हाथमें भी दिया जा सकता है व रजिस्ट्री बज द्वारा भी भेजा जा सकता है ।

३ हलफनामा दाखिल करनेका अधिकार

कर्जस्वाह स्वयं या अपनी ओरसे इस कामके लिये अधिकार दिये हुए किसी व्यक्ति द्वारा हलफनामा दाखिल कर सकता है यदि वह प्रकारसे अधिकार दिये हुए व्यक्ति द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया हो तो उसमें यह बतलाया जावेगा कि वह किस अधिकारसे हलफनामा पेश कर रहा है तथा उसे मामलेका इहम किस प्रकार हुआ है ।

व्याख्या—

यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं कर्जस्वाह ही हलफनामा पेश करे उसकी ओरसे अन्य व्यक्ति भी हलफनामा दाखिल कर सकता है परन्तु उस व्यक्तिकी चाहिये कि वह अपने अधिकारको बतलावे तथा यह भी दिखलावे कि उसे मामलेका हाल कैसे मादूम हुआ है जैसे कि मुनीम या मुस्तारजाम अधशा दफतरमें काम करने वाला व्यक्ति निजके सामने कर्ज दिया गया हो या जिसने कामजातमें इदराज किया हो हलफनामा दाखिल कर सकता है ।

४ हलफनामामें क्या बात दिखलाई जाना चाहिये

हलफनामामें कर्जकी तफसील जाहिर करनेके लिये हिसाब या हिसाबका हवाला दिया जावेगा और उसमें उन कामजातका हवाला होगा निजके जरिये उस हिसाबकी पुष्टिकी जा सकती है । आफिशल एसायनी किसी समय भी उन कामजातको पेश करा सकता है ।

व्याख्या—

हलफनामामें एक तो हिसाब दिखाना जाना चाहिये या उसका हवाला दिया जाना चाहिये जिससे कि कर्जकी

तत्कालीन मादम हो सके दूसरे यदि कोई कायनात उस हिमावर्ती पुष्टिमें कर्जस्वाहके पास होने तो उनका भी हवाला उस हकनाममें दे दिया जाना चाहिये । साथ ही साथ आफिशल एग्जायनीन्गे अभिनव प्राप्त है कि जब वह चाहे वन कायनात को गिनना हवाला हकनाममें दिया गया हो पेश करा लेवे ।

५ हलफनाममें जमानतकार जिक्र होना चाहिये

हलफनाममें यह भी दिखलाया जावेगा कि आया कर्जस्वाह महफूज कर्जस्वाह है या नहीं ।

न्याय—

सादा बपयेकी डिर्का रद्दनामके तौर पर लिखी जा सकती है । और इससे यह तत्परि निश्चिता है कि मुर्तहिन्को महफूज कर्जस्वाह समझना चाहिये । 38 Bom. 359.

६ कर्ज साबित करनेका सूच्य

कर्ज साबित करनेका सूच्य कर्जस्वाह बर्तास्त करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई खाल दुरम न देवे ।

७ सुवृत देखने व उसका सुधायना करनेका अधिकार

वह कर्जस्वाह जो अपना सुवृत दाखिल कर चुका है दूसरे कर्जस्वाहों द्वारा दाखिल किये हुए सुवृतको हमेशा उचित समय पर देख सकता है ।

८ सुवृतसे घट्टका घटाया जाना

कर्जस्वाह अपना सुवृत दाखिल करते समय अपने कर्जेमें से तिस्राती घट्टेको घटा देवेगा परन्तु वह अपने खाय कर्जे के पांच रुपये सेकडे तकका घट्टा घटानेके लिये उस समय मसबूर नहीं होगा जब कि वह मसबूर दाममें उसे घटानेके लिये तैयार रहा हो ।

न्याय—

५ रुपये सेकडे तकका घट्टा वह अपने कर्जेमें बना रहने दे सकता है जब कि मसबूर दाममें बढ़ा दिया जाता हो ।

महफूज कर्जस्वाहोंका सुवृत

६ जब कि जमानत बसूलकी जाचुकी हो तबका सुवृत

यदि कोई महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानत बसूल कर चुका हो तो वह बसूल किये हुए रुपयेको घटाने के बाद जा कर्ज दस्तका बचे उसे साबित कर सकता है ।

न्याय—

इस दफ्तर अनुसार वह महफूज कर्जस्वाह भी अपना कर्ज साबित कर सकते हैं जो अपनी जमानत बसूल कर चुके हो परन्तु ऐसा वह उन्ही समय कर सकेंगे जब कि वापानदम कुछ राक्या बसूल न हुआ हो और जमानत बसूल किये जानेके बाद भी उसका कर्ज कुछ नारी बच रहे । इस सम्बन्धमें इस बातका भा प्यास रहना चाहिये कि ऐसे कर्जस्वाह सबल बचे हुए कर्जे के सम्बन्ध ही में साबित कर सकते हैं अपना पूरा कर्जेके लिये नहीं । जमानत रद्दनाममें शरलमें अथवा अथ किता वारकी शरलमें हो सकती है ।

१० जब कि जमानत छोड़ दी गई हो उस समय सुदृढ

जब कि आफिशल एसायनी के हकमें किसी मद्दूज कर्जवाहने अपनी जमानत सब कर्जवाहको लाने छोड़ दी हो तो वह अपने पूरे कर्जों के लिये साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

जमानत छोड़ देने के बाद मद्दूज कर्जवाह भी अन्य कर्जवाहों की भाँति अपने पूरे कर्जों के लिये साबित कर सकता है ।

११ दूसरे मामलों में सुदृढ

यदि कोई कर्जवाह न तो अपनी जमानत छोड़ और न उसमें अपनी जमानत को बसूल ही किया हो तो वह हिस्सा रसदी पाने में पहिले सुनमें अपनी अन्दाजा लगाई हुई जमानत की कीमत तथा जमानत की तर्फी और इसके किये जाने की तारीख बतलायेगा और अन्दाजा लगाई हुई कीमत घटाने के बाद जो कर्ज बचेगा उन्हीं के लिये वह हिस्सा रसदी पास करेगा ।

व्याख्या—

जमानत वाले कर्जवाह जमानत की कीमत घटाकर अपने बाकी कर्जों के सम्बन्ध में हिस्सा रसदी ले सकते हैं ।

१२ जमानत की कीमत का लगाया जाना

(१) जब कि जमानत की कीमत का अन्दाजा एक प्रकार से लगाया गया हो तो आफिशल एसायनी के अधिकार होगा कि वह अन्दाजा लगाई हुई कीमत कर्जवाह को अदा करने के बाद उस जमानत को छुड़ा लेवे ।

(२) यदि किसी जमानत की अन्दाजा लगाई हुई कीमत से आफिशल एसायनी तत्पक्ष में हो तो वह जमानत की जमानत को उन शर्तों व नियमों के साथ तथा इस समयों पर नीलाम पर चढ़ा सकता है जो उसके और कर्जवाह के दमियान तथा होवें या ऐसा कोई समझौता न होने पर जैसा अदालत हुकम देवे । यदि जमानत नालाम नाम में बेची जाने को होवे तो कर्जवाह या आफिशल एसायनी दिवालिये की जमानत की तरफ से बीछी बोल सकता है व जमानत को खरीद सकता है । परन्तु शर्त यह है कि कर्जवाह किसी समय भी आफिशल एसायनी को लिखकर नोटिस दे सकता है कि वह जमानत को छुड़ाना चाहता है या नहीं अथवा उसको बसूल कराना चाहता है या नहीं और यदि ऐसा होवे तो अदालत अन्तर आफिशल एसायनी लिखकर कर्जवाह को अपने इस प्रकार के अधिकार के प्रयोग किये जाने की सूचना न देवे तो वह । फिर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता । और एक हुनकूक या अन्य कोई एक जो आफिशल एसायनी का पहुँचता होगा कर्जवाह को प्रभु हो जावेगा और उसके कर्जों की तादाद में जमानत की अन्दाजा लगाई हुई कीमत कम कर दी जावेगी ।

व्याख्या—

उपदशा (१) के अनुसार आफिशल एसायनी कर्जवाह से उन्हीं जमानत की जमानत अन्दाजा लगाई हुई कीमत पर ले सकता है तथा उपदशा (२) के अनुसार वह कीमत से अधिकमत होने पर जमानत बसूल करने के लिये कर्जवाह को मजबूर कर सकता है । इस प्रकार जमानत बसूल करने में नीलाम आग किये जाने पर कर्जवाह व आफिशल एसायनी दोनों ही जमानत को खरीद कर सकते हैं । दफ्तर में जो शर्तें लगाई गई हैं उनके अनुसार व अदालत के अदर कर्जवाह आफिशल एसायनी के निश्चय को मान्य कर सकता है । जवाब न मिलने पर आफिशल एसायनी के हक कर्जवाह की प्राप्त हो सकते हैं तथा उसकी अदालत लगाई हुई कीमत मान कर बाकी कर्जों के लिये वह हिस्सा रसदी ले सकता है ।

१३ कीमतमें संशोधन

यदि कर्जस्वाहने अपनी जमानतकी कीमत ऊपर बनाये हुए दण पर लगाई हो तो वह उसकी कीमत तथा अपने सुदुनका संशोधन किसी समय भी कर सकता है जब कि वह आफिशल एसायनी या अदालतको इस बातका विश्वास दिला देवे कि कीमत व सुदुन गलतीसे कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके कारण नुक़नीयतीसे गलत हो गये हैं । या कीमतके अन्दाजा लगाये जानेके बाद जायदादकी कीमत बढ़ या घट गई है । परन्तु इस प्रकारका संशोधन कर्जस्वाहके खर्च पर होगा तथा इन बातोंके अनुसार होगा जो अदालत अपने हुक्मके अनुसार क़ानून से इस समय इसको बचत हो जायेगी जब कि आफिशल एसायनीने बिना अदालतमें दरखास्त दिये हुए संशोधनकी आज्ञा दे दी हो ।

व्याख्या—

१३ दफ़ाके अनुसार कीमतका संशोधन अदालत तथा आफिशल एसायनी दोनों ही पक्षों के पक्ष पर बनलिये जाति पर कर सकते हैं । जब कि आफिशल एसायनी बिना अदालतमें दरखास्त दिये हुए संशोधन की आज्ञा दे देवेगा तो कर्जस्वाहका खर्च वह जायेगा जتنا अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पाबन्दा बसने परना पड़ेगा तथा खर्चों भी उनमें शामिल करना पड़ेगा । संशोधन की आज्ञा जायदादकी कीमत घटाने या बढ़ाने पर दा जासतौं है इसी प्रकार यदि किसी पक्षदीसे जायदादकी कीमतका गलत अन्दाजा लगाया गया हो तो फ़ीमाका संशोधन हो सकता है ।

१४ क़ानून क़य्या वसूल हो जाने पर उसका लौटाया जाना

जब कि ऊपर बतलाये हुए नियमके अनुसार कोई कीमत तुक्कम की गई हो तो कर्जस्वाह उस अधिक वसूल किये हुए हिस्सा रसदी को लौटा देगा जो कि उसको सहायित कीमतके हिस्सेसे न मिलना चाहिये था अथवा वह हिस्सा रसदीके किये जाने हुए रपथमेंसे अधिक हिस्सा रसदी बाँटे जानेसे पहिले उस रपथको पाने का अधिकारी होगा जो उसे ठीक की हुई कीमतके अनुसार हिस्सा रसदीमें उपादा मिलना चाहिये और जिसे वह गलत कीमतकी वजहसे न प्राप्त हो । परन्तु संशोधनसे पहिले बाँटे हुए हिस्सा रसदीमें वह किसी प्रकारकी ग़ल्-बड़ी नहीं कर सकेगा ।

व्याख्या—

संशोधनसे पहिले यदि कोई हिस्सा रसदी बँट चुका हो तो उसमें कोई रसददल नहीं दिया जायेगा परन्तु संशोधनके समय यदि कोई क़य्या हिस्सा रसदीके लिये बचा हो तो उसमेंसे अग्रग्न्य का हिस्सा रसदी बटनेसे पहिले उस कर्जस्वाहकी क़य्या दिया जायेगा जो संशोधनके अनुसार कुछ अधिक मिलना चाहिये । वह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि संशोधनसे पहिले कोई कर्जस्वाह अपने हिस्सेसे अधिक क़य्या बतौर हिस्सा रसदीके वसूल कर चुका हो तो उसे बाद संशोधन वह क़य्या बटाना पड़ेगा और उस प्रकार लौटाया हुआ क़य्या सब कर्जस्वाहोंको हिस्सा रसदीके तौर पर मिल सकेगा ।

१५ जब कि जमानत बादमें वसूल की गई हो तब संशोधन

यदि जमानतकी कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके पश्चात् कोई कर्जस्वाह अपनी जमानत वसूल कर लेवे अथवा वह रुल १२ के अनुसार वसूल की गई हो तो वसूल किया हुआ क़य्या अन्दाजा लगाई हुई कीमतके स्थान पर सनडा जायेगा और वह दा प्रकारसे कर्जस्वाह द्वारा सहायित किया हुआ मुख्य समझा जायेगा ।

व्याख्या—

कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके बाद चाहे कर्जस्वाह स्वयं जमानतकी वसूल कर लेवे अथवा वह रुल १२ के

अनुसार वसूल की जावे वसूलवा हुई कीमत ही असली कीमत माना जावेगा और उसको अदाशा लगाई हुई कीमत की जगह पर समझना चाहिये ।

१६ हिस्सा रसदीसे वंचित रहना

यदि कोई मजदूर कर्जस्वाह पिछके रुस्त (नियमों) की पाबन्दी न करे तो वह हिस्सा रसदीसे हर प्रकार वंचित रहा जावेगा ।

१७ पानेकी हद

रूल १२ के नियमोंका ध्यान रखते हुए कोई भी कर्जस्वाह रुपयेमें १६ भागसे अधिक तथा इस पृष्ठमें यतकथे हुए सूदको छोट कर और कुछ नहीं पावेगा ।

व्याख्या—

इस रूलके अनुसार कोई भी कर्जस्वाह अपने कर्जसे अधिक नहीं पासकेगा । हा वह इस पृष्ठमें बनलाये हुए नियमों के अनुसार सूद अलवता मासकता है यदि रूल १२ के अनुसार कोई कर्जस्वाह स्वयं जायदादको सस्तेमें खरीद लेवे या उसकी कम अदाशा लगाई हुई कीमत मान ली जावे तो ऐसी बातोंसे वह फायदा उठा सकता है ।

रेहनकी हुई जायदादका हिसाब लिया जाना तथा उसका बेचा जाना

१८ रेहननामे आदिकी तहकीकात

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनेको दिवालियेकी किसी खास जायदाद या ठेके पर ली हुई जायदादका मुतहिन बतलाता हो और चाहे वह मुतहिन किसी दस्तावेजके जरिये होवे अथवा किसी और प्रकारसे होवे और चाहे वह कानूनी हो या कानूनीके तौर पर (Equitable) होवे अदालतमें दरखास्त देवे या आफिशल एमाथनो एक प्रकारसे मुतहिन जाहिर करने वाले व्यक्तिकी रजामन्दारी दरखास्त देवे या अदालत इस बातकी तहकीकात करेगी कि आया वह व्यक्ति उस प्रकारका मुतहिन है या नहीं और किस मुआवित्तके एवजमें तथा किस हालतमें है और अगर यह मालूम पड़े कि वह व्यक्ति उस प्रकारका मुतहिन है तथा उस रेहननामेके अनुसार बतलाई रकम के लिये उसके हक्के विरुद्ध कोई क़ाफी बजह न मालूम हो तो अदालत उस रेहननामेके असली रुपये सूद व खर्चें का हिसाब लेवे या तहकीकात करनेका हुक्म जो उसे मुनासिब समझ पड़े देवेगी तथा किराये, मुनाफे, हिस्सा रसदी, सूद या दूसरी आमदनी जो उस व्यक्तिको या उसके हुक्मसे अथवा उसके लिये किसी दूसरे व्यक्तिकी हुई हो जब कि रेहनकी हुई कुल जायदाद या वसला कोई हिस्सा उसके कब्जेमें रहा हो तो वसला भी हिसाब व तहकीकात करनेका मुनासिब हुक्म देगी । और यदि अदालतको यकीन हो जावे कि जायदाद बेची जाना चाहिये तो इस बातकी सूचना उन अखबारोंमें निकालनेका हुक्म देगी जो उसे मुनासिब मालूम पड़े कि कब कहा किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकारसे रेहनकी हुई किस इलाक़े या जायदाद अथवा उसके किसी हक़को बेचा जावेगा और फिर उसी प्रकार वह जायदाद बेची जावेगी और आफिशल एमाथनो अगर इसके विरुद्ध कोई हुक्म न दिया गया हो उस नीलामकी कारायेगा परन्तु उस मुतहिनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसी दरखास्त अवश्य देवे । ऐसे नीलाममें मुतहिन भी बोल सकता है तथा जायदादको खरीद सकता है ।

व्याख्या—

इस दफ़्तेके अनुसार मुतहिन दरखास्त देनेके लिये बाध्य नहीं है उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है ।

यदि कोई मुर्तद्दिन दिवालियेको किसी जायदादका हकदार उस हिसाबसे अपनेकी समझता हो तो वह अदायतमें दरखास्त दे सकता है या आफिसल एसायनी द्वारा ऐसी दरखास्त दिया सकता है। दरखास्तके पहुँचने पर अदालतका कर्तव्य होगा कि वह उसके दफ्तर की तद्विज्ञान को कि वही तक व सिध प्रमाण हक उसका दिवालियेकी किस जायदादके सम्बन्धमें पहुँचना है और यदि अदालतको उसके हकका यकीन हो जाये तो वह जिस लिये जाने तथा तद्विज्ञान किये जानेका हक देवेगा कि जिससे मादग हो सके कि असल व सूद गिनना है तथा खर्चोंक तौर पर गिनना मिलना चाहिये। इस दफ्तरमें यह भी बनना दिया गया है कि यदि उस प्रकारका मुर्तद्दिन रहनेवाला हुई जायदाद या उसके किसी हिस्से पर कब्जा रहा हो अथवा उसको ओरसे अथ कोई व्यक्ति कब्जा रहा हो तो उस क जेस जिस कदर जायदा मुर्तद्दिनने या उसकी आरसे किसी अन्य ब्यापकने उदाया हो वह उसकी मुआविलेसे मुजरे लिया जावेगा। जायदाद उचित प्रजात होने पर नीलाम भी कराई जा सकेगी मुर्तद्दिन स्वयं भी गोली बोल सकता है तथा नीलामकी घुसहरी अजबसेमें कर्तई जा सकती है व नीलामका मार व निगमना आफिसल एसायनीकी होगी। इस दफ्तरमें अनुसार होने वाली कर्तवाई एक प्रकारसे दरखतीकी कर्तवाई समझना चाहिये क्योंकि इसमें कोई किसी इस्तदार्द बनने आदिनी व्यवस्था नहीं है और न उसमें कोई फ़क रहने कबजे जानेका हो जिस है केवल दोष दिये हुए रूल १२ के अनुसार आफिसल एसायनी जायदादको छुड़ा सकता है दरखास्त पहुँचने पर तद्विज्ञान करना अशुद्धता कर्तव्य है परन्तु और बाँके एफ प्रकारसे उसकी इच्छा पर निर्भर है क्योंकि उसका धरना यकीन हो जाने पर निर्भर है।

११ दस्तावेज इतकाल

खुशियारके हकमें लिखी जाने वाली दस्तावेजोंमें वह सब फरीकन शामिल होंगे जिनकेलिये अदालत हुकम देवे।

२० बिक्रीका रुपया

इस प्रकार बचे जाने पर जो रुपया आवेगा वह पहिले उस खर्चकी अन्वयगीमें लगाया जावेगा जो कि अदालतमें दरखास्त देनेके सम्बन्धमें हुआ हो या किया गया हो तथा जो नीलामके सम्बन्धमें हुआ हो और इससे आफिसल एसायनीका कमीशन भी यदि उसे कुछ मिलना चाहिये पहिले ही दिलाया जावेगा। और इसके बाद मुर्तद्दिनका वह रुपया जहाँ तक हो सकेगा दिलाया जावेगा जो उसे असल सूद व खर्चमें दिलाया जाना बरामद हो और यदि इसके बाद बिक्रीका कोई रुपया बचे हो वह आफिसल एसायनीको मिलेगा। परन्तु यदि बिक्रीके रुपयेसे मुर्तद्दिन के निकलने वाले रुपयेकी पूरी अदायगी नहीं हो सकेगी तो वह अपने बचीया रुपयेके किये बतौर कर्जेक और कर्जदारोंकी भाँति सम्भित कर सकेगा तथा उसके साथ हिस्सा रसदी पालेका अधिकारी होगा परन्तु उसका पहिले बाँटे हुए हिस्सा रसदीमें किसी प्रकारकी गदबडी नहीं कर सकेगा।

ग्याख्या—

रूल १८ में जायदादके बचे जानेका उल्लेख है उसी सम्बन्ध इस रूलमें बननाया गया है कि बिक्रीके रुपयेसे पहिले हीन प्रकारके खर्चें चुगये जावेंगे (१) एक तो वह खर्च जो अदालतमें दरखास्त देनेके सम्बन्धमें किये गये हो (२) दूसरे वह खर्च जो जायदादके बचे जानेमें किये गये हों (३) तीसरे वह कमीशन जो आफिसल एसायनीको इस सम्बन्धमें मिलना चाहिये। इसके बाद मुर्तद्दिनका रुपया अदा किया जावेगा अगर मुर्तद्दिनका पूरा कर्त उससे न पूरे हो तो वह बाँकी कर्जे को और कर्जदारोंकी भाँति सम्भित कर सकता है तथा हिस्सा रसदी ले सकता है परन्तु हिस्सा रसदी का बट चुका है उसमें बाँडे गदबडी उसके इस बचीया कर्जेकी बजहसे नहीं पड़ेगी आर्थात् आपदा यदि जाने वाले रुपयेमें ही वह हिस्सा रसदी पासकेगा। नीलामका रुपया मुर्तद्दिनका कर्जा चुगये जानेके बाद बचने पर आफिसल एसायनीको हिस्सा रसदीके तौर पर बाँटे जानेके लिये मिलेगा।

२१ तहकीकात पर फारिदाई

इस प्रकारकी तहकीकात अच्छे ढंगसे किये जानेके लिये तथा हिसाबके अच्छे ढंग पर लिखे जानेके लिये और खरीदारको एक पट्टेचानके लिये सब फरीकैनका बयान मवालात दाखिले करके या अन्य प्रकारसे जैसा अदालत सचित समझे लिया जासकता है और सब फरीकैन अदालतके हुक्मके अनुसार दिवालिएकी जायदादस सम्बन्ध रखने वाली सब दस्तावेजों, कागजात, किताबों या अन्य तहसीरकी इल्फिया पेश करेंगे।

व्याख्या—

अदालत इस रूलके अनुसार फरीकैनके बयान जिस प्रकार चाहे ल सकती है तथा उनमें जायदाद सम्बन्धी सब कागजात दाखिल कर सकती है जिससे कि तहकीकात ठीक प्रकारसे हो सके और खरीदारमें जायदादक खरादने पर एक पट्टेचान सके।

२२ समय समय पर रुपयेकी अदायगी

यदि कोई किराया या दूसरी अदायगी किसी नियतकी हुई मुहत्त पर होना चाहिये और दिवालिएा करार दिया जानेका हुक्म उस मुहत्तके अलावा किसी और समय पर किया गया हो तो वह व्यक्ति जिसे किराया या वह अदायगी मिलना चाहिये उस हुक्मके होनेकी तारीख तकके इस्तेमालसे साबित कर सकता है जैसे कि वह किराया या अदायगी रोजानाके हिसाबसे मिलनेको चाहे।

व्याख्या—

किसी मियादके समाप्त होनेसे पहिले दिवालिएा करार दियाजानेका हुक्म होने पर हुक्म होनेकी तारीख तकका हिसाब लगाया जासकता है जैसे कि यदि छमाही छमाहाना किराया किया जानेवा होवे और वेशक दो ही महीने बढने पर दिवालिएा करार दिया जानेका हुक्म हो गया हो तो दो महानाका किराया और कर्जोंकी भांति बसूल किया जासकता है या जायदाद छ महीने समाप्त होने पर किराया वामिजुल अदा होगा। इसी प्रकार दूसरी शिर्कोंके बागमें समझना चाहिये।

सूद

२३ सूद

(१) यदि किसी निश्चित कर्ज या धनके लिये सूद न रखा गया हो या तब न हुआ हो और जो दिवालिएा करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले वामिजुल अदा हो चुका हो तथा वह कर्ज या धन इस एकदके अनुसार साबित किया जासकता हो तो कर्जदारके विभिन्न प्रकारसे छे रुपया सैकडा सालाना तकके हिसाबसे सूद साबित कर सकता है—

(ए) यदि वह कर्ज अथवा धन किसी तहसीरी दस्तावेजके आधार पर किसी निश्चित समयमें अदा किया जाने को होवे तो उस अदायगी की तारीखसे दिवालिएा करार दिया जाने का हुक्म होने तकका सूद लगाया जावेगा।

(बी) और यदि कर्ज किसी अन्य प्रकारसे निकलना हो तो उस तारीखसे जबसे कि तहसीरी तौर पर रुपया भगा गया हो और कर्जदारको इस बातका नोटिस दिया गया हो कि उससे उस तारीखके बादसे अदायगी तकका सूद लिया जावेगा। यह सूद भी दिवालिएा करार दिया जाने का हुक्म होने वाली तारीख तक मिलेगा।

२ यदि दिवालियाकी कारवाहीके सम्बन्धमें साबित किये हुए किसी कर्जमें सूद या सूबके स्थानमें और कोई रूपया लगाया गया हो तो वह सूद या रूपया हिस्सा रसद्रीक लिये केवल छ रूपया सेरज साखाना ही क तौर पर जोड़ा जावेगा परन्तु साबित किये हुए सब कर्जोंक अदा हो जानेके बाद यदि कोई रूपया बचे तो उक्त उस कर्जवाहका बड़ीया तथा शुदा सूद या सुगारा दिलाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस कलके अनुसार बिना तय हुए सूदके स्थानमें छ रूपया सेरज साखाना तथा सूद दिलाया जाहकता है उक्त लिये वा सूतें बतलाई गई हैं एक ता उस वक्त जब कि रूपया किसी दम्तानके आधार पर वाणिज्य अदा हो और दूसरे बिना दस्तावेजी कर्जों पर उक्त समयसे सूत मिलेगा जब कि रूपया वाणिज्य अदा हो और बिना दस्तावेजा कर्जों पर उक्त समयसे सूद मिलेगा जब कि इसके लिय कर्जदारको नेटिव दिया गया हो दोनों हाथोंमें सूद उस तत्प्राप्त तत्का मिल सकगा जब कि दिवालिया करार । दया जानका हुका हुआ हो ।

उपरुल (२) में यह बताया गया है कि दिला रसदी कल छ रूपया सेरज साखाना हिस्से लिये हुए सूद पर हो मिल मरेगा चाहे इसके अधिक सूद या मनाफा क्यों न तब हुआ हो परन्तु माप ही साथ यह भा दिया हुआ है कि अगर साबित नियो हुए सब कल पूर्ण रूपसे चुकाया जायके व कुछ कालिज बच तो उसमें तय शुदा बकाया सूद अदा किया जावेगा ।

वह कर्ज जो भविष्यमें अदा किये जाना चाहिये

२४ भविष्यमें चुकाये जाने वाले कर्ज

कलकवाह सम्बन्धके लिये भी जो दिवालिया करार दिये जाते समय अदा किया जानेको न होने इती प्रकार साबित कर सकना है जैसे कि वह कर्ज अभी समय अदा किया जान का होवे केवल उसमेंसे छ रूपया सेरज साखाना दिलावये सूद हिस्सा रसदी बाद जनेके समयसे रूपयको वाणिज्य अदा होने वाले समय तक लिये वन शर्तकि हिस्सासे घणया जावेगा जिनके अनुसार कर्ज लिया गया हो ।

व्याख्या—

इस कलके अनुसार यदि कोई कर्ज दिवालिया करार दिये जाने वागी तत्प्राप्तके बाद किया समय अदा किया जानकी होने ही भी वह साबित किया जाहकता है उक्तमें हिस्सा रसदा वाचक समयसे कर्ज वाणिज्य अदा होने वाली तत्प्राप्त तत्का सूद छ रूपया सेरज साखाना हिस्सा वग दिया जावेगा ।

सुदूतका मान लिया जाना या उसका तारिज होना

२५ सुदूतका मान लिया जाना या उसका तारिज होना

आफिदाल एसायमी हर एक सुदन तथा कलके बतहातको समझेगा और लिखकर पूरे कल या उमर किमी हिस्से का मजूर या कामचूर करेगा या उमरका ताईदमें और अधिक सुदन मागगा । यदि वह किसी सुदूत तारिज पर तो वह उसक खयिरजकी जमीकी बतहात कर्जवाहका लिखकर बतहावेगा ।

व्याख्या—

इस कानून के अनुसार किसी सुवृत्त के खारिज निये जान की वजह कर्जस्वाह को दिसपर बताई जाना चाहिये । सुवृत्त नावाकी मादूम पडने पर अधिक सुवृत्त भी मागा जासकता है । पूरा कर्ज अथवा उसका कोई हिस्सा साबित माना जासकता है । सुवृत्त की मानना न मानना अधिकश एसायनी के हाथ है वही सुवृत्त की सुनगा व मज्दगी अथवा खारिज करनेका हुक्म दगा भी अदालतमें इसकी आज्ञा इस प्रकार बताए हुए नियमों के अनुसार की जासकती है ।

२६ बंकायदा लिखे हुए सुवृत्तको अदालत खारिज कर सकती है

यदि अधिकश एसायनीको मालूम पड़े कि कोई सुवृत्त बंकायदे ले लिया गया हो तो अदालत अधिकश एसायनीके दरखास्त देने पर कर्जस्वाह को नोटिस देनेके बाद उस सुवृत्तको निकाल सकती है अथवा उसकी तादाद कम कर सकती है ।

व्याख्या—

इस कानून के अनुसार यदि गन्तावे कोई सुवृत्त मान लिया गया हो तो अदालत उसे बादमें रद्द कर सकती है । यदि दूसरे कर्ज का सुवृत्त घात हो तो पूरा कर्ज रद्द कर दिया जावेगा अथवा यदि कर्जके किसी हिस्से का सुवृत्त ठीक न हो तो वह हिस्सा कर्जसे निकाल दिया जावेगा । अदालत इस कानून के अनुसार कर्जवाई करनेमें पहिले उस कर्जस्वाहको निसक कर्ज रद्द किया जाने की हानि सूचना देवेगा । यदि कोई मुर्तिदिन दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेसे दो सालके अन्दरवा गिला हुआ रेशननामा पेश करे तो इस बातका बार सुवृत्त मुर्तिदिन पर होगा कि वह रेशननामा काफ़ी मुआविके लिये नेक नापनाके साथ दिया गया था और यदि अधिकश एसायनीने एक बार इस कर्ज की मान भी लिया हो तो उससे बार सुवृत्त बदल नहीं जावेगा तथा अधिकश एसायनी अदालतमें उस कर्ज की रद्द कर देनेकी दाखला देसकता है । देखो अधिकश एसायनी मद्रास बचान सम्बन्ध मुद्राक्षिपर 43 Mad 739

२७ किसी सुवृत्तको रद्द कर देने या उसे घटा देनेके लिये अदालतके अधिकार

यदि अधिकश एसायनी किसी मामलेमें दस्तन्दगी करनेसे इन्कार कर देवे तो अदालत किसी कर्जस्वाह के दरखास्त देने पर किसी सुवृत्तको रद्द कर सकती है या कम कर सकती है अथवा तक्षणीया या स्वीतके मामलेमें दिवालियेके दरखास्त देने पर किसी सुवृत्तको निकाल सकती है या कम कर सकती है ।

व्याख्या—

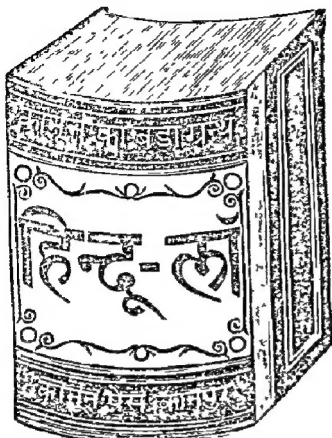
अधिकश एसायनीके अनिश्चित किसी कर्जस्वाह या दिवालियेके दरखास्त देने पर भी अदालत किसी सुवृत्तको खारिज कर सकती है या एतित शर्त कर्जकी तादादको कम कर सकती है । कर्जस्वाह उसी समय इस नियमके अनुसार कर्जवाई करनेकी दाखला दे सकता है जब कि अधिकश एसायनी दस्त दाखी करनेसे इन्कार कर देवे । दिवालिया तरकीब या स्वीम वाले मामलेमें दरखास्त देसकता है अर्थात् यदि कोई कर्ज कर्जा उसके विरुद्ध साबित किया गया हो तो उसने रद्द निये जानेका दाखला या कर्ज गट्टो हुए कर्ज को कम निये जानेकी दाखला दे सकता है ।

तीसरी सूची

(The Thired Schedule.)

मंसूख किये हुए एक्ट

साल	नम्बर	नाम	मंसूख किये जानेकी दिना
१८७८	११, १२ विधेय रिषा चैप्टर २१	I स्टैट्यूट दी इण्डियन इन्साल्वेन्सी एक्ट १८७८	वतना जो कि मंसूख न किया जा चुका हो
१८७९	२६	II. सपरिषद गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा बनाये हुए एक्ट दी इन्साल्वेन्सी इस्टेड (एनलैन्ड डिबिटिड) एक्ट, १८७९	वतना जो मंसूख न किया जा चुका हो
१८९८	१७	दी इण्डियन इन्साल्वेन्सी इन्स एक्ट, १८९८	दफाये १ व ३
१९००	३	दी लोभर वर्मा कोर्ट्स एक्ट	दफा ८ के उपदफा (१) का ड्राज (डी) और उपदफा (२), तथा दफा १७ के उपदफा (१) में मन्त्र शब्द "Official assignee" और उप- दफा (२) व (४) में यह शब्द "Official assignee"
१९०८	५	१९०८ का संशोधन अधिनियम दीवानी	दफा १२० की उपदफा (२)



हिन्दू-लॉ

दूसरी बार छपा हुआ

पहलेसे चौगुना बड़ा

हिन्दीमें वानूतना सबसे बड़ा ग्रन्थ



आज तक कानूनका ऐसा सर्वोत्तम पूर्ण ग्रन्थ हिन्दीमें नहीं छपा। पढ़तेही चित्त सुखा होगा और विना प्रशंसा किये जान न होंगे। पहिलेसे चौगुना बड़ा, चौगुनी नतीरे व सत्र नये कानून, सग चौगुना पाबदेमंद हैं, तिम पर भी मुख्य नहीं बढ़ाया गया। अझालतमें होने वाले न्याय को घरहीमें समझ लेनेक लिय यह पुस्तक छपा गया है। १० संस्कृत ग्रन्थों, १०२

दूसरे कानूनों, हजारों नजीरों, बड़ाइरणों व सैकड़ों नक़्शोंसे परिपूर्ण है। यानी शामिलशरीक या बंटे हुए परिवारमें मर्दों, स्त्रियों, लड़कों, गर्भमें बच्चोंका, जायदादमें कितना हक है, किसके सरने पर कौन वारिस कब होगा, विवाह कैसे कर-कन्याके साथ किम उमरमें, कब जायज है, कैसे विवाहके लड़के वारिस होंगे, पति, पत्नीको कैसे, कब, किस तरह अपने पास रख सकते हैं, नावाजिगका चली कौन होगा, चलीक हक, पाबान्दिया, व जिसेदागिया, कौन हैं, कैसे चली निकाला जायगा, उस पर छिन्नी होगी, मोदका पूरा कानून बया ह, ३२७ वारिसों को जिसके बाद किसे व किस हंगसेकब हक मिलता है, अये, व अन्न भन्न वारिसों का नया कानून बया है; शहियों व वश्याओं की जायदादका कानून बया है, उनके वारिस कौन, कब व जिस तरह होत हैं, भिठलाई औरताहा हक क्या है, कौन धन छी धन है, उसके वारिस कौन, कब जिस तरह होत हैं, स्त्रियोंके हकका पूरा कानून बया है, फकी रहन, वय वाली जायदादक शगडोंका कानून क्या है, दान व दयायत कैसे कब किम जायदादकी होगी कैसे हक देकर लिखी जायगी कैसे नाजायज हागी, मन्दिर, पाठशाला, धर्मशाला आदिमें जायदाद कैसे लगाई जाय, ट्रस्ट कैसे सुन्तर हो, जरायी गलतीय कैसे मसूप होगा, साधु सन्यासी महन्त, गद्दीघरोंक हक क्या है, बेरा, पुजारी, शिष्यायतक हक, अधिकार कब, किस तरह, किस जायदादमें कैसे होत हैं, दवस्थानका पूरा कानून बया है, भावी वारिसोंक हक कब कमे होंगे, इत्यादि हजारों बानाका आपरा पूर्ण ज्ञान होगा। रु० १९२५ ई० तकके सब नये कानून हजारों नजीरों व न्याय्या माहित दिय गय हैं। आप कानूनके पणेत हा सकय। मूल्य १२) टा० १॥)

मिलनेका पता:—कानून प्रेस, कानपुर